राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] पन्द्रहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का अड़तीसवां दिवस [संख्या: 13

बुधवार,

01 मार्च 2023

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 224

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री गिर्राज सिंह।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री नारायण सिंह देवल।

जालौर में जल जीवन मिशन के तहत लाभान्वित ढाणियां

225. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में जल जीवन मिशन अन्तर्गत नर्मदा कैनाल (ईआर) आधारित क्लस्टर जल प्रदाय परियोजना जसवंतपुरा-रानीवाड़ा सांचौर-सरनाऊ-चितलवाना-बागौड़ा भीनमाल-जालौर-सायला जिला जालौर में अब तक किस-किस तहसील के कितने-कितने गांव व ढाणियों को पेयजल से लाभान्वित किया जा रहा है? क्या भीनमाल शहर को नर्मदा ई.आर. प्रोजेक्ट से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में नर्मदा एफआर जालौर, सांचौर, चितलवाना, बागौड़ा, आहोर, सायला एवं डीआर क्लस्टर जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, सांचौर, सरनाऊ जिला जालौर में हर घर नल से जल कनेक्शन हेतु डीपीआर तैयार कराने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो स्वीकृत डीपीआर के अनुसार कुल कितने नल कनेक्शन जारी होने थे व अब तक कुल कितने कनेक्शन किये जा चुके हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नारायण सिंह देवल)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त योजनान्तर्गत पूर्व में किये गये सर्वे के आधार पर काफी घर कनेक्शन से वंचित रह गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त से वंचित रहे घरों का पुनः सर्वे करवाकर कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. महेश जोशी): (1) जालौर जिले में जल जीवन मिशन अन्तर्गत नर्मदा कैनाल (ईआर) आधारित जल प्रदाय परियोजना की स्वीकृति राज्यस्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.एस.सी.) की 28वीं बैठक दिनांक 08.10.2021 द्वारा राशि रु. 927.20 करोड़ की जारी की गयी। परियोजना का कार्यादेश दिनांक 03.06.2022 को राशि रु. 833.49 करोड़ का मै. जीवीपीआर इंजीनियर्स लिमिटेड, हैदराबाद के पक्ष में जारी किया गया। कार्यादेश के अनुसार कार्य प्रारम्भ तिथि 13.06.2022 एवं कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 12.03.2024 है। इस परियोजना के अन्तर्गत जालौर जिले के 306 गांव एवं 985 ढाणियों को हर घर पेयजल से 1,13,251 कनेक्शन द्वारा लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। प्रोरेटा अनुसार वांछित 27 प्रतिशत प्रगति के विरुद्ध फर्म द्वारा अभी तक 15 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया है एवं अभी तक किसी भी गांव एवं ढाणी को इसके माध्यम से लाभान्वित नहीं किया गया है। फर्म द्वारा कार्य धीमी गति से करने के कारण राशि रुपये 1.44 करोड़ की शास्ति के रूप में रोकी गई है। परियोजना के अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने वाले गांवों व ढाणियों का तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

जिला जालौर के 256 गांव एवं भीनमाल शहर की जल मांग को शामिल करते हुए नर्मदा ई.आर. आधारभूत पेयजल परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नीति निर्धारण समिति की 191वीं बैठक दिनांक 19.09.2013 के द्वारा जारी की गई थी। परियोजना के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु मुख्य अभियन्ता, परियोजना जोधपुर के कार्यादेश क्रमांक 10263-78 दिनांक 24.09.2013 द्वारा मैसर्स एसपीएमएल को राशि रुपये 372.70 करोड़ (348.47 निष्पादन एवं 24.23 संधारण) का कार्य आदेश जारी किया गया। आधारभूत संरचना निर्माण अन्तर्गत पम्प हाउस, फिल्टर प्लांट एवं मुख्य पाइप लाइन इत्यादि का निर्माण किया जाना था। कार्यादेश के अनुसार इस कार्य को दिनांक 04.10.2016 तक पूर्ण किया जाना था, परन्तु कार्यकारी फर्म

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

के स्तर पर अत्यधिक विलम्ब के कारण अब इस परियोजना को माह जून, 2023 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। संवेदक द्वारा वर्तमान प्रगति के अनुसार 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। फर्म द्वारा कार्य धीमी गति से करने के कारण राशि रुपये 20.98 करोड़ शास्ति के रूप में रोकी गई है। इस परियोजना के अंतर्गत भीनमाल शहर को पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु परियोजना के अन्तर्गत पालड़ी हैडवर्क्स पम्पिंग स्टेशन से भीनमाल पम्पिंग स्टेशन तक मुख्य पाइप लाइन का कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में पाइप लाइन की टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है। टेस्टिंग उपरान्त माह मार्च 2023 तक इस परियोजना के माध्यम से भीनमाल शहर की वर्तमान वितरण प्रणाली द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

(2) जल जीवन मिशन अंतर्गत वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में नर्मदा एफ.आर. जालौर, सांचौर, चितलवाना, बागौड़ा, आहोर, सायला एवं डीआर क्लस्टर जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, सांचौर, सरनाऊ जिला जालौर में हर घर नल से जल कनेक्शन हेतु डीपीआर तैयार कराने की घोषणा की गई थी। नर्मदा एफ.आर. एवं डी.आर. क्लस्टर पेयजल परियोजना की डीपीआर तैयार करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यस्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) की 20वीं बैठक दिनांक 11.02.2021 द्वारा क्रमशः राशि रु. 216.26 लाख एवं 113.17 लाख की जारी की जाकर डीपीआर तैयार करने हेतु मै. वैपकोस लि. को कार्यादेश दिनांक 10.03.2021 को जारी किया गया।

मैसर्स वैपकोस लि. द्वारा तैयार की गयी नर्मदा एफ.आर. क्लस्टर परियोजना की डीपीआर की स्वीकृति राज्यस्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.एस.सी.) की 29वीं बैठक दिनांक 09.11.2021 द्वारा राशि रु. 535.88 करोड़ की जारी की गयी एवं तकनीकी स्वीकृति विभागीय तकनीकी समिति की 725वीं बैठक दिनांक 29.07.2022 द्वारा राशि रु. 434.66 करोड़ की जारी की गयी। इस परियोजना के अन्र्तगत जालौर जिले के 277 गांवों एवं 915 ढाणियों में समेकित प्रबंधन सूचना तंत्र (आईएमआईएस) के अनुसार कुल 1,19,942 नल कनेक्शन जारी किये जाने प्रस्तावित हैं। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निविदा दिनांक 10.07.2022 को आमंत्रित की गई थी, जिसे वित्त विभाग द्वारा दिनांक 02.01.2023 को जारी निर्देशों के क्रम में वित्त समिति की 834वीं बैठक में दिनांक 18.01.2023 के द्वारा पत्रित कर दिया गया। वर्तमान में परियोजना की क्रियान्विति हेतु पुनः निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

इसी प्रकार नर्मदा डी.आर. क्लस्टर परियोजना की डीपीआर की स्वीकृति राज्यस्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.एस.सी.) की 27वीं बैठक दिनांक 03.09.2021 द्वारा राशि रु. 260.91 करोड़ की जारी की गयी एवं तकनीकी स्वीकृति विभागीय तकनीकी समिति की 709वीं बैठक दिनांक 12.10.2021 द्वारा राशि रु. 209.38 करोड़ की जारी की गयी। इस परियोजना के अन्तर्गत जालौर जिले के 160 गांवों एवं 494 ढाणियों में समेकित प्रबंधन सूचना तंत्र (आईएमआईएस) के अनुसार कुल 57,924 नल कनेक्शन जारी किये जाने प्रस्तावित हैं। परियोजना की क्रियान्विति हेतु दिनांक 10.02.2022 को मैसर्स डारा इन्जीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., जोधपुर के पक्ष में राशि रुपये 202.81 करोड़ का कार्यादेश जारी किया गया है। कार्यादेश के अनुसार कार्य प्रारम्भ तिथि 20.02.2022 एवं कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 19.11.2023 है। परियोजना के अन्तर्गत दिनांक 20.02.2023 तक लक्षित 49 प्रतिशत कार्य के विरुद्ध 46 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर 11,738 नल कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। परियोजना की प्रोरेटा प्रगति से अपेक्षाकृत कम प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए राशि रुपये 20.00 लाख की शास्ति के रूप में रोकी गई है। परियोजनावार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जल जीवन मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत समस्त योजनाएं वर्ष 2011 की जनगणना सर्वे के आधार पर बनाई गई हैं। विगत दशक की जनसंख्या वृद्धि के अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना में वृद्धि कर वर्तमान वर्ष की आबादी की गणनानुसार आगामी 30 वर्षों की पेयजल मांग अनुसार योजना बनाई जाती है। घरों की संख्या हेतु पंचायतों से प्राप्त आंकड़ों का इन्द्राज आई.एम.आई.एस. साइट पर किया जाता है। उक्त साइट पर दिनांक 01.04.2022 की स्थिति अनुसार जालौर जिले में कुल 3,81,005 घर स्थित हैं, जिनमें से 66,732 घरों को जल जीवन मिशन प्रारम्भ होने से पूर्व ही दिनांक 15.08.2019 तक लाभान्वित किया जा चुका था एवं शेष 3,14,273 घरों में संबंध हेतु जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

भारत सरकार द्वारा जारी अद्यतन दिशा-निर्देशानुसार "गांव/बस्तियों से दूर एकल घरों/खेतों में स्थित घरों को इस कार्यक्रम के वित्त पोषण से जल संबंध नहीं दिया जायेगा"। अत: ऐसे वंचित घरों को पुन: सर्वे करवाकर जल सम्बन्ध जारी किये जाने का प्रावधान नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ा हुआ माना। प्रश्न।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने प्रश्न के खण्ड संख्या 3 में भारत सरकार की गाइड लाइन का हवाला देकर कहा है कि गांव और बस्तियों से दूर खेतों में बसे घरों को इस योजना में कनेक्शन नहीं दिये जायेंगे, जबकि, अध्यक्ष महोदय, मेरे पास भारत सरकार की यह गाइड लाइन है। आप कहो तो मैं टेबल कर दूं। भारत सरकार की इस गाइड लाइन में बिन्दु संख्या 4.9 में साफ लिखा है कि कोई भी घर बिना कनेक्शन नहीं रहे, इसका खास ध्यान रखा जाये।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, आप गाइड लाइन का प्रश्न पूछ लें। गाइड लाइन्स लिखी हुई हैं इसलिये प्रश्न पूछें। प्रश्ने पूछें, प्रश्न क्या है आपका?

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): गाइड लाइन में 4.9 में मतलब यह साफ लिखा है कि कोई भी घर...

श्री अध्यक्ष: समझ में आ गया, प्रश्न पूछें न आप।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): यह गाइड लाइन में मंत्री महोदय है कि नहीं है? अगर गाइड लाइन है तो उसका हवाला दें। अध्यक्ष महोदय, एक मैं और कहूंगा कि तत्कालीन जलदाय मंत्री कल्ला साहब ने 24.08.2021 को जल जीवन मिशन की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट थी, उसमें प्रेस कांफ्रेंस में साफ कहा है कि गांवों की मुख्य बस्तियों से दूर बसी आबादी को नल से जोड़ा जायेगा, तो मेरा प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय यह बतायें कि भारत सरकार की गाइड लाइन सही है या बी.डी. कल्ला साहब, तत्कालीन मंत्री का वक्तव्य ठीक है या आपके अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सीधा प्रश्न है भारत सरकार की जो गाइड लाइंस हैं, उस गाइड लाइन के अनुरूप कनेक्शन देंगे कि नहीं देंगे?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास नेशनल जल जीवन मिशन के डाइरेक्टर मनोज कुमार साहू का यह पत्र है, जो उन्होंने 29 जनवरी, 2021 को हमको भेजा था। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है "providing Functional Household Tap Connection (FHTC) for single houses/farm houses for away from villages/ habitations are not be funded under JJM." आप कहें तो मैं यह लैटर टेबल कर दूं तो जो गाइड लाइंस गवर्नमेंट आफ इंडिया की होंगी, माननीय सदस्य को, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना

(डा. महेश जोशी)

चाहता हूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की जो भी गाइड लाइंस इस सम्बन्ध में होंगी, उनकी हम निश्चित रूप से पालना करेंगे।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि जेजेएम की जो इन्होंने डीपीआर बनायी, जैसे किसी गांव में पचास किलोमीटर पाइप चाहिये और इन्होंने चालीस किलोमीटर की डीपीआर कर दी तो प्रत्येक गांव में 10-15 किलोमीटर शोर्ट पड़ रही है और वह ढाणियां छूट रही हैं जिसमें आप जो कह रहे हो कि दूर हैं, इसका सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आपकी भावना समझ गया। माननीय मंत्री जी, राजस्थान में जो रेवेन्यू विलेज हैं वो रेवेन्यू विलेज में 1/3 पापुलेशन पंचायत मुख्यालय पर, 2/3 पापुलेशन हेमलेट में है। जब आप जल जीवन मिशन की स्कीम बनाते हैं तो हेमलेट की पापुलेशन को भी काउंट करते हैं, जब हेमलेट की पापुलेशन को काउंट करते हैं तो जो पाइप लाइन ले करना है उसमें वह तो इन्क्लूड है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह बात जो आपकी गाइड लाइंस में जहां आइसोलेशन में मकान हैं, 1, 2, 3 मकान हैं जो बहुत दूर हैं वह तो समझ में आता है लेकिन जो ढाणी बसी हुई है जहां पचास घर हैं, साठ घर हैं वो रेवेन्यू विलेज का पार्ट हैं इसलिये उनको कनेक्शन देने के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि डाइरेक्टर का जो है वह यह नहीं है, डाइरेक्टर का जो रिसोर्ट है यह फलाना है उनके लिए है, तो क्या ऐसी ढाणी जो रेवेन्यू विलेज का पार्ट हैं उनमें रहने वाले आदमियों को कनेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे कनेक्शंस जो स्वीकृति निकलती है एसएलएसएससी में उसमें गवर्नमेंट आफ इंडिया के हिसाब से सारा काम होता है, ऐसा कोई हैबिटेशन जो रेवेन्यू विलेज में आता हो उसको हमने छोड़ा नहीं है। छोड़ा सिर्फ उनको है जो गवर्नमेंट आफ इंडिया की गाइड लाइंस में नहीं आता। फिर भी माननीय सदस्य अगर किसी का मुझे बतायेंगे तो मैं उसको दुरुस्त कराने का आश्वस्त करता हूं।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इसका उत्तर नहीं निकलेगा। मुझे पता है। आप बैठें। प्लीज। अंकित नहीं होगा।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। I will not allow it. रिकार्ड नहीं होगा। I will not allow it. बहुत गलत बात है, मैं मदद करना चाहता हूं। आप बैठें। प्लीज। I will name you. नीचे बैठें प्लीज। गलत परम्परा डाल रहे हैं। बहुत गलत परम्परा डाल रहे हैं। आपको और प्रोब्लम हो तो अलग ढंग से लेकर आयें, I will help you पर गलत प्रश्न मत पूछें।

अगला प्रश्न। श्री जगदीश चन्द्र।

सादुलशहर में डी.एम.एफ.टी. से स्वीकृत कार्य

226. श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि DMFT के अंतर्गत जमा राशि उसी जिले के विकास कार्यों में व्यय की जाती है? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक जिला श्रीगंगानगर में उक्त फण्ड में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में वर्ष 2018 से माह दिसम्बर, 2022 तक कितनी राशि उक्त फण्ड से कौन-कौनसे विकास कार्यों पर व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खान मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 के प्रावधानों व भारत सरकार के निर्देश दिनांक 12.07.2021 के अनुसार ट्रस्ट फण्ड में उपलब्ध राशि का उपयोग जिले में खनन से प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों के हित व लाभ के लिए किया जाता है। श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट फण्ड में वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक प्राप्त राशि का वर्षवार विवरण निम्न है:-

क्र.सं.	**वर्ष**	**प्राप्त राशि (रु. लाखों में)**
1	2020-21	198.95
2	2021-22	247.85
3	2022-23 (जनवरी, 2023 तक)	233.04

(2) विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2022 तक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट फण्ड से 8 विकास कार्यों पर राशि रुपये 24.63 लाख व्यय की गई है। कार्यवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि मात्र 65 लाख की सैंक्शन सादुलशहर विधान सभा क्षेत्र में हुई है। क्या यह राशि पर्याप्त है? हमारे हिस्से के हिसाब से ज्यादा राशि बनती है, यह कम है और आगे मंत्री जी, क्या मंशा रखते हैं, सादुलशहर में कितना पैसा देना चाह रहे हैं?

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, इनके विधान सभा क्षेत्र में जो कार्य स्वीकृत हुए मैंने उनकी पूरी डिटेल दी है। जहां तक राशि स्वीकृत करने का है तो इसका निर्णय गवर्निंग काउन्सिल करती है। उसके खुद माननीय विधायक सदस्य हैं। चूंकि कुल राशि 14.11 करोड़ रुपये अभी तक वहां डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में एकत्र हुए हैं, मैं इस बाबत जिला कलेक्टर को शासन के माध्यम से पत्र लिखूंगा कि आपके जो कार्य हैं उनको वरीयता प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री ज्ञानचंद पारख।

रोहट पंचायत समिति में नरेगा मेट के बकाया का भुगतान

227. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला पाली की पंचायत समिति रोहट (पाली) में किस-किस ग्राम पंचायत में कितने समय से, कितने नरेगा मेट की कितनी-कितनी राशि का किन-किन कारणों से भुगतान किया जाना शेष है? उक्त बकाया राशि का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नरेगा श्रमिकों के भुगतान के साथ-साथ नरेगा मेट के भुगतान हेतु निश्चित अवधि निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री) (ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री के स्थान पर): (1) पाली जिले की पंचायत समिति रोहट में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मेटों की लम्बित मजदूरी राशि, मेट का नाम, ग्राम पंचायत, नियोजन अवधि एवं भुगतान लम्बित रहने के कारण का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

उक्त लम्बित बकाया भुगतान खाता संबंधी विवरणों का पीएफएमएस

(श्री रामलाल जाट)

से सत्यापन व सम्बन्धित कार्य जिस पर मेट नियोजित था, पर स्वीकृत अर्द्धकुशल/कुशल श्रम राशि में संशोधन कर भुगतान की कार्यवाही की जानी प्रक्रियाधीन है।

(2) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मेटों का भुगतान भारत सरकार से सामग्री मद में राशि प्राप्त होने पर कुशल एवं अर्द्धकुशल मद से किया जाता है।

केन्द्र प्रवर्तित महात्मा गांधी नरेगा योजना में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड व दिशा-निर्देशों के अनुरूप भुगतान किये जाते हैं। मेटों का भुगतान समय पर हो सके, इसके लिए मेटों का भुगतान श्रम मद में करने हेतु विभाग द्वारा दिनांक 02.03.2022 22.04.2022 एवं 10.02.2023 से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र प्रेषित किये गये हैं। (परिशिष्ट-2 संलग्न)

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, उक्त लम्बित बकाया भुगतान खाता सम्बन्धी विवरणों का पीएफएमएस से सत्यापन व सम्बन्धित कार्य जिस पर मेट नियोजित था, पर स्वीकृत अर्द्धकुशल/कुशल श्रम राशि में संशोधन कर भुगतान की कार्यवाही की जानी प्रक्रियाधीन है।

माननीय मंत्री महोदय, 2019 से 2023 तक चार सालों से उन मेटों का भुगतान होना बकाया है। चार सालों में बैंक खाते का मिलान नहीं हो सका तो इसके लिए आपका कोई न कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा। वह कौन अधिकारी जिम्मेदार है, उसके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करोगे?

आप कह रहे हो कि नियमों में संशोधन, यह नरेगा योजना कोई नई तो बनी नहीं है, नियम पहले के बने हुए हैं। अब जब तक भारत सरकार नियमों में संशोधन नहीं करेगी, उसके हिसाब से आप इनको पेमेंट करोगे, नहीं तो कोई और मद से आप इनका भुगतान करवाओगे क्या और विशेष तौर से इसके लिए जिम्मेदार कौन है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें, आप एक्सप्लेन बहुत करते हैं।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की पीड़ा सही है। पाली के कुल 23 ग्राम पंचायतों में से 21 ग्राम

(श्री रामलाल जाट)

पंचायतों में मेटों का भुगतान लम्बित है। यह करीब 142 कुल मेट हैं, जिसमें 120 मेटों का सत्यापन संबंधी प्रकरण लम्बित होने की वजह से 5 लाख 91 हजार रुपये बाकी हैं। रही बात समय की, पहले बड़ौदा बैंक मारवाड़ ग्रामीण बैंक के नाम से थी। थोड़े टाइम यह नाम रहने के बाद डिपार्टमेंट ने आईएफएस कोड भारत सरकार को भेजा। इस बीच इसका नाम चेंज होकर मरुधरा ग्रामीण बैंक हो गया, इस वजह से लम्बित हुआ। फिर थोड़े टाइम बाद इसका नाम राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक हो गया। आईएफएस कोड बार-बार भारत सरकार को लिखने की वजह से दिक्कत हुई। अब इसका नाम सही होने के बाद हमने अपलोड कर दिया है और इस 31 मार्च तक हम इन 142 मेटों का भुगतान कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आयेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। माननीय सदस्य, निवेदन नहीं, प्लीज। 31 मार्च तक आपको भुगतान हो जायेगा और क्या चाहते हैं आप?

अगला प्रश्न। श्रीमती सूर्यकांता व्यास।

खाद्य पदार्थों की जांच हेतु स्थापित प्रयोगशालाओं द्वारा लिए गये नमूने

228. श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच के लिए विभिन्न सरकारी प्रयोगशालाएं स्थापित हैं? यदि हां, तो उक्त प्रयोगशालाओं द्वारा विगत चार वर्षों में लिए गये नमूनों व प्राप्त रिपोर्ट का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त रिपोर्ट्स में से ऐसी कितनी रिपोर्ट्स हैं जिनमें नमूनों को अनसेफ घोषित किया गया था? उक्त अनसेफ घोषित नमूनों में से कितनों को रेफरल लैब ने अमानक घोषित कर दिया?

(3) उक्त नमूनों की प्रदेश की सरकारी प्रयोगशाला व रेफरल प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट में अन्तर आने के क्या कारण रहे? क्या सरकार उक्त के निदान के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) जी हां। राज्य खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच के लिए सरकारी प्रयोगशालाएं स्थापित हैं। सरकारी प्रयोगशालाओं में गत चार वर्षों में लिए नमूनों तथा उनसे प्राप्त रिपोर्टों का वर्षवार एवं जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त रिपोर्ट से राज्य की खाद्य प्रयोगशालाओं द्वारा अनसेफ घोषित नमूनों से रेफरल लैब में भेजे जाने पर प्राप्त रेफरल से निर्णयों अमानक एवं मानक माने गये नमूनों की वर्षवार एवं जिलेवार सूचना परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(3) खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा-46(4) में खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरुद्ध अपील संबंधित अभिहित पदाधिकारी को किये जाने के प्रावधान हैं। इन प्रावधानों के तहत संबंधित अभिहित अधिकारी द्वारा अपील किये जाने पर नमूनों की जांच अभिहित अधिकारी द्वारा रेफरल प्रयोगशाला से करवाई जा सकती है। एफएसएसएआई द्वारा राज्य के लिए मैसूर, पुणे एवं नवी मुंबई तीन रेफरल लैब नियत की गई हैं।

प्रदेश की प्रयोगशाला व रेफरल प्रयोगशाला के नतीजों में भिन्नता का मुख्य कारण अलग-अलग पैरामीटर्स पर जांच करना है एवं नमूनों की जांच के उपरान्त प्राप्त जांच परिणामों के लिए जांचकर्ता अधिकारी द्वारा अपनी राय देने के लिए प्राप्त परिणामों की व्याख्या भिन्न-भिन्न किया जाना भी एक कारण हैं।

राज्य में रेफरल लैब की स्थापना हेतु एफएसएसएआई नई दिल्ली को वर्क प्लान 2023-24 में एमओयू के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं, जो परिशिष्ट स पर संलग्न हैं।

साथ ही विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला एवं रेफरल लैब द्वारा एक ही तरह के खाद्य नमूनों के पैरामीटर पर जांच करने एवं एक तरह के नतीजे आने पर एक तरह की राय दिये जाने हेतु एक SOP जारी करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई नई दिल्ली को अर्द्ध शासकीय पत्र लिखा गया है।

(विवरण व सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। माननीय सदस्य प्रश्न पूछें आप।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

यह जानकारी चाही है कि कहां-कहां पर कितने सैम्पल लिए और उनका क्या हुआ? इन्होंने बहुत सारा पुलिन्दा तो दे दिया, लेकिन डाटा के अनुसार मुझे कुछ बात ही समझ में नहीं आ रही है।

श्री अध्यक्ष: आप क्या चाहते हो, वह पूछो आप।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह चाह रही हूं कि आपने पूरे प्रदेश का दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन किस तरीके से दिया है कि कोई जिलेवार नहीं दिया है। क्या नमूने भरे, कैसे भरे, कहां-कहां की दुकान के भरे, किसके भरे, यह इसमें कुछ नहीं है। मैं यह चाहती हूं, और कुछ नहीं तो आप सिर्फ मेरे को जोधपुर का तो बता दो कि जोधपुर में आपने कितने-कितने लिए और कहां-कहां से लिए और किस-किसके नमूने लिए और इसमें से कितने फैल हुए और कितने पास हुए? यह बता दो।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा जोधपुर से कितने लिए, मैंने जिलेवार सूची आपको दी है, आप चाहेंगे तो मैं टेबल कर दूंगा। अनसेफ के संबंध में आपका सवाल है, भारत सरकार और राज्य सरकार के पैरामीटर्स अलग-अलग हैं। हमारे यहां जो अनसेफ नमूने आते हैं, उनकी जांच वहां रेफरल से करवा सकते हैं और रेफरल की जांच हमारे यहां तीन जगह, पुणे, मुम्बई और मैसूर में होती है। अध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि यहां की जांच में और वहां की जांच में फर्क आता है। रेफरल जांच अभी हमारे स्टेट में नहीं है, हमको मैसूर, पुणे और मुम्बई में अलोट कर रखी है। वहां की जांच में और यहां की जांच में फर्क आता है, इसमें एक टेबल भी है, माननीय सदस्य ने तो सवाल नहीं पूछा। वहां रेफरल में हमने कुल 1202 अनसेफ भेजे थे, उसमें से सिर्फ 154 अनसेफ पाये गये थे। अध्यक्ष महोदय, हमने भारत सरकार को लिखा है कि हमारे यहां रेफरल लैब दी जाये। भारत सरकार और यहां के जो पैरामीटर्स हैं, हमारी लैब अलग पैरामीटर्स पर जांच करती है और वह अलग करती है, लैब सारी भारत सरकार की ही हैं।

अध्यक्ष महोदय, जब यह सवाल आया तो हमने भारत सरकार के चीफ सीईओ को पत्र लिखा है कि आप पूरे देश में एक पैरामीटर करें। हमने हमारे यहां रेफरल लैब की भी डिमांड कर रखी है। उन्होंने आश्वस्त किया है बहुत जल्दी ही राजस्थान में रेफरल लैब भी लग जायेगी।

(श्री परसादी लाल)

आप सही कह रही हैं कि यहां जोधपुर में एक कलाकंद का नमूना अनसेफ पाया गया और वहां जब वह रेफरल लैब में गया तो वह मानक हो गया। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के जो पैरामीटर्स अलग-अलग हैं, उसी के कारण यह फर्क आ रहा है। हमने भारत सरकार को भी निवेदन किया है कि पूरे देश में एक तरह के पैरामीटर्स के लिए दिशा निर्देश जारी करें।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भारत सरकार की बात करते हैं, मैं यह चाह रही हूं कि जोधपुर में आपने कितने लिए और उनमें से कितने फैल हुए और कितने पास हुए यह नहीं बताया। कौनसी दुकान के लिए, किसके लिए, दूध के लिए, मिर्च के लिए, हल्दी के लिए, नमक के लिए, किसके लिए, यह तो बताओ मेरे को। यह तो पूरे राजस्थान के मंत्री हैं, इनके पास तो सारी सूचना है, मेरे पास इतना थोड़े ही है। मैं तो जो जानती हूं वह बताती हूं। आप तीन विधान सभा क्षेत्र में से एक का तो बता दो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया, अब आप बैठें। आप बैठें, जवाब आ रहा है। आप बैठें, आपका जवाब आ रहा है।

माननीय मंत्री जी, मैं इनके साथ सप्लीमेंट्री करता हूं। मैंने खुद ने देखा है स्टेट लैब के 2019 से लगाकर जो अलग-अलग नमूने लिए हैं, कितने नमूने लिए, उतनों का रिजल्ट नहीं आया है, आप आंकड़े देख लें। स्टेट लैब में जितने नमूने ले रहे हैं, जो आपने एनेक्सचर दिया है वह 2019 से दे रखा है, मैंने 2021 का भी देखा है, 2022 का भी देखा है। जोधपुर में जितने सैम्पल स्टेट लैब में लिए हैं, स्टेट लैब के उतने सैम्पलों के बारे में भी पूरा निष्कर्ष अभी तक नहीं आया है, इसलिए माननीय सदस्य का यह प्रश्न है कि पर्टिकुलरली जोधपुर की आप डिटेल पता लगाकर माननीय सदस्य को सूचना दें कि कहां से सैम्पल लिया, किसका लिया, जिससे इनके मन में जो है, वह क्लीयर हो जाये। आप बता रहे हैं भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की लैब में अंतर है, यह एक अलग बात है, लेकिन जितने नमूने लिए, उतने नमूनों का राजस्थान स्टेट लैब का निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला है, यह मेरा प्रश्न है।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य और आपने निर्देश दिया, 2019 में जोधपुर के 21 नमूने लिए, उसमें से 14 अनसेफ निकले। सालवार मैंने विवरण दिया है। ऐसे ही 2020 का है, कुल नमूने लिए 29, इसमें से 17 अनसेफ निकले। 2021 में ....

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, मैं आपका पढ़ रहा हूं, जोधपुर में राजकीय लैब में 282 लिए, यह आपका फिगर है। इसमें 35 सबस्टेंडर्ड पाये हैं, 18 मिस ब्रांड पाये गये, 21 अनसेफ पाये गये और बाकी जीरो। कुल 282 में से आपके पास इतने ही फिगर हैं, यह 2019 का फिगर है। 2019 के 282 के संबंध में पूरा निर्णय क्यों नहीं पहुंचा?

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने सालवार विवरण में चार साल का विवरण आपको दिया है, अगर नहीं है तो मैं टेबल कर दूंगा। जो भी नमूने अनसेफ पाये गये, उन अनसेफ से कोई भी प्रभावित है तो वह रेफरल लैब में जा सकता है, उसको यह अधिकार है।

श्री अध्यक्ष: आप फिर बात नहीं समझ रहे हैं, 282 आपने लिए, 282 में तीनों फिगर मिलाकर 282 नहीं है, इसका मतलब आपने लैस दैन 75 नमूनों के बारे में ही ऐनेलेसिस किया है, बाकी के बारे में ऐनेलेसिस नहीं हुआ है।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह वर्षवार आंकड़े हैं, 2019, 2020, 2021, 2022, चारों सालों का यह आंकड़ा है। यह जोधपुर अकेले का नहीं है, सब जिलों का अलग-अलग है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं भी हैल्प कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी, आप केवल जोधपुर की डिटेल लेकर माननीय सदस्य को दे दें, फिर माननीय सदस्य अलग ढंग से इसको उठायेंगे। मैं आपकी मदद करूंगा। अगला प्रश्न।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: पब्बाराम जी, मुझे नाम तो पुकारने दो।

जोधपुर में स्वयं सहायता समूहों को भुगतान

229. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जोधपुर में विगत तीन वर्षो से स्वयं सहायता समूह को किस-किस स्थान पर व कितने समय से तथा किस-किस कार्य हेतु राशि दी जानी शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बकाया राशि का भुगतान कितनी अवधि में कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

मैं सीधा प्रश्न ही पूछ लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: पूछ लें आप।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पत्र किसी और पते पर डाला था और पहुंच गया और किसी पते पर। यह दुर्भाग्य है, पता नहीं किस लेवल पर गलती हुई, डाकिये की गलती हुई है या भगवान जाने। यह स्वयं सहायता समूह दोनों विभागों में है, ग्रामीण विकास में भी है और महिला और बाल विकास में भी है। मैंने ऊपर सीधा-सा महिला और बाल विकास मंत्रालय लिखा है और जवाब मेरे को आ रहा है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, असेंबली सैक्रेटेरिएट के बारे में प्रश्न नहीं पूछते हैं।

श्री पब्बाराम (फलौदी): मेरा पत्र सही जगह कब पहुंच जायेगा और कब मेरे को जवाब मिल जायेगा? उस जवाब का मैं इंतजार करूंगा, यही मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न स्थगित किया गया।

(स्थगित)

अगला प्रश्न। श्री सुभाष पूनिया।

सूरजगढ़ की अनुपयुक्त सड़कों का पुनर्निर्माण

230. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में कौनसे सड़क मार्ग मरम्मत के लिए उपयुक्त नहीं हैं व कितने गांव सम्पर्क सड़क से वंचित हैं तथा उक्त मार्गों की लम्बाई कितनी है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) माह जनवरी, 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक उक्त विधान सभा क्षेत्र में मरम्मत के लिए अनुपयुक्त कौन-कौनसे सड़क मार्गों का पुनर्निर्माण करवाया गया है? उक्त सड़कों की लम्बाई कितनी है व उक्त पर कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में उक्त विधान सभा क्षेत्र में सम्पर्क विहीन (मिसिंग लिंक) सड़क योजना में किन-किन मार्गों का निर्माण करवाया गया व उक्त पर कितना व्यय हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भजनलाल जाटव): (1) विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में वर्तमान में 34 सड़कों की 133.85 किलोमीटर लम्बाई पेच

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

मरम्मत के लिए उपयुक्त नहीं (नोन पेचेबल) है, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर एवं 2 गांव सड़क सम्पर्क से वंचित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(2) माह जनवरी, 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में मरम्मत के लिए अनुपयुक्त (नोन पेचेबल) सड़कों में से 205.50 किलोमीटर लम्बाई की स्वीकृति जारी कर 61.52 किलोमीटर सड़क मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया गया है। शेष कार्य प्रगति पर है, जिनका विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(3) वर्ष जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2022 तक विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में विभिन्न सड़क योजनाओं में निर्मित एवं प्रगतिरत मिसिंग लिंक सड़कों का विवरण मय व्यय राशि परिशिष्ट-4 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): अध्यक्ष जी, जवाब आ गया है। मैं प्रश्न पूछ रहा है। अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में नोन-पेचेबल की जो सड़कें शेष रही हैं, उनको कब तक बनाने का विचार मंत्री जी रख रहे हैं? यदि नहीं बनायेंगे तो क्यों और बना रहे हैं तो कब तक बनायेंगे?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जब 10-10 करोड़ की सड़कें दी गयी थीं, यहां विधान सभा के बजट में घोषणा हुई थी, किनकी अनुशंसा से वे सड़कें पिछले बजट में बनी हैं और इस बार से किनकी अनुशंसा से ली जा रही हैं? अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाह रहा हूं। क्या विधायकों की अनुशंसा लेंगे या नहीं?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न के सम्बन्ध में सप्लीमेंट्री पूछें। आपने जो प्रश्न पूछा है, उसके बारे में सप्लीमेंट्री पूछें। एमएलए की रिकमंडेशन, आपका यह प्रश्न नहीं है।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): मैंने नोन-पेचेबल के लिए पूछा है।

श्री अध्यक्ष: आप पूछो, अपनी बात को पूछो। आप एमएलए फंड की बात क्यों कर रहे हैं? आप सड़क का नाम बोलो।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): हुक्म, मैंने नोन-पेचेबल के लिए पूछ लिया है।

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है कि नोन-पेचेबल सड़कें कब तक पूर्ण

(श्री भजनलाल जाटव)

हो जायेंगी। जिस संवेदक ने वह काम लेट किया है, उसको हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया है और उसकी दुबारा से एनआईटी लगा दी है और उसकी पुन: 15.03.2023 को दुबारा से एनआईटी खुल जायेगी, उसके बाद काम शुरू कर दिया जायेगा।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): यह जो एमएलए के 10 करोड़ की सड़कें हैं, उसके लिए संरक्षण चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: अब हो गया। अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 231

श्रीमती मीना कंवर।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री बाबुलाल।

जनजाति के मेधावी छात्रों की कोचिंग की कार्ययोजना

232. श्री बाबुलाल (झाडोल): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विभाग जनजाति के मेधावी बच्चों की कोचिंग की व्यवस्था करता है? यदि हां, तो विगत चार वर्षों में कितने बच्चों को कहां-कहां, कौनसी कोचिंग करायी गयी? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): जी हां। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ टीआरआई संस्थान के माध्यम से जनजाति के मेधावी बच्चों की कोचिंग करायी जाती है। विगत चार वर्ष से 2019-20 से 2022-23 तक संस्थान के माध्यम से जनजाति विद्यार्थियों को निःशुल्क करायी गयी कोचिंग का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बाबुलाल (झाडोल): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा, आपसे मैंने चार वर्षों की सूचना मांगी थी, उसमें से आपने 2019-20 में स्कूल व्याख्याताओं में 60 है, प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु फाउण्डेशन कोर्स में 39 है और पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III में 32, कांस्टेबल भर्ती के 166, चिकित्सा एवं तकनीकी अध्ययन में 386 है। ये संख्या 683 के लगभग है।

श्री अध्यक्ष: यह तो आ गया है, आप प्रश्न पूछें।

श्री बाबुलाल (झाडोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संख्या मिलाकर 1550 के आसपास जाती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने आवेदन आये और आवेदन आये तो उनमें पात्रता क्या थी, जो आपने इतने ही लड़के कोचिंग के योग्य माने हैं? मेरा आपसे दूसरा सवाल यह है कि यह जो संख्या 1500 से पार जाती है, इनमें से कितने लड़के कोचिंग के बाद परीक्षा देकर पास हुए और कितने अब तक नौकरी में लग गये? यह बतायें।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बच्चे आवेदन करते हैं, उन सभी के लिए जाते हैं। कोचिंग के बाद में जो-जो बच्चे सलेक्ट होकर जाते हैं, उनके आंकड़े मैं लेकर अलग से दे दूंगा।

श्री बाबुलाल (झाडोल): अध्यक्ष जी, यह जानकारी पूरी नहीं है तो कब देंगे क्योंकि यह जो जनजाति सब-प्लान है, उसमें बहुत बड़ा एरिया है। क्या इसमें इतने ही लड़के आये थे? मैंने यह जानकारी चाही थी।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया है कि जिन बच्चों ने आवेदन किया, वे सारे बच्चे कोचिंग के लिए सलेक्ट हो गये। उसके अलावा भी हमने और 200 बच्चों की अलग से व्यवस्था करके नीट की कोचिंग करवायी है। उसके बाद की जो व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का यह प्रश्न है कि आपने स्कूल व्याख्याता, फाउण्डेशन में अंग्रेजी के, पुस्तकालयाध्यक्ष के जो एप्लिकेंट्स हैं, क्या इनकी संख्या उतनी है, जितनी कि आये हैं। इनका यह प्रश्न है कि क्या इतने ही लोगों ने एप्लिकेशन दी है?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): सर, जिन्होंने एप्लाई किया, वे सारे आ गये।

श्री अध्यक्ष: क्या आपके पास इसके अलावा ज्यादा जानकारी है?

श्री बाबुलाल (झाडोल): मेरी जानकारी तो नहीं है इसीलिए मैं मंत्री जी से पूछकर जानकारी चाह रहा था। इस जनजाति सब-प्लान में इतना बड़ा एरिया है। अध्यक्ष महोदय जी, इतना बड़ा क्षेत्र है, उसके बाद में क्या इतने ही लड़के आये? इसके पीछे कारण क्या है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, इनका प्रश्न बहुत वैलिड है। ट्राइबल सब-प्लान में इतने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। वहां कालेज भी है, ये भी हैं। क्या विभाग ज्यादा आदमियों को कोचिंग के लिए मोटिवेट करने के लिए कोई प्रयास कर रहा है या नहीं कर रहा है? यह उनका मोटा प्रश्न है।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): इसके प्रयास किये जा रहे हैं। इसके बावजूद आपके निर्देशानुसार आगे और प्रयास करेंगे। यह सारी कोचिंग व्यवस्था अब समाज कल्याण विभाग से गयी है और उसमें भी हमारी संख्या ज्यादा है और उसके प्रचार-प्रसार की व्यवस्था पूरी तरह से करेंगे।

श्री अध्यक्ष: मैं उसी इलाके से हूं। आपके पास जब तक यह आंकड़ा नहीं है, कोचिंग से कितने आदमी सक्सेस होकर नौकरी में आ रहे हैं, वे लोग जब स्कूल में जायेंगे, तब तक लोग मोटिवेट नहीं होंगे। क्या कोचिंग के बाद जो लोग सलेक्ट हो रहे हैं, उन बच्चों को उन स्कूलों में भेजकर स्वागत करायेंगे, जिससे बच्चे मोटिवेट हो सकें कि कोचिंग के कारण नौकरी में आ रहे हैं।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि हम आपके निर्देशानुसार पालना करेंगे। पर, मैं आपको दूसरा निवेदन कर रहा हूं कि माननीय सदस्य की पीड़ा बिलकुल सही है। एक बच्चा माननीय विधायक महोदय के वहां से था, जो कि गरीब बच्चा था, उसने आई.ए.एस. की प्री परीक्षा पास कर ली और मुझे जैसे ही सूचना मिली, मैंने उसको मोटिवेट किया। उस बच्चे ने मेन एग्जाम के लिए एप्लाई नहीं किया। इस तरह की भी कमियां हैं, तो विभाग द्वारा आने वाले समय में पूरा प्रचार-प्रसार करेंगे।

श्री बाबुलाल (झाडोल): अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र का बच्चा है, उसकी कोचिंग के लिए कलेक्टर ने रिकमंड किया। आपने कहा होगा, इसके लिए धन्यवाद। वह बच्चा मेरे वहां पर रह रहा है और मेन एग्जाम क्लियर करके इंटरव्यू देकर आया है। उनकी कोचिंग के लिए रहने की सुविधा भी आपकी है, तो कितने लड़कों को सुविधा दी? वह लड़का मेरे वहां पर रहकर अध्ययन कर रहा है। बतायें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, बहस करने का नहीं है। माननीय सदस्य की जो चिन्ता है, उससे अपने आप को एड्रेस करके और ज्यादा किस तरीके से पोपुलर करेंगे, उसके बारे में प्रयत्न करें।

अगला प्रश्न। श्री पानाचन्द मेघवाल।

होम गार्ड्स को वर्ष भर रोजगार देने की योजना

233. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बजट में बारह हजार होम गार्ड की भर्ती करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त घोषणा को समय पर पूरा नहीं होने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा विगत चार वर्षों में कितने होम गार्ड की भर्ती की गयी? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार होम गार्ड रूल्स एक्ट, 1962-63 में संशोधन कर उक्त होम गार्ड को नियमित कर वर्ष भर रोजगार देने व ईएसआई, पीएफ, डीए व निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह गलत परम्परा है।

राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा (श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा): (1) जी नहीं। बजट में बारह हजार होम गार्ड भर्ती करने की कोई भी घोषणा नहीं की गई है।

(2) होम गार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती नहीं की जाती है, केवल इनका नामांकन किया जाता है। विगत 04 वर्षों में किये गये नामांकन का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वर्ष	नामांकन हेतु रिक्त पदों की संख्या	किये गये नामांकन की संख्या
1	2018-19	0	0
2	2019-20	0	0
3	2020-21	0	0
4	2021-22	2500	851 (उपरोक्त नामांकन प्रक्रिया वर्ष 2022 में पूर्ण की गई जिसमें चयन योग्य पाये गये।)

(3) जी नहीं। स्वयंसेवकों को नियमित करने हेतु, होम गार्ड रूल्स एक्ट 1962-63 के तहत संशोधन हेतु कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

होम गार्ड एक्ट 1963 की धारा 2 के तहत होम गार्ड को नियमित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा)

होम गार्ड स्वयंसेवकों को ईएसआई, पीएफ, डीए (महंगाई भत्ता) दिये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

होम गार्ड स्वयं सेवकों को निःशुल्क चिकित्सा सेवा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रदान की जा रही है।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, अभी हाल की बजट घोषणा में माननीय मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान कांट्रेक्ट सिविल रूल, 2022 की घोषणा की है। क्या सरकार होम गार्ड को भी इन नियमों में शामिल करने का विचार रखती है? साथ ही, नियमों में संशोधन कर होम गार्ड को ई.एस.आई. और पी.एफ. की सुविधाओं का लाभ देने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: मना कर दिया न।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण): नहीं रखते हैं और न ही हमने भर्ती की घोषणा की है। हमने तो एक बार 12 हजार ड्यूटी देने की घोषणा की थी। जब कोई डिपार्टमेंट हमसे मांगेगा तो हम उनको दे देंगे। होम गार्ड, कर्मचारी नहीं हैं। होम गार्ड स्वयंसेवक हैं और उनको कर्मचारियों के समान कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है। जो चिरंजीवी स्वास्थ्य सुविधा जनता को दी जाती है, वही दी जाती है। इनको ऐसा कुछ नहीं है। आपका प्रश्न गलत है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। रामलाल शर्मा।

जयपुर में शराब की अधिकृत दुकानें

234. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में शराब नीति बनी हुई है? क्या यह भी सही है कि जिला जयपुर में वर्ष 2018 से 2022 के मध्य शराब की दुकानों में वृद्धि की गई है? यदि हां, तो किस-किस विधान सभा क्षेत्र में दुकानों में वृद्धि की गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि शराब की बिक्री रात्रि आठ बजे के बाद निषेध है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त समय के बाद बिक्री को रोकने हेतु क्या-क्या आवश्यक कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा अधिकृत दुकान के

(श्री रामलाल शर्मा)

अतिरिक्त भी जिला जयपुर में ब्रांच खोलकर शराब की बिक्री की जा रही है? यदि हां, तो अब तक जिला जयपुर में कितनी ऐसी ब्रांचों पर कार्रवाई की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

आबकारी मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) राज्य सरकार द्वारा आबकारी एवं मद्यसंयम नीति जारी की जाती है। वर्तमान में आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 प्रभावी है। जिला जयपुर में वर्ष 2018-19 से 2022 के मध्य शराब की दुकानों में वृद्धि नहीं की गयी है। विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। निर्धारित समय के बाद स्वीकृतशुदा दुकानों से मदिरा की बिक्री को रोकने हेतु विभाग द्वारा नियमित रूप से रेड गश्त करायी जा कर सतत निगरानी रखी जाती है। वर्ष 2022-23 में माह जनवरी, 2023 तक निर्धारित समय रात्रि 8.00 बजे पश्चात् मदिरा विक्रय पाये जाने पर जिला जयपुर में मदिरा अनुज्ञाधारियों के विरुद्ध कुल 26 अभियोग पंजीकृत किये गये हैं।

(3) जी नही। जयपुर जिले में सरकार द्वारा स्वीकृत मदिरा दुकानों के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान से मदिरा की अवैध बिक्री नहीं की जा रही है।

स्वीकृतशुदा मदिरा दुकानों के अतिरिक्त कहीं पर भी मदिरा का अवैध विक्रय/संग्रहण/निर्माण/परिवहन आदि पाये जाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

अवैध मदिरा के संग्रहण, निर्माण, विक्रय, भण्डारण के वर्ष 2022-23 के दौरान माह जनवरी, 2023 तक आबकारी जिला जयपुर के आबकारी वृत्तों/थानों में कुल 1245 अभियोग पंजीकृत किये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। रामलाल जी प्रश्न पूछिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जयपुर जिले के अंदर जो आपके आबकारी के नियम हैं कि हम मंदिर के पास दुकान नहीं खोलेंगे, इतने मीटर दूरी छोड़ेंगे, कितनी शिकायतें आपको जयपुर जिले के अंदर मिलीं इस तरीके की और कितनी शिकायतों का आपने निस्तारण किया?

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा, उस संबंध में कोई शिकायत विभाग को अब तक नहीं मिली है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक जानकारी मंत्री महोदय से मैं और जानना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान के अंदर, अध्यक्ष महोदय, आपने भी देखा होगा, किस तरीके से 100 मीटर की दूरी एनएच से छोड़कर फिर दुकानें आबंटन करने की प्रक्रिया है। आज भी एनएच की 100 मीटर की दूरी की पालना कहीं पर भी नहीं हो रही है। मेरी विधान सभा के अंदर भी नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या शिकायत आने के उपरांत उनके ऊपर आप कार्यवाही करने का विचार रखते हैं?

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कोई शिकायत नहीं आयी, मैंने आपको कहा। शिकायत आएगी तो निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बिहारीलाल।

मुकाम (बीकानेर) के पशु उप केन्द्र का प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नयन

235. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार पशु उप केन्द्र मुकाम को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पशुपालन मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): जी हां। बजट घोषणा 2023-24 के बिन्दु संख्या 187 अनुसार पशु चिकित्सा उप केन्द्र, मुकाम को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है।

पशु चिकित्सा संस्थायें आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार क्रमोन्नत की जाती हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। आपका काम हो गया है।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि वहां जिले की सबसे बड़ी गौशाला है। प्रदेश का सबसे बड़ा रेस्क्यू सेंटर है। समाज ने दो करोड़ रुपये से बनाया है।

श्री अध्यक्ष: अभी तो उप केन्द्र खुल रहा है। आप आगे तक कहां जा रहे हैं?

श्री बिहारीलाल (नोखा): उस चिकित्सालय को ए ग्रेड का, माननीय मंत्री जी, करने का प्रस्ताव करें।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, अभी उप केन्द्र ही नहीं हुआ और ए ग्रेड में जा रहे हैं।

श्री बिहारीलाल (नोखा): 70 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं, उनको भरने का काम करें।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए, प्लीज। आपका प्रश्न बहुत लिमिटेड है। उप केन्द्र का है और वह खोल रहे हैं। अब खोल रहे हैं तो आप ए ग्रेड में जा रहे हो।

अगला प्रश्न। श्री रामकेश।

गंगापुर में जे.जे.एम. योजना से वंचित ग्राम

236. श्री रामकेश (गंगापुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगापुर के कितने ग्रामों को जेजेएम योजना से जोड़ा जा चुका है तथा शेष ग्रामों को कब तक जोड़ दिया जाएगा? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जहां पानी का स्थायी स्रोत नहीं है, वहां चम्बल परियोजना से ग्रामों को जोड़ने की कार्ययोजना है? यदि हां, तो उक्त को कब तक जोड़ दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जेजेएम एवं अमृत योजना से शेष बचे क्षेत्र व गंगापुर शहर में कब तक पानी उपलब्ध करवा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. महेश जोशी): (1) विधान सभा क्षेत्र गंगापुर के कुल 119 ग्रामों में से 92 ग्रामों को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत लाभान्वित करने हेतु 68 अन्य योजनाओं (वृहद परियोजनाओं के अतिरिक्त) की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.एस.सी.) की विभिन्न बैठकों द्वारा जारी की जा चुकी है। इन 68 योजनाओं में से 28 योजनायें पूर्ण कर 33 ग्रामों को जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा चुका है। शेष 40 योजनाओं में से 12 योजनाओं (13 ग्राम) का कार्य प्रगतिरत है एवं 26 योजनाओं (44 ग्राम) हेतु निविदायें प्रक्रियाधीन हैं।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

02 योजनाओं यथा ग्राम कड़ी झोपड़ी का जल स्रोत असफल (सूखा) होने के कारण एवं ग्राम नौगांव में ग्रामवासियों के विवाद के कारण योजनाओं का कार्य नहीं हो पाया है। विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

स्वीकृति से शेष रहे 27 ग्रामों में भूजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने के कारण इन ग्रामों को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सतही जल स्रोत चम्बल नदी पर आधारित करौली एवं सवाई माधोपुर जिले के 1426 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने की वृहद पेयजल परियोजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त वृहद पेयजल परियोजना के अन्तर्गत इन 27 गांवों को घर-घर कनेक्शन के माध्यम से लाभान्वित करने के लिए आवश्यक कार्यों सहित विधान सभा क्षेत्र के समस्त 119 गांवों की जल मांग तथा शहरी क्षेत्र गंगापुर सिटी सहित सवाई माधोपुर जिले के 579 ग्रामों एवं करौली जिले के समस्त 847 ग्रामों (कुल 1426 गांव एवं 06 शहर) को लाभान्वित करने के लिए राशि रु. 4657.37 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.एस.सी.) की 36वीं बैठक दिनांक 29.12.2022 में प्रस्तुत की गई। बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार वर्तमान में परियोजना के प्रस्ताव राष्ट्रीय जल जीवन मिशन भारत सरकार नई दिल्ली के स्तर पर तकनीकी परीक्षण हेतु प्रक्रियाधीन है। परियोजना की स्वीकृति के उपरान्त बजट उपलब्धता के आधार पर योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।

(2) जी हां। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सतही जल स्रोत चम्बल नदी पर आधारित करौली एवं सवाई माधोपुर जिले के 1,426 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने की वृहद पेयजल परियोजना के अन्तर्गत गंगापुर विधान सभा क्षेत्र के समस्त 119 गांवों एवं गंगापुर शहर की जल मांग को सम्मिलित करते हुए राशि रु. 4,657.37 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.एस.सी.) की 36वीं बैठक दिनांक 29.12.2022 में प्रस्तुत की गई। बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार वर्तमान में परियोजना के प्रस्ताव राष्ट्रीय जल जीवन मिशन भारत सरकार नई दिल्ली के स्तर पर तकनीकी परीक्षण हेतु प्रक्रियाधीन है। परियोजना की स्वीकृति के उपरान्त बजट उपलब्धता के आधार पर योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।

(3) गंगापुर शहर के विभागीय योजनाओं से अलाभान्वित क्षेत्रों को

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

पेयजल सुविधा से लाभान्वित करने के लिए अमृत 2.0 योजना के अन्तर्गत राशि रुपये 40.33 करोड़ के प्रस्तावों का राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एसएचपीएससी) की अभिशंसा पर आवासन एवं शहरी कार्यालय मंत्रालय, भारत सरकार की अमृत योजना की एपेक्स कमेटी की बैठक दिनांक 04.01.2023 में अनुमोदन किया गया। रूडसिको के पत्रांक 1078 दिनांक 06.02.2023 द्वारा गंगापुर शहर में पेयजल के कार्य हेतु राशि रुपये 40.33 करोड़ के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है। योजना के तकनीकी प्रस्ताव बनाने का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गंगापुर के कुल 119 ग्रामों में से 92 ग्रामों को लाभान्वित करने हेतु 68 अन्य योजनाओं (वृहद परियोजनाओं के अतिरिक्त) की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। शेष 27 ग्रामों को (मय आंतरिक वितरण तंत्र) सतही जल स्रोत चम्बल नदी पर आधारित करौली एवं सवाई माधोपुर जिले के 1,426 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने की वृहद पेयजल परियोजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत, शहरी क्षेत्र गंगापुर सिटी एवं विधान सभा क्षेत्र गंगापुर के सभी 119 ग्रामों की जल मांग को शामिल करते हुएं चम्बल नदी पर आधारित करौली एवं सवाई माधोपुर जिले के 1,426 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने की वृहद पेयजल परियोजना की राशि रु. 4,657.37 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.एस.सी.) की 36वीं बैठक दिनांक 29.12.2022 में प्रस्तुत की गई। बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार वर्तमान में परियोजना के प्रस्ताव राष्ट्रीय जल जीवन मिशन भारत सरकार नई दिल्ली के स्तर पर तकनीकी परीक्षण हेतु प्रक्रियाधीन है। परियोजना की स्वीकृति के उपरान्त बजट उपलब्धता के आधार पर योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: उत्तर पढ़ा हुआ मान लिया। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका लगभग मुझे जवाब मिल गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट

(श्री रामकेश)

घोषणा में 1,426 गांवों के लिए पेयजल योजना की घोषणा की है। मैं माननीय मंत्री जी से केवल एक सवाल पूछ रहा हूं कि आपके द्वारा जो 15 करोड़ रुपये अतिरिक्त पेयजल के लिए मेरे गंगापुर शहर को और 109 गांवों को अतिरिक्त व्यवस्था के लिए मैंने जो मांग की थी, केवल माननीय मंत्री जी यह बता दें इसको आप कब तक पूरा कर देंगे?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 15 करोड़ वाला जो मुद्दा माननीय विधायक ने पूछा है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि हम लोगों ने 15 करोड़ 46 लाख रुपये का प्रस्ताव बनाकर बजट के लिए भेजा था और बजट में इसकी घोषणा हो चुकी है। जो प्रक्रिया में समय लगेगा, उस समय के अलावा हम कोई अतिरिक्त समय नहीं लेंगे। जल्दी से जल्दी इसको हम पूरा करायेंगे।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय मंत्री जी, ये आशंका थोड़ी मुझे इसलिए है कि एसपीएमएल का जो प्रोजेक्ट है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए। आशंका नहीं, प्रश्न पूछिए आप।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, वही बात कहना चाह रहा हूं कि उसमें पहले ही गंगापुर शहर बहुत लंबे टाइम से पेयजल की समस्या भुगत रहा है। 2005 की स्कीम 2023 तक पूरी नहीं हुई। मैंने छोटी-सी मांग की है। प्रक्रिया कब तक पूरी कर लेंगे और अगर समय भी आप नहीं बता पाएं तो मेरा इतना-सा अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को पूरा कर दें। इस गर्मी में गंगापुर शहर को पेयजल उपलब्ध हो जाए, यह मेरी मांग है।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी तरफ से कोई देरी इसके अंदर नहीं होगी। मैं एप्रिशिएट भी करता हूं कि माननीय सदस्य अपने विधान सभा क्षेत्र में पेयजल को लेकर इतने चिंतित है। मुझसे भी कई बार मिले हैं, मुख्य मंत्री जी से भी मिले हैं, लेकिन जो सिस्टम है, उस सिस्टम के बाहर जाना सम्भव नहीं हो पाता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कि हम यथाशीघ्र इस काम को कराने की हरसम्भव कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री नरेन्द्र नागर।

बारां की ग्राम पंचायतों में गौशालाएं खोलने की कार्ययोजना

237. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) (श्री प्रताप सिंह (छबड़ा) के स्थान पर): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि माह जनवरी, 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक जिला बारां में गौशालाओं के लिए राशि व्यय की गई है? यदि हां, तो कौन-कौनसी गौशालाओं हेतु कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार गौवंश के संरक्षण के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर गौशालाएं खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

गोपालन मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) बारां जिले की पात्र गौशालाओं को जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2022 तक दी गई सहायता राशि का गौशालावार एवं पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। बजट वर्ष 2022-23 में जिन ग्राम पंचायतों में गौशाला/पशु आश्रय स्थल का संचालन करने के लिए सक्षम एनजीओ उपलब्ध होंगे वहां प्राथमिकता से 1-1 करोड़ रुपये तक की राशि से गौशाला स्थापित की जाएगी। घोषणा की गई है।

बजट घोषणा अनुरूप गौशाला/पशु आश्रय स्थल स्थापित करने हेतु ग्राम पंचायत गौशाला/पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना दिनांक 15.01.2023 को अनुमोदित कर दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं जो परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 200 ग्राम पंचायत गौशाला/गौ आश्रय स्थल के लिए राशि रु. 183.60 करोड़ प्रावधित है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चार सप्लीमेंट्री दो बार में पूछ लेता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि बारां जिले में कौन-कौन-सी तहसीलों में कहां-कहां पर गौशालाएं संचालित हो रही हैं? दूसरा, बारां जिले में संचालित गौशालाओं में जनवरी 2019 से दिसम्बर 2022 तक सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदान बकाया हैं? यदि हां, तो कौन-कौन-सी गौशालाओं का कितना-कितना अनुदान बकाया है? बकाया अनुदान कब तक दे दिया जाएगा?

श्री अध्यक्ष: ये चार नये क्वेश्चन एड करेंगे। माननीय मंत्री जी, बी ब्रीफ।

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य जी ने जो बारां जिले की गौशालाओं की संख्या के बारे में जानकारी चाही है, बारां जिले में कुल 44 गौशालाएं संचालित हैं। 25 गौशालाएं गो निधि नियमों के अनुरूप अनुदान की पात्र में आती हैं, 19 गौशालाएं ऐसी हैं जो अनुदान की पात्रता नहीं रखती हैं। मुख्य कारण दो वर्ष के शुरू में 100 से कम गोवंश का पाया जाना और उनका एक वर्ष से कम संचालन होना।

साथ ही 44 गौशालाओं का तहसीलवार विवरण जो चाहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, अंता तहसील में 3, मांगरोल तहसील में 4, अटरू तहसील में 6, बारां तहसील में 7, छबड़ा तहसील में 5, छीपाबड़ौद तहसील में 11, किशनगंज तहसील में 4, शाहबाद तहसील में 4, कुल 44 गौशालाएं संचालित हैं। साथ ही जो अनुदान के बारे में जानकारी चाही है, माननीय अध्यक्ष जी, दिसम्बर, 2022 तक सरकार द्वारा दिये गये अनुदान में बारां जिले की किसी भी गौशाला का कोई एक रुपया अनुदान बाकी नहीं है।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या बारां जिले में उक्त अवधि में गो वंश संरक्षण के लिए काऊ सेस के माध्यम से राशि प्राप्त हुई है? यदि हां, तो प्राप्त राशि में से किन-किन गौशालाओं में कितना हुआ?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज, हो गया।

अगला प्रश्न। श्री कैलाश चन्द्र जी मेघवाल।

भीलवाड़ा में आपणी योजना-आपणो विकास

238. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या ग्राम पंचायतों के समग्र विकास के लिए लोक केंद्रित मुख्य आकर्षण न्यूनतम कब्जा कतरों की जांच के लिए आपणी योजना आपणो विकास के तहत पंचायत के लाभों में हस्तान्तरित की जाती है? यदि हां, तो जिला भीलवाड़ा की कौन-कौनसी ग्राम पंचायत को कौन-कौनसे कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में हस्तान्तरित कर दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ग्राम पंचायतों को प्राप्त राशि का प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों व अब शेष रही ग्राम पंचायतों को कब तक जारी कर दिया जायेगा?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री) (पंचायती राज मंत्री के स्थान पर): (1) 14वां वित्त आयोग (2015 से 2020) द्वारा ग्राम पंचायतों के विकास हेतु राशि का हस्तांतरण करने के उद्देश्य से जारी दिशा-निर्देशों एवं मार्गदर्शिका को "आपणी योजना आपणो विकास" के नाम से संचालित किया गया था। यह कोई वित्तीय योजना नहीं थी। चूंकि अब वर्तमान में 15वां वित्त आयोग वित्तीय वर्ष 2020-21 से चल रहा है। इसलिए वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपणी योजना आपणो विकास के तहत भीलवाड़ा जिले में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई है।

(2) उपरोक्तानुसार सूचना शून्य है।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें पूरक प्रश्न की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, मान लिया।

अगला प्रश्न। श्री संजय शर्मा।

अलवर के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में रिक्त पद

239. श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): क्या उपभोक्ता मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अलवर में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष का पद लगभग डेढ़ वर्ष से रिक्त है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त आयोग के अध्यक्ष के पद सहित अन्य रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उपभोक्ता मामलात मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अलवर में अध्यक्ष का पद दिनांक 04.07.2021 से रिक्त है। अध्यक्ष, जिला आयोग, अलवर का दिनांक 03.07.2021 को कार्यकाल पूर्ण हो जाने के कारण उक्त पद रिक्त है।

(2) विभिन्न जिला आयोगों में रिक्त अध्यक्ष/सदस्यों के पदों (जिसमें अध्यक्ष, जिला आयोग, अलवर भी शामिल है) को भरे जाने हेतु दिनांक 17.08.2022 को विज्ञप्ति जारी कर अभ्यर्थियों के साक्षात्कार दिनांक 10.10.2022 से 12.10.2022 तक लिए जा चुके हैं तथा नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने खुद ने स्वीकार किया है कि अलवर में यह पद 19 माह से रिक्त है, चार हजार केस लम्बित हैं। साक्षात्कार हुए भी तीन माह से अधिक हो चुके हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि ये रिक्त पद कब तक भर दिया जायेगा, किस समय सीमा के अंदर?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): रिक्त पद की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है, जल्दी से जल्दी भर दिया जायेगा। कभी भी घोषणा हो सकती है। आपको ये जानकारी भी होगी कि अलवर में दौसा के अध्यक्ष हर थर्ड वीक को जाकर बैठते हैं। भीलवाड़ा के अध्यक्ष हर फोर्थ वीक को जाकर बैठ रहे हैं। कार्यवाही वहां जारी है। लेकिन यह जो प्रक्रियाधीन है, ये जल्दी से जल्दी पूरा कर दिया जायेगा।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 हजार से अधिक केस लम्बित हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा, क्या राज्य सरकार वहां दूसरा उपभोक्ता मंच न्यायालय खोलने की मंशा रखती है?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 4 हजार से ज्यादा केस पेंडिग हैं। आप अलवर के विधायक हैं, आप यदि चाहते हैं कि वहां अलग से कोर्ट होना चाहिए, आप लिखकर दें। हर विधायक की भावना का सम्मान किया जाएगा।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

किसानों की कर्ज माफी

240. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जन घोषणा-पत्र में प्रदेश के किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो अब तक कितने किसानों की कर्ज माफी की गई? किस-किस श्रेणी के व किस-किस प्रकार का कर्ज माफ किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कामर्शियल बैंकों से जुड़े किसान वर्तमान में भी कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

(3) क्या यह भी सही है कि विगत तीन वर्षों में कर्जा नहीं चुकाने के कारण कई किसानों की ज़मीनें सरकारी आदेशों से नीलाम हुई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में उप खण्ड अधिकारी के आदेशों से हुई उक्त नीलामी से ली गई जमीनों को पुन: किसानों को लौटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

आयोजना मंत्री (श्रीमती ममता भूपेश): (1) जी हां। प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी हेतु सरकार द्वारा कृषक ऋण माफी आदेश क्रमांक प17(15) सह/2018, दिनांक 19.12.2018 जारी किया। (परिशिष्ट-1)

उक्त आदेश की क्रियान्विति हेतु कैबिनेट के निर्णय दिनांक 29.12.2018 की पालनार्थ मंत्रिमण्डल सचिवालय के आदेश दिनांक 01.01.2019 द्वारा मंत्रीगण की एक समिति का गठन किया गया।

समिति द्वारा समस्त पहलुओं पर विचार-विमर्श कर यह अनुशंसा की:- राष्ट्रीकृत बैंक, शिड्यूल्ड बैंक तथा आर.आर.बी. से जुड़े कृषक, जो आर्थिक रूप से संकटग्रस्त हैं और अपना अल्पकालीन फसली ऋण नहीं चुका पा रहे, उनका दिनांक 30.11.2018 की स्थिति में 02 लाख रुपये की सीमा तक का अल्पकालीन फसली ऋण, जो एन.पी.ए. हो गया है, को माफ करने के लिए बैंकों से परामर्श कर One Time Settlement (OTS) Scheme लायी जावे।

समिति की अनुशंसा के निर्णय की क्रियान्विति हेतु सहकारिता तथा आयोजना विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।

सरकार द्वारा दिनांक 31.12.2022 तक राज्य के सहकारी बैंकों की राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2018 (अल्पकालीन) के तहत 7 हजार 5 सौ 71 करोड़ 83 लाख (7571.83 करोड़) रुपये एवं राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019 (अल्पकालीन) के तहत 20 लाख 77 हजार (20.77 लाख) कृषकों (लघु, सीमांत एवं अन्य) का 7 हजार 8 सौ 55 करोड़ 32 लाख (7,855.32 करोड़) रुपये सहित कुल 15 हजार 4 सौ 27 करोड़ 15 लाख (15,427.15 करोड़) रुपये का अल्पकालीन ऋण माफ किया है।

इसके अतिरिक्त राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019 (मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन) के तहत 32 हजार 7 सौ 34 (32,734) लघु एवं सीमांत किसानों का 3 सौ 65 करोड़ 10 लाख (365.10 करोड़) रुपये का कर्ज माफ किया गया।

(आयोजना मंत्री)

राज्य सरकार के ऋण माफी आदेश दिनांक 19.12.2018 की पालनार्थ दिनांक 30.11.2018 को राष्ट्रीयकृत, अनुसूचित एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋणी 3,49,257 कृषकों की गैर निष्पादित परिसम्पत्ति (चूक कर्ता किसानों की डिफाल्टर ऋण राशि) NPA राशि 6 हजार 18 करोड़ 93 लाख (6,018.93 करोड़) रुपये है। उक्त में से 02 लाख तक की पात्रतानुसार 3 लाख 49 हजार 2 सौ 57 (3,49,257) कृषकों की राशि 5 हजार 6 सौ 38 करोड़ 47 लाख (5,638.47 करोड़) रुपये है। SLBC के अनुसार दिनांक 30.11.2018 के पश्चात दिनांक 31.10.2022 तक 2 लाख 50 हजार 7 सौ 73 (2,50,773) कृषकों की NPA राशि 4 हजार 1 सौ 82 करोड़ 4 लाख (4,182.04 करोड़) रुपये को सम्बन्धित बैंकों द्वारा repaid/upgraded कर दिया गया है। वर्तमान में 95 हजार 6 सौ 29 (95,629) कृषकों की (चूक कर्ता किसानों की डिफाल्टर ऋण राशि) NPA राशि 1 हजार 8 सौ 19 करोड़ 10 लाख (1,819.10 करोड़) रुपये का NPA लम्बित है।

इसी क्रम में राष्ट्रीयकृत बैंक, शिड्यूल्ड बैंक तथा आर.आर.बी. से जुड़े कृषकों की ऋण माफी हेतु माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान ने माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार को दिनांक 15.06.2019 तथा माननीय प्रधान मंत्री, भारत सरकार को दिनांक 02.01.2019, 21.12.2020 व 27.12.2021 को ऋण माफी की ओटीएस (एक मुश्त ऋण माफी योजना) हेतु राज्य सरकार को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने तथा बैंकों को निर्देशित करने का अनुरोध किया है।

माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान के पत्र दिनांक 21.12.2020 के क्रम में माननीय किसान एवं कल्याण मंत्री, भारत सरकार ने पत्र दिनांक 11.04.2022 द्वारा राज्य सरकार को स्वयं के फण्ड से किसानों की कर्ज माफी करने की सलाह दी है।

उक्त के अलावा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में दिनांक 09.11.2021 को OTS एक मुश्त ऋण माफी योजना के तहत 90:10 का ऋण माफी का प्रस्ताव वाणिज्यिक बैंकों, अनुसूचित बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्पोरेट कार्यालयों को भिजवाया गया तथा स्मरण पत्र दिनांक 27.01.2022, 05.05.2022, 22.07.2022 व 16.11.2022 को प्रेषित किये गये हैं, लेकिन किसी भी बैंक प्रबन्धन ने सरकार के प्रस्ताव पर अब तक सहमति नहीं दी है।

(आयोजना मंत्री)

मुख्य सचिव महोदया ने दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को उक्त बैंकों के दिनांक 30.11.2018 को बकाया अवधि पार कृषि ऋण माफी हेतु सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को अर्द्ध शासकीय पत्र लिख कर सभी बैंकों को उक्तानुसार कृषि ऋण माफ करने के लिए सभी बैकों को OTS योजना लाए जाने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध किया है।

(2) जी हां। सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी हेतु कृषक ऋण माफी आदेश क्रमांक प17(15)सह/2018, दिनांक 19.12.2018 जारी किया।

सहकारिता विभाग द्वारा सरकार के आदेश दिनांक 19.12.2018 की अनुपालना में सरकार द्वारा दिनांक 31.12.2022 तक राज्य के सहकारी बैंकों की राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2018 (अल्पकालीन) के तहत 7 हजार 5 सौ 71 करोड़ 83 लाख (7571.83 करोड़) रुपये एवं राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019 (अल्पकालीन) के तहत 20 लाख 77 हजार (20.77 लाख) कृषकों (लघु, सीमांत एवं अन्य) का 7 हजार 8 सौ 55 करोड़ 32 लाख (7855.32 करोड़) रुपये सहित कुल 15 हजार 4 सौ 27 करोड़ 15 लाख (15427.15 करोड़) रुपये का अल्पकालीन ऋण माफ किया है।

इसके अतिरिक्त राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019 (मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन) के तहत 32 हजार 7 सौ 34 (32734) लघु एवं सीमांत किसानों का 3 सौ 65 करोड़ 10 लाख (365.10 करोड़) रुपये का कर्ज माफ किया गया, जबकि राज्य सरकार के ऋण माफी आदेश दिनांक 19.12.2018 की पालनार्थ दिनांक 30.11.2018 को राष्ट्रीयकृत, अनुसूचित एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋणी 3,49,257 कृषकों की NPA राशि 6,018.93 करोड़ है। उक्त में से 02 लाख तक की पात्रतानुसार 3,49,257 कृषकों की राशि 5,638.47 करोड़ है। SLBC के अनुसार 30.11.2018 के पश्चात् 31.10.2022 तक 250773 कृषकों की NPA राशि 4182.04 करोड़ रुपये को सम्बन्धित बैंकों द्वारा repaid/upgraded कर दिया गया है। वर्तमान में 95,629 कृषकों की NPA राशि 1,819.10 करोड़ रुपये का NPA लम्बित है। (परिशिष्ट-2) इनकी कर्ज माफी की कार्यवाही ओटीएस के तहत प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। गत तीन वर्षों में कर्जा नहीं चुकाने के कारण केवल 32

(आयोजना मंत्री)

किसानों की ज़मीनें नीलाम हुई हैं, जिनमें 31 प्रकरण राजस्व विभाग तथा 01 प्रकरण सहकारिता विभाग से संबंधित है। (परिशिष्ट-3)

किसानों की 5 एकड़ तक की कृषि भूमि को कुर्की एवं नीलामी से बचाने हेतु राज्य सरकार द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020 (विधेयक 2020 का विधेयक सं. 33) विधान सभा में पारित कराया गया है, जो माननीय राज्यपाल महोदय के दिनांक 27.01.2022 को हस्ताक्षर उपरान्त वर्तमान में माननीय राष्ट्रपति महोदया के स्तर पर विचारार्थ एवं अनुमति (Assent) हेतु रक्षित किया गया है।

भविष्य में उप खण्ड अधिकारियों के आदेशों से किसानों की 5 एकड़ तक की कृषि भूमि को कुर्की एवं नीलामी से बचाने की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, इतना लम्बा उत्तर है। उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। माननीय, प्रश्न पूछ लें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, खण्ड-3 के उत्तर के अनुसार 31 किसानों की जमीन नीलामी हुई है। क्या सरकार कर्जा नहीं चुकाने वाले किसानों की कुर्की व नीलाम की गई ज़मीनें पुन: किसानों को लौटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों? दूसरा और पूछ लूं? वर्तमान में जिन किसानों का राष्ट्रीयकृत बैंक शिड्यूल्ड बैंक तथा..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह प्रश्न अलग-अलग विभागों से सम्बन्धित है। आयोजना के सम्बन्ध में मंत्री जी जवाब दे पाएंगे, इसलिए स्पेसिफिक पूछ लें, अन्यथा इस प्रश्न को दूसरे माध्यम से लेकर आएं।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): इससे जुड़ा हुआ ही है, अलग से नहीं है।

श्री अध्यक्ष: ये आयोजना के मंत्री हैं। न को-आपरेटिव के मंत्री है न उनके। आपका उत्तर, जो चाहेंगे, वह उत्तर नहीं आ पाएगा। बात को समझो।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): एक बार आ जाए।

श्री अध्यक्ष: आप पूछ लें। माननीय मंत्री जी, बताएं।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): सैकण्ड है...

श्री अध्यक्ष: एक का जवाब आने दें, फिर दूसरा पूछ लेना।

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्य किसानों द्वारा बैंकों का ऋण नहीं चुकाने के नियमानुसार जो कुर्की की बात है, उसके लिए सरकार बहुत चिन्तित है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने, हमारी सरकार ने वर्ष 2023-24 के कृषि बजट में राजस्थान फार्मर्स डैट रिलीफ एक्ट का गठन किया। यह एक्ट लेकर आने की घोषणा की, जिसके अन्तर्गत रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को डैट रिलीफ कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है। उसके अलावा, कुर्की से सम्बन्धित नियम हैं इनके अंदर संशोधन करके, ठोस नियम इस प्रकार के बनें जिससे किसानों की जमीन कुर्की न हो, इसके लिए यह कमीशन बनाया गया। हमारी सरकार किसानों के प्रति इस मसले पर चिन्तित है।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): वर्तमान में जिन किसानों का राष्ट्रीयकृत बैंक, शिड्यूल्ड बैंक तथा आर.बी.आई. से जुड़े हुए कृषकों का जो कर्जा बकाया चल रहा है, उन किसानों का अब कर्जा लौटाना है या नहीं? यदि नहीं, तो वर्तमान में कर्ज माफी की प्रतीक्षा में जिन किसानों की जमीनें कुर्की व नीलामी होना प्रक्रियाधीन है, क्या सरकार उन्हें संरक्षण प्रदान करने का विचार रखती है? एक और बाकी रह जाएगा, साहब।

श्री अध्यक्ष: चार बोल दो एक साथ।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): वह जवाब साथ ही दे पाएंगे।

श्री अध्यक्ष: आप शिड्यूल्ड बैंक का पूछ रहे हैं। शिड्यूल्ड बैंक का स्टेट गवर्नमेंट से सम्बन्ध नहीं है तो शिड्यूल्ड बैंक के बारे में स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी। अगला प्रश्न।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): एक इसी से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, हो गया।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): इसी से सम्बन्धित एक और है।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, आप बैठें। हो गया। अगला प्रश्न। गिरधारीलाल।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। आप सुन नहीं रहे? I will deprive you to ask the questions. प्लीज, आप सुन नहीं रहे क्या? आप सुन नहीं रहे क्या? (व्यवधान) आप भारत सरकार से बात कर लेना। I will not allow it. सुन नहीं रहे क्या आप? (interruptions) I will name you. मैं आपको बाहर

(श्री अध्यक्ष)

निकालूंगा। आप भारत सरकार का फैसला यहां करेंगे? आप बैठें प्लीज। आप सुन नहीं रहे ...(व्यवधान) Mr. Rathore, I will not tolerate it. यह बहुत गलत तरीका है and I will not allow you to ask any question; if you don't want to adhere to the rules.

अगला प्रश्न। गिरधारीलाल।

श्रीडूंगरगढ़ में डामर सड़कों से वंचित पंचायत मुख्यालय

241. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के कितने ग्राम पंचायत मुख्यालय अब तक डामर सड़क से वंचित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों को डामर सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? क्या सरकार गांव डेलवां से लादड़िया तक डामर सड़क बनाकर पंचायत मुख्यालय से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार लूणकरणसर (एस.एच. 6ए) से कानूता मार्ग वाया सहजरासर, सेरूणा, सूडसर, सावंतसर, लिखमीसर राजेडू, बापेऊ, सोनियासर इयारा कैम्प रोड तक घोषित मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड (एम.डी.आर.) का निर्माण कब तक करवाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भजनलाल जाटव): (1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ का कोई भी ग्राम पंचायत मुख्यालय डामर सड़क मार्ग से वंचित नहीं है।

(2) डामर सड़क मार्ग से कोई भी ग्राम पंचायत मुख्यालय जुड़ने से वंचित नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के गांव डेलवां से लादड़िया के मध्य मिसिंग लिंक है। ग्राम पंचायत डेलवां के अन्तर्गत दो गांव डेलवां (ग्राम पंचायत मुख्यालय) एवं लादड़िया हैं। ग्राम पंचायत मुख्यालय डेलवां स्टेट हाईवे संख्या 93 से डामरीकृत सम्पर्क सड़क से जुड़ा हुआ है एवं लादड़िया भी अन्य ग्राम पंचायत मुख्यालय उदरासर से डामर सड़क से जुड़ा हुआ है। ग्राम

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

लादड़िया व संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय डेलवां के मध्य मिसिंग लिंक की दूरी 9.00 किमी. है, जिसको स्वीकृत करना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(3) लूणकरणसर (एस.एच. 6ए) से कानूता मार्ग वाया सहजरासर, सेरूणा, सूडसर, सावंतसर, लिखमीसर, राजेडू, बापेऊ, सोनियासर, इयारा कैम्प रोड तक घोषित एमडीआर सं. 298 की कुल लम्बाई 140.70 किमी. है, जिसमें से बीकानेर जिले में 103.90 किमी. एवं चूरू जिले में 36.80 किमी. लम्बाई की डामरीकृत सड़क है। राज्य सरकार द्वारा बीकानेर जिले में एसआरएफ-एमडीआर योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के अन्तर्गत 11 किमी. लम्बाई में सड़क के इन्टरमिडियेट लेन (5.50 मीटर) चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की स्वीकृति राशि रू. 353.57 लाख दिनांक 15.02.2023 को जारी की गई है। चूरू ज़िले में मुख्य मंत्री द्वारा बजट घोषणा 2023-24 में 23.20 किमी. की लम्बाई में सड़क के इन्टरमिडियेट लेन (5.50 मीटर) चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु रू. 23.00 करोड़ की घोषणा की गई है, जिसकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, सड़क के मामले में बिन्दु एक, बिन्दु दो, मैं सीधे ही तीसरे पर आना चाहता हूं। लूणकरणसर से कानूता मार्ग वाया सहजरासर से सेरूणा, जिसमें 140 किलोमीटर सड़क राजस्थान सरकार द्वारा मंजूर की गई है, जिसमें 36 किलोमीटर चूरू में आती है, 103 किलोमीटर बीकानेर ज़िले में आती है। जिसमें बताया गया है कि 11 किलोमीटर सुदृढ़ीकरण बीकानेर जिले में किया जाएगा, बाकी का सुजानगढ़ क्षेत्र में किया जाएगा। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा, मेरे क्षेत्र में जो सुदृढ़ीकरण का काम किया गया है एमडीआर रोड का, वह किस क्षेत्र से, कहां से शुरू किया जाएगा? यह बताने का कष्ट करें।

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपके मूल प्रश्न हैं, उत्तर में हमने यह पूरा दिखा रखा है। मैं पढ़कर सुना देता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उनका लिमिटेड है। उनके विधान सभा क्षेत्र में कहां से कहां तक सड़क बनेगी, यह बता दें आप।

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल सड़क की लम्बाई 298 किलोमीटर है। बीकानेर की 103.90

(श्री भजनलाल जाटव)

किलोमीटर है, चूरू की 36 किलोमीटर है, डूंगरगढ़ की 84.40 किलोमीटर है। लूणकरणसर की 23.50 किलोमीटर है।

श्री अध्यक्ष: वह जगह पूछ रहे हैं, डूंगरगढ़ की कहां से शुरू होगी, कहां खतम होगी, यह उनका इन्टरेस्ट है।

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता देता हूं। राज्य सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में किलोमीटर 77/0 से 88/11 किलोमीटर लम्बाई में और सड़क के 5.50 मीटर चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण एवं कार्य...

श्री अध्यक्ष: गांव के नाम हों तो गांव के नाम बोल दो।

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें किलोमीटर चिह्नित करने पड़ते हैं, जीरो किलोमीटर से लेकर कितने किलोमीटर तक। योजना में राशि...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप माननीय सदस्य को, कौनसे गांव आते हैं उनकी सूचना दे दें। अगला प्रश्न।

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपके आदेश की पालना होगी।

श्री अध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा।

सिरोही जेल का अन्यत्र स्थानान्तरण

242. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या जेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मंत्री द्वारा वर्ष 2022 में सिरोही जेल का निरीक्षण किया गया था? यदि हां, तो उक्त निरीक्षण में क्या-क्या कमियां पाई गईं व क्या शिकायतें प्राप्त हुईं तथा उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सिरोही की वर्तमान जेल को आबादी क्षेत्र से अन्यत्र स्थानान्तरित करने का विचार रखती है?

(3) उक्त जेल में कितने कैदियों को रखने की क्षमता है व अभी कितने कैदी रखे गये हैं? जिला सिरोही की अदालतों में विचाराधीन मामलों में कितने कैदी किन कारणों से अन्य जिलों की जेलों में रखे गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जेल मंत्री (श्री टीकाराम जूली): (1) जी हां। यह सही है कि माननीय जेल मंत्री द्वारा दिनांक 02.04.2022 को जिला कारागार, सिरोही का दौरा किया गया था। दौरे के उपरान्त माननीय जेल मंत्री ने विजिटर बुक में यह अंकित किया था कि "आज सिरोही कारागार का निरीक्षण किया गया। स्टाफ से भी क्षमता से अधिक कैदियों पर निगरानी एवं संभालने का कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा रहा है। कैदियों को विधिक राय उपलब्ध कराने की एवं सरकारी कर्मचारियों को पेशी पर समय पर जाने की जरूरत है। पुन: सभी स्टाफ का धन्यवाद।"

उक्त दौरे के उपरान्त अब तक कारागृह के कुल 18 बंदियों को विधिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

निरीक्षण के दौरान बंदी गेमला पुत्र लखाराम द्वारा माननीय मंत्री महोदय को मौखिक निवेदन किया गया कि वर्तमान में जिस प्रकरण में वह निरुद्ध है उसमें उसे झूठा फंसाया गया है क्योंकि अपराध के समय वह बाली जेल में निरुद्ध था।

बंदी द्वारा जिस अपराध के संबंध में निवेदन किया है, उस पर कार्यवाही करने हेतु माननीय न्यायालय सक्षम है। कारागार विभाग के स्तर पर कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

इसके अतिरिक्त अन्य कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

(2) जिला कारागार, सिरोही के नवीन जेल भवन हेतु भूमि आबंटन के लिए महानिदेशालय कारागार के पत्रांक 18023-27 दिनांक 07.06.2022 के द्वारा जिला कलेक्टर, सिरोही को पत्र लिखा गया। इस पर जिला कलेक्टर, सिरोही ने उनके पत्रांक 3649-53 दिनांक 07.07.2022 के द्वारा आयुक्त, नगर परिषद्, सिरोही को भूमि उपलब्ध कराने हेतु पत्र व्यवहार किया गया है।

बजट घोषणा 2022-23 के क्रम में नवीन जेल हेतु भूमि उपलब्ध होने पर जिला कारागृह, सिरोही को स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जायेगी।

(3) जिला कारागार, सिरोही की बंदी क्षमता 205 के विरुद्ध दिनांक 24.01.2023 की स्थिति में 290 बंदी निरुद्ध रहे हैं। दिनांक 24.01.2023 को सिरोही कारागार की अदालतों में विचाराधीन मामलों के 08 बंदियों को जनाधिक्य एवं 09 बंदियों को शिकायतन/प्रशासनिक कारणों से अन्य जिलों की कारागृहों में रखा गया है। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री अध्यक्ष: जिस स्पीड से आप पढ़ रहो हो, पढ़ा हुआ माना गया। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछ लें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रिमण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। माननीय मंत्री जी, आपके दौरे के दौरान, जिस एसटी के गेमला राम गरासिया ने आपको बताया कि जिस दिन लाडूदेवी देवासी की हत्या हुई वह बाली जेल में बंद था। आपने स्वयं बाली जेल से लिखित में सूचना मंगवाई। जेलर ने भेजा कि हां, इस तारीख को गेमला राम गरासिया बाली जेल में बंद था। उसके बाद डीआईजी की जांच में प्रमाणित भी हो गया कि उनको असत्य फंसाया गया है। आपने मंत्री के रूप में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए क्या कार्यवाही की? मैं इतना पूछना चाहता हूं।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जेल विभाग का काम नहीं है कि कौन बंदी रहेगा, कौन छूटेगा। न्यायालय के द्वारा जिनको हमें सौंपा जाता है, उनको हमारे यहां रखते हैं। आर्डर होते हैं कि छोड़ दिया जाए, तब हम छोड़ देते हैं। मैं माननीय सदस्य के साथ खुद दौरे पर था, जहां बताया गया। माननीय सदस्य के द्वारा मेरे से यह जानकारी ऑन रिकार्ड चाही गई थी कि वह बाली में बंद थे या नहीं थे, वह जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करा दी थी। उसके बाद इसका निर्णय या तो पुलिस करेगी या फिर कोर्ट करेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि मंत्रिमण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। जब आपकी जानकारी में आ गया कि जिस दिन हत्या हुई, उस दिन गेमला गरासिया बाली जेल में बंद था, तो क्या आपको पुलिस को लिखना नहीं चाहिए था कि दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करे?

श्री अध्यक्ष: क्या, माननीय सदस्य, मुख्य मंत्री के सलाहकार की कोई जिम्मेदारी है? (व्यवधान)

अगला प्रश्न। श्रीमती कल्पना देवी।

लाडपुरा में पंजीकृत मन्दिर

243. श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(श्रीमती कल्पना देवी)

(1) विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में विभाग के अधीन कुल कितने मन्दिर हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मंदिरों के अधीन कुल कितनी भूमि दर्ज है तथा कितनी भूमि पर अतिक्रमण हैं? क्या सरकार उक्त मन्दिरों के अधीन उक्त भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? मन्दिरों के नाम दर्ज भूमि का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

देवस्थान मंत्री (श्रीमती शकुन्तला रावत): (1) विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में निम्नलिखित 4 मंदिर देवस्थान विभाग के अंतर्गत आते हैं:-

1. राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री कर्णेश्वर महादेव, कंसुआ, कोटा।
2. राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर, श्री डाढ देवी माताजी, उम्मेदगंज, कोटा।
3. राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री मुरलीमनोहरजी, दीपपुरा, कोटा।
4. राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर, श्री गौराजी गढ़, मण्डाना, कोटा।

(2) उक्त मंदिरों के अधीन कुल 9.17 हैक्टेयर भूमि दर्ज है, जिसमें मंदिर श्री कर्णेश्वर महादेव, कोटा के अधीन 4.95 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण है जिस पर रियासत काल से अतिक्रमण है। देवस्थान विभाग द्वारा वर्ष 1998 से अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूमि के संबंध में न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, कोटा के यहां वर्ष 2013 से 8 वाद लम्बित हैं, जिनमें देवस्थान विभाग के निरीक्षक द्वारा प्रभावी पैरवी की जा रही है।

राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री मुरली मनोहरजी के नाम 4.22 हैक्टेयर भूमि दर्ज है, जिसको प्रतिवर्ष मुनाफाकाश्त पर दिया जाता है। इस भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।

राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री डाढ देवी माताजी उम्मेदगंज कोटा एवं राजकीय प्रभार मंदिर श्री गौराजी गढ़ मण्डाना के नाम कोई भूमि नहीं है।

अतिक्रमण मुक्त कराये जाने के संबंध में न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, कोटा के आदेश के अध्याधीन विभाग द्वारा अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): उत्तर पढ़ा हुआ माना जाए। अध्यक्ष जी, मैं सीधे ही पूछ लूं?

श्री अध्यक्ष: हां, पूछिये, आप।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड-2 में जवाब आया है उसके तहत मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि कर्णेश्वर महादेव मंदिर के अधीन जो भूमि है उसका सीमांकन करवाकर, भू-माफिया से जो शेष भूमि बची है, उसको बचाने के लिए सरकार क्या ठोस कार्यवाही कर रही है?

दूसरा प्रश्न पूछ लूं? क्या इस शेष भूमि को अपने कब्जे में लेकर बाउण्ड्रीवाल बनाने की सरकार की मंशा है, जिससे शेष भूमि भू-माफियाओं से बच सके? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, रियासतकाल से ही कुछ जमीन पर कब्जा था। अभी हमने लास्ट 24.01.2023 सीमा ज्ञान हेतु आधुनिक तकनीक ईटीएस से करवाये जाने के लिए भूप्रबंधक अधिकारी, कोटा को हमारे विभाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं, जिसकी अनुपालना में भू-प्रबंधक, कोटा द्वारा राजस्व दल का गठन कर दिया गया है। दिनांक 08.02.2023 को आधुनिक तकनीक ई.टी.एस. के द्वारा सीमा ज्ञान की कार्यवाही इसमें लगभग सम्पूर्ण कर दी गयी है, हमारे पास रिपोर्ट नहीं आयी है। जैसे ही हमारे पास यह रिपोर्ट आयेगी तो इस जमीन के लिए हमारे विभाग की एक योजना हम बना रहे हैं, जिसकी पिछले महीने हमने मीटिंग भी कर ली है। नंदन-कानन योजना के तहत हम इसको किसी भी तरीके से बाउंड्री करवाकर जहां पर जितनी भी ऐसी मंदिरों की जमीनें हैं उनको रक्षित करने के लिए, एक तरह से उनका संरक्षण करने के लिए पेड़-पौधे लगाकर जो हमारे पूजनीय पौधे हैं, वह चाहे पीपल का है, आंवले का है, कल्पवृक्ष है, ऐसे पौधे लगाकर हम इसको संरक्षित करेंगे।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहती हूं कि मंत्रीजी ने यह कहा कि इसका सीमा ज्ञान हो चुका है पर पूर्ण नहीं हुआ है तो कब तक यह पूर्ण हो जायेगा? ये जो कह रहे हैं कि रियासतकालीन के कब्जे हैं, तो क्या यह सही है कि जो मन्दिर की भूमि है, जो रियासतकालीन से लोग बसे हुए हैं, क्या आप उनको रेगुलराइज्ड करने की मंशा रखते हैं?

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): इस तरीके की हमारी कोई रेगुलाइज करने की मंशा नहीं है लेकिन राजस्व विभाग से जो हमारी जमीन खाली है और जिसको अपन खाली करवा सकते हैं, उसकी यह रिपोर्ट आनी है। ई.टी.एस. से सर्वे हो चुका है और रिपोर्ट आते ही हम आपको भी उसकी कापी दे देंगे और मैंने पूरे ही मंदिरों का, पूरे राजस्थान के भी और अन्य जो बाहर

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

के मन्दिर हैं उनकी भी ई.टी.एस. से करवाने का हम एक नया प्रयोजन कर रहे हैं, जिससे कि इनको संरक्षित कर सकें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): सीमा ज्ञान पूर्ण कब तक हो जायेगा?

श्री अध्यक्ष: वे यह पूछ रहे हैं कि सीमा ज्ञान कब तक पूरा हो जायेगा?

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सीमा ज्ञान के लिए अभी हमने जनवरी में जो तारीख दी है, जैसे ही सीमा ज्ञान की यह रिपोर्ट आ जायेगी, ई.टी.एस. से करवाया है, वैसे तो पहले कई बार आ चुकी है, लेकिन उससे हमारा विभाग संतुष्ट नहीं था, अब यह रिपोर्ट आनी बाकी है और रिपोर्ट आते ही आपको सूचित कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

कोटा व बूंदी में माडा योजना में स्वीकृत कार्य

244. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला कोटा व बूंदी में माडा योजनान्तर्गत संविधान की धारा 275(1) के तहत माह जनवरी, 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक किस-किस गांव में किस-किस कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण करा लिए गये हैं व कितने कार्य प्रारम्भ नहीं हुए हैं तथा कितने कार्य अपूर्ण हैं? उक्त कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): (1) कोटा व बूंदी जिले में माडा योजनान्तर्गत संविधान की धारा 275(1) के तहत जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2022 तक कोटा जिले हेतु 19 निर्माण कार्यों हेतु राशि रुपये 235.07 लाख एवं बूंदी जिले हेतु 62 निर्माण कार्यों हेतु राशि रुपये 1102.19 लाख, कुल 81 निर्माण कार्यों हेतु राशि रुपये 1337.26 लाख की राशि के कार्य स्वीकृत किये गये हैं। पंचायतवार व वर्षवार सूची परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

(2) उक्त माडा योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों में से कोटा जिले में 19 निर्माण कार्यों में से 3 कार्य पूर्ण किये गये, शेष 16 कार्य प्रगतिरत हैं। बूंदी जिले में 62 निर्माण कार्यों में से 1 कार्य पूर्ण है एवं वर्तमान में 4 कार्य प्रगतिरत हैं तथा 57 कार्य अप्रारम्भ हैं। निर्माण कार्य की प्रकृति एवं लागत मूल्य के अनुसार कार्यकारी एजेन्सी पंचायत समिति को आबंटित कार्य लगभग 6 माह तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग को आबंटित कार्य 9 माह में पूर्ण होने की संभावना है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी।)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं डाइरेक्ट प्रश्न पूछ लूं?

श्री अध्यक्ष: हां, आप डाइरेक्ट प्रश्न पूछें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहती हूं कि कोटा एवं बूंदी जिले में माडा की एक साथ राशि स्वीकृत हुई और एक साथ टीएस./ एफ.एस. जारी हुई, उसके बावजूद भी 19 कार्यों में से 9 कार्य पूरे कोटा जिले में किये गये, बाकी के सभी 16 कार्यों पर उनका काम चल रहा है, प्रगतिरत है। क्या कारण रहा कि बूंदी जिले के जो मेरे 62 कार्य थे, उनमें से मात्र एक कार्य ही पूर्ण हुआ है, 4 प्रगतिरत हैं और बाकी के 57 कार्य जिनकी राशि जारी नहीं की जा रही है जो अभी तक भी आठ-नौ माह बीत जाने के बाद भी चालू नहीं हो पाये हैं, तो इस राशि को कब तक जारी कर देंगे?

दूसरा, यह क्या कारण है कि 2439.45 लाख रुपये, इतनी बड़ी राशि को जिला परिषद्, बूंदी कुंडली मारकर आठ महीने से बैठी हुई है। पीडब्ल्यू.डी. जिन कामों में वर्क एजेंसी है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): हां, बिलकुल। आप मुझे यह बता दें। स्टेट की जो माडा की राशि आती है, वह बूंदी जिले में, कोटा जिले में आपने चार साल में कितनी दी है, यह भी मुझे बताने की कृपा करें।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, राशि का सारा विवरण खण्ड-अ में दिया हुआ है।

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

जहां तक बूंदी जिले में काम प्रारम्भ नहीं होने की माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जुलाई, अगस्त, सितम्बर में सारी वित्तीय स्वीकृति दे दी। उसके बाद में बूंदी जिले का एक डेपुटेशन सी.ई.ओ. जिला परिषद्, बूंदी को मिला और उन्होंने हमारे को 17.09.2022 को एक लैटर कार्यकारी एजेंसी चेंज करने के लिए लिखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में 28.09.2022 को जहां से कार्यों की अनुशंसा आयी थी, वहां से फिर एक अनुशंसा आयी कि जहां पर जगह उपलब्ध नहीं है और जो कार्य जिनकी अनुशंसा की थी, उनके काम के बदले दूसरे मद से कार्य स्वीकृत हो गये थे, उनके लिए दूसरी अनुशंसा आयी और उसके बाद में 28.12.2022 को फिर हमारे पास में जिस एजेंसी से कार्य की स्वीकृति के लिए यह लैटर आये थे, उन्होंने वापस कार्यकारी एजेंसी चेंज करने के लिए हमारे पास में पत्र भेजे और हमने उसके अलावा 10.02.2023 को सी.ई.ओ., जिला परिषद् को कार्यकारी एजेंसी चेंज करने के और उसकी राशि जारी करके काम प्रारम्भ करने की चिट्ठी लिख दी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आपने यहां से पत्र जारी कर दिया कि कार्यकारी एजेंसी चेंज की जाये, उसके बावजूद भी जैसे ही कल, मेरा आज प्रश्न यहां पर आया, कल कुछ ग्राम पंचायतों की राशि ट्रांसफर की गयी है, तो मेरा इतना ही निवेदन है कि उस राशि को तुरंत ट्रांसफर करें और काम चालू करें। पूरे आठ महीने से यह 24 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं तो उसका सदुपयोग होगा और आप बोल रहे हैं कि 6 महीने में हम काम कम्प्लीट कर देंगे, तो जब नौ महीने में कुछ नहीं कर पाये तो फिर यह कैसे कर पाएंगे?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने विलम्ब का कारण बता दिया है। माननीय सदस्य को विलम्ब के पत्र भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा, आप चाहें तो मैं टेबल भी कर दूं? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा विभाग सम्बन्धित विभाग को राशि ट्रांसफर कर देता है और उसके बाद में विभाग है, सी.ई.ओ., जिला परिषद् जैसे उन पंचायतों को राशि ट्रांसफर करता है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): मैंने यह पूछा है कि स्टेट की तरफ से कितनी राशि दी गयी है, उसका भी पूछा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप एक बार मंत्रीजी को सुन लें, फिर आप दुबारा पूछ लेना। वे खड़े हुए हैं। हां, आप बोलें।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने हमारी राशि जो भी उसमें 40 परसेंट स्वीकृति के अगेंस्ट में देनी थी, वह सारी राशि ट्रांसफर कर दी है और बाकी काम प्रारम्भ होने के बाद में, यू.सी. आने के बाद में शेष राशि वापस उसमें ट्रांसफर कर दी जायेगी और वह सारा काम सी.ई.ओ. और पंचायत समिति के द्वारा होता है और उसमें कार्यकारी एजेंसी और सारे काम के लिए लैटर मेरे पास में सारे उपलब्ध हैं, विलम्ब के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): इस राशि में स्टेट गवर्नमेंट का भी कुछ हिस्सा है क्या या पूरी राशि केन्द्र सरकार की है? यह मेरा इसमें प्रश्न है।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष केन्द्रीय सहायता की 275 (ए) के तहत यह राशि स्वीकृत करवायी गयी और वह केन्द्रीय सहायता के हिसाब से यह राशि उपलब्ध हुई है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, सीधा ही प्रश्न कर लूं?

श्री अध्यक्ष: आप मंत्रीजी को दो मिनट पढ़ने दें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या?

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी को बोलने दें। आप बैठें। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

शहीदों के परिजनों को देय सहायता

245. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या सैनिक कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश के शहीद हुए सैनिक व अर्द्धसैनिक बलों के परिजनों को दी जाने वाली सभी प्रकार की सहायता का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत तीन वर्षों में प्रदेश के कितने सैनिक व अर्द्धसैनिक आतंकी घटनाओं, दुर्घटना एवं अन्य आपदाओं में शहीद हुए? शहीदों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री संदीप शर्मा)

(3) क्या यह सही है कि अनेक प्रकरणों में शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली सहायता के प्रकरण लम्बित हैं? यदि हां, तो किन-किन मामलों में कौन-कौनसी सुविधाएं दिया जाना लम्बित हैं? क्या सरकार शहीदों के परिजनों को सहायता प्रदान करने के लिए समयावधि निश्चित करने पर विचार रखती है?

राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण (श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा): (1) सरकार द्वारा प्रदेश के शहीद हुए सैनिक व अर्द्धसैनिक बलों के परिजनों को दी जाने वाली सभी प्रकार की सहायता का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) विगत तीन वर्षों में आतंकी घटनाओं, दुर्घटना एवं अन्य आपदाओं में प्रदेश के 34 सैनिक शहीद हुए हैं, जिनके नाम सहित सूची का विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(3) जी हां। शहीदों के परिजनों को लम्बित सहायता का विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

सरकार द्वारा लम्बित सहायता शीघ्र उपलब्ध करवाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बिंदु संख्या-3 के परिशिष्ट-ग में यह बताया है कि 23 प्रकरण तो सिर्फ तीन वर्ष से विचाराधीन हैं। शेष या तो कलेक्टर के पास लम्बित पड़े हैं या अन्य विभागों में उलझे हुए हैं। मंत्रीजी ने उत्तर में यह कहा है कि सहायता शीघ्र उपलब्ध करवाने की कार्यवाही की जा रही है। मेरा मंत्रीजी से यह निवेदन है कि यह शीघ्र कब पूरा होगा? मंत्रीजी इसका समय निर्धारित करेंगे क्या क्योंकि शहीद हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं और उनके परिजन जिस तरीके से आज परेशान हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कोटा में ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछ रहे हैं या उत्तर दे रहे हैं?

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): हां, प्रश्न पूछ रहा हूं। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि 14 फरवरी, 2019 को पुलवामा में अमर शहीद श्री हेमराज मीणा की अंत्येष्टि में क्या सरकार के द्वारा उनके परिजनों को कोई घोषणा की गयी थी? वहां सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा घोषणा की गयी थी?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप कितने प्रश्न पूछेंगे? आप बैठें। माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम शहीदों को जो जमीन 25 बीघा अलॉट करते हैं उसमें कुछ लोग तो वहां जाकर जमीन देखने के बाद उनको वह पसंद नहीं आती है। कुछ लोगों को कलेक्टर और रेवेन्यू के अधिकारियों के लेवल पर कोआपरेट नहीं किया जाता और इस मामले में हम शहीदों को 25 लाख रुपये, 25 बीघा जमीन या 25 लाख रुपये, हाउसिंग बोर्ड का मकान या फिर 50 लाख रुपये देने का राज्य सरकार का प्रावधान है। यह कलेक्टर के लेवल पर कुछ रेवेन्यू के अधिकारियों के द्वारा शहीदों को सच में कोआपरेट नहीं किया जाता है।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के प्रतिनिधि उनके घर पहुंचे थे श्री हेमराज मीणाजी की अंत्येष्टि के समय तो उस समय यह वादा किया था कि उनके घर तक ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बात हो गयी, आप प्रश्न पूछें, मान्यवर।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): सड़क बनाने का क्या सरकार के प्रतिनिधियों ने वादा किया था और वहां पर जो मूर्ति स्थापना का विषय था, वहां पर क्या उनकी मूर्ति स्थापना हो गयी तथा उनका जो विद्यालय जिसमें वे पढ़े थे, वहां पर क्या उनके नाम से स्कूल हो गया? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सैनिक कल्याण बोर्ड ने कुछ वादा किया था? सैनिक कल्याण विभाग ने किया या जन प्रतिनिधियों ने वादा किया? वादा विभाग ने किया था या जन प्रतिनिधियों ने किया था?

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): सरकार के प्रतिनिधि ने, साहब।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(समय: 12.00 बजे)

(शेष तारांकित व समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठें प्लीज। आप बैठें, प्लीज।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(श्री अध्यक्ष)

(1) प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती से आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति विषयक स्थगन प्रस्ताव निम्नांकित माननीय सदस्यों से प्राप्त हुए हैं-

I. श्री धर्मेन्द्र कुमार

II. श्री हमीर सिंह भायल

III. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल

IV. श्री मदन दिलावर

V. श्री सतीश पूनियां

VI. श्रीमती शोभा चौहान

VII. श्री जोराराम कुमावत

VIII. श्री रामलाल शर्मा

IX. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी

X. श्री राजेन्द्र राठौड़

XI. श्री बिहारीलाल

बीएसी की मीटिंग में इस बारे में चर्चा करके एक दिवस फिक्स करेंगे।

(2) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से जिला पाली में युवक की हत्या को आत्महत्या में बदलने में पुलिस की मिलीभगत से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से नगरपालिका छबड़ा को 'डी' श्रेणी से 'सी' श्रेणी में क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत गरनिया के जल बहाव क्षेत्र में कचरा संग्रहण स्थल बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से ग्राम मेहरवाला तहसील टिब्बी, हनुमानगढ़ में भूमिहीन परिवारों को आबंटित की गई कृषि भूमि का आबंटन निरस्त करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से प्रदेश के रावणा राजपूत समाज की 11 सूत्री मांगों पर शीघ्र निर्णय करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा तहसील में दो वर्ष पूर्व एसीबी द्वारा सीज किये तहसीलदार आवास को रिक्त करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(8) श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में वर्ष 2022 में टैंकरों द्वारा की गई पेयजल सप्लाई की बकाया राशि का भुगतान शीघ्र करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर में राष्ट्रीय राजमार्ग 325 पर बाईपास बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्रीमती कल्पना देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के वार्ड नं. 17 नगर निगम, कोटा उत्तर, उम्मेदगंज में प्रस्तावित ट्रेचिंग ग्राउण्ड को अन्यत्र शिफ्ट करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में नव क्रमोन्नत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हाइला कुई में डी एम एफ टी फण्ड से स्वीकृत कक्षों का निर्माण प्रारम्भ नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से प्रदेश में पुलिस कार्मिकों को मानदेय एवं पदोन्नतियां अन्य राजकीय कार्मिकों की तुलना में कम होने के सम्बन्ध में।

(13) श्री जोगेश्वर गर्ग, सदस्य की ओर से माही समझौता लागू कर जवाई बांध का जल नदी में छोड़ने की मांग पर जिला मुख्यालय जालौर में भारतीय किसान संघ के धरना-प्रदर्शन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में लम्बित भर्तियों के कारण बेरोजगारों को हो रही समस्याओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्रीमती संतोष, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के ग्राम 3 एनएम 3 एमएलडी एवं 13 केएनडी में पेयजल संकट का जल जीवन मिशन के तहत समाधान करने के सम्बन्ध में।

(16) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मावली में बेमौसम वर्षा एवं ओलावृष्टि से नष्ट फ़सलों का किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिलवाने के सम्बन्ध में।

(17) श्री कालूराम, सदस्य की ओर से स्टेट हाईवे 19-ए (बीओटी) सुकेत से डग तक सड़क का सुदृढ़ीकरण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(18) श्री रामप्रताप कासनियां, सदस्य की ओर से प्रदेश में अधिवक्ता

(श्री अध्यक्ष)

सुरक्षा कानून लागू करने की मांग के सम्बन्ध में अधिवक्ताओं की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी, श्रीमती कल्पना देवी, श्री जोगेश्वर गर्ग एवं श्रीमती संतोष को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से प्रदेश के छात्रों से निजी चिकित्सा विश्वविद्यालयों द्वारा अत्यधिक फीस वसूले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में शीतलहर से फ़सलों के हुए नुकसान का किसानों को मुआवजा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री पुखराज, सदस्य की ओर से प्रदेश में राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति को वर्तमान में देय आरक्षण में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती कृष्णा पूनियॉ, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में एनएच-52 के क्रोसिंग पर अंडरपास का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री ज्ञानचंद पारख, सदस्य की ओर से प्रदेश में आदिवासी एवं घुमन्तु जातियों के शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को उठाने के लिए अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री पदमाराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौहटन में प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित व्यक्तियों को लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत समितियों द्वारा 1200 वर्ग गज तक के पट्टे दिये जाने का नियम लागू करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(8) श्री रामनारायण मीना, सदस्य की ओर से भारतीय वन्य जीव संस्थान, सोरसन (बारां), दरा एवं गांधीनगर को मिलाकर वृहद जीव अभयारण्य घोषित करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से मंडार रेवदर सिरोही मेगा हाई-वे की टोल संग्रहण कम्पनी की निर्धारित समयावधि समाप्ति के उपरान्त बार-बार समय सीमा बढ़ाये जाने से उत्पन स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री गणेश घोघरा, सदस्य की ओर से नर्सिंग अधिकारियों की पदोन्नति सूची में हुई गड़बड़ियों की जांच कर पात्र कार्मिकों के नाम सूची में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से नगरपालिका रावतसर एवं पीलीबंगा में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में कार्य व्यवस्था अथवा प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित शिक्षकों को उनके मूल पदस्थापन का कार्यभार दिए जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से प्रदेश में गोचर भूमि को संरक्षित करने एवं मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के सम्बन्ध में।

(14) श्री बलवीर सिंह लूथरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में गंगनहर परियोजना की खाटा माइनर को स्वीकृत कर उसमें पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

(15) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के कतिपय गांवों में दाह-संस्कार हेतु श्मशान भूमि आबंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्य, आज शिक्षा के क्षेत्र में डिमाण्ड पर चर्चा होगी, इसलिए 295 पढ़े हुए माने जाएंगे।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-01 देखें)

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

राजसमन्द में टैंकरों द्वारा पेयजल सप्लाई की बकाया राशि का भुगतान

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं संचालन नियमों के नियम 50 के अन्तर्गत आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जिसको यह जिम्मेदारी दी कि वह प्यासों को पानी पिला सके, आज जब उनको पेमेंट करने की बारी आई तो हम उन्हीं को प्यासा छोड़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आती हूं वह एक ग्रामीण क्षेत्र है। 48 पंचायतों में से करीबन 33 पंचायतें, 300 गांव इस बात पर आश्रित रहते हैं कि टैंकर के द्वारा वहां सप्लाई की जाए। पानी की सप्लाई अभी से शुरू हो जाती है। जब तीन महीने का ग्रीष्मकालीन दौर आता है, उसमें तो यह सप्लाई और बढ़ जाती है, लेकिन अभी से हम लोग उस पर आश्रित हो जाते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जिला लेवल पर जितनी आम सभाएं हुईं उसमें भी इस बात को उठाया है। छोटे-छोटे गांव में टैंकर की व्यवस्था करने वाले लोग वहीं के लोग होते हैं, जिनकी दैनिकी दैनिक श्रम पर आधारित है। उन लोगों को आज तक भी पैमेंट नहीं हुआ है। राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र में करीबन 45 से 50 लाख रुपये तक का भुगतान बकाया है। ये टैंकर व्यवसायी मेरे कार्यालय पर आकर भी इतनी बार रोये हैं कि हम लोगों के एक -एक, डेढ़-डेढ़ लाख रुपये बकाया हैं, सरकार हमें पैसे नहीं दे रही है। हमने जब भी इस बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो डिपार्टमेंट ने सीधी हमें यह बात कही कि भीलवाड़ा का ठेकेदार है उसको हमने पेमेंट कर दिया है, वह अगर पेमेंट नहीं कर रहा है तो हम क्या करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पूरे प्रकरण में मुझे सिर्फ भ्रष्टाचार की बू आ रही है। जो गांव में पानी पिला रहा है, वह आज तक भी इस बात का इंतजार कर रहा है कि मुझे पेमेंट मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे दो मिनट का समय दिया है, इसलिए मैं बहुत लम्बी बात नहीं रख पाऊंगी लेकिन मैं आपको यह बोलना

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

चाहूंगी कि जिस प्रकार से हमारी प्रक्रिया चल रही है, एक ओलिगोपॉली बनाना चाह रहे हैं। हम बड़े-बड़े टेंडर उठाने वालों को तो...

श्री अध्यक्ष: Please be specific. आपको पेमेंट करवाना है कि पेयजल पर बोलना है?

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, पेमेंट करवाना है...

श्री अध्यक्ष: तो उसी पर बोलें, प्लीज।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): हम यह कोशिश नहीं करेंगे तो यह सारे टैंकर वाले...

श्री अध्यक्ष: Be confined to it. That's all.

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, लास्ट में अपनी बात रखते हुए मैं आपको यह कहना चाहूंगी कि घर घर पानी के टैंकर पहुंचाने वाले गरीबों का इंसाफ कब होगा? उनकी आंखों से बहता पानी पूछता है कि जनाब हमारा हिसाब कब होगा? धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कल्पना देवी।

लाडपुरा के उम्मेदगंज में प्रस्तावित ट्रेंचिंग ग्राउण्ड का अन्यत्र स्थानान्तरण

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे स्थगन पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। एक बहुत गम्भीर समस्या मैं आपके सामने रखना चाहती हूं और इसके लिए मैं आपका संरक्षण भी चाहती हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, उम्मेदगंज एक रियासतकालीन ग्राम है। यहां गुपचुप तरीके से ट्रेचिंग ग्राउण्ड शिफ्ट करने की योजना बनाई जा रही थी। जब ग्रामवासियों को इसका पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया और इसको रोकने का प्रयास किया। उसके बाद प्रशासन ने उनको यह बोलकर बात मनाने की बात रखी कि ट्रेचिंग ग्राउण्ड नहीं बनाएंगे परन्तु कचरा पाइंट बनाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या मतलब है। इसको रोकना जरूरी है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत लॉजिकल पाइंट से बताना चाहती हूं कि केवल उस पाइंट से 150 से 200 मीटर पर आबादी का क्षेत्र है।

(श्रीमती कल्पना देवी)

जो क्षेत्र इन्होंने चुना है यह ऊपरी क्षेत्र है। इसका यहां से असर पड़ेगा तो उस गांव के सारे ट्यूबवैल, कुएं, बावड़ी, नलकूप इन सबका पानी प्रदूषित हो जाएगा। उसके अलावा, बगल में एक तालाब है जहां पक्षी विहार बना हुआ है। एक तरफ सरकार ने वेटलेंड्स योजना में पक्षी विहार के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये स्वीकृत कराये हैं और यहां प्रवासी पक्षी भी आते हैं। जैसे स्पून बिल, स्टार्क, पेंटड स्टार्क, सारस, ये सब आते हैं तो उनके यहां भी आने का असर पड़ेगा। दूसरी ओर पांच सौ मीटर पर वन भूमि का क्षेत्र है। वन भूमि में एक तरफ से गांव वालों को लकड़ी काटने नहीं दिया जाता और अब जब इस वन भूमि को संरक्षण की जरूरत है, वहां पता नहीं कैसे उनको एनओसी मिली है। बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज। ऊपर से राइट विंग कैनाल जाती है जो लगभग 01 लाख 32 हैक्टेयर को सिंचित करती है। यह केवल लाड़पुरा क्षेत्र को ही सिंचित नहीं करती है। वहां किसान त्राहि-त्राहि मचा रहे हैं, उसका पानी भी प्रदूषित होगा। यह कैसी योजना है जो न पर्यावरण को संरक्षण दे रही है, न किसान को दे रही है, न पशु को दे रही है, न पक्षी को दे रही है। कल पुलिस प्रशासन द्वारा वहां पहुंच कर लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे चुपचाप मान जायें और वहां कचरा पाइन्ट बनाने दें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। इसको रोकने के लिए मैं आपसे निवेदन कर रही हूं। मैं समझती हूं कि कचरा का डिस्पोजल करना है पर कोटा स्मार्ट सिटी है, हम स्मार्ट तरीके ढूंढें कि कैसे इसका डिस्पोजल करें। एसआरएम का प्रोजेक्ट है उसको आप उपयोग में लें और इस योजना को तुरन्त बन्द करवायें। मेरा आपसे यही निवेदन है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगेश्वर गर्ग।

माही समझौता के अंतर्गत जवाई बांध का जल नदी में छोड़ने हेतु जालौर में भारतीय किसान संघ का धरना-प्रदर्शन

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): अध्यक्ष महोदय, जालौर जिला मुख्यालय पर परसों से हजारों की संख्या में किसान धरने पर बैठे हैं भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में। चार महीने पहले भी वे लोग बैठे थे। दीपावली पर हमको लग रहा था कि जवाई बांध पूरा भर जायेगा और नदी में पानी ओवरफ्लो होगा। वह स्थिति बन रही थी लेकिन अचानक से अधिकारियों की बदमाशी से जवाई बांध में जो पानी आ रहा था उसको रोक दिया गया और बाद में वह

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

पानी फालतू बहता हुआ समुद्र में गया। यदि वह पानी जवाई बांध में आ रहा होता तो निश्चित रूप से फाटक खुलते और नीचे डाउन स्ट्रीम में उन लोगों के कुएं रिचार्ज होते, जमीन रिचार्ज होती लेकिन वह फाटक बन्द कर दिया। उधर सिंदरू बांध को भरने के लिए जवाई बांध के फाटक खोल दिये, तो दोनों तरफ से हमको मार पड़ी और बांध का जल स्तर नीचे उतर गया। नदी से फ्री-फ्लो मिलने से हम वंचित हो गये। उसको लेकर 27 अक्टूबर से धरने पर किसान बैठे थे। लगभग 11 दिन बैठे। राजस्थान सरकार की तरफ से जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष श्री पुखराज पाराशर साहब ने किसानों के डेलिगेशन को जयपुर बुलाया। उनकी उच्चाधिकारियों से बातचीत करवायी और उनको यह आश्वासन दिया कि हम एक हाई पावर कमेटी का निर्माण करेंगे जो यह तय करेगी कि उस बांध में से कितना पानी फ्री-फ्लो के लिए छोड़ा जाना चाहिए। उस बारे में हम हाई पावर कमेटी बनायेंगे। अध्यक्ष महोदय, चार महीने हो गये, वह कमेटी अभी तक बनी नहीं है। उसको लेकर आक्रोश है।

दूसरा हमारा मुद्दा है माही परियोजना का हमारा जो समझौता है 1966 का, उसको लागू करने का समय आ गया है लेकिन सरकार उस विषय में कुछ नहीं कर रही है। उसको लेकर लोगों में आक्रोश है।

तीसरा मुद्दा बिजली की सप्लाई का है, उसको लेकर बहुत आक्रोश है। गई साल हमारे बहुत सारे गांवों में रात में बिजली नहीं दी जा रही थी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में केवल 19 गांवों को ही रात में बिजली दी जा रही थी। इस साल शत-प्रतिशत गांवों में बिजली दी गई है। यहां तक कि अब जब प्रेशर कम हो गया है, लोड कम हो गया है तब भी रात में बिजली दी जा रही है।

ये तीन बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर किसान आक्रोशित हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इन तीनों मुद्दों पर सकारात्मक रवैया अपनाते हुए उन किसानों को कुछ न कुछ ठोस नतीजा निकाल कर दें।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती संतोष।

अनूपगढ़ के ग्राम 3 एनएम, 3 एमएलडी एवं 13 केएनडी में पेयजल संकट का समाधान

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

(श्रीमती संतोष)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के अन्दर पेयजल को लेकर जनता को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मेरे क्षेत्र के अन्दर जल जीवन मिशन योजना के अन्दर 156 स्कीम्स स्वीकृत हैं। उनमें से 40 वाटर वर्क्स का काम अभी तक चालू नहीं हुआ है। भारी संकट को देखते हुए मेरे क्षेत्र की जनता को प्रदर्शन और आन्दोलन करना पड़ रहा है।

ऐसा ही एक मामला है। मेरे क्षेत्र की ग्राम पंचायत लूनिया के 3 एनएम ढाबा के अन्दर पांच दिन तक धरना लगाया गया क्योंकि वहां पर जल जीवन मिशन योजना के द्वारा 01 करोड़ 28 लाख रुपये मंजूर होने के बाद भी आज भी वह गांव प्यासा का प्यासा है क्योंकि विभाग द्वारा 70 लाख रुपये की सिर्फ पाइप लाइन डाल दी गयी और बाकी का कार्य जो है, वह बता कर विभाग के अधिकारियों ने यह कह दिया कि हमारे पास बजट ही नहीं है डिग्गी निर्माण के लिए। 28 मार्च से हमारे यहां नहर बन्दी प्रस्तावित है। अगर पानी स्टोरेज की व्यवस्था नहीं हुई तो आने वाले समय में जनता को पेयजल समस्या का सामना करना पड़ेगा।

मैं यह बताना चाहूंगी कि इसी प्रकार से हमारी अन्य जो ग्राम पंचायतें हैं उनके अन्दर भी जल जीवन मिशन योजना का कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। मेरे क्षेत्र अनूपगढ़ शहर के अन्दर भी पेयजल की भारी समस्या है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 नम्बर ऐसे वार्ड हैं और प्रेम नगर पूरा पेयजल की समस्या का सामना कर रहा है। पीएचईडी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता और नगरपालिका भी इसमें टालमटोल कर रही है तो जनता कहां जाये?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज वाइन्ड-अप करें।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): अध्यक्षजी, इसी तरह 20 एलएम लूनिया में भी यही हालत है। बहुत बड़ी समस्या है। लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 एनएम ढाबा, 3 एमएलडी, 1 एसडीवाई, 59 जीबी रामसिंहपुर, घड़साना, रावला मतलब पूरे क्षेत्र के अन्दर जल जीवन में इतना पैसा, इतना बजट मंजूर होने के बाद भी राज्य सरकार की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण यह स्थिति पैदा हो रही है कि आने वाले समय में 28 मार्च से नहर बन्दी होने के बाद हम पानी स्टोरेज कहां करेंगे और जनता को कैसे पानी की व्यवस्था करवायेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया। बार-बार रिपीट नहीं करें।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): मेरा यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्यवाही करके जनता को राहत दी जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री जगदीश चन्द्र।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सादुलशहर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत गेहूं की समय पर आपूर्ति

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर की 25 दुकानों में से 23 दुकान 17 ग्राम पंचायतों की हैं और 02 दुकान...

श्री अध्यक्ष: केवल आप ध्यान आकर्षित करें। मंत्री जवाब देंगे, उसके बाद प्रश्न पूछें। आप खाली बोलें कि ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गंगानगर रसद विभाग के माध्यम से कल्याण योजना के गेहूं के सप्लाई के बारे में आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। मंत्रीजी बोलेंगे, उसके बाद कोई भी क्वेरी कर लें।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनातर्गत माह दिसम्बर, 2022 के लिए आबंटित किये गये खाद्यान्न का वितरण माह जनवरी, 2023 में किया जाना था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनातर्गत माह दिसम्बर, 2022 हेतु जिला श्रीगंगानगर को 5615.311 मै. टन का आबंटन किया गया। विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध सूचनानुसार भारतीय खाद्य निगम से 5615.311 मै. टन का उठाव किया जाकर जिले की समस्त उचित मूल्य दुकानों पर उक्त मात्रा की आपूर्ति की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनातर्गत जिला श्रीगंगानगर को दिसम्बर, 2022 के पेटे आबंटित किये गये खाद्यान्न की शत प्रतिशत मात्रा का भारतीय खाद्य निगम से उठाव किया जाकर शत-प्रतिशत मात्रा ही समस्त दुकानों पर उपलब्ध कराई गई है। विभागीय पोर्टल सूचना की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर से प्राप्त सूचनानुसार विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनांतर्गत माह जनवरी,

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

2023 में वितरण हेतु 9500.75 क्विंटल गेहूं का आबंटन किया गया। थोक विक्रेता क्रय-विक्रय सहकारी समिति सादुलशहर द्वारा 4153.02 क्विंटल तथा थोक विक्रेता क्रय-विक्रय सहकारी समिति श्रीगंगानगर द्वारा 5347.73 क्विंटल गेहूं का उठाव किया जाना था। दोनों थोक विक्रेताओं को भारतीय खाद्य निगम श्रीगंगानगर द्वारा उक्त गेहूं का उठाव करवाने हेतु अनूपगढ स्थित निजी गोदाम से अनुमति दी गई है। थोक विक्रेता क्रय-विक्रय सहकारी समिति सादुलशहर द्वारा भारतीय खाद्य निगम श्रीगंगानगर द्वारा जारी किये गये अनूपगढ़ रिलीज आर्डर को सादुलशहर से अनूपगढ़ की दूरी लगभग 155 किमी. दूर होने के कारण राज्य सरकार द्वारा थोक विक्रेताओं को देय निर्धारित दर से अधिक व्यय होने के कारण सहकारी समिति को अत्यधिक वित्तीय हानि हो रही थी, के कारण परिवर्तन करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ। भारतीय खाद्य निगम से समन्वय करते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनांतर्गत उक्त गेहूं की श्रीकरणपुर स्थित गोदाम से उठाव करवा दी गई।

भारतीय खाद्य निगम से रिलीज आर्डर जारी होने के बाद थोक विक्रेताओं द्वारा गेहूं उठाव कर उचित मूल्य की दुकान को भेजी जाती है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदाम से ट्रक निकलने पर गेट पास जारी किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी गेट पास पर संबंधित वाहन का नंबर, ड्राइवर का नाम एवं मात्रा का विवरण होता है। थोक विक्रेताओं द्वारा उचित मूल्य दुकानदार के पास गेहूं पहुंचाने के बाद एस्सी.एम. पोर्टल पर उक्त गेट पास के आधार पर उचित मूल्य दुकानदार द्वारा प्राप्त की गई गेहूं ऑनलाइन की जाती है। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उक्त ऑनलाइन की गई गेहूं को ऑनलाइन रिसीव करने पर पोस मशीन में प्रदर्शित होती है। पोस मशीन में गेहूं प्रदर्शित होने के बाद संबंधित उपभोक्ता द्वारा पोस मशीन पर अपना अंगूठा लगाकर अर्थात् बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद उचित मूल्य दुकानदार द्वारा गेहूं का वितरण किया जाना सम्भ्व हो पाता है।

विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर को आबंटित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का कुल गेहूं 9500.75 क्विंटल उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा प्राप्ति ऑनलाइन रिसीव कर लिया गया, अर्थात् शत-प्रतिशत उठाव किया जाकर शत-प्रतिशत रिसीव भी कर लिया गया। विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनातर्गत माह जनवरी, 2023 में चयनित 1 लाख 82 हजार 365 लाभार्थियों में से 1 लाख 68 हजार 094 लाभार्थियों को 8,407.70

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

क्विंटल गेहूं का वितरण उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा कर दिया गया। माह जनवरी, 2023 में वंचित उपभोक्ताओं को गेहूं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत माह जनवरी, 2023 एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनांतर्गत माह दिसम्बर, 2022 के पेटे खाद्यान्न के वितरण की अवधि दिनांक 20.02.2023 तक बढ़ाई गई है। पत्र की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

अतः उपरोक्त तथ्यात्मक सूचना को दृष्टिगत रखते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय से विचाराधीन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ग्राह्य नहीं किये जाने हेतु निवेदन है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपने लगाना प्रारम्भ किया, इसके लिए आपको कोटि-कोटि धन्यवाद। पहले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगते ही संबंधित अधिकारी आकर दर्शक दीर्घा में बैठा करते थे। एक अधिकारी नहीं है। यह अधिकारी इतने लापरवाह हो गये, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी गंभीरता ही खतम हो गयी। मंत्रीजी ने इतना अच्छा उत्तर दिया, पर एक भी अधिकारी सामने नहीं बैठा।

श्री अध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जो आदत डाली है अधिकारियों की, उनको प्रैक्टिस हो रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): तैयारी कर लो इधर आने की। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपकी बात पर ध्यान देंगे।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो डिपार्टमेंट की चिट्ठी आयी है, इसमें पांच नंबर पर जो रिप्लाई दिया गया है, जो मंत्रीजी ने अभी फरमाया है हाउस में, यह तथ्य से बिलकुल परे है। 27 जनवरी को यह दिखा रहे हैं कि गेहूं की आपूर्ति कर दी गयी है, जबकि पोर्टल में दिसम्बर में ही अपलोड कर दिया गया है और फिजिकल तौर पर 85 प्रतिशत गेहूं का दिखाया है कि हमने अलाटमेंट कर दिया। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा घपला और वह भी कागज के ऊपर सदन को गुमराह किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पूरे मामले की ए.सी.बी. से जांच करायें और इसके साथ-साथ जो तत्कालीन DSO है, वह लम्बे समय से गंगानगर में बैठा हुआ है, पहले भी तीन-चार इंक्वायरी उसके खिलाफ हो चुकी हैं, जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

(श्री जगदीश चन्द्र)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि एक चिट्ठी राजस्थान सरकार के सेक्रेटरी साहब की 19.04.2022 की है, जिसमें लिखा गया है अटैचमेंट की जो दुकानें हैं, उसकी परमिशन बाकायदा कलेक्टर और डिपार्टमेंट से ली जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी तत्कालीन DSO ने किसी प्रकार की परमिशन नहीं लेकर 11 दुकानों का अलाटमेंट कर दिया। यह सिर्फ सादुलशहर का मसला है। इसके अलावा जिले में कितनी दुकानों का अलाटमेंट किया गया है, जिसकी सूची आज तक सदन पटल पर नहीं रखी गयी है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि यह बहुत बड़ा घोटाला है। गंगानगर में पहले भी गरीब का गेहूं खाया गया है, जिसके बारे में सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपसे निवेदन करूंगा और मंत्रीजी से दरख्वास्त करूंगा कि तत्कालीन अफसर को बर्खास्त करके उसके खिलाफ कार्यवाही करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: रिपीटिशन नहीं, माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले भी गंगानगर DSO पर कार्यवाही की गयी थी, आपको पता ही है। आप सही कह रहे हैं, 31 दिसम्बर को इन्होंने जो पोर्टल पर चढ़ाया, वह अधिकारियों की गलती है। मैंने इसकी सारी जांच की है और जिन अधिकारियों ने पोर्टल पर गलत चढ़ा दिया, उनकी गलती है, लेकिन यह तय बात है कि करणपुर दूर पड़ रहा था, लेकिन पोर्टल पर उन्होंने जो डेट डाली वह गलत है। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि यह जो ऑनलाइन सिस्टम है ..(व्यवधान) जगदीश जी, आप बैठो। आपकी पूरी बात करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप सुन तो लो, जवाब तो देने दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह डिपार्टमेंट वह डिपार्टमेंट है, जो 4 करोड़ 40 लाख लोगों को पोस मशीनों के जरिये गेहूं बांटने का काम करता है। बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं का उठाव होता है। 2014 में यह योजना लागू हुई और पिछली सरकार ने खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून लागू किया। मैं इतना कह सकता हूं NFSA परिवारों में, यह मैं सारे सदन को कह रहा हूं कि आपको कहीं लगता है कोई भी कर्मचारी, पहले तो कोई गड़बड़ कर नहीं सकता, उसको ऑनलाइन काम करना पड़ेगा, फिर भी यदि आपको लगता

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

है कोई गड़बड़ है तो आप नाम दे देना, यह जनता से जुड़ा हुआ गरीब का डिपार्टमेंट है, उसको बिलकुल रवानगी दे देंगे और सस्पैण्ड करना होगा, सस्पैण्ड कर देंगे। आपके यहां पर तो अधिकारियों पर कार्यवाही हुई है। यह पोर्टल पर गलत चढ़ाया गया।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप मान रहे हो कि गलत चढ़ाया है?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हां, गलत चढ़ाया है।

श्री अध्यक्ष: तो फिर कार्यवाही होनी चाहिये, बात खतम हुई।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): कार्यवाही करेंगे। इस पर कार्यवाही हो जायेगी और फिर भी आपका कोई सुझाव है, आप कहोगे उस एजेंसी से जांच करा देंगे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे और किसी को भी माफ नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। 131, श्री छगनसिंह।

आहोर में विद्युत कनेक्शन हेतु डिमांड राशि जमा कराने के बाद भी कनेक्शन जारी नहीं करना

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के तहत आहोर विधान सभा क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन हेतु डिमांड राशि जमा कराने के बाद भी कनेक्शन जारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ऊर्जा राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र आहोर में विधायक मद से वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल एक कार्य एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 3 कार्य एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में माह जनवरी, 2023 तक कुल 2 कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से कुल 4 का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष 2 स्वीकृत कार्य पूर्ण किया जाना वर्तमान तक लम्बित है। जिनमें से वित्तीय वर्ष 2020-21 का एक कार्य रूट विवाद के कारण लम्बित था। वर्तमान में रूट विवाद का निस्तारण कर दिया गया है तथा शेष अन्य एक कार्य हेतु कार्यादेश जारी किया जा चुका है,

(श्री भंवर सिंह भाटी)

जिसका कार्य प्रगति पर है, जोकि मार्च, 2023 के अंत तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उक्त विधान सभा क्षेत्र में घरेलू व अघरेलू श्रेणी के विद्युत कनेक्शन विद्युत आपूर्ति हेतु नियम व शर्तें 2021 में वर्णित प्रावधानानुसार आवेदक द्वारा मांग पत्र राशि जमा कराने के उपरान्त वरीयता अनुसार जारी किये जा रहे हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है।

विगत चार वर्षों में माह जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2022 तक उक्त विधान सभा क्षेत्र में मांग पत्र जमा होने के उपरांत घरेलू श्रेणी के कुल 3602 एवं अघरेलू श्रेणी के कुल 346 विद्युत कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं तथा वर्तमान में मांग पत्र जमा वाले घरेलू श्रेणी में कुल 49 व अघरेलू श्रेणी में कुल 6 आवेदन लम्बित हैं, जिनको विद्युत कनेक्शन जारी किये जाने का कार्य प्रगति पर है, जोकि मार्च, 2023 के अंत तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा-सा सवाल है कि विधायक मद से रायथल और गोविन्दा में और एक केयल में किसान ने डिमांड भरा है। यह कार्य कब तक पूर्ण कर लोगे, इसकी डेडलाइन तारीख बता दीजिये।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय के द्वारा एक तो रायथल, दूसरा गोविन्दा, इन दो कार्यों के बारे में पूछा गया है। उक्त कार्य हेतु माह नवम्बर, 2022 में विभागीय ठेकेदार फर्म मैसर्स रामदूत एंटरप्राइजेज जालौर को कार्य सम्पादित करने हेतु लाइन मैटेरियल उपलब्ध करवाया गया था एवं मौके पर भेजकर कार्य प्रारम्भ करवा दिया गया था। माह नवम्बर से माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा के अनुरूप कृषि श्रेणी के जमा आवेदकों को प्राथमिकता से विद्युत कनेक्शन जारी करने की पालना में कृषि सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति श्रेणियों, तुरंत प्राथमिकता श्रेणी के आवेदकों के विद्युत तंत्र स्थापित करने का कार्य करवाये जाने के कारण उक्त कार्य बाद में माह फरवरी के अन्त में दुबारा प्रारम्भ करवाया गया, जिसे दिनांक 15.03.2023 तक पूर्ण करवा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: तारीख बता दी आपको 15 मार्च, 2023, और क्या रह गया? हो गया। चर्चा समाप्त हुई। माननीय मंत्रीजी बैठें।

श्री बी.डी. कल्ला।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित तीन वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22)

1- जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा-64 के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22;

राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

2- कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21; एवं

जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2020-21)

3- कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2020-21.

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र पारीक।

समिति प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति 'क' के प्रतिवेदन (क्र.सं. 3 से 5)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार प्राक्कलन समिति 'क' 2022-23 एवं 2019-20 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1- सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित तृतीय प्रतिवेदन,

2- आबकारी विभाग से संबंधित चतुर्थ प्रतिवेदन एवं

(श्री राजेन्द्र पारीक)

3- प्राक्कलन समिति 'क' 2019-20 के प्रथम प्रतिवेदन में समाविष्ट ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक पंचम प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: अनुदान की मांग पर विचार एवं मतदान। श्री बुलाकी दास कल्ला।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 20 - प्रारंभिक शिक्षा की प्रस्तुति

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 20 - प्रारंभिक शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,89,85,40,53,000/- (एक सौ नवासी अरब पचासी करोड़ चालीस लाख तिरेपन हजार) तक की राशि प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 20 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-02 देखें।)

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र यादव।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): सर, एक और है।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, सॉरी।

मांग संख्या 21 - माध्यमिक शिक्षा की प्रस्तुति

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 21 - माध्यमिक शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,43,92,25,08,000/- (दो सौ तैतालीस अरब बानवे करोड़ पच्चीस लाख आठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 21 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-03 देखें।)

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र यादव।

मांग संख्या 22 - उच्च शिक्षा की प्रस्तुति

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 22 - उच्च शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 23,23,66,51,000/- (तेईस अरब तेईस करोड़ छियासठ लाख इक्यावन हजार) तक की राशि प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 22 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-04 देखें।)

श्री अध्यक्ष: श्री वासुदेव देवनानी।

मांग संख्या 20-प्रारंभिक शिक्षा, मांग संख्या 21-माध्यमिक शिक्षा व मांग संख्या 22-उच्च शिक्षा पर विचार

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 20, 21 व 22 पर सदन में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा पर चर्चा हो रही है। हर सरकार यह चाहती है कि बच्चों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, ताकि देश के लिए हम लोग श्रेष्ठ नागरिक तैयार कर सकें, लेकिन इस हेतु तीव्र इच्छा शक्ति, शैक्षणिक वातावरण, उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग, आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था, टीम का विश्वास व आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन करने का मानस आवश्यक है।

हालांकि हमारे मंत्री जी अच्छे आदमी हैं, विद्वान हैं। मैं भी यहां एक शिक्षक के नाते विषय रख रहा हूं ताकि हम लोग शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर सकें। हम यह नहीं कहें कि आपने यह किया, हम यह कर रहे हैं, उसको साढ़े 4 साल हो गये। अब तो हम यह करें कि इसमें सुधार कैसे ला सकते हैं, उस पर यदि चर्चा को सही रूप में लेंगे तो मुझे लगता है कि उससे सदन का लाभ होगा। हमने यह प्रयत्न किया था और उसके परिणामस्वरूप राजस्थान देश में 26वें नंबर से दूसरे नंबर पर आ गया था। आपने भी अपने घोषणा-पत्र में पेज क्रमांक 10 के क्रमांक 17 के बिन्दु संख्या 1 में उल्लेख किया है कि प्रदेश के शत-प्रतिशत बच्चों को हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। उसका क्या हुआ? आइये, जरा हम लोग जानें।

(समय: 12.33 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

शिक्षा विभाग में हर माह जिलों की शैक्षणिक रैंकिंग होती है। यह रैंकिंग नामांकन इंस्पायर्ड अवार्ड के लिए चयनित विद्यार्थियों की संख्या,

(श्री वासुदेव देवनानी)

औसत उपस्थिति, लाइब्रेरी से पुस्तकों का वितरण, नामांकन बढ़ोतरी, जन आधार प्रमाणीकरण, ज्ञान संबल पोर्टल पर प्राप्त राशि आदि प्रावधान के आधार पर दी जाती है।

मुझे बड़ी पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्तमान में प्रदेश के जिला रैंकिंग के लिए जो 150 स्कोर है, इसका एक तिहाई भी अंक जिले हासिल नहीं कर सके। केवल जनवरी में 50 अंक से ज्यादा इसको प्राप्त करने वाले 4 जिले हैं, अर्थात् बाकी 29 जिले इससे भी पीछे हैं। बाकी का तो मुझे लगता है कि भगवान ही मालिक है। प्रदेश में शिक्षा की गर्त में जाती हुई स्थिति दर्शाती है कि यह हो भी क्यों नहीं, शिक्षा में न आपके निरीक्षण की व्यवस्था है, न पर्यवेक्षण की व्यवस्था है और न ही शिक्षण की व्यवस्था है।

वर्तमान में संयुक्त निदेशक से लेकर प्रिंसिपल शिक्षक तक 01 लाख से अधिक पद रिक्त हैं, तो कैसे होगा? जब निदेशक का पद खाली होगा तो निरीक्षण नहीं होगा, पर्यवेक्षण नहीं होगा। अध्यापक नहीं होंगे तो शिक्षण भी कैसे होगा? इस प्रकार की स्थिति आज शिक्षा में बड़ी कमी को दर्शाती है।

दसवीं और बारहवीं की बोर्ड की परीक्षाएं इसी माह से प्रारम्भ हो रही हैं। पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है। आप बताइये कि इस शैक्षणिक सत्र में कार्य दिवस केवल 131 हुए हैं जो कि नियमानुसार 180 होने चाहिए। बताइये, फिर पढ़ाई कैसे होगी? हमने अच्छा प्रयोग किया है कि शनिवार को नो बैग डे होगा। आपने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाएं कोई हो रही हैं, उसके कारण से भी उसमें लिए जाते हैं। देखिये, वर्किंग डे पूरे होंगे तभी तो पाठ्यक्रम पूरा होगा। पाठ्यक्रम पूरा करने की चिंता करनी चाहिए क्योंकि इस बार बोर्ड की परीक्षाओं के बाद तुरंत ही अन्य परीक्षाएं भी होंगी। यदि पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा तो बच्चे का शिक्षण अधूरा रहेगा, वह बोर्ड की परीक्षा देकर के हो सकता है कि पास हो जाये, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है, वह बहुत डाउन होगी। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थन है कि इस विषय को भी गंभीरता से लें कि कैसे हम बच्चों को 180 दिन पढ़ा सकें।

माननीय सभापति महोदय, हमने अंग्रेजी माध्यम की खूब वाहवाही की। कब तक हिन्दी माध्यम के स्कूलों को बंद करके अंग्रेजी माध्यम में बदलते हुए महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खोलेंगे? जबकि महात्मा गांधी का अंग्रेजी के साथ कोई संबंध नहीं है। वह तो स्वभाषा के समर्थक रहे। हम उसमें केवल वाहवाही लूटना चाहते हैं। आखिर हम बच्चों को पढ़ाना क्या चाह रहे हैं? न वह

(श्री वासुदेव देवनानी)

घर के हैं, न वह घाट के रहे हैं। बिना योजना के अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की केवल रेवड़ियां हम बांट रहे हैं। उसका परिणाम ढाक के तीन पात ही हो रहा है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इस पर भी आप जरूर चिंता करें।

माननीय सभापति महोदय, शायद मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री जी को पूरी जानकारी नहीं होगी कि हम कितनी घोषणाएं कर रहे हैं, उसमें से स्कूल कितने खुले। वर्ष 2020-21 और 2022-23 की घोषणा अनुसार प्रदेश में 3400 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले गये, लेकिन अभी तक शुरू केवल 1625 हुए हैं। अभी हाल ही के इस बजट में आपने माननीय मुख्य मंत्री जी से घोषणा करायी कि हम ग्रामीण और शहरों में 1-1 हजार अंग्रेजी के स्कूल और खोल रहे हैं।

मैं अंग्रेजी के स्कूलों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इन स्कूलों में वर्षों से पढ़ रहे हिन्दी माध्यम के बच्चों की वैकल्पिक व्यवस्था किये बिना हम कैसे अंग्रेजी स्कूल खोल रहे हैं। इससे छात्रों, अभिभावकों को गंभीर संकट में डाल दिया है कि हम जायें तो कहां जायें। मेरे पास ग्रामीण क्षेत्र के कई बच्चे आते हैं, हम स्कूलों से निकाल दिये गये हैं, प्रिंसिपल जबरदस्ती टी.सी. दे रहा है। हम कहां जायें? उनको कई किलोमीटर दूर जाकर पढ़ने को मिलता है।

आपको यदि अंग्रेजी के स्कूल खोलने थे तो उसकी पूरी प्लानिंग करते, होमवर्क करते, उसकी सारी व्यवस्था करते। कोई अंग्रेजी के अध्यापक भी ढूंढते। तब उन बच्चों को अधकचरा तो नहीं रहना पड़ता। इन स्कूलों में आज 10 हजार अंग्रेजी शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं। पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं हैं। आपने भर्ती का राग तो अलापा, लेकिन मात्र 16,900 रुपये प्रतिमाह पर कौन आयेगा? किस स्तर का शिक्षक मिलेगा? अध्यापकों के अभाव में बच्चों के जीवन के साथ पूरी तरह खिलवाड़ किया जा रहा है।

यह केवल अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के लिए तो हम ताली बजा देंगे, डेस्क बजा देंगे, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? इससे न तो बच्चा अंग्रेजी समझ पायेगा और न कोई पढ़ाने वाला होगा। अंग्रेजी का नहीं होगा तो केवल अंग्रेजी माध्यम में पढ़कर आया हूं, इससे फील्ड में जाकर वह पूरी तरह से फेल होगा। इसलिए महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों पर वाहवाही मत लूटो। जितनी चादर है उतने पैर पसारो। जितने स्कूलों की आपकी व्यवस्था हो सकती है, उतने स्कूल खोलो।

(श्री वासुदेव देवनानी)

अभी तो आपने हद कर दी कि बीच सत्र में 436 स्कूलों को आपने अंग्रेजी माध्यम कर दिया। इससे न तो बच्चे हिन्दी के रहे और न बच्चे अंग्रेजी के रहे। खोलना है तो इन दिनों प्रारम्भ में घोषणा करो। वहां पर आप हिन्दी माध्यम की व्यवस्था करो, अंग्रेजी अध्यापकों की व्यवस्था करो। 16900 पर तो थर्ड ग्रेड टीचर की भी तनख्वाह नहीं होती। 16,900 पर कौन अंग्रेजी पढ़ाने वाला अध्यापक आपको मिलेगा? केवल अंग्रेजी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम, हम भी बड़े खुश हो रहे हैं। खुश होने की बात नहीं है। उसे न तो अंग्रेजी आयेगी और न ही उसे हिन्दी आयेगी। उसे न कहीं नौकरी मिलेगी। इस प्रकार का जो दृश्य आज खड़ा हो रहा है, यह केवल सस्ती लोकप्रियता के आधार पर हो रहा है। यह अभिभावक और विद्यार्थी आपको कभी माफ नहीं करेंगे। जितनी व्यवस्था कर सकते हो, उतनी की घोषणा करो। उतनों को व्यवस्थित चलाओ तो शायद शिक्षा के साथ न्याय होगा।

माननीय सभापति महोदय, विद्या संबल योजना का आपने बड़ा डंका बजाया। उससे न तो विद्या मिली और न ही संबल मिला। यानी आखिर क्या रहा? आपने घोषणा की कि हम विद्या संबल योजना में अध्यापक नियुक्त करेंगे। यह शुरू से ही विवादों में रही है। कारण कि आपने बिन होम वर्क के इसे शुरू किया। स्कूलों में पद खाली बताये गये। बेरोजगार लोग पहुंचे। वहां से तो वेतन उठ रहा था। फिर उसके बाद कई कारण आये। आपने उसको स्थगित कर दिया, इसलिए शिक्षकों की कमी से आज आये दिन तालाबंदी हो रही है, जिसके कारण से आज शैक्षणिक व्यवस्था खतरे में पड़ गयी है।

हमने स्टाफिंग पैटर्न लागू किया था, जिसके लिए मैंने पिछली बार एक प्रश्न भी लगाया था। स्टाफिंग पैटर्न में व्यवस्था थी कि बच्चों के बराबर स्कूल की पोस्टें होंगी, पद होंगे, लेकिन वर्तमान में इसकी खुले आम धज्जियां उड़ रही हैं। जहां बच्चे कम वहां अध्यापक ज्यादा और जहां अध्यापक ज्यादा वहां बच्चे कम, यानी यह अगेंस्ट द पोस्ट लगाने का केवल हम जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र के यस मैन को खुश रखने के लिए, तू ले जा ट्रांसफर, तू तेरे यहां जो चाहे ले जा, लेकिन शैक्षिक व्यवस्था का क्या होगा, माननीय मंत्री महोदय? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जरा इसकी व्यवस्था करें। आपके 17 हजार सीनियर हायर सैकंडरी स्कूल हैं, उनमें से 12 हजार स्कूलों में अनिवार्य विषयों के व्याख्याता के पद तक स्वीकृत नहीं हैं, कौन पढ़ाएगा? उनकी क्या व्यवस्था

(श्री वासुदेव देवनानी)

होगी? इसकी कोई चिंता नहीं कर रहा है। बस, खोले जाओ। आपने कहा कि हमने बहुत ज्यादा खोले, आपने निश्चित रूप से 3 हजार 800 क्रमोन्नत किये, तो 7 हजार क्रमोन्नत तो हमने भी किये थे लेकिन व्यवस्था के साथ किये थे, स्टाफिंग पैटर्न किया, हर जगह हर विषय का अध्यापक मिले, उसकी व्यवस्था की, जिसके कारण से हुआ।

माननीय सभापति महोदय, एक बात का उल्लेख और करना चाहूंगा कि हमने हमारे गत कार्यकाल में 22 हजार स्कूलों को आसपास के स्कूलों में मर्ज किया। मैं उधर से बोल रहा था, यहां से इनके तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो आजकल इनके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, शायद उस समय वे सचेतक थे, उन्होंने बड़े जोर-जोर से हल्ला मचाया, हम आएंगे, 22 हजार स्कूल खोल देंगे, बड़ी घोषणा की। कितने खोले? आपने पिछले बजट में बताया था कि हमने 1 हजार 250 स्कूल खोले, बाकी 20 हजार 500 का क्या हुआ? इसका मतलब हम सही थे। आज उन मर्ज्ड स्कूलों की आपके यहां भी यही स्थिति है। उनमें से आज भी 580 स्कूलों की स्थिति यह है कि जहां संख्या 25 से कम है, 151 स्कूल तो ऐसे हैं जहां 'जीरो' नामांकन हैं लेकिन वहां पर अध्यापक लगे हुए हैं। आज भी स्थिति यही है। इसलिए सही बात विपक्ष भी करे तो सरकार किसी की भी हो, उसको स्वीकार करते हुए उसकी वाहवाही करनी चाहिए, उसके अनुसार अपने को भी आगे कदम से कदम मिलाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आज कह रहा हूं कि हमने बहुत सोचसमझकर स्कूल मर्ज किये थे ताकि हर स्कूल में अध्यापक मिले। जहां विद्यार्थी ही नहीं हैं वहां पर अध्यापक देने का क्या तुक है? इस प्रकार केवल काम्पीटिशन, केवल खुश रखने के लिए, जाओ, स्कूल खोले जाओ। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसको राजनीति से अलग हटकर हम शैक्षणिक व्यवस्थाओं को ठीक करें, उसमें जरूर माननीय मंत्रीजी ठीक करेंगे तो मुझको लगता है कि केवल आलोचना नहीं कि 22 हजार, 20 हजार बंद कर दिए, हम नारेबाजी कर सकते हैं, पब्लिक में, अख़बार में छप सकते हैं, लेकिन बच्चों के साथ इससे न्याय नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदय, आप एक बात में और वाहवाही लूट रहे हो। हम बच्चों को दूध पिला रहे हैं। भाई, कौनसा दूध पिला रहे हो? हम तो बच्चों को 6 दिन दूध पिला रहे थे, आपने 4 वर्ष तक बच्चों के मुंह से दूध भी छीन रखा था। इसलिए आपको बच्चों और अभिभावकों से माफी मांगनी चाहिए कि हम 4 वर्ष तक आपको दूध नहीं दे पाए। उसके बाद जब सुध आई, चुनाव

(श्री वासुदेव देवनानी)

नजदीक आने लगे तो पहले सप्ताह में 2 दिन, अब चुनाव नजदीक देखते हुए 6 दिन, वो भी डिब्बे का दूध, उसकी क्वालिटी कैसे मेनटेन होगी, पता नहीं। हम ताजा दूध बच्चों को पिलाते थे, जिससे बच्चे खुश होते थे लेकिन आपको पता नहीं क्या जंची कि बच्चों को दूध नहीं पिलाएंगे। बच्चों ने क्या कसूर किया? योजना हमारी थी, आपकी थी, लेकिन राजनीति से ऊपर उठकर इसको देखना चाहिए था क्योंकि आखिर बच्चे तो आपके हैं, हमारे हैं। बच्चा न कांग्रेस का होता है न बीजेपी का होता है। बच्चे सबके होते हैं, उनको दूध पिलाने की व्यवस्था थी जो आपने ठीक तरह से नहीं की।

माननीय सभापति महोदय, स्कूल ठीक चले, उसके लिए स्कूलों को हमने कम्पोजिट स्कूल ग्रांट शुरू की थी। उसमें बिजली का बिल, चॉक, डस्टर, सफाई आदि के लिए किया था लेकिन उसमें था 1 से 30 नामांकन होगा तो 10 हजार रुपये, 31 से 100 होगा तो 25 हजार रुपये, 101 से 250 तक नामांकन होगा तो 50 हजार रुपये, 251 से 1 हजार तक 75 हजार रुपये, 1 हजार से ज्यादा नामांकन होने पर 1 लाख रुपये देंगे, लेकिन कब देंगे? आप सत्र के प्रारम्भ में देते तो उनको डस्टर, चॉक कुछ तो मिलता। आपने सत्र के अंत में अब जाकर देना शुरू किया है। आपकी पूरी शैक्षणिक व्यवस्था चौपट हो रही है, यह मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे 2014 से लेकर 2018 तक लगातार नामांकन बढ़ रहा था लेकिन आज 6 लाख 11 हजार नामांकन इस वर्ष कम हुए हैं। कम क्यों हुए? स्कूल तो आप खोलते गए, काहे को नामांकन कम हुआ? इसका मतलब है कि आपके यहां शैक्षणिक व्यवस्थाओं का अभाव है। केवल स्कूल खोलते जा रहे हो तो नामांकन तो बढ़ना चाहिए, फिर नामांकन कम क्यों हुआ? इस पर थोड़ा विचार करेंगे तो आपकी व्यवस्था थोड़ी ठीक होगी।

माननीय सभापति महोदय, आपने फ्री ड्रेस का खूब डंका पीटा। इसमें 60 प्रतिशत तो भारत सरकार का है। उसमें भी आपने क्या किया कि 40 परसेंट हिस्सा तो दिया लेकिन ड्रेस सिलवाने के लिए आपने 200 रुपये तय किए। 200 रुपये में कौन ड्रेस सिलता है? कोई माई का लाल हो तो बता दें? 200 रुपये में कोई ड्रेस नहीं सिलती है। आखिर क्यों गरीब अभिभावक अपनी जेब में से दें? इसकी कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय सभापति महोदय, हमने स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल शुरू किये थे। उनके 40 हजार बच्चों को

(श्री वासुदेव देवनानी)

यह ड्रेस नहीं दे रहे हैं, उनका क्या कसूर? आप स्कूलों को दे रहे हैं तो वो भी तो विवेकानन्द मॉडल स्कूल के आपके ही बच्चे हैं, उनको भी वो ड्रेस मिले, इसकी व्यवस्था भी करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का अभिनन्दन करता हूं कि उन्होंने कहा था कि ट्रांसफर पालिसी तैयार है, मैं इसको प्रोसेस में ले जा रहा हूं। पूरा वर्ष बीत गया, कहां है वो ट्रांसफर पालिसी? हम तो उसको ढूंढ़ते-ढूंढ़ते, अगरबत्ती जला कर थक गए, जरा वो ट्रांसफर पालिसी तो बताओ और उसको लागू करो। लेकिन केवल वाहवाही लूटने के लिए कहते जाओ, प्रेस में स्टेटमेंट देते जाओ, सदन में गुमराह करते रहो।

आपने एक बात और कही थर्ड ग्रेड अध्यापकों के ट्रांसफर के बारे में, आपने कहा था कि ट्रांसफर पालिसी लागू हो गई तो हम करेंगे, आपकी कोई ट्रांसफर पालिसी लागू नहीं हुई। आपने प्रिंसिपल्स के ट्रांसफर कर दिए, फर्स्ट ग्रेड के कर दिए, सैकंड ग्रेड के कर दिए लेकिन थर्ड ग्रेड टीचर का आखिर क्या कसूर है? आपने आवेदन भी मांगे, 85 हजार आवेदन भी मिले लेकिन वे बेचारे ठगे से रह गए और आज भी वे परेशान हैं अपने ट्रांसफर के लिए।

माननीय सभापति महोदय, इन्होंने बच्चों से 5 करोड़ रुपये ऐंठे हैं शिक्षक दिवस पर झंडियों के नाम पर, बच्चों से 5-5 रुपये स्कूलों में वसूले गए। 100 रुपये शिक्षकों से लिए गए, 50 रुपये अन्य कर्मचारियों से लिए गए। इस तरह से 5 करोड़ इकट्ठे किए। यह कौनसा नियम है, किस आधार पर आपने लोगों से पैसे लिए? कुछ नहीं, कोई उत्तर नहीं।

माननीय सभापति महोदय, बच्चों को संस्कार मिले, आप और हम सब चाहते हैं। मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि विदेशों के अंदर स्कूलों में रामायण पढ़ाई जाती है, गीता पढ़ाई जाती है लेकिन यहां तो केवल राजनीति की भेंट चढ़कर हमने योगाभ्यास तक बंद कर दिया। प्रार्थना के बाद योगाभ्यास का कार्यक्रम शुरू हुआ था, लेकिन चूंकि बीजेपी या दूसरी सरकार ने शुरू किया इसलिए बंद। मैं आज आपको बता रहा हूं कि इससे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होता है, मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि हम आएंगे तो यह पढ़ाई, महाभारत, गीता और रामायण की हम स्कूलों में शुरू कराएंगे। आप चाहे करो चाहे मत करो, योगाभ्यास भी शुरू कराएंगे, इनसे लोगों को संस्कारित करेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए।

(श्री वासुदेव देवनानी)

माननीय सभापति महोदय, आरटीई में आपने अच्छा किया, आपने इसको बढ़ाया, आरटीई में एडमिशन कब होने चाहिए? आपने सत्र के अंत में जाकर लाटरी शुरू की है। यह होनी चाहिए आपके अप्रैल, मई, जून या जुलाई में होनी चाहिए, लेकिन आपने अब जाकर शुरू की है। सत्र के अंत में ये आरटीई वाले बच्चे भटक रहे हैं, आखिर कहां जाएं, कैसे हों, इस ओर भी आप जरा ध्यान करें। मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, आप विद्यालय धड़ाधड़ क्रमोन्नत करते जाओ, करना भी चाहिए क्योंकि हर साल स्कूलों की मांग आती है, बच्चे भी बढ़ते हैं, क्रमोन्नत भी होने चाहिए लेकिन केवल सुर्खियां बटोरना उसका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। उसके लिए नव क्रमोन्नत विद्यालय में लेक्चरर के पद भी तो सृजित करो। आज आपने 3 हजार 800 क्रमोन्नत किये लेकिन उनमें पद सृजित नहीं हैं। उनमें बच्चे पढ़ेंगे कैसे? माननीय मंत्रीजी, आप शिक्षक भी रहे हैं, आप विद्वान भी हैं, आप इसकी भी थोड़ी-सी चिंता करेंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा आगे बढ़ेगी।

माननीय सभापति महोदय, आज तो कई शिक्षा माफिया सक्रिय हैं, वो शिक्षा को भी बेच रहे हैं। पेपर भी बेच रहे हैं। रीट का प्रकरण आपके सामने आया, लेकिन अभी तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन जारोली से आज तक कोई पूछताछ नहीं हुई। कारण, तार ऊपर से जुड़े हुए हैं। इस बात में मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता क्योंकि यह विषय सदन में कई बार आ चुका है। आप तो जांच इस बात की करो कि पेपर लीक कैसे हुआ, कहां से हुआ। यह आपको पता नहीं, केवल अपराधी का पता चला और आपने उसको पकड़ लिया, आप सुर्खियों में आ गए लेकिन पेपर लीक किसने किया, कैसे हुआ, कहां हुआ, इस पर जब तक आप नहीं जाओगे तब तक सच सामने नहीं आएगा। आप तो सच को सामने लाने वाले व्यक्ति हो, मैं आपकी इज्जत भी करता हूं, उस सच को तो सामने लाओ, माननीय मंत्रीजी, उस सच के बिना केवल लीपापोती से कुछ नहीं होगा। उसमें कोई भी मंत्री आता हो, कोई भी एमएलए आता हो, किसी भी पार्टी का आता हो, उसको पकड़ो, उसको सज़ा दिलवाओ तो मानेंगे कि आप एक विद्वान और सच्चे व्यक्ति हैं और शिक्षा का हित चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात चल रही है। कोचिंग इंस्टीट्यूट के कोई नियम नहीं हैं। अखबारों में आता है कि इसके

(श्री वासुदेव देवनानी)

लिए कोई नियमावली बन रही है लेकिन जब तक यह बनेगी तब तक पता नहीं आपकी सरकार ही चली जाएगी। चार-पांच महीने के आप मेहमान हैं। तब तक कोई नियमावली बनेगी, लागू होगी इसकी कोई संभावना नहीं है। आज कोचिंग इंस्टीट्यूट के तार पेपर लीक के साथ जुड़े हुए हैं। इनके बड़ेबड़े लोगों के तार प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर कई बच्चे आज आत्महत्याएं भी कर रहे हैं। सैकड़ों बच्चों ने सुसाइड किया है, इसलिए माननीय सभापति महोदय, इस पर विचार होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अपना राज्य शिक्षा में वर्षों से बहुत श्रेष्ठ रहा है, लेकिन आज यह बीमारू राज्य की श्रेणी में जा रहा है। पहले हम कहते थे, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, इनके बारे में कई बातें चलती थीं लेकिन पूरी शैक्षणिक व्यवस्था आज पंगु हो गई है। शिक्षा की दुर्गति हो रही है, भविष्य की चिंता का विषय है।

माननीय सभापति महोदय, मिड डे मील की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। छहछह महीने तक भुगतान नहीं हो रहा है, कैसे व्यवस्था होगी, इसकी चिंता करें।

फिर लेक्चरर की 2020-21 के बाद से डीपीसी नहीं हुई। बाकी पदों को भी नियमित नहीं किया। नियमित डीपीसी कराएं। एक बात और, प्रबोधकों के साथ आप क्यों धोखा कर रहे हैं? हमने प्रबोधकों को वरिष्ठ प्रबोधक बनाने के लिए कदम उठाये थे। आपने भी उसके अनुरूप एक आदेश निकाला। आपने वह आदेश निरस्त भी कर दिया। वे सैकंड ग्रेड के इक्विलेंट होंगे। बाकी 9-18-27 तो उन्हें वैसे ही मिलेगी। उन्हें भी लेवल-2 का हैडमास्टर बनाने का जो प्रावधान है, उसे आप क्रियान्वित करेंगे तो 21-22 हजार जो प्रबोधक हैं, उनके साथ न्याय होगा।

लास्ट में स्कूली शिक्षा पर मैं केवल एक विषय रखूंगा। नयी एजुकेशन पालिसी, यह नये भारत के निर्माण के लिए लागू हुई। वह पालिसी न बीजेपी की है, न आपकी है। वह सबकी है। राजीव जी ने भी नयी पालिसी बनायी थी, जिसका अनुसरण सबने किया। आज मोदी जी ने भी नयी पालिसी बनायी है। उसके अनुरूप कदम तो उठाएं। उसमें स्पष्ट है, इस नये भारत के निर्माण में एलकेजी, हायर केजी तथा आंगनबाड़ी को शिक्षा के साथ जोड़ा जाये। इसमें आपने कोई कदम नहीं उठाये। हम 18 हजार को उस परिसर में

(श्री वासुदेव देवनानी)

ले आये। 64 हजार आंगनबाड़ी हैं। उन्हें जरा शिक्षा के साथ जोड़ें। 5+3+3+4 का जो फार्मूला है, उसे आगे लाएं। व्यावसायिक शिक्षा शुरू करें। मातृभाषा में शिक्षा शुरू करें। ये सारी बातें होंगी तब जाकर नयी एजुकेशन पालिसी पर सही ढंग से विचार होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं जरा उच्च शिक्षा का जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि मांग संख्या 22 उसके साथ जुड़ी हुई है। उच्च शिक्षा का तो सम्पूर्ण ढांचा चरमरा गया है। मैं उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा का व्यक्ति रहा हूं, इसलिए मुझे ध्यान है, आप तो मंत्री हैं, उच्च शिक्षा में क्या हो रहा है, आप जरा गहराई में जाना तो शुरू करें।

केवल हम मंत्री बनते घूम रहे हैं और अपना औपचारिक काम कर रहे हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है। आज उच्च शिक्षा में न शिक्षक हैं, न अशैक्षणिक स्टाफ है, न संसाधन हैं और न ही विजन है। प्रदेश में कुल 490 राजकीय महाविद्यालय हैं। सामान्य के 445, बीएड के 16, कृषि के 29, इनमें स्वीकृत पद 9060 हैं, कार्यरत 4617 हैं। यानी 50 प्रतिशत से अधिक पद खाली हैं। टीचर्स नहीं होंगे तो कालेज में पढ़ाई कैसे होगी? कौन बच्चा आयेगा?

नियुक्तियों की बात करूं तो चार वर्षों में, यूं तो आप कह देंगे कि हमने 583 सहायक आचार्य नियुक्त किये, लेकिन यह अभ्यर्थना भी भाजपा सरकार के समय की है। इस सरकार ने एक भी पद अभ्यर्थना में नहीं भेजा। यदि मैं गलत हूं तो आप अपने उत्तर में जरूर बता दीजियेगा, मैं आपकी बात स्वीकार कर लूंगा। स्थायी प्रिंसिपल ही कालेज को चलाता है। पूरे 490 में से स्थायी प्रिंसिपल्स केवल 36 में हैं। लाइब्रेरियंस 490 में से केवल 22 में हैं। शारीरिक शिक्षक 490 में से केवल 26 में हैं। अकाउंटेंट 80 प्रतिशत नहीं हैं। लैब असिस्टेंट 70 प्रतिशत नहीं हैं। नोन-टीचिंग 60 प्रतिशत से अधिक खाली।

क्या चाहिए भाई? आखिर प्रिंसिपल में तो कोई पैसा नहीं चाहिए। प्रिंसिपल्स क्यों नहीं नियुक्त करते हैं? इसी सदन में मैंने प्रश्न लगाया था। अध्यक्ष महोदय ने तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री जी से पूछा था। उन्होंने कहा था कि हम अगले सत्र के पहले नियुक्तियां कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं हुई। यह सदन की अवमानना है। यह सब क्यों है, इसकी मैं गहराई में गया। यह केवल राजीव स्टडी सर्कल के लोगों को प्राचार्य बनाने की मंशा है। रातों-

(श्री वासुदेव देवनानी)

रात वरिष्ठता सूची में हेर-फेर हुआ। न्यायालय में मुद्दा चला गया। अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वरिष्ठता सूची के साथ क्यों हेर-फेर करते हैं? जो वास्तविक है, उसके हिसाब से बनना चाहिए। इसमें न कोई राजीव स्टडी सर्कल का होगा, न किसी और का होगा, वह तो शिक्षक होगा। शिक्षक शिक्षक होता है। उसके साथ न्याय करें। यह तो आपके सामान्य महाविद्यालयों की स्थिति है।

कृषि महाविद्यालयों की यदि मैं चर्चा करूं, कृषि महाविद्यालय पिछले बजट में 29 खुले, इस बजट में 7 की घोषणा की, पुराने चार, कुल चालीस। अध्यापक कितने? कृषि के अध्यापक कुल 20 हैं, अर्थात् दो महाविद्यालयों में केवल एक शिक्षक। कैसे कृषि चलाएंगे? कैसे मेरा बच्चा कृषि के बारे में जानेगा? कहां उसे नौकरी मिलेगी? उसके साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं? कुछ तो करें। इसीलिए परिणाम क्या हुआ है? बीस वर्षों तक उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ता रहा, इस वर्ष नामांकन में कमी आयी है। इतने महाविद्यालय खुल गये, नामांकन तो बढ़ना चाहिए था, आखिर कम क्यों हुआ, इसकी भी आप चर्चा करें।

इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र के पेज 10 के बिन्दु 7 में कहा है, विद्यार्थियों के अनुपात में कक्षा निर्धारण व शिक्षक नियुक्ति की बात की, लेकिन वर्तमान में अनुपात क्या है? वर्तमान में विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात 115:1 है, यानी एक टीचर के पास 115 विद्यार्थी हैं। होने कितने चाहिए? नियम कहता है कि आपके आर्ट्स का है तो 30 विद्यार्थियों पर 1 और यदि साइंस फैकल्टी है तो 25 पर एक। आप 115 पर क्या शिक्षा देंगे? कैसे शिक्षा व्यवस्था चलेगी?

आप युवाओं की बहुत बात करते हैं। आप जरा अपना बजट देख लीजिये। युवाओं की केवल बातें करते हैं। युवा विकास केन्द्र अघोषित रूप से बन्द हैं। आपने तीन वर्ष में मात्र एक हजार रुपये का प्रावधान रखा है।

विश्वविद्यालय की चर्चा करता हूं। राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय। क्या आज विश्वविद्यालय वित्त पोषित हैं? कितने की सहायता है? केवल खाता खुला रखने हेतु 1000/2000 रुपये आपने बजट में दर्शा दिये। उससे क्या होगा? इससे भी अधिक आपने खुला मजाक किया है, महिला योग्यता छात्रवृत्ति, स्वतन्त्रता सेनानियों के बच्चों को छात्रवृत्ति, मृतक

(श्री वासुदेव देवनानी)

राज्य कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति, शोध, ललित कला, पूर्व सैनिक आश्रितों के बच्चों की छात्रवृत्ति। इन सब छात्रवृत्तियों के लिए आपने बजट कितना रखा? इन सबको मिलाकर केवल एक लाख रुपये। क्यों मजाक कर रहे हैं आप इन बच्चों के साथ? क्या देंगे आप? कुछ दे ही नहीं पाएंगे। इस प्रकार की स्थिति बनी।

श्री सभापति: कृपया चार मिनट में समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं विषय पर ही बोलूंगा, विषय के अन्यत्र कहीं नहीं जाऊंगा। आर्ट्स में प्राचार्य समकक्ष पद हैं, लेकिन वहां पर प्राचार्य इतने उपलब्ध होने के बाद भी नहीं रखे। 10-12 वर्ष से जूनियर शिक्षकों को संयुक्त निदेशक पद पर रखा। केवल तुष्टीकरण। अपने चहेते राजीव स्टडी सर्कल के लोग लगाना। इस प्रकार की व्यवस्था प्रभावशाली नहीं रहेगी। यह शिक्षा के साथ मजाक है।

नवीन राजकीय महाविद्यालय आपने खोले, उनका संचालन कौन करेगा? राजस्थान कालेज एजुकेशन सोसाइटी। यह कदम आपको शिक्षा में रसातल की ओर ले जाने वाला है। कोई कर्मचारी शिक्षक उसमें स्थायी नहीं है। यहां तक कि प्राचार्य भी स्थायी नहीं है। खोले जाएं कालेज। आप तालियां, डेस्क बजाते जाएं कि हमारे यहां कालेज खुल गया। उस राजस्थान एजुकेशन सोसाइटी में आपकी गवर्निंग बॉडी में 10 हैं, उसमें से शिक्षाविद् एक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 7 में से 1 है। बाकी सारे ब्यूरोक्रैट्स हैं। क्या शिक्षा चलाएंगे आप? और तो और, आपने एडेड महाविद्यालय के 700 से अधिक स्टाफ को सरकार में लिया। इंजीनियरिंग कालेज में भी यह योजना चली। असफल गयी। अब 200 कालेजों में यह योजना सोसाइटी के अधीन, क्या करेंगे?

इनकी हालत जो बता रहा हूं, स्वीकृत शैक्षणिक 1148 पद हैं, कार्यरत हैं शून्य। अशैक्षणिक पद 2324, कार्यरत शून्य। विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों की स्थिति दयनीय है। ये विश्वविद्यालय केवल अब डिग्री बांटने वाले हो गये। इनका मैंने वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ा। उस प्रतिवेदन में न शोध है, न गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का है, न राष्ट्रीय स्तर का कोई जिक्र है। हद तो तब हो गयी जब राजस्थान विश्वविद्यालय की भावी योजना में इन्होंने इन्दिरा रसोई योजना चलाने का उल्लेख किया। यह कोई विश्वविद्यालय का काम है? विश्वविद्यालय का काम तो शोध कराना है। उसका कहीं उल्लेख नहीं।

(श्री वासुदेव देवनानी)

एमडीएस यूनिवर्सिटी का आप प्रतिवेदन पढ़ें। 2021-22 का ही 2022-23 में कापी-पेस्ट किया है। उस प्रतिवेदन के पृष्ठ 14 में सम्बद्ध महाविद्यालय 315, पृष्ठ 65 में 275, क्या यह ठीक है? जरा पढ़कर तो उसे अप्रूव करें। कोई पढ़ता ही नहीं है। केवल सदन में बजट ही पुराना नहीं पढ़ा गया, उच्च शिक्षा विभाग की पूरी रिपोर्ट कापी-पेस्ट करते हैं। उच्च शिक्षा का प्रतिवेदन 2020-21 का देख लें, 2021-22 का देख लें, 2022-23 का देख लें। उसमें आलोच्य वर्ष की विशेष उपलब्धियां देख लें, पूरा एक समान, कहीं कोई एक अक्षर का भी उसमें अन्तर नहीं। वर्ष की महत्वपूर्ण उपलब्धियां, वह पूरा कापी-पेस्ट। 2021 में उसमें लिखा है, पुस्तकालय का कम्प्यूटरीकरण, सारा वही का वही विवरण 2021-22 में और वही का वही 2022-23 में, अर्थात् आपने आगे एक भी कुछ कदम ही नहीं बढ़ाया। क्या कर रहे हैं उच्च शिक्षा में? वाई-फाई इंटरनेट, वही की वही रिपोर्ट्स हैं। इस प्रकार की स्थिति बनी।

माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत जल्दी कम्प्लीट कर रहा हूं। आखिर विश्वविद्यालय की स्थिति तो सदन के सामने आ जाये। चार विश्वविद्यालय हैं- सीकर, अलवर, भरतपुर, बांसवाड़ा। इनमें एक भी शैक्षणिक पद की नियुक्ति नहीं हुई है। तीस के तीस पद खाली। कैसे चलेंगे विश्वविद्यालय? क्यों खोल रहे हैं? खोलने हैं तो फिर पद भी तो दें, लेकिन पद नहीं देंगे। शेष विश्वविद्यालयों में क्या हाल हैं, मैं ज्यादा लम्बा न करके केवल तीन-चार यूनिवर्सिटीज का बताऊंगा। एमडीएस यूनिवर्सिटी मेरे अजमेर की, उसमें 48 में से 34 पद खाली हैं। 14 पदों से क्या विश्वविद्यालय चलेगा? इसी तरह कोटा में 78 में से 56 पद खाली हैं। बीकानेर में 77 में से 60 पद खाली हैं। यह स्थिति है। स्किल्ड यूनिवर्सिटी, जिसकी हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, डींगें हांकते हैं। वहां 2 वर्ष से न तो कुलपति है, न कोई स्थायी स्टाफ है। यह हालत हो गयी कि जो छात्र थे, 2532 की जगह केवल 816 रह गये। सम्बद्ध महाविद्यालय 97 में से केवल 43 रह गये। ये हाल हैं स्किल के। क्या आप बच्चों को स्किल्ड नहीं बनाना चाहते? यूनिवर्सिटी तो खोल दी, उसके आगे की भी तो व्यवस्था सम्भालें। इन्हें कोई चिन्ता नहीं है। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, आपसे निवेदन करता हूं कि जरा राजनीति से ऊपर उठकर इन व्यवस्थाओं को ठीक करें।

(श्री वासुदेव देवनानी)

(समय: 13.00 बजे)

आपने जोधपुर में फिनटेक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया पर आज तक एक्ट अनुमोदित नहीं हुआ, एआईसीटीई और यूजीसी से कोई मान्यता नहीं मिली पर आपने शिलान्यास कर दिया। निजी विश्वविद्यालयों में किस तरह से खुलकर भ्रष्टाचार चल रहा है और खोलने में क्या फर्जीवाड़ा चल रहा है, वह सदन के सामने ही है। गुरुकुल यूनिवर्सिटी, सौरभ यूनिवर्सिटी, ड्यून्स यूनिवर्सिटी, व्यास यूनिवर्सिटी, आप आज तक केवल आंखें मूंदकर सत्यापन करते हैं और भ्रष्टाचार का बड़ा खेल हो रहा है, इसलिए आप जरा इसको देखिये। फिर आपने सोसायटी से किया पर अभी तक 165 कालेजों की कोई सोसायटी नहीं बनी। मुझे पाठ्यक्रम का भी आश्चर्य हुआ कि केवल बी.ए. है और लैब इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो क्या बी.ए. करने से उनको कोई नौकरी मिलेगी क्या? यह तो बताओ। आज उनको रोजगार की जरूरत है और उसके लिए केवल बी.ए. पर्याप्त नहीं है, उसमें कुछ और भी करो। विद्या सम्बल योजना में गैस्ट फैकल्टी बेरोजगारों के साथ मजाक है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि...

श्री सभापति: थैंक यू माननीय।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): एक-दो मिनट में कर रहा हूं। आपने चयनित वेतनमान, एसोसियेट प्रोफेसर को 1.2.2018 से, आज 5 वर्ष हो गये पर उनके प्रमोशन लम्बित हैं। नयी शिक्षा नीति में केवल राजनीतिक जिद के कारण शिक्षा गर्त में जा रही है। मल्टी डिसिप्लिनरी उच्च शिक्षण संस्थाओं के स्थान पर केवल 2-4 कमरों में एक-दो शिक्षकों के साथ जो आप महाविद्यालय खोल रहे हैं, उनमें न लैब है, न आधारभूत संरचना है तो इस तरह से महाविद्यालय चलाने का कोई लाभ नहीं होगा।

यदि गुणवत्ता की मैं एक मिनट में चर्चा करूं तो 490 में से केवल 70 को नेक ग्रेड है। 4 कालेज को ए ग्रेड है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में पहले 300 में कोई इंजीनियरिंग कालेज नहीं है। यूनिवर्सिटी में केवल एक सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है। यह इसलिए है कि हमने केवल अपने चमचों को रेवड़ियां बांटी हैं और काम करने वालों को 600-600, 700-700 किलोमीटर दूर फेंका है।

पेपर लीक प्रकरण में आयुक्त कार्यालय में जो तीन टीचर्स डाक्टर बनेसिंह, सुभाष यादव, बी.एस. बैरवा थे उनको दिखावे के लिए निलम्बित

(श्री वासुदेव देवनानी)

किया, हैड क्वार्टर वहीं रखा और आज वापस उनको आयुक्तालय में ले आये। क्या सज़ा हुई? कारण यह है कि वे राजीव स्टडी सर्किल के हैं। जुगाड़ के सहारे यह उच्च शिक्षा चल रही है, कहीं होस्टल में है तो कहीं स्कूल में है। आपने एक जवाब दिया कि हम तो होस्टल में खोल देंगे।

श्री सभापति: थैंक यू, माननीय सदस्य।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): धरातल पर नींव खोखली है, न भवन है जिसका खामियाजा आज एक लाख 70 हजार विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। आज 8 विश्वविद्यालयों में वी.सी. नहीं हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने डाक्टर अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के वी.सी. की नियुक्ति को रद्द कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, एक बात और कहते हुए अपनी बात पूरी करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री हमारे सबके मुख्य मंत्री हैं और आदरणीय हैं पर ये सिर्फ जोधपुर के मुख्य मंत्री ही हैं क्या?

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): जोधपुर की लिस्ट पढ़ूं तो जो यूनिवर्सिटी खोलो जोधपुर में खोलो। जोधपुर में जयनारायण व्यास से लेकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी, आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस, डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी आफ पुलिस, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नोलॉजी, इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ हैण्डलूम टेक्नोलॉजी, इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट जैसे प्रमुख महत्वपूर्ण तो पहले से ही है।

श्री सभापति: थैंक यू। डाक्टर जितेन्द्र सिंह जी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): पिछले बजट में फिनटेक यूनिवर्सिटी, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी दिव्यांग इंस्टीट्यूट, सब जोधपुर में हैं।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आप मुख्य मंत्री हमारे भी हो, कुछ हमारी भी चिन्ता करो।

लास्ट में एक मिनट। इस तरह मेरा आपसे एक ही है कि निजी विश्वविद्यालयों और कोचिंग इंस्टीट्यूटों को आप जरा कसिये और 2023-24

(श्री वासुदेव देवनानी)

में जुगाड़ के सहारे इस उच्च शिक्षा को मत चलाइये। कहीं हॉस्टल तो कहीं स्कूल में और धरातल पर नींव खोखली हो रही है क्योंकि न भवन है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सीकर के पाटन कालेज में तो केवल 3 अध्यापक हैं। अत: मेरा आपसे निवेदन है कि हम कम से कम बच्चों के साथ तो न्याय करें। बच्चे कैसे बनकर तैयार होंगे, वे अपनी आजीविका कैसे कमायेंगे, अच्छे नागरिक कैसे बनेंगे, इसके लिए यदि दोनों मंत्री महोदय चिन्ता करेंगे तो आप और हम मिलकर आगे बढ़ेंगे और इसमें कहीं आपको सहयोग की आवश्यकता हो तो अनुभव के आधार पर एक टीचर होने के नाते, पूर्व मंत्री होने के नाते मैं आपका सहयोग करने के लिए सदैव तत्पर हूं। इतना विश्वास दिलाते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य, क्या है?

सूचना

सूरजगढ़ में पुलिस द्वारा डकैती के अभियुक्तों की गिरफ्तारी

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): सभापति जी, चार रोज पहले सूरजगढ़ में डकैती हुई थी उसमें मैं पुलिस को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज उन छह डकैतों को पुलिस ने डिटेन किया और अभी मुठभेड़ हुई है जिसमें दो डकैतों के पैर में गोली लगी है तथा एक कांस्टेबल के हाथ में गोली लगी है। इसलिए मैं इस सम्बन्ध में सदन को अवगत करा रहा हूं।

श्री सभापति: थैंक यू। डाक्टर साहब।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 20-प्रारंभिक शिक्षा, मांग संख्या 21-माध्यमिक शिक्षा व मांग संख्या 22-उच्च शिक्षा पर विचार

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी): सभापति महोदय, आज एजुकेशन और हायर एजुकेशन पर हाउस में चर्चा है। माननीय सभापति महोदय, the God has given gray matter equal to everybody, whether he is a Son of a Maharaja or a common farmer. Gray matter denotes the intelligence of the brain लेकिन, सभापति महोदय, जो हमारे अच्छे अध्यापक हैं वे ब्रेन को कल्टीवेट करते हैं और वही कारण है कि प्रतिभायें उभरकर बाहर निकलती हैं।

(श्री जितेन्द्र सिंह)

सभापति महोदय, हिन्दुस्तान पूरे विश्व में ज्ञान और धर्म का गुरु था। हमारे नालन्दा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे जहां दुनियाभर के लोग पढ़ने आते थे। आप तो स्वयं एजुकेशन कमिश्नर रहे हैं। 300 साल पहले अमेरिका जो आज सबसे डवलप्ड कंट्री है, that was the Country of Red Indians. एजुकेशन नाम की चीज नहीं थी, बिल्कुल बैकवर्ड था लेकिन जो लाभ मिला वह एजुकेशन का लाभ मिला। माननीय सभापति महोदय, एजुकेशन के लिए कहा गया है कि-

"अश्कों को मोती बना देती है शिक्षा,

जख्मों पर मरहम लगा देती है शिक्षा,

जब जीने की वजह ही न बची हो तो,

मौत को भी जिन्दगी बना देती है शिक्षा।"

माननीय सभापति महोदय, आप जानते हो कि हमारा गुर्जर समाज एजुकेशन में सबसे बैकवर्ड समाजों में माना जाता था। मैं मेरी बड़ाई नहीं कर रहा पर मेरे स्वयं के फादर के बड़े भाई ने 1922 में एमए, एलएलबी इलाहाबाद से किया और मैसूर हाई कोर्ट के जज बने। शिक्षा का यह इतना बड़ा महत्व है। मेरे पिताजी ने 1937 में आर जी कर, कलकत्ता से एमबीबीएस किया और डाक्टर बने जो सम्भवतया हमारे समाज के पहले डाक्टर हों। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा का इतना बड़ा चमत्कार है।

माननीय सभापति महोदय, भारत का अपना इतिहास रहा है। कालिदास, वाल्मीकि अपने आपमें बहुत बड़े व्यक्तित्व रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ ग्रंथ लिखे हैं। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी। आप कल्पना करिये कि हमारे अपने जो मार्डर्न साइंस के डाक्टर जगदीश चन्द्र बसु, डाक्टर हरगोविन्द खुराना, जिनको नोबेल प्राइज मिला, हमारे डाक्टर सी.वी. रमन जिन्होंने रमन रेज बनाई, रवीन्द्र नाथ टैगोर आदि यहां हुए। सभापति महोदय, भारत के पास इंटेलेक्चुअल्स की कमी थी क्या? मेरी सिस्टर आस्ट्रेलिया में है और वह कहती है कि भाई साहब, हिन्दुस्तान में अच्छे विश्वविद्यालय नहीं हैं क्या जो हमारे यहां पर हजारों बच्चे आस्ट्रेलिया में आ रहे हैं और उनको यही पता नहीं है कि विश्वविद्यालय का स्तर क्या है। वह गलत नहीं कह रही थी। हमारे बच्चे विदेशों की अंधी दौड़ में लगे हुए हैं। अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं और अच्छे इंस्टीट्यूशन तो हर जगह हैं। मैं खुद जयसिंह हाई स्कूल, खेतड़ी से पढ़कर

(श्री जितेन्द्र सिंह)

निकला, आप स्वयं झुन्झुनूं और पिलानी से पढ़कर निकले। क्या आप आईएएस आफिसर नहीं बन गये? क्या मैं डाक्टर नहीं बन गया? माननीय सभापति महोदय, 1964 में पूरे झुन्झुनूं जिले से मैं एसएमएस मेडिकल कालेज में अकेला लड़का था और एक और उदयपुरवाटी के थे। डाक्टर पूनियां ने एक कार्यक्रम किया था और आज मेडिकल कालेज, जयपुर में पीजी, यूजी में मिलाकर 350 बच्चे हैं जो सिर्फ शिक्षा का चमत्कार है, सभापति महोदय।

आज हमारे पूरे राजस्थान में 51 यूनिवर्सिटीज प्राइवेट सैक्टर में हैं, 15 गवर्नमेंट सैक्टर में हैं और 1800 कालेज हैं। मुझे खुशी है और आप तो स्वयं जानते हैं कि झुन्झुनूं में पहले गवर्नमेंट कालेज ही नहीं था। आपके पिलानी में तो बिरलाओं के थे। मैं 1998 में मिनिस्टर बना, सौभाग्य से खेतड़ी खुला, झुन्झुनूं में गर्ल्स कालेज खुला और सभापति महोदय, वुमैन एजुकेशन में झुन्झुनूं जिला पूरे राजस्थान में नम्बर वन पर है, मेल एजुकेशन में नम्बर टू पर है। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा में रिजर्वेशन का बहुत बड़ा रोल है। मैं 1998 में उच्च शिक्षा मंत्री था, तब मुख्य मंत्री जी ने कहा और रिजर्वेशन का बिल मुझे पेश करना था। हमारे मंत्रिमण्डल की मीटिंग में मैंने हमारे अधिकारी को बुलाया और उससे पूछा कि एससी का रिजर्वेशन कितना है? मैं सारे हाउस को बताना चाह रहा हूं। माननीय मंत्री जी आप विराजे हैं, कल्ला साहब विराजे हैं। सभापति महोदय, 1998 की बात है। मैंने लिस्ट उठाकर देखी, एससी का रिजर्वेशन 8 परसेंट था, 1947 से लेकर 2008 तक एससी का रिजर्वेशन 8 परसेंट था। एसटी का रिजर्वेशन 6 परसेंट था। ओबीसी का कोई रिजर्वेशन नहीं था। एमबीसी का तो था ही नहीं। मैंने हमारे अधिकारियों को बुलाया। हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हायर एजुकेशन थे and I said, this reservation is directly proportional to the population. आपने 1947 से लेकर आज तक ध्यान ही नहीं दिया कि क्या होगा। अब कितनी पापुलेशन हो गई है, साहब, डबल तो हो ही गई है।

सभापति महोदय, मैंने मेरे पैन से लिखा कि 8 परसेंट को बढ़ाकर 16 परसेंट एससी का रिजर्वेशन कर दिया जाये। सभापति महोदय, एसटी का रिजर्वेशन 6 परसेंट था, आप रिकार्ड उठाकर देखें, मैंने उसको 12 परसेंट किया। ओबीसी का 21 परसेंट करने की दिल्ली में कार्यवाही चल रही थी। उस समय एमबीसी रिजर्वेशन के मैटर्स नहीं आये।

(श्री जितेन्द्र सिंह)

दूसरे दिन हाउस में रखा। कांग्रेस सरकार को सारा फायदा मिला। मैं नहीं जानता, हमारे बहुत से एससी, एसटी वालों को पता भी है या नहीं। 1998 में हमारी सरकार दुबारा आई।

सभापति महोदय, एमबीसी के आरक्षण का मैटर चला। सभापति महोदय, मैंने 2007 में दूसरा जलियांवाला बाग़ देखा राजस्थान के अन्दर। लाखों की भीड़, जिसने एमबीसी के लिए रिजर्वेशन मांगा था। पुलिस की गोली से 74 बच्चे भून दिये गये। उनका कसूर इतना था कि उन्होंने अपने लिए आरक्षण मांगा था।

सभापति महोदय, मैं बूंदी का प्रभारी था। मैं सवाई मानसिंह हास्पिटल के मुर्दाघर के बाहर खड़ा था। एक लड़की अपने पिता के साथ आई और उसने कहा कि, डाक्टर साहब, आपने मेरे भाई को देखा क्या? मैं बून्दी का प्रभारी था, मैं उनको जानता था। मन्दिर में घुस-घुसकर गोलियां मारीं। सभापति महोदय, देवनारायण के मन्दिर में घुस-घुसकर गोलियां मारीं। मैं उस लड़के सुरेन्द्र को जानता था। मैंने कहा, बेटा मैं देखता हूं। सभापति महोदय, मैं अन्दर गया तो बर्फ की सिल्ली पर छह फीट के गोरे-चिट्टे सुरेन्द्र की नीली जीन्स में लाश पड़ी थी। मेरे पास शब्द नहीं थे। मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन माता-पिता का यह फर्ज होता है कि बेटे की बात सुनें, बेटे का सर कलम न करें।

मैं अशोक गहलोत को धन्यवाद दूंगा, इसलिए नहीं कि हमारे मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने सुनी, मैं 2009 में मंत्री था, मैं उनके चैम्बर में गया। गहलोत साहब चैम्बर में घूम रहे थे। मैंने कहा, सर, ऐसे कैसे घूम रहे हो। भाई, तुम्हारे भाइयों ने ट्रैक रोक रखे हैं, हाईवे 20 दिन से बन्द हैं। मैंने कहा, साहब, उनसे बात करो। उन्होंने कहा, मंत्री जी, वे तो कहते हैं कि ट्रैक पर आकर अशोक गहलोत हमसे बात करें। मैंने कहा कि, साहब अशोक गहलोत क्यों बात करेंगे, डा. जितेन्द्र सिंह जायेगा। मुख्य मंत्री जी ने कहा, डाक्टर साहब, आप जाओगे। वहां पर फैनेटिक क्राउड बैठी है, एक लाख। मैंने कहा, साहब, यह मेरी जिम्मेदारी है। अगर मेरे समाज से जुड़ा हुआ मामला नहीं भी होता तो भी आप भेजते हैं, यह तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मैं जाकर समझाऊं।

सभापति महोदय, मैं दूसरे दिन रेलवे ट्रैक पर गया। मैं नीचे उतरा तो एडिशनल डीजी परमदीप सिंह खड़े थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। डाक्टर

(श्री जितेन्द्र सिंह)

साहब, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मैंने कहा, क्यों नहीं जाने दोगे? भाई, मैं तो वार्ता करने आया हूं। वे बोले, डाक्टर साहब, एक लाख की भीड़ को कहां रोकूंगा। वहां तो चम्बल के डकैत भी एसएलआर लेकर बैठे हैं। हम आपकी सुरक्षा कैसे करेंगे? आप सरकार के प्रतिनिधि हैं। मैंने कहा, मैं जाऊंगा।

सभापति महोदय, मैं वहां गया। वहां जाकर सब समझाया। मैंने कहा, आप वार्ता नहीं करोगे तो काम कैसे बनेगा, आप वार्ता करिये। कर्नल साहब ने कहा, डाक्टर साहब, आरक्षण नहीं दिलाया तो मैंने रेजिग्नेशन जेब से निकाला। मैंने कहा, कर्नल साहब, मैं भी आपके साथ आकर बैठ जाऊंगा, तो निरुत्तर हो गये। मैंने कहा, आप दो दिन का वक्त दें। इतनी देर में मेरे साथ जो सिविल ड्रेस में पुलिस वाले थे उन्होंने कहा, डाक्टर साहब, तुरन्त मूव करें। वे सामने जो 12 लोग आ रहे हैं, उनमें डकैत हैं। उनके पास एके 47 राइफल्स हैं। हम आपको बचा नहीं सकेंगे। मैं मूव करने लगा तो वहां पर बीबीसी की संवाददाता खड़ी थी, उसने मेरे आगे माइक किया, उसने कहा, well Minister, how could you dare enter the fanatic crowd? मैंने हंसकर कहा, मैडम, शेर की मांद में शेर ही घुस सकते हैं और कौन यहां जायेगा।

सभापति महोदय, धन्यवाद दूंगा मुख्य मंत्री जी का, पांच परसेंट आरक्षण किया। सभापति महोदय, उसी वक्त ईबीसी का भी 15 परसेंट आरक्षण किया था माननीय अशोक गहलोत ने, लेकिन वह बाद में टर्न डाउन हो गया हाई कोर्ट के अन्दर, क्योंकि 50 परसेंट से ऊपर का प्रतिबंध था।

सभापति महोदय, आज उस रिजर्वेशन का फायदा हजारों बच्चे, हर क्लास, एससी-एसटी के डबल बच्चे मेडिकल में आ रहे हैं, अनेक इंस्टीट्यूशंस में आ रहे हैं। हमारे बच्चे आ रहे हैं। घूंघट निकाले हुए एक महिला खड़ी और एक लड़की आई, पांव छुए और बोली, डाक्टर साहब, मुझे जानते हो। मैंने कहा, बेटा मैं नहीं जानता हूं। मेरा आरएएस में चयन हुआ है ये मेरी मां हैं, ये मेरे पिताजी हैं। साधारण परिवारों के बच्चे आज रिजर्वेशन से समकक्ष आ रहे हैं। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि यह राजस्थान में क्रान्ति होगी, हर सब्जैक्ट के अन्दर।

कल्ला साहब ने सैकण्डरी एजुकेशन में बहुत लोंग इनिंग खोली है। 1980 में एजुकेशन मिनिस्टर बने, बहुत अच्छा काम किया। डोटासराजी नहीं हैं, उन्होंने इंग्लिश स्कूलें खोली हैं। 3600 स्कूल, आज से 35 साल पहले मैं

(श्री जितेन्द्र सिंह)

जीता, शिवचरण माथुर चीफ मिनिस्टर थे। मैंने कहा, साहब, लायल की स्कूल को सैकण्डरी स्कूल बना दें। मैंने सैकण्डरी बना दी और गांव नाच रहा था। आज एक साथ एक पैन से 3600 स्कूल 10+2 खुल गई।

सभापति महोदय, आप भी जानते हैं, आप तो आईएएस आफिसर रहे हैं। English is very important. हमारे फोर्मर एजुकेशन मिनिस्टर बोल रहे हैं, महात्मा गांधी अंग्रेजी नहीं जानते थे। वे तो अफ्रीका के अन्दर बैरिस्टर थे, क्या बैरिस्टर अंग्रेजी नहीं जानते हैं क्या? सभापति महोदय, मैं मेडिकल में हूं, आईआईटी के बच्चे, आप आईएएस आफिसर हो, अंग्रेजी हमारे पूरे वर्ल्ड की लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अंग्रेजी इस बात के लिए नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपको वाकया सुनाऊं। हमारे मेडिकल में रिटन और प्रैक्टिकल में अलग-अलग पास होना पड़ता है। हमारे खेतड़ी का लड़का था, उसके रिटन में 98 परसेंट थे। हमारे जैकब थी, she was a Jewish doctor. इजराइल से जब हुआ था, उस वक्त डा. हैलिगन जैकब आ गई थी। डा. हैलिगन जैकब, वह अंग्रेजी में बोली, वह अंग्रेजी में जवाब नहीं दे सका। उसको फेल कर दिया, पचास में से जीरो। मेरा रूम मैट जैकब मैडम के पास गया। मैडम, इसको आपने कैसे फेल कर दिया? बोली, इसने जवाब नहीं दिया होगा। उन्होंने मार्कशीट दिखाई। मैडम, इसके प्रैक्टिकल 100 में से 98 नम्बर आये हैं। आप अंग्रेजी में बोलने लगीं, यह गांवड़ा है, यह अंग्रेजी नहीं जानता है। उसने कहा, आई एम सोरी, भाई। अंग्रेजी की आवश्यकता तो यों है। कोरोनरी आर्टरी है, आप उसको पता नहीं हिन्दी में क्या-क्या बोलेंगे। आज इंग्लिश स्कूलें दो हजार खोली हैं, फिर दो हजार खोल दीं, चार हजार हो गईं।

सभापति महोदय, आप तो पिलानी के हैं, आपके वहां इंस्टीट्यूशंस हैं, बिड़लाओं की बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है। हमारे बच्चे भर-भरकर नारनौल में जाते हैं, चालीस-चालीस बसें खड़ी रहती हैं। बच्चों की एक-एक लाख रुपये फीस है। आज यहां इंग्लिश स्कूल खुल गई, बच्चों की भीड़ लगी। सभापति महोदय, मैं समझता हूं, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा।

माननीय सभापति महोदय, साधारण परिवारों के बच्चे, मेरे खुद खेतड़ी के, जो इसरो है, अहमदाबाद, उसके हैड आफ दी डिपार्टमेंट डा. राम रतन खेतड़ी के हैं। नम्बर टू, इसरो, बैंगलोर, उसके एचओडी डा. सुरेन्द्र पाल हैं। साधारण परिवारों के बच्चे हैं। डा. राम रतन तो जब दिल्ली में पढ़ते थे,

(श्री जितेन्द्र सिंह)

सभापति महोदय, उनके पास एक कुर्ता-पाजामा और एक थैला था। प्रेस के पैसे नहीं होते थे, मोड़ कर तकिये के नीचे लगा लेते थे और आर्यभट्ट से लेकर जितने सैटेलाइट गये सबके आप्टिक्स का काम डा. राम रतन ने ही किया और जो डा. सुरेन्द्र पाल थे, जितने सैटेलाइट गये जिसमें हमारी कल्पना चावला भी शहीद हुई, वह तो खैर कल्पना चावला जिस सैटेलाइट में गयीं वह तो यूएसए में बना था लेकिन इंडिया में जितने सैटेलाइट बने, हम गये थे बेंगलोर, हम और हमारे साथी, वहां सम्मेलन था 1998 में, उन्होंने ले जाकर सैटेलाइट किस तरह से बनते हैं, हमको बताया। हमको बाकायदा स्टरलाइज करके ले गये वहां पर। यह साधारण परिवारों के निकल-निकल कर आज किन बुलंदियों पर, ऊंचाइयों पर पहुंचे, आप कल्पना कर सकते हैं। It is simply education.

माननीय सभापति महोदय, हमारे झुन्झुनूं जिले में इंडियन आर्मी का करीब 10 परसेंट, करीब एक लाख फौजी हैं। मेरे अकेले विधान सभा क्षेत्र में 15 हजार फौजी हैं और 100 हमारे मोर्टियर्स हैं शहीद हो गये। अधिकारी नहीं हैं। हमारे लेफ्टीनेंट जनरल कटेवा से मैं मिलने गया, चिड़ावा के हैं आप। मैंने कहा, कटेवा साहब, आप बताइये जहां एक लाख फौजी हों वहां जनरल कटेवा एक निकल कर लेफ्टीनंट जनरल बन रहा है क्या, बाकी के हमारे बच्चों का क्या होगा? उनको शिक्षा चाहिये अधिकारी बनने की और अब तो नयी सरकार ने यह अग्निवीर और बना दिया चार साल का। बच्चों का भविष्य अंधकारमय कर दिया।

सभापति महोदय, मैंने प्रयास किये थे। आज पंजाब में और साउथ में इसलिये आर्मी आफिसर आते हैं कि वहां स्कूल में मिलिट्री साइंस सब्जेक्ट है। माननीय कल्ला साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे एक लाख फौजी हैं झुन्झुनूं में, हजार भी डाइरेक्ट रिक्रूटेड आफिसर नहीं होंगे। उसका रीजन है कि हमारे वहां पर उनका गाइडेंस नहीं है। पंजाब में और साउथ में, कर्नाटक और तमिलनाडु में स्कूल में ही मिलिट्री एजुकेशन सब्जेक्ट है और मिलिट्री एजुकेशन सब्जेक्ट से, सभापति महोदय, गाइड लाइन मिल जाती है और वो सीधे के सीधे खड़गवासला और उनमें सलेक्ट हो जाते हैं। माननीय कल्ला साहब, आपसे मेरा आग्रह है कि मिलिट्री साइंस सब्जैक्ट, मैंने भी कोशिश की थी, मैं उच्च शिक्षा मंत्री रहा दो बार, मैंने प्रयास किये थे लेकिन मैं समझता हूं, it is too late, लेकिन फिर भी आप प्रयास करें इसमें कि

(श्री जितेन्द्र सिंह)

मिलिट्री साइंस जैसा सब्जैक्ट होना चाहिये एजुकेशन में और वह निश्चित रूप से हमारी जो नैक्स्ट जनरेशन है उसके लिए बहुत बड़ा लाभप्रद होगा। यह बताना चाहूंगा मैं।

सभापति महोदय, दूसरा, हमारे कालेजेज के लड़के आज कोटा कोचिंग हब है, आपका सीकर बहुत बड़ा, पारीक साहब बैठे हैं, सीकर बहुत बड़ा एजुकेशन हब बन गया लेकिन एक-एक लाख रुपया खर्च होता है, सभापति महोदय। मैंने मेरे वक्त में प्रयास किया था, मैं माननीय मंत्री महोदय से फिर आग्रह करना चाहूंगा कि जो कालेज एजुकेशन में हमारे टीचर्स एक्स्ट्रा क्लास लेकर और वहां कोचिंग अगर कालेज में ही प्रारम्भ करें आईआईटी और पीएमटी की तो मैं समझता हूं कि बच्चों को सस्ते लेवल पर कालेज के कालेज में अलग से उनको कोचिंग मिलने की सम्भावना रहेगी। कालेजेज सरकार ने बहुत खोल दिये, माननीय मंत्री जी बैठे हैं यहां पर, कालेजेज बहुत बड़ी संख्या में खुल गये। आज स्कूल्स की यह पोजिशन है कि आज पूरे राजस्थान के अन्दर मोर देन 72,000 स्कूल्स हैं। करीब हमारे 92 लाख, मैं नहीं जानता वो डाटा कहां से लाये लेकिन 92 लाख 30 हजार 458 बच्चे हैं, वह कम नहीं है, उनका जो वो बता रहे हैं रिकार्ड कि, साहब, उनका गिरा है। अलग से चार लाख से बड़ा स्टाफ है टीचर्स का तो इन्फ्रास्ट्रक्चर उनका ठीक है।

माननीय सभापति महोदय, बहुत लम्बी बात नहीं कहनी है, मैं समझता हूं कि बहुत सारे साथियों को बोलना है। गांवों के बच्चे कितने प्रतिभाशाली हैं, यह मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं पहले हायर एजुकेशन पर आया, फिर एजुकेशन पर, अब हमारे नर्सरी एजुकेशन पर। हमारे बच्चों को सब ये ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन कितना खतरनाक है, सभापति महोदय, यह मायोपिया बना रहा है। बच्चों के इतने मोटे-मोटे ग्लास 6-6 साल में लग रहे हैं। अंधा बना कर छोड़ देगी यह ऑनलाइन स्टडीज। उनको आउट साइड के स्पोर्ट्स खेलने की आवश्यकता है। मैं नहीं जानता, ऑनलाइन सब पढ़ते हैं, ऑनलाइन का फायदा भी है।

मैं चारावास गया था, आप तो पधारे थे चारावास में, धन्यवाद आपको। वहां एक लड़की आयी, पांव छुए। एक बुजुर्ग सफेद साफा बांधे थे, उसने कहा कि डा. साहब मेरी लड़की दिल्ली की परीक्षा में खूब नम्बर लायी है। मैंने कहा कि, बेटे, दिल्ली की कौन सी परीक्षा में, तो उसने कहा, सर, मैं आईएएस में इंडिया में 41वीं रैंक पर आयी हूं। मैंने पूछा, बेटा तू कहां पढ़ी,

(श्री जितेन्द्र सिंह)

उसने बताया कि मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं हैं, मैं तो ऑनलाइन पढ़ रही थी। प्रतिभाओं की कमी नहीं है, सभापति महोदय, उनको मौका मिलना चाहिये और निश्चित रूप से आज बच्चे इसके अन्दर आगे आ रहे हैं। एक शायर ने शेर कहा है, ''मेहनत से उठा हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं। आसमां से ज्यादा जमीं की कद्र जानता हूं। लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधियां, मैं मगरूर दरख्तों का हश्र जानता हूं।'

सभापति महोदय, सब कुछ मिला और मैं समझता हूं कि इस हाउस ने जो मैग्जीमम दे सकते थे 6 बार विधायक बनाया, मंत्री बनाया दस वर्ष तक, यह कम नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूं इस हाउस का जिन्होंने इन बुलंदियों पर पहुंचाया और मैं अन्त में एक बात कहना चाहूंगा, हमारे मंत्री जी चले गये यहां से, 21 हजार स्कूलें राजस्थान की जिन बच्चों को, जो पूर्व मंत्री जी हैं...

श्री सभापति: बैठे हैं।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी): उधर बैठ गये आप। सुन लीजिये आप। मंत्री जी, कृपया सुन लीजिये। पूर्व मंत्री जी, मेरी इधर से स्लिप होते ही आप तक बात जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने अपने समय में 21 हजार स्कूलें हमारी बन्द कर दीं, बच्चों पर कुठाराघात किया, गरीबों के बच्चों को बाहर निकलने का मौका मिला।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आपने खोली क्या? यह बताओ।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी): खोल रहे हैं, साहब। धीरे-धीरे खुल रही हैं और सुन लो, बाद में आप भाषण में बोल लेना।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 21 हजार तो मान लिये, लेकिन यह 1,200 केवल क्या है?

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी): कुछ तो खोल रहे हैं। माननीय राजीव गांधी जी का नाम था स्कूलों में, माननीय राजीव गांधी जी का नाम ही हटा दिया। आप बताइये राजीव गांधी जी का नाम था, बाद में बता देना।

सभापति महोदय, मैं अन्त में आपको बता रहा हूं, मैं 1998 में संचार मंत्री था। हमारी दिल्ली में मीटिंग थी। अटल बिहारी वाजपेयी की मैं तारीफ करूंगा इस हाउस में कि कितनी इम्पार्शियल पर्सनेलिटी थी वह। मैंने जब उनको बताया कि राजस्थान में पत्रकार/साहित्यकार तो हैं नहीं, हम यहां उनको जयपुर में 45-45 रुपये में जमीनें दे रहे हैं, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन दे रहे हैं,

(श्री जितेन्द्र सिंह)

उनके लिए फ्री में मेडिसिन का इंतजाम कर रहे हैं। पत्रकार/साहित्यकार कल्याण कोष बना रहे हैं। मैंने सब दिया, मैं बोला। लंच में मेरे पास स्लिप आयी कि प्रधान मंत्री जी आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैं गया, मैंने अपने राजस्थान का उनको लैटर बनाकर सारा बताया। मैं वापस लौट आया। पन्द्रह दिन बाद मेरे पास लैटर गया कि इंडिया की जो संचार कमेटी है उसमें उन्होंने मुझे नियुक्त कर दिया। वह थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी जो ऐसे इम्पार्शियल पर्सनेलिटी थी। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि, डाक्टर साहब, आप तो कांग्रेस के थे, अटल जी ने आपको कैसे बना दिया। आपके ऐसे प्रधान मंत्री भी थे, जिनकी तारीफ करने की है, तारीफ करूंगा। (व्यवधान) अब यह तो वक्त बतायेगा। सभापति महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि

"चलते रहे कदम तो किनारा जरूर मिलेगा,
जुड़ते रहे हाथ तो लोगों का साथ जरूर मिलेगा, जो राहुल जी ने कहा,
आज बढ़ेंगे सबका साथ लेकर, हमको किनारा जरूर मिलेगा।"

धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति: श्री सुभाष पूनिया।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): माननीय सभापति जी, मांग संख्या-20, 21 और 22 पर आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। सभापति जी, आप और हम जिस जिले से आते हैं, वह निश्चित रूप से इस प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी जिला है। महिला शिक्षा में तो अपना अव्वल हैं ही, लेकिन मेल में दो नंबर पर हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस शिक्षा के माध्यम से ही आज पूरे प्रदेश के हर कोने में, हर ब्लाक में हमारे यहां से अध्यापक भी हैं, एएनएम भी हैं, अन्य अधिकारी भी हैं। यह सारा श्रेय शिक्षा को जाता है लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि इतना कुछ होते हुए भी जब विद्यालयों में जाते हैं तो स्कूल की हालत देखते हैं कि वहां के भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं, हर बार हम कहते आ रहे हैं। और तो और, जब किसी विद्यालय में जाते हैं तो वहां शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी नहीं है। स्कूलों की हालत पर एनुअल स्टेटस आफ एजुकेशन रिपोर्ट, 2022 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि देश के एक चौथाई स्कूलों में पेयजल तक नहीं है और राजस्थान में तो उससे भी कहीं

(श्री सुभाष पूनिया)

ज्यादा हालत खराब है। जिस प्रदेश में और झुंझुनूं जैसे जिले में स्कूल में पेयजल की व्यवस्था नहीं है, इससे ज्यादा और शर्म की बात क्या होगी? आज हम कहां हैं, इसके बावजूद भी आज पेयजल की व्यवस्था नहीं है। कई स्कूल में बिजली के कनेक्शन नहीं हैं, बात हम कम्प्यूटर की कर रहे हैं। बैठने के लिए जगह नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जिन भी विद्यालयों में बिजली कनेक्शन नहीं हैं, हमारे जिले में उनमें अतिशीघ्र कनेक्शन किये जाएं। और तो और, आज विद्यालयों में शौचालयों की क्या हालत है, पृथक् शौचालय नहीं है। लड़कियों के लिए अलग से शौचालय होने चाहिये।

मुझे याद है घड़साना में जब सीडीएस रावत के साथ कुलदीप राव शहीद हुए थे, तब सारे नेतागण वहां पधारे थे, मंत्री भी थे। तब वहां पास में एक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है, लंबा-चौड़ा विद्यालय है। जब हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने लघु शंका के लिए टायलेट के लिए पूछा तो टायलेट पर ताला लगा हुआ था और दूसरा टायलेट जो खुला हुआ था, वह जाने लायक नहीं था। यह हालत आज हमारे विद्यालयों की है। सभापति महोदय, हमारे शिक्षा मंत्री जी वास्तव में भले हैं, मैं चाहूंगा कि वह इस ओर ध्यान देंगे, यह मेरा आपसे आग्रह है। कई शौचालय तो ऐसे हैं जहां शौचालय तो बन गये हैं लेकिन उनमें पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी का कनेक्शन नहीं है। मैंने कहा है कि जब पेयजल के लिए ही वहां छात्र तरसते हैं तो शौचालय के लिए पानी की व्यवस्था कहां से होगी।

आपने खूब विद्यालय क्रमोन्नत किये, इसके लिए सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद, लेकिन क्या क्रमोन्नत के बाद वहां कोई विषय खोले गये और जहां विषय हैं, वहां सब्जेक्ट टीचर नहीं हैं, तो छात्रों को क्या पढ़ायेंगे? मैं समझता हूं कि आपने केवल वाहवाही लूटने का काम किया है कि हमने हजारों विद्यालयों को क्रमोन्नत किया है, लेकिन वह क्रमोन्नत होने के बाद भी छात्रों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। मंत्री जी विराजे हुए हैं, मैं कहना चाहूंगा कि आप उनमें जल्दी ही सब्जेक्ट टीचर लगाकर छात्रों को लाभान्वित करें।

एक सबसे बड़ी कमी है कि विद्यालय हैं, लेकिन वहां खेल मैदान नहीं हैं। जिन विद्यालयों में खेल मैदान हैं, वहां गांव वालों ने अतिक्रमण कर रखे हैं। कई बार अधिकारियों को कहने के बावजूद भी कोई न कोई फोन कर देता है कि मेरे वोट नहीं टूट जाएं, खेलों के मैदानों पर अतिक्रमण हो रहा है, बड़ी

(श्री सुभाष पूनिया)

शर्म की बात है। कम से कम उन खेल मैदानों को तो अतिक्रमण से मुक्त करवाएं। यह भी मेरा आग्रह है।

मिड-डे मील की हालत तो आपने देखी होगी। पिछले दिनों की एक खबर थी, उसमें साफ लिखा हुआ है कि पोषाहार पशुओं को दिया जा रहा है। इसलिए दिया जा रहा है कि वह पोषाहार नहीं, पशु आहार है। बच्चे बीमार न हो जायें, इसलिए ग्रामीणों ने जानवरों को डाला है, यह हालत पोषाहार की है। इसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है।

आपने अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खूब खोले हैं। हम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध हो, यह आपका मानस है क्या? वहां अभी तक स्थायी स्टाफ की नियुक्ति नहीं हुई है। मेरा आपसे आग्रह है कि पृथक् कैडर का निर्माण कर सीधी भर्ती से पद भरे जाएं तो निश्चित रूप से इन विद्यालयों का खोलने का कोई फायदा मिलेगा।

उच्च शिक्षा में आपने खूब कालेज खोले हैं और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि मैंने मांग की थी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो कालेज खुलने चाहिये। एक सूरजगढ़ में खुल गया, एक बुहाना में खुल गया। सूरजगढ़ में हमने जमीन उपलब्ध करवा दी है, बजट भी यहां से अलाट हो गया है, लेकिन आज तक वह भवन शुरू नहीं हुआ है तो क्या फायदा? छात्रों के लिए वहां कोई बुनियादी सुविधाएं तो हैं ही नहीं। किराये के भवन में वह चल रहा है और फर्नीचर है नहीं। मैं चाहूंगा कि बहुत जल्द वह भवन बने तो उसका फायदा होगा। बुहाना और सूरजगढ़, दोनों जगह कालेज में बच्चे तो खूब आये, लेकिन वहां लेक्चरर नहीं हैं। क्या इसी तरह से कालेज चलेंगे? एजुकेशन के मामले में झुंझुनूं जिले को कम से कम बिहार न बनायें, यह भी मेरा आपसे आग्रह है कि बहुत जल्द इसके लिए आप कोई व्यवस्था करें।

मैं कोई ज्यादा लंबी-चौड़ी बात नहीं कह कर एक बात जरूर कहूंगा कि जिस तरह से शिक्षा माफिया इस प्रदेश में हावी हुआ है, वह बहुत शर्म की बात है। आज राजस्थान प्रदेश पेपर लीक के मामले में इस देश में नंबर वन पर है। मैं यह नहीं कहता कि और प्रदेशों में नहीं हुए होंगे, लेकिन जिस तरह से सवा चार साल के कार्यकाल में जितने पेपर लीक हुए हैं, आप इस शिक्षा माफिया पर, जिन्होंने यह कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रखे हैं, इन पर सख्त कार्यवाही करके इन पर ध्यान देने की जरूरत है। यही मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जगदीश चन्द्र।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): सभापति महोदय, धन्यवाद। मांग संख्या 20, 21 और 22 पर आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर पहली दफा जो शिक्षा में बदलाव हुआ है वह ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। मुझे इस बात को कहते हुए गर्व है और खुशी भी है। सभापति महोदय, हमारे शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में एडमिशन का रेशो 20 परसेंट बढ़ा है। जिन सरकारी स्कूलों की कल्पना इस सरकार ने की थी और मुख्य मंत्री जी की मंशा थी एवं शिक्षा मंत्री जी की मंशा है कि हमारे सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतरीन स्कूल हों, कान्वेंट स्कूलों से अच्छे स्कूल हों, जिस शुरुआत से जो नवाचार राजस्थान के एजुकेशन सिस्टम में किया है, वह निश्चित तौर पर काबिल-ए-तारीफ है।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने शिक्षा में बदलाव के लिए जो ऐतिहासिक पहल 2018 में शुरू की थी, आज वह जमीन के ऊपर दिखायी दे रही है। हमने पहली दफा यह फैसला किया कि इस प्रदेश के जो तमाम सरकारी स्कूल हैं, उनके आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाये। कहीं स्टाफ की कमी है तो स्टाफ की भरपाई की जाये। उसके लिए भी सरकार बनने के साथ ही थर्ड ग्रेड के 25 हजार टीचर्स की भर्ती की, सैकण्ड एवं फर्स्ट ग्रेड की भर्ती प्रक्रियाधीन है। पहली दफा सरकार की मंशा इससे जाहिर होती है कि 62 हजार टीचरों की भर्ती की प्रक्रिया सरकार के तहत प्रक्रियाधीन है, आने वाले दिनों में हम भर्ती करके सारे स्टाफ की कमी पूरी करेंगे।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं। एक समय 2013 से 2018 का समय था, पिछले पांच साल की जो सरकार थी, हमारे साथी बैठे हैं, मैं चर्चा करना चाहूंगा कि शिक्षा का राजस्थान में क्या हाल था? शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन किसने किया था? यह हमारी सरकार ने नहीं किया। अगर आप पीछे जाओ और थोड़े दिल्ली की तरफ दौड़ो, अभी जो भारत सरकार ने यूनियन बजट पेश किया है, उस यूनियन बजट की यदि राजस्थान के बजट से तुलना करें तो उस हिसाब से उस प्रपोर्शनेट एरिये में बहुत कम बजट भारत सरकार ने दिया है। भारत सरकार ने पहली दफा शिक्षा के बजट को कम किया है, जो कि गैर-वाजिब है, जो कि सरकार को नहीं करना चाहिए।

(श्री जगदीश चन्द्र)

डा. भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पीयेगा, उतना दहाड़ेगा।। उनके सपनों को साकार करने के लिए ये लोग भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं, लेकिन शिक्षा की दृष्टि से हायर एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन में, माध्यमिक शिक्षा की एजुकेशन में जो पैसा कम किया है, वह बिलकुल चिन्ता की बात है।

मैं आपसे यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि भारत सरकार द्वारा आरडी सैक्टर में जो रिसर्च का कंसेप्ट था, उसको भी करीब-करीब खतम करने की बात आ रही है। अभी अजमेर से आने वाले हमारे साथी नयी शिक्षा नीति की बात कर रहे थे, शिक्षा के मंत्री भी रह चुके हैं। अगर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार की शिक्षा की नीति को देखेंगे तो आपको समझ में आ जायेगा कि केन्द्र के क्या मंसूबे हैं? केन्द्र सरकार शिक्षा नीति में किस प्रकार का बदलाव करना चाह रही है? ये मंसूबे जानना बहुत आवश्यक है।

सभापति महोदय, पिछले चार साल में हमने ऐतिहासिक परिवर्तन किये हैं। गांव और देहात के अन्दर हर आदमी और गरीब का बच्चा, हर किसान का बच्चा अंग्रेजी की पढ़ाई करना चाहता है, तो राइट टू एजुकेशन का अधिकार डा. मनमोहन सिंह ने इस देश के अन्दर दिया था। उसकी पूरी पालना करने के लिए राजस्थान सरकार के मुखिया ने इस बात को महसूस किया कि जो गांव का बच्चा आगे बढ़ना चाह रहा है, उसको वे सारे अवसर मिलने चाहिए, जो दिल्ली के एक बच्चे को मिलते हैं, जो गंगानगर के बच्चे को मिलने चाहिए, झुंझुनूं के बच्चे को मिलने चाहिए। उस कल्पना को साकार करने के लिए राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने पहली बार 11 हजार 500 ग्राम पंचायतों पर अंग्रेजी स्कूलों की शुरुआत करने की कोशिश की है। बच्चा पूरी जिन्दगी भर महसूस करता है, पूरी जिन्दगी भर कुंठा रहती है कि मेरे मां-बाप के पास पैसा नहीं था, मैं अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं कर पाया। इसको महसूस किया गया, उसमें हमने एक नया कदम उठाया है। एक नवाचार स्टार्ट किया। आज राजस्थान के अन्दर 1700 से ज्यादा अंग्रेजी के स्कूल शुरू हो गये हैं। इस साल करीब-करीब एक हजार गांवों में और एक हजार शहरों में नये अंग्रेजी के स्कूल हम लोग खोल रहे हैं। सभापति महोदय, माननीय बी डी कल्ला साहब बैठे हैं। मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि अंग्रेजी मीडियम के स्कूल के साथ-साथ अंग्रेजी के महत्व को समझते हुए सही मायने में अंग्रेजी भाषा क्या है, उसके लिए 10 हजार टीचर्स की भर्ती का प्रावधान भी हमने रखा है।

(श्री जगदीश चन्द्र)

अलग से सैक्टर बनाने की बात की है। मैं बी.डी. कल्ला साहब को धन्यवाद करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, जब राजीव गांधी देश के प्रधान मंत्री थे, तब इस देश में कम्प्यूटर आया था तो कुछ लोगों एवं कुछ विपक्षी पार्टियों ने पूरे देश में हल्ला मचाया था कि कम्प्यूटर आ जायेगा तो देश में बेरोजगारी फैलेगी। आज उसी कम्प्यूटर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल वही लोग कर रहे हैं, जिन्होंने उस जमाने में विरोध किया था, जिन लोगों ने राजीव गांधी का कम्प्यूटर साइंस के लिए विरोध किया था। राजीव गांधी का एक सपना था कि भारत 21वीं शताब्दी में जा रहा है, 21वीं शताब्दी का मायना यह नहीं है कि परमाणु की शताब्दी होगी, 21वीं शताब्दी, शिक्षा की शताब्दी होगी। जिस देश के बच्चों का एजुकेशन का लेवल ठीक होगा, बच्चों में कांफिडेंस आयेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, निश्चित तौर पर दुनिया में वही मुल्क आगे जायेगा। उसी कल्पना को साकार करने के लिए राजीव जी कम्प्यूटर साइंस भारत में लेकर आये थे। आज हर आदमी इस्तेमाल कर रहा है। हम लोग भी कर रहे हैं, ये लोग भी कर रहे हैं। इन्होंने तो कम्प्यूटर साइंस के माध्यम से दो चुनाव जीत लिए हैं। कम्प्यूटर एवं आईटी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करके इन लोगों ने दो चुनाव जीत लिए हैं। इसलिए कांग्रेस की भारत सरकार की जो नीति थी, डा. मनमोहन सिंह ने इस देश में पहली बार 'शिक्षा का अधिकार' का कानून दिया। एक सामाजिक अधिकार को कानूनी रूप दिया है, जिसमें प्रावधान किया है कि इस देश के प्रत्येक बच्चे को पढ़ने का अधिकार होगा। मैं इस बात के लिए भारत की यूपीए की सरकार को धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने यह भी महसूस किया है कि राजस्थान के गांव व देहात के बच्चे हैं, सरकारी स्कूलों में बड़े लोगों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, गांव के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, वर्दी का भी अभाव होता है, खाने की दिक्कत होती है। इसलिए मुख्य मंत्री जी ने एक सकारात्मक मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर यह फैसला किया है कि पहली क्लास से बारहवीं क्लास तक के बच्चों को हम किताबें फ्री देंगे, वर्दी भी फ्री देंगे और वर्दी के साथ-साथ 200 रुपये हम सिलाई के लिए भी दे रहे हैं, ताकि बच्चा महसूस करे। सरकारी स्कूल की वर्दी पहनकर जायेगा, अच्छे मन से पढ़ाई करेगा और

(श्री जगदीश चन्द्र)

उसके बाद उसके दूध की व्यवस्था भी की गयी है। पिछले बजट में हम सात दिन में दो दफा दूध दिया करते थे, अब पूरे सात के सात दिन मिलेगा।

सभापति महोदय, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए राजस्थान की सरकार ने लम्बे समय से पीटीआई के पद जो पद खाली पड़े हुए थे, शिक्षा विभाग इस बात को महसूस कर रहा था कि बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ खेल के भी संस्कार दिये जाने चाहिए। हमारी सरकार ने इसके लिए भी भर्ती की है।

मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान के अन्दर पहली बार ओलम्पिक की शुरुआत की है। 30 हजार लोगों ने पार्टिसिपेट किया, गांव के अन्दर वातावरण बना। जो बच्चे स्कूल के माध्यम से आगे नहीं बढ़ सकते थे, उनको आगे बढ़ने का एक मौका दिया गया और उसमें कामयाबी तथा सफलता भी मिली। आने वाले दिनों में हम शहरों में भी ओलम्पिक के टूर्नामेंट करा रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों के अन्दर जो टैलेंट है, जो स्पोर्ट्स का टैलेंट है, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारे 01 हजार स्कूल के आसपास जो बाल वाटिका प्रारम्भ की गयी हैं, जिसके तहत पूर्व प्राथमिक शिक्षा की सुविधा निजी स्कूलों के समान मिलेगी। गांव की सरकारी स्कूलों में एनुअल फंक्शन नहीं होते थे। बच्चे देखते रहते थे कि पूरे साल हमने जो स्कूल में सीखा है, उसको कहां पर प्रदर्शित करें। राजस्थान की सरकार ने शुरुआत करते हुए पहली दफा जो वार्षिक उत्सव का जो कार्यक्रम स्टार्ट किया है, उसके महत्वपूर्ण रिजल्ट आ रहे हैं। मैं जब गांवों के स्कूलों में जाता हूं, मैं लगातार जा रहा हूं, इस तरीके से बच्चों का जो दबा हुआ टैलेंट था, उसको आगे बढ़ने का मौका मिला है। गांव का बच्चा इस बात को महसूस करने लगा है कि वास्तव में सरकारी स्कूल जो कि हमारे दूसरे स्कूलों से बेहतरीन स्कूल हैं।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन सारे सदन के सामने करना चाह रहा हूं कि सरकारी स्कूल का जो टीचिंग स्टाफ है वह बेहतरीन स्टाफ है। एक पैरामीटर पास करके उसको सरकार की नौकरी मिलती है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस देश की प्रथम महिला भी सरकारी स्कूल की पढ़ी हुई हैं। इस प्रदेश के मुखिया भी सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं। इस सदन के जो स्पीकर हैं वे सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं और आपका विधायक भी सरकारी स्कूल का

(श्री जगदीश चन्द्र)

पढ़ा हुआ है। सरकारी स्कूल किसी भी मायने में कम नहीं हैं। यह जो भावना गांवों के अन्दर फैली हुई है, उसमें जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है कि सरकारी स्कूलों का प्रचार-प्रसार करें।

इस देश के अन्दर एक जमाना था, 31 सौ साल पहले, सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं मिलता था। इस देश के अन्दर यह गर्व की बात थी कि चाणक्य जैसे शिक्षक भी इस देश में ही पैदा हुए हैं, जिन्होंने एक गड़रिये को देश का राजा बनाया। शिक्षा के माध्यम से बनाया है। वह जो शिक्षा नीति थी, कोई जमाना था, जब इस देश के अन्दर फाहयान जैसे भी देश में शिक्षा के लिए आया करते थे। मुझे 2014 का याद है। मैं ब्रिसल में था। यूरोपीय यूनियन के कार्यक्रम में गया हुआ था। फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति ने मुझ से पूछा कि हिन्दुस्तान में एजुकेशन का सिस्टम क्या है? मैंने कहा कि आपने इस देश के सिस्टम को डिस्ट्रोय करने के लिए खूब कोशिश की। पहले ब्रिटिश ने किया, पुर्तगालीज ने किया, फ्रेंच ने किया, इसके बावजूद भी, inspite of that we have maintained our all traditions और हमारी शिक्षा का जो सिस्टम, हमने आज भी मेंटेन किया हुआ है। भारत में जो सरकारी स्कूल हैं खास तौर पर बेहतरीन स्कूल हैं। खासकर मैं राजस्थान की बात करूं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। इस बजट में हमने 8 हजार आंगनबाड़ियों का प्रावधान किया है और 2 हजार मिनी आंगनबाड़ी खोलने का प्रावधान किया है, ताकि गांव के सबसे गरीब के बच्चे को पढ़ाई का पूरा अवसर मिले और राइट टू एजुकेशन के अधिकार से वंचित नहीं हो। इस भावना के साथ में सरकार ने जो आंगनबाड़ी खोलने का फैसला किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाह रहा हूं।

सभापति महोदय, मुझे इस बात का अफसोस है कि 2016 से भारत सरकार ने आंगनबाड़ी केन्द्रों की कोई परमिशन हमें नहीं दी है। भारत सरकार ने आंगनबाड़ी केन्द्रों की परमिशन बन्द कर रखी है। इसके साथ-साथ एजुकेशन है, वह कान्करन्ट लिस्ट का इश्यू है। भारत सरकार समय-समय पर दखलंदाजी तो करती ही है, लेकिन भारत सरकार की जो 60-40 की स्पोंसर स्कीम है, उसमें भारत सरकार काफी रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रही है। जहां-जहां उनकी सरकारें नहीं हैं, वहां पर दिक्कत पैदा कर रहे हैं। हमारे पैसे को भी रोका जा रहा है। केन्द्र सरकार से जो फंड आता है, उसको भी रोका जा रहा है।

(श्री जगदीश चन्द्र)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि आरटीई के तहत कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा का प्रावधान, जिसमें 9 से 12वीं तक की समस्त राशि का भुगतान राज्य सरकार कर रही है। प्रदेश के विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज प्रारम्भ की गयी हैं, जिससे डिजिटल एजुकेशन को भी बढ़ावा मिला है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि यह पहला प्रदेश है हिन्दुस्तान का जहां बीए तक की पढ़ाई बिलकुल मुफ्त और खासकर हमारी जो बच्चियां हैं, जो हायर एजुकेशन लेना चाह रही हैं, 45 हजार रुपये बीए तक की पढ़ाई करने वाली को वजीफा राजस्थान की सरकार दे रही है। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने वाली बच्ची को भी 45 हजार रुपये वजीफा देने का प्रावधान मुख्य मंत्री जी ने बजट में किया है।

सभापति महोदय, पिछले बजट के दौरान माध्यमिक विद्यालयों को, 3820 विद्यालयों को हमने अपग्रेड किया है। 1000-1000 महात्मा गांधी स्कूल खोलने और अलग से कॉडर बनाने का भी निवेदन मैं आपसे कर चुका हूं। बालिका विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के लिए 1886 उच्च प्राथमिक स्कूलों को हमने प्रमोट किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि स्कूलों की जो दशा थी, बिल्डिंग्स की काफी कमी थी। भारत सरकार की तरफ से वर्ल्ड बैंक से जो पैसा आना था, नाबार्ड से जो पैसा आना था, उस पैसे में भी कमी की गयी है, उस राशि को घटाया गया है। नये जो कमरे बनने थे, नये जो भवन बनने थे, वह नहीं बन पाये। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जो यह नई शिक्षा नीति की बात करना चाह रहे हैं, नई शिक्षा नीति में नये भवनों की भी आवश्यकता पड़ेगी। हमने स्कूल अपग्रेड कर दिये, बच्चों की तादाद भी बढ़ गयी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार राजस्थान की तरफ ध्यान दे। 11,500 ग्राम पंचायतों में अभी स्कूल और खोलने की आवश्यकता है जिस पर सरकार काम कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि पहली दफा एक नया एक्सपेरिमेंट, नवाचार हमने राजस्थान में स्टार्ट किया। हमने अलग-अलग सब्जेक्ट्स खोले हैं। बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहां-जहां जिस सब्जेक्ट की आवश्यकता है, वह खोले गये हैं। मैं शिक्षा मंत्री जी का

(श्री जगदीश चन्द्र)

धन्यवाद करना चाहूंगा कि गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले के लिए जो पंजाबी बहुल क्षेत्र हैं, जहां पंजाबी की आवश्यकता थी, आपने आवश्यकता के आधार पर टीचर की भर्ती भी की है, आपने सब्जेक्ट भी खोले हैं। वह इस बात को महसूस कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार एक अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ भी विशेष ध्यान दे रही है। इसके साथ-साथ जो मदरसों में एजुकेशन का लेवल है, राजस्थान सरकार ने उसको भी कम्प्यूटराइज करने की बात की है, उसको भी माडर्नाइज करने की बात की है। वहां भी अगर अंग्रेजी की पढ़ाई स्टार्ट करने की बात की है, तो वह राजस्थान सरकार ने की है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवदेन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के माध्यम से जो हमारी कालीबाई भील स्कूटी योजना थी, जो हमने 5 हजार के आसपास शुरू की थी, पिछले बजट में हमने 20 हजार की। इस साल हमने 30 हजार बच्चियों को स्कूटी देने का प्रावधान किया है। मैं मुख्य मंत्री जी का और शिक्षा मंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। जो गार्गी पुरस्कार की राशि थी, उसको भी बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। मैं मांग करूंगा शिक्षा मंत्री जी से कि गार्गी पुरस्कार की राशि को भी इस बजट में बढ़ाया जाए ताकि बच्चियों को प्रोत्साहन मिले और वह शिक्षा जारी रख सके।

इसके साथ-साथ जो स्पोर्ट्स का वातावरण है, उसमें भी ग्राउण्ड की आवश्यकता है। इसके लिए भी बजट में अलग से प्रावधान किया गया है कि हम ग्राउण्ड के लिए पैसे देंगे। कई जगह मेजर ध्यानचंद के नाम से ग्राउण्ड खुल रहे हैं। कई जगह दूसरी चीज के माध्यम से, दूसरी संस्थाओं के माध्यम से भी बच्चों को खेल की एक्टिविटीज में आगे बढ़ाने के लिए हम प्रावधान करें। इसकी सरकार कोई न कोई व्यवस्था करे।

श्री सभापति: आप दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, इसके साथ अगर हायर एजुकेशन की मैं बात करूं तो राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री बैठे हैं राजेन्द्र जी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हायर एजुकेशन का जो राजस्थान का ढांचा था, शिक्षा मंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि इसको पहली बार ठीक करने का प्रयास किया। हमने इस साल 210 नये कालेज खोले हैं, जिसमें 93 गर्ल्स कालेज खोले हैं, जो 66 परसेंट है कालेज के हिस्से का। यह बहुत

(श्री जगदीश चन्द्र)

बड़ी बात है। पहली दफा 29 राजकीय कृषि महाविद्यालय भी खोले गये हैं। अभी बात कर रहे थे हमारे अजमेर से आने वाले साथी, हायर एजुकेशन की वह बात कर रहे हैं, नेक की भी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से वाइस चांसलर का अपाइंटमेंट राजस्थान में किया है, वह शेमफुल है। जिनकी काबिलियत नहीं है यूजीसी क्वालिफाइंग नहीं कर रहे और ऐसे-ऐसे लोगों को विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर बना दिया गया है, can you imagine? आप उम्मीद कर सकते हो कि आपकी हायर एजुकेशन का स्टैण्डर्ड ठीक होगा? मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि सरकार इसकी इंक्वायरी करे कि किस आधार पर वाइस चांसलर का सलेक्शन हुआ है? किस तरीके से सर्च कमेटी के लोगों को नोमिनेट किया गया है, जिसके माध्यम से राजस्थान के विश्वविद्यालयों का सत्यानाश करने पर लोग तुले हुए हैं।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में हायर एजुकेशन का जो एक फैसला किया सरकार ने, राजीव गांधी स्कोलरशिप फोर एकेडमिक एक्सीलेंसी, बहुत बड़ी योजना है, हमने स्टार्ट की है। एक एक्सीलेंसी कम से कम बाहर विदेशों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको एक मौका दिया सरकार ने जो विदेश के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, कल्पना भी नहीं कर सकते थे, सरकार ने कोशिश की है कि उनको भी आगे बढ़ाया जाए। राजस्थान में आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर हायर एजुकेशन का स्टैण्डर्ड बेहतर होगा। कोई जमाना था राजस्थान विश्वविद्यालय का इस देश में नंबर हुआ करता था। उसी पैटर्न पर सरकार पूरी कांशियस है। सरकार ने अलग से एक कमेटी भी बनाने का फैसला किया है, जो पीएसी में डिस्कस भी हो चुका है। हायर एजुकेशन के लिए सरकार विचार कर रही है कि राजस्थान में हायर एजुकेशन का सिस्टम हो जो ऑक्सफोर्ड में, केम्ब्रिज में, दूसरी यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन का पैटर्न है, इस राजस्थान में लागू किया जाए।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरी दो मांग हैं। एक मांग मेरे यहां गांव है चक बादल जिसकी ग्राम पंचायत हाकमाबाद है, उसके स्कूल को अपग्रेड करने की बात है और दूसरी है गांव जमींद सिंह वाला, ग्राम पंचायत सरदारपुरा जीवन, ये दो स्कूल हैं, जो अपग्रेड करने से काफी दिनों से पेंडिंग हैं, इनको अपग्रेड करने के लिए मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा।

(श्री जगदीश चन्द्र)

इसके साथ-साथ मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तरफ तो राजस्थान सरकार शिक्षा में इस तरीके का बेहतरीन काम कर रही है और शिक्षा के क्षेत्र में अगर पूरा बजट देखें और सरकार के फैसले देखें तो आये दिन कोई न कोई फैसला शिक्षा के बारे में सरकार कर रही है, लेकिन अच्छी बात को सबको एप्रिशिएट करना चाहिए। सरकार के स्कूल में, सरकार की जो शिक्षा की नीति है, वह सब पर लागू होती है, चाहे पक्ष का आदमी हो, चाहे विपक्ष का आदमी हो। हमारी मानसिकता, हमारी मंशा, सरकार की मंशा है कि राजस्थान में शिक्षा का बेहतरीन वातावरण बने, निश्चित तौर पर देश में और देश के बाहर जाकर हमारे विद्यार्थी नाम रोशन करें और आने वाले समय में भारत सरकार की जो अच्छी-अच्छी पोजिशंस हैं, राजस्थान के लोग शिक्षा लेकर जाये। जिस तरह से कोटा में, सीकर में एजुकेशन हब बनाने का प्रयास किया गया है...

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि पूरे देश का किस तरीके से टर्न आउट हमारे राजस्थान की तरफ हो रहा है। इसके लिए सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। माननीय शिक्षा मंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने शानदार डिबेट करवाकर महत्वपूर्ण विषय को लिया।

सूचना

श्री किरोड़ीलाल मीणा, सांसद का शहीदों की वीरांगनाओं के साथ जारी धरना

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, राजस्थान में किरोड़ी लाल जी मीणा कल से धरने पर बैठे हैं। लगातार धरने पर बैठे हैं। सरकार सुन नहीं रही है। धरने पर बैठे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। (व्यवधान) वीरांगनाओं की मांग को लेकर बैठे हैं। पुलवामा के शहीदों के लिए बैठे हैं। किसी घर के लिए नहीं बैठे हैं। राजस्थान में इस तरह से सरकार की दादागीरी नहीं चलेगी। (व्यवधान) सरकार की मनमर्जी नहीं चल सकती इस प्रकार से।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, (व्यवधान) कल बात हो गयी थी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): एक सांसद धरने पर बैठा है। (व्यवधान) आदिवासी सांसद धरने पर बैठा है। एससी/एसटी के लोग धरने पर बैठे हैं। शहीदों की, वीरांगनाओं की मांग के लिए बैठे हैं।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): आप बीच-बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। (व्यवधान) मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): शहीदों की वीरांगनाएं वहां पर बैठी हैं। शहीदों के बच्चे वहां पर बैठे हैं।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा। (व्यवधान) ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं।

श्री सभापति: आप सब सुनिए। सुनिए तो सही।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): सभापति महोदय, ये दिल्ली सरकार के जो फैसले हैं, उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। (व्यवधान) देश को बर्बाद करने के जो आपने फैसले किये हैं। मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा। आपने मुझे डिस्टर्ब करने का प्रयास किया है।

श्री सभापति: बैठिए प्लीज।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): बात हो गयी है उनसे। (व्यवधान) कल बात हो गयी। बात हो गयी थी।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा... (व्यवधान) आप भारत सरकार की बुराई क्यों नहीं सुन रहे हैं?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): कल बात हो गयी थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय। एक मिनट, राजेन्द्र जी...

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, कल राजेन्द्र जी यादव की उनसे बातचीत हो गयी थी। उसके बाद ही वे वहां से उठकर गये थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, सवाल इस बात का है कि जिन्होंने देश के लिए जान दी, वे वीरांगनाएं अपने नन्हे-नन्हे बालकों के साथ आज 48 घंटे से धरने पर बैठी हैं। मंत्री महोदय ने वार्ता की होगी, परन्तु मंत्री महोदय की वार्ता बेनतीजा इसलिए रही कि जो वादा इन वीर शहीदों की शहादत पर मंत्रीगणों ने अंत्येष्टि स्थल पर जाकर किया, वह नहीं कर रहे। उनके नाम से विद्यालय का भवन नहीं कर रहे। सरकार ने स्वयं ने जो पैकेज की घोषणा की, उस पैकेज की घोषणा पर सरकार अमल नहीं कर रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): वह बीजेपी के नेता बनना चाह रहे हैं... (व्यवधान) आप उनको स्पेस नहीं दे रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिए आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, पूरा हिन्दुस्तान हमें लानत कर रहा है। (व्यवधान) मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता। एक मिनट, मैं आपके माध्यम से सरकार से यही कहूंगा कि सरकार वार्ता करे। कल वार्ता किस हालात में टूटी, दोबारा वार्ता करे। उस घोषित पैकेज के अलावा एक पैसा नहीं दे, परन्तु घोषित पैकेज पर अमल करे। सभापति महोदय, आपसे हाथ जोड़कर विनती है। हाथ जोड़कर विनती है मेरी।

श्री सभापति: आपकी बात सरकार के नोटिस में आ गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): संवेदनाएं रखें थोड़ी-थोड़ी।

श्री सभापति: Let him speak.

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सिर्फ एक मांग उनकी है (व्यवधान) अपने देवर को नौकरी वाली।

श्री सभापति: आप बोलने तो दीजिए उनको।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): इसके ऊपर बात उनकी नहीं थी। बाकी उनकी सारी चीज़ें पूरी हो चुकीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं इस पर आगे बढ़ाना नहीं चाहता। इन शहीदों की चिताओं पर जाकर आप कहीं सड़क की घोषणा करते हैं, कहीं स्कूल की घोषणा करते हैं, पैकेज की घोषणा करते हैं। किसने आपको कहा कि पैकेज की घोषणा करें? आज सवाल उठाया था कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने, 11 ऐसे शहीद हैं, जिनकी वीरांगनाओं को एक पैसा सरकार ने नहीं दिया। शर्म की बात है।

श्री सभापति: फिर भी जो आपने कही है, राज्य सरकार के ध्यान में आ गयी है। (व्यवधान) आप इसको देख लीजिए। श्री छगनसिंह।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): सभापति महोदय, वादा इनको पूरा करना पड़ेगा।

श्री सभापति: श्री छगनसिंह राजपुरोहित। (व्यवधान) बात आ गयी है आपकी। श्री छगनसिंह जी, बोलिए। प्लीज, बैठिए।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 20-प्रारंभिक शिक्षा, मांग संख्या 21-माध्यमिक शिक्षा व मांग संख्या 22-उच्च शिक्षा पर विचार

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 20-प्रारम्भिक शिक्षा, 21-माध्यमिक शिक्षा एवं 22-उच्च शिक्षा के लिए मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के शिक्षा मंत्री बैठे हैं, मैं शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान जालौर जिले की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। जब भी परीक्षाएं होती हैं, रीट के एग्जाम होते हैं तो जालौर जिले में परीक्षा का केन्द्र नहीं दिया जाता है, तो जालौर जिले में परीक्षा का केन्द्र नहीं देने से आपकी परीक्षा के जो पेपर लीक हो रहे हैं, वे बंद हो गये क्या? शिक्षा मंत्रीजी, मैं माननीय सभापति महोदय के माध्यम से आपसे यह पूछना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र आहोर विधान सभा के जो छात्र/परीक्षार्थी परीक्षा देने जयपुर आये थे तो एक-एक छात्र के करीब दस हजार रुपये का खर्चा आया है, तो क्या इसका पुनर्भरण सरकार करेगी? किस प्रकार से आप इस तरह के अवरोध पैदा कर रहे हैं कि यह परीक्षा केन्द्र बंद करके क्या आपने पूरे राजस्थान में रीट की परीक्षा के पेपर लीक होना बंद करवा दिया? मैं यह चाहूंगा कि अगली बार जब भी परीक्षा हो, जहां पर जिस जिले के हैं, आप पुख्ता इंतजाम करें, जिससे परीक्षा भी उसी क्षेत्र में हो, जिससे मेरे बच्चों को भी, मेरे परीक्षार्थियों को भी सही सुविधा मिल सके और वे मानसिक रूप से परेशान न होकर सही तरह से परीक्षा दे सकें।

माननीय सभापति महोदय, वार्षिकोत्सव चल रहे थे तो सभी स्कूलों में मेरा जाना हुआ, मुझे बड़ा दुःख हुआ कि सभी के सभी विद्यालय जो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत भी हुए हैं, कहीं पर भी शिक्षक नहीं हैं। सिर्फ अभी जो विद्यालय सहायक, अभी जो वहां पर पंचायत सहायक से विद्यालय सहायक बनाये हैं, उनके भरोसे ही विद्यालय चल रहे हैं। दो-दो स्टाफ, तीन-तीन स्टाफ और 400-400 छात्रों की संख्या के साथ में चल रहे हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जितनी भी स्कूल्स हैं उनको कम से कम वास्तविक विषयवार तो बच्चों के अध्यापन के लिए शिक्षक दें। अभी सादुलशहर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर पढ़ने वाले छात्र गरीब वर्ग के जाते हैं, किसान वर्ग से जाते हैं, तो वहां पर अध्यापक नहीं होंगे तो वह गरीब वर्ग और किसान वर्ग का बच्चा कैसे पढ़ेगा?

(श्री छगनसिंह)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आहोर में करीब 80 से 85 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, वहां की आप एक बार लिस्ट मंगवा लेना, मेरे पास एक स्कूल की तो यह लिस्ट है, उसमें एक भी आपका, यह पंचायत सहायक जो विद्यालय सहायक बना है, उसके अलावा एक भी पद भरा हुआ नहीं है, पूरे के पूरे रिक्त पद हैं, इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है?

माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आप नवाचार करने में हमेशा आगे रहते हो। नोरवा गांव, नोरवा में यह, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आप नवाचार भी करते रहते हो, आपका शिक्षा के प्रति ध्यान भी है तो मैं जालौर जिले के प्रति जो हमेशा डार्क जोन जिला है, उसका ध्यान आपकी ओर आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे जिले में जब भी नये अध्यापकों की नियुक्तियां होती हैं तो वे जालौर जिले में लग जाते हैं, पर लगने के बाद प्रोबेशन पीरियड निकलते ही वे सीधे ट्रांसफर करवाकर चले जाते हैं। जिस प्रकार से सिविल सेवा में कैडर बना दिया जाता है कि जिस स्टेट में उनका सलेक्शन होता है, उनको उसी स्टेट में ही नौकरी करनी पड़ती है, तो मैं भी नवाचार के तहत आपको यह कहना चाहूंगा कि आप भी जालौर जिले और अन्य जो भी डार्क जोन जिले हैं, जहां पर अध्यापकों की हमेशा कमी रहती है तो या तो आप जिलेवार उनकी नियुक्तियां करें या उनका सलेक्शन करायें या फिर आप कैडर बना दीजिए कि जो जिस जिले में जायेगा उसको कम से कम 20 वर्षों तक वहां पर नौकरी करनी पड़ेगी, जिससे उस क्षेत्र में कम से कम हमेशा, जो सादुलशहर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि गरीब, किसानों के बच्चे जो शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, उनकी भी शिक्षा बराबर हो।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा प्रबोधकों के विषय को लेकर। प्रबोधकों के लिए 14 जून, 2021 को मुख्य मंत्रीजी ने एक घोषणा की थी कि प्रबोधकों का प्रमोशन करेंगे, उनको वरिष्ठ प्रबोधक कहा जायेगा। वरिष्ठ प्रबोधक मतलब, वरिष्ठ अध्यापक, तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि या तो मुख्य मंत्रीजी ने वरिष्ठ प्रबोधक नाम खाली दिया है और अगर नाम नहीं देकर उनको वरिष्ठ अध्यापक जैसे जितने फायदे हैं, उतने मिलने चाहिए, तो उन्हें या तो सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में विषयवार, जिस-जिस विषय से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है उनको उनके विषयनुसार सीनियर हायर सैकण्डरी में लगा दिया जाय या उच्च प्राथमिक

(श्री छगनसिंह)

विद्यालय में उन्हें उस स्कूल का हैड-मास्टर बना दिया जाये जिससे उन वरिष्ठ प्रबोधकों को भी यह लगेगा कि मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की है, वह वास्तव में की है, नहीं तो यही लगेगा कि मुख्य मंत्रीजी भाषण देते हैं और कोई अधिकारी उनकी मानते नहीं हैं।

शिक्षा मंत्रीजी, यह वास्तव में बहुत गंभीर विषय है। प्रबोधक हमेशा सभी से चर्चा भी कर रहे हैं। प्रबोधकों की कई समस्या को लेकर जो इनका वरिष्ठ प्रबोधक नाम है, उनको भी वरिष्ठ अध्यापक में किया जाय। आज जब भी आप रिप्लाई दें तो यह प्रबोधकों के विषय में यह वरिष्ठ प्रबोधक हटाकर वरिष्ठ अध्यापक करें क्योंकि इनका मानदेय, उनकी सैलरी जो है, वह ही है। जब आप सिस्टम से पूरा-पूरा कर रहे हैं तो उनका नाम भी चेंज कर दो, वे भी मूल धारा में आ जाएंगे और उनको भी यह लगेगा कि हम भी अध्यापक हैं नहीं तो उनके देखने का नजरिया भी लोगों में डिफरेंट होता है इसलिए, शिक्षा मंत्रीजी, मैं यह निवेदन करूंगा कि आप जब रिप्लाई दें तो इन वरिष्ठ प्रबोधकों की जो महती मांग है, उसको पूरा किया जाये।

(समय: 14.05 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

मेरे क्षेत्र जालौर जिले में जो 92 प्रबोधक, जिनकी अभी तक किसी कारण से नियुक्ति नहीं हुई है, उनकी भी नियुक्ति नियमों के अनुसार होने वाली थी, उनकी नहीं हुई है तो उनकी भी नियुक्ति की जाये, जिससे आने वाले समय में उनके परिवारवालों को भी फायदा मिले। सिर्फ 92 पद रिक्त हैं और वे नियम में आते हैं तो, शिक्षा मंत्रीजी इस पर ध्यान देंगे और उनका सलेक्शन जरूर करेंगे।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब विषय कक्षा कक्ष के बारे में अभी चर्चा हुई कि सभी स्कूलों में कक्षा कक्ष नहीं है। मेरे क्षेत्र में चार भामाशाहों ने, ये चार भामाशाह हैं- आकोली में पूरा का पूरा विद्यालय बनाकर दे रहे हैं करीब दो से ढाई करोड़ रुपये का, नाम है जितेन्द्रजी जैन, रतन चंद जी जैन, उनकी माताजी शकुंतला देवीजी की याद में वे पूरा विद्यालय बनाकर दे रहे हैं, आकोली में सीनियर हायर सैकण्डरी। इसी प्रकार से गुड़ा में भी प्रवीण कुमार नथमल जी रामाणी परिवार, जैन परिवार है, वे भी पूरा का पूरा विद्यालय बनाकर दे रहे हैं और जवेर चंदजी चान्दराई में

(श्री छगनसिंह)

आदर्श विद्या मन्दिर बनाकर दे रहे हैं और हरजी में ए.के. जैन साहब तीन कक्षा कक्ष बनाकर दे रहे हैं। जिला स्तर पर कहीं पर भी कलेक्टर ने उनको सम्मानित नहीं किया है। वहां पर काम चल रहा है। मैं यह चाहूंगा, शिक्षा मंत्रीजी, जो पूरी की पूरी बिल्डिंग बनाकर दे रहे हैं तो राज्य स्तर पर उनको बुलाकर उनका सम्मान करें और उस व्यक्ति का सम्मान जिनके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि पूजनीय आत्मानंदजी, जिन्होंने आज से साठ वर्ष पूर्व जब शिक्षा की बहुत कमी थी, हर गांव में जहां पर प्राथमिक भी नहीं होते थे तो उस समय उन्होंने बड़े-बड़े शहरों में छात्रावास खोले थे, तो उनके नाम का एक पुरस्कार घोषित करके, छात्रावास जिन्होंने बनाये थे आत्मानंदजी सरस्वती धाम ने, तो मैं आपको यह निवेदन करूंगा कि उनके नाम का पुरस्कार घोषित करके इन सभी को जैसे यह रतन चंदजी हैं, जितेन्द्रजी हैं, प्रवीण कुमारजी हैं, जवेर चंदजी हैं, इनको पुरस्कार दिये जायें और राजस्थान में आत्मानंदजी पुरस्कार के नाम से घोषणा करके उन्हें पुरस्कार दें जिससे आने वाले समय में जो भी भामाशाह होंगे उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा कि वास्तव में हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और राज्य सरकार भी उसका कहीं न कहीं अनुमोदन करती है। मैं धन्यवाद दूंगा उन्हें भी जो इस प्रकार के काम करते हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय सभापति महोदय, अभी तो शुरू किया है। माननीय सभापति महोदय, मेरी कुछ विशेष मांग है। मैं यह मांग करूंगा कि रोड़ला, चादराई, भवरानी, शंखवाली, हरजी और गुडा बालोतान में विज्ञान संकाय खोला जाये। ये बड़े-बड़े गांव हैं और वास्तव में वहां पर छात्रों की संख्या भी पूरी है। आप भले ही रिकार्ड मंगवा लेना, वास्तव में इन स्कूलों में अगर विज्ञान संकाय खुल जायेगा तो वहां के छात्रों का हित होगा।

इसी प्रकार से मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से कुछ विद्यालय जो गांव पंचायत स्तर के विद्यालय हैं, गांव हैं- बेदानाकलां, मीठड़ी, सुमेरगढ़खेड़ा, सेलड़ी, बुढ़ोतरा और बिजली, यह ग्राम पंचायत स्तर के गांव हैं, जिस प्रकार से सरकार ने घोषणा की थी कि सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल होंगे, पूर्व में वसुन्धरा राजेजी की सरकार ने भी किये, उससे पहले भैरोंसिंहजी ने उच्च प्राथमिक विद्यालय बनाये थे, इसी

(श्री छगनसिंह)

प्रकार से अभी जब परिसीमन हुआ तो हमारे क्षेत्र में एक भी ग्राम पंचायत नई नहीं बनी है लेकिन यह जो गांव हैं बेदानाकलां, मीठड़ी, सुमेरगढ़खेड, सेलड़ी, बुढ़ोतरा और बिजली, इनमें क्रमोन्नत करके उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाये जायें क्योंकि यह आबादी के हिसाब से भी बहुत बड़े गांव हैं और इनमें बच्चों की संख्या भी पूरी-पूरी है। मैं शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि इन स्कूलों को आप क्रमोन्नत करवाकर वहां के बच्चों को लाभ दें।

कक्षा कक्ष की अगर व्यवस्था देखें तो सराणा, नौसरा, जोड़ा, छिपरवाड़ा, सनवाड़ा, चांडण, किशनगढ़, मोहीवाड़ा, कोराणा, अगवरी, अगवरी का बालिका विद्यालय, पादरली का बालिका विद्यालय, बागून्दा, मडला और बेदाना ऐसे स्कूल हैं जहां पर वास्तव में कक्षा कक्ष की आवश्यकता है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इन कक्षा कक्षों के लिए भी आप बजट आबंटित करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी से बार-बार मिला हूं और मैंने अवगत करवाया है कि एक आलावासी है, वहां पर प्राथमिक विद्यालय है और वास्तव में वहां पर बच्चों की संख्या आप देख लेना रिकार्ड में, उसकी घोषणा तो आलावासी की वहां के सभी...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री जे.पी. चन्देलिया।

श्री छगनसिंह (आहोर): वहां सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जनजाति के छात्र पढ़ते हैं। पूरा का पूरा गांव अनुसूचित जनजाति का है। आपकी बड़ी कृपा होगी कि आज अगर मांग में आप यह घोषणा कर देंगे तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री छगनसिंह (आहोर): मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, भारत माता की जय।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट आफ राजस्थान एक बहुत डायनेमिक लीडरशिप में इस समय चल रहा है। वर्तमान एजुकेशन मिनिस्टर कल्ला साहब बहुत अनुभवी, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। ऐसे हाथों में एजुकेशन का चलना जो है इस कारण से बहुत ज्यादा उम्मीद हम कर सकते हैं। गत चार वर्षों में परिणाम अच्छे आये हैं। इनसे पहले वाले भी अच्छे थे। फिर कल्ला साहब को चार्ज मिला। हमें उत्तरोत्तर प्रगति एजुकेशन में देखने को मिल रही है, चाहे

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

वह प्रारम्भिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो और जहां तक उच्च शिक्षा का सवाल है, वहां भी गत चार वर्षों में जो प्रगति हुई, वह उल्लेखनीय और सराहनीय है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि समय की अपनी सीमा है, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ बात आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी के नोटिस में लाना चाहता हूं। मेरे यहां छह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जहां साइन्स फैकल्टी खुलवाने के लिए मैंने खूब पत्र लिखे हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी लिखे हैं, आपको भी लिखे हैं और एडिशनल सी एस, स्कूल एजुकेशन के जो रहे हैं, उनको भी लिखे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमती बनारसी देवी लाट गवर्नमेंट सीनियर सैकंडरी स्कूल मण्डरेला, शहीद नायक बजरंग लाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ढंढार, कुलहरियों का बास, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खुड़ानियां, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नरहड़, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, वार्ड नं. 2 पिलानी, ये जो विद्यालय हैं इनमें निश्चित रूप से विज्ञान संकाय खुलना चाहिए। इनमें कला संकाय है, दूसरे विषय भी हैं लेकिन जब तक बच्चे को विज्ञान विषय का स्कोप पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, सुविधा नहीं मिलेगी, आज के जमाने में मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण स्टडीज जो है वह विज्ञान की है इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विद्वान शिक्षा मंत्रीजी को विनम्र निवेदन करना चाहता हूं मण्ड्रेला, ढंढार कुलहरियों का बास, खुड़ानियां, नरहड़, एक पिलानी इट सेल्फ का है, इनमें विज्ञान संकाय आप खोलें। पिलानी और मण्ड्रेला जैसी जगह पर विज्ञान संकाय सीनियर सैकंडरी स्कूल में आप स्वीकृत नहीं कर रहे हो तो मेरे विचार से बहुत बड़ा प्रश्न वाचक चिह्न सिस्टम पर लगता है। विनम्र निवेदन है कि आप इनमें जरूर विज्ञान संकाय खुलवायें।

दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि दो विद्यालय मेरे यहां ऐसे हैं जहां विज्ञान तो है लेकिन कला नहीं है। माननीय सभापति महोदय, सारे विद्यार्थी विज्ञान में नहीं चल सकते। विज्ञान के लिए बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा टैलेंट चाहिए, उसकी उसमें अभिरुचि भी चाहिए। हम चाहते हैं कि श्री अडूकिया गवर्नमेंट सीनियर सैकंडरी स्कूल, चिड़ावा और गवर्नमेंट सीनियर सैकंडरी स्कूल भगीना, ब्लाक पिलानी, ये दो विद्यालय हैं, मैंने आपको खूब पत्र लिख रखे हैं, इन दो में आप कृपया कला संकाय स्वीकृत करिये। ज्यादा खर्चा भी नहीं है,

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

लगभग उसी स्टाफ में काम चल जाता है और वह बच्चे जिनकी पढ़ाई छूट जाती है, विज्ञान में वह चल नहीं सकते और दूसरी जगह अभिभावक बच्चों को भेज नहीं सकते। विशेष रूप से मैं कहता हूं कि हम कितने ही माडर्न बन जायें फिर भी दसवीं और बारहवीं क्लास पढ़ने के लिए लड़कियों को दस किलोमीटर भी भेजने के लिए अभिभावक को सोचना पड़ता है। मैं स्कूल का नाम रिपीट कर रहा हूं अडूकिया गवर्नमेंट सीनियर सैकंडरी स्कूल चिड़ावा और गवर्नमेंट सीनियर सैकंडरी स्कूल, भगीना, ये पिलानी ब्लाक में हैं, इन दोनों में कृपया आप कला संकाय जरूर स्वीकृत करिये ताकि बच्चों को आगे पढ़ने का काम रूके नहीं।

तीसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र शिक्षा में बहुत आगे है। मेरे पूर्व विद्वान साथियों ने कह भी दिया और रिकार्ड पर भी है कि महिला एजुकेशन में हम नम्बर वन पर हैं। मेल एजुकेशन में हम नम्बर दो पर हैं राजस्थान में। अगर सिल्वर मैडल लेने वाला खिलाड़ी है और अगर आप उसको गोल्ड मैडल के लिए तैयार करते हो तो यह कार्य बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है। हमें आप प्रोत्साहित करिये।

बहुत पुरानी स्कूल्स हैं जिनमें कक्षा कक्षा की दुर्दशा है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, मैंने आपको और माननीय जाहिदाजी को भी जिनके पास अभी चार्ज आया है समग्र शिक्षा अभियान का, राज्य मंत्री हैं, इस काम को देख रही हैं, चूंकि डिपार्टमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर आप हैं, मैंने एडिशनल क्लास रूम्स के लिए निवेदन किया है। वहां कृपया एडिशनल क्लास रूम स्वीकृत करें अन्यथा बच्चों को खुले में बैठना पड़ता है, पेड़ के नीचे बैठना पड़ता है। भवन गिरने वाला है, कमरा गिरने वाला है, उस स्थिति में बैठना पडता है जो बहुत खतरनाक है। मैंने पत्रों के माध्यम से जो आपके रिकार्ड पर हैं, वहां एडिशनल क्लास रूम की व्यवस्था कराने का कष्ट करें।

माननीय सभापति महोदय, एक बात जरूर बड़ी तकलीफ के साथ निवेदन करना चाहता हूं, कोई कम्प्लैंट नहीं कर रहा हूं। कई बार अधिकारी व्हिम्सिकल आर्डर पास कर देता है। अधिकारियों की शिकायत मैं पेश नहीं करना चाहता, उन्हीं में से निकला हुआ एक आदमी हूं लेकिन ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल पर एक अधिकारी आपने लगा रखा है चूरू। किन परिस्थितियों में लगा, कैसे लगा, आपसे मेरी बात हो चुकी है। मुझे ध्यान है जिसको आपने चूरू ज्वाइंट डायरेक्टर लगाया है। मैं यह निवेदन करता हूं कि

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

अगर विधायक ने लिखकर दे दिया तो पहली प्रायोरिटी जैसाकि सिस्टम में है, विधायक की डिजायर को ऑनर करना चाहिए। अगर मंत्री के यहां से विधायक की डिजायर ज्वाइंट डायरेक्टर, चूरू के पास चली गयी तो वह ओवर राइडिंग प्रायोरिटी प्राप्त करती है। वह अपने यहां से अन्य किसी को लगा दें और उस डिजायर को इग्नोर कर दें, यह मेरे विचार से नहीं चलेगा। आप कृपया पिलानी विधान सभा क्षेत्र में, मैं वहां का विधायक हूं, सैकंड ग्रेड टीचर्स की, बाकी तो सब हो गये मेरे, मेरे प्रिंसीपल के भी हो गये, सारे हो गये, सब हो गये, everything is done. खाली सैकंड ग्रेड की बात कर रहा हूं। सैकंड ग्रेड का ही अधिकार ज्वाइंट डायरेक्टर को होता है। सैकंड ग्रेड के कितने टीचर अपने लेवल से ज्वाइंट डायरेक्टर ने पिलानी विधान सभा क्षेत्र में लगाये। कृपया उनकी जांच करवायें और साथ में यह भी दिखवायें कि क्या संबंधित विधायक, पिलानी की डिजायर आयी थी? यदि आयी हुई थी तो वह डिजायर ऑनर होनी चाहिए। उसके व्हिम्सिकल आर्डर नहीं होने चाहिए। मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने स्तर से उसकी जांच करवायें। किसी सीनियर अधिकारी से इसकी जांच करवायें। अगर यह पाया जाता है कि विधायक की डिजायर आलरेडी एग्जिस्ट करती थी तो उन आर्डर्स को रिवर्स करिये। यह मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, बाकी एजुकेशन विभाग बहुत शानदार चल रहा है। जनता में इसका बहुत ज्यादा स्वागत है। जो परिणाम आ रहे हैं वह भी शानदार आ रहे हैं। आपके नवाचार शिक्षा को बूस्ट-अप कर रहे हैं। मैं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं कि मेरे यहां विशेषकर मांग संख्या 21-माध्यमिक शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा होता जा रहा है। हमारे बच्चे खूब मैरिट में आ रहे हैं।

अन्त में निवेदन करना चाहता हूं कि हम शिक्षा में अग्रणी हैं। थोड़ा सा आप और सपोर्ट कर दें तो राजस्थान में जैसे हम मेल एजुकेशन में 2 पर हैं, उसमें भी हम नम्बर 01 पर होंगे और महिला शिक्षा में हम नम्बर 01 पर हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। Thank you verry much.

श्री सभापति: श्री जोराराम कुमावत।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, मांग सख्या 20-प्रारम्भिक शिक्षा, 21-माध्यमिक शिक्षा और 22-उच्च शिक्षा पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी पहली गुरु मां होती है। मां उसे पाल कर बड़ा करती है, उसे चलना सिखाती है,

(श्री जोराराम कुमावत)

उसे बोलना सिखाती है, उसे व्यावहारिक ज्ञान सिखाती है। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसे शिक्षा देने के लिए सरकारी विद्यालय में शिक्षकों के पास भेजते हैं, अपने गुरु के पास भेजते हैं। इस आशा के साथ भेजते हैं कि विद्यालय में बच्चे को सम्पूर्ण शिक्षा मिलेगी, उसे भारतीय संस्कार मिलेंगे, पढ़-लिखकर बच्चे होनहार नागरिक बनेंगे लेकिन माता-पिता को बाद में पता चलता है कि सरकारी स्कूलों में अध्यापक ही नहीं हैं, व्याख्याता ही नहीं हैं, विषय के अध्यापक नहीं हैं, स्कूलों में बैठने के लिए कमरे नहीं हैं, कहीं पानी की सुविधा नहीं है, कहीं बिजली की सुविधा नहीं है। विद्यालयों में अध्यापकों की कमी से बच्चों को सम्पूर्ण शिक्षा नहीं मिलती। आधे विषयों की जानकारी नहीं मिलती, जिससे उनका ज्ञान आधा अधूरा ही रहता है। मनुष्य की नींव ही शिक्षा है, लेकिन विद्यार्थियों की शुरुआत में ही नींव कमजोर हो जाती है जिससे कई विद्यार्थियों का भविष्य खराब हो जाता है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में 63 ग्राम पंचायतें हैं और 2 नगरपालिका क्षेत्र हैं। इनमें 82 स्कूलें राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें प्रधानाचार्य, उप-प्रधानाचार्य, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक लेवल-I एवं लेवल-II, शारीरिक शिक्षक के करीब 510 से ज्यादा अध्यापकों के पद रिक्त हैं। इसी तरह से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, अध्यापक और शारीरिक शिक्षकों के 112 से ज्यादा पद रिक्त हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों एवं विवेकानन्द मॉडल स्कूल सहित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों को मिलाकर कुल 650 अध्यापकों के पद रिक्त हैं। कई विद्यालयों में दो अध्यापक हैं, कई में तीन हैं, कई में चार हैं। माननीय सभापति महोदय, अध्यापकों की कमी से विद्यार्थियों का अध्ययन प्रभावित हो रहा है एवं रिजल्ट भी प्रभावित हो रहा है। अभिभावक सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अध्यापकों की कमी से अध्ययन नहीं होने से प्राइवेट विद्यालयों की ओर उनका ध्यान आकर्षित हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, आज सरकार की उदासीनता से शिक्षा विभाग में नई भर्ती नहीं होने से सरकारी विद्यालयों में नामांकन कम हो रहे हैं। चार वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक होना व रीट के पेपर चोरी होना, राजस्थान के इतिहास में शर्मनाक घटना है। सरकार की लापरवाही से राजस्थान को कलंकित करने का काम सरकार ने किया है।

(श्री जोराराम कुमावत)

माननीय सभापति महोदय, पिछले साल ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने ओलम्पिक खेल करवाये। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में खेल मैदान तैयार नहीं थे, कई स्कूलों में खेल मैदान आबंटित भी नहीं हैं फिर भी बिना सुविधा के खेल ओलम्पिक करवा दिये। मैं कई कार्यक्रमों में गया। कई जगह खेलों के आयोजन हुए। कई जगह मैदान उबड़खाबड़ थे, कई जगह खेल खेतों में ही आयोजित हो गये, कई जगह मिट्टी उड़ रही थी। आयोजन के लिए स्कूलों को सरकार द्वारा कोई पैसा नहीं दिया गया और ग्राम पंचायतों पर ही सारा भार डाल दिया। टीमों का चयन भी सही नहीं हुआ।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक स्कूल में गया तो कबड्डी की टीम थी, उसमें एक तरफ 10-12 साल के लड़के और दूसरी तरफ 20-25 के लड़के, उनके बीच में मुकाबला था। जब मैंने टीम को देखा तो आश्चर्य हुआ। उसी समय मैंने एस.डी.ओ. साहब को कहा कि इस तरह से यह कैसे खेलेंगे, इनके सामने यह बच्चे कैसे टिकेंगे? तब जाकर एस.डी.ओ. साहब ने टीम चेंज करवायी। इस तरह से ओलम्पिक खेलों में भी खूब लापरवाही हुई। बिना तैयारी के ही यह ओलम्पिक खेल सरकार ने करवाये, जिसका नतीजा यह हुआ कि ओलम्पिक खेलों में जब आवेदन किये और ओलम्पिक खेलों की शुरुआत सरकार ने करनी चाही और उस समय आवेदन ही नहीं आये तो आखिर में सरकार को वह सारे ओलम्पिक खेल भी रद्द करने पड़े। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि अगले साल ग्रामीण ओलम्पिक से पूर्व सभी विद्यालयों में खेल के मैदान आबंटित करवाकर खेल के मैदान विकसित करवायें व खेलों में प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए विद्यालयों में खेल सामग्री भी सरकारी स्तर पर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था सरकार कराये।

माननीय सभापति महोदय, सुमेरपुर में पांच वर्ष पूर्व कालेज स्वीकृत हुआ था और कालेज के लिए फर्स्ट फेज में 6 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई थी, पांच वर्ष हो गये लेकिन अभी तक वह भवन पूरा नहीं हुआ है, आज भी कालेज एक विद्यालय के कमरों में ही चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्रीजी से आग्रह करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि इस भवन को शीघ्र पूरा करायें और शीघ्र पूरा कराकर कालेज दूसरी जगह संचालित है, उसे नई बिल्डिंग में संचालित करने के लिए स्थापित किया जाये। माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से सैकण्ड फेज के लिए जो राशि जारी होनी थी, वह राशि भी जारी नहीं हुई है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सैकण्ड फेज के लिए भी राशि जारी करावें।

(श्री जोराराम कुमावत)

माननीय सभापति महोदय, सुमेरपुर कालेज की शैक्षणिक व्यवस्था की बात करें तो जितने भी शैक्षणिक पद हैं, उनमें से आधे पद रिक्त हैं और अशैक्षणिक के सारे के सारे पद रिक्त हैं, तो कालेज की व्यवस्था सही रूप से संचालित करने के लिए इन पदों को भी भरने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से मेरे क्षेत्र में एक कालेज तखतगढ़ कन्या महाविद्यालय, जो 2021-22 में राज्य सरकार ने खोला है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन इसके साथ-साथ ही आपके संज्ञान में यह बात भी लाना चाहूंगा कि उस कालेज में 19 महीने हो गये, परन्तु इन 19 महीनों में वहां एक भी शैक्षणिक और अशैक्षणिक पद भरे नहीं हैं। वहां 100 प्रतिशत पद अभी भी रिक्त हैं, तो वह कन्या महाविद्यालय कैसे चलेगा, वह तो आप भी जानते हो।

माननीय सभापति महोदय, सरकार की गलत नीतियों के कारण, लापरवाही कहो या उदासीनता के कारण इन कन्या महाविद्यालयों में पढ़ने वाली कन्याओं के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सुमेरपुर राजकीय महाविद्यालय के भवन का कार्य शीघ्र पूरा करावें। स्कूल की बिल्डिंग में चल रहे कालेज को नई बिल्डिंग में शिफ्ट करावें व भवन के सैकण्ड फेज की स्वीकृति भी जारी करावें। इसके साथ ही सुमेरपुर व तखतगढ़ की कालेजों में सारे रिक्त पद, शैक्षणिक व अशैक्षणिक पद शीघ्र भरने की व्यवस्था करावें, जिससे विद्यार्थियों का सुचारु रूप से अध्ययन हो सके और कालेज की व्यवस्था भी सुचारु रूप से चल सके।

माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत आपने राजस्थान के सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत तो कर दिया, लेकिन क्रमोन्नत विद्यालयों में एक भी व्याख्याता नहीं लगाया, जिससे 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को कौन पढ़ायेगा? चार वर्षों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नये विषय- कामर्स, आर्ट्स और विज्ञान आदि विषय खोलने थे, आपने एक भी विषय नहीं खोला, जिससे विद्यार्थियों को आज भी इच्छित विषय का ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। विद्यालय क्रमोन्नत करने के बाद विद्यालयों में कक्षा-कक्षों की कमी हो रही है, लेकिन कक्षा-कक्षों की कमी की भी राज्य सरकार ने पूर्ति नहीं की है। कई विद्यालयों के भवन जीर्ण-शीर्ण

(श्री जोराराम कुमावत)

अवस्था में हैं, लेकिन जीर्ण-शीर्ण भवनों की मरम्मत के लिए भी राज्य सरकार चिन्तित नहीं है। मैं सरकार से आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा और मांग करता हूं कि इन क्रमोन्नत विद्यालयों में व्याख्याता लगायें, क्रमोन्नत विद्यालयों में नये विज्ञान, कामर्स और आर्ट्स आदि विषय खोले जायें और कक्षा-कक्षों की स्वीकृति भी दें और क्षतिग्रस्त भवनों की भी रिपेयरिंग करने की व्यवस्था सरकार कराये।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं जहां की बच्चियां पढ़ना चाहती है, लेकिन वहां समुचित शिक्षण व्यवस्था नहीं होने से एवं बारहवीं तक की स्कूल नहीं होने से वह स्कूल छोड़कर घर पर बैठी हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नांकित मेरे कुछ गांवों के लिए मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां भी उच्च प्राथमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करायें:-

1. केरला
2. पिचावा
3. राजपुरा
4. नवागुड़ा
5. सांगवा
6. घनापुरा
7. ऐंदलाबास
8. सापुनी
9. कानपुरा
10. बाला
11. वेनपुरा
12. पड़ासला कला
13. बालिका खिवान्दी
14. बालिका बांकली
15. विद्यालय नंबर 1 सुमेरपुर
16. विद्यालय संजय नगर सुमेरपुर

(श्री जोराराम कुमावत)

इन विद्यालयों में वर्तमान में अभी उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं, उनको उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करवाने की व्यवस्था करावें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में पांच विद्यालय ऐसे हैं जिनका पिछले साल समायोजन हुआ था, लेकिन अभी वह प्राथमिक विद्यालय बहुत दूर संचालित हैं। वहां पर छोटे-छोटे बच्चे उन विद्यालयों में नहीं जा पाते हैं, तो उन विद्यालयों को वापस अलग कराने की व्यवस्था करावें। ये विद्यालय निम्न हैं:-

1. रा.उ.प्रा.वि. हाउसिंग बोर्ड में चल रहा है, उसे संजय नगर में शामिल कर दिया, उसे भी अलग करने की व्यवस्था करावें।
2. रा.उ.प्रा.वि. पालड़ी जोड़, जिसे माध्यमिक विद्यालय में समायोजित किया, उसे वापस अलग करने की व्यवस्था करावें।
3. रा.प्रा.वि. भोपालसिंह की ढाणी, खिमाड़ा जो अलग संचालित है, उसे वापस अलग कराने की व्यवस्था करावें।
4. रा.प्रा.वि. बलवना और सांडेराव को भी अलग करवाने की व्यवस्था करावें।

बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री बाबूलाल नागर।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 20-प्रारम्भिक शिक्षा, मांग संख्या 21-माध्यमिक शिक्षा, मांग संख्या 22-उच्च शिक्षा के संबंध में डिमांड्स पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका आभार।

माननीय सभापति महोदय, पिछले चार साल में शिक्षा में राजस्थान की सरकार ने जो नवाचार किये, ऐतिहासिक फैसले किये, चाहे वह अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय बनाने की बात हो, चाहे इन विद्यालयों में कक्षा-कक्ष बनाने हों। पहले की सरकारों में हुआ करता था कि भारत सरकार पर सर्वशिक्षा अभियान में कक्षा-कक्षों के लिए निर्भर रहा करते थे। प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी नाबार्ड से लोन लेकर, चाहे सर्वशिक्षा हो, चाहे शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाएं हों, सरकार लोन लेकर भी कक्षा-कक्षों का निर्माण कर रही है।

सभापति महोदय, प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने युवाओं के क्षमता,

(श्री बाबूलाल नागर)

विकास के लिए जयपुर में राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी बनाये जाने की घोषणा की, इससे निश्चित रूप से हमारे राजस्थान के युवाओं को एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी।

सभापति महोदय, उच्च शिक्षा के मामले में इस सरकार ने ऐतिहासिक फैसले किये। मेरे यहां दूदू, फागी में सरकारी महाविद्यालय हैं। मैं आग्रह करूंगा कि जो सरकारी महाविद्यालय दूदू, फागी हैं, इसको पीजी की जाये।

हमारे यहां एक महिला महाविद्यालय भी मुख्य मंत्री जी ने खोली है, उसके भवन का काम भी चल रहा है। उसमें केवल साइंस है, जब आपने बेटियों का महाविद्यालय खोला है तो मैं आग्रह करना चाहूंगा कि उसमें कामर्स और आर्ट्स भी खोली जाये।

सभापति महोदय, संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इसको कार्ययोजना में शामिल किया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की फागी तहसील में नारहेड़ा ऐसा गांव है जिसके 10, 15, 20 किलोमीटर में 3 वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय हैं। वहां अगर नारहेड़ा में शास्त्री महाविद्यालय खोल दिया जाता है तो पूरे क्षेत्र में संस्कृत अध्ययनरत बच्चों को तकलीफ से मुक्ति मिल जायेगी।

सभापति महोदय, मैं प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले बजट में मुख्य मंत्री जी ने दुनिया के जो सबसे उच्च शिक्षण संस्थान थे, उनमें अध्ययन के लिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप फोर एकेडमिक एक्सीलेंसी योजना शुरू की थी। उसमें 200 होनहार विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता दी जा रही थी। इस बार मुख्य मंत्री जी ने बजट में 500 विद्यार्थियों को सहायता देने का प्रावधान किया है, इससे हमारे प्रदेश के बच्चे दुनिया के बेहतरीन स्कूलों में सरकारी खर्चे पर पढ़ेंगे। इससे निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे।

सभापति महोदय, इसी तरह से हमारे जो राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षक हैं, उनको देश-विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में रिसर्च एवं ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए टीचर्स इंटरफेस फोर एक्सीलेंस (टीआईई) कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित किया है। इसमें 500 शिक्षकों का चयन होगा। यह 500 शिक्षक दुनिया की बेहतरीन एजुकेशन संस्थाओं में रिसर्च करेंगे तो राजस्थान में हमारा एजुकेशन स्तर आगे बढ़ सकेगा।

(श्री बाबूलाल नागर)

सभापति महोदय, नवीन आईटीआई भी सरकार ने बहुत खोली हैं। अब प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने बहुत उपखण्ड खोल दिये, बीडीओ कार्यालय खोल दिये, तो राज्य में जिस भी उपखण्ड में या विकास अधिकारी कार्यालय में आईटीआई नहीं है, मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी को पूरे राजस्थान में से सभी क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईटीआई खोलने चाहिए। आज बेरोजगारी का मामला बहुत बढ़ा हुआ है। बच्चे तकनीकी शिक्षा लेंगे तो स्वयं अपने पैरों पर खड़े होंगे। मेरे यहां फागी में आईटीआई नहीं है। पहले फागी में आईटीआई थी, लेकिन अभी उपखण्ड एवं परिसीमन से वह माधोराजपुरा में चली गयी। मेरे फागी ब्लाक में, फागी उपखण्ड में आईटीआई नहीं है। मौजमाबाद में आईटीआई नहीं है। मैं चाहूंगा कि मेरे यहां नवीन आईटीआई खोली जाये।

सभापति महोदय, इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने यह बहुत अच्छा काम किया है कि हमारी जो बच्चियां हैं, अभी छात्राओं को स्कूल शिक्षा की तर्ज पर उच्च शिक्षा संस्थानों में भी, महाविद्यालयों में आने-जाने के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम लागू करने की घोषणा की है। अब यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय में भी हमारी जो बच्चियां हैं, उनको आने-जाने के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर सरकार द्वारा दिये जायेंगे। इससे निश्चित रूप से उनका मनोबल बढ़ेगा।

सभापति महोदय, मैं अंग्रेजी स्कूलों के संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी लोगों ने प्रशंसा की है। इसकी काफी डिमांड है। मेरे यहां करीब 19 स्कूलें खोलीं। सारे पंचायत मुख्यालयों पर हर जगह बहुत भारी डिमांड है। मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी हर पंचायत मुख्यालय पर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय खोली जाये। इससे हमारा एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा।

सभापति महोदय, राजस्थान के यशस्वी, दूरदर्शी मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश की आवश्यकता को पहचान कर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों की एक श्रृंखला प्रारम्भ की है। यह कदम प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने विगत बजट सत्र में 10 हजार अंग्रेजी माध्यम शिक्षकों का कैडर अलग से सृजित कर प्रदेश में अंग्रेजी

(श्री बाबूलाल नागर)

भाषा में पिछड़ापन दूर करने का प्रयास प्रारम्भ किया है। अंग्रेजी भाषा में कमजोरी की वजह से प्रदेश के युवा पिछड़ते रहते हैं। इस संदर्भ में सदन के सामने निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश में लगभग 265 महाविद्यालयों में पीजी संचालित की जा रही है, इनमें से मात्र 30 महाविद्यालयों में अंग्रेजी साहित्य में पीजी संचालित है। 265 में से 30 महाविद्यालयों में संचालित है। अंग्रेजी माध्यम के 10 हजार शिक्षकों का कैडर आप भर्ती करना चाह रहे हैं, तो शिक्षक कहां से लायेंगे?

सभापति महोदय, मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि कम से कम जिले के एक महाविद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर अंग्रेजी साहित्य की और संभाग मुख्यालय पर अंग्रेजी भाषा की पीजी संचालित की जानी चाहिए। जब आप 10 हजार अंग्रेजी अध्यापक लगाने की बात कर रहे हैं, कैडर बनाने की बात कर रहे हैं और आपके पास एक भी पीजी नहीं है, जितनी भी 265 हमारे पीजी महाविद्यालय हैं, तो आप कहां से अंग्रेजी के अध्यापक लाओगे?

सभापति महोदय, इसी तरह मैं कहना चाहूंगा कि निजी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण बिलकुल नहीं हो रहा है। 2005 से निजी विश्वविद्यालय राजस्थान में कार्यरत हैं। इनका कोई धणी-धोरी नहीं है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रसारण संस्थान के नियमानुसार इनकी स्थापना के 6 वर्ष बाद विश्वविद्यालयों को अपनी गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए नैक से ग्रेड प्राप्त करनी चाहिए। बिना नैक से ग्रेड प्राप्त किये, जब इनका स्तर ही नहीं है तो यह हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यह आवश्यक कर देना चाहिए कि जो भी निजी विश्वविद्यालय हैं वह 6 साल में नैक से ग्रेड प्राप्त करें। जो नहीं करते हैं, विधान सभा में जिस तरह से हम निजी विश्वविद्यालय खोलते हैं, उसी तरह से वापस विधान सभा में आकर इन निजी विश्वविद्यालयों को बंद करने का काम करना चाहिए। ऐसे विश्वविद्यालयों का कोई मतलब ही नहीं है जो कि बच्चों का भविष्य खराब कर दें। इस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं सुझाव दूंगा कि इसी तरह हमारी उच्च शिक्षा के विकास के लिए एक विशेष समिति का गठन करना चाहिए। इसमें आईआईटी, आईआईएम के बड़े प्रोफेसर्स, विशेषज्ञ लगते हैं, इनको गांवों का ज्यादा अनुभव नहीं होता है। आईआईटी, आईआईएम वालों को ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाता

(श्री बाबूलाल नागर)

है। इन बड़ी संस्थाओं के प्रोफेसर्स को गांव, कस्बों में आ रही चुनौतियों की ज्यादा जानकारी नहीं होती है, इन्हें जमीनी सच्चाई नहीं पता है। इस कारण ऐसी समिति की रिपोर्ट मात्र सरकारी दस्तावेज बन जाती है। जो हमारे निजी महाविद्यालय हैं, वहां के प्रोफेसर्स को इसमें मौका देना चाहिए।

सभापति महोदय, रूसा एक अनुदान है। राजकीय महाविद्यालयों को रूसा के अंतर्गत आधारभूत ढांचे हेतु 2 करोड़ रुपये का अनुदान मिलता है। अनेकों महाविद्यालयों का कायाकल्प कर दिया है। इसमें नैक बी प्लस ग्रेड होना आवश्यक है, मगर बी प्लस ग्रेड राजकीय महाविद्यालयों की नहीं होने के कारण इस 2 करोड़ रुपये का राजस्थान के महाविद्यालयों को फायदा नहीं होता है। इसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, इसी तरह से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री महोदय और उच्च शिक्षा मंत्री बैठे हैं, मेरे यहां दूदू महाविद्यालय है। प्रदेश के मुख्य मंत्री ने महाविद्यालय के भवन बनाकर हमारे प्रदेश के बच्चों को एक तरह से वरदान दिया। उस महाविद्यालय में अध्यापकों की हालत ऐसी कर दी है, उच्च शिक्षा विभाग में डाक्टर प्रज्ञा शर्मा, समाज शास्त्र की मेरे यहां राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत थी, आज सांगानेर में डेपुटेशन पर है। डाक्टर लालचंद यादव, लोक प्रशासन के हमारे यहां पर राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत थे, आज किशनगढ़-रेनवाल में डेपुटेशन पर हैं। डाक्टर समीर शर्मा, कालेज निदेशालय में इनको लगा दिया गया है। पहले ये डेपुटेशन पर थे, विद्या सम्बल योजना में मैंने रिक्वेस्ट की थी सेक्रेटरी साहब से, एक शिमला चौधरी आई, लेकिन कैसे आई, कुछ दिन के लिए भेजा, वहां से वो शिमला चौधरी भी चली गई, वापस उसको कालेज निदेशालय में लगा दिया। इसी तरह से एबीएसटी की टीचर हमारे डाक्टर वीणा शर्मा, ये हमारे बस्सी में लगा दी। मेरे समझ में नहीं आ रहा, चाहे स्टेनोग्राफर हो, चाहे बुक लिफ्टर हो, इसी तरह से हमारे कन्या महाविद्यालय में रामावतार जाट था, उसको भी वहां से हटा दिया। मैंने रिक्वेस्ट करके, मंत्रीजी, सीमा गर्ग को हमारे यहां फागी में लगाया था सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय में, पता नहीं क्या रखा है इस कालेज निदेशालय में, बंद कर दो इन कालेजों को, जब आपको निदेशालय में ही अध्यापक चाहिए, इसको भी आपने वहां से उठाकर, बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़-जोड़कर लगवाया, पर उसको भी आपने कालेज निदेशालय में लगा दिया।

(श्री बाबूलाल नागर)

माननीय सभापति महोदय, यह हालत अगर आप करेंगे तो क्या मतलब है आपका कालेज खोलने का? अगर आप इनको ऐसे ही तनख्वाह देना चाहते हो, ऐसे ही आब्लाइज करना चाहते हो, ऐसे ही आप घर बैठे ही इनको आब्लाइज करना चाहते हो, माननीय सभापति महोदय, मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि अधिकारी भी यहां बैठे हैं, मंत्रीजी भी बैठे हैं, ये मेरी गरीब जनता के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं करूंगा कतई भी। मैं चेता रहा हूं सरकार को, इस डिपार्टमेंट को भी चेता रहा हूं कि ये कारनामे करना बंद करें, मेरे जो अध्यापक हैं, इनको डेपुटेशन निरस्त कर वापस मूल स्थान पर लगाएं। चाहे एक विद्यालय में आठ-दस अध्यापक लगाएं, इनमें से छह-सात को आपने डेपुटेशन पर लगा दिया, बच्चे बार घाल रहे हैं, रो रहे हैं, धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, आंसू पड़ रहे हैं कि यहां क्यों कालेज खोली है? क्यों स्कूल का भवन बना दिया? अगर आपको इनको नहीं लगाना था तो मेहरबानी करते कोई विद्या सम्बल में लग जाता, कम पढ़ा-लिखा, कम ज्ञानी आदमी लग जाता जो कि हमारे बच्चों को कुछ तो पढ़ाता।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसी तरह से राजस्थान विश्वविद्यालय में छह सहायक आचार्य, 21 वर्षों से इनकी पदोन्नति, वेतन नियमितीकरण का मामला लम्बित चल रहा है। इन छह सहायक आचार्यों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने परीक्षण करने के बाद आदेश किया है कि आप 272 शिक्षकों को इनके समकक्ष मानते हुए प्रकरण निस्तारण करके विभाग को अविलम्ब सूचित करें। इसी तरह से सिंडिकेट ने भी फैसला किया है और उस फैसला करने के बाद दो बार सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के आदेश जारी करने के बाद वह आदेश पता नहीं ऐसी कौनसी कोटड़ी में पड़ा हुआ है कोई पूछने वाला नहीं है और वो छह शिक्षक, एक शिक्षक तीन महीने बाद रिटायर हो रहा है, आज 21-21, 22-22 साल सेवा करने के बाद भी पदोन्नति की आस में बैठे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये छह शिक्षक, महीपाल यादव, सुरेन्द्र सिंह चौहान, नरेश मलिक, रमेश चावला, के एल बत्रा, अशोक सिंह, ये सरकार को भी, यूनिवर्सिटी प्रशासन है आपका, सरकार को भी कुछ नहीं समझता है, अंगूठा दिखा रहा है सरकार को, दो बार सरकार के आदेश देने के बाद भी इनकी न तो पदोन्नति हुई है और न ही वेतन निर्धारण किया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं

(श्री बाबूलाल नागर)

आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें माननीय मंत्रीजी और विभाग के अधिकारियों को हस्तक्षेप करना चाहिए। सरकार की जब मंशा है, प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्रीजी की मंशा है कि संविदा कार्मिक, डेली मानदेय वाले, सबको प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी ने, आज सारे के सारे शिक्षक प्रोफेसर हो गए, इनमें दो-तीन महीने बाद रमेश चावला रिटायर हो जाएगा। वो रोता रहेगा, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय सभापति महोदय, मैं शोर्ट करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुछ इम्पोर्टेंट मामले थे, समय की कमी है, आप बता रहे हो, आप मुझे कह रहे हो। मैं इसको टेबल करना चाहता हूं। मैं आपको टेबल करना चाहता हूं।

श्री सभापति: मैं इसकी अनुमति देता हूं।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय सभापति महोदय, आपने जो काम किया है, हायर एजुकेशन में, माध्यमिक में, आपने प्राइमरी एजुकेशन में ऐतिहासिक काम किया है, लेकिन ऐतिहासिक निर्णयों में ऐसे धब्बे मत डालो, किसी को आब्लाइज करने के लिए, किसी को राज़ी करने के लिए, आपने जो महाविद्यालय खोले हैं उन पर आप ताला लगाने का काम मत करो।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री पब्बाराम विश्नोई।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इनको टेबल करना चाहता हूं, आप मुझे परमिशन दें। धन्यवाद।

श्री सभापति: परमिशन देता हूं।

(माननीय सदस्य श्री बाबूलाल नागर (दूदू) के सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-05 देखें।)

श्री पब्बाराम (फलौदी): परम आदरणीय सभापति महोदय। चूंकि सरकार में हैं इसलिए सरकार के पक्ष की बात करते हैं परन्तु फिर भी अंदर का दर्द झलक जाता है। दूदू से आने वाले माननीय सदस्य जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उनका दूदू तो बिलकुल शहर के पास में है, जयपुर के पास में है, उनकी यह हालत है तो रेगिस्तान में हमारा हाल क्या होगा? जो फलौदी और अन्य दूरस्थ स्थानों पर हम बैठे हुए हैं, हमारी क्या परिस्थिति है, उसका मैं

(श्री पब्बाराम)

बयान करता हूं। आप बहुत बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने इतने सीनियर सैकंडरी स्कूल बना दिए, सीनियर सैकंडरी स्कूल हमने भी बनाए थे पंचायत हैडक्वाटर पर, पर स्टाफ पूरा दिया था। हमने नीति बनाई थी, उसी नीति के तहत स्टाफिंग पैटर्न, यानी कि जितने छात्र होंगे उसके हिसाब से अध्यापक होंगे। उसके बाद में काउंसलिंग सिस्टम, माननीय वासुदेवजी देवनानी शिक्षा मंत्री थे, यानी वहीं विद्यालय में सीट खोली जाए जिसके अंदर पद ज्यादा खाली हैं, 70 परसेंट भरना है तो जालूवाला के अंदर भी 70 परसेंट बच्चे होने चाहिए, बोर्डर के ऊपर भी 70 परसेंट स्टाफ होना चाहिए, यह सुनिश्चित करने का काम पिछली सरकार ने किया, इसका यह रिजल्ट मिला कि सर्वाधिक एनरोलमेंट हुआ और हमारे सरकारी विद्यालयों के बच्चे मैरिट के अंदर भी आने शुरू हुए।

माननीय सभापति महोदय, आप यह कह रहे हैं कि हमने सीनियर सैकंडरी स्कूल खोले। आप यह बता दें, शिक्षा मंत्री महोदय, कि पूरे हिन्दुस्तान में दसवीं का स्तर कहां पर रह गया है? नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आठवीं से सीधा बारहवीं ही है, आपकी मजबूरी थी वो खोलने की क्योंकि आपको भारत सरकार से एड मिल रही है। खोलना तो था लेकिन उन विद्यालयों में शिक्षक कौन लगाएगा? शिक्षक तो आपको लगाना है, ये परिस्थितियां हैं आपकी। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों के ज्यादा पद खाली हैं। आपने स्टाफिंग पैटर्न और काउंसलिंग सिस्टम को धता बताते हुए आपके मिनी मुख्य मंत्रीजी हैं उनके माध्यम से सारे के सारे शहरों के पास में आपके शिक्षक लगा दिए, ग्रामीण विद्यालय खाली बोल रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको एक बानगी बताता हूं कि हमारे शिक्षा विभाग में तीन ब्लाक हैं, तीन ब्लाक में 1 हजार 13 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। अब कैसे शिक्षा में सुधार होगा, आप क्या करना चाहते हैं? इसी तरह से हमारे राजकीय जयनारायण मोहनलाल पुरोहित स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, इसका पूरा भवन भामाशाह ने दिया है, आज भी वो भामाशाह सपोर्ट कर रहे हैं परन्तु वहां पर हालत क्या है? 28 पद हैं, 28 में से 9 पद वहां पर भरे हुए हैं। कैसे होगा शिक्षा में सुधार? आप कह रहे हैं कि इतने कालेज खोल दिए, इतने विद्यालय खोल दिए। इसी प्रकार से इसमें कामर्स है परन्तु कामर्स के तीनों फैकल्टी में कोई भी शिक्षक नहीं है। इसी तरह से बाप, पिछली सरकार के समय में 6 करोड़ का बजट दिया था, अब

(श्री पब्बाराम)

जाकर लास्ट में बना है, परन्तु उसकी बाउंड्री नहीं बनी है। इसमें 21 पद कालेज में स्वीकृत हैं। आप यूं समझिए कि 21 में से 5 पद भरे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, यह कर दिया, शिक्षा में सुधार कर दिया, शिक्षा में एक बड़ी सोच लेकर आये हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस तरह से अगर शिक्षकों का असमान वितरण करोगे तो आपको उस क्षेत्र के लोग कभी भी माफ नहीं करेंगे।

भवन निर्माण की बात कर रहे हो आप कि हमने यह बना लिया, वो बना लिया, कहीं नहीं बनाया, समसा, समग्र शिक्षा अभियान के तहत केन्द्र के द्वारा बजट आया है वो सारा का सारा, एक कमरा मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं बनाया गया है आपके विभाग के द्वारा।

आपने पिछली बार अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के बारे में बहुत बड़ी-बड़ी बातें की थीं। आपकी सोच यह है कि हमारे यहां पर एजुकेशन में बच्चे पढ़ें नहीं। पढ़ा हुआ बच्चा हमसे दूर चला जायेगा, कांग्रेस को वोट नहीं करेगा। शिक्षक नहीं लगाना, यह शुरू से आपकी नीति रही है। विद्यालय खोल देंगे, घोषणा कर देंगे, तालियां बजवा देंगे, पर शिक्षक नहीं लगाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं। यह आपका काम है। पिछले दो साल में कुल आपने 3400 स्कूल्स की घोषणा की, उसमें से आप 1625 ही खोल पाये, 1775 नहीं खोल पाये। एक हजार की और घोषणा की है, वे कब तक खुलेंगे, कब क्या होगा, कुछ पता नहीं।

आपने हिन्दी माध्यम के बच्चों के साथ अन्याय करके उन्हीं हिन्दी माध्यम के विद्यालयों के भवनों में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोल दिये, शिक्षक भी वही हिन्दी माध्यम के। उन्हें यह भी पता नहीं है कि स्माल लैटर, कैपिटल लैटर में अन्तर क्या है। ऐसे लोगों को वहां लगाकर आप क्यों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं? आप 10 हजार शिक्षक लेने की बात कह रहे हैं। जब तक आप ये शिक्षक लेंगे, तब तक तो जनता आपको चलता कर देगी कि आपने उसके साथ किस प्रकार से धोखा किया है।

अब वहां पर एक ही सीनियर सैकंडरी विद्यालय है और आपने वहां से उस सीनियर सैकंडरी विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय खोल दिया। नजदीक में कोई भी विद्यालय नहीं होने से वहां की बच्चियों को 10-10 किलोमीटर दूर जाकर हिन्दी में पढ़ाई करनी पड़ रही है। वे बच्चियां पहली कक्षा से लेकर 10वीं-11वीं तक हिन्दी में पढ़ी हैं और आप उन्हें कह रहे हैं कि यहीं अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में एडमिशन ले लें। पढ़ाने वाले भी वही शिक्षक

(श्री पब्बाराम)

हैं। आपने लैपटॉप और टैबलेट वितरण की बात की थी, कहां पर हैं? वितरण नहीं हुआ अभी तक। थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर आप नहीं कर पाये।

हमने पिछली बार एक नियम बनाया था कि जो डार्क जोंस हैं, वहां से भी हम 2008 से पहले लगे हुए शिक्षकों का ट्रांसफर उनके स्थान पर करेंगे। आज यह सरकार अन्तिम सांसें ले रही है, उस समय भी आप कह रहे हैं कि आप नीति बना रहे हैं। नीति नहीं, आपके दिमाग में अनीति है। उन शिक्षकों का आपको ट्रांसफर करना ही नहीं है।

कुछ बातें मैंने शिक्षा मंत्री जी को लिखकर दी हैं, कृपया वे उन पर विचार करके उन्हें पूरा करने का प्रयास करें।

एक पंचायत समिति है घंटियाली, उच्च शिक्षा में वहां न तो आईटीआई कालेज है और न ही महाविद्यालय है, मेहरबानी करके वहां भी खोलने का प्रयास करें।

महोदय, मुझे एक चीज का दर्द है। आप इतने विद्वान शिक्षा मंत्री हैं, बात-बात पर संस्कृत के श्लोक बोलते हैं, क्या आप कभी नीले वस्त्र पहनकर पूजा करने के लिए मन्दिर में बैठे हैं? आपने राजस्थान के छात्रों को सरस्वती के मन्दिर में ले जाकर नीले वस्त्र पहनकर सरस्वती की आराधना करने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं तो कहता हूं, यह बहुत ही घिनौना कार्य किया है। कम से कम पिछले शिक्षा मंत्री को देख तो लेते। आप तो विद्वान थे।

"स्नानम् दानम् जपो होमः स्वाध्याय पितृ तर्पणम्।
पंचयज्ञा वृथा तस्य नीली वस्त्रस्य धारणात्।।"

इस प्रकार से पांच प्रकार के यज्ञ नष्ट हो जाते हैं, जब वह नीले वस्त्र धारण करता है। स्वाध्याय भी उसमें है, अध्ययन भी उसमें है।

माननीय सभापति महोदय, आप 2200 स्कूल ही खोल पाये। सभी पंचायत समितियों में बालिका छात्रावास खोलने की आपने बात की थी, आप नहीं खोल पाये। आपने हर पंचायत समिति पर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की बात की थी, अभी तक कई जगहों पर उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं खुल पाये हैं। आरटीई के द्वारा जो आप एडमिशन दिलवाते हैं, उनके पैसे आप नहीं दे पा रहे हैं। मॉडल स्कूल में प्राइमरी भवन बना एक करोड़ की लागत से। दो साल हुए हैं बने हुए।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री मेवाराम।

श्री पब्बाराम (फलौदी): आज वह जर्जर स्थिति में है। मैंने लिखकर दिया है। उसके अन्दर दरारें आ गयी हैं।

श्री सभापति: विराजें। अंकित नहीं होगा।

श्री पब्बाराम (फलौदी): 000

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य। सहयोग करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, आज बहुत ही महत्त्वपूर्ण मांगों पर विचार हो रहा है। मांग संख्या 20-प्रारम्भिक शिक्षा, मांग संख्या 21-माध्यमिक शिक्षा एवं मांग संख्या 22-उच्च शिक्षा पर मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार।

सभापति महोदय, हमारी पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी का मानना था कि शिक्षा मानव को मन्दिरों से मुक्त करती है। आज के युग में तो यह लोकतंत्र की भावना का आधार भी है। जन्म तथा अन्य कारणों से उत्पन्न जाति एवं वर्ग की विषमताओं को दूर करते हुए यह मनुष्य को सबसे ऊपर उठाती है।

सभापति महोदय, इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारी केन्द्र की यूपीए सरकार ने माननीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में शिक्षा का अधिकार, 2009 लागू किया, जिससे हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले। इसी का अनुसरण करते हुए हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब और हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय बी.डी. कल्ला साहब और पूर्व शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षा की व्यापक पहुंच और गुणवत्ता सुधार की दिशा में निर्णायक, ऐतिहासिक फैसले लिए और नवाचार किये। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, अभी चर्चा शिक्षा पर चल रही है और ये बीजेपी वाले भी इस पर बोल रहे थे। मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने 21 हजार स्कूलें बन्द करने का काम किया। कांग्रेस की सरकार में जो स्कूलें बनी थीं, शानदार भवन बने थे, उन्हें इन्होंने बन्द किया। उन्हें खोलने का काम हमारे मुख्य मंत्री जी ने, हमारी सरकार ने किया। वे भवन शानदार बने हुए थे, वहां से लोग दरवाजे खोलकर ले जा रहे थे। अन्दर क्या-क्या हो रहा था। यह जो कार्य मुख्य मंत्री जी और हमारी सरकार ने किया, मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में शिक्षा के कदम जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वह किसी से छिपा नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा होगा, ऐतिहासिक फैसले लिए गये। माननीय मुख्य मंत्री जी ने हर पंचायत

(श्री मेवाराम जैन)

मुख्यालय पर सीनियर सैकंडरी स्कूल खोलने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसमें किसी तरह की राजनीति नहीं की गयी। हर पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सैकंडरी स्कूल खोलने का निर्णय लिया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

मैं अपनी बात करना चाह रहा हूं। पुराने समय में मैं बालेवा गांव में पढ़ता था। बालेवा बाड़मेर से 72 किलोमीटर दूर है। उस बीच मात्र एक सीनियर सैकंडरी स्कूल थी बिसाला। तब लोग शहरों में जाकर पढ़ते थे। अब हर पंचायत मुख्यालय में जो सीनियर सैकंडरी की घोषणा की गयी है, इससे हमारे बच्चे-बच्चियों को दूर नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे संस्कार मिलेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी की दूरदर्शी सोच के कारण सभी ग्राम पंचायतों पर सीनियर सैकंडरी स्कूलें खुलीं। इसी तरह से राजस्थान में बच्चियों के लिए जितनी भी मिडिल स्कूलें थीं, उन्हें क्रमबद्ध तरीके से सीनियर सैकंडरी स्कूलें खोलने का ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्य मंत्री जी ने लिया।

हमारी बच्चियां आठवीं पास करने के बाद स्कूल छोड़कर घर चली जाती थीं। उन्हें घर न जाना पड़े, उसके लिए और स्कूलों को क्रमोन्नत किया और एक ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्य मंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में बच्चियों के लिए किया। इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

(समय: 15.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने इन चार सालों के अन्दर और इस बजट में शानदार तरीके से ऐतिहासिक रूप से स्कूलें खोलने का निर्णय लिया। इसमें किसी तरह की कमी नहीं रहे, इसके लिए ग्रामीण एरिया में 480, शहरी में 180 एवं 13 प्राथमिक विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम के राजकीय विद्यालयों में रूपान्तरित किया है। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि अंग्रेजी मीडियम की स्कूलें क्यों खोलीं, पढ़ाने वाला तो कोई नहीं है। अभी शुरुआत की है, तो आप इसको बढ़ाने का काम करो, इसकी निन्दा या आलोचना मत करो। ये गरीब बच्चे हैं जो अंग्रेजी मीडियम की कक्षा में पढ़ने की सोच रहे थे। उनके मन में सपना था, उस सपने को माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूरा किया। आज अंग्रेजी मीडियम की स्कूलें खुलेंगी और उसमें अंग्रेजी मीडियम में बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने के लिए 10 हजार अध्यापकों की भर्ती के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया है और अभी इस बजट में भी एक हजार शहरों में और एक हजार ग्रामीण एरिया में

(श्री मेवाराम जैन)

अंग्रेजी मीडियम की स्कूलें और खोलने का निर्णय लिया है, जो बहुत ही स्वागत योग्य है। इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आने वाले भविष्य में इससे बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, 1054 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे ही उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करना, 3834 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करना, 548 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करना और 143 नवीन विद्यालय खोले गये हैं और आपने देखा होगा कि बच्चों का प्रवेश था, वह 20 प्रतिशत इन विद्यालयों को खोलने की वजह से बढ़ा था। दूर-दराज एरिया में जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, स्कूल नहीं जा पा रहे थे, वे बच्चे स्कूल खोलने से उनमें आये, क्योंकि प्राइवेट विद्यालय शोषण कर रहे थे। आज हालत क्या है कि जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें शानदार व्यवस्थाएं हो रही हैं, अध्यापक लग रहे हैं। कुछ पद खाली जरूर हैं पर उनको भी भर रहे हैं। 25 हजार पहले भर लिए, 65 हजार भर्ती की प्रोसेस में हैं और फर्स्ट, सैकण्ड ग्रेड, रीट की परीक्षा हो चुकी है जिससे खाली पदों की आप बात कर रहे हैं वे बहुत ही जल्दी सारे खाली पद भरे जाएंगे। आप चिन्ता नहीं करें, राजस्थान की सरकार पूरी तरह से चिन्तित है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिले, स्कूलों में अध्यापक कैसे लगें, नई स्कूलें कैसे खुलें। यह सरकार की सोच है और आने वाले दिनों में आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी इस बजट के अन्दर 100 प्राथमिक विद्यालय खोलने, 300 विद्यालयों को क्रमोन्नत करना और 300 विद्यालयों में नवीन विषय खोलने का निर्णय लिया है। सभापति महोदय, इसमें मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि रेगिस्तानी और पहाड़ी एरिया में 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर-दूर गांव और ढाणियां बसे हुए हैं, वहां पर और अधिक स्कूलें खोलने की आवश्यकता रहेगी इसलिए वहां पर आरटीई के नोर्म्स के अनुसार प्राइमरी से मिडल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता रहेगी। जहां मिडल स्कूलें हैं और उनके पास में सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं है तो वहां पर खोलने की आवश्यकता रहेगी। जहां दो किलोमीटर नजदीक कोई स्कूल नहीं है वहां पर नवीन प्राथमिक स्कूलें खोलने की भी मैं बात करूंगा कि इस बजट में जो संख्या बतायी गयी है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि

(श्री मेवाराम जैन)

इसे बढ़ायेंगे, जिससे बच्चों को दूर नहीं जाना पड़े और हमारे रेगिस्तानी एरिया में स्कूलें खुलने से शिक्षा आगे बढ़ेगी तथा बच्चों-बच्चियों को शिक्षा का लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, नवाचार की बात करें तो उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर विज्ञान को ऐच्छिक विषय के रूप में लिए जाने का विकल्प दिया है। प्रत्येक ब्लाक मुख्यालय पर एक-एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कला, विज्ञान, वाणिज्य तथा कृषि विज्ञान के चारों संकाय खोलने की घोषणा की है जो स्वागत योग्य है। प्रदेश में विद्यालयों में अध्ययनरत बालकों के लिए 8 आवासीय विद्यालय एवं सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास खोले जाएंगे, जिससे बच्चों को वहां रहने की दिक्कत नहीं हो तथा इन आवासीय विद्यालयों में पढ़ने की सुविधा हो। यह माननीय मुख्य मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी की सोच है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिले, उनको रहने-ठहरने की कोई दिक्कत नहीं हो।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, देवनारायण बालक छात्रावास हो या बालिका छात्रावास हो, अनुसूचित जनजाति के भी 8 छात्रावास खोलने का निर्णय लिया, जिससे उन बच्चों को इससे राहत मिलेगी जो गरीब हैं, जा नहीं पा रहे हैं। उनके लिए यह खोलने का निर्णय लिया है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे बाल गोपाल योजना हो, चाहे आंगनबाड़ियां खोलने की बात हो और जो योजनाएं लागू की गयी हैं कि बच्चों का सही तरह से कैसे पोषण हो। दूध वाली स्कीम जो पहले बन्द थी, उसको वापस शुरू किया। सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि बच्चों को यूनिफार्म देने की बात की गयी है तथा सिलाई के पैसे भी साथ में दिये जा रहे हैं, जिससे आज तक 63 लाख 20 हजार से ज्यादा विद्यार्थी इससे लाभान्वित हुए हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा एरिया बोर्डर एरिया है और वहां पर बाहर से अध्यापक लगते हैं फिर ट्रांसफर कराकर चले जाते हैं, जिसके कारण पद खाली रहते हैं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जो भर्तियां हो रही हैं उनमें फिक्स कर लें कि और भी थर्ड ग्रेड, सैकण्ड ग्रेड हो और वहां से कोई जाना चाह रहा है, स्थानान्तरण कराना

(श्री मेवाराम जैन)

चाह रहा है तो उनका आप स्थानान्तरण करो पर कितने पद खाली हैं, कितने जा रहे हैं, उसके लिए जो नई भर्ती हो रही है उसमें पहले जहां खाली हैं वहां ट्रांसफर कर दो और इतने वहां कम कर दो, ताकि ये जाने वाले वहां चले जाएंगे और हमारे खाली पद भर जाएंगे। इस तरह से इस भर्ती में आप कर लेंगे तो वे कई सालों से जाने का, ट्रांसफर का कर रहे हैं तो उनके लिए भी आराम हो जाएगा और हमारे भी स्कूलें खाली नहीं रहेगी। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा।

मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में शानदार काम किया है। अब आलोचना आप कितनी भी करो चाहे अंग्रेजी मीडियम की हो, चाहे ग्रामीण ओलम्पिक खेल करने की बात करो, चाहे भर्तियों की बात करो, शिक्षा के क्षेत्र में शानदार काम हो रहा है और इसके लिए मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं यही निवेदन करूंगा कि आने वाले दिनों में नई स्कूलें और खोलने के लिए मैं कहूंगा तथा जो पद खाली हैं उनके लिए जो भर्ती की शुरुआत की गयी है उसमें हमारे बोर्डर एरिया में ये पद भरे जाएं, यही मैं निवेदन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 20-प्रारम्भिक शिक्षा, मांग संख्या 21-माध्यमिक शिक्षा और मांग संख्या 22-उच्च शिक्षा पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

हम शिक्षा विभाग पर चर्चा कर रहे हैं और विद्यालय के अन्दर जब बच्चा प्रवेश करता है तो दरवाजे पर लिखा होता है 'ज्ञान के लिए प्रवेश-सेवा के लिए प्रस्थान'। हमारे शिक्षा मंत्री जी बहुत ही विद्वान हैं और इनकी विद्वता का आज प्रदर्शन भी होगा। पिछली बार इनको दूसरे विभाग का मंत्री बना दिया था, पर अब वास्तव में सही मंत्री बने हैं। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि शिक्षा ही इस देश में, इस प्रदेश में सब कुछ है और ज्ञान के लिए

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

शिक्षा जरूरी है। शिक्षा उन्नति का द्वार है, शिक्षा प्रगति का द्वार है, शिक्षा जीवन में सफलता के द्वार खोलती है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो सफलता की ओर अग्रसर करती है तथा शिक्षा हमें इस संसार में सर्वश्रेष्ठ बनाती है।

किताबी ज्ञान ही शिक्षा नहीं, व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव से भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। कोफी अन्नान ने कहा था, ज्ञान ही ताकत है, जानकारी स्वतंत्रता है। प्रत्येक परिवार में शिक्षा प्रगति का आधार है। जॉन डिवी ने कहा, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं, शिक्षा ही जीवन है। गुरु और शिष्य का नाता हमारे इस देश में और पूरे संसार में है। आदिकाल से गुरु और शिष्य का नाता बना हुआ है। गुरु का दर्जा ईश्वर से भी बड़ा है। कबीरदास जी ने कहा था, "गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागूं पाय। बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताय।"

इस अवसर पर मैं कहना चाह रहा हूं, हमारे गुरु हमको अंधकार से प्रकाश की ओर लाते हैं और जीवन में हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत कोई देता है तो वह गुरु देता है। हमारे गुरुजन पढ़ाने के साथ-साथ हमारा सर्वांगीण विकास करते हैं। हमारा शिक्षक देश का निर्माता कहलाता है, बालकों का निर्माण करता है। बालकों को आत्मविश्वासी बनाता है, निर्भीक बनाता है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है, ज्ञानवान बनाता है, तार्किक बनाता है, देशभक्त बनाता है, अनुशासित बनाता है, राष्ट्रवादी बनाता है, ईमानदार बनाता है, मानवता का पुजारी बनाता है। करुणा के भावों से ओत-प्रोत करके बालक का सर्वांगीण विकास करने का काम कोई करता है तो वह काम शिक्षक करता है। हम गुरु को बारम्बार प्रणाम करें तो भी कम है।

शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर बजट का प्रावधान तो खूब रखा जाता है। सरकारें विद्यालय तो खोलती हैं, कालेज भी खोलती हैं, प्रशिक्षण संस्थान भी खोलती हैं, लेकिन शैक्षणिक गतिविधियों के लिए व संचालित करने के लिए विभिन्न श्रेणी के पदों की आवश्यकता होती है। उन पदों पर भर्ती नहीं करने के कारण, आपका यह वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 मेरे पास है। मैं आज की स्थिति बताऊं, शिक्षा के क्षेत्र में द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों के स्वीकृत पद 17 हजार 439 हैं और 10 हजार 445 पद भरे हैं और 6 हजार 994 पद खाली पड़े हैं। यानी, 7 हजार पद खाली होंगे तो शिक्षा का तो भट्ठा बैठना ही

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

है। द्वितीय लेवल के 13 हजार 562 पद खाली पड़े हुए हैं। प्रथम लेवल के पद 14 हजार 560 खाली पड़े हुए हैं। शारीरिक शिक्षक और उनके समकक्ष 4 हजार 184, मैं कुल मिलाकर चारों का योग लगाऊं तो 2 लाख 8 हजार 237 पद स्वीकृत हैं, उनमें से 1 लाख 68 हजार 937 पद भरे हुए हैं और लगभग 40 हजार पद राजस्थान में शिक्षा विभाग में खाली होंगे, तो गुरुदेव, शिक्षा का भट्ठा बैठ जायेगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप शिक्षकों के जितने भी पद खाली हैं, उन पदों को भरकर शिक्षा की गुणवत्ता को और शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करें। अभी मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर कई पद खाली हैं। फिर, आपने स्थानान्तरण का उद्योग प्रारम्भ किया। स्थानान्तरण का उद्योग ऐसा चला कि हमारे और पद खाली हो गये। मुख्य मंत्री जी ने एक समोराह के अन्दर अध्यापकों से पूछा था कि स्थानान्तरण में पैसा तो नहीं लगता है। मुख्य मंत्री जी के सामने अध्यापकों ने खड़े होकर कहा, पैसे लगते हैं। दूसरी बार पूछा, क्या पैसे लगते हैं? कुर्सी पर खड़े होकर अध्यापकों ने कहा, पैसे लगते हैं। ऐसी स्थिति राजस्थान प्रदेश में बनी हुई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा स्थानान्तरण उद्योग नहीं चले। खैर, कल्ला साहब, आपके समय में ऐसा नहीं होगा, हमें पूरा विश्वास है। जो होना था, हो गया और वे चले गये। वह नाथी का बाड़ा था, नाथी का बाड़ा बन्द हो गया।

मैं प्रबोधकों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। 1993 में, मैं जब पहली बार आया था, तब गुलाब चन्दजी कटारिया, शिक्षा मंत्री थे। उस समय प्रबोधक लगाये गये थे। आपने प्रबोधकों की पदोन्नति का काम करने के लिए, अभी हमारे मुख्य मंत्री जी ने बीपीएड, बीएड और बीबीएड, जितने भी प्रबोधक हैं, उन प्रबोधकों की पदोन्नति के लिए दिनांक 01.11.2021 को वित्त मंत्री, वित्त विभाग को हमारे मुख्य मंत्री जी ने सहमति प्रदान की, लेकिन आज तक 5 हजार प्रबोधकों की पदोन्नति का कार्य पैंडिंग पड़ा हुआ है। यह आपकी पुस्तक कह रही है।

एक निवेदन और है, प्रबोधकों को वेतन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। इनका नाम परिवर्वित करके अध्यापक कर दो। क्या दिक्कत आ रही है? प्रबोधक कहो, चाहे अध्यापक कहो, बात तो वही है। इसलिए उनका नाम परिवर्तन कर दें तो उनको एक सम्मान मिलेगा।

पैराटीचर, पंचायत सहायकों के वेतन के लिए भी मुख्य मंत्री जी ने

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

कुछ समय पहले, दो-तीन महीने पहले कहा था, इनको 21 हजार रुपये का वेतन दिया जायेगा। फिर अपनी बात से पलट गये और उनको कहा अब 10 हजार रुपये देंगे, अब उन 10 हजार का भी पता नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, विद्या सम्बल योजना, अध्यापकों की कमी को देखते हुए आपने विद्या सम्बल योजना प्रारम्भ की। फार्म जमा कराये, करोड़ों रुपये अभ्यर्थियों के खर्च हो गये और वह योजना बन्द, क्या होगा? माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार से बच्चों को गुमराह नहीं करें तो अच्छा रहेगा।

चुनाव के समय में कांग्रेस पार्टी ने कुछ वादे किये, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, भत्ता तो आज दिन तक नहीं मिला। उन बेरोजगारों को धोखा जरूर मिला।

अभी बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि आपके राज में 21 हजार विद्यालय बन्द हो गये। आपने यह घोषणा की थी कि हम आते ही सारे विद्यालय प्रारम्भ कर देंगे। क्या विद्यालय प्रारम्भ हो गये? वे सारे के सारे विद्यालय अभी तक बन्द पड़े हुए हैं। आप वादा करते हो, निभाते नहीं हो। यह जादूगर की सरकार चल रही है। अध्यापकों की भर्ती के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपस में वार्ता नहीं।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): अभी प्रदेश के अन्दर परीक्षाएं हो रही हैं। रीट की परीक्षा हुई, सबने खूब जोर-जोर से तैयारियां कीं और पेपर लीक हो गया। क्या यह पेपर लीक की सरकार है? मैं निवेदन करना चाहूंगा, अभी मैं एक मार्केट में गया था। एक बिल्डिंग को सड़क पर धराशायी देखा, मैंने पूछा, क्या हुआ? पता चला कि यह पेपर लीक करने वाली बिल्डिंग है। मैंने पूछा, कैसे पेपर लीक करती है। वह किरायेदार है, उस किरायेदार की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया गया। आपको बुलडोजर चलाना था तो वास्तव में जो बेईमानी करता है, जो उसका पैतृक मकान है, उसको आप जरूर सज़ा देते तो हमको बड़ी खुशी होती, लेकिन आपने उसके साथ अन्याय किया।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं दो महीने पहले एक विद्यालय में गया। मुझे आमंत्रित किया गया था। उस विद्यालय में मुझे पोशाक वितरण के कार्यक्रम में बुलाया। मुझे अच्छा लगा पोशाक दे रहे थे।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): सर, अभी तो चार मिनट ही हुए हैं। मेरा निवेदन है, कृपा रखें।

मैं उस पोशाक का वितरण करने लगा। मैंने देखा थैले के ऊपर हमारे जादूगर मुख्य मंत्री जी की फोटो थी, प्रसन्नता हुई। मैंने कहा, यह जो पोशाक का पैसा है, वह 60 प्रतिशत पैसा केन्द्र सरकार का है, इस पर प्रधान मंत्री जी की फोटो और लग जाती तो कौन-सा बुरा था। यानी, प्रधान मंत्री जी की फोटो से आपको क्या एलर्जी है? पैसा लेने में तो आप एलर्जी नहीं करते हो। उनका फोटो छापने में ऐसी एलर्जी कर रहे हो। मेरा निवेदन है कि ऐसा नहीं करेंगे तो ठीक रहेगा। अभी तक पोशाक का पता नहीं, सिलाई के पैसे का पता नहीं है। मुझे अभी पता चला कि राजस्थान में कक्षा एक से आठ तक 75 लाख बच्चों का नामांकन है और आप ड्रेस दे रहे हैं 67 लाख बच्चों को, 8 लाख बच्चों की पोशाक कहां गई? कहां गायब हो गई है? वे बच्चे क्या विदाउट ड्रेस में आयेंगे?

मैं अभी एक विद्यालय में और गया। बाल गोपाल दुग्ध योजना, जिसे चार साल से आपकी सरकार ने बन्द कर रखा था, उस योजना को प्रारम्भ किया, बहुत-बहुत धन्यवाद। बच्चों को दूध मिले, लेकिन डेयरी का मिलना चाहिए। आप डेयरी का दूध नहीं पिला रहे हैं, आप डिब्बा पैक पाउडर का दूध पिला रहे हैं, वह घटिया दूध है। वह घटिया पाउडर है। कौन-सी कम्पनी को आप आब्लाइज करना चाहते हैं? यह आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पाउडर वाला दूध पीने से बच्चे बीमार हो रहे हैं। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा, हमारी पूर्ववर्ती सरकार में जिस प्रकार से बच्चों को डेयरी का दूध मिलता था, वही डेयरी का दूध पिलायेंगे तो बच्चे अच्छे स्वस्थ होंगे। एक और निवेदन करूंगा, गाय के अन्दर बुद्धि होती है, भैंस के अन्दर बुद्धि नहीं होती है। गाय को खेत से घर आने में कोई समय नहीं लगता है और यदि भैंस को आप छोड़ देंगे तो वह घर तक नहीं पहुंचेगी न खेत तक पहुंचेगी। इसलिए बच्चों को यदि आप पिलाना चाहते हो तो गाय का दूध पिलायें तो और अच्छा होगा। मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): अंग्रेजी स्कूल खोलने का काम आपने किया है। अंग्रेजी स्कूलों की हालत क्या है? हमने भी विद्यालय खोले हैं।

श्री सभापति: श्री पदमाराम।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): सर, दो मिनट में अपनी बात पूरी करता हूं।

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य। प्लीज, सहयोग करें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मेरा निवेदन है आप शिक्षा विभाग के अन्दर भर्ती करें। विद्यालय के अन्दर कक्षा-कक्षों की कमी को पूरा करें, फर्नीचर लगायें, बिजली की व्यवस्था करें, कम्प्यूटर की व्यवस्था करें। आप ऐसी सारी व्यवस्था करेंगे तो मैं सोचता हूं कि शिक्षा विभाग के साथ न्याय करेंगे। बालकों का भविष्य बनायेंगे तो आपके ऊपर भी कोई न कोई ईश्वर रहम करेगा वरना, आपकी सरकार तो जाने वाली है। इसे कोई रोक नहीं सकता है। इसी के साथ बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिन्द।

सूचना

श्री किरोड़ी लाल मीणा, सांसद का शहीदों की वीरांगनाओं के साथ जारी धरना

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, अभी हम धरना स्थल पर गये थे और धरना स्थल पर जो बात माननीय मंत्री जी ने कही, वह पूरी तरह से असत्य निकली।

श्री सभापति: विराजिए। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: आसन पैरों पर। विराजिये आप। विराजिये। आसन पैरों पर है। कुछ परम्पराएं सीख लीजिये। प्लीज विराजिये आप। क्यों उत्तेजना फैला रहे हो? माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: कल माननीय अध्यक्ष महोदय ने आपको पाबन्द किया था। आपको बोलने के अधिकार से वंचित किया जायेगा, मैं सही कह रहा हूं आपसे। प्लीज, विराजिये आप। माननीय सदस्य, विराजिये। बहुत वरिष्ठ हैं विराजिये आप।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): 000

श्री सभापति: आप विराजिये। प्लीज। एक मिनट सुनिये, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। जितने भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं आप यदि यह चाहते हैं कि उनका वक्तव्य नहीं हो तो आसन को कोई एतराज नहीं है, आसन सीधा मंत्री जी को रिप्लाई के लिए बुलायेगा। मंत्री अपना रिप्लाई देंगे और हाउस एडजर्न होगा। मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा इस तरह से। क्या तरीका है यह? बेवजह उत्तेजना फैला रहे हो। जो माननीय सदस्य तैयारी करके आये हैं, बोलना चाहते हैं, आपको हाउस को हाईजैक करने बिलकुल नहीं दूंगा मैं। आगे से ध्यान रखें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं आपको फिर पाबन्द कर रहा हूं। माननीय राठौड़ साहब, मैं आपको पाबन्द कर रहा हूं माननीय सदस्य को बोलने के अधिकार से वंचित करूंगा मैं। इनको किसी बात पर बोलने की अनुमति नहीं दूंगा मैं। यह कतई ठीक नहीं है। आप यह चाहते हैं कि हाउस को हाईजैक करके जो मर्जी आये बोलेंगे आप हाउस में। इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। अच्छा लगता है? पूरा राजस्थान आपको जानता है कि राजस्थान में आप शिक्षा में क्या नवाचार करने जा रहे हैं। क्या आप अपना नया सन्देश देना चाह रहे हैं?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: विराजिये आप। आप अपने सदस्यों को अनुशासित रखें। अच्छी परम्पराएं नहीं हैं ये, हर बात में बोलना, हर बात में इंटरवीन करना। बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। 1990 से आप मेरे साथ हैं। यही सीखा आपने इतने वर्षों में? क्या सन्देश देना चाहते हैं, जो नये लोग आये हैं उनको आप क्या सन्देश देना चाहते हैं? अभी भी वक्त है। माननीय राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं क्षमा के साथ बात प्रारम्भ करना चाहूंगा कि यह उत्तेजना क्यों फैली। अभी माननीय सदस्यों का एक शिष्ट मण्डल जहां चार वीरांगनाएं धरने पर बैठी हैं वहां जाकर आया और इन्होंने जो मुझे बताया और उन चारों वीरांगनाओं से मिलकर बात यह सामने आयी कि माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा था कि सिर्फ एक वीरांगना की, जो शहीद रोहिताश्व हैं, उनके भाई की नियुक्ति के अलावा सारी बात हो गयी। अब वो शहीद की वीरांगनाएं वहां बैठी हैं चार-चार। आपके मंत्री गये, वहां वादा आपने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किया, उसके छोटे भाई को नौकरी का, ढाई सौ मीटर सड़क का, उसने जो स्मारक बना दिया उसकी चारदीवारी का। यह शहीद रोहिताश्व की पत्नी मंजू, नगर में सुन्दरी पत्नी जीतराम को वादा किया, नगर में उसके कालेज का नामकरण का, शहीद के भाई को नौकरी का। मधुबाला हेमराज की अदालती चौराहे पर शहीद की मूर्ति लगनी थी, शहीद के घर तक सड़क बननी थी। शहीद जहां विनोदकलां गांव में पढ़ा, उसको क्रमोन्नत करना था। रेणु सिंह शहीद जितेन्द्र सिंह की, इसकी अनुकम्पात्मक नियुक्ति थी। मैं समझता हूं आप सदन में बोलें, आप बोलें, आपका अधिकार है। एक मिनट, मैं दो मिनट में बैठूंगा। अपनी शान्ति से बात करेंगे, कोई उत्तेजना फैलाना नहीं चाहते।

माननीय सदस्य वहां जाकर आये, मैं भी जाकर आया। अब चार-चार वीरांगनाएं नन्हें-नन्हें बालकों के साथ वहां बैठी हैं और आपने सदन में यह कह दिया कि सारी बात आपकी हो गई। आपसे प्रार्थना हमने इतनी ही की थी फोल्डेड हैंड कि आप उन वीरांगनाओं से मिलकर यह छोटी-सी बात है, अब मूर्ति लगनी है, नगरपालिका ने एनओसी दे दी। आपके मंत्री जो गये, उनका वीडियो लेकर आया हूं, मैं सभापति महोदय को सुनाऊंगा। वहां घोषणा कर दी जहां धूं-धूं करके शहीद की चिता जल रही थी, अब उन घोषणाओं को पूरा कर दो आप और जो वो धरने पर बैठी हैं, उनसे बुलाकर बातचीत करो। सिर्फ इतनी सी बात है, सभापति महोदय।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मंत्री जी ने गलतबयानी की। या तो ये अपने बयान से मुकर रहे हैं।

श्री सभापति: विराजिये प्लीज। आपने अपनी बात कह दी। आप मंत्री को बाध्य नहीं कर सकते। प्लीज। श्री पदमाराम।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, जो आप कह रहे हैं, जो वहां कोटा डिविजन में वीरांगना है, उसका तो खेत में वहां दो किलोमीटर की कोई सड़क का मामला था, जिसमें सड़क कटी नहीं थी। उनके खुद के परिवार की ढाणी है। उसके लिए भी मैंने वादा कर दिया था, उसको कटवा देंगे। दूसरा, यह जो शाहपुरा वाला मामला था, उसमें ढाई सौ मीटर सड़क बननी है। ढाई सौ मीटर में दोनों भाइयों के कोई विवाद है, पीछे से डंडा भी हो गया और जो बाकी बची है उसके अन्दर भी विवाद

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

सैटल होते ही वह रोड भी बन जायेगी। एमएलए खुद बुलाकर, मैंने बात कर ली थी और नौकरी की बात है तो नौकरी में सिर्फ वह देवर वाली बात मैंने की थी, बाकी जो चीजें हैं वे सारी सोर्ट आउट हो रही हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): स्कूल का नामकरण?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): स्कूल के नामकरण का आ रहा है, मेरे पास जो कालेज का है नगर वाला। वह आ रहा है वहां से प्रस्ताव बनकर। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, प्लीज विराजिये आप। आपको यदि कोई चर्चा करनी है तो आप इनके चैम्बर में जाकर करें। श्री पदमाराम।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, कई ऐसे सेंसेटिव इश्यू हैं।

श्री सभापति: नहीं-नहीं कोई इश्यू नहीं है। माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें। उन्होंने अपनी बात बता दी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं कोई सनसनी फैलाना नहीं चाहता पर शहीदों की वीरांगनाएं बैठी रहें, मंत्री बयान देना चाहें और आसन अनुमति नहीं दे। यह कोई बात थोड़े है।

श्री सभापति: माननीय राठौड़ साहब, उन्होंने अपनी बात कह दी। आपने अपनी बात कह दी, उन्होंने अपनी बात कह दी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, यह बात गलत है।

श्री सभापति: नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह बात थोड़ी है, सभापति महोदय, आज चार-चार वीरांगनाएं बैठी हैं।

श्री सभापति: प्लीज, माननीय राठौड़ साहब, यह गलत परम्परा है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि यह गलत परम्परा है। जाइये, अपने आसन पर जाइये। अपने आसन पर जाइये आप। प्लीज जाइये अपने आसन पर। माननीय सदस्य। माननीय राठौड़ साहब, मैं फिर आपसे विनम्र आग्रह कर रहा हूं। मैं, माननीय राठौड़ साहब, फिर आग्रह कर रहा हूं, प्लीज जाइये अपने आसन पर। नहीं चलाना हाउस आपको? प्लीज जाइये आप। विराजिये आप। माननीय राठौड़ साहब, यही परम्परा डालेंगे आप? जाइये आसन पर जाइये।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 20-प्रारंभिक शिक्षा, मांग संख्या 21-माध्यमिक शिक्षा व मांग संख्या 22-उच्च शिक्षा पर विचार

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय राठौड़ साहब, आपके माननीय सदस्यों को बैठाओ। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 20-प्रारंभिक शिक्षा, मांग संख्या 21-माध्यमिक शिक्षा और मांग संख्या 22-उच्च शिक्षा के ऊपर चर्चा करने का आपने समय दिया, आपका बहुत बड़ा आभार।

सभापति महोदय, मनुष्य जीवन के अन्दर शिक्षा का योगदान बहुत अहम योगदान है। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीयेगा वह दहाड़ेगा। शिक्षा एक ऐसा धन है न तो कोई उसको खर्च कर सकता है न कोई बांट सकता है न कोई छीन सकता है और मनुष्य जीवन शुरुआत से लगा कर अन्त तक हमेशा शिक्षा ग्रहण करता रहता है और उसके अन्दर प्रगति होती रहती है। उस विषय पर आज चर्चा हो रही है। सदन के सभी माननीय सदस्य इस शिक्षा की अलख जगाने के लिए मिल कर नवाचार कैसे करें, उच्च क्वालिटी की शिक्षा आम ग्रामीण क्षेत्रों में हम कैसे पहुंचायें, उसके बारे में विचार करना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले चार साल से राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री और हमारे शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षा में कई नवाचार किये हैं। हर जगह पर स्कूल खोलना, पुरानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो 21 हजार स्कूलें मर्ज की थीं उनको वापस चालू करना, पंचायत हैडक्वार्टर पर पहले भी सीनियर सैकण्डरी स्कूलें खोली थीं, परन्तु जो पंचायत वंचित थी, उसी पंचायत हैडक्वार्टर पर सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोलना, सैकण्डरी स्कूलों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करना और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिकाओं की प्राइमरी स्कूलों को मिडल स्कूल किया, मिडल को सीनियर सैकण्डरी करके एक मैसेज दिया कि जिस परिवार में महिला शिक्षित है वह परिवार हमेशा शिक्षा की ओर अग्रसर होगा। संस्कार की सीढ़ी महिला को मजबूती देने के लिए राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह नवाचार किया है, मैं उनको बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं।

आज जो पिछड़ा क्षेत्र है, वह पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्र है, उसमें स्कूलें बहुत खुली हैं। भारत सरकार द्वारा राइट टू एजुकेशन के तहत भी

(श्री पदमाराम)

स्कूलें खुल गई हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि रेगिस्तानी क्षेत्रों को कुछ प्राथमिकता दी जानी चाहिये। रेगिस्तान में जो भी अध्यापक लगते हैं, वह दो साल अपनी सर्विस पूरी करके ट्रांसफर कराकर वापस चले जाते हैं और इससे रेगिस्तानी स्कूलें खाली हो जाती हैं। आज हमारे बोर्डर क्षेत्र की सभी सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में लेक्चरर के पद खाली हैं, वरिष्ठ अध्यापकों के पद खाली हैं और प्रिंसिपल के तो लगभग सभी पद खाली हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में एक गरीब के बेटे को शिक्षा देना उचित नहीं है। इसलिए मेरा माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि अभी लेक्चरर और वरिष्ठ अध्यापकों की परीक्षा हो गई है, इन परीक्षाओं में आप अभ्यर्थियों से विकल्प भरवाते हो, वह विकल्प है कि कौन अभ्यर्थी दूर जाना चाहेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको प्राथमिकता देवें और दूर-दराज की स्कूलों में विशेष सब्जेक्ट खोलें और पहली प्राथमिकता से उनको भरें।

दूसरा मेरा निवेदन है कि शहर के नजदीकी स्कूलों में अध्यापकों की भरमार है, पूरी स्कूलें भरी हुई पड़ी हैं, वहां स्टूडेंट से ज्यादा अध्यापक नौकरी कर रहे हैं। उनके बारे में आप विचार करें और ग्रामीण क्षेत्रों की खाली स्कूलों में इनका ट्रांसफर करके वहां भेजें, यह पहली प्राथमिकता होनी चाहिये। जब भी ट्रांसफर होते हैं, हर आदमी चाहता है कि मैं आपका वोटर हूं, मेरे बेटे को घर के नजदीक लगावें, अपन सब मिलकर दूर-दराज के लेक्चरर, वरिष्ठ अध्यापक, थर्ड ग्रेड टीचर, प्रिंसिपल को वहां ले जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति खराब हो जाती है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप प्राथमिकता के तौर पर इस पर विचार करें।

आपने बहुत नयापन किया है। आपने शिक्षा की अलख जगाने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोल दीं, बहुत बड़ी योजना है। विरोध कुछ भी कर दो, जब शुरुआत होती है पूरे संसाधन नहीं होते हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री जी भाषण दे रहे थे कि हमारे समय में हमने बहुत अच्छा कर दिया। आप कह रहे थे कि हमारे क्षेत्र में हमने नयापन किया। हमने कोई ऐसा जादू तो किया नहीं, आपने जो नयापन किया था उसको हमारी सरकार ने बंद तो किया नहीं। किया कुछ नहीं, बातें करना आपको बहुत अच्छी तरह से आती हैं। आप बहुत बड़ी-बड़ी बातें करना चाहते हैं परन्तु मूल काम को करने की भावना आपमें बहुत कम है। आप सरकार की प्रशंसा तो कर नहीं सकते, इसलिए आपको विरोध करना है, यह आपका धर्म है, आप निभाओगे लेकिन जो हकीकत है,

(श्री पदमाराम)

वास्तव में सरकार ने एक लगन के साथ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा को मजबूती देने के लिए और आम आदमी और गरीब के बेटे में एक नई रोशनी लाने का काम किया है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को मैं बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। आज एक गरीब के दिल में एक जज्बा जगा है कि मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जायेगा और वह भी कलेक्टर, एसडीएम, इंजीनियर, डाक्टर बन सकता है। आज एक नई सोच की शुरुआत हुई है। आज हमने इंग्लिश मीडियम के अध्यापकों को इंटरव्यू के माध्यम से इंग्लिश मीडियम स्कूलों में लगाया है, यह बहुत अच्छी बात है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जितनी भी इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली हैं उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हो, परन्तु इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो संसाधन होने चाहिये, उसके लिए आप नवाचार करें, पहले उनकी पूर्ति करें। इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर होने चाहिये, भवन होना चाहिये, बच्चों के कम्प्यूटर की व्यवस्था होनी चाहिये। वहां शिक्षा को बढ़ोतरी देने के संसाधनों में आप लगन से काम करें।

राजस्थान की जनता आपकी तरफ देख रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जनता के लिए दिल खोलकर काम किये हैं और जनता आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। किसी भी क्षेत्र में विरोध नहीं है। विरोध नाम की चीज नहीं है। आपको तो यह मैसेज जनता तक पहुंचाना है। जहां पुराने भवन हैं, उनकी मरम्मत की व्यवस्था करो, जहां स्कूलों में शौचालय नहीं है, वहां शौचालय की व्यवस्था करो, पानी की व्यवस्था करो। स्कूल के भवन मजबूत हों, स्कूलों में ज्यादा संसाधन हों और शिक्षा की बढ़ोतरी के लिए उच्च क्वालिटी के अध्यापक हों। आज प्राइवेट स्कूलों की हालत अच्छी नहीं है। पहले यह होड़ लगी हुई थी कि हर आदमी अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता था, वह मामला अब धीरे-धीरे कम हो गया है। हाई प्रोफाइल स्कूलों में जरूर पैसे वाले लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन आज आपका हर अधिकारी, कर्मचारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहता है। आज रिजल्ट में भी टॉप लेवल पर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल के जितने भी टॉप बच्चों की बातें हो रही हैं, वह सिर्फ मैनेजमेंट के तौर पर आते हैं। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि आप इसमें नयापन करें।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): आपने शिक्षा की बढ़ोतरी के लिए बहुत-सी स्कूलों को क्रमोन्नत किया। आपने ब्लाक स्तर पर सभी सब्जेक्ट खोलने की घोषणा कर दी। छात्रवृत्ति की घोषणा कर दी। आपकी मेहरबानी से मेरे विधान सभा क्षेत्र में कस्तूरबा गांधी छात्रावास खोल दिया। अनुसूचित जनजाति को मजबूती देने के लिए अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका विद्यालय खोल दिया। अल्पसंख्यकों को मजबूती देने के लिए दो-दो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोल दिये। कस्तूरबा गांधी छात्रावास गोडके तले में खोल दिया, आपने बहुत अच्छा काम किया है। बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए गार्गी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार चालू किये। अच्छे अंक वालों को स्कूटी की व्यवस्था, साइकिल की व्यवस्था की। दूध की व्यवस्था, बच्चों की पोशाक की व्यवस्था, सिलाई की व्यवस्था, वाउचर के मार्फत उनके किराये की व्यवस्था की, ऐसी कई योजनाएं लाये हैं। इसके लिए जनता आपकी वाहवाही कर रही है। हर क्षेत्र में हम जाते हैं तो हमारी प्रशंसा होती है, हमारा स्वागत होता है। आपने मेरे विधान सभा क्षेत्र में 68 सीनियर सैकण्डरी स्कूलें खोली हैं, बहुत बड़ा काम किया है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि शिक्षकों की कमी पर आप विशेष ध्यान देंगे और दूरदराज की सभी स्कूलों में शिक्षकों की पूर्ति करेंगे।

श्री सभापति: श्री नारायण बेनीवाल।

श्री पदमाराम (चौहटन): दूसरा, उच्च शिक्षा मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आपने बहुत कालेजें खोल दीं, बहुत अच्छी बात है। आज गरीब के बेटे के दिल में एक जज्बा है कि मैं मेरे घर के नजदीक की कालेज में जाकर अध्ययन कर लूंगा, डिग्री हासिल कर लूंगा और भारत का नेक नागरिक बनने की चेष्टा करूंगा।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): मेरा निवेदन है कि जो प्राइवेट कालेजें चल रही हैं, दूसरी प्राइवेट संस्था चल रही है..

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): एक मिनट। वह जनता के साथ दोहरा घात कर रहे हैं। मनमर्जी से पैसे वसूल किये जा रहे हैं। पहले से बच्चों को कह देते हैं कि आपको स्कूल आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी कालेज है ही नहीं, कालेज नाम की चीज नहीं है और लोगों से पैसा वसूल करने का काम कर रहे

(श्री पदमाराम)

हैं। मंत्री जी, इसमें आप थोड़ा-सा ध्यान दें और नोट करें कि कौन जनता के साथ खिलवाड़ कर रहा है, पैसा लूटने का काम कर रहा है। बड़ी-बड़ी हवेलियां बनाकर घूम रहे हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं और जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जा रहा है। जिन कालेज के अन्दर लेक्चरर नहीं हैं।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य विराजिये। श्री नारायण बेनीवाल।

श्री पदमाराम (चौहटन): 000

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 20-प्रारम्भिक शिक्षा, 21-माध्यमिक शिक्षा और 22-उच्च शिक्षा के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

शिक्षा एक इंसान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आभूषण है। आज आधुनिकता भरी जिन्दगी में कोई अपना वजूद बनाये हुए है तो वह है शिक्षा। कहा जाता है कि शिक्षा पर किया गया खर्च हमेशा सूद सहित वापस मिलता है। माननीय सभापति महोदय, महात्मा गांधी जी के शिक्षा दर्शन में कहा गया है कि सभी बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, मगर वह शिक्षा जीवनोपयोगी हो तथा रोजगार पैदा करने वाली हो। आज जब हम अपने देश में बेरोजगारी की स्थिति देखते हैं तो निश्चय ही शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठेंगे। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया, जिसमें औद्योगिक प्रशिक्षण भी सम्मिलित था। इस तरह बच्चा 10वीं तक पढ़ते-पढ़ते किसी हस्तकौशल में निपुण बन जाता तथा यह बेरोजगारी की समस्या से निजात दिलाने वाला कारगर उपाय था।

माननीय सभापति महोदय, सुबह से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा हो रही है। पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बात भी कही है। अभी चौहटन से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने कहा कि विपक्ष के लोगों का परम दायित्व निन्दा करना है, लेकिन हम निन्दा नहीं करते हैं। हम अच्छे काम के लिए बिलकुल धन्यवाद भी देंगे। मुख्य मंत्री जी ने यदि बजट के अन्दर अच्छे काम किये हैं तो उसके लिए तो धन्यवाद। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी भी बैठे हैं। मेरे इलाके में भी आपने पिछले बजट में कालेजों की घोषणा की थी। दो कन्या महाविद्यालय खोले, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा, लेकिन विडम्बना इस बात की है कि

(श्री नारायण बेनीवाल)

पांचला के अन्दर जो कन्या महाविद्यालय खोला, उसके लिए एक भी पद भरा हुआ नहीं है। सारे के सारे को विद्या सम्बल योजना के लोग चला रहे हैं। सिर्फ निन्दा करना हमारा कर्तव्य नहीं है। हम लोग आपको जरूर कोई न कोई ऐसी बात बतायेंगे, जो विपक्ष के माननीय सदस्य आये हैं, वे लोग आपको कोई बात बतायेंगे। हम तो सिर्फ इस सदन के अन्दर बताते हैं, बाकी देश का मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है, वह बार-बार आपको और हम सबको एवं आम जनता को भी बातें बताता रहता है कि क्या आमूलचूल परिवर्तन होने चाहिए। शिक्षा पद्धति के अन्दर क्या परिवर्तन हों। कई माननीय विधायकों ने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव आपको दिये हैं। दैनिक भास्कर में बहुत बड़ी खबर छपी कि भर्ती की परीक्षा, भर्तियां निकालने में बीता 2022, 19 बड़ी भर्तियां निकालीं, 95,184 युवाओं को नौकरी मिलनी थी, किसी को भी नहीं मिली। इससे बड़ी विडम्बना की बात हमारे लिए नहीं हो सकती है।

माननीय सभापति महोदय, आज यदि हम इस प्रदेश का इतिहास उठाकर देखें तो जब तक प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक चिकित्सा को हम ठोस नहीं बनायेंगे, क्योंकि दोनों नींव के पत्थर हैं, इन दोनों को यदि हम मजबूत नहीं बनायेंगे, तो जिस सुन्दर इमारत की हम सब की कल्पना है, उसको हम सही साकार रूप नहीं दे पायेंगे।

यह हकीकत बात है कि भर्तियों के अन्दर जो घोटाले हुए रीट की बात करें, चाहे सैकंड ग्रेड की बात करें। अब तो यह तय हो गया, भर्ती के अन्दर पेपर आउट होना आम बात हो गयी है। हम सब जन-प्रतिनिधियों का भी यह नैतिक कर्तव्य है कि हम सब मिलकर पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठकर ऐसा कानून बनायें, जो छात्र पढ़-लिखकर ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहता है, उसको इस चीज का अवसर भी मिले, क्योंकि यह उसका मौलिक अधिकार है।

आज यदि शिक्षा विभाग की बात करें तो मैं मेरे नागौर जिले की बात करूंगा। यह हकीकत बात है कि सत्ता के अन्दर परिवर्तन, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आती है और दूसरी बार कांग्रेस की सत्ता आती है। यह हमारे राजस्थान का आज तक का इतिहास रहा है। किसी ने आज तक सरकार रिपीट नहीं की। उसमें सबसे बड़ी भूमिका का यदि हम अध्ययन करें तो चिकित्सा एवं शिक्षा मंत्रियों के कार्यकलापों के कारण ही सरकारों को विपक्ष के अन्दर बैठना पड़ा। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप विराजमान हैं, इस बात को आप अन्यथा नहीं लें। समय रहते यदि आपने इसके अन्दर कोई आमूलचूल

(श्री नारायण बेनीवाल)

परिवर्तन किये, तो निश्चित रूप से आपके पक्ष के जो विधायक हैं, जो कहते हैं कि हम फिर से सत्ता पर काबिज होंगे, हो सकता है कि आपका सपना साकार हो जाये। मैं आपसे जरूर निवेदन करूंगा कि इस बात को अन्यथा नहीं लें।

आज अगर मैं नागौर जिले की बात करता हूं तो अध्यापक के विभिन्न लेवल में 22 हजार 791 पदों में से 5 हजार 120 पद खाली हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं बीकानेर की बात बता रहा हूं, जहां से माननीय मंत्री जी आते हैं, अलमारी में बन्द लाखों पुस्तकों को चाट रही दीमक, सार-संभाल करने वाला कोई नहीं, राज्य के 75 फीसदी स्कूलों में लाइब्रेरियन के पद ही नहीं हैं, जबकि डिजिटल लाइब्रेरी, हम कह रहे हैं कि स्वाध्याय, बच्चा लाइब्रेरी के अन्दर बैठकर पढ़े। आज आप देखें कि नया ट्रेंड चल पड़ा है। गांवों तक में लाइब्रेरियां शुरू हो गयी हैं। एक तरफ लाइब्रेरी का रुझान बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हमने स्कूल और कालेजों में लाइब्रेरियनों के पद खतम कर दिये। कोई सिंगल भर्ती नहीं हो रही है। लाइब्रेरियन कहीं नहीं हैं। इस चीज के बारे में हमको कोई ठोस नीति बनाकर सोचना होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक स्कूल की चर्चा यहां पर करूंगा। जिसके लिए पत्रिका ने बहुत बड़ी खबर अख़बार में छापी कि जरा सरकार सोचिये, थामड़िया के 197 बच्चों वाले विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं है और ऐसे तीन स्कूल हैं, जहां नामांकन एक भी नहीं है, फिर भी अध्यापक लगा रखे हैं। अभी चौहटन से आने वाले माननीय विधायक ने बहुत ही अच्छी बात कही है और उस बात को आप जरूर नोट करना कि जो शहरी क्षेत्र है और जिला हैडक्वार्टर है, उसके 15 किलोमीटर के इलाके में यदि स्कूलों को देखें तो वहां पर टीचर्स की संख्या बहुत ज्यादा है और सुदूर इलाके के अन्दर सारे के सारे पद रिक्त पड़े हैं। इसके अन्दर जरूर कोई ठोस नीति बनाकर उन लोगों को आप उधर एडजस्ट कीजिये। बीकानेर की एक बड़ी खबर और छपी, लैपटॉप योजना, जिसके लिए सरकार हर साल बजट के अन्दर घोषणा करती है। लैपटॉप योजना, राज्य में मेधावी विद्यार्थियों को तीन सत्रों के लैपटॉप मिलने हैं, 93 हजार विद्यार्थियों को इन्तजार, चार साल से ठंडे बस्ते में योजना। एक तरफ हम इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। हम यह कहते हैं कि हम बच्चों को ऐसा बनायेंगे कि इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी के अन्दर नयी-नयी चीजों से वे जाग्रत हों, वे जुड़ें, लेकिन यदि ऐसी योजनाएं सिरे नहीं चढ़ीं तो हम उनको जो शिक्षा देना चाहते हैं, उससे वे वंचित न रह जायें।

(श्री नारायण बेनीवाल)

यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं वे नागौर के प्रभारी मंत्री भी हैं। आपका भी मैं ध्यान आकर्षित करूंगा कि आप जब भी नागौर आयें, प्रभारी मंत्री जी, नागौर के एक भी सरकारी कालेज में लाइब्रेरियन नहीं है। आप वहां के प्रभारी मंत्री हैं और बड़ी विडम्बना की बात यह है कि पीजी, चाहे बलदेव मिर्धा गवर्नमेंट कालेज की बात करें, खींवसर की बात करें या नागौर जिले के किसी भी कालेज की बात करें, आप वहां के प्रभारी मंत्री हैं। पीजी क्लासों के खोलने की बात हो, लेक्चरर्स के पद भरने की बात हो, बच्चे लोग हमेशा ज्ञापन देते हैं। आप बड़े संवेदनशील होकर, मैं आपसे पूरी आशा रखता हूं कि आप संवेदनशीलता दिखाते हुए इसके लिए आप जरूर प्रयास करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, सरकार नये बोर्ड सेन्टर खोले। जिसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जनाणा में बोर्ड का परीक्षा सेन्टर खुलवाने की मांग करता हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): सर, अभी तो छह मिनट ही हुए हैं। दस मिनट तो दें, मैं एक ही व्यक्ति बोल रहा हूं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो मांगें हैं, खींवसर उप खण्ड मुख्यालय पर स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा करें। नये विद्यालय खोलने में दूधिया नाड़ा, बामड़ियाड़ा, दयानाड़ा, दूजासर, कसवा की ढाणी, कुम्हारों व नायकों की ढाणी, नदवाणी, एमजी मेघवाड़ों की ढाणी, कलालथल डोर, धोलिया डेर और राजपूत नाइकों की ढाणी, खरखाड़ी में नये विद्यालय खोलने की मैं आपसे मांग करता हूं।

प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने हेतु मांग-राजकीय प्राथमिक विद्यालय बेनीवालों की ढाणी, मादाड़ियों की ढाणी, शहीद चौखाराम राजकीय प्राथमिक विद्यालय, रामदेव मन्दिर कुरची, राजकीय प्राथमिक विद्यालय राइकों की ढाणी नदवाड़ी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय करमो नाई की ढाणी, सुओ की ढाणी, चारणीसरा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जाननों की ढाणी, भोमासर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पूर्व ढाणी, खरखाड़ी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय शहीदों की ढाणी रूंड, राजकीय प्राथमिक विद्यालय संतों की ढाणी नयापुरा नागड़ी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय संख्या

(श्री नारायण बेनीवाल)

3 देऊं और राजकीय प्राथमिक विद्यालय नाइकों की ढाणी खजवाड़ा के अन्दर उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नति की मैं मांग करता हूं।

नये महात्मा गांधी स्कूल। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, शीलगांव, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, सेनड़ी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, असावरी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सुथारों की ढाणी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुरछी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बिरालोका में नये महात्मा गांधी स्कूल खोलने की मैं मांग करूंगा।

खींवसर क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में नये संकाय खुलवाने हेतु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिरलोका, पांचोड़ी, गुढ़ा भगवानदास, खींवसर, काटिया, जनाणा, शंखवास, कंकड़ाई, पालड़ी जोधा, गाजू, कडलू, करनाल, बलाय और शीलगांव में विज्ञान संकाय शुरू करने की मांग करता हूं। साथ ही, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माडपुरा में कला संकाय शुरू करवाने की मांग कर रहा हूं। इसके अलावा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खजवाड़ा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रूड़, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माड़कपुर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शंखवास में भी कृषि संकाय शुरू करवाने की मांग करता हूं। मैं उच्च शिक्षा मंत्री जी से मांग करूंगा कि जब उत्तर दें तो हमारे खजवाड़ा के अन्दर हम कालेज की मांग करते हैं।

मेड़ता विधान सभा क्षेत्र के रियांबड़ी कस्बे के 30-40 किलोमीटर में कोई कालेज नहीं है, वहां भी आप कालेज की स्वीकृति जारी कराएं। मेरा परम सौभाग्य है कि मैं जिस विधान सभा से आता हूं, लोक देवता वीर तेजाजी का जन्म भी वहीं हुआ।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि खींवसर के राजकीय महाविद्यालय का नामकरण लोक देवता वीर तेजाजी के नाम से किया जाए।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): खींवसर राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान संकाय खोलकर विद्यार्थियों को राहत प्रदान करें।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): राजकीय कन्या महाविद्यालय में

(श्री नारायण बेनीवाल)

विज्ञान संकाय और नागौर के बी आर मिर्धा राजकीय महाविद्यालय में पीजी में नये विषय, हिन्दी, भूगोल, बॉटनी, जियोलॉजी, भौतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान को शामिल करने की स्वीकृति जारी करवाने का कष्ट करें।

सभापति महोदय, मैं एक सेन्टेंस के साथ ही अपनी वाणी को विराम दूंगा। अभी उच्च शिक्षा के अंदर आयुक्त महोदय का एक तुगलकी फरमान जारी हुआ कि छात्रसंघ के चुने हुए प्रतिनिधि हैं वे सम्बन्धित विधायक से परमिशन लेने के बाद उद्घाटन करेंगे। इस देश के अंदर मेरे हिसाब से इतना बड़ा तुगलकी फरमान कभी नहीं आया। छात्रसंघ का जब अध्यक्ष चुना जाता है तो कम से कम वह मर्जी से जिसको बुलाना चाहे, उद्घाटन का कार्यक्रम करे।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): आपके माध्यम से, अंत में मैं यही बात सरकार तक पहुंचाना चाहूंगा।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): पंचायत सहायक भर्ती 2017 में वंचित रहे 6500 विद्यार्थी मित्रों को शिथिलता प्रदान कर विद्यालय सहायक, संविदा कैडर 2022 में शामिल करके रोजगार प्रदान करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, मांग संख्या 20, 21, 22 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय शिक्षा, जिसमें पिछले चार साल में बहुत कुछ हुआ है बहुत कुछ होना बाकी है। खुले वातावरण के स्कूलों में खेल मैदान, खेल मैदान के साथ कम्प्यूटर लैब, कम्प्यूटर लैब के साथ विषयों की लैब, स्कूल में हॉल, शैड, यह सारी की सारी मांग हर स्कूल में है। आपने एल्युमनाई मीट कराया, पुराने लोग स्कूलों में पढ़े, आगे तक गए, वह स्कूलों में आए। स्कूलों में आने के बाद गांवों में मदद भी हुई। स्कूल बहुत अच्छे-अच्छे हुए। चमकीले स्कूल। आंगनबाड़ी जब अंदर आई, उसको लीपा-पोता गया, उस पर कलाकृतियां की गईं तो यह लगा कि स्कूलों की थोड़ी-सी आभा और बढ़ने लगी है।

सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना

(श्री बलवान पूनियां)

चाहूंगा। हिन्दुस्तान में एक स्टेट दिल्ली है जो पिछले तीन-चार साल से बजट का चौथा हिस्सा एजुकेशन पर खर्च कर रहा है। उसके साथ दूसरा स्टेट केरल है, जहां के स्कूल बहुत बेहतर हैं। वहां बच्चे की इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है।

बहुत अच्छा किया सरकार ने, यहां बहुत स्कूल खोले हैं। बंद स्कूल भी खोले हैं। अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी खुले हैं। प्राथमिक से उच्च प्राथमिक व उच्च प्राथमिक से सीधे उच्च माध्यमिक तक स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं। कालेज भी खुले हैं, लेकिन हमें आज और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है। अच्छी एजुकेशन का माहौल पैदा करेंगे तो स्टेट आगे जाएगा। जिस तरीके से हम स्कूलों के अंदर आजादी के बाद एक वातावरण बना पाए, स्कूल में कोई भेदभाव नहीं। जो मासूम बच्चा स्कूल जाता है, वह न हिन्दू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, वह सिर्फ और सिर्फ स्कूल का स्टूडेंट है। अनुच्छेद 30 यह कहता है कि आप स्कूल के अंदर कोई धार्मिक आयोजन नहीं करेंगे। स्कूल के अंदर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाये गये इस विधान के अंदर यह ताकत दी गई। इस ताकत के चलते हिन्दुस्तान के अंदर ऐसे-ऐसे नागरिक इन स्कूलों में पढ़कर तैयार हुए। आईएएस, आईपीएस, आईआईएम तक जाने वाले लोग, बड़ी-बड़ी संस्थाओं, वर्ल्ड बैंक तक जाने वाले लोग, इन सरकारी स्कूलों में हुए हैं। इसलिए हम आज पुरज़ोर मांग करते हैं कि इन स्कूलों को और ताकत दी जाए। जिस तरह से आपने 475 कालेजों की संख्या बढ़ाई है, इन स्कूलों में और ज्यादा स्ट्रेन्थ बढ़े, उसके साथ-साथ कालेज में व्याख्याता, आचार्य, सहायक आचार्य के पद जनरेट करते हुए उनको वहां लगाने की जरूरत है।

सभापति महोदय, आज स्कूलों में फर्स्ट ग्रेड, सैकण्ड ग्रेड की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, तुरंत प्रभाव से रिजल्ट निकालकर खाली पदों को भरने की जरूरत है। आज थर्ड ग्रेड के अध्यापक, जहां प्राथमिक शिक्षा में स्कूल खाली है वहां भरने की जरूरत है। मैं मांग करता हूं, सभापति महोदय, मुझे लालच है वोट का, मुझे लालच है इस बात का, हर जनप्रतिनिधि को है, कि उसका आदमी खुश रहे, मैं मांग करता हूं कि थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर खुलें। साथ ही मैं यह मांग करता हूं कि राजस्थान के किसी भी हिस्से के, किसी नौनिहाल बच्चे का स्कूल खाली नहीं रह जाए। हम यह मांग करते हैं। हमें इस बात का लालच है कि हमारी बहन, बेटियां, भतीजियां बैठी हैं, वे रोज कहती हैं कि

(श्री बलवान पूनियां)

आप हमारा ट्रांसफर कराओ, पर हम नहीं चाहते कि कोई स्कूल बंद हो, किसी स्कूल में बच्चे इस बात का इंतजार करते रह जाएं। सुदूर बाड़मेर, सुदूर प्रतापगढ़ में, मैं टीएसपी के उस अध्यापक की बात तो करता हूं जो मेरे क्षेत्र से हैं, पिछले 10-12 साल से बैठा है, वह सामाजिक बंधन नहीं निभा पा रहा है। मैं यह भी मांग करता हूं कि टीएसपी क्षेत्र में नये टीचर की व्यवस्था के लिए सरकार गम्भीरता से बात करे। सिर्फ मेरी बात ही नहीं सुनें, उस बच्चे की बात सुनें, टीएसपी क्षेत्र के पहाड़ी पर बसने वाले 50 घरों की बात सुनें, जिनके बच्चे आज भी शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। आज भी वह इस बात से डरते हैं। उनके मां-बाप छोटे-छोटे पठार पर खेती करते हैं। अगर वह बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए पांच किलोमीटर चले जाएं तो शाम को वापस आएंगे, बच्चे को लाने ले जाने में ही रह जाएंगे। इसलिए मांग करते हैं कि वहां टीचर्स की संख्या बढ़े।

बजट में आपने सड़क की खूब व्यवस्था की, लेकिन इसके साथ-साथ शिक्षा पर बेहतर करने की जरूरत है। आने वाले समय में हम सबके लिए चिंता का विषय है। अच्छे नागरिक होंगे तो इस सदन की डिबेट का स्तर भी बढ़ेगा। प्रदेश में, देश में अच्छे नागरिक होंगे तो बात भी आगे बढ़ेगी। जिस शेरनी के दूध की बात कर रहे हैं, मदन दिलावर ने तो ज्यादा पी लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। आपको भी आज इन्होंने खूब परेशान किया है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वह दहाड़ता है। अभी नारायण कह रहा था कि मदन ने ज्यादा पी लिया वह दूध, इसलिए ओवर डोज हो गई। सभापति महोदय, जिसने शिक्षा प्राप्त की है वह समाज को आगे लेकर गया है।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांग हैं, जिन पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। मेरे गवर्नमेंट कालेज बना, भवन बनकर तैयार हो गया, बच्चों की संख्या भी खूब हो गई, उसको पीजी तक किया जाए। उसका नाम शहीद भगतसिंह महाविद्यलाय किया जाए।

सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने ग्रामीण कन्या महाविद्यालय को सरकारी किया है, लेकिन इसी सत्र से उसका सरकारीकरण किया जाए।

सभापति महोदय, मैं मांग करना चाहता हूं कि मेरी कांस्टीट्यूएंसी के

(श्री बलवान पूनियां)

बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो अभी भी अंग्रेज़ी माध्यम होना चाहते हैं। राजकीय प्राथमिक गेउ, कडाउ, मलसीसर, निनाव करनपुरा के स्कूल अंग्रेज़ी माध्यम होना चाहते हैं। मेरे 21 अंग्रेज़ी माध्यमिक विद्यालय हुए हैं, 325 से 350 तक की स्ट्रेन्थ हो गई। अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल बहुत अच्छे से आगे पहुंच रहे हैं।

सभापति महोदय, मेरी मांग है डीपीसी समय पर हो। पढ़ाई प्रभावित नहीं हो, इस हेतु साइंटिफिक सिस्टम विकसित किया जाए। ग्रेड थर्ड ट्रांसफर टीएसपी से नोन-टीएसपी ट्रांसफर किए जाएं। रिक्त पद भरे जाएं। फर्स्ट ग्रेड, सैकण्ड ग्रेड के रिजल्ट जारी किए जाएं। विद्यालयों को भौतिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। महात्मा गांधी स्कूलों का अलग से कैडर बनाया जाए। महात्मा गांधी विद्यालय की जिस प्रकार से कामयाबी है, इसलिए अलग से कैडर स्थापित किया जाए।

प्रबोधकों की मांग है कि पुरानी सेवा को सेवानिवृत्ति में गणना की जाए ताकि उनको सेवानिवृत्ति का लाभ मिल सके। वाइस प्रिंसिपल की भर्ती सीधी भर्ती के बजाय आधे उन लोगों को मौका दिया जाए जो सेवा में हैं, उनको काम्पीटिशन दिया जाए, इसलिए समानता का अधिकार और अवसर का उनको अधिकार मिल सके।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कायम का बास स्कूल नम्बर दो को क्रमोन्नत किया जाए। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रामबास को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया जाए। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, अमरपुरा और चकभुजासर को भी क्रमोन्नत किया जाए। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, डोबी, जो एक कन्या विद्यालय भी है, लेकिन को-एजुकेशन के रूप में, पंचायत हैडक्वार्टर होते हुए भी, शिक्षा मंत्री महोदय, वहां डोबी गांव में सीनियर स्कूल नहीं है। कन्या विद्यालय, जो सीनियर विद्यालय है, उसको आप को-एजुकेशन में कन्वर्ट करें, ताकि सह शिक्षा में बच्चे 12वीं तक गांव में शिक्षा प्राप्त कर सकें।

सभापति महोदय, मैं आप सब साथियों का इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में साथियों ने जो सुझाव दिए इन सुझावों के साथ-साथ आप और हम मिलकर इस राजस्थान को मजबूत बनाने का काम करेंगे।

आज जिस तरीके से पेपर को लेकर सब चिंता जाहिर कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि यह चिंता सिर्फ टांग खिंचाई की चिंता नहीं है, यह सबकी चिंता

(श्री बलवान पूनियां)

है। मैं समझता हूं कि इससे एक बात में मजबूती आएगी। जनप्रतिनिधियों के पास लोग सिफारिश लेकर आते थे कि मेरी पेपर में सेटिंग कराओ, आज सदन में जो आपकी आलोचना कर रहे हैं, वह कम से कम सेटिंग में हाथ तो नहीं मारेंगे। यह गम्भीर बात है। इन चीजों को लेकर कौन आया है। लोगों की हिम्मत कैसे हुई, कहीं न कही हमारी शह है। हम जनप्रतिनिधियों का, इस सदन में बैठने वाले मजबूत लोगों का, जो बड़े-बड़े ओहदों पर रहे हैं और बड़े-बड़े ओहदों पर रहने वाले हैं, उन लोगों की शह है। यहां आलोचना करने वाले कम से कम शह तो नहीं करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि पेपर्स में पारदर्शिता बरती जाए। ऐसा भय कायम हो कि लोगों की हिम्मत ही नहीं पड़े कि कोई पेपर लीक करने की भी सोच सके।

सभापति महोदय, हमारे यहां 2-3 बड़े गांव हैं, जो बड़े क़स्बों के रूप में हैं, गोगामेड़ी उत्तरी भाग का सबसे बड़ा मेला भरता है, बड़ी आबादी है। वहां मैं गवर्नमेंट कालेज खोलने की सरकार से मांग करता हूं।

सभापति महोदय, प्राइवेट स्कूल, कालेज, यूनिवर्सिटी पर सरकार कठोर रूप से नियंत्रण हेतु रेगुलेटरी एक्ट बनाए, जिससे यह पता चले कि शिक्षा का स्तर वास्तव में क्या है। आज स्थिति यह है, सुबह से आप सरकारी स्कूल पर चर्चा कर रहे हैं लेकिन प्राइवेट स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है, प्राइवेट स्कूलों की फीस का नियंत्रण क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, डेप्थ क्या है, वहां खेल मैदान है या नहीं है, वहां लाइब्रेरी है कि नहीं है, वहां कमरों का वातावरण कैसा है, सफोकेशन तो नहीं है, बच्चों को मानसिक रूप से वहां पीड़ा तो नहीं हो रही है, बच्चों को शारीरिक रूप से परेशानी तो नहीं हो रही है, उनकी हैप्पीनेस चैक करने की जरूरत है। बच्चों की स्किल्डनेस को हमें चैक करने

(समय: 16.00 बजे)

की जरूरत है। इसलिए हम एजुकेशन में बेहतर कर पाएंगे, इसलिए प्राइवेट स्कूलों पर भी नियंत्रण राजस्थान की सरकार ऐसे करे, नियंत्रण का बोर्ड बने और वह बाकायदा बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लीपापोती के, बिना किसी इस बात के ही यह पोलिटिकली रूप से हमारे खिलाफ है, हम उसको बंद कर देंगे, ऐसा नहीं हो। एक बोर्ड बनाये, एक मापदंड तय करे और हर प्राइवेट स्कूल पर यह चीज लागू हो। माननीय सभापति महोदय, हर प्राइवेट कालेज पर भी यह चीज लागू हो क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा को ...(व्यवधान)

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): मैं समाप्त करना चाहता हूं। जिस तरीके से शिक्षा को व्यापार से बदलकर और अब शिक्षा को हम मैनडेटरी के रूप में देखना चाहते हैं। जिस तरीके से यू.पी.ए.-2 में यह कानून आया कि शिक्षा के अधिकार के रूप में हम शिक्षा को देना चाहते हैं तो हम यह समझते हैं कि कानून से ये सारी चीजें बंधी हुई हों। कालेज लेक्चरर की भर्ती जल्दी से जल्दी निकालकर कालेजों में लेक्चरर्स की भर्ती की जाये ताकि जो कालेज आपने खोले हैं उनकी सार्थकता प्रामाणिक हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं तो यही बात कहते हुए मेरी बात को पूरी करना चाहूंगा कि शिक्षा पर जो खर्चा बढ़ना चाहिए, हमारी तो यह मांग होती थी विद्यार्थी जीवन से जब एस.एफ.आई. में काम करते थे, तो शिक्षा पर जो खर्चा हो, वह बजट का दसवां हिस्सा हो लेकिन आज निर्मला सीतारमणजी ने बजट में प्रावधान थोड़ा जरूर बढ़ाया क्योंकि शिक्षा पर अब की बार उन्होंने थोड़ा-सा खर्चा बढ़ाया है लेकिन जो हम उम्मीद कर रहे थे भारत सरकार से, पूरे देश में शिक्षा पर खर्च करने के लिए बेहतर माहौल बनाएंगे, उन्होंने ऐसा कुछ बजट में नहीं किया। मैं राजस्थान की सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि जब आपने इस बजट में शिक्षा का प्रावधान तो करा है, बजट बढ़ाया भी है लेकिन इसको भविष्य में और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है ताकि हम हर स्कूल तक, हर कालेज तक, हर लाइब्रेरी तक, हर जगह हम बेहतर कर पाये। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।

श्री सभापति: श्री समाराम गरासिया।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 20-प्रारम्भिक शिक्षा, मांग संख्या 21-माध्यमिक शिक्षा और मांग संख्या 22-उच्च शिक्षा पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से सरकार में बैठे हैं वे वाहवाही करते हैं और हम सच्चाई को बताते हैं क्योंकि यदि वे वाहवाही नहीं करेंगे तो फिर क्या हो सकता है कि उनका टिकट कट जायेगा, क्या होगा आगे? बाकी वाहवाही करना इनका धर्म है और सच्चाई बताना हमारा धर्म है। हम जिस प्रकार से इन वार्षिकोत्सव में गये हैं, हर स्कूल में जाने का हमें मौका मिला है। कई स्कूलों के अन्दर कमरों की कमी है, कई स्कूल क्रमोन्नत ही नहीं की है और जो आपने क्रमोन्नत किये हैं यह कोई नई बात नहीं है। यह तो

(श्री समाराम गरासिया)

हमारी 2003 से 2008 तक की जो सरकार थी तो हर पंचायत मुख्यालय पर दस-दस स्कूलों को किया था, तो यह पहली बार आप नई क्रमोन्नत नहीं कर रहे हैं। हर पंचायत मुख्यालय पर 2013 से 2018 तक, उसमें 12वीं तक की स्कूलें की थीं। कोई आपने नई शुरू नहीं की है शिक्षा विभाग के अन्दर और जिस प्रकार से शिक्षा विभाग की दशा वह कर रखी है जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर अध्यापक नहीं है और वहां पर बैठने तक की जगह नहीं है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? आप कह रहे हैं कि हमने स्कूलों में किराया दिया, हमने वह दिया, तो क्या यह कोई नई बात कही है क्या? आपने एक भी नई बात कही हो तो बता दो। वह तो हमारे 2003 से 2008 तक सारी व्यवस्था हो चुकी थी। एक भी नवाचार नहीं किया और शिक्षा सम्बल अभियान, नाम तो बड़ा-बड़ा देते हैं लेकिन काम के अन्दर बिलकुल जीरो।

रमसा के अन्दर इतना बजट आता था, कभी दिया है एक पैसा भी किसी स्कूल के कमरे के लिए? आप यह तो बता दें कि कभी हमने कमरों के बजट को भी दिया है, बैठने के लिए। जहां अभी बोर्ड की परीक्षा है, बोर्ड की परीक्षा में बैठने के लिए जहां सेंटर किया है, वहां पर स्टूल-टेबल तक की व्यवस्था नहीं हो पायेगी और हम जब एम.एल.ए. फंड से भी देंगे तो वह भी आपके जिला परिषद् में जायेंगे तो कई प्रकार के नियम बताएंगे। एम.एल.ए. फंड का बजट स्कूलों के लिए होता है, उसमें कई सारी प्रोब्लम्स आती हैं तो तुरंत प्रभाव से वह भी पास नहीं हो पाता है।

आपने बड़ी-बड़ी घोषणा की कि हम हर मुख्यालय पर एक खेल स्टेडियम बनाएंगे तो 25-25 लाख रुपये तो हमने एम.एल.ए. फंड से दिये हैं। वह भी शायद दो साल हो चुके हैं, अभी तक वह स्टेडियम बना नहीं है। आप क्या कर पाएंगे?

आपकी घोषणा घोषणा ही रह जाती है और मेरे वहां पिंडवाड़ा के अन्दर एक कालेज खोला गया था पूर्व सरकार में और वह बिल्डिंग/भवन बंद है, भवन बन नहीं रहा है, चौथे बजट में भी मैंने फिर से बोला था तो वह छह करोड़ के करीब कुछ बजट आपने स्वीकृत जरूर किया, शुरू किया फिर भी अब बंद है। क्या वह हमारी सरकार का ही इंतजार कर रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकार में ही वह भारतीय जनता पार्टी के अन्दर बनेगा कालेज, अभी तक वह कालेज बंद है।

(श्री समाराम गरासिया)

डी.एम.एफ.टी. का फंड आता है, वहां पर किसी बजट की आवश्यकता नहीं होती है लेकिन आपके जो कालेजों के अन्दर बजट डी.एम.एफ.टी. का फंड होता है तो राजनीतिक दबाव से कहीं ओर जगह पर चला जाता है और जिस प्रकार से आदिवासी एरिया के अन्दर इन स्कूलों के भवनों की स्थिति खराब है, वहां पर डी.एम.एफ.टी. का फंड नहीं लगेगा।

वहां पर अधिकारी भी नहीं है। सिरोही जिले के अन्दर जिला शिक्षा मुख्यालय पर जिला शिक्षा अधिकारी नहीं है। वहां पर प्रारम्भिक जिला शिक्षा अधिकारी नहीं है तो वहां पर अध्यापकों की हालत कैसी होगी? पहले तो कम से कम मुख्य अधिकारी ही नहीं है, ब्लाक शिक्षा अधिकारी रेवदर में नहीं है, पिंडवाड़ा में नहीं है, शिवगंज में नहीं है तो क्या विकास हो पाएगा स्कूलों के अंदर? क्या बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि यह जो हालत बनाकर रखी है स्कूलों के अन्दर उसको थोड़ा सुधारा जाये क्योंकि सरकारें, आप तो वाहवाही लेने के लिए बढ़ा-चढ़ाकर बोलते हैं कि हमने वह किया, वह किया पर आपने कुछ भी नहीं किया है। रीट की परीक्षा के अन्दर पेपर लीक हुआ, आप यह कहते हो कि हमने इतनी नौकरियां दी हैं, इतनी वह दी हैं, तो कौनसी नौकरियां, कितने पद आपने भरे हैं? पेपर लीक होते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस राजस्थान का? जो बच्चा बड़ी मुश्किल से पेपर देता है और पेपर लीक हो जाता है तो फिर तो यह सरकार की पूरी लीक है।

माननीय सभापति महोदय, जनजाति क्षेत्र में जैसे हमारे आते हैं, जनजाति क्षेत्र में एक भी मां-बाड़ी नहीं खोली गयी है। एक भी मां-बाड़ी इस सरकार के अन्दर नहीं खोली गयी है क्योंकि मैं जनजाति क्षेत्र से आता हूं, जहां पर टी.एस.पी. क्षेत्र है, वहां पर कहीं पर स्कूल नहीं है, दो-तीन किलोमीटर बच्चे दूर जाते हैं तो वहां पर एक भी जनजाति विभाग से एक नई फूटी कौड़ी तक नहीं लगी, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है सिरोही जिले के लिए?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जरूर कहूंगा कि स्कूलों के अन्दर आप व्यवस्था सुधारें और जहां स्कूल आपने इंग्लिश मीडियम खोल दिया कि हमने इंग्लिश मीडियम खोल दिया, तो इंग्लिश मीडियम के

(श्री समाराम गरासिया)

अध्यापक तो लगाये होते, उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता तो वह बच्चों को क्या पढ़ायेगा?

माननीय सभापति महोदय, आप वाहवाही लेते हैं और वाहवाही लेते रहो, आखिर में अंत समय में पांच-छह महीने ही बचे हैं, इसमें भी कुछ सुधार हो जाये तो बच्चों का भविष्य भी उज्ज्वल हो जाये, ठीक हो जाये नहीं तो फिर यदि आप यहां पर भी बैठेंगे तो भी आपको जनता माफ नहीं करेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने बोलने का मौका दिया।

श्री सभापति: श्री अमित चाचाण।

श्री अमित चाचाण (नोहर): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद कि आपने मुझे मांग संख्या 20-प्रारम्भिक शिक्षा, मांग संख्या 21-माध्यमिक शिक्षा एवं मांग संख्या 22-उच्च शिक्षा पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, गत चार वर्षों में हमारे राज्य के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने, हमारे शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्लाजी ने, उच्च शिक्षा मंत्री राजेन्द्र यादवजी ने और शिक्षा विभाग ने इन चार वर्षों में अनेक नवाचार किये, जिससे कि शिक्षा को मजबूती मिली, शिक्षा में गुणवत्तात्मक सुधार हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान शिक्षा विभाग ने नये आयाम स्थापित किये हैं।

माननीय सभापति महोदय, बाबा भीमराव अंबेडकरजी ने यह कहा था कि बच्चे के पैर में चाहे चप्पल-जूते न हो लेकिन उसके हाथ में किताब होना अति आवश्यक है। शिक्षा के ही माध्यम से, शिक्षा से ही चाहे वह व्यक्ति हो, परिवार हो, समाज हो या देश हो, उनकी नींव मजबूत होती है। इन चार वर्षों में हमारी सरकार ने शिक्षा में जो नवाचार किया है, उसके माध्यम से आज पूरे राजस्थान में हमारे बच्चों का, अभिभावकों का राजकीय विद्यालयों के प्रति विश्वास बढ़ा है, इसी का कारण है कि इन राजकीय विद्यालयों की तरफ हमारे अभिभावकों का विश्वास बढ़ने की वजह से नामांकन संख्या भी बढ़ी है।

विपक्ष के साथी जो कह रहे हैं, मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि आप यह तुलना कीजिए कि आपने अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में क्या किया और इन चार वर्ष के कार्यकाल में राजस्थान की सरकार ने क्या किया तो मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि आपके पांच साल के कार्यकाल में आपने कोई

(श्री अमित चाचाण)

भी नई प्राइमरी स्कूल नहीं खोली जबकि हमारी सरकार ने 266 विद्यालयों को खोलने का काम किया। आपके कार्यकाल में मात्र 178 प्राइमरी स्कूलों को क्रमोन्नत करने का काम किया, वहीं हमारी सरकार ने 1453 स्कूलों को प्राइमरी से अपर प्राइमरी में करने का काम किया। आपने अपर प्राइमरी से सैकण्डरी में मात्र 307 स्कूलों को क्रमोन्नत करने का काम किया वहीं हमारी सरकार ने 1127 स्कूलों को क्रमोन्नत करने का काम किया है। इसके साथ ही मुख्य मंत्रीजी ने गत बजट में 3864 को, एक साथ जितने भी माध्यमिक विद्यालय थे, पूरे राजस्थान में पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का काम किया।

सभापति महोदय, एक गरीब परिवार के बच्चे का सपना था कि वह बच्चा बढ़ती महंगाई के कारण, प्राइवेट स्कूलों में अत्यधिक फीस थी, वह अंग्रेज़ी माध्यम में नहीं जा पा रहा था, उसके पड़ौस का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा था, उस बच्चे के सपने को साकार करने का काम किया तो हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने किया।

आप विपक्ष के साथी कह रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम में आपने क्या किया। मैं उनको कहना चाहता हूं जो बच्चा जन्म लेगा वह चलेगा भी, दौड़ेगा भी। आपको आगे जाकर अहसास होगा कि मुख्य मंत्री जी का फैसला एक क्रांतिकारी फैसला है जो आगे जाकर राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य को आगे ले जाने का काम करेगा। हम आज चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात करें, सरकारी सेक्टर की बात करें, किसी भी क्षेत्र की बात करें, आज अंग्रेजी भाषा आना अत्यन्त आवश्यक है। इसी को देखते हुए मुख्य मंत्री जी ने क्रांतिकारी फैसला किया है।

माननीय सभापति महोदय, हमें दु:ख होता है। आज के इस दौर में, जब-जब भी सरकारें आईं, उन्होंने पाठ्यक्रम बदलने का काम किया। कांग्रेस सरकार ने देश के संविधान की अनुशंसा के हिसाब से पाठ्यक्रम को किया, लेकिन हमारे विपक्ष के साथी ने अपने एजेंडे को भी इसमें शामिल करने का काम किया। आने वाले समय में यह सही नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, विपक्षी ने पाठ्यक्रम में आघात लगाने का काम किया। जब-जब भी उनकी सरकार आई, उन्होंने पाठ्यक्रम में बदलाव किये हैं। यह हम सबके हित में नहीं है। महात्मा गांधी जी ने कहा था शिक्षा के माध्यम से ही आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा ही ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से हम बड़ी से बड़ी लड़ाई भी लड़ सकते हैं।

(श्री अमित चाचाण)

माननीय सभापति महोदय, पिछले दिनों एक साथ पांच देश भक्ति गीतों का, जिसमें 1 करोड़ 12 लाख बच्चों ने भाग लेकर वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज करवाया, यह भी एक सराहनीय कदम था। राजस्थान सरकार ने नो व्हीकल डे रखा, उसके तहत 38 लाख बच्चों ने भाग लिया, उसका भी वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज किया गया। प्रत्येक विद्यालय में वार्षिक उत्सव शुरू किये, इससे यह परिणाम निकला कि उस गांव के भामाशाहों का इन विद्यालयों के प्रति जुड़ाव रहा। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिभाएं छिपी हुई थीं, उनको भी आगे आने का अवसर मिला। राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में भामाशाहों के द्वारा मूलभूत सुविधाएं पूरी करने का काम किया गया।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से कुछ बात कहना चाहता हूं। जो भी प्राथमिक विद्यालय है, जिसमें 5वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं, छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, वे गांव से दूर दूसरे विद्यालयों में नहीं जा पाते हैं, जिस गांव में एक ही राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, उसको क्रमोन्नत करने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, आज चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पदों की संख्या कम होती जा रही है। विद्यालय को खोलने की बात हो, साफ-सफाई की बात हो, घंटी बजाने की बात हो, यह बड़ी समस्याएं आ रही हैं तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की जाए।

सभापति महोदय, तृतीय श्रेणी के स्थानान्तरण जो 15-15, 20-20 साल से अपने परिवार से दूर बैठे हैं, एक ऐसी स्थायी स्थानान्तरण नीति बनाई जाए जिसके तहत उनके भी ट्रांसफर किए जाएं। मेरे क्षेत्र में 2013 में कांग्रेस शासन काल में डाइट खोलने की घोषणा की थी। 2017 में भवन का निर्माण भी हो चुका था, आज दिन तक वह डाइट संस्था की परमिशन नहीं मिली, भवन जर्जर हो रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं डाइट खोलने की बात करें।

माननीय सभापति महोदय, पूर्व सरकार ने जिन विद्यालयों को बंद करने का काम किया था, उनमें बहुत से ऐसे विद्यालय थे जिन्होंने भामाशाहों द्वारा अमूल्य धन लगाकर भवनों का निर्माण किया था, आज वह बिल्डिंग जर्जर हो रही है और भामाशाहों का अपमान भी हो रहा है। मेरी मांग है, जो स्कूल नहीं खोल पाते वह अन्य गतिविधियों के लिए दिए जाएं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा। इसके लिए मेरे क्षेत्र में उच्च प्राथमिक से उच्च

(श्री अमित चाचाण)

माध्यमिक विद्यालयों में जोजासर, दुरजाना, रातोसर, दुधली, बांगासर, छियारपीएम व ढाणी राइनो को क्रमोन्नत करने की मैं आपसे मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैंने भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक नवाचार किया। हमारे विद्यालय में रोजाना जो प्रार्थना करते हैं, बाल सभाएं होती हैं, गर्मी-सर्दी, बारिश के कारण विद्यालय में बच्चे परेशान होते थे, मैंने 80 से अधिक विद्यालयों में शैड निर्माण का कार्य किया, जो कि एक हॉल की पूर्ति भी करेगा। मेरा प्रयास यही रहता है कि मेरा ज्यादा से ज्यादा विधायक कोटे का पैसा इन राजकीय विद्यालयों में लगाऊं।

सभापति महोदय, दूसरी तरफ विपक्ष के साथी कहते हैं कि सत्ता के विधायक हैं वह ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लेते हैं। मैं आज इस पवित्र सदन से कहना चाहता हूं, मैंने 400 से अधिक, जो 20-20 साल से बाहर बैठे थे, नोहर विधान सभा क्षेत्र में लाने का काम किया है। अगर कोई व्यक्ति यह साबित करे कि अमित चाचाण ने एक पैसा लिया है तो मैं राजनीति ही नहीं, विधायक पद से भी इस्तीफा दे सकता हूं। हमने निःस्वार्थ भाव से किया। हमारे छोटे भाई-बहन बाहर बैठे थे, उनको बगैर पैसे लिए नोहर विधान सभा क्षेत्र में लाने का काम हमने किया है। कोई एक रुपये का भी आरोप नहीं लगा सकता। अगर कोई विपक्ष का साथी एक रुपये का भी आरोप लगाता है तो मैं विधायक पद से इस्तीफा देने का काम करूंगा। आज इस पवित्र सदन में आपके सामने कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षक भगवान का रूप है, शिक्षक वह व्यक्ति होता है कि हमारा बच्चा जब स्कूल जाता है एक मिट्टी का पुतला होता है, शिक्षक अपने ज्ञान की बदौलत उसको एक नया रूप देता है। उनकी जो-जो मांगें चली आ रही हैं, आप उसको पूरा करने का काम करें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती कल्पना देवी।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय सभापति जी, आपने मुझे प्रारम्भिक शिक्षा मांग संख्या 20, माध्यमिक शिक्षा मांग संख्या 21 एवं उच्च शिक्षा मांग संख्या 22 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए धन्यवाद।

(श्रीमती कल्पना देवी)

शिक्षा का महत्व हम सब समझते हैं। हम जानते हैं कि शिक्षा हमें मानसिक एवं शारीरिक रूप से मजबूत करती हे। जिंदगी की जो चुनौतियां हैं, उसका सामना करने के लिए हमें दृढ़ संकल्पित भी करता है। आज राजस्थान में शिक्षा का दृश्य बिन पहिए वाली गाड़ी जैसा है। हमें सब विद्यालयों में बुलाया जाता है, भले ही उनके वार्षिक उत्सव के लिए हो या कोई और कार्यक्रम के लिए हो। मूल रूप से विद्यालय के प्रिंसिपल, टीचर्स हमें यह दिखाना चाहते हैं कि उनके विद्यालय की स्थिति क्या है। हम सबने देखा है कि हर विद्यालय का क्या हाल है। निर्माण के लिए आप राशि पालिसी में रखते हैं। मरम्मत कार्य के लिए कोई राशि नहीं देते या बहुत ही कम राशि रखते हैं। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कई स्कूलों में नहीं है। एक न्यूज पेपर रिपोर्ट में आया है कि स्कूलों में नल से जल में झारखण्ड, राजस्थान, उड़ीसा व मेघालय पीछे। राजस्थान का नाम इसमें लिखा हुआ है। यह बहुत शर्म की बात है। हमारे बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो क्या शुद्ध पेयजल भी नहीं पी सकते क्या?

मैंने एक अतारांकित प्रश्न लगाया था। उसमें आपने जवाब दिया कि भवनों की सुरक्षित स्थिति जानने हेतु कोई सर्वे नहीं की जाती है। क्यों, क्या हम किसी हादसे के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसा हादसा होगा, फिर हम सब दौड कर जाएंगे, मीडिया आएगा, फिर हम वहां मुआवजा देंगे? हम पहले से ही क्यों नहीं एक सर्वे करें और देखें कि किस स्कूल की क्या स्थिति है, ताकि आगे कोई हादसा नहीं हो। जो ज्यादा जर्जर अवस्था में हैं उनके लिए कुछ राशि अलग से स्वीकृत कराकर, उनकी मरम्मत करें। इतना पैसा खर्च होता है परन्तु सरकारी स्कूलों की बदहाली किससे छिपी हुई है। मैं मांग रखती हूं कि आप मरम्मत के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा दें, ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें।

मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहती। मैं सीधे अपने क्षेत्र की मांगों पर आती हूं। क्रमोन्नत करने के लिए मैं आपसे मांग रखती हूं। सभी5वीं तक की स्कूल को 8वीं तक एवं 8वीं तक स्कूलों को 10वीं तक तथा 10वीं तक की स्कूलों को 12वीं तक क्रमोन्नत किया जाए। आपने इसमें एक और प्रावधान रखा है कि 8वीं में अगर पर्याप्त बच्चे नहीं हैं तो आप उनको क्रमोन्नत नहीं करेंगे। इसमें एक समस्या आती है, जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जो बहुत ही दूर हैं, वहां बच्चे पढ़ते हैं, खासकर बच्चियां, वहां पर्याप्त मात्रा में न होने से आप उस स्कूल को

(श्रीमती कल्पना देवी)

क्रमोन्नत नहीं करते हैं। मां-बाप बच्चों को स्कूल में इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि वह स्कूल 10वीं तक नहीं है, बच्चे बाद में क्या करेंगे? 'What came before, the egg or the chicken?' पालिसी हो गई है। मेरी यह रिक्वेस्ट है कि भले ही दो-चार बच्चों की कमी हो, तो आप इसको ध्यान में रखते हुए इनको भी क्रमोन्नत करें।

मेरे रायपुरा में एक स्कूल है जो 1950 में चालू हुई थी वह तब 5वीं तक थी। फिर 1978 में उसको 8वीं तक किया गया। 1978 से आज तक वह 8वीं तक ही चल रही है। इस पर भी आप विशेष ध्यान दें और इसको क्रमोन्नत करने की कृपा करें।

विषय की बात करें। मैं मांग रखती हूं कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रायपुरा में साइंस विषय की मांग है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डीसीएम में साइंस एवं मैथ्स के विषय की मांग है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चंद्रेसर में राजनीतिक विज्ञान एवं अंग्रेज़ी साहित्य की मांग है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रंगपुर में भूगोल विषय एवं अर्जुनपुरा विद्यालय में एग्रीकल्चर विषय और ऐसे ही ताथेड़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एग्रीकल्चर विषय की मांग करती हूं।

यूनिफार्म के लिए आपने स्कूल्स में 200 रुपये तय किये हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी 200 रुपये में यूनिफार्म सिलाई कर सकता है। मैं यह मांग करती हूं कि इसकी राशि बढ़ा कर कम से कम 01 हजार रुपये प्रदान करें ताकि बच्चों के लिए यूनिफार्म की सिलाई हो सके।

कोरोना के समय हमने देखा कि आपने ऑनलाइन पढ़ाई कराई। कई बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाये और वह पढ़ाई में पिछड़ गये। मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं कि जो बच्चे पढ़ाई से वंचित रह गये या पिछड़ गये, उनके लिए क्या आप कोई स्पेशल व्यवस्था या असिस्टेंस रखना चाहते हैं ताकि वह वापस दूसरे साथियों के लेवल पर आ सकें? ऐसी व्यवस्था का प्रावधान किया या नहीं? यदि नहीं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उनको ऐसी मदद प्रदान करें।

मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय की बात की है। फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इसका जिक्र किया कि कई बच्चियां जिनको उनके मां-बाप ने बालिका विद्यालय में

(श्रीमती कल्पना देवी)

एडमिशन दिलवाया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि वह को-एड में पढ़े। मैं मानती हूं कि अंग्रेजी पढ़ाना बहुत अच्छी बात है और आज की जरूरत है। उसके लिए अंग्रेजी का महत्व है परन्तु बहुत मुश्किल से गांवों में मांबाप अपनी बच्चियों को बाहर निकालकर पढ़ाई के लिए परमिशन देते हैं। वह नहीं चाहते कि उनकी बेटियां बॉय स्कूल में जायें। आपने मेरे क्षेत्र में दो राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों को रूपान्तरित करके इंग्लिश मीडियम प्रारम्भ किया। मेरी मांग है कि आप उनको दो पारियों में चलायें ताकि इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वह भी पढ़ सकें और जो बच्चियां या उनके मां-बाप उनको को-एड में नहीं पढ़ाना चाहते हैं, उनकी पढ़ाई में कोई रोक या बाधा नहीं आये और वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें।

अंग्रेजी की बात करते हैं। मैं कई स्कूल्स में गयी हूं, मैंने देखा कि जो इंग्लिश टीचर हैं उनसे ही ढंग से नहीं बोला जा रहा था तो आप कैसे सब सब्जेक्ट को इंग्लिश में पढ़वायेंगे? कहां से टीचर्स आप उपलब्ध करवायेंगे? यह मेरी समझ से बाहर है।

मैं महाविद्यालय की बात करूं तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लाडपुरा में एक भी महाविद्यालय नहीं है। मैं मांग करती हूं कि आप कम से कम एक महाविद्यालय लाडपुरा में खोलें और कन्या महाविद्यालय भी खोलें।

डी एम एफ टी की बात करें तो जो फण्ड हमने जून की मीटिंग में स्वीकृत करवाया था उसमें कई स्कूल्स के लिए भी फण्ड स्वीकृत करवाये थे। उसमें से जनजाति छात्रावास के लिए भी हमने पैसे स्वीकृत करवाये थे परन्तु आज तक उस डी एम एफ टी फण्ड से एक भी रुपया खर्च नहीं हो पाया। ऐसे ही जब मैंने मेरे एमएलए फण्ड से मीणा समाज के छात्रावास के लिए पैसे दे रखे हैं, दस लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। ऐसे ही मैंने बैरवा समाज के छात्रावास के लिए पैसे दिए हैं, वह आज तक स्वीकृत नहीं हो रहे हैं तो मेरी मांग है कि आप एमएलए फण्ड से भी, जहां जनजाति क्षेत्र हो या एस सी की बच्चियां जहां पढ़ना चाहती हो, उनके लिए अलग से स्पेशल प्रावधान करें ताकि हम हमारा फण्ड इन बच्चियों को पढ़ाई करने में मदद कर सकें और उनकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आये।

माननीय सभापति महोदय, पेपर लीक की बात करें तो इस पर काफी लम्बी चर्चा हो चुकी है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मां-बाप मुश्किल से कोई

(श्रीमती कल्पना देवी)

सब्जी बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाता है, कोई किस परिस्थिति में अपने बच्चे को पढ़ाता है और सबके पास दस लाख रुपये नहीं है उस पेपर को लेने के लिए तो उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? उनके पास ऐसा पैसा नहीं है कि वह पेपर खरीद सकें। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): Education is the movement from darkness to light. बच्चे हमारा भविष्य हैं और देश की सबसे बड़ी पूंजी उसके शिक्षित नागरिक हैं। अगर वह पढ़ेंगे तो वह आगे बढ़ेंगे। अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्भर बनेंगे।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): मैं अपने क्षेत्र की इन मांगों को चार साल से रख रही हूं। माननीय मंत्रीजी यहां विराजे हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि वह मेरी बातों का ध्यान रखेंगे। And I end with a quote given by Nelson Mandela, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the World." मैं मानती हूं कि हम सबका दायित्व एवं कर्तव्य बनता है कि कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गिर्राज सिंह।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 20, 21 एवं 22 पर मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, अभी विपक्ष के माननीय सदस्य बोल रहे थे कि विद्यालयों में अध्यापक नहीं हैं, खाली पड़े हैं। इनकी कुछ बातें ठीक नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, क्या हो रहा है यह? शांति रखो न। आपका नम्बर आये तब आप बोल लेना। अभी तो वह बोल रहे हैं न। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप?

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): पद खाली पड़े हैं, यह तो हम भी मानते हैं लेकिन खाली आज ही तो नहीं हुए हैं खाली तो पहले से ही चले आ रहे हैं। अगर आप शिक्षकों की भर्ती करते तो खाली नहीं रहते। वह आपकी वजह से खाली पड़े हैं। इन्होंने कोई भर्ती ही नहीं की। यहां आरोप लगा रहे हैं कि

(श्री गिर्राज सिंह)

आपने खाली कर दिये। स्कूल किसने बन्द किये? आपकी सरकार के समय स्कूल बन्द हुए। कितने स्कूल आपने बन्द करवाये थे? ध्यान है? 21 हजार कराये थे आपने। आप शिक्षा की दुहाई दे रहे हैं कि हम शिक्षा के बहुत ज्यादा हितैषी हैं। आपने तो छोटे-छोटे बच्चों का गला घोंटा है। वह शिक्षित ही नहीं हो पाये। गरीब लोगों के बच्चे नहीं पढ़ पाये।

(समय: 16.27 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

आपकी सरकार ने ऐसे काम किये हैं और यहां पर आप दुहाई दे रहे हैं कि हमने यह किया, वह किया। क्या किया आपने? आप बतायें। शिक्षा के क्षेत्र में आपने एक भी नया स्कूल खोला हो तो आप बतायें। 21 हजार स्कूल बन्द करने के बावजूद भी आप यहां पर दुहाई दे रहे हैं। ये पाप किसने किये? यह बीजेपी राज की देन है, और किसी की नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार की कुछ कमियां हैं वह भी मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं। जो स्कूल्स खाली हैं भर्ती करके उनकी पूर्ति करवायी जाये। आपने तमाम कालेज खोल दिये, उनमें एक-एक आदमी लगे हुए हैं। वह कैसे शिक्षा प्रदान करेगा? जितने भी कालेज या स्कूल खाली हैं उनको तत्काल प्रभाव से भरा जाना चाहिए। अब समय कम बचा है, समय रहते हुए अगर हम स्कूल्स को ठीक कर देंगे तो ठीक रहेगा। बच्चों के भविष्य की बात है।

माननीय सभापति महोदय, कुछ जिलों में ट्रांसफर पर बैन लगा हुआ है, वहां से ट्रांसफर नहीं होते हैं। लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। थर्ड ग्रेड वाले करते हैं। उन लोगों को बीस-बीस साल हो गये, मंत्रीजी, आप थोड़ा गम्भीरता से लें। उनका जीवन निकल गया पूरा। उन लोगों को अपना लेकर नहीं आये तो उनका तो पूरा जीवन निकल जायेगा। उनके लिए ऐसी पालिसी बनायी जाये कि जो लोग बाहर पड़े हैं, पालिसी दस साल की बनायें या पांच साल की बनायें, नियम एक ही बनाना। ऐसा मत कर देना कि किसी की डिजायर पर कर दें। किसी को एपीओ करके मत कर देना, जैसा पहले होता था। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी के साथ एक जैसा काम होना चाहिए। थर्ड ग्रेड के लिए बैन खोला जाये और जिन स्कूल्स में अध्यापकों की कमी है वहां पर पूर्ति की जाये, नई भर्ती की जाये। कालेजों की स्थिति ठीक नहीं है। उनकी भी पूर्ति करें।

(श्री गिर्राज सिंह)

माननीय सभापति महोदय, प्राइवेट कालेज वाले बच्चों को लालच दे कर फीस जमा करवा लेते हैं और बाद में कह देते हैं कि आप बच्चे को कालेज मत भेजना। कोई किसी जिले का है और कोई दूसरे जिले का है। उनसे इस बात के भी पैसे मांगे जाते हैं। किसी से 20 हजार रुपये, किसी से 30 हजार रुपये, किसी से 50 हजार रुपये, जैसा उनका सिस्टम है, उस सिस्टम से लेते हैं। यह शिक्षा माफिया हैं, इनको थोड़ा-सा ठीक किया जाये। सबके लिए एक ही नियम होना चाहिये। बार-बार गरीब बच्चों से पैसे लिए जाते हैं तो यह गलत बात है। इसमें हमको संशोधन करना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, आपने स्कूल क्रमोन्नत तो कर दिये पर उन स्कूलों में बिल्डिंग की कमी है। आपने स्कूल तो बारहवीं तक क्रमोन्नत कर दिये, कोई दसवीं तक कर दिये, कोई आठवीं तक कर दिये, पर उनके हिसाब से हमने बिल्डिंग की कोई व्यवस्था नहीं की। बारहवीं के लिए बारह कमरों की जरूरत है, वहां पर चार कमरों में ही स्कूल चल रहे हैं। उन स्कूलों में अगर बिल्डिंग ही नहीं होगी तो वहां पर बच्चे कैसे पढ़ पायेंगे? माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से मांग करता हूं कि जितने विद्यालय आपने क्रमोन्नत किये हैं, वहां पर बिल्डिंग की कमी है, वहां पर बिल्डिंग की व्यवस्था की जाये।

माननीय सभापति महोदय, जिन स्कूलों में टीचर नहीं हैं, कालेजों में नहीं हैं, उनके लिए आप एक सर्वे करवायें कि किस स्कूल में कितने टीचर्स की जरूरत है, उस हिसाब से हम नई भर्ती करें और बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिये। उनको उसी हिसाब से शिक्षा मिलनी चाहिये, वह गरीब लोग हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह बात सही है कि आपने सुधार किया है। अभी आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं। जो बच्चे शुरू से इंग्लिश नहीं पढ़ पाये हैं, वह एकदम से इंग्लिश में कैसे काम्पीटिशन कर पायेंगे? जो इंग्लिश स्कूल हमने बनाये हैं, उनके साथ ही हिन्दी मीडियम भी चलायें। आप पांच साल में, दस साल में बंद करें तो उनको इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि जिन बच्चों ने कभी इंग्लिश पढ़ी ही नहीं है और उनको एकदम से हिन्दी मीडियम से अंग्रेजी मीडियम में डालेंगे तो वह नहीं पढ़ पाता है। गांव के कई लोग तो यह कह रहे हैं कि जो हमने इंग्लिश मीडियम बना दिये,

(श्री गिर्राज सिंह)

उनके लिए कहते हैं कि हमारे यहां तो बंद करवा दें, हमारे यहां तो हिन्दी मीडियम ही ठीक है। उनको इंग्लिश नहीं आती है, तो यह समस्या है। आप इसको थोड़ा-सा ठीक करावें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे बाड़ी के अंदर एक स्कूल में 2874 बच्चे हैं, वह माध्यमिक विद्यालय है, उस विद्यालय को दो पारियों में कराया जाये। एक पारी में 2874 बच्चे आने में बहुत दिक्कत आती है। इतनी तो वहां पर बिल्डिंग भी नहीं है और कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए मैं आपसे मांग करता हूं कि इस स्कूल को दो पारियों में चलाया जाये।

माननीय सभापति महोदय, बाड़ी प्रोपर में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जाये। इसके लिए मैं मंत्रीजी से मांग करता हूं।

इसके साथ ही, माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में जो इधर वाले बैठे हैं, जो अभी जयकारे लगा रहे थे, बड़ी जोर-शोर से बातें करते हैं, जिन्होंने सभी स्कूलें बंद कर दीं, उसमें इनके भी नहीं बचे, इनके भी बंद हुए हैं, पर हम लोग, जो कांग्रेस से चुनकर नहीं आये, इनको हमारा हल्ला पसंद नहीं लगता, उधर जब हम चिल्लाते थे तो हम लोग, जो 21 लोग थे, इन्होंने चुन-चुनकर कि यह ज्यादा हल्ला मचाते हैं, इनके स्कूल पहले बंद कराये जायें। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने उस समय हमारे ज्यादा स्कूल बंद कराये थे। मैं मंत्रीजी से मांग करता हूं कि आप इसको थोड़ासा नोट करें। एक तो मड महुआ खेड़ा, कोरापुरा रेवई, खेड़ा, कुदना का पुरा, ऊंची का पुरा, हासी का पुरा, इन सभी को, मंत्रीजी, आपको चालू करने के लिए निवेदन करता हूं। गांव वाले काफी समय से इनकी मांग कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे यहां सैपऊ में एक कालेज है, मैं मंत्रीजी से मांग करता हूं कि आप इस कालेज को क्रमोन्नत करें। जो गरीब लोग हैं, उनको दूर-दूर जाना पड़ता है। मंत्रीजी से मैं मांग करता हूं कि आप सभी स्कूलों में कमरे दे देना, मैं आपको लिस्ट दे देता हूं, नहीं तो आप कहो तो मैं लिस्ट पढ़कर बता दूं। माननीय सभापति महोदय, मेरी मांग है कि क्षेत्र के अंदर जितने कमरे खाली पड़े हैं, जहां बिल्डिंग नहीं हैं, उनके लिए बिल्डिंग बनवायी जाये। आपने काफी स्कूल क्रमोन्नत किये हैं, यह बात ठीक है, पर उस हिसाब से बिल्डिंग तो बनवायी नहीं, उस हिसाब से जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, उनकी हमने व्यवस्था नहीं की तो खाली क्रमोन्नत करने से क्या फायदा? इससे वहां पर बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है।

(श्री गिर्राज सिंह)

माननीय सभापति महोदय, जो बच्चे हैं उनके बारे में आप सोचें। जो स्कूल आपने क्रमोन्नत किये हैं, उनमें उस हिसाब से स्टाफ लगाया जाये और आगे ज्यादा से ज्यादा कोशिश यह करें कि जो स्कूल क्रमोन्नत करें, पांचवीं से आठवीं और आठवीं से सीधी बारहवीं कर रहे हैं, वह क्रमोन्नत करें। वह तो अच्छी बात है, और करने भी चाहिये। छोटे-छोटे बच्चे हैं, वह कहां पर जायेंगे, पर उसी हिसाब से अपने को स्टाफ की भी जरूरत है। आप स्टाफ की व्यवस्था पहले करें फिर हम विद्यालय को क्रमोन्नत करें। हम उनकी तो व्यवस्था कर नहीं पा रहे हैं और स्कूल हम क्रमोन्नत करते चले जा रहे हैं। यही हाल कालेजों का है। कालेजों में अपना एक-एक टीचर लगा रखा है, एक टीचर कितनी क्लास ले पायेगा? इस व्यवस्था को थोड़ा सुधारने की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जब्बर सिंह जी सांखला।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-20, 21 और 22 पर बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा पर आज सवेरे से चर्चा हो रही है। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे। मेरा ऐसा मानना है कि राजस्थान में जो हमारी सरकारी स्कूलें हैं, उनमें आज की तारीख में जो व्यवस्थाएं हैं, अगर उनको सुधारी जायें और शिक्षकों के जो पद खाली हैं, वह भरे जायें तो प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छी तरह की पढ़ाई हमारे सरकारी स्कूलों में होती है। वर्तमान समय में जो राजस्थान की स्थिति है, जैसा अभी बाड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है, मैं उनकी बात का 100 प्रतिशत समर्थन करता हूं। हम सभी विद्यालयों को क्रमोन्नत तो करते हैं, लेकिन उसमें बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं होती है। वहां पर पेड़-पौधों के नीचे बैठकर बच्चे पढ़ाई करते हैं। कमरे चार होते हैं और स्कूल वहां पर आठवीं तक चलता है। उसको हम क्रमोन्नत करते हैं दसवीं तक, पर वह कमरे चार के चार ही रहते हैं। वहां पर पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं, वह चार-पांच से ज्यादा नहीं होते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन ब्लाक हैं, जहां ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहां पर पूरे कमरे नहीं हैं, बैठने के लिए जगह नहीं है और वहां पर बहुत सारे टीचर्स के पद खाली हैं। हम हरियालो

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

राजस्थान की भी बात करते हैं। वहां पर बाउण्ड्री नहीं होने की वजह से हमारे वहां के जो टीचर्स हैं, वह पेड़-पौधे लगाने के इच्छुक हैं, वह लगाते हैं लेकिन बाउण्ड्री नहीं होने के कारण वहां पर पेड़-पौधे नहीं पनप पाते हैं। बहुत सारी स्कूलें ऐसी भी हैं जहां पर बाउण्ड्री नहीं हैं। आदरणीय मंत्री महोदय यहां पर विराजे हुए हैं, मेरा निवेदन रहेगा कि जिन विद्यालयों में कमरे नहीं हैं, उनमें कमरे बनावायें और जो बाउण्ड्रीविहीन विद्यालय हैं उनमें विशेष तौर से बाउण्ड्री का एक फण्ड आप इसी बजट में दे देंगे तो आपकी कृपा होगी।

माननीय सभापति महोदय, मेरे आसीन्द शहर में एक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक था, उसको आपने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम बना दिया। आसीन्द शहर नगरपालिका क्षेत्र है, उसमें 25 वार्ड हैं। बालिकाओं के लिए पढ़ने के लिए उच्च माध्यमिक की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि इंग्लिश मीडियम तो आपने खोल दिया, लेकिन वहां धरातल पर थोड़ी अलग स्थिति है। वहां पर आप जाकर देखिये आपके पास इंग्लिश पढ़ाने के लिए टीचर नहीं हैं। आपने खोला, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं। आपने जहां भी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं मेरा उसके लिए विरोध नहीं है, लेकिन बालिकाओं के लिए जो माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करना चाहती हैं, उनके लिए आसीन्द शहर, जो 25 वार्ड का शहर है, वहां बालिकाओं के लिए उच्च माध्यमिक की शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आप इस पर भी थोड़ा गौर करेंगे तो आपकी मेहरबानी होगी।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में उखलिया, रतनपुरा, बाडची, हिरास और ओझियाणा में उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जैसे हिरास और ओझियाणा, इनके लिए मैं पिछले पांच साल से मांग करता आ रहा हूं, आज भी हिरास गांव में बल्लियां लगी हुई हैं। वहां माध्यमिक स्कूल है और हिरास ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर है, वहां पर बल्लियां लगी हुई हैं। DMFT से 2 करोड़ रुपया पास भी हो रखा है ओझियाणा और हिरास के लिए, लेकिन आज तक काम चालू नहीं हो पाया है। इसी तरह बडाच में और रतनपुरा में चार-पांच कमरे हैं, बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। वहां पर पहाड़ी इलाका है, मगरा क्षेत्र है, इसके लिए मेरा निवेदन रहेगा।

डी एम एफ टी का पैसा शिक्षा विभाग में जहां कमरे नहीं हैं, बैठने की व्यवस्था नहीं है, उसमें लगे। सरकार के पास पैसा हो या न हो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारा जो डी एम एफ टी का पैसा भीलवाड़ा जिले में

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

है, आसीन्द हुरड़ा विधान सभा में डी एम एफ टी का सबसे ज्यादा पैसा आता है। मेरा निवेदन आपसे रहेगा कि आप कलेक्टर को आदेश दें।

सभापति महोदय, क्रमोन्नत के लिए हुरड़ा साइड में आगूचा ग्राम पंचायत में भगवानपुरा, सरीरी ग्राम पंचायत में जालिमपुरा, तश्वारा ग्राम पंचायत में आदर्श नगर, टोकरवाल ग्राम पंचायत में सुरास और कंवलियास ग्राम पंचायत में गोपालपुरा और एक नवगठित ग्राम पंचायत जालखेड़ा है, वहां क्रमोन्नत के प्रस्ताव आपके पास आये हुए हैं आप इन विद्यालयों को क्रमोन्नत करेंगे तो आपकी अति कृपा होगी।

सभापति महोदय, मेरा एक विशेष निवेदन रहेगा कि मैंने गुलाबपुरा में बॉय्ज कालेज के लिए बहुत्सी बार मांग की है। मेरा आज पुन: एक बार हाथ जोड़कर निवेदन है कि गुलाबपुरा में बॉय्ज कालेज खोला जाये। बदनौर जो मेरा उपखण्ड क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, पूरा मगरा इलाका है, अरावली की पहाड़ियों में बसा हुआ है वहां 17 ग्राम पंचायतें पहाड़ों में हैं, वहां आप महाविद्यालय खोलने की कृपा करें, आपकी अति मेहरबानी होगी।

सभापति महोदय, एक मेरा विशेष निवेदन यह रहेगा कि कुक कम हैल्पर जो हमारी महिलाएं हैं, वह अपने घर के काम को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर के स्कूलों में जाती हैं और वहां खाना बनाती हैं, उनका पूरा दिन बर्बाद होता है। उनको हम मानदेय के नाम से 1200, 1300 रुपये देते थे। पिछली बार मैंने यहां आवाज उठायी थी उस समय 10 प्रतिशत पैसा आपने बढ़ाया है। अभी 1500, 1600 रुपये उनका मानदेय है। मेरा मानना है कि नरेगा में जाने वाले लोग बबूल की छांव में बैठते हैं, उनको 200 रुपया मिलता है। कुक कम हैल्पर महिलाएं जो अपना घर का सारा काम छोड़कर के हमारे बच्चों का खाना बनाने के लिए जाती हैं, उनको केवल 1200, 1500 रुपये मिलते हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि उनका जो मानदेय है, वह कम से कम 6 हजार रुपये किया जाये। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि अगर हम पैसा पूरा नहीं देंगे, मानदेय पूरा नहीं देंगे तो फिर कोई भी ईमानदारी से काम नहीं कर पायेगा। आप कुक कम हैल्पर का कम से कम 6 हजार रुपये मानदेय करें।

सभापति महोदय, मेरे आसीन्द हुरड़ा के सभी सरकारी विद्यालयों में बच्चों को शुद्ध पानी पिलाने के लिए आर.ओ. प्लांट लगाये जायें और वाटर

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

कूलर लगाये जायें। अभी जो वहां पानी की व्यवस्थाएं हैं, चंबल की लाइनों का काम चल रहा है, चंबल का पानी जब मिलने लगेगा तो सही रहेगा। वहां अलग ही तरह का पानी है। वहां सभी विद्यालयों में आर.ओ. लग जायेगा तो शुद्ध पानी बच्चों को पीने के लिए मिल जायेगा।

सभापति महोदय, साथ ही मेरे यहां जो बाउंड्रीविहीन स्कूल हैं, वह मैं आपको बता देता हूं, डेडी का बाड़िया जो कि रघुनाथपुरा ग्राम पंचायत में है, गंगाराम जी का खेड़ा जो दड़ावट में है, खैरपुरा जो दड़ावट में है, रैलियां मारुधोरा जो दड़ावट में है, सांगनी ग्राम पंचायत दांतड़ा में है, हरिपुरा ग्राम पंचायत इरास में है। 6 विद्यालय ऐसे हैं जहां कांटे वाले तार लगे हुए हैं। कुछ विद्यालयों में कांटों की बाड़ लगी हुई है। जो थोर होते हैं उनकी चारों तरफ बाड़ें लगा रखी हैं, वहां सांप, बिच्छू वगैरह सब निकलते हैं, बच्चों के लिए खतरा बना रहता है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि 52 स्कूलों में बाउंड्रियां नहीं हैं। बाउंड्रीविहीन 52 स्कूल हैं। जिसमें 6 विद्यालय ऐसे हैं जहां थोर की बाड़ लगी हुई है। आप उस पर भी अगर ध्यान देंगे तो आपकी अति कृपा होगी।

श्री सभापति: 2 मिनट में समाप्त करें।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): सभापति महोदय, मेरे आसीन्द विधान सभा क्षेत्र में बदनौर उपखण्ड है, जिसमें कक्षा कक्षों की कमियां हैं। आप नोट कर लें। बूंडेला, चौहानों का बाड़िया, बेगाला की बाली, गोपालपुरा, काछियों की बेरी, कलेसियों का बाड़िया, खन्याज, कोलपुरा, लगेतों का बाड़िया, लक्ष्मण जी का खेड़ा, महाराम जी की झौंपड़ियां, रणावतों का खेड़ा, सबल सागर, सिंहपुरा, थड़िया, भील बस्ती पाटन, भीलों की बस्ती, बूंडेला दुलहा का खेड़ा, बेदला का बाड़िया, गांधी नगर, गंगाराम जी की झौंपड़ियां, गोपालपुरा, गोपालपुरा की झौपड़ियां, हमीरगढ़, जवानपुरा, जोधगढ़, कुंभलाई, कुंडा की थाक, लगेतों का बाड़िया, मानपुरा, महाराम जी की झौंपड़ियां, मोडा मगरां, नाहर मगरां, नारायणपुरा, पूरण सिंह जी का बाड़िया, रघुनाथपुरा, संग्रामपुरा, सूरेला वार्ड नंबर 7, रायरा, बड़ाच, जैतगढ़ पाटन, कर्मा का बाड़िया, इन सभी विद्यालयों में कमरों की कमी है। मेरे पास लिस्ट है, मैं टेबल कर दूंगा। इन सभी जगहों के लिए आप अलग से फंड दिलायें।

सभापति महोदय, मेरा आपसे एक विशेष निवेदन रहेगा कि हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह जी शेखावत, देवली की शौर्य गाथा को विस्तृत रूप से

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

राजस्थान के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाये। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द। वन्दे मातरम।

(माननीय सदस्य श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द) के सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-05 देखें)

श्री सभापति: थैंक यू। श्रीमती सफिया जुबेर।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 2 घंटे बढ़ाकर 7 बजे तक कर दिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय 7 बजे तक कर दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 7 बजे तक बढ़ाया गया।

श्रीमती सफिया जुबेर।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 20-प्रारम्भिक शिक्षा, मांग संख्या 21-माध्यमिक शिक्षा व मांग संख्या 22-उच्च शिक्षा पर विचार

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 21 और 22 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगी।

सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं मुख्य मंत्री जी को देना चाहूंगी जिन्होंने पिछले 4 साल में शिक्षा के क्षेत्र में समस्त राजस्थान में ऐतिहासिक काम किये हैं। हालांकि पिछली सरकार ने भी ऐतिहासिक काम तो किये थे, जब इन्होंने हजारों की संख्या में स्कूलों को बंद कर दिया था। इस बार हमारे मुख्य मंत्री ने बड़ा दिल रखते हुए, हालांकि इनके इलाकों में, इनकी विधान सभाओं में खूब स्कूल भी क्रमोन्नत किये हैं, कालेज भी खोले हैं। मैं सुबह से देख रही हूं कि बुराई करने में लग रहे हैं और अंत में आपसे मांग भी रहे हैं। मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि यह गुर्रा भी रहे हैं और मांग भी रहे हैं। इनकी बातों पर ध्यान न दें।

(श्रीमती सफिया जुबेर)

सभापति महोदय, मैं मेवात के इलाके से आती हूं तो सबसे ज्यादा बात मेवात की ही करूंगी। मेवात शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अन्य जिलों से कोसों दूर है। यहां शिक्षा का उजाला करने के लिए प्रदेश व केन्द्र सरकार की दर्जनों योजनाएं आयीं, लेकिन फिर भी यहां शिक्षा का स्तर उस हिसाब से नहीं बढ़ पाया है जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए था। इसके पीछे अनेकों कारण रहे होंगे, फिर भी शिक्षा को धरातल पर लाना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें कड़ा परिश्रम करने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, मेवात क्षेत्र में अलवर व भरतपुर में 16 मेवात आवासीय विद्यालय हैं। 11 आवासीय विद्यालय जो अलवर में थे, उन्हें तो शुरू कर दिया गया था, लेकिन भरतपुर के स्कूलों को शुरू नहीं किया गया है। मैं आपसे मांग करूंगी कि इन स्कूलों को अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट को दिया जाये और इनको भी शुरू किया जाये। इसमें बहुत सारा बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेवात बोर्ड से दिया गया है। यह अच्छे स्कूल बन जायेंगे।

मुख्य मंत्री जी ने भी इन स्कूलों के लिए आश्वासन दिया था कि आठवीं के स्कूल हैं, गर्ल्स स्कूल हैं, इनको बारहवीं कर दिया जायेगा, लेकिन अभी तक यह बारहवीं नहीं हुए हैं। मैं इस सदन के माध्यम से आपसे मांग करूंगी कि इन स्कूलों को बारहवीं किया जाये क्योंकि राजस्थान के समस्त गर्ल्स स्कूल चाहे वह कस्तूरबा गांधी हों, वह भी बारहवीं हो गये हैं, लेकिन हमारे मेवात के स्कूल अभी भी आठवीं ही हैं। यह सबसे पुरजोर डिमांड मैं आपके सामने करती हूं।

सभापति महोदय, मेवात की बात करें तो मेवात को पिछड़ापन, बैकवर्ड, इस तरह से जोड़ा जाता है। सांगानेर से एक विधायक आते हैं, वह भी कल जब पुलिस पर डिमांड थी तो मुझे कह रहे थे कि, विधायक जी, क्राइम तो आपके यहां से शुरू होते हैं और आपके यहां ही खतम होते हैं। उनका कहने का मतलब था कि मेवात में ही क्राइम होता है। आता कहां से है? हरियाणा से आता है और वापस चला जाता है।

जैसे अभी आपने देखा कुछ दिनों पहले हरियाणा से लोग आये और हमारे जुनैद और नासिर को किडनैप करके ले गये और उनको जिंदा जला दिया। उन्होंने बिलकुल सच्चाई बयान की है। बिलकुल सच्चाई बयान की है उस विधायक ने। ऐसा हुआ है। हमारे भोले-भाले लोग, कर दिया उनका

(श्रीमती सफिया जुबेर)

अंतिम संस्कार। अगर इनके यहां कुछ हो जाता तो यह 12 दिन तक नहीं करते और जाने क्या-क्या मांगते, लेकिन हमारे तो भाले-भाले लोग थे, उनको तो समझ नहीं थी। वह तो छोटा-मोटा जो आश्वासन दिया, उसमें हो गये। यह घटना इस बात को दर्शाती है कि इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है तो लोगों का स्तर हमें बढ़ाना ही पड़ेगा, वरना तो वे लोग भी डिमांड करते न कि एक करोड़ भी दो, 2 सरकारी नौकरियां दो। क्यों नहीं कर पाये क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं थी।

मैं इस सदन के माध्यम से डिमांड करती हूं कि उन लोगों को वह सभी मिलना चाहिए जो उदयपुर में कन्हैया को मिला था। यह उनका अधिकार है। आदमी कोई भी मरे, जीवन का मूल्य सबका समान है इस देश में और इस लोकतंत्र में। आप इसमें भेदभाव नहीं कर सकते। आप डवलपमेंट में तो भेदभाव कर सकते हो लेकिन इस बारे में, यह जो मौलिक अधिकार है, उसमें आप भेदभाव नहीं कर सकते। यह संविधान में लिखा हुआ है जो डा. भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था।

सभापति महोदय, अब हम शिक्षा की बात करें तो मैं कहना चाहूंगी कि राजस्थान में कोटा एक कोचिंग सेंटर बन गया है, एक रोल मॉडल बन गया है। कोचिंग सेंटर्स हमारे अलवर में भी हैं। अभी कुछ दिनों पहले 24 से जब बोर्ड एग्जाम थे, तब कुछ बच्चों का फोन आया कि, मैडम, हमें हमारे प्रिंसिपल हॉल टिकट नहीं दे रहे हैं। मैंने पूछा, क्यों नहीं दे रहे हैं? कह रहे, मैडम, हम कोचिंग सेंटर में जाते हैं तो हमारी फीस यह कोचिंग सेंटर वाले ही स्कूल्स को देते हैं। फिर वह हमें हॉल टिकट देते हैं। फिर कोचिंग सेंटर वालों से पूछा तो कहा कि, मैडम, हमने फीस जमा नहीं करायी है। हम सब करा देंगे तो यह प्राइवेट स्कूल वाले प्रेक्टिकल में नंबर नहीं देंगे। मतलब, यह टोटल माफिया है। इन कोचिंग सेंटर्स में ऐसा क्या है जो सरकारी स्कूल्स में नहीं है? सरकारी स्कूल के टीचर्स अच्छे हैं, क्वालिफाइड हैं। यही टीचर्स जाकर के कोचिंग सेटर्स में पढ़ाते हैं। वह बच्चों को मानसिक प्रताड़ना इनकी वजह से हो रही है इन कोचिंग सेंटर्स और प्राइवेट स्कूल वालों से। प्राइवेट स्कूल वाले उनको पेपर्स में एडमिशन दे देते हैं लेकिन उनकी अटेंडेंस नहीं होती है। मैं तो आपसे कहना चाहूंगी कि प्राइवेट स्कूल्स पर इलेवंथ और ट्वेल्थ में आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस करवाइए ताकि ये बच्चे उसी स्कूल में जाएं और कोचिंग में

(श्रीमती सफिया जुबेर)

न जाएं ताकि सच्चाई सबके सामने आये। हजारों करोड़ रुपये कमा रहे हैं प्राइवेट स्कूल और कोचिंग सेंटर वाले और गरीब बच्चे तो वहां जा नहीं सकते हैं और वो रह जाते हैं और इनका तो माफिया है, पेपर भी लीक होता है तो इनकी सांठ-गांठ से ही होता है कोचिंग सेंटर से, ऐसे नहीं होता है। मैं इस बात की डिमांड करूंगी कि प्राइवेट स्कूल्स पर थोड़ी लगाम कसनी चाहिए। इतनी अधिक फीस भी ये वसूलते हैं और मनमाने काम भी ये करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं मेरे इलाके की बात करूं तो बहुत से स्कूल माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दिये हैं, कोई कमी नहीं छोड़ी है। स्कूल्स हों, चाहे कालेजेज हों, चाहे सब्जेक्ट्स हों। छप्पर फाड़ कर दिया है। मुख्य मंत्रीजी तो हमारे अभिभावक हैं, मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि आप मांगते-मांगते थक जाओगे लेकिन मैं देते-देते नहीं थकूंगा। मैं फिर मांगूंगी कि हमारे इलाके में चोरेटी ईस्तमुरार स्कूल है उसको बारहवीं किया जाए। एक मानकी में है, एक बूजाका में है, इसन के बास में, इनको ट्वेल्थ किया जाए क्योंकि बहुत जरूरत है। अगर हमें मेवात का सो कॉल्ड पिछड़ापन दूर करना है तो। इसके अलावा साहडोली में एक बालिका स्कूल है, जिसको आपने ट्वेल्थ किया लेकिन वहां जगह की कमी है तो हमने नई जगह अलाट करवाई है, तो उसके लिए पूरी बिल्डिंग का पैसा भी मैं चाहूंगी कि सरकार की तरफ से दिया जाए। इसके अलावा साइंस सब्जेक्ट्स भी खोलने हैं, बल्कि मैं तो यह चाहूंगी कि सभी ट्वेल्थ के स्कूल जो आपने क्रमोन्नत किये हैं, सभी में साइंस सब्जेक्ट भी होना चाहिए और आर्ट्स भी होना चाहिए, नहीं तो गांव में रहने वाले बच्चे डाक्टर, इंजीनियर कैसे बनेंगे तो सभी स्कूलों में साइंस हमारे यहां होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, बहुत से प्राइमरी स्कूल्स हैं जहां उनको जरूरत है कि आरटीई के अनुसार आठवीं कर दिया जाए। कालेज की बात करें तो मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि आपने तीन कॉलेजेज दिए हैं फिर भी अगर एक और पोलीटेक्निक कालेज और आ जाए रामगढ़ में तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम हो जाएगा पूरे इलाके में और जो रामगढ़ में कालेज है उसको राजकीय पोस्ट ग्रेजुएट कालेज बनाना चाहिए और कुछ सब्जेक्ट भी इसमें एड करने चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, महिला शिक्षा की बात करें तो मुझे लगता

(श्रीमती सफिया जुबेर)

है कि अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में महिला शिक्षा तो बहुत ही पीछे चल रही है। शिक्षा में मुझे लगता है कि इसको जो संभाल रहे हैं वो सारा पुरुषों के हाथ में है। मुझे लगता है कि इस डिपार्टमेंट में ज्यादातर महिला आफिसर्स होनी चाहिए। आज हमारे यहां बैठी हैं, अपर्णा अरोड़ाजी, इन्होंने पहले भी बहुत काम किया है, तो ऐसी आई ए एस आफिसर आप लगाएंगे शिक्षा विभाग में ज्यादा से ज्यादा तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम होगा। बल्कि मैं तो यही कहूंगी कि स्कूल आपने ट्वेल्थ करा दिए तो रूम्स मांगने की हमें क्या जरूरत है। अगर आपने बारहवीं का स्कूल किया है तो उसमें 12 कमरे होने ही चाहिए। अगर आपने आठवीं का किया है तो उसमें 8 कमरे होने ही चाहिए। पांचवीं है तो 5 कमरे होने ही चाहिए। साइंस सब्जेक्ट है तो लैब होनी ही चाहिए। ये सारी चीजें मुझे लगता है कि मैनेजमेंट लेवल पर तय हो जानी चाहिए कि कहां किसकी जरूरत है और वहां उसके अनुसार उसको बांट देना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत काम किये हैं। रोज बच्चों को दूध मिल रहा है, यूनिफार्म मिल रही है, 200 रुपये सिलाई के भी मिल रहे हैं। इन 200 रुपये के बारे में भी बहुत सारे एमएलए जिक्र कर रहे थे कि 200 रुपये में क्या होगा? कुछ तो होगा, यह भी बहुत बड़ी बात है कि कुछ तो होगा, कुछ दिया ही तो है, किसी से कुछ लिया तो नहीं है, लेकिन जब नेगेटिव सोच होती है तो मुंह से भी सब बातें नेगेटिव ही निकलती हैं।

माननीय सभापति महोदय, जो बात आई है इंग्लिश मीडियम की, यह एक बहुत बड़ा कदम है। मुझे ध्यान है कि जब मैं पहली क्लास में थी तो भरतपुर में थी। वहां तो अंग्रेजी भी हिन्दी में पढ़ाते थे। फिर पांचवीं क्लास में मैं साउथ इंडिया चली गई तो वहां पर हिन्दी की मैडम को ही बस हिन्दी आती थी। यह बहुत फर्क था, आज से 40-45 साल पहले की बात बता रही हूं। यहां पर स्कूल में अब इंग्लिश आ रही है तो मतलब हम काफी पीछे हैं, यह मानो कि हम इंग्लिश के मामले में पचास साल पीछे चल रहे हैं। यह करके बहुत अच्छा किया है कि बच्चों को जो वंचित रह रहे थे, प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते थे, वो इंग्लिश उनको पढ़ने का मौका मिलेगा। हालांकि टीचर्स की कमी है, सबकी कमी है लेकिन एक दिन में सब कुछ नहीं सुधरता, इस बात को मैं समझती हूं लेकिन एक शुरुआत की है, बहुत ही पोजिटिव

(श्रीमती सफिया जुबेर)

कदम है और इसका बहुत पोजिटिव असर हमारे स्टूडेंट्स पर गया है और सबने इसकी वाहवाही भी की है। हालांकि थोड़ी स्टाफ की कमी हो सकती है लेकिन अब टीचर्स की भर्ती हो रही है तो मुझे लगता है कि यह कमी भी दूर हो जाएगी। पद खाली हैं इसीलिए भर्ती हो रही है। स्कूल बढ़ेंगे तो पद भी बढ़ेंगे, खाली होंगे तो भर्ती भी होगी और हमारे नौजवान नौकरी में भी लगेंगे।

माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि मेवात को पिछड़ेपन से जोड़कर न देखा जाए, जितना ज्यादा हो सके, मेवात में विकास होना चाहिए, इसके लिए मेवात विकास बोर्ड भी बनाया गया है। जिसका बजट पिछली बार 25 करोड़ रुपये था, मुझे लगता है कि उसको कम से कम 100 करोड़ होना चाहिए। इस बार का सारा बजट स्कूल्स में लगा है, रूम्स में लगा है, पूरा हंडरेड परसेंट बजट उसमें लगा है। हम तीन विधायक मेवात से आते हैं, तीन विधायक आते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ हमारे इलाके में बढ़िया होना चाहिए ताकि लोगों को भी लगे कि हमने उनके लिए काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, आप देखिए, मेव अलवर, भरतपुर, नूंह और थोड़ा मथुरा में बसते हैं, जहां कृष्णजी का जन्म हुआ था। मैंने भी पूरा इतिहास निकलवाया जागाओं से कि हमारा इतिहास क्या है तो उस इतिहास में निकलकर आया कि मेव तो राम और कृष्ण के वंशज हैं। चाहे धर्म का परिवर्तन हो गया हो, कुछ भी हो गया हो लेकिन खून तो आदमी का नहीं बदलता, खून तो हममें राम और कृष्ण का ही है तो इस बात को आप सब लोग ध्यान में रखें कि मेव क्या हैं और इन्हें मेवा समझें। इन्हें बार-बार पिछड़े और ये और वो किसी को कहने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आप दस साल में देखिएगा कि मेव कहां पर पहुंचेंगे। जब हम तीन विधायक यहां पर पहुंचे हुए हैं तो आप सोचो कि हम कहां-कहां पर भी पहुंच जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ की उम्मीद हम आपसे करते हैं कि जब सी एम साहब यहां पर रिप्लाई देकर बजट पास कराएंगे तो मेवात के क्षेत्र के लिए ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा डवलपमेंट के काम की घोषणा करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री गोपी चन्दजी मीणा।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 20-प्रारम्भिक शिक्षा, मांग संख्या 21-माध्यमिक शिक्षा, मांग संख्या 22-उच्च शिक्षा पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, सम्पूर्ण प्रदेश में और मेरे जिले की बात करूं तो जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता में कमी आई है, उसका कारण है कि हमने विद्यालय तो क्रमोन्नत किये हैं, विषय भी खोले हैं लेकिन स्टाफ की कमी है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि रिक्त पदों को भरा जाए। विद्यालय में तृतीय श्रेणी अध्यापक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद भी सृजित किए जाएं। थर्ड ग्रेड टीचर लेवल वन और टू के रिक्त पदों को भरा जाए, व्याख्याता और संस्था प्रधान के पद भरे जाएं। विद्यालय में भौतिक संसाधनों को सुरक्षित और विकसित करने के लिए वहां चारदीवारी का भी निर्माण किया जाना चाहिए। आज भी विद्यालयों में दूर-दराज से आने वाले बच्चे पानी की केटली साथ लाते हैं। मेरा अनुरोध है कि चम्बल योजना के तहत हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी ने प्रत्येक ढाणी-ढाणी, मजरे में जल जीवन मिशन योजना में पानी देने का काम किया है, तो प्रत्येक विद्यालय को भी मैं उस योजना से जोड़ने की मांग करता हूं ताकि शुद्ध पेयजल बच्चों को मिल सके।

अभी आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आर ओ भी वहां लगाया जाए ताकि शुद्ध पेयजल छात्र-छात्राओं को मिल सके। मेरा निवेदन है कि भीलवाड़ा जिले में सरकार पैसा नहीं दे कोई बात नहीं लेकिन भीलवाड़ा जिले में डी एम एफ टी का जो पैसा है, उसमें पूरे जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र सहित पूरे जिले में डी एम एफ टी के तहत आर ओ प्लांट लगाए जाएं ताकि शुद्ध और मीठा पानी बच्चों को मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं कि विद्यालयों में शौचालयों की व्यवस्था हो और खेल मैदान भी विकसित किए जाएं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि चारदीवारी निर्माण का मनरेगा में अनुमत तो कर रखा है लेकिन बाउण्ड्री वाल का एक भी मनरेगा में कार्य स्वीकृत नहीं किया जाता है। मेरा निवेदन है कि सरकार अधिकारियों को डाइरेक्शन जारी करे कि मनरेगा में अनुमत करके उसको कम्प्लसरी करे और चारदीवारी निर्माण का कार्य करवाया जाए। इसी के साथ खेल मैदान की चारदीवारी का निर्माण भी किया जाए ताकि हमारे बच्चों को खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने की सुविधा मिल सके।

(श्री गोपी चन्द मीणा)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर 10 साल, 15 साल, 20 साल से तृतीय श्रेणी के अध्यापक पड़े हुए हैं, उनका भी परिवार है, तो मेरा निवेदन है कि नियमों में शिथिलता बरतते हुए तबादला नीति भी लागू की जाए और उन शिक्षकों को गृह जिले में स्थानांतरण और पदस्थापित किये जाने की मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की मांग करना चाहता हूं कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फतेहपुर, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गड़बोदिया, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तलोदा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आगरया, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नातूण, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय माल का खेड़ा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बोराणी। इन विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की मांग करता हूं।

(समय: 17.00 बजे)

मेरे यहां कोटड़ी उप-खण्ड क्षेत्र बड़ा कस्बा है, वहां छात्र-छात्राओं का सीनियर स्कूल है, छात्र-छात्राओं की मांग है कि वहां विज्ञान संकाय खोला जाये। इसके साथ ही गणित संकाय खोलने की मैं मांग करता हूं। वहां कला संकाय के अलावा कोई और सोर्स नहीं है। बच्चों को एडमिशन के लिए दूर भीलवाड़ा जाना पड़ता है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि विज्ञान, गणित और कृषि संकाय उप-खण्ड मुख्यालय पर खोले जाएं ताकि छात्र-छात्राओं को सुविधा मिल सके।

सभापति महोदय, एक सैनिकों का गांव है लुंहारीकलां, वहां भी बच्चों की अच्छी स्ट्रैंथ है, मैं वहां भी विज्ञान संकाय खोलने की मांग करता हूं। सरसिया में भी मैं गणित और विज्ञान संकाय खोलने की मांग करता हूं। सभापति महोदय, मेरे जहाजपुर में विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों की शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण करने के लिए विद्यालय भवन की चारदीवारी निर्माण कार्य हो। मैं खेल मैदानों के लिए भी निवेदन करना चाहता हूं। जहाजपुर और कोटड़ी में उप-खण्ड स्तर पर डी एम एफ टी के माध्यम से इनडोर और आउटडोर खेल स्डेडियम खोला जाये ताकि वहां के छात्र-छात्राओं को सुविधा मिल सके।

(श्री गोपी चन्द मीणा)

सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रदेश के प्रबोधक संघ हैं, उनकी मांग को पूरा किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मेरे जहाजपुर में अतिक्रमण की बहुत समस्या है। मेरा निवेदन है कि भू-माफियाओं से हमारे खेल मैदानों और आरक्षित जमीन को बचाने के लिए सरकारी अधिकारियों को डायरेक्शंस दिये जाएं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय मुंशीपुरा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामपुरा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोटड़ी के खेल मैदानों से अतिक्रमण हटाया जाये ताकि ग्रामवासियों को लाभ मिल सके।

सभापति महोदय, ग्रामवासियों के द्वारा बार-बार ज्ञापन देने के बावजूद प्रशासनिक अधिकारी सहयोग नहीं करते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है, मंत्री जी से अनुरोध है कि जहां भी सरकारी विद्यालयों में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण है वहां सम्बन्धित संस्था प्रधान की जिम्मेदारी फिक्स करें, सम्बन्धित सीबीईओ, सीडीओ की जिम्मेदारी फिक्स करें। अगर वह कार्रवाई नहीं करता, उसके खिलाफ नोटिस, चार्जशीट जारी करें।

सभापति महोदय, मेरे जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के कुछ विद्यालय जो बन्द हो गये थे, जैसे- राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवपुरा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय खण्डेरिया, राजकीय प्राथमिक विद्यालय घटी का बाड़ा, नेशनल हाईवे पर आने-जाने में आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अत: मेरा अनुरोध है कि उपरोक्त विद्यालयों को पुन: चालू किया जाये। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि विद्यालयों में सरकारी आयोजनों में राजनीतिकरण किया जा रहा है। इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है।

सभापति महोदय, साइकल वितरण समारोह, वार्षिकोत्सव कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिताओं में जो आयोजन होते हैं उनमें 100 परसेंट राजनीतिकरण किया जा रहा है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि कम से कम विद्यालयों में राजनीतिकरण न करें। वहां के संस्था प्रधान, वहां के सीबीओ, आदि को शामिल किया जाता है। वहां के स्थानीय जन प्रतिनिधियों को न बुलाकर अन्य जो हिस्ट्रीशीटर लोग हैं, जो न कभी वार्ड पंच बने, न ही कभी किसी संवैधानिक पद पर रहे, उन्हें बुलाकर आयोजन किया जाता है। बार-बार मेरे द्वारा लिखित में शिकायत देने के बाद

(श्री गोपी चन्द मीणा)

भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की। मेरा निवेदन है कि कम से कम विद्यालयों में राजनीतिकरण न हो।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): सभापति महोदय, मेरे जहाजपुर की कुछ डिमांड्स मैं रखना चाहूंगा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इटूंदा, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कुचलवाड़ा, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरसिया, राजकीय माध्यमिक विद्यालय खेड़ी कोटड़ी, इन विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि भवन के लिए आप बजट आबंटित करें।

मैं अपने जहाजपुर के निम्नलिखित विद्यालयों के जो कुछ क्षतिग्रस्त भवन हैं, जो पहले के बने हुए हैं और आज पूर्ण रूप से जर्जर हो चुके हैं, उनके लिए नवीन भवन और अतिरिक्त कक्षा कक्ष की मांग करता हूं:- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खोहराकलां/बिलेठा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिन्ध्याभाटा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ऊंचा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोरमगढ़, राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोदान का बाड़ा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गणेशपुरा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय माल का खेड़ा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झीकली, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामपुरा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रावतखेड़ा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीपुरा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय लाला का बाड़ा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मातोलाई, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बोरानी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सेहलादाता, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पांचा का बाड़ा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मनोहरगढ़, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ढगरिया, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय माताजी का खेड़ा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मीणा का खेड़ा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बावड़ी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हथोड़िया बिहाड़ा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अमरपुरा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बारला पोलिया, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय झालरा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शिवपुरा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नराणा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय माना का बरड़ा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चावंडिया, राजकीय

(श्री गोपी चन्द मीणा)

प्राथमिक विद्यालय गोदयाला का झूपड़ा लुहारीकलां, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोठाज, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढोकलिया कोटड़ी।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: Thank You. श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव): सभापति महोदय, मांग संख्या 20, 21 एवं 22 को पास करने का मैं समर्थन करता हूं। इसके साथ आज के विषय पर यह कहना चाहता हूं कि नसीहत के तौर पर कई भाई अच्छी-अच्छी बातें कहते हैं, वह तो मैं नहीं कहना चाहता हूं, नसीहत सबको मिली हुई है। शिक्षा ही एक ऐसा मार्ग है जिससे हैवान के स्थान पर इंसान बनता है। जमीन और आसमान के बीच में लाखों खुदा की मख़लूक़ है, उस मख़लूक़ में खुदा को भी सबसे ज्यादा पसन्द इंसान है। इंसान को अच्छा और इज्जतदार उसका इल्म बनाता है। इल्म की जहां कमजोरी है वहां सरकार का दायित्व है कि उस जगह अच्छी तरह से गरीबों के बच्चे फ्री में पढ़ें। यह इन्तजाम करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। अपने राजस्थान में भूतपूर्व मुख्य मंत्री स्वर्गीय मोहन लाल सुखाड़िया ने 11 रेगिस्तानी जिलों में जितने भी कर्मचारी बाहर से, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में शुरू से लेकर आज तक शिक्षा का स्तर कमजोर है और वहां के स्थानीय लोग, कर्मचारी अधिकारी नहीं आते थे, इसलिए सुखाड़िया साहब ने प्रतिबन्ध लगाया था 11 जिलों में कि यहां से किसी भी कर्मचारी को बाहर के जिले में बदला नहीं जायेगा।

भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी। किसानों की हितैषी। इसने वह पाबन्दी तोड़ दी। उस पाबन्दी को तोड़ने से अब हमें भारी नुकसान हो रहा है। सरकार उस मामले में मेरे ख्याल में जागरूक नहीं है। जो नये सरकारी कर्मचारी भर्ती होते हैं, उनकी सर्विस दो साल में कन्फर्म होती है। वे दो साल तो हमारे यहां नौकरी करते हैं। नौकरी की जगह तो हम देते हैं, ज्योंही दो साल पूरे होते हैं, वे अपने-अपने विधायकों को पकड़कर मंत्रियों पर दबाव डालकर सारे तबादले करवा लेते हैं। उन तबादलों से वही की वही यथास्थिति कायम है।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र शिव एक विशाल एवं रेगिस्तानी क्षेत्र है जो पाकिस्तान की सीमा से लगता है। 900 वर्ग किलोमीटर में यह विधान सभा क्षेत्र फैला है। राजस्थान का धौलपुर भी 300 वर्ग किलोमीटर में है। आप अन्दाज करें कि शिक्षा देने के लिए उस 900 वर्ग किलोमीटर में और 300

(श्री अमीन खां)

किलोमीटर में चार एमएलए की सीटें हैं। उनमें किस तरह से इंतजाम किया जायेगा। सरकार ने एक सर्कुलर निकाला है कि प्राइमरी स्कूल में 25 बच्चे रहेंगे तो वह स्कूल रहेगी और 25 से कम बच्चे होते ही वह स्कूल बन्द कर दी जायेगी। उस सन्दर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने 21 हजार स्कूलों को बन्द किया, जिनमें हमारी भी कई स्कूलें बन्द हुईं। इससे आप अन्दाज करो कि डेमोक्रेसी का अर्थ यह है कि जनता की भावना सुनो और जनता की भावना समझो। जहां 900 वर्ग किलोमीटर का एक विधान सभा क्षेत्र है और एक 150 वर्ग किलोमीटर का विधान सभा क्षेत्र है वहां तो आप 25 ही नहीं 50 पर भी पाबन्दी कर सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है पर हमारे वहां आबादी बहुत दूर-दूर बसी हुई है तो उस दूर बसी हुई आबादी में 20 बच्चों तक एक अध्यापक की अनुमति रहनी चाहिए, नहीं तो यह जो संविधान में नागरिक को फण्डामेंटल राइट दिया गया है वह राइट उसको नहीं मिलेगा और मिल भी नहीं रहा है।

आज की तारीख में शिव विधान सभा क्षेत्र में अध्यापकों के 800 पद खाली हैं। आज इससे अन्दाज करो कि अगर एक क्षेत्र में मास्टरों के 800 पद खाली हैं तो वहां पर गरीब बच्चों की क्या हालत होती होगी। ये जो प्राइवेट स्कूलें आजकल फैशन वाले चला रहे हैं बसों और गाड़ियों में, ये खुलेआम गरीबों का शोषण कर रहे हैं। सरकार की कमजोरी का फायदा लेकर ये लोगों को तबाह कर रहे हैं और प्रचार कर प्रचार के माध्यम से जगह-जगह अपनी स्कूलें चला रहे हैं तथा आगे जाकर इनका एक भी बच्चा सफल नहीं होने वाला है इसलिए इस पर सरकार को सख्त रवैया अपनाना चाहिए और इन प्राइवेटों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये गरीबों का शोषण करते हैं।

इसके साथ ही, मैं यह कहना चाहूंगा कि स्कूलों के लिए मुख्य मंत्री ने बजट की घोषणा की है, उसमें मैं तो यह समझता हूं कि इन्होंने कोई चीज बाकी नहीं छोड़ी तो किस चीज की शिकायत हम करें। इन्सान की जितनी भी डिमांड थी उसमें इस मुख्य मंत्री की छाती को, बहादुरी को मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने सबकी पूर्ति कर दी है। अब रहा वोट का सवाल तो वोट तो लोगों की मर्जी पर होता है, वे दें तो दें और नहीं दें तो मत दें, लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्री ने जनता को खुश रखने के लिए देने में कोई कमी और कसर नहीं रखी है और न किसी का पक्षपात किया है। पंचायत हैडक्वार्टर पर सीनियर सैकण्डरी स्कूल की, उसमें सभी पार्टियों के पंचायत हैडक्वार्टर आ गये। उसमें कोई यों तो है नहीं कि कांग्रेस पार्टी का ही हैडक्वार्टर आया हो।

(श्री अमीन खां)

यही बात कहते हुए, शिक्षा मंत्री जी, जो 11 रेगिस्तानी जिले हैं उनका विशेष रूप से सरकारी स्तर पर इंतजाम करो, नहीं तो ये पहले भी पिछड़े हुए रहे हैं और भविष्य में भी इनको पिछड़ा रखने की साजिश है।

वहां बाड़मेर में इनके आरएसएस के कोई आदमी आपके शिक्षा विभाग में काउंसलिंग करते हैं और वे काउंसलिंग में यह फैसला कराते हैं कि जहां अल्पसंख्यकों के बहुल एरिया की स्कूल है उसमें हमेशा मास्टर काटते हैं तो इस चीज की भी गवर्नमेंट को निगरानी रखनी चाहिए तथा इस पर सख्त इंतजाम करना चाहिए नहीं तो अल्पसंख्यक पहले ही कमजोर हैं और इससे और ज्यादा मायूस होते हैं। हम तो इसको सेक्युलर देश 31 अक्टूबर, 1984 के बाद मानते ही नहीं हैं। 31 अक्टूबर, 1984 के दिन इस सेक्युलर देश का खात्मा हो गया, हम तो वक्त गुजारते हैं। हिन्दू राष्ट्र भी हो जाएगा तो हमको कोई नहीं मारेगा, हिन्दू धर्म का हम अच्छी तरह से ज्ञान जानते हैं। हिन्दू भी दूसरे इन्सान की रक्षा करेगा, लेकिन यह धर्म निरपेक्ष सिर्फ कागजों में ही है। राजस्थान में हर स्कूल में आप एक सम्प्रदाय की पूजा से स्कूल का कार्यक्रम शुरू करते हो जो मजबूत धर्म निरपेक्ष देश का निशान नहीं है। लोग बोलते नहीं हैं तो डर से नहीं बोलते हैं पर जानते सभी हैं।

यही बात कहते हुए कहना चाहूंगा कि मंत्री जी, आप रेगिस्तानी जिले के हो और आपके जिले की हालत भी करीब-करीब हमारी जैसी ही होगी इसलिए आप रेगिस्तान में अध्यापकों के पदों को ज्यादा भरें तथा रेगिस्तानी जिलों में सुखाड़िया साहब ने जिस तरह से पाबन्दी लगायी थी, आप भी मंत्रिमण्डल की बैठक में वहां के कर्मचारियों को बदलने पर पाबन्दी लगायें। जय हिन्द।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री शंकर सिंह जी रावत।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 20, 21 और 22 पर बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, राजस्थान में आपने इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली हैं उनमें हमारे एक जवाजा की स्कूल भी है। स्कूल खोली वह तो अच्छी बात है कि बच्चों में इंग्लिश पढ़ी जाएगी, लेकिन, सभापति महोदय, जिस जगह पर स्कूल खोली उस स्कूल को या तो दो पारी में रखना चाहिए जिससे इंग्लिश पढ़ने वाली बच्चियां भी वहां पढ़ सकें और हिन्दी मीडियम में जो पढ़ रही थीं

(श्री शंकर सिंह रावत)

उनकी स्कूल भी नहीं छूटे। आज वहां पर सैकड़ों बच्चियों की स्कूल छूट चुकी है। यह मैं जवाजा की बता रहा हूं और इसी प्रकार राजस्थान में और कई जगह पर हुआ होगा। मैं चाह रहा हूं वे बच्चियां घर बैठी हैं नजदीक में कोई स्कूल नहीं है, 22 किलोमीटर तक उनकी कोई स्कूल नहीं है और लड़कियां अकेली नहीं जा सकती हैं इसलिए या तो दो पारी में स्कूल चलानी थी या नई बिल्डिंग बनाकर इंग्लिश मीडियम खोलते तो अच्छा रहता। इसमें मेरा सुझाव है कि जहां पर भी ऐसे हो तो या तो दो पारी में चलायी जाये ताकि उनमें एडजस्ट हो सके।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि शिक्षा का मन्दिर, विद्या मन्दिर एक तरह से मन्दिर का ही रूप है जिसमें उसी विद्यालय में पढ़ा हुआ आदमी बहुत ऊंचाई तक जाता है। माननीय मंत्री महोदय, यह ध्यान देने योग्य चीज है कि अगर उनकी हालत आज देखी जाये तो उसमें चाहे प्राइमरी स्कूल हो, मिडल स्कूल हो, सैकण्डरी हो, सीनियर सैकण्डरी स्कूल हो, उनकी बिल्डिंग जब से बनी है तब से आज तक वैसी की वैसी है और उसको अपन ने जाकर देखा तक नहीं है इसलिए उनके सुधार की आवश्यकता है। किसी में छत टपक रही है, किसी में प्लास्टर टूट रहा है, जाले जमे हुए हैं और टीचर आकर अपनी ड्यूटी देकर वापस चले जाते हैं। वहां पर बच्चे ही झाड़ू निकालते हैं। उनकी मरम्मत के लिए किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है इसलिए ऐसी कोई व्यवस्था करावें। चाहे विधायक कोष से या नरेगा के अन्दर भी ऐसी योजना लागू कर उनकी मरम्मत कराने की आवश्यकता है। नये भवन आप कितने भी बनाओ पर पुरानी बिल्डिंग भी खराब हो जाएगी तो निश्चित रूप से उसके मरम्मत की आवश्यकता है। विधायक कोष में भी आप स्कूलों की मरम्मत का प्रावधान लागू करायें। उसमें मरम्मत का नहीं है। नया भवन दे सकते हो, नये भवन का है लेकिन पुराने की मरम्मत कराने का ऐसा कोई उसमें लागू नहीं है। कलेक्टर उसके लिए कह देता है कि मरम्मत इसमें लागू नहीं है जबकि एक लाख रुपये में ही उस भवन का प्लास्टर टूटकर सही हो सकता है। अगर पंचायतों में या किसी डिपार्टमेंट को आप दोगे तो जिस प्रकार हैण्डपम्प लगाने के लिए गांव में कोई लगायेगा तो 50-60 हजार रुपये में नया हैण्डपम्प लग जायेगा पर गवर्नमेंट की तरफ से या और किसी कोष से अपना पीएचईडी को देंगे तो उसके सवा लाख रुपये लगेंगे, डेढ़ लाख रुपये लगेंगे। अब उसमें

(श्री शंकर सिंह रावत)

डिपार्टमेंट के बजाय आधे पैसे में काम हो जाता है। इसी प्रकार विधायक कोष में भी ऐसा प्रावधान किया जाये कि वह किसी डिपार्टमेंट को ठेके पर नहीं दे तथा गांव में काम करने वाले वहीं के लोग मजदूरी करते हैं और उन्हीं को बोलो कि आप अपना टेंडर दो तो 50 परसेंट पैसे में उस स्कूल की मरम्मत हो जाएगी। बजट भी उसमें आधा लगेगा, यह मेरा सुझाव है और निश्चित तौर पर अपने को उसमें करना चाहिए। जब तक विद्या के मन्दिर के ये भवन अच्छे नहीं बनेंगे तब तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं होने वाली है।

दूसरे लोगों ने काफी कुछ कह दिया है। स्कूलों में जितने पद खाली हैं आज पूरे राजस्थान में उच्च शिक्षा के अन्दर प्राचार्य के 292 पद स्वीकृत हैं और 84 कार्यरत हैं, वहां 208 पद खाली हैं। उप-प्राचार्य के 9 पद हैं और 9 स्वीकृत हैं। सहायक के 6 हजार 962 पद हैं और 4 हजार 195, तो 2 हजार 767 पद अभी भी खाली पड़े हैं। व्याख्याता बीएड के 47 पद स्वीकृत हैं, 15 कार्यरत हैं, 22 अभी भी खाली हैं। इसी प्रकार पूरे राजस्थान में देखा जाए तो 47 हजार पद अभी भी शिक्षा विभाग में खाली हैं। अगर आप नई भर्ती करेंगे तो भी आपके 16 हजार पद खाली रहेंगे। मेरा निवेदन है कि इसमें भी आप करें। इन बिल्डिंगों को, ये विद्या के मन्दिर हैं, इनको थोड़ा सही करायें। बच्चे घर से निकलकर जाते हैं तो नहा-धोकर जाते हैं, उनमें अन्दर जाने की हिम्मत नहीं होती। आप भी जाओगे तो बाहर से देखकर कहोगे, अच्छा, यह स्कूल है, लेकिन अन्दर जाकर के नहीं देख पायेंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि इनकी मरम्मत करवायें। बच्चे भी अच्छे से पढ़ेंगे और मास्टरों का भी दिल लगेगा।

मेरे ब्यावर में भी आपने कालेज दिया है, उसके लिए धन्यवाद है। उस कालेज का नाम क्योंकि वह एरिया सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय कन्या महाविद्यालय, ब्यावर के नाम से रखा जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी बोलेंगे तो निश्चित तौर पर इस बात का भी जिक्र करेंगे। मेरा आपसे ऐसा अनुरोध है।

स्कूल के मामले में, हमारी मिडल स्कूलें हैं, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, फतेहपुर (प्रथम), राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, स्वरूपां, रावली, सेदरिया, बाडिया, अज्बा, मालीपुरा, हाउसिंग बोर्ड, ब्यावर। ब्यावर के विद्यालय तो सिटी में हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में हैं, वे जंगली इलाकों में हैं। इन विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक में करने की बहुत आवश्यकता है। ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है।

(श्री शंकर सिंह रावत)

माननीय शिक्षा मंत्री जी, निश्चित तौर पर जब भी आप जवाब दें, इसमें दें। निश्चित तौर पर स्कूल की मरम्मत करने के कार्य का आप जरूर जिक्र करेंगे। ऐसा कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री राकेश पारीक।

श्री राकेश पारीक (मसूदा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 20, 21 और 22 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। शिक्षा, प्राथमिक से उच्च प्राथमिक और उच्च माध्यमिक शाला, तीन तो ये आते हैं कल्ला साहब के और राजेन्द्र यादव जी का महाविद्यालय, उच्च शिक्षा भी इसी में आता है। यह ऐसा विषय है।

हम धन्यवाद देंगे आदरणीय मुख्य मंत्री गहलोत साहब का, आदरणीय कल्ला साहब का और आदरणीय राजेन्द्र यादव साहब का कि हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है, गांवों के अन्दर खूब स्कूलें खोलीं। मेरे यहां राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने दो कालेज खोले। पायलट साहब का भी धन्यवाद ही है। चिन्ता मत करो, पायलट साहब कांग्रेस के ही नेता हैं, पायलट साहब का तो धन्यवाद ही है। वे ही हमें विधान सभा में लेकर आये हैं। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, उन्होंने कहा कि तुम मांगते-मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते-देते नहीं थकूंगा। (व्यवधान) आप देखिये, ये विपक्षी लोग ऐसे ही हैं। ये आरएसएस की मानसिकता के लोग हैं। ये कुछ भी बोल सकते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप चालू रखिये।

श्री राकेश पारीक (मसूदा): मैं सरकार को धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो राजकीय माध्यमिक विद्यालय खुले हैं, भिनाय में और मसूदा में। मेरी हर ग्राम पंचायत पर सीनियर सैकण्डरी स्कूल खुले हैं। मेरे यहां पांचवीं से आठवीं तक स्कूल हुई। मेरा इलाका मगरे का इलाका है। मेरे 15 पंचायतें ऐसी आती हैं, जिन ग्राम पंचायतों में आजादी से अब तक 23 शहीद हुए हैं। काठात कम्यूनिटी है, रावत कम्यूनिटी है, शंकर सिंह जी बोल रहे थे, इनके समाज के, ये भी मेहरात समाज से आते हैं तो उस इलाके में, आरदणीय मुख्य मंत्री महोदय, ऐसा क्राइटेरिया बनाया जाए, क्योंकि वहां बाड़ियों की शक्ल में छोटे-छोटे गांव हैं, जितनी भी मेरी मगरे की ग्राम पंचायतें हैं, उन ग्राम पंचायतों में आठवीं की जो स्कूलें हैं, आदरणीय कल्ला

(श्री राकेश पारीक)

साहब, थोड़ा कलम चलाओ और सारी उच्च प्राथमिक शालाओं को उच्च माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत किया जाए। मैंने आदरणीय कल्ला साहब को और सी एम साहब को बजट से पहले लिखकर दिया है। मेरे बाकी इलाके में 10 उच्च प्राथमिक शालाओं से उच्च माध्यमिक शाला की जाये। मेरे यहां पर उच्च प्राथमिक शालाएं हैं, उनको माध्यमिक और प्राथमिक शाला की जाये और बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर प्राइमरी खोलने की इच्छा है। सामने वाले तो बोलने की स्थिति में ही नहीं हैं, इन्होंने 22 हजार प्राथमिक स्कूलें बन्द की थीं, जो कांग्रेस के राज में खुली हुई थीं। ये तो यूं ही बोलते हैं और बोलते रहेंगे, लेकिन मैं, मंत्री महोदय, आपको टेबल करता हूं और सारी की सारी लिस्ट दूंगा।

मेरी इच्छा है, मेरा ग्रामीण इलाका है, केवल मात्र एक नगरपालिका है। मेरे यहां पर संस्कृत की उच्च प्राथमिक शाला एक भिनाय में है, जो पंचायत समिति हैडक्वार्टर है और एक दौतलपुरा (फर्स्ट) है, उसमें ग्राम पंचायत है। एक प्राथमिक शाला लक्ष्मीपुरा, ग्राम पंचायत कणीया कलां में है, उसको आप क्रमोन्नत कराने की व्यवस्था करायें। मेरे इलाके में 10-10 मांगी हैं और मगरा क्षेत्र की 15 पंचायतों में आप सबको क्रमोन्नत करेंगे, मुझे विश्वास है।

मैं एक बार पुन: सरकार का धन्यवाद देता हूं, शिक्षा मंत्री आदरणीय कल्ला साहब का धन्यवाद देता हूं कि ये बड़े अनुभवी हैं और हमारी इस पीड़ा को समझते हुए पूरी मजबूती से हमारा पक्ष रखकर हमारे इलाके को मदद करेंगे।

आप देखिये, यादव साहब, मेरे यहां पर तीन महाविद्यालय हैं। दो महाविद्यालय कांग्रेस की सत्ता में आदरणीय गहलोत साहब से हमने लिए भिनाय और विजयनगर में। आप देखेंगे, आपकी जो विद्या सम्बल योजना है, उससे आप शिक्षकों को लगायेंगे, लेक्चरर लगायेंगे, जिससे बच्चों का विकास हो सके।

मैंने तो यह कहकर लिया कि मेरे विजयनगर के अन्दर सरकारी कालेज नहीं था। गरीब बच्चों को 25 हजार रुपये फीस के देने पड़ते थे, आज बच्ची 700 रुपये में और लड़के 900 रुपये में पढ़ रहे हैं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं कि ऐसी सरकार जिसने लोगों की भलाई के लिए इतने काम किये हैं। आज, मंत्री महोदय, आप लिखें, पैन चलायें थोड़ा, मेरे इलाके के बच्चों को तो कालेज दे दी, लेकिन मेरे इलाके की बच्चियों के लिए एक भी कालेज, जब आपने दुनिया को दी है, मैं गहलोत साहब से और

(श्री राकेश पारीक)

आपसे मांग करूंगा कि हमारे बांदनवाड़ा में एक राजकीय बालिका महाविद्यालय खोला जाये।

मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सरकार का, करें तो कम है। मेरे इलाके में 28 करोड़ का एक देवनारायण आवासीय विद्यालय, मसूदा में कार्यरत है। मेरे यहां पर अल्पसंख्यक विभाग का छात्रावास, आवासीय स्कूल मसूदा में बन रहा है। एक अल्पसंख्यक छात्रावास मसूदा में खुला है और ज्योतिबा फुले बालिका एससी/एसटी की बालिकाओं के लिए छात्रावास नागौला में खुला है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि एक-दो छात्रावास और दिये जायें। मेरी इच्छा है कि ये जो कालेज खुले हैं तीनों और चौथा और खोलोगे, मुझे विश्वास है बांदनवाड़ा में खुल गया समझो। राजेन्द्र यादव साहब भी हंस रहे हैं, आदरणीय सभापति जी की भी इच्छा है और पूरे सदन की इच्छा है तो मेरे इन चारों कालेजों में चूंकि गांव का बच्चा घर से चल कर जब आता है पढ़ने के लिए तो उसकी जेब में अगर यह नरेगा नहीं चलता हो तो हमारे गांव का बच्चा स्कूल की किताब-कापी भी नहीं ला सकता। आपसे आग्रह है मेरा कि एक तो आप खोलेंगे, तीन मेरे खुले हुए हैं, इन चारों महाविद्यालयों में एक-एक बच्चों का छात्रावास भी स्थापित किया जाये जिससे मेरे बच्चे कांग्रेस की सरकार को दुआ देंगे। आप सब लोगों को दुआ देंगे। मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। राम-राम।

श्री सभापति: श्री ललित कुमार जी ओस्तवाल।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 20-प्रारम्भिक शिक्षा, मांग संख्या 21-माध्यमिक शिक्षा, मांग संख्या 22-उच्च शिक्षा पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका एवं मेरी पार्टी के नेताओं का बहुत-बहुत आभार। मैं सदन का ध्यान 22 और 23 तारीख के अख़बार की तरफ दिलाना चाहूंगा। 'सरकारी स्कूलों में बिना साइंस लैब के स्टूडेंट को दिखा रहे कलाम, कल्पना चावला बनने का ख्वाब। प्रैक्टिकल के लिए दूसरे स्कूलों में ले जाते हैं विद्यार्थियों को। उधार के शिक्षकों के सहारे बेहतर परिणाम की कवायद। इस साल अभी तक हुई सिर्फ 116 दिन पढ़ाई, कोर्स अधूरा।' आपने पेज नं. 11 क्रम संख्या 25, संस्कृत शिक्षा तथा संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन देने का लिखा, लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में मोरवण में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संस्कृत चल रहा है

(श्री ललित कुमार ओस्तवाल)

जिसमें छात्र संख्या 162 है और अध्यापक केवल एक है। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने की बात करते हैं लेकिन सच्चाई यह है कि दस विद्यार्थी उर्दू भाषा के पढ़ने वाले होते ही वहां पर संस्कृत को बन्द कर उर्दू भाषा विषय खोल दिया जाता है। मॉडर्न स्कूलों में प्रारम्भिक शिक्षा भवन बनकर तैयार हैं लेकिन उनमें प्रारम्भिक शिक्षा प्रारम्भ नहीं की जा रही है। मेरा निवेदन है कि वहां पर प्रारम्भिक शिक्षा अविलम्ब प्रारम्भ की जाये।

विद्यालय भवनों की स्थिति, वह भले ही प्राथमिक विद्यालय हो, उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक जो भी विद्यालय हो, लेकिन भवनों की स्थिति बहुत खराब है, बहुत दयनीय स्थिति है, जर्जर अवस्था में भवन हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि उन सभी भवनों का सरकारी स्तर पर सर्वे करा कर जहां रिपेयरिंग हो सकती है वहां रिपेयरिंग और नहीं हो सकती है तो उसको डेस्ट्रोय करके नया भवन बनाने की कृपा करें। जिन विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है वहां पर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जाये। जिन विद्यालयों में बालक-बालिकाओं को अलग-अलग शौचालय टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है वहां पर ये व्यवस्थाएं की जायें। जिन विद्यालयों में बिजली कनेक्शन नहीं है वहां पर बिजली कनेक्शन अविलम्ब कराया जाये। जिन विद्यालयों में फर्निचर की कमी है वहां पर फर्निचर की व्यवस्था करायी जाये। जिन विद्यालयों में छात्र संख्या तथा कक्षाओं के अनुपात में कक्षा कक्षों की कमी है वहां पर नये कक्षा कक्षों का निर्माण किया जाये और कई बार देखने में आता है, सुनने में आता है, पढ़ने में आता है, कोई भी अध्यापक अगर छात्राओं से छेड़-छाड़ करते हुए पाया जाता है तो उसका स्थानान्तरण काफी नहीं है, उसको नौकरी से हटा देना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, चित्तौड़ जिले में संचालित विद्यालयों में स्वीकृत पद एवं कार्यरत का एक हल्का-सा लेखा-जोखा मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। प्रधानाचार्य स्वीकृत पद 423, कार्यरत 199, रिक्त पद 224; उप प्रधानाचार्य स्वीकृत पद 332, कार्यरत 24, रिक्त 308; व्याख्याता 1517, कार्यरत 935, रिक्त 582; वरिष्ठ अध्यापक 1964, कार्यरत 1148, रिक्त 816; अध्यापक लेवल-1 स्वीकृत 1100, कार्यरत 903, रिक्त 197; लेवल-2 स्वीकृत 1224, कार्यरत 1024, रिक्त 210; धमोतर उपखण्ड है मेरे विधान सभा क्षेत्र में सीनियर सैकण्डरी बालिका विद्यालय, धमोतर, स्वीकृत पद 11,

(श्री ललित कुमार ओस्तवाल)

कार्यरत 2, बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय बाराबरदा स्वीकृत पद 11, कार्यरत 3, सीनियर सैकण्डरी स्कूल बाराबरदा स्वीकृत पद 26, कार्यरत 14, सीनियर सैकण्डरी स्कूल बरडिया स्वीकृत 22, कार्यरत 12, सीनियर सैकण्डरी स्कूल गमेत, स्वीकृत पद 5, कार्यरत शून्य, सीनियर सैकण्डरी स्कूल जोलर स्वीकृत पद 18, कार्यरत 7, सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोरिया स्वीकृत पद 16, कार्यरत 8, सीनियर सैकण्डरी स्कूल कोतवाल स्वीकृत पद 13, कार्यरत 6, सीनियर सैकण्डरी स्कूल नकोर, स्वीकृत पद 21, कार्यरत 9, सीनियर सैकण्डरी स्कूल पाल स्वीकृत पद 16, कार्यरत 6, सीनियर सैकण्डरी स्कूल टीला, स्वीकृत पद 5, कार्यरत शून्य, सीनियर सैकण्डरी स्कूल सरीपीपली स्वीकृत पद 18, कार्यरत 7. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय माण्डकलां स्वीकृत पद 10, कार्यरत 4, राजकीय प्राथमिक विद्यालय आंतर स्वीकृत पद 2, कार्यरत शून्य। डुंगलाखंड राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थिति प्रधानाचार्य के स्वीकृत पद हैं 36, कार्यरत हैं 11, रिक्त हैं 25; उप प्रधानाचार्य स्वीकृत पद 28, कार्यरत शून्य, रिक्त हैं 28 के 28; व्याख्याता 118, कार्यरत 54, रिक्त पद हैं 64 और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थिति वरिष्ठ अध्यापक 30 पद स्वीकृत हैं उनमें कार्यरत हैं 6. राजकीय महाविद्यालय मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक है बड़ी सादड़ी में, वहां पर एक भी स्थायी कर्मचारी नहीं है, केवल विद्या सम्बल वाले ही चला रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बहुत कम विद्यालयों में कार्यरत हैं। मेरा निवेदन है कि अध्यापकों के साथ-साथ सभी विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भी भर्ती की जाये ताकि विद्यालय में सफाई की और पेयजल की व्यवस्था सुचारु रूप से हो सके।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगें रखना चाहूंगा। अभी मैं विपक्षी दलों का और सहयोगी दलों का भाषण सुन रहा था तो वो सभी कह रहे थे जब शुरू में उनका टोन होता है तो पांच मिनट शुरू-शुरू में जब वो बोलते हैं कि हमको बहुत दिया, दिल खोल कर दिया, छप्पर फाड़ कर दिया और अगले पांच मिनट में जब वो बोलते हैं न कि मेरे यहां यह क्रमोन्नत करना, यह विद्यालय खोलना, तो इसका मतलब वहां भी कार्य बाकी हैं। मेरी डूंगला तहसील, तहसील मुख्यालय है, उपखण्ड मुख्यालय है, पंचायत समिति मुख्यालय है, बोहेड़ा चित्तौड़गढ़ जिले का सबसे बड़ा गांव है। चार उच्च माध्यमिक विद्यालय उस गांव में संचालित हैं। देवगढ़ और बाराबरदा टीएसपी क्षेत्र में है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्यगण, सुनिये प्लीज। हां, बोलिये आप।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): इन चारों स्थानों पर राजकीय महाविद्यालय खोला जाये और भूरकिया डूंगला, टांडा, बरखेड़ा, लाम्बी चोटी, नालवा, माण्डकलां, फाचर, मरावदिया यहां पर उच्च प्राथमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में इनको क्रमोन्नत किया जाये। बाराबरदा, मंगलवाड़, चिकारड़ा राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाये। गुमानपुरा, फलासिया, आफरातलाव, कटई, गुजरपनवा, रणा, आजमपुरा, भीलाखेड़ा, (मोरवड़न) लक्ष्मीपुरा, (इडरा) छाजवी, पालखेड़ी, नंगाखेड़ा, जल खेड़ी, रोड़जी का खेड़ा, जाड़ सादड़ी, प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाये। थोलीमंगरी, नांगेड़ी, भीखाखेड़ा, डकलई में नये प्राथमिक विद्यालय खोले जायें। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निकुम में विज्ञान राजकीय, उच्च माध्यमिक विद्यालय बिलोट में विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भाणूजा में गणित, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेरमालिया में कृषि, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जरखाणा में कृषि, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नकोर में कला विषय खोले जायें।

कई विद्यालयों के नाम जमीन दर्ज है। खेल मैदान के नाम पर दर्ज है पर वहां पर उनका अतिक्रमण है, तो उस अतिक्रमण को तुरन्त हटाया जाये। शिक्षकों को शिक्षक कार्य के अलावा जो भी कार्य दिये जा रहे हैं उनको बन्द किया जाये, उनके लिए केवल शिक्षण कार्य किया जाये। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पैंसठ वर्ष की आयु में 5 प्रतिशत, 70 वर्ष की आयु में 10 प्रतिशत, 75 वर्ष की आयु में 15 प्रतिशत, 80 वर्ष की उम्र में अभी जो लागू है 20 प्रतिशत उसे यथावत रखा जाये। सीनियर विद्यालयों में अभी पंचायती राज संस्थाएं...

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् विकास का कोई कार्य नहीं कर सकती है, इसको अनुमत किया जाये कि ये पंचायती राज संस्थाएं भी इन विद्यालयों में काम कर सकें। पंचायत सहायकों को विद्यालय सहायक घोषित कर दिया है, उनका मानदेय अब सरकार देगी। पूर्व में मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी इनको 21,400 रुपये मानदेय देंगे, लेकिन नहीं दिये जा रहे हैं तथा इनमें जो

(श्री ललित कुमार ओस्तवाल)

ओवरएज हो गये उनको वापस नहीं लिया गया है। इन्हें वापस नौकरी पर लिया जाये तथा इनका कार्यकाल जब से नाम बदला है दिसम्बर, 2021 से गिना जायेगा जबकि ये पिछले काफी वर्षों से कार्य कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इन्हें मानदेय 21,400 रुपये दिये जायें तथा कार्यकाल पहले से जब से कार्य कर रहे थे तब से गिना जाये। बालिका विद्यालय में एक मेरा निवेदन है बालिका विद्यालय में कोई भी पुरुष अध्यापक नहीं लगाया जाये, वहां पर पूरा स्टाफ महिला कर्मचारी ही हो।

माननीय सभापति महोदय, यहां पर प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी पर टिप्पणी की गई। उन प्रधान मंत्री पर जो आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उन पर टिप्पणी की गई। उन प्रधान मंत्री पर जिन्होंने सिर्फ एक फोन रूस के राष्ट्रपति जी को किया और एक यूक्रेन के राष्ट्रपति जी को किया और दोनों देश कुछ समय के लिए युद्ध विराम के लिए तैयार हुए और वहां पर जो अपने भारत के 20 हजार बच्चे फंसे हुए थे, वह सब राज़ी खुशी अपने देश लौट कर आये। जिन्होंने अभी बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना में 66 परसेंट की बढ़ोतरी की, 79 हजार करोड़ रुपया ज्यादा प्रधानमंत्री आवास में स्वीकृत किया, उन प्रधान मंत्री पर टिप्पणी की। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि इन मांगों को पूरा किया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय भारत, जय राजस्थान, जय चित्तौड़, जय बड़ी सादड़ी।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र सिंह बिधुरी।

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, बीच में मत बोलो, मैं आपकी बुराई भी नहीं करूंगा, आपकी चमचागीरी भी नहीं करूंगा। हिन्दुस्तान का इतिहास और जो आज हम पढ़ रहे हैं, उसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यह सदन हम सबका है, यह कांग्रेस-बीजेपी का नहीं, हम सदन के सदस्य हैं।

सभापति महोदय, मांग संख्या-20, 21 और 22 पर मुझे समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आज जिस शिक्षा पद्धति पर हम मंथन कर रहे हैं, यह शिक्षा पद्धति लार्ड मैकाले की हिन्दुस्तान के गुलामों पर लागू करने की थी। 1857 के विद्रोह के बाद जब हर हिन्दुस्तानी ने, हिन्दू, मुसलमान, जाट, गुर्जर, अहीर, राजपूत, बनिया, बामन सब जाति छोड़ कर दलित, अगड़ा, पिछड़ा, सबने हिन्दुस्तान में विद्रोह किया और जब ईस्ट इंडिया कंपनी से

(श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह)

विक्टोरिया रानी ने हिन्दुस्तान को सीधा अपने अंदर कर लिया तो पूरे भारत का भ्रमण करवाया गया कि हिन्दुस्तान के लोग एक कैसे हो गये, एक होकर कैसे लड़ गये? एक बूढ़े बादशाह बहादुर शाह जफर को कैसे हिन्दुस्तान का राजा बना दिया? पूरे हिन्दुस्तान में वह घूमे और घूमने के बाद जब वह गांव में दौरा मारने के लिए गये तो अपने आप वहां ऐसा ताना-बाना था कि गांव की बेटी, चाहे दलित की, चाहे पिछड़े की, चाहे अगड़े की, चाहे किसान की, वह पूरे गांव की होती थी। उनको ऐसी शिक्षा दो कि वह हमारे सेवक बनकर रहें या हमारे क्लर्क बनकर रहें और आज हम लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को पढ़ रहे हैं।

सभापति महोदय, मनुष्य की सबसे पहली शिक्षक मां होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो मां उसे बोलना सिखाती है, मां उसे खेलना सिखाती है, मां उसे खाना सिखाती है। शिक्षा का मतलब है सीखना, शिक्षित होना है। छत्रपति शिवाजी की माताजी जीजा बाई ने महाराज शिवाजी को शिक्षित करके छत्रपति बना दिया, सभी क्षत्रियों का पति। गुरु गोविंदसिंह जी की माता जी गुजरी ने जब गुरु तेगबहादुर जी ने कुर्बानी दी, उसके बाद महान गुरु गोविंदसिंह महाराज को शिक्षित करके माता गुजरी ने, गुरु गोविंदसिंह महाराज की वह कहावत सिद्ध कराई 'सवा लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊं, तबै गुरु गोबिंदसिंह नाम कहाऊं।'

हमारी सबसे पहली शिक्षक मां है। हमारी मां हमें पढ़ना-लिखना, खेलना-कूदना, चलना-फिरना सिखाती है, हम उससे सीखते हैं। भारत एक ऐसा देश है कि हमारे यहां महान क्रांतिकारी भी स्कूल के शिक्षक हुए हैं। उन्होंने बाहर से शिक्षा लेकर भी देश की आजादी के लिए काम किया है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमको संविधान दिया। बाबा साहब ने कहा है कि दलितों, पिछड़ों, अगड़ों, हिन्दुस्तानियों, अगर दूध पीना है तो शिक्षा रूपी शेरनी का पीओ। जब आप शिक्षित बनोगे, संगठित बनोगे, देश की तरक्की करोगे, मिलजुल कर रहोगे तो आगे बढ़ोगे। बाबा साहब अंबेडकर जी ने शिक्षा के रूप में शेरनी का दूध पीने की बात कही। आज हमारे बीच में दलित, पिछड़े, अगड़े, बैकवर्ड क्लास के लोग, गरीब लोग कितने आईएएस, आईपीएस आफिसर हैं। हमें शिक्षा का स्तर सुधारना पड़ेगा। स्कूलों में शिक्षा मूल बेस है। शिक्षित हिन्दुस्तान में जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसके मां-बाप हमारे शिक्षक होते हैं।

(श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह)

चौधरी बंसीलाल जी का मुझे एक वाकया याद है, मैंने किताब में पढ़ा था। जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था, 1969 में वह पहले मुख्य मंत्री बने थे। वहां स्कूल में टीचर बच्चों को पढ़ाते नहीं थे, रोज हड़ताल होती थी, सड़क के मोड़ होते थे। हरियाणा के मुख्य मंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी ने शिक्षक की मरोड़ निकाली। कोई भी शिक्षक बीड़ी पीकर नहीं आता था और सड़क के मोड़ निकाले। हरियाणा में प्राइमरी स्कूल से लेकर और उच्च शिक्षा तक के किसी विद्यालय को कच्चा नहीं छोड़ा। उन्होंने बेसिक काम शिक्षा पर किया। हमको भी सोचना पड़ेगा कि प्राइमरी स्कूल बच्चे की नींव होती है।

हमारे हिन्दुस्तान में डबल एजुकेशन है। बड़े-बड़े उद्योगपतियों के, बड़े-बड़े नेताओं के, बड़े-बड़े अधिकारियों के बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं और किसानों के, गरीबों के, दलितों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हमें सरकारी स्कूलों को पब्लिक स्कूलों के बराबर सुविधाएं देनी पडेंगी। हमें पहले एक अंगुली अपनी तरफ करनी पड़ेगी, अपने नेताओं के, अपने अधिकारियों के बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। हमारे बच्चों की पहली च्वाइस पब्लिक स्कूल की है और गरीबों के बच्चों की पहली च्वाइस सरकारी स्कूलों की है। हिन्दुस्तान ऐसा देश है जहां ड्वेल एजुकेशन है। अमीर के लिए शिक्षा बिकती है और गरीब बिना शिक्षा के रह जाता है। हमारी मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इसी बात को सोच कर कि पूरा हिन्दुस्तान शिक्षित बने, हमें राइट टू एजुकेशन दिया और हिन्दुस्तान के हर नागरिक को अपने बच्चों को पढ़ाने का अधिकार दिया। हमें इस ड्वेल एजुकेशन सिस्टम को खतम करना पड़ेगा। शिक्षा को व्यापार बनाना बंद करना पड़ेगा। हमें यह सोचना पड़ेगा कि जो हमारे विद्यालय हैं, जो हमारे कालेजेज हैं, उनमें हिन्दुस्तान के नागरिक का बच्चा फ्री एजुकेशन ले, उनमें कोई भेद नहीं हो। राजा और रंक का बेटा, जैसे भगवान श्रीकृष्ण और सुदामा एक ही स्कूल में पढ़ते थे, गरीब ब्राहमण का बेटा और राजा का बेटा एक ही स्कूल में पढ़ते थे। हमें इस शिक्षा पद्धति को खतम करना पड़ेगा। हमारे बीच जो दलित, पिछड़ों, अगड़ों का गैप है, आदिवासियों के गांवों में स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, शिक्षक नहीं हैं, हमें उनमें सुधार करना पड़ेगा। हिन्दुस्तान की 75 साल की आजादी के बाद जो हमारे शहीदों ने सपना देखा था कि हम ऐसा सशक्त भारत बनायेंगे, ऐसा शिक्षित भारत बनायेंगे, ऐसा भारत बनायेंगे कि अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, पोलेंड, हालेंड,

(श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह)

जर्मनी, फ्रांस, जापान, सबको हिन्दुस्तान पीछे छोड़ देगा। यह उम्मीदें मुझे खरी होती नजर नहीं आ रही हैं। बाबा साहब अंबेडकर का सपना पूरा नहीं हो पा रहा। दलित के बेटे को अच्छी एजुकेशन देने के लिए सरकार ने बहुत-सी योजनाएं बनाई हैं लेकिन सरकार की योजनाएं कागजों पर रह जाती हैं। हमें सख्ती दिखानी पड़ेगी, हमें चौधरी बंसीलाल की तरह सख्त होना पड़ेगा।

मैं एक वाकया याद दिलाता हूं। हम माननीय मुख्य मंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र जी के साथ शिमला से सोलन की तरफ जा रहे थे, मैं उनकी गाड़ी में बैठा हुआ था। मेरे बायें तरफ के कुछ अधिकारी नाराज हो सकते हैं, उन्होंने एक गाड़ी पर एक झंडी देखी। गाड़ी स्कूल के बाहर खड़ी हुई थी, डी सी की गाड़ी थी। डी सी के बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए एक गाड़ी खड़ी हुई थी। राजा साहब ने गाड़ी रोकी और बोला कि यह गाड़ी किसकी है? कहा कि डी सी साहब की। डी सी साहब तो मुझे पीछे एयरपोर्ट पर लेने आ रहे हैं, उनको हेलिकाप्टर से आना था, मौसम खराब हो गया इसलिए बाई रोड निकल गये थे। आप यह सोच सकते हैं कि डी सी की गाड़ी उनके बच्चों को स्कूल से लेने-छोड़ने जाती थी। उसी वक्त उस डी सी को सस्पेंड किया। अपनी आत्मा पर हाथ रख कर देखिए कितनी गाड़ियां पब्लिक स्कूलों के बाहर इन अधिकारियों की गाड़ियां इनके बच्चों को छोड़ने और लेने में लगी रहती हैं और राष्ट्र का पैसा वेस्टेज करते हैं। इनको तुरन्त प्रभाव से, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, इनको बन्द करना चाहिए।

एमएलएज को फ्लैट मिलते हैं, अधिकारियों को बड़ी-बड़ी कोठियां, इनको भी एक बस में लाया जाये, जैसे जापान एवं जर्मनी में अधिकारियों को बस में लाया जाता है। इनको भी फ्लैटों में रखा जाना चाहिए। इनको बड़ी-बड़ी कोठियां क्यों दी जाती हैं? ये शिक्षा में अपने आपको सबसे ऊपर समझते हैं। जनता हमको चुनती है कि आप इनको कंट्रोल कीजिये। चाहे शिक्षा विभाग हो, जहां पर भी जाकर देखेंगे। डायरेक्टर है, वह जाता है तो स्कूल में टीचर नहीं है, स्कूल में लैब नहीं है, स्कूल में पढ़ाने का टाइम नहीं है। कई जगह तो जी.एल. चलती है। जी एल का मतलब समझते हैं? सभापति महोदय, मैं आपसे निवदेन करना चाहता हूं कि जी एल का मतलब है, गोता लीव। बिना बताये गोता लीव मार जाते हैं। स्कूल से शिक्षक गायब हो जाता है। तनख्वाह उठा ली जाती है, बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं।

(श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह)

स्कूलों में माननीय मुख्य मंत्री जी ने दसवीं से बारहवीं तक के स्कूल किये, मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री की सोच हर गरीब के बच्चे को पंचायत के स्तर पर शिक्षा देने की है। हम भी जब गांवों में रहते थे, 20-20 किलोमीटर दूर स्कूल में पढ़ने जाते थे। आज राजस्थान में इसी बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने हर पंचायत के स्कूल को क्रमोन्नत करके 12वीं तक का स्कूल कर दिया है। स्कूल के अन्दर, जहां पर हमारी शिक्षा का स्तर है, जहां पर हमारे टीचर नहीं हैं, वहां पर टीचर भरे जाने चाहिए।

हमने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोल दिये हैं। गांवों के अन्दर भी बच्चों को शहर के बच्चों की तरह अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा मिलती है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने गांवों के स्कूलों के अन्दर, दलित एवं पिछड़े इलाकों के अन्दर ही महात्मा गांधी स्कूल खोलकर दलितों, पिछड़ो, गरीबों के बच्चों का ख्याल रखा। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो महात्मा गांधी स्कूल की योजना चलायी है, उसका हमें बहुत फायदा मिला है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने गरीब बच्चों को साल में दो बार वर्दी देने के इस अभियान में, जिसमें दो बार वर्दी फ्री मिलती है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री की सोच एक गरीब से गरीब और पिछड़े इलाके के, राजस्थान के हर बच्चे को दो बार दूध मिले, साल में दो बार वर्दी मिले और किताबें फ्री मिलें। 12वीं एवं कालेज तक की शिक्षा को फ्री करने का जो आह्वान किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि भारत के अन्दर, राजस्थान के अन्दर पूरा हिन्दुस्तान शिक्षित बने। राजस्थान में कोई भी बच्चा स्कूल में जाये बगैर नहीं रहे। इस सोच को लेते हुए हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री ने राजस्थान की जनता के लिए और राजस्थान के बच्चों के लिए जो तोहफा दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय, हमारे साथी कह रहे थे। प्रधान मंत्री सबके माननीय होते हैं, हमारे भी होते हैं। पूरे देश के प्रधान मंत्री हैं, वे कांग्रेस-बीजेपी के प्रधान मंत्री नहीं हैं। नरेन्द्र मोदी भारत के प्रधान मंत्री है। नरेन्द्र मोदी हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री हैं। जो अच्छा काम करते हैं तो हम उनकी कोई बुराई नहीं करेंगे। उनका काम इस देश को चलाना है और देश को मजबूत करना। देश की जनता फैसला करेगी कि किसको चुनना है और किसको नहीं चुनना है। हमारी प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी जी ने, जब 1971 में पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया

(श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह)

था, अपनी फौज को बांग्लादेश में भेजा था तो इंग्लैंड ने कहा था कि भारत आक्रमणकारी है। इन्दिरा गांधी ने कहा था कि बड़े देश हमें धमकाने की कोशिश नहीं करें, आदेश देने का दुस्साहस नहीं करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, शिक्षा पर केंद्रित सारा भाषण है। इसलिए इनको और समय दें। मैं मांग कर रहा हूं कि आप और बोलें। आप अच्छा बोल रहे हैं।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपका समय भी इनको दे देंगे।

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): इन्दिरा जी ने कहा था कि बड़े देश आदेश देने का दुस्साहस नहीं करें। हर प्रधान मंत्री की ड्यूटी होती है अपने देश की रक्षा करना, अपने देश के 140 करोड़ लोगों की तरक्की, शिक्षा, एजुकेशन और भारत को पूरी दुनिया में मजबूत करना। कोई भी प्रधान मंत्री हो, हर मुख्य मंत्री की ड्यूटी होती है कि वह जब भी मुख्य मंत्री है, हरेक की, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, अपने राज्य की जनता की सेवा करना, अपने राज्य की जनता के लिए अच्छी योजनाएं लाना, अपने राज्य का विकास करना, सड़कों का जाल बिछाना। राज्य के हर नागरिक को शिक्षित करना और राज्य की तरक्की करना, हर मुख्य मंत्री का सपना होता है। चाहे आपके मुख्य मंत्री रहे हों, चाहे आज हमारे मुख्य मंत्री हैं। इसी सोच के हिसाब से हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री ने हर वर्ग का ख्याल रखकर शिक्षा के बजट को दुगुना किया जो शिक्षा का बजट आधा था। आपने तो केन्द्र में शिक्षा का बजट आधा किया है, हमने दुगुना किया है। हमने शिक्षा में छात्रवृत्ति भी बढ़ायी। हमने आवासीय विद्यालय खोले। हमने स्कूलों की बिल्डिंग के लिए पांच सौ करोड़ रुपये दिये। मैंने पहले भी बताया कि हमने वर्दियां फ्री दीं। हमने पांचवीं-आठवीं तक के बच्चों को दूध फ्री दिया। हम सब मिल-जुलकर काम करें, क्योंकि देश हम सब का है।

मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी बड़े नेता थे, सरदार पटेल हो, विट्ठल भाई पटेल हो, अशफाक उल्ला खां हो, हमने शिक्षा के स्तर, जब हिन्दुस्तान में शिक्षा नहीं होती थी तो इंग्लैंड पढ़ने जाते थे और पढ़कर देश भक्ति की भावना लेकर आते थे। हमारे कई क्रान्तिकारी शिक्षक रहे हैं। शिक्षा पद्धति में कई क्रान्तिकारी, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल हो, चन्द्र शेखर आजाद हों, उधम सिंह हों, सब लोगों ने शिक्षित होकर देश में आजादी की

(श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह)

अलख जगायी और हमें शहीदों की कुर्बानी के बाद आजाद भारत दिया। डीएवी की स्थापना की। डीएवी का मलतब होता है, दयानन्द एंग्लो वैदिक विद्यालय। अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती थी तो हमारे बच्चे पीछे रह जाते थे। डीएवी कालेज में पढ़कर भगतसिंह इतना बड़ा क्रान्तिकारी बना। हमारे स्कूलों के अन्दर पेट्रियोटिक एजुकेशन सिस्टम का बोलबाला होना चाहिए। हमारे स्कूलों के नाम, कालेजों के नाम शहीदों और महान नेताओं के नाम पर होने चाहिए। सरदार पटेल के नाम पर होने चाहिए, अब्दुल कलाम आजाद के नाम पर होने चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होने चाहिए, इन्दिरा गांधी के नाम पर होने चाहिए, राजीव गांधी के नाम पर होने चाहिए, जिससे बच्चों के अन्दर ऐसी भावना आ सके, जिस स्कूल के अन्दर पढ़ने जा रहे हैं, वह देश भक्ति के लिए। जब हम पढ़ते थे तो हमारी क्लास के नाम नेताजी सुभाष चन्द्र बोस रूम, भगतसिंह, बाबा साहब अम्बेडकर, उधम सिंह तो बच्चों के अन्दर एक भावना आती है कि इन लोगों ने हमारे देश के लिए काम किया है। 5वीं क्लास का बच्चा, जो क्लास के अन्दर शहीदों का फोटो देखता है, देश पर जान देने वाले फौजियों का।

मैं सच्चा वाकया बताना चाहता हूं तो अपने आप देश भक्ति की भावना जागती है। हमें किताबों में पाठ्यक्रम लागू करने चाहिए। हमें कृष्ण भगवान के शब्द लागू करने चाहिए। हमें यह बताना चाहिए। हमें रामायण के, हमें कर्ण की वीरता, हमें ऐसे वीरों की, पृथ्वीराज, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का। बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में कि ऐसे दलित समाज के व्यक्ति ने भूखा व गरीब रहकर बाहर पढ़कर हमको देश चलाने के लिए संविधान दिया है। हमें स्कूलों के अन्दर रानी झांसी, माता जीजाबाई, माता गूजरी, मृगनयनी, पन्ना धाय, मीरा, ऐसे इतिहास के सब्जेक्ट, उनके पाठ्यक्रम की जीवनी पढ़ानी चाहिए, जिससे बच्चों में देशभक्ति की भावना जागे। जब तक हम देश भक्त नहीं बनेंगे, हम हिन्दुस्तान को सदियों तक सुरक्षित नहीं रख सकते। हर हिन्दुस्तानी को, कांग्रेस-बीजेपी छोड़ दो, हिन्दुस्तानी बनो, भारतीय बनो।

मैं जापान का एक वाकया आपको याद दिलाता हूं। मेरा एक्सपोर्ट का कुछ काम था। जापान के ट्रेडर्स आये तो उन्होंने हमारे पड़ोस में स्कूल विजिट किया। उस स्कूल के अन्दर देश या किसी का भी फोटो नहीं लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि जापान के हर स्कूल के अन्दर उस स्कूल से जो बच्चे पढ़कर

(श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह)

जाते हैं... माननीय सदस्य आप सुनिये, जापान में क्या होता है। जिस स्कूल से जो बच्चा पढ़कर जाता है और देश के लिए जान देता है या देश के लिए कुछ करता है, उसकी क्लास में, उसकी स्कूल में उसका फोटो लगा होता है तो बच्चे के अन्दर पेट्रिओटिज्म आता है, देश भक्ति आती है कि मैं भी अपने देश के लिए वह काम करूंगा, जैसे मेरी क्लास में जिसका फोटो लगा होता है, उसने देश के लिए काम किया है। हमें देश की एजुकेशन को पेट्रियोटिक एजुकेशन बनाना पड़ेगा। हमें शहीदों की, अपने महापुरुषों की, अपने देश के लिए कुर्बानी देने वालों की जीवनियों को पाठ्यक्रम में शामिल करना पड़ेगा। हमें हिन्दू-मुसलमान में शहीद और वीरों को नहीं तोलना है। हर शहीद, हर जाति-पांति पर देश नहीं होता है। देश हम सबका है। अगर हम अच्छी शिक्षा देंगे, देश भक्ति की शिक्षा देंगे तो जातिवाद अपने आप खतम होगा। हम अगर जाति में हिन्दुस्तान को बांटेंगे तो इतनी जातियां इस देश में रहती हैं, हिन्दुस्तान के इतने टुकड़े हो जाएंगे, आज तो आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक अकेले पूरे भारत में घूमते हैं, जर्मनी से छोटा हमारा देश हो जायेगा, यूरोप से छोटा।

(समय: 18.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के स्कूलों के अन्दर इतने पद खाली हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि जितने हमारे स्कूल के अन्दर टीचर्स नहीं हैं, उनको कृपा करके भरा जाये। यह बहुत जरूरी है। सारा इलाका हमारा खाली पड़ा है और उन शिक्षकों को दूसरी जगह पर लगा दिया जाता है।

श्री सभापति: थैंक यू।

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): आप शिक्षकों को भरें। जब स्कूल में शिक्षक ही नहीं होंगे तो उन बच्चों को कौन पढ़ायेगा? यह दलितों का, पिछड़ों का इलाका है, अमीरों के बच्चे तो पैसा देकर पढ़ लेंगे लेकिन दलितों, पिछड़ों के बच्चे कैसे पैसा देकर पढ़ेंगे? दलितों के, पिछड़ों के, बैकवर्ड के गांवों के इलाकों में स्कूल नहीं है। उनके अन्दर शिक्षक नहीं हैं।

हमने अंग्रेजी माध्यम स्कूल तो खोल दिये हैं लेकिन, माननीय मंत्री महोदय, जो हमारे स्कूल खुले हैं उनमें आप अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की जल्दी से भर्ती करिये।

(श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं अपने, जो भी मेरे स्कूल खाली पड़े हैं, इन सबको मैं टेबल करता हूं। जय हिन्द, जय भारत। धन्यवाद।

(माननीय सदस्य श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं) के सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-05 देखें)

श्री सभापति: ठीक है। श्री हमीर सिंह भायल।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 20, 21 एवं 22 पर बोलने के लिए मुझे अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा में नवाचार समय-समय पर जो भी सरकार रही है, उसने करने की कोशिश की है। इस राजस्थान में बिना भेदभाव अगर शिक्षा में नवाचार किया है तो वह स्वर्गीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने किया है। उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने गांव ढाणी तक, एक-एक पंचायत हैडक्वार्टर तक पांचवीं से आठवीं सबसे पहले बिना भेदभाव जो पहल की थी, उससे शिक्षा में राजस्थान ने पूर्व-पश्चिम एवं उत्तर-दक्षिण प्रगति की है। 2003 से 2008 तक जब आदरणीय वसुन्धराजी मुख्य मंत्री बनीं तो उन्होंने आठवीं से दसवीं करने में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी विराज रहे हैं। 2013 से 2018 तक सैकण्डरी से सीनियर सैकण्डरी करने में हर पंचायत हैडक्वार्टर पर करने की कोशिश की। मैं यह नहीं कहूंगा कि वर्तमान सरकार ने नवाचार नहीं किये हैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने नवाचार जरूर किये हैं, आप अभी भी, जैसे सिवाना बाड़मेर जिले के अन्दर भाजपा का विधायक मैं सिवाना में हूं तो मेरे यहां जो क्रमोन्नत स्कूलें होनी चाहिए प्राइमरी से उच्च प्राथमिक, सैकण्डरी से सीनियर सैकण्डरी, उसमें कमी झलकती है और यह नवाचार हर सरकार करती है और शिक्षा के बिना प्रदेश उन्नति नहीं करेगा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा परन्तु जब आपने स्कूलें क्रमोन्नत कर दीं, खोल दीं, अब जहां पर 22 का स्टाफ है वहां एक या दो स्टाफ लगा हुआ है और पांच सौ बच्चे हैं तो उनका क्या होगा? इसकी तरफ भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है।

अब अपना स्कूलें खोलकर क्रमोन्नत करके, कालेज खोलकर धन्यवाद अर्जित करते हैं पर उन कालेज का क्या होगा, जहां पद खाली हैं? मेरे विधान

(श्री हमीर सिंह भायल)

सभा क्षेत्र में तीन कालेज हैं और एक चौथी बन रही है। गुढ़ामालानी से लगाकर बालोतरा तक एक भी प्रोफेसर, एक भी अध्यापक/लेक्चरर स्थायी नहीं है। 600 से 700 बच्चे हर कालेज में हैं, तो उनका क्या हाल होगा? इसकी तरफ अगर अपना ध्यान नहीं देंगे तो बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी, गुणवत्ता नहीं होगी, तब तक वह आगे नहीं बढ़ेंगे, तो सबसे पहले अपने को यह ध्यान देने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि मूक-बधिर, नेत्रहीन व दिव्यांगों को पढ़ाने के लिए सीनियर स्कूलें तो खोल दीं लेकिन लेक्चरर पद का कैडर बनाना ही सरकार भूल गयी। हमारे यहां पर तीन हजार बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी। अभी भी न स्पेशल टीचर को पदोन्नति दी, न ही शाला दर्पण पोर्टल पर पद अपडेट किये हैं। आज उनकी क्या हालत है? उनके लिए अगर नवाचार करके आगे अपना कालेज खोल रहे हैं, जैसे प्रदेश में चार-पांच विशेष आवासीय स्कूल आपने खोले हैं। सैकण्डरी बांसवाड़ा से लगाकर नेत्रहीन आवासीय बीकानेर, अजमेर, वहां से जब तक ग्यारहवीं, बारहवीं करके लड़का आगे नहीं जायेगा तो कालेज में कैसे पहुंचेगा? वहां पर आपके एक भी शिक्षक नहीं है, तो इस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है।

एकीकरण में स्कूलें पहले जो बंद हुई थीं उनको खोलने के लिए सरकार ने वादा किया था लेकिन अभी आज दिन तक भी वह की वह स्थिति है और उलटा आप कम नामांकन वाले स्कूल बंद करने जा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा का स्तर गिर रहा है। बाड़मेर जिले में सैकड़ों अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपने बाड़मेर जिले से, जैसलमेर से लगाकर रेगिस्तानी एरिया में लगाकर जितने भी थे उनका ट्रांसफर तो कर दिया पर उनको भरने का काम नहीं किया।

नये प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की हर बजट में घोषणा हुई है लेकिन सिवाना क्षेत्र में कम खोले जा रहे हैं। मेरे द्वारा सरकार को 16 नये विद्यालय खोलने की डिमांड माननीय मंत्री महोदय को दी है। क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की मांग मेरी व आमजन की है, जिसमें सिवाना क्षेत्र के लक्ष्मणनगर, तेलवाड़ा, जीनपुर, देवाणी की गुगरवालों की ढाणी, बाण्डानाडा सहित 17 विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के लिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन कर चुका हूं।

(श्री हमीर सिंह भायल)

उच्च प्राथमिक विद्यालय कितना परसेंट मतलब, कई जगह पर 70 से 80 परसेंट पद खाली पड़े हैं, तो बच्चे अध्ययन कैसे करेंगे? रिक्त पदों के अलावा भवन की स्थिति भी यह की यह है। जब तक बच्चों को बैठने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है तो वे कैसे पढ़ेंगे? आप स्कूल तो खोल देते हैं पर उसमें भवन नहीं है, चारदीवारी नहीं है। जहां कन्या पाठशाला है वहां पर शौचालय नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। अंग्रेजी माध्यम के कोई वरिष्ठ अध्यापक नहीं हैं और अंग्रेजी माध्यम की आपने महात्मा गांधी की नाम से खोल दी, पर उसका फायदा क्या होगा? उसमें आप कम से कम अंग्रेजी पढ़े हुए मास्टर लगाने की कोशिश करें।

माननीय मंत्री महोदय से मैं दो बार मिलकर निवेदन कर चुका हूं कि भलरो का बाड़ा स्कूल के अन्दर पिछले दो वर्षों से दो मास्टर ही हैं और 450 लड़के हैं और वहां पर बजट स्वीकृत होने के बाद में भी वहां का जो पहले प्रिंसिपल था, उन्होंने कहा कि जमीन नहीं है, यूं कहकर भेज दिया था। वापस दो साल से मैं प्रयत्न कर रहा हूं। उसका बजट स्वीकृत हो गया था और उसके बाद में अभी तक वह बजट वापस लैप्स हो गया और वह बजट अभी तक नहीं आया, तो बिना भवन के भलरो का बाड़ा समदड़ी तहसील के अन्दर यह स्कूल चल रही है। नये संकाय खोलने के लिए निवेदन है कि विज्ञान विषय पादरू, इन्द्राणा, मायलावास, बालिका सिवाना, सिणरे में विज्ञान संकाय खोली जाये।

माननीय सभापति महोदय, मायलावास भवन निर्माण पांच वर्ष से, राजकीय महाविद्यालय सिवाना में वीर नारायण परमार, पांच साल से भवन का बजट स्वीकृत होने के बाद भी, वहां पर ठेकेदार द्वारा काम चालू किया गया था परन्तु वह अभी तक भी यूं का यूं अधूरा ही पड़ा है। ऊपर मंजिल बनाने में यूं का यूं काम पड़ा है, आज दिन तक नहीं कर पाये।

समदड़ी में महाविद्यालय की भूमि दूर है और सिवाना में कन्या महाविद्यालय आपने खोल तो दी, खेल मैदान के अन्दर आपने भवन बनाना शुरू किया, जमीन भी अभी तक अलाट नहीं हुई और वह भी कंजेस्टेड जगह में है, आप दूसरी कोई जगह लेकर करते।

माननीय सभापति महोदय, प्रतिनियुक्तियों पर सारा काम चल रहा है। मेरे समदड़ी के अन्दर 12 करोड़ रुपये की आई.टी.आई. बनी हुई है, वह भवन दुर्दशा की हालत में पड़ा हुआ है, वहां पर अभी तक भी कोई कार्य शुरू

(श्री हमीर सिंह भायल)

नहीं हुआ है, इसको भी आप देखें। सिवाना के अन्दर आई.टी.आई. है, इसमें पेट्रोकेमिकल विषय को भी चालू करायें ताकि रिफाइनरी पास में आने की वजह से अगर पेट्रोकेमिकल सब्जेक्ट होगा या इससे जुड़ा हुआ सब्जेक्ट होगा तो लोगों को बेनिफिट होगा, फायदा मिलेगा।

अभी माननीय सदस्य यह फरमा रहे थे कि शहीदों के नाम, देश भक्तों के नाम, महापुरुषों के नाम स्कूलों के नाम होने चाहिए। वास्तव में भारत में महापुरुष और शहीदों के नाम आजादी के बाद कभी के ही हो जाने चाहिए थे। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतर कर आप देखें, एरोड्रोम के नाम देखें, रेलवे स्टेशंस के नाम देखें। वह किनके नाम पर रखे गये, वह कैसे हुए? मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि भारत के प्रधान मंत्रीजी ने देशभक्त, महापुरुष और शहीदों के नाम पर नामकरण करने का काम किया है। द्वीपों के नाम भी भारत के शहीदों के नाम पर करने की कोशिश की है।

मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा भर्ती करें। जब तक पूरे शिक्षक और प्रिंसिपल वगैरह नहीं होंगे, तब तक स्कूल्स का सुधार नहीं होगा। पेपर लीक नहीं हो, इसके लिए भी आप पूरा प्रबन्ध करें। कुक एवं हैल्पर के मानदेय बढ़ाये जायें। हर स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था की जाये। बालिका स्कूल में शौचालय की व्यवस्था की जाये। अंग्रेजी स्कूल्स में टीचर के पद जो खाली हैं, वह भरे जायें। स्कूल्स के ऊपर बिजली की हाईटेंशन लाइन जहां गुजर रही हैं, उनको हटाया जाये।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती गायत्री देवी त्रिवेदी।

श्रीमती गायत्री देवी त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 20, 21 एवं 22 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं राजस्थान के गांधी माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत साहब एवं शिक्षा मंत्री बी. डी. कल्लाजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होने मेरी विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई इबारत लिखी है। एक ओर बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शिक्षा को बढावा देने के लिए विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जा

(श्रीमती गायत्री देवी त्रिवेदी)

रहा है, जिससे बच्चों को अध्ययन के लिए दूरस्थ विद्यालयों में नहीं जाना पड़े। बच्चों को निःशुल्क दूध, ड्रेस वितरित की जा रही है।

'शिक्षा के अभाव में, खिले न गुण का फूल।

शिक्षा में ही बसा, जगत प्रगति का मूल।।'

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान के समस्त सैकण्डरी स्कूलों को, बारहवीं कक्षा के स्कूलों को बिना किसी राजनैतिक भेदभाव के क्रमोन्नत कर दिया। इससे बड़ा क्रान्तिकारी कोई निर्णय नहीं हो सकता।

मैं सदन के माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी एवं मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो स्कूल्स क्रमोन्नत नहीं हुई वह हैं- कालीमंगरी (डेलाना) एवं कुम्हारियाखेडा (देवली) प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करावें। सरेवडी (भींटा), मियाला (बागड), टूंगच (खाखरमाला), भटेवर (भींटा), आलोली (अरनिया), झबरकियां (सोनियाणा), भैसाकुण्डल (देवली), शिवपुरा (दूडिया), जाग्रदरी (सेथूरिया) मोमी (गुरला), आमली पुरावतान (बरडोद) उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करावें।

माननीम सभापति महोदय, मैं उच्च शिक्षा मंत्री महोदय को कहना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में लेक्चरर नहीं हैं वहां जल्दी से जल्दी भर दिया जाय ताकि बच्चों को पढ़ने में सुविधा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के विद्यालयों में शिक्षकों के पद काफी संख्या में रिक्त चल रहे हैं, इस कारण बच्चों की पढ़ाई में परेशानी हो रही है, मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए शिक्षकों के रिक्त चल रहे पदों को शीघ्र भरवावें ताकि सरकारी विद्यालयों का नामांकन स्तर बढ़ सके और शिक्षा का स्तर बढ़ सके।

साथ ही राज्य में कार्यरत महिला शिक्षिकाएं शादी के बाद अपने उपनाम बदलवाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है वह काफी लम्बी एवं जटिल प्रक्रिया है। उक्त प्रक्रिया को सरल करने के साथ-साथ जिला स्तर पर सम्पादित करवा दिया जाये तो महिला शिक्षिकाओं को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

अन्त में मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी के सम्मान में चन्द लाइनें कहना चाहती हूं:-

(श्रीमती गायत्री देवी त्रिवेदी)

"राजस्थान का नाम और पहचान आपसे है,
राजस्थान की आन बान शान आपसे है,
आपके विकास कार्यों ने क्षेत्र की दशा बदल दी,
इसलिए हर चेहरे पर मुस्कान है।"
जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री जगसी राम।

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 20-प्रारम्भिक शिक्षा, मांग संख्या 21-माध्यमिक शिक्षा और मांग संख्या 22-उच्च शिक्षा पर आज चर्चा हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, आज शिक्षा का क्षेत्र आमजन से जुड़ा हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव का रवैया वर्तमान की सरकार अपना रही है। राजस्थान में सिरोही जिले को आकांक्षी जिला माना गया है उसके उपरान्त भी विधान सभा क्षेत्र रेवदर में प्रधानाचार्य और व्याख्याताओं के सारे पद खाली हैं। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय विराजमान हैं, रेवदर विधान सभा क्षेत्र में हर स्कूल में प्रधानाचार्य और व्याख्याताओं के रिक्त पद हैं, आप नोट करें और जब आप जबाव दें तब भरने के बारे में कहने का कष्ट करें।

राजस्थान में जो स्कूल्स क्रमोन्नत की हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र रेवदर में काफी स्कूल्स मापदण्ड पूरे करते हैं फिर भी उनको क्रमोन्नत नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहूंगा कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय या उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूं। ग्राम पंचायत जेतावाड़ा में बासाड़ा, ग्राम पंचायत रायपुर में वडवज, ग्राम पंचायत धवली में क्यारिया, ग्राम पंचायत मारोल में निम्बोड़ा, ग्राम पंचायत लूणोल का राजगढ़, ग्राम पंचायत मगरीवाड़ा में जावाल, ग्राम पंचायत चण्डेला में तेलपुर फली, ग्राम पंचायत चण्डेला में ढुढाई फली, ग्राम पंचायत भैरूगढ में करेली, ग्राम पंचायत मकावल में गोरेली और ग्राम पंचायत धाण में मलावा को क्रमोन्नत करने के लिए आपसे विशेष निवेदन है क्योंकि अलग-अलग ढाणियों के अन्दर वहां पर जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको परेशानी होती है। उनको इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। सभी

(श्री जगसी राम)

माननीय सदस्यों ने भी यह बात कही है। महात्मा गांधी सरकारी स्कूल जो खोली गयी हैं, मेरे यहां रेवदर उपखण्ड स्तर पर, वहां वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम हुआ था, उसमें मुझे जाने का मौका मिला था। वहां पर अभिभावकों और ग्रामवासियों का यही कहना था कि जहां इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली हैं, वहां के हिन्दी मीडियम वाले बच्चे कहां जायेंगे? इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको दो शिफ्ट में किया जाये। इससे दोनों को फायदा मिलेगा। नहीं तो क्या है कि बच्चा न तो इधर का रहेगा और न ही उधर का रहेगा। मेरे से पूर्व सभी सदस्यों ने भी यही बात कही है। यह भी कहा गया कि उन स्कूल्स में अध्यापकों की विशेष कमी है, उसके लिए सरकार को पुख्ता व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, स्कूल्स के अन्दर जो खेल के मैदान हैं, उसके बारे में सभी माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही है। एक दो कमरों की आवश्यकता तो हमेशा रहती है। पुराने भवनों के डाक्यूमेंट के हिसाब से वह दायरे में नहीं आते हैं, इसलिए उनमें कमरे बनवाने के लिए एमएलए और एमपी ग्रान्ट का पैसा नहीं लग पाता है, तो सरकार कोई भी ऐसा एक रास्ता निकाले ताकि बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था हो जाये।

आबू रोड पंचायत समिति में क्यारा ग्राम पंचायत है, तीन साल पहले मैंने विधान सभा में भी बात रखी थी, उसका भवन बनाने के लिए बजट तो आ गया, पर वहां पर जमीन आबंटित नहीं होने की वजह से आज तक भवन नहीं बना है। इसी तरह से पंचायत समिति आबू रोड की धामसरा ग्राम पंचायत है, वहां पर भी छोटे तीन कमरों के अंदर बारहवीं तक की स्कूल है, वहां पर आधे बच्चे बाहर बैठते हैं और आधे बच्चे स्कूल के अंदर बैठते हैं। मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि उसके लिए भी आप जमीन का आबंटन करवायें, जिससे बच्चों के लिए व्यवस्था हो जाये।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से पंचायत समिति रेवदर में एक ग्राम पंचायत पादरका है, वहां पर भी कागजों के अंदर जमीन को इधर-उधर करने के बाद में अभी जमीन अलाट हुई है चार महीने पहले, लेकिन बजट का अभाव बता रहे हैं। पहले तो रमसा के माध्यम से लाखों रुपये आते थे और उसमें बिल्डिंग्स बनती थीं। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि इसी बजट को वापस रिलीज करके वहां पर विद्या मंदिर के लिए, स्कूल के लिए पैसा रिलीज करें।

(श्री जगसी राम)

माननीय सभापति महोदय, पंचायत समिति रेवदर ब्लाक के अंदर जो बच्चे विद्यालयों में पढ़ते हैं, उसके अंदर मैं समझता हूं कि कृषि क्षेत्र ब्लाक स्तर पर किसानों से संबंधित ऐसा विषय खोलें ताकि आने वाले समय के अंदर बच्चे कृषि से संबंधित क्षेत्र से जुड़ें।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों के अंदर पहले स्टाफ सही था और अच्छी तरह से स्कूलें चल रही थीं, लेकिन अब स्टाफ न होने की वजह से अन्य स्कूलों का जो स्टाफ है, वहां से स्टाफ लगाकर व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरी जगह से स्टाफ लगायेंगे तो वहां पर कमी होगी, तो इसका स्थायी निराकरण करने के लिए सरकार को कदम उठाने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जिन स्कूलों की बिल्डिंगें जर्जर पड़ी हैं, वहां पर जाने से पहले बच्चों को डर लगता है। बारिश के अंदर वहां पर बच्चों की पहले से ही छुट्टियां कर दी जाती हैं कि आज स्कूल बैठने योग्य नहीं है, कक्षा-कक्ष पानी से जर्जर हो रहे हैं। इसलिए मैं सरकार की जानकारी में लाना चाहूंगा कि ऐसी कई स्कूलें हैं। पूरे रेवदर विधान सभा क्षेत्र में काफी स्कूलें हैं लेकिन मैं मोटे-मोटे तौर पर आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा। ग्राम पंचायत धवली के अंदर सरलिया खेड़ा है, खाखरबास थल है, पेरवा, परमाण, मालपुरा, दौलपुरा है। इसी तरह से आबू रोड में आमथला, दांतराई और आमलाखेड़ा-अनादरा और मकावल, इन स्कूलों की स्थिति बहुत दयनीय और खराब है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह चीज मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार की जानकारी में लाना चाहूंगा कि रेवदर ब्लाक के अंदर प्रधानाचार्यों के 31 पद रिक्त हैं और काम करने वाले, मैं समझता हूं नहीं हैं। इसी तरह से आबू रोड ब्लाक के अंदर अधिकतर पद रिक्त हैं, उनको भी भरवाने की आप मेहरबानी करें।

माननीय सभापति महोदय, रेवदर महाविद्यालय में हिन्दी एवं राजनीति विज्ञान और आबू रोड महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर रसायन विज्ञान खोली जाये, ताकि वहां पर आबू रोड और रेवदर में ग्रामीण क्षेत्र से काफी बच्चे पढ़ने आते हैं, उनको मूलभूत सुविधा मिलेगी और जब पढ़ेंगे तो वह

(श्री जगसी राम)

शिक्षा पाकर आगे बढ़ेंगे और नौकरी में जायेंगे। अगर उनको सुविधा नहीं मिलेगी और वह नहीं पढ़ेंगे तो मैं समझता हूं उनको फायदा नहीं मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, आबू रोड का जो ग्रामीण क्षेत्र है वह पूरा आदिवासी क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि में अम्बाजी से भी आगे 20 किलोमीटर का लम्बा क्षेत्र है, उसके अंदर आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए यदि सरकार की मंशा है तो मैं समझता हूं कि आबू रोड उपखण्ड पर एक महिला महाविद्यालय और रेवदर उपखण्ड पर महिला महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से स्कूलों के अंदर पेयजल की समस्या है। मैं समझता हूं कि कई बच्चे बैग के साथ पानी की बोतल भी साथ लाते हैं, क्योंकि वहां पर शुद्ध पानी नहीं मिलता है। सरकार से हम कहना चाहते हैं कि विधायक कोष से वहां पर शुद्ध पेयजल के लिए R.O. प्लांट के लिए सरकार कोई योजना बनाये। इसके लिए हम पैसे देने के लिए भी तैयार हैं। इससे बच्चों को शुद्ध पेयजल मिल सकेगा, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, अंतिम बात कहकर दो मिनट में मेरी पूरी बात पूरी कर दूंगा। जो संस्कृत विद्यालय हैं, इन संस्कृत स्कूलों के अंदर कहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक तो नागाणी है, एक आबू रोड के अंदर उमरेणी है, वहां पर स्टाफ बिलकुल भी नहीं है, तो उन पदों को भरवाने की कृपा करें। वहां पर संस्कृत स्कूल में पढ़ने की सबकी इच्छा है, पर स्टाफ ही नहीं होगा तो वहां पर कैसे पढ़ाई हो पायेगी? इसके अलावा, स्कूलों के अंदर दूध पिलाने वाली योजना पूर्ववर्ती सरकार ने चालू की थी, इसकी क्वालिटी सही नहीं है, उसमें सुधार किया जाये। समय-समय पर उनकी मॉनिटरिंग करेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा रहेगा नहीं तो वह कागजों तक ही सीमित रह जायेगी।

यूनिफार्म अभी सरकार ने जो लागू की है, मैं समझता हूं मैं पूरे राजस्थान की बात नहीं करता, लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो यूनिफार्म सिर्फ स्कूलों के अंदर फोटो खिंचवाने तक है, वह यूनिफार्म सब जगह नहीं पहुंची है। उसकी मॉनिटरिंग करके उसको दिखवाने की व्यवस्था करावें। मैं समझता हूं कि सरकार ने कोई योजना लागू की है तो उसका कोई फायदा मिले।

मैं मेरी बात को ज्यादा न कहते हुए अब यही कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो मेरी छोटी-मोटी मांग रखी हैं, उनके ऊपर गौर करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गिरधारीलाल जी।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 20, 21 और 22 पर बोलने का मौका दिया, आपका आभार। राजस्थान विधान सभा के अंदर शिक्षा पर चर्चा हो रही है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार थी, उन्होंने कई गांवों में, कई कस्बों में स्कूलें बंद कीं। वर्तमान सरकार ने जो बच्चे दो-तीन किलोमीटर चलकर आते थे, उनके लिए स्कूलें खोलीं, उसके लिए तो सरकार को धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव बेसीपुरा, सिंदु, लालासर, मणकासर, रासीसर, नारसीसर, सेरूणा, सोनियासर में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करना आवश्यक है। इसके अलावा, बजरासर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुखराम की ढाणी को क्रमोन्नत किया जावे।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मेरे क्षेत्र के बाजनोर में दसवीं में, बारहवीं में बोर्ड का परीक्षा केन्द्र खोलने के लिए लम्बे समय से मांग की जा रही है, क्योंकि इन गांवों के हजारों बच्चों को प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षा के समय नजदीकी गांवों में परीक्षा देने के लिए जाना पड़ता है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र गांव कल्याणसर नया में रामलाल की ढाणी, लिखमीसर के हनुमान जी मंदिर के पास पाटवालों की जोहड़ और बावरियों का मोहल्ला, श्रीडूंगरगढ़ शहर में नवीन राजकीय विद्यालय खोले जावें, क्योंकि इन सभी स्थानों में बड़ी संख्या में बच्चे निवास करते हैं। यहां से विद्यालयों की दूरी अधिक होने के कारण परेशानी होती है। माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार भोम बीदासरिया ग्राम में पड़ा बंद विद्यालय खोला जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम टेऊ, लिखमीसर, आडसर, धन्नेरू, कुचोर, अथूनी, भाटियाण, लालासर, लालनदेसर छोटा में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जायें।

माननीय सभापति महोदय, जहां शिक्षा की बात शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी का राज आने के बाद चाहे केन्द्र में हो, चाहे राज्य में हो, शिक्षा नीति को पलटा जा रहा है। हर बात को धर्म से जोड़ा जा रहा है। पाठ्य-पुस्तक हो, चाहे अन्य आयोजन हो स्कूलों में, निश्चित रूप से यह चल रहा

(श्री गिरधारीलाल)

है। आज भारत देश धर्म निरपेक्ष देश है। हर व्यक्ति को बात कहने की यहां पर छूट है। उस सूरत में पाठ्य-पुस्तकों को, शिक्षा नीति को बदला जा रहा है। जे.एन.यू. जैसे शिक्षण संस्थानों को उजाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम आने वाले समय में जब शिक्षा नीति पर बात करते हैं, शिक्षा पर चर्चा होती है तो राजस्थान के जन-प्रतिनिधियों को सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा, सांप्रदायिक ताकतों के द्वारा शिक्षा नीति व इतिहास को तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है, पाठ्यपुस्तकों को तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है, उस पर गौर करना चाहिए।

सभापति महोदय, राजस्थान की पाठ्यपुस्तकों में राजस्थानी भाषा को भी महत्व देना चाहिए। चाहे किसी को गलत लगे, करना चाहिए। जब अन्य राज्यों की भाषा अनुच्छेद सूची 8 में है तो हमारे यहां भी राजस्थानी को शामिल करने का प्रयास करें। पहले प्रस्ताव भी भेजा गया है। अगर केन्द्र गवर्नमेंट नहीं करती है तो उस सूरत में राजस्थान सरकार के पास ताकत है, उसको दर्जा भी दिया जाये। धन्यवाद। जय हिन्द।

(माननीय सदस्य श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़) के सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-05 देखें)

श्री सभापति: श्रीमती रमीला खड़िया।

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 20, 21 और 22 के ऊपर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं, राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि इन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा दिया। इन्होंने 2-2 कालेज मुझे दीं। इन कालेजों का काम चालू हो चुका है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्कूलें क्रमोन्नत कीं और इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोलीं। उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

सभापति महोदय, मैं इसके साथ ही आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में जो इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली गयी हैं, इनमें हिन्दी और इंग्लिश मीडियम दोनों साथ ही चलें तो सरकार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वहां से बच्चों को निकालकर भेजा जा रहा है। वहां एक पारी में इंग्लिश मीडियम और दूसरी पारी में हिन्दी मीडियम चले।

(श्रीमती रमीला खड़िया)

सभापति महोदय, इसके साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में 4-5 दिन पहले बहुत बड़ी घटना होते-होते रह गयी। ग्राम पंचायत चुड़ादा में बच्चे बरामदे में खाना खा रहे थे, टीचर्स वहां चाय पी रहे थे, तभी वहां छत गिर गयी। वीरसिंह जी गुरुजी थे, उनको पीठ पर लगी। एक बच्चे को भी लगी जो अपने मां-बाप का इकलौता बेटा था, वह वहां बरामदे में बैठकर खाना खा रहा था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि जो भी स्कूलें जर्जर अवस्था में हैं, इन स्कूलों की जांच कराकर, एक जांच कमेटी बनाकर उसको भेजकर जो भी पुरानी स्कूलें हैं, इन स्कूलों को गिराकर नया भवन उनको दिया जाये। इसी तरह से सोमासा में, हमारे पाटन में सरोना है, वहां रात के समय एक स्कूल गिर गयी। बहुत सारी ऐसी स्कूलें हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं कहना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ व सज्जनगढ़ में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मसारासात है, वहां करीब 700 बच्चे हैं, वहां कक्षा कक्ष 3 से 4 ही हैं। मैं कहना चाहती हूं कि जहां भी कक्षा कक्ष, कमरे नहीं हैं और बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां कक्षा कक्षों की मैं मांग रखती हूं।

सभापति महोदय, इसी तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुंडियां खूटा में 100 बच्चे हैं, वहां मात्र 2 कमरे हैं। एक तो आंगनबाड़ी उसमें चल रही है, उसमें एक स्कूल चल रही है। वास्तव में वह स्कूल जर्जर अवस्था में है। मुझे सोमासा में बुलाया था और मैं वहां गयी तो वहां पर बैठने लायक ही नहीं है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तामेसरा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चुडादा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अंदेश्वर, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जखोड़िया नाथा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोंदड़ी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पाली चोटी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय चौकी डूंगरी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शकरवाड़ा, पाडला कटारा में, यह 2-3 स्कूलें हैं, उनको क्रमोन्नत करने की मैं मांग करती हूं। यह मैं पहले भी दे चुकी हूं।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में स्कूलों में कक्षा कक्ष दें। उसके साथ ही चारदीवारी भी स्कूलों में नहीं है, खेल मैदान भी नहीं हैं। जो दसवीं से बारहवीं और आठवीं से दसवीं तक स्कूलें हैं, वहां बालक, बालिकाओं के लिए शौचालय नहीं है। मैं मांग करती हूं

(श्रीमती रमीला खड़िया)

कि इन चारदीवारियों को भी बनाया जाये। जिन स्कूलों में शौचालय नहीं हैं, हम हर स्कूल में कहीं न कहीं कार्यक्रमों में जाते रहते हैं तो बालिकाएं कहती हैं कि, मैडम, हमारे जाने-आने के लिए शौचालय की काफी समस्या है, हम कहां जायें? कहीं न कहीं इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूलों में शौचालय बनवायें। ट्यूबवैल और टंकी के माध्यम से उनमें पानी की व्यवस्था की जाये।

विपक्ष के लोग भी बता रहे थे कि इस सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि हमारे राजीव गांधी पाठशाला हर वार्ड में खोली गयी थी, वहां हमारे छोटे-छोटे बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे, वह स्कूलें बंद की गयी हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि इन स्कूलों को वापस चालू किया जाये। अगर नहीं चालू करें तो वहां आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, उनमें चलायें। बहुत जगह ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, जहां भवन नहीं हैं, ताकि वहां साफ-सफाई रहे, रख-रखाव रहे। इससे वह भवन सुरक्षित रहेगा।

सभापति महोदय, जब पिछली सरकार ने साइकिलें आयीं तो साइकिलों का कलर बदल दिया। बीजेपी का कलर कर दिया। ड्रेस आयी तो ड्रेस में पीला कलर कर दिया। यह जो काम किये हैं, वह बीजेपी सरकार ने किया था। मैं कहना चाहती हूं कि हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री ने शिक्षा को बढ़ावा दिया है। बहुत अच्छा काम किया है।

हमारे मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। मैंने जिन स्कूलों के नाम लिए हैं उन स्कूलों में 2-2, 3-3 कमरे हैं, उनको वास्तव में देखें। मंत्री जी, अभी 3-4 दिन पहले ही यह घटना घटी है। भगवान की दया थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनमें कमरे देने की मैं मांग करती हूं। मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री राजकुमार रोत।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सभापति महोदय, आपका धन्यवाद, आज मांग संख्या 20, 21 और 22 पर आपने बोलने का अवसर प्रदान किया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इन मांगों पर अपना वक्तव्य रखने से पहले कहना चाहूंगा कि पूर्व में शिक्षा विभाग की डिमांड पर ही मैंने मंत्री जी से मांग की थी कि हमारे यहां शिक्षा की देवी के रूप में कालीबाई कलासुआ को जाना जाता है, जिन्होंने शिक्षा के लिए अपनी जान दी। उनके नाम से जो स्कूल चल रही थी, बीजेपी शासन काल में वह स्कूल बंद कर दी

(श्री राजकुमार रोत)

थी, हमने मांग रखी तो मेरी मांग के अनुरूप मंत्री जी ने वह विद्यालय खोल दिया, लेकिन उसका नामकरण कालीबाई कलासुआ किया जाए। यह मैं दुबारा इसमें मांग रख रहा हूं।

इन तीन-चार सालों में मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई विद्यालय क्रमोन्नत हुए लेकिन हमारे यहां राजस्थान में अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो डूंगरपुर जिले में सबसे अधिक लिंगानुपात है और विधान सभा की अगर बात की जाए तो 200 विधान सभा क्षेत्रों में चौरासी विधान सभा क्षेत्र में सबसे अधिक लिंगानुपात है। हमने जो महात्मा गांधी विद्यालय खोले, हमारे तीन ऐसे बालिका विद्यालय, जोत्री बालिका विद्यालय, पंचायत समिति मुख्यालय पर एकमात्र चल रहा था।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय अनुदान की मांग संख्या 20-प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, मांग संख्या 21-माध्यमिक शिक्षा विभाग, मांग संख्या 22-उच्च शिक्षा विभाग की मांगें पारित होने और आज की कार्यसूची पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाए?

श्री सभापति: बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ा दिया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 20-प्रारंभिक शिक्षा, मांग संख्या 21-माध्यमिक शिक्षा व मांग संख्या 22-उच्च शिक्षा पर विचार

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, लिंगानुपात हमारे यहां सबसे अधिक है। बालिका विद्यालय खुला हुआ था लेकिन महात्मा गांधी विद्यालय खोलने से जोत्री, चिखली, विकास नगर, पीठ, ऐसे तीन से चार बालिका विद्यालय बंद हो गये हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि या तो नये बालिका विद्यालय खोलें या उसी में दो पार्ट कर दिये जाएं,

(श्री राजकुमार रोत)

पहले तो महात्मा गांधी विद्यालय खुलें और दोपहर बाद जो बालिका विद्यालय हैं वो रहें।

माननीय सभापति महोदय, हमारे इलाके में जो शिक्षा के लिए बलिदान दिया था, स्वतंत्रता सेनानी सेंगा भाई, नाना भाई खांट, कालीबाई कलासुआ, शिक्षा के लिए जो गुरु का काम कर रहे थे, स्वतंत्रता सेनानी सेंगा भाई, उनकी जन्म स्थली, भीला, पंचेला ग्राम पंचायत में है। हमारे उस क्षेत्र के लोग लम्बे समय से मांग कर रहे हैं कि उस विद्यालय का नाम स्वतंत्रता सेनानी सेंगा भाई रोत के नाम से किया जाए। ब्रिटिश काल में हमारे शिवरामजी रोत, उन्होंने भी शिक्षा के लिए काम किया और वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तो जोत्री विद्यालय उनके नाम किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जोत्री, पूनावाड़ा, उदड़िया, चिखली, ये जो विद्यालय हैं वहां पर साइंस भी खुली हुई है तो मैं चाहूंगा कि इसमें दो विद्यालय ब्लाक लेवल पर हैं इनमें अतिरिक्त संकाय भी खोला जाए।

माननीय सभापति महोदय, हमने अभी चर्चा सुनी कि विद्यालयों की क्या स्थिति है, हमने कई योजनाएं लागू कीं, लेकिन हमारा जो एजुकेशन स्तर है, हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है, बच्चों को जो शिक्षा देने का मूल काम है उसको प्रभावित तो वे नहीं कर रही हैं? कई ऐसी योजनाएं हैं, हमारा बच्चा सुबह स्कूल में गया, स्कूल में जाने के बाद हम आधा घंटा प्रार्थना करवाते हैं, इसके बाद बच्चे को हम दूध देते हैं, तो कम से कम एक घंटा दूध में उसका बर्बाद होता है। लम्बी लाइन लगती है फिर उसको दूध देंगे, दूध ठण्डा होगा, इसके बाद एक घंटा वह पढ़ेगा फिर हम उसको पोषाहार देंगे। पोषाहार खाने के लिए लाइन लगेगी लम्बी, फिर वह खाएगा और फिर बर्तन धोने जाएंगे, यह जो सिस्टम है वो सिस्टम कहीं न कहीं उस बच्चे का दो से ढाई घंटा बर्बाद कर रहा है, तो इसमें कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए। जैसे कि हम बच्चों को कभी कहते हैं कि वो धोएंगे, फिर कहते हैं कि कुक या हैल्पर गिलास और थाली धोएगा, हमने कुक और हैल्पर का पैसा तो बढ़ाया नहीं है, तो वो गिलास और थाली क्यों धोएंगे तो यह जो समय है दो से ढाई घंटा, हम किसी स्कूल में जाकर प्रैक्टिकल चैक करेंगे तो यह चीज हमारे सामने आएगी।

माननीय सभापति महोदय, आज अभी बात हो रही थी, हमारा देश

(श्री राजकुमार रोत)

धर्म निरपेक्ष देश है, पंथ निरपेक्ष देश की बात हो रही थी लेकिन कई विद्यालयों में विशेषकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में उनको धार्मिक प्रयोगशाला बना रखा है। कई जगह ईसाई मिशनरियों का प्रचार होता है स्कूलों के अंदर, कई जगह हिन्दुत्व का प्रचार होता है, कई जगह राम-रहीम और रामपाल जैसे बाबाओं का धर्म है, उनका प्रचार होता है। मतलब आदिवासी बहुल क्षेत्र को प्रयोगशाला बना रखा है, तो हम धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं तो विद्यालयों के अंदर जो धार्मिक गतिविधियां हैं, उनको बंद कर दिया जाए। कई विद्यालयों में मेरा जाना हुआ, मैंने बच्चों को पूछा कि पहली शिक्षिका कौन थी, उन बच्चों को सावित्रीबाई फुले के बारे में नहीं पता है, कालीबाई कलासुआ के बारे में नहीं पता है, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में नहीं पता है। जितने काल्पनिक देवी-देवता हैं उनके बारे में पूछेंगे तो सारे बच्चे बता देंगे, तो इससे कहीं न कहीं यह स्थिति बनी हुई है वहां पर कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको कम जानते हैं, काल्पनिक देवी-देवताओं को ज्यादा जानते हैं। वहां जो धार्मिक गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को कम कर दिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, उस इलाके में सोमवार का दिन आप देखना, सोमवार के दिन विद्यालयों में लगभग 30 से 40 प्रतिशत ही उपस्थिति आपको मिलेगी। बालिकाओं की 80 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहेगी क्योंकि वो धार्मिक गतिविधियों में व्रत के लिए जाते हैं, नवरात्रि आती है, दशामाता आती है तो बारह-बारह, पन्द्रह-पन्द्रह दिन तक बच्चे विद्यालयों में नहीं आते हैं क्योंकि उनकी शुरुआत उस विद्यालय से हुई है।

माननीय सभापति महोदय, भौतिक सुविधाओं को लेकर चर्चा हो रही थी। हमारे उस इलाके में भौतिक सुविधा यह है कि किसी स्कूल में मुश्किल से चारदीवारी मिल जाएगी। कई विद्यालय ऐसे हैं जहां शौचालय नहीं मिलेंगे, कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पर्याप्त मात्रा में भवन नहीं मिलेगा। हमने लाखों-करोड़ों रुपये उस आदिवासी बहुल क्षेत्र के लिए घोषणा कर दी लेकिन उनका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर हम विद्यालयों की स्थिति भौतिक सुविधाओं के सम्बन्ध में सुधारना चाहते हैं और विशेषकर मैं हमारे क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा कि हमारे टीएडी विभाग के जो कमिश्नर हैं, पंचायती राज विभाग और एजुकेशन विभाग के जो कमिश्नर हैं, वो तीनों काम्बीनेशन बैठाएं और टीएडी विभाग का जो पैसा है, उस पैसे को भी विद्यालय की भौतिक सुविधाओं पर

(श्री राजकुमार रोत)

खर्च करें। पंचायती राज विभाग मनरेगा से लाखों-करोड़ों रुपये खर्च करता है लेकिन स्कूल की चारदीवारी मनरेगा में हम सैंक्शन नहीं करवा पाते हैं, तो इसका प्रावधान किया जाए कि टीएडी विभाग, पंचायती राज विभाग और एजुकेशन डिपार्टमेंट काम्बीनेशन बैठाकर भौतिक सुविधाएं विद्यालयों में उपलब्ध कराएं।

माननीय सभापति महोदय, उस इलाके में ड्राप आउट की काफी समस्या आ रही है। बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ समय बाद वो स्कूल छोड़ देते हैं। यह समस्या क्यों आ रही है? या तो वो अभिभावक पढ़ाना नहीं चाह रहा है या ध्यान नहीं दे रहा है, या कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं। हमने जो महसूस किया विशेषकर मातृभाषा, बच्चे की पहली शिक्षिका या शिक्षक कहें तो वो मां है, उसकी पहली लैंग्वेज अपनी मातृभाषा, स्थानीय भाषा है। पहली पाठशाला अपना परिवार है। अब बच्चा वहां पर सीधा स्कूल में गया, हमने हमारी शिक्षण व्यवस्था, हमारी लैंग्वेज उस पर थोप दी। बच्चा डरता है, बच्चे के समझ में नहीं आता कि ये क्या बोल रहे हैं और वह बच्चा ड्राप आउट होता है। आपने इस सदन में देखा होगा कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों से आने वाले जितने भी विधायक हैं, इनकी अब तक स्पीच निकालकर देखना, तो जो 'च', 'छ', 'ठ', 'क्ष' है, इनके जो शब्द हैं, उन शब्दों को आज वे विधायक बन गए लेकिन वो नहीं बोल पाते हैं, हम लोग भी नहीं बोल पाते हैं क्योंकि हमारी जो मातृभाषा है उस भाषा में ये शब्द नहीं हैं। हम चाहेंगे कि जो पांचवीं तक एजुकेशन है उसमें उन टीचर्स को पाबंद किया जाए कि पहले मातृभाषा के अंदर बोला जाए।

श्री बाबुलाल (झाडोल): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपत्ति है, माननीय सदस्य इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, वो गलत लगा रहे हैं।

श्री सभापति: पहले उनको कम्प्लीट कर लेने दें।

श्री बाबुलाल (झाडोल): ये कह रहे हैं कि इन शब्दों का हमारा उच्चारण ठीक नहीं है। हम बोलते हैं न। यह हमारी भाषा है, बोलेंगे। माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं वो ठीक नहीं है।

श्री सभापति: आपकी बात ध्यान में आ गई, लेट हिम कम्प्लीट। दो मिनट में समाप्त कीजिए आप।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, हमारी पार्टी को जो समय मिला है उसमें बोलने का अवसर प्रदान करें।

श्री सभापति: समय जो मिला है उसी के हिसाब से कह रहा हूं।

(समय: 18.49 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, स्थानीय भाषा में प्रारम्भिक शिक्षा हो ताकि बच्चा ड्राप आउट न हो। हमारे विद्यालय क्रमोन्नति का जो मापदंड है कि हम दूरी देखते हैं, एनरोलमेंट देखते हैं। हमारी स्थिति है कि हमारे फोरेस्ट का इलाका है, नामांकन बहुत कम रहता है। बच्चे को जाना है दूसरी जगह तो फोरेस्ट इलाका होने की वजह से नहीं जा पाता है, तो जो मापदंड हैं उनमें ट्राइबल एरिये में राहत प्रदान की जाए।

माननीय सभापति महोदय, धूम्रपान, स्कूलों के आस-पास अड्डे लगे हुए हैं। एक तरफ है कि 200 मीटर की परिधि में कहीं धूम्रपान नहीं बेचेंगे, आप सर्वे कराकर देख लें, स्कूल के बिलकुल नजदीक गेट के बाहर दुकान लगी है। वहां बीड़ी, तम्बाकू, सिगरेट, गांजा वगैरह सब मिल रहा है। ऐसी व्यवस्था को हम सुधारें। ऐसी स्कूलों को लिस्टेड करें और ऐसी दुकानें बन्द कराएं।

माननीय सभापति महोदय, स्थानान्तरण को लेकर हमने थर्ड ग्रेड पर वहां प्रतिबन्ध लगा रखा है। करौली, सवाईमाधोपुर, भरतपुर सीकर की तरफ से बहुत सारे टीचर्स वहां लगे हुए हैं। थर्ड ग्रेड के पर्याप्त मात्रा में वहां अध्यापक हो गये हैं, लेकिन जो कालेज व्याख्याता और स्कूल व्याख्याता की हमें जरूरत है, कई विद्यालय ऐसे मिल जाएंगे, हमारे जैसे चिखली में कोंचरी है, चाडोली है, बासिया है, एक भी व्याख्याता नहीं है। साइंस खुली हुई है लेकिन एक भी व्याख्याता नहीं है। व्याख्याताओं के लिए पालिसी बनाएं कि शिड्यूल्ड एरिया में जो आ रहे हैं, उन पर पांच साल तक प्रतिबन्ध लगाया जाये।

माननीय सभापति महोदय, उच्च शिक्षा की बात हो रही थी। उच्च शिक्षा में भी यही समस्या है। हमने कालेज खोल रखी है, लेकिन वहां पर हमारा कालेज व्याख्याता नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में संस्कृत कालेज पीठ है, वहां एक एलडीसी के भरोसे पूरी कालेज चल रही है। कालेज खुली थी, उस समय और आज के एनरोलमेंट को देखें तो काफी अन्तर हो गया है, गिरावट आ रही है। तीन से चार साल हो गये, एक भी व्याख्याता नहीं, एक एलडीसी के भरोसे पूरी कालेज चल रही है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, हमारे

(श्री राजकुमार रोत)

एसबीपी गवर्नमेंट कालेज में भी व्याख्याता की सख्त आवश्यकता है। एक लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे यहां एक कन्या महाविद्यालय खुले। माननीय सभापति महोदय, सीमलवाड़ा में पूर्व में जो हमारे यहां कालेज खुली हुई है उसके अन्दर अतिरिक्त संकाय खोला जाये।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, शिक्षक भर्ती में रिजर्वेशन का मामला हर बार आता है। हमारे 1167 पद जो हैं वे 2018 की भर्ती से अभी तक रिक्त हैं, मेरा अनुरोध है कि शिक्षा मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे और इन 1167 पदों को पात्र अभ्यर्थियों से भरेंगे।

श्री सभापति: श्री आलोक बेनीवाल।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति क्यों दी जा रही है? हमारा छात्रवृत्ति देने का मुख्य उद्देश्य यह है कि उस शिक्षण सत्र में उस बच्चे को किताब लाने में, कपड़े लाने में सहयोग मिले, लेकिन पूरा साल निकल जाता है और तब जाकर उसे छात्रवृत्ति मिलती है।

श्री सभापति: सहयोग करें, माननीय सदस्य।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगें हैं। एक हमारे बांसवाड़ा में कृषि संकाय कालेज है, वहां 240 विद्यार्थियों का एडमिशन है, लेकिन इस कालेज की मान्यता नहीं है, तो 240 विद्यालयों का भविष्य खतरे में है। यह कालेज बोरवट, बांसवाड़ा में है। इसकी जांच कराएं और इसे मान्यता दिलाने में सहयोग करें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक विद्यालय सारणसाद, डूंडी में बाबड़ी, बागवा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय धनोरा, ये ऐसे-ऐसे विद्यालय हैं जहां पर क्रमोन्नत कराने की सख्त जरूरत है। आप चाहें तो मैं टेबल कर दूं विद्यालयों को।

श्री सभापति: हां, टेबल कर दीजिये आप।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): धन्यवाद।

(माननीय सदस्य श्री राजकुमार रोत (चौरासी) के सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-05 देखें)

श्री सभापति: श्री आलोक बेनीवाल।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 20, 21 और 22 पर आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका आभार। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज सदन में चर्चा चल रही है और सभी माननीय सदस्यों ने इस पर अपने-अपने विचार रखे। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो उस प्रदेश की आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करता है, उसके व्यक्तित्व के निर्माण का काम करता है। सरकारी क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक इसका जो गठन है, वह बहुत ही मजबूत होना चाहिए।

राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब और हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय बी.डी. कल्ला साहब ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी नवाचार किये हैं और शिक्षा के प्रचार और प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेकर इस प्रदेश की जनता और मेरे विधान सभा क्षेत्र को भी काफी सौगातें दी हैं। किसी जमाने में, आज से थोड़े साल पहले किसी माध्यमिक स्कूल को अगर उच्च माध्यमिक में कराना होता था तो एक या दो स्कूलें मिला करती थीं। माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी ने निर्णय किया कि जो माध्यमिक स्कूल्स हैं, उन सबको ही उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करेंगे। मेरे इलाके में 11-12 स्कूलें एक साथ क्रमोन्नत हुई थीं। यह कोई मामूली बात नहीं है। पांच साल, दस साल निकल जाते थे, इन स्कूलों के क्रमोन्नयन में समय बहुत निकल जाता था। ऐसे ही आठवीं से दसवीं की स्कूलें भी हुईं। कुछ स्कूलें हमारी प्राथमिक भी खुलीं। इंग्लिश मीडियम की स्कूलें भी हमारे यहां खूब अच्छी संख्या में खुली हैं।

राजस्थान के मुख्य मंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने खास तौर से जो अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में खोली हैं, वे कस्बाई क्षेत्रों में खुली हैं। माननीय सभापति महोदय, एक दिन में किसी चीज में परिवर्तन नहीं होता है, यह जो काम आज किया गया, यह आने वाले समय में उन परिवारों के लिए बहुत ही सुखदायी होगा। आज का समय ग्लोबलाइजेशन का है, पूरी दुनिया खुल गयी है। जब बच्चा प्राइमरी से लेकर सीनियर सैकंडरी में पढ़कर उच्च शिक्षा की तरफ जाता है, कहीं न कहीं उसे इंग्लिश की आवश्यकता पड़ती है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में यह ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में गेम चेंजर होगा। वे गरीब बच्चे, जो सोच नहीं सकते थे कि वे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी और

(श्री आलोक बेनीवाल)

मंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन गरीब के बच्चों का आपने ध्यान रखा। शिक्षा के क्षेत्र में गरीब को गणेश मानकर सरकार जो काम कर रही है, वह बहुत बड़ा काम है। मेरे यहां कई स्कूलें बन्द होने की कगार पर थीं। जब वे स्कूलें इंग्लिश मीडियम बनीं तो उनमें छात्र संख्या बढ़ी और वे पुनर्जीवित होकर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो गयीं। जिन स्कूलों में बीस से तीस बच्चे रह गये थे, मेरे यहां की पंचायत बास का टीबा में एक स्कूल है, उसमें आज 215 बच्चे हो गये हैं। अब इस आने वाले सैशन में और बच्चे बढ़ेंगे। इंग्लिश मीडियम स्कूलों की तरफ लोगों का काफी अच्छा रुझान हो रहा है। मैं शिक्षा मंत्री जी से इतना ही निवेदन करूंगा कि इसमें जो शिक्षकों का पदस्थापन है, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम जरूर करें। मेरे यहां जो स्कूलें खुली हैं, उनमें कहीं न कहीं अध्यापकों की कमी अभी भी है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह शुरुआती दौर है आने वाले समय में इनमें शिक्षक भी आएंगे और शिक्षण व्यवस्था भी अच्छी होगी।

साथ में, सब लोगों द्वारा हमारे सरकारी क्षेत्र की जो संस्थाएं हैं, इनके इन्फ्रास्ट्रक्चर की बहुत बात की गयी है कि कमरे नहीं हैं, चारदीवारी नहीं है। बहुत सारी चीजों की बात की गयी। मैं विधायक बना, उस समय मैंने स्कूलों के जब हालात देखे तो मैंने अपने विधायक कोष से इस पर काम करना शुरू किया था। मुझे इस बात की तसल्ली है कि मैंने पिछले चार साल के कार्यकाल में लगभग पचास स्कूलों में 5 करोड़ 11 लाख रुपये का काम अपने विधायक कोष से किया है। चाहे उसमें कमरे बनाने का काम हो, चारदीवारी के निर्माण का काम हो, चाहे हॉल बनाने का काम हो, चाहे कमरों की छत के रिपेयर का काम हो, बहुत सारे काम इन सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं में हमने किये हैं।

आज स्कूलों की स्थिति काफी सुधरी है और क्षेत्र की जनता और आम बच्चे जो वहां पढ़ने जाते हैं, उन्हें सुविधाएं भी मिली हैं, लेकिन हमारी भी एक लिमिटेशन है हमारा बजट जितना है उसमें और भी काम हमें करने पड़ते हैं। समसा के माध्यम से भी पैसा आता है, लेकिन, माननीय मंत्री महोदय, आपका विभाग बहुत बड़ा है और इसमें लाखों की संख्या में छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं। कौन लोग पढ़ते हैं, यह आप भली-भांति जानते हैं। मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने दस करोड़ रुपये हमें

(श्री आलोक बेनीवाल)

सड़क निर्माण के लिए दिये, चाहे वह रिपयेर कराएं या नयी बनाएं। एक ऐसा प्रावधान आप मुख्य मंत्री जी से और कराएं कि दस करोड़ रुपये हर विधान सभा क्षेत्र में स्कूलों के पुनर्निर्माण में आप विधायक कोटे से दे सकें। कोई बड़ा काम नहीं है। 200 विधान सभा क्षेत्र हैं, 10 करोड़ रुपये हैं, अब आप हिसाब लगा लीजिये, करीब 2 हजार करोड़ रुपये होता है, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूं अगर ये स्कूलें अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर के रूप में अच्छी तरह से डवलप होती हैं, छात्रों की संख्या भी बढ़ेगी और आपका शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। अभाव में पढ़ने से बच्चे-बच्चियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है।

(समय: 19.00 बजे)

एक चीज और भी है कि हमारी सरकारी क्षेत्र की जो संस्थाएं हैं, आप उनके सभी संस्था प्रधानों को पाबन्द करें कि उसमें पढ़ने वाले जो छात्र-छात्राएं हैं उनके अभिभावकों को समय-समय पर बुलायें, उनके साथ मीटिंग करें कि आपके जो बच्चे पढ़ते हैं, उनका शैक्षणिक स्तर क्या आ रहा है। यह जानकारी सबको देनी चाहिए और सब अभिभावकों को लेनी भी चाहिए। मैं जब भी स्कूल में जाता हूं तो निश्चित रूप से उन अभिभावकों से बात करता हूं उनसे कहता भी हूं, संस्था प्रधानों से भी कहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चे-बच्चियां जो आपके स्कूल में आते हैं उनके अभिभावकों को समय-समय पर बुलाया करें तथा उस बच्चे के शैक्षणिक स्तर को जांचने का काम करें। हमारे जो शिक्षक हैं, इस क्षेत्र में लगे हुए जो गुरुजन हैं, उनसे भी मैं प्रार्थना करता हूं कि यह विभाग सेवा का विभाग है और ये बच्चे हमारे आने वाले भविष्य के कर्णधार हैं। इनके प्रति आपका नजरिया कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो शिक्षक निश्चित रूप से अपने काम में लापरवाही करते हैं, उनके लिए तो आप कोई न कोई ऐसा रास्ता ढूंढे, जिससे उनको यह एहसास हो कि मैं अपने काम के प्रति निश्चित रूप से कोई गलती की है। तब जाकर इस शिक्षा व्यवस्था को हम जिस स्तर पर ले जाना चाहते हैं, उस स्तर पर ले जाने में हम सफल हो पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय का बहुत लम्बा राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव है और मैं उम्मीद करता हूं तथा मैं चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र की जो संस्थाएं हैं उनमें कम से कम इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम कहीं न कहीं अच्छी

(श्री आलोक बेनीवाल)

व्यवस्था के रूप में उभरकर आएं। आपने और तो नवाचार खूब कर दिये, स्कूल क्रमोन्नत कर दिये....

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): दो मिनट लूंगा सर।

स्कूल क्रमोन्नत कर दिये, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोल दिये, सब्जेक्ट खोल दिये और आने वाले समय में आप और काम भी करेंगे। मैं भी मेरे विधान सभा क्षेत्र की कई स्कूलों को क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव आपको निवेदन करूंगा, लेकिन इस काम के ऊपर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे तो ये स्कूलें अच्छी बनकर तैयार होकर हमारे साथ खड़ी हो पाएंगी। बन्द नहीं होंगी, बल्कि बच्चे इनमें बढ़ेंगे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत सारी स्कूलों को देखा है जिनके हालात खराब थे तथा आज सुधरे हैं तो उनमें बच्चे भी बढ़े हैं। इसलिए यह मैं आपसे, उच्च शिक्षा मंत्री जी से और माननीय मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा।

पिछले चार साल के बजट में मुझे एक महाविद्यालय राडावास में मिला है जो एकमात्र महाविद्यालय मिला है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे खेजरोली बहुत बड़ी पंचायत है, जिसकी लगभग 50 हजार की जनसंख्या है तथा उसके आस-पास और भी पंचायतें पड़ती हैं इसलिए वहां पर महाविद्यालय की बहुत ही आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से और मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मुझे, आपको, एक ही महाविद्यालय मिला है तो, मंत्री महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी को आप कहें कि मुझे एक ही महाविद्यालय मिला है, तो मैं चाहूंगा कि एक महाविद्यालय मेरे खेजरोली में आप खोलें, वह चाहे कन्या महाविद्यालय खोलें या को-एजुकेशन वाला महाविद्यालय खोलें, लेकिन महाविद्यालय वहां जरूर खोलें। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस काम में सक्षम हैं इसलिए इस काम में आप मेरी मदद जरूर करेंगे। वहां की जनता की मांग है क्योंकि आस-पास के क्षेत्र में कहीं भी सरकारी महाविद्यालय वहां नहीं है, जिससे बच्चों और बच्चियों को काफी दूर आना पड़ता है या प्राइवेट सैक्टर में जाना पड़ता है और यह हर किसी के वश की नहीं है कि वह प्राइवेट सैक्टर में पढ़ा सके। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि मेरी इस मांग को आप निश्चित रूप से पूरा करेंगे। धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री जोगिन्दर सिंह अवाना।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय सभापति जी, आज आपने मुझे मांग संख्या 20, 21 एवं 22 पर बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने 2023-24 के बजट में जो घोषणाएं की हैं उनके लिए मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बजट में उच्च शिक्षा के विस्तार को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालय एवं कन्या महाविद्यालय खोलने के लिए, जिसमें राजकीय महाविद्यालय 26 व कन्या महाविद्यालय 20 हैं, जिसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को और माननीय मंत्री जी का तहेदिल से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही यह बताना चाहूंगा कि इसी बजट में प्रदेश के मेधावी युवा अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए विश्व के प्रसिद्ध उच्च शिक्षण संस्थानों में उन्हें अध्ययन के अवसर देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी स्कालरशिप फोर एकेडेमिक एक्सीलेंस योजना शुरू की गयी है। इसी योजना के तहत पूर्व में 200 होनहार विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता दिये जाने का भी प्रावधान था जिसका दायरा बढ़ाते हुए 500 विद्यार्थियों को लाभान्वित किये जाने की घोषणा की गयी है, जो कि एक सराहनीय कदम है। युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में इंटर्न्स के रूप में भी सहयोग देने का प्रावधान किया गया है, जिसमें 25 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित किया गया है।

माननीय सभापति जी, इसी बजट में राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को देश-विदेश में प्रतिष्ठित संस्थाओं में रिसर्च एवं ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से टीचर्स इंटरफेस फोर एक्सीलेंस कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

मेरा जो नदबई विधान सभा क्षेत्र है, बजट में उसके लिए राजकीय कन्या महाविद्यालय की घोषणा की है, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का और माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही, यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई में क्षेत्र की बच्चियां उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए 20-25 किलोमीटर दूर बयाना, रूपवास व भरतपुर के महाविद्यालय में जाती थीं उनके लिए पिछले तीन बजटों में माननीय मुख्य मंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने मेरे विधान सभा क्षेत्र के चाहे नदबई

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

हो, चाहे उच्चैन हो, वहां 5-5 महाविद्यालय दिये हैं उसके लिए भी मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पहले बच्चियां या तो बयाना जाती थीं या भरतपुर जाती थीं जिनकी 25-30 किलोमीटर दूरी थी पर अब निश्चित तौर पर जो 5-5, 6-6 कालेज पिछले तीन बजट में खुले हैं उससे बच्चियों, बच्चों को बहुत बड़ा लाभ होगा।

माननीय सभापति जी, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए वर्तमान बजट में समस्त राजकीय विद्यालयों के कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को नि:शुल्क स्कूल यूनिफार्म दिये जाने की घोषणा की गयी है जिस पर 560 करोड़ रुपये का व्यय होगा, जो कि एक सराहनीय कदम है।

माननीय सभापति जी, प्रदेश में कुल 100 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने के साथ ही 300 विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने की तथा 300 विद्यालयों में नवीन विषय खोले जाने की जो घोषणा की है, इससे निश्चित रूप से शिक्षा का स्तर उच्च होगा। माननीय सभापति जी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कम्प्यूटर विज्ञान को ऐच्छिक विषय के रूप में दिये जाने का विकल्प दिया जायेगा, जो कि एक सराहनीय कदम है। प्रत्येक ब्लाक मुख्यालय पर एक-एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में चारों संकाय कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं कृषि की सुविधा उपलब्ध कराने की जो घोषणा हुई है वह भी एक अच्छा सराहनीय कदम है।

माननीय सभापति जी, राजकीय विद्यालयों में आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण एवं सुविधाओं के विस्तार हेतु माननीय मुख्य मंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत साहब द्वारा जो घोषणा की गयी है उसके लिए मैं उनका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। इसमें विस्तार करते हुए प्रदेश में 358 शैक्षणिक ब्लाकों का विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों हेतु लर्निंग एड सामग्री युक्त सन्दर्भ कक्षों का निर्माण करवाया जायेगा जिसकी बजट में घोषणा हुई है। माननीय सभापति जी, विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं यथा-क्लासरूम, लैब्स, शौचालयों के निर्माण तथा जर्जर भवन आदि के लिए 200 करोड़ व्यय करने की जो घोषणा हुई है, उसका भी मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं।

इसी बजट में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में एक-एक हजार महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और खोले जाने की भी जो घोषणा की है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल हैं उसमें

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

गरीब माता-पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते थे तो निश्चित तौर पर इसका एक बड़ा लाभ मिलेगा।

प्रदेश में विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय खोले जाने, जिनमें छात्रावासों की कुल 8 संख्या है, की घोषणा की है, उसका भी मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं।

माननीय सभापति जी, विधान सभा क्षेत्र नदबई के राजकीय प्राथमिक विद्यालय चकचोबा (कल्याणपुर) को क्रमोन्नत किये जाने की भी मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं। माननीय सभापति जी, इसी के साथ-साथ राजकीय प्राथमिक विद्यालय नगला परसा (भैंसा) जो लम्बे समय से, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय से बन्द पड़ा हुआ है, उसको प्रारम्भ करने की भी मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं। साथ ही माध्यमिक शिक्षा में नदबई विधान सभा क्षेत्र के कल्याणपुर में ग्राम पंचायत स्तर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की भी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं। उसके साथ-साथ, विधान सभा क्षेत्र नदबई में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खुड़ासा में विज्ञान संकाय के स्थान पर कला संकाय खोले जाने की भी मैं मांग करता हूं।

माननीय सभापति जी, विधान सभा क्षेत्र नदबई में नवीन सीबीईओ कार्यालय भवन के निर्माण हेतु राशि अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है मैं उसकी भी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं। साथ ही, विधान सभा क्षेत्र नदबई के उच्चैन में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोले जाने की भी मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं। उच्च शिक्षा विभाग में विधान सभा क्षेत्र नदबई की ग्राम पंचायत खानवा व झारोली में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की मांग करता हूं, क्योंकि आस-पास 10-15 किलोमीटर तक कोई सरकारी कालेज नहीं है और बच्चों को मजबूरन दूर जाना पड़ता है और दूर होने के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

माननीय सभापति जी, राजकीय महाविद्यालय, नदबई व उच्चैन को स्नातक से स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएशन) में क्रमोन्नत करने की भी मैं मांग करता हूं।

माननीय सभापति जी, आपने मुझे मांग संख्या 20, 21 व 22 पर बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुरेश टाक।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 20-प्रारंभिक शिक्षा, मांग संख्या-21 माध्यमिक शिक्षा और मांग संख्या-22 उच्च शिक्षा पर बोलने का मौका दिया।

मैं मेरी बात शुरू करने से पहले राज्य के मुखिया और लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी, हमारे शिक्षा मंत्री जी और हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में पूरे राजस्थान में ऐसे नवाचार किये।

आज शिक्षा पर चर्चा हो रही है और करीब-करीब सभी साथी एक कामन बात कह रहे हैं कि स्कूलें बहुत सारी खुली हैं, बहुत सारी स्कूलों को क्रमोन्नत किया है, संकाय खुले हैं, कालेज खुले हैं, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलना, पूरे भारत में एक माइलस्टोन वर्क हुआ तो इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करूंगा।

साथ ही, मैं मेरी बात की शुरुआत मेरे विधान सभा क्षेत्र से करूंगा कि आपने मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो कालेज दिये हैं, एक किशनगढ़ में बालिका महाविद्यालय और एक बोराड़ा में, अभी रिप्लाई में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बोराड़ा में एक कालेज दिया है। इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा।

साथ ही, माननीय मंत्री महोदय, आपने भी मेरी तकरीबन पचास स्कूलें क्रमोन्नत की हैं, जिसमें प्राथमिक से लेकर उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक, इसके लिए मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद करूंगा।

मैं एक बात से मेरी बात शुरू करूंगा। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो केवल रोजी-रोटी कमाना नहीं, बल्कि जीवन जीना सिखाये और यह तभी सम्भव होगा जब हमारी जो सरकारी स्कूलें हैं, उनका स्तर अच्छा हो। करीब-करीब हर सदस्य ने यह बात बोली है, स्कूलें जर्जर हैं, कमरे कम हैं, क्रमोन्नतियां हुई हैं जैसे-जैसे क्रमोन्नतियां हुई हैं उसी आधार पर स्कूलें बढ़ गई हैं कक्षा-कक्ष बढ़े हैं, उतनी बैठने की सुविधाएं नहीं हैं और अगर कहीं हैं तो वे पुरानी स्कूलें हैं, जर्जर हो गई हैं। माननीय मंत्री महोदय, इस बात पर आप विशेष तौर से ध्यान दें और इस पर निर्णय जरूर लें, अधिकारीगण भी सामने बैठे हैं।

विधायक को रिपेयर करने का पैसा अनुमत नहीं है, इसको आप अनुमत करा दें तो कम से कम विधायक उन स्कूलों को, जो जर्जर हो रही हैं, उनकी रिपेयर करा दें और बच्चे उनमें बैठ जायें, किसी तरह का हादसा नहीं हो। अभी

(श्री सुरेश टाक)

कुशलगढ़ से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा है कि कुछ दिन पहले उनकी स्कूल में हादसा हुआ, कैजुअल्टी होने से बच गई। ऐसी कोई स्थिति नहीं बने, विधायकों को आप अनुमत कर दें कि अपने विधायक फण्ड से वे स्कूलों की मरम्मत करा लें। यह एक बड़ा काम होगा।

साथ ही, अभी शाहपुरा से आने वाले मेरे साथी सदस्य ने बताया था कि जिस तरह से नगर परिषद् क्षेत्र में, नगरपालिका क्षेत्र में, नगर निगम में और गांवों में दस-दस करोड़ की सामूहिक रूप से सड़कें दी हैं, उसी तरह स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए भी, दस करोड़ नहीं तो पांच करोड़ रुपये प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र को दे दिये जायें तो भी स्कूलों का स्तर सुधर जायेगा।

हमारे राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में गरीबी रेखा से नीचे 80 प्रतिशत से ज्यादा लोग जीवनयापन करते हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं, वे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने नहीं जाते हैं। आज अगर प्राइवेट स्कूल फल-फूल रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी सरकारी स्कूलों में सुविधाओं का अभाव है और इसी वजह से प्राइवेट स्कूलों में लोग जा रहे हैं। जो सक्षम हैं, वे जा रहे हैं जो सक्षम नहीं हैं, वे ऐसे ही सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। हमारी सरकारी स्कूलों का जो स्तर है उसको बढ़ायें, उसको इतना अच्छा बनायें कि हमारे बच्चे वहां पढ़कर अपने आपको प्राउड फील करें और उनको लगे कि सरकारें हमारे स्कूल के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनका स्वाभिमान बढ़े और इस स्वाभिमान के साथ पढ़कर वे आगे बढ़ें।

मैं अपनी बात की शुरुआत एक बार वापस इसी बात से कहना चाहूंगा कि गरीबी को दूर करने का अगर कोई सबसे बड़ा माध्यम है तो वह शिक्षा है। अगर बच्चे शिक्षित हो जायेंगे तो वह परिवार आगे बढ़ेगा, शिक्षित नहीं होंगे तो वह परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी आती है कि सरकार उन स्कूलों को बहुत अच्छी तरह से विकसित करे।

आज बात शिक्षा की चल रही है और अगर मैं शिक्षकों पर बात नहीं करूं तो शायद उनके साथ अन्याय भी होगा। मैं धन्यवाद दूंगा सभी शिक्षकों को, पहली बात तो मैं मेरे उन गुरुजनों को धन्यवाद दूंगा। मैं भी गांव से पढ़कर इस विधान सभा तक पहुंचा हूं। गांव के एक स्कूल में पढ़ा और मेरे गुरुजनों की शिक्षा के बाद ही मुझे यह मौका मिला है। मेरे मतदाताओं के साथ-साथ मैं उन शिक्षकों का भी धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी और इस स्तर तक पहुंचाया। आज भी मैं शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं मेरे

(श्री सुरेश टाक)

गांव की स्कूलों को देखता हूं। ऐसे शिक्षक हैं जो अपने घर से ज्यादा अपनी स्कूलों को महत्व देते हैं। वे चाहे जा-जाकर भीख मांग लेंगे, वे भामाशाहों के पास जायेंगे, बच्चों को पढ़ाने के साथ-साथ वे यह कोशिश करेंगे कि हमारी स्कूल में सरकार से कोई सुविधा नहीं आ रही है तो मैं भामाशाहों के पास जाऊं, उनसे मैं मेरे बच्चों के लिए टीन शैड लाऊं, पीने के पानी की व्यवस्था करूं, कमरे में टाट-पट्टी, दरी-पट्टी, फर्नीचर या ऐसी कोई सुविधा, पंखा, कुछ नहीं है तो मैं लाकर लगाऊं। ऐसे हजारों उदाहरण हैं। आज उनका जिक्र नहीं करेंगे तो शायद उनके साथ अन्याय होगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा शिक्षा का क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। हम शिक्षकों को अलग-अलग ड्यूटियों में लगा रहे हैं, अलग-अलग काम में लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी उनका शिक्षा के प्रति फोकस रहना, यह उनका एक समर्पण है शिक्षा और बच्चों के साथ।

मैं धन्यवाद दूंगा सारे शिक्षकों को, पूरे राज्य के, पूरे भारत के शिक्षकों को कि वे अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम करके हमारी एक नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। जो देश के, राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देगी।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, एक बड़ा नवाचार हमारे राज्य में अंग्रेजी स्कूलों को खोलकर, हमारे बच्चों का कान्फिडेंस बढ़ गया है। इतनी लम्बी लाइन लगी हुई है। मुझे बार-बार जब भी बोलने का मौका मिलता है तो मैं यह बात कहता हूं कि एक बड़ा नवाचार है, जो अपने आप में इतिहास बन गया है। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुलने से बच्चों का कान्फिडेंस डवलप हुआ है और उनके पैरेंट्स भी प्राउड फील करने लगे हैं। वे हमसे सिफारिश मांगते हैं, लेकिन सिफारिश का सिस्टम ही नहीं है। आपने सिस्टम इतना बढ़िया कर दिया है कि लाटरी के बाद ही, लाटरी में अगर नम्बर आयेगा तो ही उसका एडमिशन होगा। यह एक पारदर्शिता है, जिससे कि कोई भी किसी तरह का आरोप नहीं लगा सकता है। इसको बनाये रखा जाए। लाटरी से ही बच्चों का एडमिशन हो, ताकि बच्चों को यह नहीं लगे कि हम किसी की सिफारिश से यहां आ गये या सिफारिश की वजह से हम आ जायेंगे। मैं इस नवाचार के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा।

आज मैं इस सदन में खुले मन से शिक्षक जगत को धन्यवाद देना चाहूंगा। सारा समाज शिक्षक जगत का ऋणी है। शिक्षक कम संसाधनों में भी अपनी शिक्षण स्कूल को चला रहे हैं।

(श्री सुरेश टाक)

माननीय मंत्री महोदय जी नहीं हैं। मंत्री महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा, इस बात को जरूर नोट कर लें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 पर एक स्कूल था। राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तारीकरण हुआ और उस विस्तारीकरण में 13 कमरों को तोड़ दिया गया। उन 13 कमरों को तोड़ा, लेकिन उसका जो पैसा है, 70 लाख रुपये, वे स्कूल को मिल गये हैं पर वे 70 लाख रुपये स्कूल के फंड में एफडी के रूप में जमा हैं। अगर उन 70 लाख रुपये की अनुमति फाइनेंस से मिल जाए तो वहां वे कमरे बन जायेंगे। बच्चे बहुत बुरी स्थिति में हैं। मैं कितने भी कमरे दे सकता हूं पर वे कम पड़ेंगे, जहां 13 कमरे टूट गये हों, आप अन्दाजा लगा लीजिए, वह स्कूल बचा ही नहीं। इसलिए 70 लाख रुपये के लिए विशेष तौर से मंत्री महोदय के यहां से फाइनेंस में पत्र चला जाये तो वह पैसा स्कूल को मिल जाए और उनसे उन कमरों का निर्माण हो जाये, ताकि बच्चे आराम से पढ़ सकें।

हम लगातार कोशिश करते हैं कि स्कूलों में टीन शैड की व्यवस्था हो, ताकि प्रार्थना स्थल अच्छे बनें। मैं हर स्कूल में देने का प्रयास कर रहा हूं। मैं एक आग्रह और करूंगा, जिस तरह अभी करीब-करीब सभी सदस्यों ने एक कामन-सी बात कही है, खेल के मैदान की चारदीवारी और स्कूल की चारदीवारी, जिस तरह खेल के मैदान की चारदीवारी, आप नरेगा में अनुमत कर रहे हैं, उसी तरह स्कूल की चारदीवारी को अगर नरेगा में अनुमत कर दें तो वे भी बनना शुरू हो जायेंगी और एक बहुतबड़ी समस्या से निजात मिल जायेगी।

प्राय: यह देखा जाता है कि गांवों में अतिक्रमण बढ़ रहा है। लोगों की नजर ऐसी खाली पड़ी जमीनों पर होती है, वे श्मशान को भी नहीं छोड़ते हैं, वहां खेल मैदानों को भी नहीं छोड़ा जाता है। वहां चरागाह पर अतिक्रमण कर लिया जाता है तो मैं चाहता हूं कि खेल मैदानों की चारदीवारी का निर्माण तो नरेगा से हो रहा है, स्कूल की चारदीवारी का निर्माण भी नरेगा से हो जाये तो शायद यह बहुत अच्छी व्यवस्था होगी।

कमरों का, कक्षा-कक्षों का निर्माण डी एम एफ टी फण्ड से हो, प्राथमिकता उसमें दी जाये ताकि हमारी स्कूलों की शिक्षा का स्तर बढ़े। हमारे स्कूल के भवन अच्छे हों तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे वहां जाने का प्रयास करेंगे, पैरेंट्स भी वहां भेजेंगे और बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ-साथ अच्छा माहौल मिलेगा।

(श्री सुरेश टाक)

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात को कह कर अपनी बात खतम करूंगा। पहले कुछ स्कूलें मर्ज हो गई थीं। मैं भी उसी बात में अपनी बात को जोड़ते हुए कहना चाहूंगा, कम से कम दो स्कूलें ऐसी हैं जो अनिवार्य रूप से वापस खुलनी चाहिए। एक मेरी शहरी क्षेत्र की स्कूल है जो मर्ज कर दी गयी बजरंग कालोनी में। पहले बजरंग कालोनी ग्रामीण क्षेत्र में थी, पेरिफेरी एरिया में थी, अब वह नगर परिषद् में शामिल हो गयी है। बजरंग कालोनी के लिए मैंने पत्राचार भी किया है और वहां पर 150 बच्चों ने अपनी सहमति दे दी है। पहले नामांकन के अभाव में वह स्कूल बन्द हो गया था। अब कम से कम 150 बच्चे हैं, जो पढ़ना चाह रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि उस कालोनी में नेशनल हाईवे 8 को क्रोस करके वे बच्चे आते हैं। आप अन्दाज लगा लीजिये छोटे-छोटे बच्चे पहले इस नेशनल हाईवे को क्रोस करेंगे, फिर रेलवे लाइन को क्रोस करेंगे, उसके बाद वो स्कूल में जायेंगे। पता नहीं कितनी ही दुर्घटनाएं हुई हैं, कितने एक्सीडेंट हुए हैं जिनमें उनके माता-पिता की या उनकी मृत्यु हो गयी है तो मैं बहुत विन्रमता के साथ आपसे आग्रह करता हूं इस बात पर ध्यान दें कि बजरंग कालोनी का एक स्कूल जो मर्ज हो गया है, उसको पुन: डीमर्ज कर दिया जाये। वहां पर अगर भवन की कोई दिक्कत हुई तो मैं भामाशाह को तैयार कर लूंगा, मेरे विधायक फंड से लगा दूंगा, पर वहां स्कूल चालू हो जाये। आप सहमति दे दीजिये, बाकी काम हम सब अपने आप कर लेंगे। हमारा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है, बहुत सारे भामाशाह ऐसे तैयार हैं जिनसे मैं स्कूल के कमरे बनवा कर एक बार स्कूल को चालू करवा सकता हूं।

इसी तरह एक ग्रामीण क्षेत्र का पूर्व प्राथमिक विद्यालय, डोरिया जो जीरोदा पंचायत में आता है, 2017 में यहां से शिक्षकों को हटा दिया था, क्योंकि यहां पर बच्चों के नामांकन का अभाव था, पर यूडाइस कोड आज भी वो ही है, परन्तु इस विद्यालय की एनआईसी आईडी व पासवर्ड शाला दर्पण पोर्टल पर दर्शा नहीं रही है, इसलिये विद्यार्थियों का दाखिला वापस नहीं हो पा रहा है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वहां भी सौ से अधिक अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो इसको पुन: संचालित करने के लिए इसका एनआईसी कोड शाला दर्पण पोर्टल पर चालू कर दिया जाये ताकि वहां पर नामांकन स्टार्ट हो जाये। बहुत छोटा-सा काम है और इस काम को मैं समझता हूं कि इस बजट सत्र के साथ-साथ ही पूरा कर दिया जाना चाहिये।

(श्री सुरेश टाक)

विद्यालयों में शिक्षकों की कमी आम बात है। मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत जल्दी शिक्षकों की कमी पूरी होगी जिससे बच्चों को उच्च शिक्षा मिले, शिक्षा गुणवत्तापूर्ण मिले और वे यह नहीं समझें कि यहां शिक्षकों के अभाव में प्राइवेट स्कूल में जाना पड़े।

श्री सभापति: श्री रामलाल मीणा।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): एक मिनट में खतम कर रहा हूं, सर।

मैं शिक्षक के पदों के साथ-साथ हमारे जो स्कूल हैं उनकी क्रमोन्नति की बात भी करना चाहूंगा। सबसे पहले प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए मेरे दो स्कूल हैं देवपुरी, पचीपलां और गोठियाणा मालियों की ढाणी, कुचील में, इनको प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत किया जाये। उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नति के सम्बन्ध में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खंडाच, ग्राम पंचायत डीडवाना, सबसे पहली प्राथमिकता खंडाच को दी जाये, क्योंकि यहां पर जमीन के साथ पूरी बिल्डिंग बनाने के लिए आरके मार्बल चैरिटेबल ट्रस्ट ने सहमति दे दी है, वह पूरी बिल्डिंग अपनी जमीन पर बनाने को तैयार है, इसलिये इस राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खंडाच को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाये। गुजरवाड़ा जोगियान ग्राम पंचायत डामोलाव की डांग स्कूल, टिहरी चिताखेड़ा।

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्य, सहयोग करें प्लीज।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): जी। बस एक मिनट में कर रहा हूं।

मैं कालेज के लिए एक बात कहना चाहूंगा। मैं धन्यवाद के साथ मंत्री जी को यह धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे दो कालेज दे दिये। एक कालेज स्टार्ट हो गया है पिछले साल ही महिला कालेज हमारे किशनगढ़ का गर्ल्स कालेज और अभी बोराड़ा, माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया है। गर्ल्स कालेज की बिल्डिंग का निर्माण भी हो रहा है पर वहां पर कुछ कमियां हैं। मैं उन कमियों को आपसे निवेदन करना चाहूंगा। राजकीय कन्या महाविद्यालय, किशनगढ़ के प्राचार्य, पीटीआई, पुस्तकालयाध्यक्ष, कार्यालय लिपिक और लेखाधिकारी का एक-एक पद स्वीकृत है, किन्तु ये सारे पद रिक्त हैं, अब इनको नियुक्ति दी जाये, क्योंकि अगले साल एक क्लास बढ़ जायेगी सैकण्ड ईयर स्टार्ट हो जायेगा। छात्राओं के लिए राजनीतिक विज्ञान और समाज शास्त्र व चित्रकला के अतिरिक्त विषय खोले जायें, जिससे छात्राओं की मांग पूरी हो

(श्री सुरेश टाक)

सके। भूगोल विषय, गृह विज्ञान विषय के प्रायोगिक सामान क्रय करने के लिए बजट में प्रावधान किया जाये, जिससे हमारी बेटियों को पढ़ने के लिए सुविधाएं मिल सकें। हमारा अरांई कालेज बहुत समय से चल रहा है। पिछले पांच साल से कालेज चल रहा है, लेकिन अभी तक भी अरांई कालेज के छात्र परीक्षा देने के लिए किशनगढ़ आते हैं, तो अरांई को परीक्षा सेन्टर बनाया जाये, ताकि कालेज खोलने की सार्थकता हो सके। जब कालेज वहां खुल गया, शिक्षा वहां हो रही है, सब कुछ वहां हो रहा है लेकिन एग्जाम देने के लिए अगर अरांई से किशनगढ़ आना पड़ा तो वहां कालेज खोलना भी मेरे को लगता है कि ठीक नहीं है। राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ़ में छात्रों की मांग को देखते हुए..

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। प्लीज सहयोग करें।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): ...एमएससी गणित और एमएससी बाटनी विषय खोले जाने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।

श्री सभापति: श्री रामलाल मीणा।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 20, 21 व 22 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो माननीय शिक्षा मंत्री जी को और उच्च शिक्षा मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ ही माननीय मुख्य मंत्री जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप प्रतापगढ़ के अन्दर शिक्षा के क्षेत्र में वो क्रान्ति लाये हो, जिससे मेरे प्रतापगढ़ क्षेत्र की पूरी जनता आपकी हमेशा आभारी रहेगी। आपने इतने स्कूल क्रमोन्नत किये जो आज तक कभी नहीं हुए भले ही वो प्राथमिक से उच्च प्राथमिक का हो या उच्च प्राथमिक से डायरेक्ट बारहवीं तक का स्कूल हो। सारे स्कूल अधिकतम, मैं तो यह मानता हूं कि लगभग सभी सदस्यों में सबसे ज्यादा स्कूल मेरे क्रमोन्नत हुए हैं इसलिये मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

साथ ही, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और उच्च शिक्षा मंत्री जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले कई वर्षों से एक भी कालेज प्रतापगढ़ के अन्दर नहीं खुला, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने इन चार साल के कार्यकाल में मुझे सात कालेज देकर के प्रतापगढ़ की जनता के ऊपर

(श्री रामलाल मीणा)

बहुत-बड़ा उपकार माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी करती है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अन्दर प्रतापगढ़ के अन्दर एक भी कालेज नहीं खुला। एक पीजी कालेज था, वह भी जब हरलाल जी मीणा, जब कांग्रेस के एमएलए थे उस समय का था लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने उन सभी कमियों को पूरा करते हुए सात कालेज, भले ही वह कन्या महाविद्यालय हो, भले ही वह पीपलखूंट महाविद्यालय हो, भले ही वह दलोड़ का महाविद्यालय हो, भले ही वह नर्सिंग महाविद्यालय हो, भले ही वह कृषि महाविद्यालय हो, भले ही वह संस्कृत महाविद्यालय हो, यहां तक कि मेडिकल कालेज भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने राज्य मद से दिया है, क्योंकि पिछले दो वर्ष पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि राज्य और केन्द्र की मद से प्रतापगढ़ के अन्दर मेडिकल कालेज की स्थापना की जायेगी, लेकिन हमारे यहां के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिल्ली में जाकर कह दिया कि प्रतापगढ़ तो आदिवासी क्षेत्र है, छोटा-सा जिला है, वहां मेडिकल कालेज खोलने का कोई औचित्य ही नहीं है।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी को हमारे तत्कालीन चिकित्सा मंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और अभी वाले चिकित्सा मंत्री जी भी हैं, तीनों ने मिल करके उस समय यह घोषणा करवाई थी लेकिन उस समय नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी ने राज्य मद से मेडिकल कालेज की घोषणा की। यह हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है।

आज मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाह रहा हूं कि, माननीय मंत्री महोदय, प्रतापगढ़ जिला ट्राइबल जिला है, सात कालेज आपने दे दिये, बहुत बड़ा उपकार प्रतापगढ़ की जनता के ऊपर आपने किया है, लेकिन प्रतापगढ़ जिले में बिल्डिंग बन चुकी है, साथियों। आपकी जैसे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कालेज अभी खुलता और पांच-दस साल तक बिल्डिंगों की कोई सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन आज कन्या महाविद्यालय की डबल मंजिल की छत भरी जा रही है। नर्सिंग कालेज की बिल्डिंग बन रही है, दलोड़ कालेज की बिल्डिंग बन रही है, पीपलखूंट कालेज की बिल्डिंग बन रही है। मैं इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आज अभी का जो बजट है उस पर भी कार्यवाही होना चालू हो गयी है।

आप यह कहते रहते हो कि हमको कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया।

(श्री रामलाल मीणा)

मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान और माननीय मुख्य मंत्री जी उधर का काट कर सारा का सारा इधर दे दो, क्योंकि उधर वाले मानने वाले तो हैं नहीं वैसे भी। (व्यवधान) आज सबका साथ सबका विकास नहीं, खुद का विकास। आज मोदी जी की बात आप कर रहे हो लेकिन जो स्थिति न खाऊंगा न खाने दूंगा, यह काम माननीय मोदी जी ने किया था। आपने मोदी जी की बात की थी, तो हम तो पांच सौ रुपये में सिलेण्डर दे रहे हैं, आपने पचास रुपये तो गैस सिलेण्डर घर की रसोई वाले के बढ़ा दिये और साढ़े तीन सौ व्यावसायिक वाले के बढ़ा दिये। अब जनता के फांसी लगाना ही बाकी रख दिया। इसके अलावा आपने क्या रखा है? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): उज्ज्वला योजना की बात आप कर रहे थे, लेकिन उज्ज्वला योजना के अन्दर आपने कुछ भी नहीं किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, यह एजुकेशन पर है? शिक्षा की मांग पर है यह?

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): लोगों को गैस की टंकियां बांटने का काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राहुल गांधी जी को और माननीय मुख्य मंत्री जी को आपने पांच सौ रुपये में गैस का सिलेण्डर देकर पूरे घर का, पूरा माताओं-बहनों का आपने ध्यान रखा है नहीं तो ये आज माताएं-बहनें लकड़ी के चूल्हे में ही आंखें फोड़ती रहतीं। (व्यवधान) बढ़िया किया पचास और साढ़े तीन सौ रुपये बढ़ा कर, जनता में जाओगे तो बता देगी जनता आपको।

श्री सभापति: इधर, इधर आसन की तरफ।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा खुद का गांव बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र ...

श्री सभापति: अपने क्षेत्र की बात कर लो, आकाश-पाताल मत बांधो, वरना टाइम पूरा हो जायेगा।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): जी। शुरुआत ये ही करते हैं, साहब।

श्री सभापति: आप इधर देखो।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा मेरा खुद का गांव बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है, उस गांव में प्राथमिक विद्यालय नहीं है। वहां प्राथमिक विद्यालय खोलें और

(श्री रामलाल मीणा)

राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय, पानमोड़ी के अन्दर मांग करता हूं, राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय, पानमोड़ी की मांग करता हूं। राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय, सेलारपुरा में मांग करता हूं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, दलोट की मांग करता हूं, क्योंकि दलोट में हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिया और वहां एक हिन्दी मीडियम स्कूल भी है, लेकिन हिन्दी मीडियम स्कूल 8-12 तक है जिससे 1-8 तक के बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनके लिए अलग से विद्यालय खोला जाये।

मैं प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की मांग कर रहा हूं। प्राथमिक विद्यालय, पुन्याखेडी; प्राथमिक विद्यालय, खेरमगर; प्राथमिक विद्यालय, नागदेडा; प्राथमिक विद्यालय, सातमहुडी; प्राथमिक विद्यालय, चौकलीपीपली; प्राथमिक विद्यालय, सीतामगरी; प्राथमिक विद्यालय, लालपुरा; प्राथमिक विद्यालय, मोरुंडी; प्राथमिक विद्यालय, परवी पाड़ा; प्राथमिक विद्यालय, धनियारूडी; प्राथमिक विद्यालय, छायण; प्राथमिक विद्यालय, मदपुरी; प्राथमिक विद्यालय, अंधारिया बड़ला; प्राथमिक विद्यालय, शोली हनुमान जी; प्राथमिक विद्यालय, सात सहेलियां; प्राथमिक विद्यालय, उकाला; प्राथमिक विद्यालय, देवलदी; प्राथमिक विद्यालय, मचलाया; प्राथमिक विद्यालय, अचनपुरिया; प्राथमिक विद्यालय, सुजानपुरा; प्राथमिक विद्यालय, मोटीपुटवास को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की मैं मांग करता हूं।

माननीय मंत्री महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, करोली एक सूची में क्रमोन्नत हो गया था, लेकिन बाद में वह वापस विलोपित हो गया था। इससे वहां के लोगों में नाराजगी है, इसलिए उसको भी उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाये। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जाम्बुवेला जो बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है और सीतामाता बेरन में पड़ता है, वहां 12-15 किलोमीटर के आस-पास में कोई उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है, वहां के बच्चे 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, इसलिए इस स्कूल को भी उच्च माध्यमिक विद्यालय में करने की कृपा करें। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रिछावरा; राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, मोखमपुरा; राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, टाडा जो कुलमीपुरा, बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है, इनको भी उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत की मांग करता हूं।

(श्री रामलाल मीणा)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री महोदय से झोली फैला कर मांग करता हूं, प्रतापगढ़ क्षेत्र की जनता की तरफ से मैं याचना कर रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत कुछ दिया है जो दिया है उसका उपकार जिंदगी भर तक मेरे क्षेत्र की जनता नहीं भूल सकती है। पूरे टीएसपी क्षेत्र के युवाओं की तरफ से मांग कर रहा हूं कि आज नोन टीएसपी के कार्मिक अवैध तरीके से प्रतापगढ़ और टीएसपी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। वह खुद भी अपने क्षेत्र में जाना चाहते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी और आपकी भी इच्छा है, तत्कालीन शिक्षा मंत्री हमारे डोटासरा साहब की भी इच्छा थी कि उनको जल्दी से जल्दी अपने गृह क्षेत्र में भेजकर वहां के स्थानीय युवाओं को नौकरी लगाया जाये। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से हाथ जोड़ कर मेरा निवेदन है कि नोन टीएसपी के शिक्षकों को जल्दी से जल्दी टीएसपी क्षेत्र में भेजकर वहां के स्थानीय बेरोजगार युवाओं को नौकरी लगाने का काम करें। माननीय मंत्री महोदय, यह बहुत बड़ी और विशेष मांग है, इसका पूरा-पूरा ध्यान रखें।

आज पहली बार राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई है। पहले हम सुनते थे कि प्राइवेट स्कूलों में वार्षिक उत्सव होता है, लेकिन राजस्थान की गहलोत सरकार ने एक आदेश जारी करके यह निर्देश प्रदान किये कि हर स्कूल में वार्षिक उत्सव होगा। आज हम सब स्कूलों में जाते हैं तो देखते हैं कि इतने बढ़िया तरीके से कार्यक्रम होते हैं। लोगों में यह धारणा बैठने लगी कि अब प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में कोई भेद नहीं है। आज आपने देखा होगा, गरीब का बच्चा सपना तक नहीं देखता था कि मुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का मौका मिलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी को और तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी को कि आपने गांव-गांव में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोल कर उस गरीब के बच्चे को एक लाख रुपये नहीं देने पड़े, पचास हजार रुपये नहीं देने पड़े और सीधे इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है, यह पहली बार मुझे देखने को मिला। मेरे यहां आधे स्कूल सिटी में खुले और आधे स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में खुले। तीन स्कूल पहली बार खुले, उसमें से एक स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में खुला। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों में इंग्लिश स्कूल के प्रति जल्दी रुझान नहीं बना तो आधी सीटें खाली रह गईं। सिटी के लोगों को पता लगा कि वहां अंग्रेजी माध्यम स्कूल में सीटें खाली हैं, पहली बार प्राइवेट बस करके सिटी के बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में इंग्लिश

(श्री रामलाल मीणा)

मीडियम की पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। इतना बढ़िया काम शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी एवं शिक्षा मंत्री जी ने किया है, इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

आज चाहे साइकिल बांटने का काम हो या स्कूटी बांटने का काम हो, पोशाक बांटने का काम हो। मैं एक स्कूल में गया और एक छोटे से बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा, तेरे मां-बाप का क्या नाम है? उसने कहा कि मेरे मां-बाप का नाम तो यह है। मैंने कहा तीसरा बताओ, उसने कहा कि अशोक गहलोत भी हमारे मां-बाप हैं, क्योंकि कपड़े देने का काम माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है। छोटे-छोटे बच्चों को दूध पिलाने का काम माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है। (व्यवधान) दूध या तो मां पिलाती है या गहलोत साहब ने पिलाया है, इसमें क्या बात है? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): साथियों, आप चाहे कुछ भी कह दो, लेकिन जो काम पिछले चार साल में माननीय मुख्य मंत्री जी एवं शिक्षा मंत्री जी ने किये हैं, हमारे शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्य मंत्री जी एवं उच्च शिक्षा मंत्री जी की पूरी विशेष कृपा प्रतापगढ़ पर है। मैंने जो छोटा-सा निवेदन टीएसपी क्षेत्र के लिए किया है, उसको आप जल्दी से जल्दी पूरा करा दीजिए। इससे सभी तरह से फायदा हो रहा है, वहां के युवा भी प्रसन्न हो रहे हैं और वहां जो कार्मिक लगे हुए हैं, वह भी प्रसन्न हो रहे हैं, इसलिए यह काम किसी भी हालत में जल्दी से जल्दी हो जाये, मैं यही मांग करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गणेश घोघरा।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 20, 21 और 22 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार जो हमारे गांव के गरीब लोग थे, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में इतनी मोटी फीस नहीं दे सकते थे, आज वह इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं टीएसपी क्षेत्र की, जनजाति बहुल क्षेत्र की बात करूंगा, हमारी जो शहीदों और वीरों की भूमि है, वीरबाला, कलासुआ (भील) कालीबाई को नमन करता हूं जिस

(श्री गणेश घोघरा)

साक्षरता की देवी ने हमारे टीएसपी में, पूरे उदयपुर संभाग में शिक्षा का अलख जगाया। किसी समाज को आगे बढ़ना हो, किसी वर्ग को आगे बढ़ना हो, जिस क्षेत्र में शिक्षा है, वह समाज भी आगे बढ़ा है, वह क्षेत्र भी आगे बढ़ा है और वहां विकास भी हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा कि इन्होंने कई बातें कीं। अशोक गहलोत जी ने हर पंचायत में 2-3 राजीव गांधी स्कूल खोली थीं, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने नाम बदलने का काम किया। इनकी सरकार में 21 हजार स्कूलों को बंद करने का काम इन्होंने किया। वहां आदिवासी बहुल क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र है, नदी-नाले हैं, उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि गरीब का बच्चा कैसे पढ़ने जायेगा। यह भारतीय जनता पार्टी एस टी, एस सी, ओ बी सी के बिलकुल खिलाफ है। यह नहीं चाहते हैं कि दलित का, आदिवासी का बच्चा आगे पढ़कर होशियार बने, यह इनकी सोच है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय दिया, विधि महाविद्यालय दिया, रामसागड़ा में कालेज खोला, पालदेवल में कालेज खोला। जो भी मांगा, मुख्य मंत्री जी ने पूरा दिल खोल कर दिया। कई स्कूल क्रमोन्नत भी हुई हैं। माननीय सभापति महोदय, प्रारंभिक शिक्षा में बच्चे स्कूल पढ़ने आते हैं, हमारे एस टी के बच्चे काफी आगे भी बढ़े हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज मैं मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि आज कुक-हैल्पर को खाली 1700 रुपये मिलते हैं और उसमें भी कभी-कभी तीन चार महीने हो जाते हैं, समय पर उसका भुगतान नहीं होता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे राजस्थान के कुक-हैल्परों की तरफ से मांग करना चाहूंगा कि उनका कम से कम मासिक मानदेय 9000 कराया जाये। स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भी आवश्यकता है। मैं कई स्कूलों में जाता हूं तो देखता हूं कि वहां बच्चे झाड़ू निकालते हैं बच्चे ही पानी पिलाते हैं। इसलिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बहुत ही आवश्यकता है, इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि चतुर्थ श्रेणी की भर्ती की जाये।

माननीय सभापति महोदय, कई स्कूलें जर्जर अवस्था में हैं। कई स्कूलों में कमरों की भी आवश्यकता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्कूलों के कमरों की मरम्मत और नये कमरों की भी मांग करना चाहूंगा। एक विशेष

(श्री गणेश घोघरा)

मांग, जो हमारे साथी विधायक रामलाल जी मीणा ने की है, नोन टीएसपी के शिक्षक, जो वर्षों से हमारे टीएसपी क्षेत्र में लगे हुए हैं, 20-25 साल हो गये हैं, वे भी अपने क्षेत्र में आना चाहते हैं। वे भी परेशान हैं, वे भी दुःखी हैं। हमारे सब जनप्रतिनिधि भी चाहते हैं कि नोन टीएसपी के शिक्षक आ जायें और हमारे वहां जो टीएसपी के बेरोजगार युवा हैं, उनको वहां पर नौकरी मिले, यह मैं सरकार, मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द नोन टीएसपी के शिक्षकों का स्थानान्तरण उनके गृह क्षेत्र में किया जाये।

साथ ही, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बीएलओ, पांचवीं तक की एक स्कूल में एक या दो टीचर हैं, उसमें से एक शिक्षक को बीएलओ की ड्यूटी दे रखी है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वह बीएलओ पता नहीं किस-किस के घर जा रहा है, कौनसे नाम जोड़ रहा है, लेकिन पूरा समय, इससे स्कूल के बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बीएलओ के काम के लिए शिक्षकों से हटाकर कोई और व्यवस्था की जाये, मेरा ऐसा मानना है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ स्कूल क्रमोन्नत करने हैं, उनकी मैं मांग करता हूं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सलियाट को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करें। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पिथापुर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में; राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, घोगरा फला पालदेवल को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में; राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, उन्दरड़ा को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में; राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, डेंडली को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में; राजकीय प्राथमिक विद्यालय बोड़ा डूंगरा को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में; राजकीय प्राथमिक विद्यालय, घाटाफलां को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में; राजकीय प्राथमिक विद्यालय, टेबरनफलां को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में; राजकीय प्राथमिक विद्यालय, टेंगरवाड़ा को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में; राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पुनरावाड़ा को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में; राजकीय प्राथमिक विद्यालय, नया तालाब को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में; राजकीय प्राथमिक विद्यालय, हिंडवाफलां को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में; राजकीय

(श्री गणेश घोघरा)

प्राथमिक विद्यालय, पावड़ा को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में; राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पांच महड़ी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में; राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कण्डूला को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में; राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, महादेव फलां को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में; राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बोलादरा को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय जी से और हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत जी से मांग करता हूं।

साथ ही, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ स्कूलों में संकाय खोलने की मांग रखता हूं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मझोला में कृषि एवं विज्ञान संकाय खोला जाये। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रोहनवाड़ा में कला संकाय खोला जाये। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गड़ा मोरैया में कला संकाय खोली जाये। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जालुकुआं में कृषि संकाय खोली जाये। शहीद कालिया मनाक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पालेदवल में कृषि संकाय खोली जाये। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, घूघरा में विज्ञान संकाय खोली जाये। मंत्री जी से ये मेरी मांग है और सरकार से निवेदन है।

साथ ही में, बिछीवाड़ा राजकीय महाविद्यालय है, उसमें मैं उच्च शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा और मांग करना चाहूंगा कि यूजी कला वर्ग को पीजी किया जाए। साथ ही, वहां पर विज्ञान वर्ग भी किया जाये, क्योंकि वहां से मुख्यालय काफी दूर पड़ता है, गाड़ी भी नहीं मिलती है, पैसे भी लगते हैं। वहां से छात्र-छात्राएं समय पर नहीं पहुंच पाते हैं और उनको शिक्षा लेने में दिक्कत आती है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि बिछीवाड़ा कालेज को पीजी किया जाये और वहां पर विज्ञान संकाय खोली जाये। वहां पर जो दूरदराज के गांवों से आते हैं, वे बच्चे किराये पर कमरा लेकर नहीं रह सकते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। वहां बिछीवाड़ा में छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग हॉस्टल की व्यवस्था की जाये।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त कीजिये।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): एनएसएस, राष्ट्रीय सेवा योजना, इसी के साथ ही बच्चों को पुलिस में भर्ती के लिए, मिलिट्री में भर्ती के लिए कालेज में एनसीसी का पाठ्यक्रम चलाया जाये। यह मैं मांग करना चाहूंगा। हमारे डूंगरपुर

(श्री गणेश घोघरा)

में भोगीलाल पंड्या एक ही महाविद्यालय है, वहां पर कमरों की हालत खराब है, जर्जर अवस्था में है। सभी कालेजों में, भले ही भोगीलाल पंड्या हो, पालदेवल हो, बिछीवाड़ा हो, रामसागड़ा हो, इनमें व्याख्याताओं के जो रिक्त पद हैं, वे जल्दी से जल्दी भरे जायें। जैसे कि जैलाणा स्कूल है, कई सारी स्कूलें हैं, उनमें भी शिक्षकों के काफी पद रिक्त हैं, वे रिक्त पद जल्दी से जल्दी भरे जायें। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी, आप तो हमारे क्षेत्र को जानते हैं, पहाड़ी एरिया है, आप वहां पर काफी रहे हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे वहां की तकलीफ देखकर, वहां के लोगों की समस्याओं को देखते हुए वहां की स्कूल क्रमोन्नत करें और कमरों की जो भी आवश्यकता है, उसे पूरी करने की कृपा करें। यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, आपने मुझे शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय की मांग संख्या 20, 21 और 22 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, जो कुछ भी हमने स्कूलों से सीखा है, वह सब कुछ भूल जाने के बावजूद भी जो याद रहता है, वही शिक्षा है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह कहा है, शिक्षा का सही उद्देश्य तथ्यों को नहीं, बल्कि मूल्यों को सीखना और मूल्यों का ज्ञान है। शिक्षा व्यक्ति की पहचान बनाती है।

श्री सभापति: कृपया शान्त रहें, उनको बोलने दें। आपस में वार्ता नहीं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): शिक्षा से व्यक्ति में विवेक उत्पन्न होता है और यही विवेक उसे अच्छे और बुरे को सोचने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए शिक्षा कितनी आवश्यक है, यह हम सब लोग बहुत भलीभांति जानते हैं।

चूंकि आज शिक्षा के तीनों ही स्तरों पर चर्चा हो रही है। सभापति महोदय, शिक्षा के तीनों स्तरों में से प्राइमरी एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण है। जब मैं प्राइमरी एजुकेशन की बात करती हूं और कई बार मुख्य मंत्री जी को सुनती हूं तो मुख्य मंत्री जी ने दोतीन बार इस बात का उल्लेख किया है कि राइट-टू-एजुकेशन का बिल, यदि कोई लाये तो यूपीए गवर्नमेंट लेकर आयी। यदि राइट-टू-फूड का बिल कोई लायी तो यूपीए गवर्नमेंट लेकर आयी और अब

(श्रीमती अनिता भदेल)

स्वास्थ्य के अधिकार का बिल कोई लेकर आयेगा तो कांग्रेसनीत सरकार ही लाने वाली है, पर क्या राइट-टू-एजुकेशन बिल से सारी समस्याओं का समाधान हो गया?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम, 2009 के द्वारा शिक्षक छात्र अनुपात में अध्यापकों की उपलब्धता, खेल मैदान, पर्याप्त कक्षा-कक्ष, बालक-बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय, पुस्तकालय, पेयजल और शारीरिक रूप से अक्षम बालक-बालिकाओं के लिए निर्बाध पहुंच आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथसाथ इसको लागू करना, हमने किस हद तक और कितनी मंशा के साथ में इसको लागू किया है। कानून बना देना बहुत आसान है, क्योंकि उसमें सिर्फ नियम बनाने हैं। उसको विधान सभा या लोक सभा से पारित कराना है। उसमें पैसा लगने वाला नहीं है। उसमें बजट नहीं लगने वाला है। जिस चीज में पैसा नहीं लगे, वह कानून बना दो, फिर उस कानून की पालना, 2009 से आज 2023 चल रहा है। लगभग 13-14 साल व्यतीत होने के बावजूद भी आज इतने सारे माननीय सदस्यों ने शौचालय की बात की, पीने के पानी की बात की, बिजली की बात की, कक्षा-कक्षों की बात की, खेल के मैदान की बात की। जब हमने कानून बना दिया और इस कानून को बनाये हुए 13 साल हो गये। धरातल पर हमने क्या दिया है?

आज भी हमारे स्कूलों में ड्राप-आउट की समस्या है। अभी डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि सरकार ने मिड-डे-मील की व्यवस्था की है। मिड-डे-मील होने के बावजूद भी ड्राप-आउट क्यों है? माननीय मुख्य मंत्री जी ने दूध की योजना को चार साल बन्द रखने के बाद अब पुन: चालू कर दिया है। पर, पहले तो चार साल बन्द क्यों किया और अब पुन: चालू किया है तो ये करप्शन मुक्त कैसे हो सकता है?

माननीय मंत्री महोदय, आप शिक्षा में बहुत विद्वान हैं प्रशासनिक दृष्टि से आप बहुत सिद्ध हस्त हैं। उसके बावजूद भी आपने अपनी स्कूली एजुकेशन में, शिक्षा में कभी करप्शन नहीं देखा होगा, लेकिन अब शिक्षा में भी करप्शन आ गया है। पाउच वाले पाउडर से करप्शन नहीं होगा क्या? मेरा आपसे निवेदन है, आपको सुझाव है कि जो व्यवस्था माननीया वसुन्धरा जी ने प्रारम्भ की थी कि सहकारी दुग्ध समितियों से, वहीं गांव से ही दूध खरीदते थे,

(श्रीमती अनिता भदेल)

गरम करके बच्चों को पिलाते थे, उसमें करप्शन नहीं होता था। यह पाउच निश्चित रूप से करप्शन का कारण बनेंगे। आधे बच्चों को तो बंटेगे और आधों की बंदरबांट होगी। मेरा निवेदन है कि इस व्यवस्था को चेंज करे। ताजा दूध गांव से कलेक्ट होता है, वही बच्चों को दिया जाए, तो मुझे लगता है कि ड्राप आउट की समस्या है, उस ड्राप आउट की समस्या से हम किसी हद तक निजात पा लेंगे। दोपहर भोजन की व्यवस्था तो इसी कारण से हुई थी न कि बच्चों का नामांकन तो हो जाता है, लेकिन बीच में स्कूल छोड़कर चले जाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, बालिकाओं का स्कूल छोड़ने का क्या कारण है? हम बालिका शिक्षा पर जोर दे रहे हैं। मानव की आधी आबादी महिलाएं हैं, यदि उसको शिक्षित नहीं किया तो आपका समाज पिछड़ा का पिछड़ा रह जाएगा। इसलिए इस आधी आबादी को शिक्षित करने के लिए, स्कूली एजुकेशन तो बहुत जरूरी है। स्कूली एजुकेशन कैसे मिले, वह स्कूल जाए तो शौचालय नहीं है, शौचालय है तो उसमें पानी नहीं है। पानी नहीं है तो शौचालय का उपयोग वह कर ही नहीं सकती। विशेष दिनों में स्कूल जाने में उसको शर्म आती है, स्कूल नहीं जाती। अगर 3-4 दिन या एक सप्ताह स्कूल नहीं गई तो यह समझ लो कि 15 दिन तक वह स्कूल नहीं जाएगी।

स्कूलों में बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। आप देखिएगा, मैं उदाहरण से आपको बताना चाहती हूं। स्कूल में बलात्कार की घटनाएं 3 साल में, राज्य के विभिन्न ज़िलों में बालिका के साथ जो घटनाएं हुई हैं, उसके 133 मामले पंजीबद्ध हुए हैं। अब ऐसे में वह बालिका स्कूल कैसे जाए। मां-बाप कैसे तैयार हों कि उन हैवानों के भरोसे उन बालिकाओं को छोड़ दिया जाए। इसलिए सदन में जो मांग उठी है कि आप ऐसे केसेज में जो कर्मचारी है, बदमाश है, जिसने अपराध किया है, उसको तुरंत बर्खास्त करें। उसको सस्पेंड करने के बाद तुरंत नौकरी से बर्खास्त करें, तो मुझे लगता है कि हम बालिका शिक्षा के प्रति आश्वस्त कर पाएंगे उनके माता-पिता को, कि शिक्षा के लिए सरकार कटिबद्ध है और सरकार ने इसलिए यह उपाय किये हैं।

माननीय सभापति महोदय, नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कानून लागू है। अभी बहुत सारे माननीय सदस्यों ने यह बात कही कि इन स्कूलों में जाता कौन है। डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बीजेपी की सरकार तो एस सी, एस टी विरोधी है, इस कारण से उन्होंने नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय, आप तो 2003 में भी

(श्रीमती अनिता भदेल)

सरकार में थे, आप इस सदन में बैठे थे। उस समय वसुन्धरा जी ने शिक्षा के क्षेत्र में काम काज किया, वह हम सबको मालूम है। हमारे नेता, प्रतिपक्ष हुआ करते थे गुलाब जी भाई साहब, वह अब महामहिम हो गये हैं, मैंने उनको अनेकों बार सुना है।

50 के दशक में हमारे देश में गणतंत्र लागू हुआ और चुनाव होने प्रारम्भ हुए। 90 के दशक तक हमारे राजस्थान में प्राइमरी एजुकेशन के लिए ग्राम पंचायतों पर प्राथमिक शिक्षा के केन्द्र नहीं थे। ग्राम पंचायतों पर पहली बार प्राथमिक शिक्षा का स्कूल किसी सरकार में प्रारम्भ हुआ, तो वह मुख्य मंत्री भैरोंसिंह शेखावत जी की सरकार में प्रारम्भ हुआ। यह चार दशक, जिसको चालीस साल कह सकते हैं, चालीस सालों में कांग्रेस ने इस बात को नहीं आंका क्या कि शिक्षा की साक्षरता को बढ़ाने के लिए, शिक्षा को बढ़ाने के लिए हमें ग्राम पंचायत स्तर पर प्राथमिक स्कूल खोलने चाहिए? जो लोग इतिहास नहीं समझते, जो इतिहास नहीं पढ़ते वह अपनी जड़ों से कट जाते हैं। वह समाज को ठीक ढंग से नहीं समझ सकते। हमारे विकास की दिशा किस ओर जानी चाहिए, यह नहीं समझ सकते। इसलिए आज जब ग्लोबलाइजेशन का युग है, तभी हम स्कूली एजुकेशन पर बात कर रहे हैं कि हमारी स्कूली एजुकेशन ठीक नहीं है। स्कूल एजुकेशन में शिक्षक नहीं हैं। शिक्षक ही नहीं है, हम शिक्षक ही नहीं दे रहे तो फिर ऐसी स्कूली एजुकेशन किस काम की। स्टाफिंग पैटर्न से हम शिक्षकों को नहीं लगा रहे हैं। यूनिफार्म की बात की गई। माननीय सभापति महोदय, मैं इन कामन विषयों पर बात नहीं करूंगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं टीचर ट्रेनिंग के बारे में निवेदन करना चाहूंगी। हमारे यहां शिक्षा से जुड़े हुए लोग, एक मशीन के साथ काम नहीं करते, वह एक इंसान से डीलिंग करते हैं। ह्यूमन विंग से डीलिंग करते हैं। इसलिए बीएड करने के तुरंत बाद, अच्छे नम्बर लेकर आ जाए और शिक्षक बन जाए, यह गारंटी नहीं होती कि अच्छा शिक्षक बन जाए। अच्छा शिक्षक रिटन एग्जाम से नहीं बन सकता। अच्छा शिक्षक बन सकता है कि उनका कन्वर्सेशन कैसा है, उसकी बातें बच्चों को कितनी गले उतर रही हैं, इससे वह अच्छा शिक्षक बन सकता है। स्कूली ट्रेनिंग, जिन शिक्षकों को, जिन कर्मचारियों को हमने स्कूल में लगाया है, क्या हमने उसके विशेष प्रोग्राम बनाये हैं ट्रेनिंग के? क्या कन्वर्सेशन को हम तय कर पाये हैं कि बच्चों के

(श्रीमती अनिता भदेल)

साथ उनका कन्वर्सेशन कैसा होना चाहिए। हम सब सिर्फ मूलभूत सुविधाओं की ही बात कर रहे हैं कि मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए।

शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मुझे उनका सुझाव अच्छा लगा इसलिए उसको स्वीकार करते हुए माननीय मंत्री महोदय, आपको निवेदन करना चाहूंगी। खेल मंत्री महोदय मेचिंग ग्रांट की स्कीम लेकर आये, यदि विधायक अपना कोष दे और सरकार उतना मेचिंग ग्रांट बनाकर जिला स्तर पर स्टेडियम निर्माण करे। यदि यह मेचिंग ग्रांट आप शिक्षा विभाग में, अपने मंत्रालय में लेकर आ जाएंगे तो मुझे लगता है 100 परसेंट, यहां पर 200 एम एल एज बैठे हैं, कोई भी इस योजना को नहीं छोड़ेगा। सब लोग अपने विधायक कोष से स्कूल की बिल्डिंग बनाते हैं, खेल मैदान की बाउण्ड्री वाल बनाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे यहां पर एक स्कूल है नगरा भजनगंज। नगरा भजनगंज प्राथमिक था, प्राथमिक से अपर प्राइमरी हो गया, अपर प्राइमरी से माध्यमिक हो गया, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक हो गया, आज भी वह किराये के भवन में चार कमरों में चल रहा है। उच्च माध्यमिक विद्यालय चार कमरों में चल रहा है, किराये के भवन में चल रहा है। उसके लिए भवन की कोई व्यवस्था नहीं है। आर्ट्स के नाम से वहां दो सब्जेक्ट चल रहे हैं, तीसरा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। ऐसी स्थिति में बालिका शिक्षा की बात हम कैसे करें?

मेरा एक स्कूल पीपल का कुआं धोलाभाटा। पीपल का कुआं हायर सैकण्डरी स्कूल है, वह भी किराये के भवन में चल रहा है। इस बारिश में इतना जर्जर हो गया कि शिक्षा विभाग को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। अभिभावक आ गये कि आप इसको शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बच्चे इतनी दूर नहीं जाएंगे। समाज के सहयोग से, दानदाताओं से, मैंने स्वयं उस भवन की रिपेयरिंग कराई, 11 लाख रुपये लगाकर। इसलिए मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगी कि चिह्नित करें, एक पालिसी बनाएं कि राजस्थान में उच्च माध्यमिक विद्यालय जो किराये के भवनों में चल रहे हैं, उन उच्च माध्यमिक विद्यालयों को हम भूखण्ड आबंटन करेंगे और वहां का स्थानीय विधायक उसके भवन निर्माण का काम करेगा। मुझे लगता है विधायक भी सहयोग करेंगे और सरकार भी सहयोग करे तो हम इनकी भौतिक सुविधाओं का अच्छे से ध्यान रख पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त मैं विषय विशेषज्ञों की बात करती हूं। हमने यदि किसी विद्यालय में विज्ञान विषय खोला है तो

(श्रीमती अनिता भदेल)

उसमें लैब ही नहीं है। अब बिना लैब के वह विज्ञान विषय कैसे चलेगा? यदि हमने किसी में कृषि विषय खोला है, कृषि विषय पढ़ाने के लिए कोई साधन ही नहीं है, खेत ही नहीं है, कहीं जगह ही नहीं है, ऐसी स्थिति में हम कृषि विषय कैसे पढ़ाएंगे? जितने भवन विहीन विद्यालय हैं, उनको भवन देना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगी।

माननीय सभापति महोदय, जो संस्था प्रधान हैं, जो भामशाहों से सहयोग लेकर अपने विद्यालयों का कायाकल्प करते हैं, कोई अपने यहां सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, कोई कम्प्यूटर लैब बना देता है, कोई और सुविधाएं कर लेता है, ऐसे शिक्षकों को मोटिवेट करने की जरूरत है, ऐसे शिक्षकों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। मैंने देखा है, पुरस्कार लेने वालों की भी लॉबी होती है, सिफारिश से आते हैं और पुरस्कार लेकर चले जाते हैं। जो एक्चुअल में काम करने वाले लोग होते हैं, वह बिना पुरस्कार के ही वहां बैठे रहते हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है। मेरा निवेदन है ऐसे शिक्षकों को मोटिवेट करो और उनको भी प्रोत्साहन देने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से ऐसे कार्मिक हैं, अध्यापक हैं, हम उनकी संख्या में बढ़ोतरी कर पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, टैक्निकल प्रोब्लम होती है, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान पर, माननीय मंत्री महोदय, जो भी भवन बनते हैं, वे सारे के सारे भवन प्लिंथ लेवल पर बनते हैं। यदि स्कूल का भवन खड्डे में है, तो वह खड्डे में ही उसका प्लिंथ नहीं बढ़ाते हैं। खड्डे में ही क्लास रूम बना देते हैं। बारिश में वह कमरे भर जाते हैं, बरामदा पानी से भर जाता है। यह सर्व शिक्षा अभियान के नोर्म्स की बहुत बड़ी समस्या है। मैं इसलिए इस मामले में सुझाव देना चाहूंगी कि आप कहीं सर्व शिक्षा अभियान से कोई भवन स्वीकृत करते हैं, यदि वह खड्डे में है, नीचे है, तो उसके समाधान के लिए आप वहां के विधायक को रिक्वेस्ट कर लें, वह अपना फण्ड नीचे दे देगा तो उसके ऊपर आप बिल्डिंग बना दें। नीचे अगर उसमें भरती होती जाएगी, भरती होती जाएगी तो वह प्लिंथ लेवल में आने में उसको 20-25 साल लगेंगे। अभी हम प्लिंथ लेवल पर उन भवनों को बना रहे हैं तो वहां तो बारिश के समय में पानी भर जाता है, बच्चों की स्टेशनरी खराब हो जाती है, किताबें खराब हो जाती हैं। पानी भरने की समस्या से बच्चों को स्कूल बंद करना पड़ता है। मेरा

(श्रीमती अनिता भदेल)

निवेदन है कि सर्व शिक्षा अभियान में आप जितनी बिल्डिंग बनाएं, उसका इस दृष्टि से आपको ध्यान रखना चाहिए।

(समय: 20.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ डिमांड कर देती हूं और फिर हायर एजुकेशन के विषय में बात करूंगी। माननीय सभापति महोदय, राजा कोठी उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुलाबबाड़ी, यह गुलाबबाड़ी, माननीय सभापति महोदय, इस राजा कोठी विद्यालय में बोय्ज स्कूल चलता था और गर्ल्स स्कूल दूसरे विद्यालय में चल रहा था। जब वसुन्धराजी की सरकार थी तो मैंने दोनों भवनों को एक्सचेंज करवाया क्योंकि बोय्ज जो हैं वे प्राइवेट स्कूल में ही जाते हैं। हमारे शहर में तो यही परंपरा है कि मां-बाप यह सोचते हैं कि लड़का तो मेरा निजी विद्यालय में पढ़े, क्योंकि वहां पर अच्छी पढ़ाई होती है और लड़की, उनको यह लगता है कि बोझ है इसलिए इसको सरकारी स्कूल में डाल दो तो ऐसा होता था कि लड़कियों का सरकारी स्कूल तो छोटी बिल्डिंग में चलता था और लड़कों का स्कूल बड़ी बिल्डिंग में चलता था। लड़कों के लिए जो स्कूल था, वह पूरी तरह से खाली रहता था और लड़कियों के लिए जो छोटा भवन वाला स्कूल था वह बिलकुल खचाखच भरा हुआ रहता था, उसमें जगह ही नहीं होती थी कि बच्चियों को वहां बैठा सकें, तो मैंने इन दोनों बिल्डिंग्स को एक्सचेंज करवा दिया। लड़कों की में लड़कियों को कर दिया और लड़कियों की में लड़कों को कर दिया। मैंने डाइरेक्टर साहब से निवेदन किया तो उन्होंने इसकी अनुमति दे दी। उसके बाद, माननीय सभापति महोदय, इस विद्यालय में लड़कियों का नामांकन दो हजार इस विद्यालय में हो गया। इसकी बाउंड्री-वाल भी हमने बनवायी, इसमें खेल मैदान भी बनवाया लेकिन इसमें जो साइंस विषय है, वह साइंस विषय स्ववित्त पोषण योजना के तहत चल रहा है, तो मेरा यह निवेदन है कि इस साइंस विषय को स्ववित्त पोषण योजना से निकाल कर नियमित राज्य सरकार के वित्त पोषण से किया जाये ताकि बालिकाओं को इसका लाभ मिल सके।

इसी के साथ, माननीय सभापति महोदय, मेरा जो गांव का विद्यालय है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माखुपुरा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलाबबाड़ी में कृषि संकाय और कल्याणीपुरा भजनगंज, पहाड़गंज में

(श्रीमती अनिता भदेल)

विज्ञान संकाय और इसके साथ ही आदर्श नगर स्कूल में जो कला संकाय है, उस कला संकाय में चित्रकला और संगीतकला के विषयों को यदि जोड़ दिया जाता है तो मेरे शहर की बालिकाओं को लाभ होगा और मेरे शहर की बालिकाएं इन विषयों के लिए सेंटर गर्ल्स स्कूल जाती हैं और उस सेंटर गर्ल्स स्कूल में नामांकन ढाई-तीन हजार से भी अधिक है। एक-एक क्लास में दो-दो सौ बच्चियां हैं तो यदि यह विषय यहां पर खुल जाते हैं तो मुझे यह लगता है कि शहर में बालिकाओं को जाना नहीं पड़ेगा और इन्हीं विद्यालयों में बालिकाएं एडमिशन ले लेंगी।

माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि जो अंग्रेजी माध्यम के माध्यमिक विद्यालय हैं अभी सभी माननीय सदस्यों ने इस बात की चर्चा की है तो मैं भी यह निवेदन करना चाहूंगी कि जो विवेकानंद मॉडल विद्यालय हैं उन विवेकानंद मॉडल विद्यालयों में यदि कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा की व्यवस्था हो जाती है, पढ़ाई प्रारम्भ हो जाती है कक्षा 1 से 5वीं तक तो जो हमारी अंग्रेजी की मांग है, उस अंग्रेजी की मांग को भी पूरा किया जा सकता है और विवेकानंद मॉडल स्कूल चूंकि 6 से 12वीं तक ऑलरेडी इंग्लिश में चलते हैं तो उससे बच्चों को सुविधा होगी। हमारे यहां पर तो आपने कोई एक भी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय परिवर्तित नहीं किया है। मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 20 से 25 हायर सैकण्डरी स्कूल हैं लेकिन एक को भी आपने अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित नहीं किया है, तो इसलिए यह आपको जानकारी रहे। कुछ लोग कह रहे थे कि हमने सुओ-मोटो ही कर दिया, अंग्रेजी माध्यम कर दिया, यह कर दिया, वह कर दिया पर मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी विद्यालय नहीं है और हो तो आप बता दीजिए, मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूं।

माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त एस.एस.ए. स्कीम के तहत विद्यालयों को जो ग्रांट मिलती है, आप सत्र के एंड में वह ग्रांट दे रहे हैं। चारों सालों का यदि हम एवरेज देखें तो यह ग्रांट सत्र के एंड में मिली है इसलिए यदि इस ग्रांट को हम सत्र के प्रारम्भ में ही दे दें तो जो प्रधानाध्यापक हैं, वे प्रधानाध्यापक इधर से मांग करते हैं, उधर से मांग करते हैं, विकास कोष से पैसा निकालते हैं, तो इससे बच पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त अभी चर्चा हो रही थी

(श्रीमती अनिता भदेल)

वार्षिकोत्सव की कि सभी विद्यालयों में वार्षिकोत्सव के आर्डर दिये गये हैं, तो यह निश्चित रूप से अच्छी बात है। यह पहले भी होते आये हैं, वार्षिकोत्सव पहले भी मनाते आये हैं सरकारी विद्यालयों में। आप सरकारी विद्यालयों में वार्षिकोत्सव के लिए पांच हजार रुपये की राशि स्वीकृत करते हैं तो मुझे यह लगता है कि यह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। माननीय सभापति महोदय, पांच हजार रुपये में तो पुरस्कार भी नहीं आते हैं। कई विद्यालय हमारे पास आते हैं कि, बहिनजी, मैडम, आप हमारे पुरस्कारों की व्यवस्था करवा दो तो हम बच्चों को पुरस्कार दे देंगे और हम भामाशाहों से इधर-उधर करके उन पुरस्कारों की व्यवस्था करवाते हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इसको आप पांच हजार रुपये से बढ़ाकर कम से कम 20-25 हजार रुपये करें क्योंकि छोटे से छोटा मोमेंटो भी आता है तो वह 100 रुपये से कम नहीं आता है और यदि पूरे स्कूल के विद्यार्थियों को आपको पुरस्कार देना है तो पांच हजार रुपये तो पुरस्कार ही पुरस्कार में चला जाता है, इसलिए आपको यह सुझाव है।

माननीय सभापति महोदय, विद्यालयों को जो शनिवार को बाल सभा के नाम पर आपने कहा है कि विद्यालयों के बाहर सार्वजनिक स्थानों पर बाल सभाएं होंगी। यह बाल सभाओं के लिए भी खर्चा होता है और कोई ग्राम पंचायत स्कूलों को सहयोग नहीं करती क्योंकि हर शनिवार को यह करना है। माननीय सभापति महोदय, साल में एक बार वार्षिकोत्सव होता है तो चलो कोई सहयोग कर देता है लेकिन यह बाल सभाएं तो हर शनिवार को होनी हैं तो हर शनिवार को कोई पंचायत समिति, कोई ग्राम पंचायत इसमें सहयोग नहीं करती हैं तो इसलिए इसको आप बदलकर, क्योंकि अभी कुछ माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि स्कूल के वर्किंग आवर्स कम हो गये हैं। वर्किंग आवर्स कम होने में यह शनिवार वाला डे भी हमारा एक बहुत बड़ा कारण है और दूसरा कारण हमारा बना है कि बच्चे जो हैं वे छुट्टियों के कारण से, बाकी के कारण से उनके वर्किंग आवर्स कम हो गये हैं। कभी एग्जाम के कारण से छुट्टी हो जाती है, कभी और किसी कारण से छुट्टी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में यदि हम बच्चों को अधिक वर्किंग आवर्स नहीं देंगे, उनके कालांश अधिक नहीं बढ़ाएंगे तो उनका पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा और यदि पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा तो उस लेवल की शिक्षा वह प्राप्त कर पायेगा, यह सम्भव नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ आर.टी.ई., अभी मैं शिक्षा के अधिकार की बात कर ही रही थी तो आर.टी.ई. में आपने पहले तो यह कहा

(श्रीमती अनिता भदेल)

कि नर्सरी क्लास से आर.टी.ई. के बच्चों को लिया जायेगा। फिर आपने पिछले साल यह कह दिया कि पहली क्लास से आर.टी.ई. के बच्चों को दाखिला करेंगे। कुछ लोग कोर्ट चले गये और कोर्ट ने सरकार को यह आर्डर किया कि आप प्रारंभिक कक्षाओं में भी आर.टी.ई. की क्लासेज में एडमिशन करेंगे। आपने आनन-फानन में आर.टी.ई. के फार्म निकाल दिये और आर.टी.ई. के फार्म निकालकर आपने नर्सरी में, एल.के.जी. में, एच.के.जी. में और फर्स्ट में आर.टी.ई. के फार्म निकाल दिये और लोगों ने भर भी दिया।

माननीय सभापति महोदय, 25 परसेंट कोटे में ही आप भर सकते हैं और आपने यह और कह दिया आर.टी.ई. में कि यह पैसा सरकार पुनर्भरण नहीं करेगी। इस लाइन का हवाला लेकर सारे स्कूल कोर्ट चले गये और कोर्ट ने शायद यह डिसाइड कर दिया मैं शायद सही हूं तो, कि आर.टी.ई. में यह आपको या तो पुनर्भरण देना पड़ेगा और यदि आप पुनर्भरण नहीं देते हैं तो आपके बच्चों को एडमिशन इसमें नहीं मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में अभिभावक बहुत ही कंफ्यूज हैं। हम बकाया उनका दे नहीं रहे हैं और हर साल हम एडमिशन के नये-नये तौर तरीके निकाल रहे हैं इसलिए नये-नये तौर-तरीके आप निकालें, अच्छी व्यवस्था करें, पारदर्शी व्यवस्था करें, वहां तक तो ठीक है लेकिन लेवल फर्स्ट में, आप एल.के.जी. में, एच.के.जी. में और नर्सरी में भी आर.टी.ई. के तहत एडमिशन लेंगे तो हरेक क्लास में आर.टी.ई. के तहत एडमिशन हो जायेगा 25-25 परसेंट तो यह तो 100 परसेंट हो गया, इट मीन्स 100 परसेंट बच्चों को तो कोई निजी विद्यालय फ्री में पढ़ायेगा नहीं, तो इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस व्यवस्था को बदलना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही आप देखिये कि शिक्षा में लैपटाप योजना, स्कूटी और साइकिल। साइकिल की अभी बात की, स्कूटी की अभी बात की लेकिन हम कब यह बांटते हैं? जब शिक्षा का सत्र पूरा हो जाता है। अभी गार्गी पुरस्कार के बारे में जब हमने यहां प्रश्न लगाया तब गार्गी पुरस्कार के आवेदन मांगे गये। बच्चियां स्कूल छोड़कर चली गयीं तो बच्चियों को टेलीफोन कर-करके उनके आवेदन पत्र भरवाने पड़े तो यह जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के आप टाइमली यदि फार्म भरवाएंगे, आवेदन मांगेंगे तो बच्चे स्कूल में ही उपलब्ध रहेंगे और सुविधापूर्वक इन लाभों को ले पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से अब मैं प्रबोधकों के बारे में निवेदन करना चाहूंगी। जो आपने प्रबोधकों का कैडर बनाया है, उस प्रबोधक

(श्रीमती अनिता भदेल)

कैडर में लेवल-1 और लेवल-2 तो आपने शिक्षकों के समान ही रखा है लेकिन लेवल-10 और 11 में उनको प्रमोशन तो दिया आपने 9, 18 और 27 क्योंकि उनको 9 साल हो गये, तो प्रमोशन तो दे दिया आपने लेकिन वह पद नहीं दिया जिस पद के वे इक्विलेंट हैं, तो उनमें इस बात का रोष है कि हमको प्रमोशन देने के बाद में आपने वही थर्ड ग्रेड की पोस्ट पर ही पदस्थापित किया है इसलिए हमें उन पदों पर पदस्थापित किया जाये जो बाकी के लेवल के लोगों को मिलता है तो इसलिए यह आपसे निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं कुछ हायर एजुकेशन के बारे में निवेदन करना चाहूंगी। सभी माननीय सदस्यों ने प्राथमिक एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छे से बोला है लेकिन हायर एजुकेशन को शायद छोड़ दिया है। माननीय सभापति महोदय, हायर एजुकेशन में कालेज खुले हैं, इसकी सब लोगों ने बहुत भरसक तारीफ की है और जिनके यहां पर नहीं खुले हैं उन्होंने डिमांड भी की है पर इन कालेजों की क्या स्थिति है? माननीय सभापति महोदय, एक-एक करके जो पिछले चार सालों के प्रतिवेदन हैं, उन प्रतिवेदनों के पन्नों को पलट-पलट कर मैंने यह फैक्ट्स उनमें से निकाले हैं। बजट का जादू उच्च शिक्षा विभाग में पिछले तीन प्रगति प्रतिवेदनों से देखा जा सकता है। पिछले तीन सालों में 202 नवीन महाविद्यालय खोले गये, इसमें से 117 महाविद्यालय वर्ष 2022 में खोले गये।

माननीय सभापति महोदय, यह आश्चर्य की बात है और मैं माननीय मंत्री महोदय का भी ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी कि यदि महाविद्यालय खुले हैं तो नैचुरल-सी बात है कि हायर एजुकेशन में नामांकन भी बढ़ना चाहिए। जितने ज्यादा महाविद्यालय खोले गये, यह 202 नवीन महाविद्यालय खुलेंगे तो हायर एजुकेशन में नामांकन भी तो बढ़ना चाहिए, वह खाली तो नहीं रहेंगे। अब मैं आपको एक-एक की संख्या बताती हूं। सामान्य और आर्थिक कमजोर वर्ग के छात्र 48,915 के स्थान पर 44,345 छात्र आये, मतलब पहले थे 48,915 वह घटकर नामांकन हो गया 44,345 का। छात्राएं 59,948 की तुलना में 58,745 हैं। यानी कि हम 69 से 58 पर आ गये। एक हजार कम का नामांकन हुआ। अनुसूचित जाति के छात्र 57,230 की तुलना में 54,075 हैं। यानी कि 57 से घट कर 54 हो गया। 03 हजार तो वहां पर भी माइनस हुआ है। अनुसूचित जनजाति के छात्र 33,248 के स्थान पर 30,873 हैं। अन्य व विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र 01 लाख 03 हजार 997 के स्थान पर 01 लाख

(श्रीमती अनिता भदेल)

01 हजार 297 हैं। इस प्रकार से राजकीय महाविद्यालयों में कुल नामांकन में भी 0.2 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी है। यह कैसे हो गया? यह नामांकन का डाटा तो मैंने प्रगति प्रतिवदनों में से ही निकाला है, किसी और चीज से मुझे नहीं मिला है। यदि कालेजों की संख्या बढ़ी है तो नामांकन भी तो बढ़ना चाहिए। यह घटा क्यों है? यह आप खुद समझ सकते हो। ऐसा पिछले 20 सालों में पहली बार हुआ है। राजकीय महाविद्यालयों में नामांकन में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आयी है। उच्च शिक्षा का यह कैसा विस्तार है? कैसे दिया है इसको विस्तार का रूप? मुझे तो समझ में नहीं आता।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने युवाओं की बात करते हुए कई महाविद्यालय खोलने की बात कही। कहा गया कि हम युवाओं को शिक्षित करना चाहते हैं। महाविद्यालयों में जितने युवा केन्द्र संचालित थे, उन सबको अघोषित रूप से बन्द कर दिया गया और पिछले तीन वर्षों में युवा केन्द्रों के लिए जो बजट प्रोविजन किया गया था वह सांकेतिक बजट प्रोविजन है, मात्र एक हजार रुपया। यह युवाओं के वेल विशर के लिए है? युवा केन्द्रों के लिए है? मेरी समझ से परे है। माननीय सभापति महोदय, आप बजट उठा कर देख लेंगे तो आपको पता चल जायेगा कि मात्र एक हजार रुपया है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही महाविद्यालय तो दो सौ से ज्यादा खोल दिये लेकिन उसके अनुपात में हम गुणवत्ता की बात करते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं तो उसके अनुपात में पुस्तकालय और प्रयोगशाला के लिए बजट में कोई प्रोविजन नहीं है, बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं है। यदि दो सौ महाविद्यालय खुले हैं तो उसी प्रपोर्शनेट में पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं के लिए भी तो बजट होना चाहिए, लेकिन उसमें बढ़ोतरी नहीं की है। इट मीन्स पुस्तकालय और प्रयोगशाला कालेजों में नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में हम देख सकते हैं कि कैसी गुणवत्ता वाली शिक्षा है। खेल मैदान और खेल सामग्री के लिए तो बजट की कोई व्यवस्था है ही नहीं।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अधिकांश विश्वविद्यालय जिनको राज्य से सहायता प्राप्त है, उनको हमने पैसा दिया है। हम कहते तो हैं कि यह निजी विश्वविद्यालय है, यह राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय है यानी राज्य इसको चलाता है। राज्य वित्त पोषित है तो उसको हमने कितने पैसे दिये हैं। इस मद में मात्र एक हजार और दो हजार रुपये दर्शाये गये हैं। विश्वविद्यालय का लेखा खुला रखने के

(श्रीमती अनिता भदेल)

लिए मद में मात्र एक हजार और दो हजार रुपये दिखाये हैं। माननीय मंत्री महोदय कैसे हायर एजुकेशन को ठीक करेंगे, समझ में नहीं आता।

राजीव गांधी स्कालरशिप फोर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के अन्तर्गत दो सौ विद्यार्थियों को विदेशी संस्थान में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। एक ओर तो हम कुछ भी नहीं करें और दूसरी जगह जब हमने दो सौ विद्यार्थियों के लिए बजट में व्यवस्था की है, यह बजट भाषण की स्पीच है मुख्य मंत्री महोदय की, उसमें दो सौ की जगह हम 244 विद्यार्थियों को स्कालरशिप का लाभ दे रहे हैं, अच्छी बात है लेकिन दो सौ के अतिरिक्त वह 44 हैं कौन? यह तो बताओ। पारदर्शिता तो होनी चाहिए। किसको उपकृत किया गया है इस स्कालरशिप के माध्यम से? कोई अता पता नहीं है। कोई जवाब देने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार जब मैं देखती हूं तो महिला योग्यता छात्रवृत्ति, स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति, मृतक राज्य कर्मचारियों को देय छात्रवृत्ति और पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान बेटियों को देय छात्रवृत्ति, कारगिल शहीदों के आश्रितों को छात्रवृत्ति, शोध छात्रवृत्ति, ललित कला छात्रवृत्ति, इन सबके लिए यदि प्रोजिवन किया है तो सिर्फ एक लाख रुपये का प्रोजिवन किया गया है। क्या यह सब छात्रवृत्तियां एक लाख रुपये में पूरी हो जायेंगी? दे दी जायेंगी? माननीय मुख्य मंत्रीजी जब बजट पढ़ते हैं तो हम बहुत थपथपाते हैं और बहुत अच्छे से महसूस होता है कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हो जायेगा। स्कालरशिप मिलेगी तो बच्चे किसी तरह से स्कॉलरशिप लेने के लिए मेहनत करेंगे, लेकिन जब यह पता चलता है कि सिर्फ एक लाख रुपये का ही प्रोविजन है तो कैसे इसको पार लगायेंगे, यह समझ से परे है।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार जब मैं हायर एजुकेशन का प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 का पढ़ती हूं तो देखती हूं। आप देखिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ विद्या विस्तार योजना के सम्बन्ध में एमओयू को पिछले साल दर्शाया गया था, जिसको इस साल भी दर्शाया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहूंगी कि आप तीनों सालों का प्रगति प्रतिवेदन उठायें और उन अधिकारियों को बुला कर लपकायें जिन्होंने एक बिन्दु भी चेन्ज नहीं किया है। आप देखिए कि यही उल्लेख 2020-21 में, वही 2021-22 में और वही 2022-23 में। यह क्या प्रगति प्रतिवेदन है? हम करेंगे नहीं और दूसरों को बार-बार बेवकूफ बनाने के लिए रिपीट करते जाएंगे।

(श्रीमती अनिता भदेल)

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार वार्षिक प्रतिवेदन में वर्ष की महत्वपूर्ण उपलब्धियों वाले चैप्टर को देखें तो कई उपलब्धियों को हर वर्ष एज इट इज कापी किया गया है जिससे ऐसा लगता है कि जैसे मुख्य मंत्रीजी ने पुराना बजट पढ़ दिया था न, मुझे लगता है यह उसी की कापी है। मुख्य मंत्रीजी जब पुराना बजट पढ़ सकते हैं तो हम पुराना प्रगति प्रतिवेदन क्यों नहीं रिपीट कर सकते। यह उसी से मोटिवेट होकर किया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, 40 राजकीय महाविद्यालयों में से 27 राजकीय महाविद्यालयों में पुस्तकालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है, शेष 13 का कार्य प्रगति पर है। 2020-21 में भी यही लिखा था। 2021-22 में भी यही लिखा कि 40 में से 27 राजकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है, शेष 13 पर कार्य प्रगति पर है। बिना एक शब्द बदले कह दिया। यही बात 2021-22 में कही गयी और यही बात 2022-23 में भी एज इट इज रिपीट की गयी।

माननीय सभापति महोदय, आप देखिए। ये दो, तीन, चार उदाहरण हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूं। वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट में लिखा है कि मुख्य मंत्रीजी की बजट घोषणा 2020-21 की अनुपालना में समस्त राजकीय महाविद्यालयों में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने के क्रम में अब तक लगभग 49 राजकीय महाविद्यालयों में सुविधा उपलब्ध करवायी जा चुकी है। 2020-21 में यह लिखा है। आगे आप देखिये। बिना एक भी शब्द बदले यही वाक्य 2021-22 में भी लिखा है। फिर आगे पढ़िए। 2022-23 की रिपोर्ट में इनकी संख्या 11 बढ़ कर 49 से 60 हो गयी। ऐसे 400-500 महाविद्यालयों में वाईफाई करेंगे तो कितना समय लग जायेगा? आप प्रगति प्रतिवेदन निकाल लीजिए, एक-एक को पढ़ते जाइये। बैठा दीजिए और बताइये। पूछिए अधिकारियों से कि यह क्या कर रहे हो? इस प्रदेश को मजाक बना रखा है क्या? कोई पढ़ेगा नहीं या कोई जानता नहीं है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मेरा तो विषय ही पूरा नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि समाप्त करें। मैंने बिना बोले ही एक पन्ना तो नीचे रख दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक विशेष निवेदन करना चाहती हूं।

(श्रीमती अनिता भदेल)

स्थायी नियुक्ति के स्थान पर संविदा पर नियुक्ति करने का प्रावधान आपने किया है और जो नये कालेज खोले हैं उसको सोसायटी द्वारा संचालित किये जाने की आपने बात कही है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रही हूं कि इसके पहले जो इंजीनियरिंग कालेज राजस्थान में खुले थे, वह भी सोसायटी के अधीन खुले थे और उनका प्रतिफल यह रहा आज कि वह कालेज बन्द होने की कगार पर हैं। उनमे कोई एडमिशन लेने को तैयार नहीं है क्योंकि फुल फीस पे करनी पड़ेगी। जो सोसायटी के तहत महाविद्यालय खुल रहे हैं उनके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि उससे शिक्षा की गुणवत्ता का नुकसान होगा। आपने जो नोर्म्स बनाये हैं कि यूजीसी के नोर्म्स के एकार्डिंग शिक्षकों को संविदा पर लेंगे। आपने यह बात नहीं की यूजीसी के नोर्म्स के एकार्डिंग ही आप उनको वेतन भत्ते देंगे। आप योग्यता की तुलना तो यूजीसी के नियमों से कर रहे हो लेकिन जो मानदेय आप दे रहे हो, जो पैसा आप उसको दे रहे हो, वह यूजीसी के नियमों से गवर्न क्यों नहीं कर रहे हो? उसको भी यूजीसी के नियमों से दीजिए ताकि वह पूरे समर्पण भाव से विद्यार्थियों के लिए शिक्षा दे। आप ऐसा नहीं करने वाले हैं। आप सिर्फ प्रशंसा के लिए कर रहे हैं ताकि आपका विधायक आपके लिए मेज थपथपाये कि हमने खूब सारे महाविद्यालय खोल दिये।

श्री सभापति: प्लीज सम-अप करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे विश्वविद्यालयों की स्थिति के बारे में निवेदन करना चाहूंगी। विश्वविद्यालय तो मात्र परीक्षा आयोजित करने या डिग्री बांटने की संस्थाएं मात्र रह गयी हैं। उच्च शिक्षा विभाग के प्रगति प्रतिवेदन की मैं बात करूं तो इसमें शोध गुणवत्ता, शिक्षा और राष्ट्रीय स्तर के संस्थान बनाने जैसी बात इन विश्वविद्यालयों में दिखाई नहीं दे रही है। इसके अतिरिक्त आप देखिए। आप प्रगति प्रतिवेदन में यह बात कहते हैं कि हम भावी योजना लेकर आयेंगे। हम राजस्थान विश्वविद्यालय में एक छोटी-सी योजना इन्दिरा गांधी रसोई योजना को चलायेंगे लेकिन आपने राजस्थान विश्वविद्यालय में यह इंदिरा गांधी रसोई योजना नहीं चलायी। भावी योजनाओं में आपकी यह योजना भी थी, लेकिन आपने प्रारम्भ नहीं की।

माननीय सभापति महोदय, जयनारायण विश्वविद्यालय में भी यही हाल है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की बात करूं तो उसका भी यही हाल है और सबसे बड़ी बात जिस शहर से मैं आती हूं वहां महर्षि दयानन्द

(श्रीमती अनिता भदेल)

सरस्वती विश्वविद्यालय से सम्बद्ध जो कालेज हैं, आप देखिये, सामान्य शिक्षा के महाविद्यालयों की संख्या 315 लिखी हुई है प्रगति प्रतिवेदन में, लेकिन यदि इसका पृष्ठ संख्या 65 मैं उठाती हूं तो 275 की संख्या लिखी हुई है। मुझे यकीन नहीं होता कि किस बात को हम कह रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, सहयोग करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): बस लास्ट है। राज्य के विश्वविद्यालयों की बात करते हुए मैं निवेदन करूंगी।

श्री सभापति: आपने 30 मिनट का समय ले लिया।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): बस लास्ट है। दो पेपर और हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर में शैक्षणिक पदों की संख्या स्वीकृत है 1016, खाली पदों की संख्या 559 है, यानी की 60 प्रतिशत के लगभग है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में स्वीकृत पदों की संख्या 482, इनमें 272 खाली हैं। सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में स्वीकृत पदों की संख्या 258, इनमें खाली 83 हैं। इसी तरह महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में स्वीकृत पदों की संख्या 48 हैं, इनमें 34 खाली हैं। सभी में इस तरह 60 प्रतिशत से ज्यादा खाली पदों की संख्या है। ऐसी स्थिति में हम हायर एजुकेशन को कैसे ऊंचाइयां देंगे, मुझे यह बात समझ में नहीं आती।

माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त निजी विश्वविद्यालयों की मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि आप मुझे टोक देंगे। मैं अंत में, एक बात कहकर अपनी बात को पूरा करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, हम सब 200 माननीय विधायक अपनी-अपनी विधान सभा क्षेत्रों से चुनकर आते हैं और हम जब कैबिनेट की बात करते हैं तो सामूहिक दायित्व की बात करते हैं, लेकिन पिछले चार सालों का बजट और प्रतिवेदन जब मैंने देखे तो मुझे लगा कि हमारे राजस्थान से जो मुख्य मंत्री आ रहे हैं, वह राजस्थान के मुख्य मंत्री नहीं हैं, वह सिर्फ और सिर्फ जोधपुर के मुख्य मंत्री हैं। आप देखिये कि जोधपुर के लिए हायर एजुकेशन, सिर्फ एक विषय, हायर एजुकेशन के लिए कितनी घोषणाएं हुई हैं इन चार सालों में, उसके बाद मैं अपनी बात को पूरा करूंगी। जोधपुर में जयनारायण विश्वविद्यालय के अलावा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी, आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइस,

(श्रीमती अनिता भदेल)

डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी आफ पुलिस (सिक्योरिटी एण्ड क्रिमिनल जस्टिस), एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टैक्नोलोजी, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ हैण्डलूम टैक्नोलोजी, स्टेट इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट जैसे प्रमुख और महत्वपूर्ण डिग्री देने वाले उच्च संस्थान और विश्वविद्यालय, जो पहले से कार्यरत हैं, इनके अलावा 400 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ नई फिनटेक यूनिवर्सिटी को भी जोधपुर में ही स्थापित करने की घोषणा की गयी है। इस बजट में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी और दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर में खोलने की घोषणा की गयी है।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, सहयोग करें। ऐसे तो एण्ड-लेस है यह तो।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मुख्य मंत्रीजी से कहूंगी कि आप मात्र जोधपुर के मुख्य मंत्री नहीं हैं, बल्कि राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं। आप राजस्थान का मुख्य मंत्री बनने की अपेक्षा पर खरा उतरेंगे और सभी विधान सभाओं में भी बराबर विकास को पहुंचायेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रदेश का विकास होने वाला है, अन्यथा कांग्रेस सरकार ने जो किया है वह सबके सामने है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र यादव।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 22 पर सदन में चर्चा हुई। सभी माननीय सदस्यों ने बड़े ही उत्साह से इस चर्चा में भाग लिया। माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों के लिए मांग के साथ सुझाव भी दिये। मैं इसके लिए सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उच्च शिक्षा विभाग की मांग संख्या 22 के अन्तर्गत माननीय सदस्यों ने विभिन्न स्थानों पर नवीन राजकीय महाविद्यालय/नवीन संकाय/नवीन विषय/रिक्त पदों को भरने एवं महाविद्यालयों में भवन निर्माण संबंधी 230 प्रस्तावों से अवगत करवाया है। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर संसाधनों एवं गुणावगुण के आधार पर उचित निर्णय लिया जायेगा। माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्तावों का जवाब विभाग द्वारा प्रेषित किया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह जो सुनाना चाहते हैं, आप टेबल करवा दो। भले आदमी हैं। 8.30 बज रहे हैं। मंत्री महोदय ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। हम मेज थपथपाकर इनका स्वागत करेंगे। आप तो टेबल करवा दो।

श्री सभापति: आप तो मेजें थपथपाकर इनको बोलने की इजाजत दें। सुनना पड़ेगा आपको।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं लोकप्रिय, यशस्वी एवं ऊर्जावान माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने उच्च शिक्षा में सभी वर्गों, युवाओं एवं बालिकाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर बजट में उच्च शिक्षा को विशेष प्राथमिकता देते हुए कई घोषणाएं एवं नवाचार किये हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि प्रदेश में 2018 तक कुल 250 राजकीय महाविद्यालय थे, उनमें से 47 कन्या महाविद्यालय थे। हमारी सरकार द्वारा 2019 से 2022 तक 240 नवीन महाविद्यालय, जिनमें से 94 कन्या महाविद्यालय एवं 29 कृषि महाविद्यालय खोले गये। इसी क्रम में बजट 2023-24 में कुल 79 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले गये, जिनमें से 28 कन्या महाविद्यालय एवं 07 कृषि महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है। आगामी सत्र से इन नवीन महाविद्यालयों को प्रारम्भ किया जायेगा। माननीय मुख्य मंत्री महोदय के निर्देशानुसार इन महाविद्यालयों हेतु अस्थायी भवन एवं भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

माननीय सभापति महोदय, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिन विद्यालयों में 11वीं एवं 12वीं में कुल 500 से अधिक छात्राएं हैं, वहां कन्या महाविद्यालय खोलने की नीति के अन्तर्गत 9 नवीन महाविद्यालय खोले गए तथा 20 स्थानों पर पूर्व में संचालित 20 कन्या महाविद्यालयों में अतिरिक्त सेक्शन प्रारम्भ किये गये।

उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए 50 UG स्तर के महाविद्यालयों को PG स्तर में क्रमोन्नत किया गया। स्नातक स्तर पर 89 नवीन विषय, स्नातकोत्तर स्तर पर 129 नवीन विषय और 74 नवीन संकाय खोले गये।

माननीय सभापति महोदय, दिव्यांगों की शिक्षा के प्रति राज्य सरकार संवेदनशील है। पहली बार मूक बधिर विद्यार्थियों हेतु पृथक से जयपुर में राजकीय महाविद्यालय खोला गया है।

माननीय सभापति महोदय, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

महाविद्यालय तो खोले ही गये, महाविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु रुपये 1150 करोड़ का बजट आबंटित किया गया। वर्तमान में 200 से अधिक महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य निर्माणाधीन हैं। गत सरकार ने महाविद्यालय खोलने की घोषणा की, पर बजट स्वीकृत नहीं किया। ऐसे भवन विहीन 18 राजकीय महाविद्यालयों को भी बजट उपलब्ध करवाते हुए कार्य प्रारम्भ करवाया गया है।

माननीय सभापति महोदय, केवल भवन निर्माण ही नहीं, इसके साथ-साथ आधारभूत संरचना में गुणवत्ता एवं महाविद्यालयों के नैक (NAAC) ग्रेड में सुधार हेतु लाइब्रेरी अपग्रेडेशन, प्रयोगशालायें एवं आईसीटी सुविधाओं हेतु बजट 2023-24 में 100 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है।

माननीय सभापति महोदय, यह उल्लेखनीय है कि डा. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर एवं हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर को हमारी सरकार ने वर्ष 2012 में प्रारम्भ किया था, लेकिन पिछली सरकार ने इन्हें बन्द कर दिया था, जिन्हें पुनः स्थापित कर सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। एम.बी.एम. अभियांत्रिकी महाविद्यालय को अपग्रेड करके एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर खोला गया।

माननीय सभापति महोदय, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर का भवन निर्माण कार्य 109 करोड़ 93 लाख रुपये की लागत से किया जा रहा है। निर्माण कार्य इसी वर्ष पूर्ण किया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर के भवन का निर्माण 119 करोड़ 21 लाख रुपये की लागत से प्रारम्भ हो गया, जो सितम्बर, 2023 तक पूर्ण किया जाना है।

माननीय सभापति महोदय, एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर में Petroleum विभाग के निर्माण हेतु 20 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है। RUDSICO को कार्यकारी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है, शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, महात्मा गांधी इन्स्टीट्यूट आफ गवर्नेन्स एण्ड सोशल सांइसेज, राजा रामदेव पोद्दार Residential School of Excellence, राधाकृष्ण लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर एवं राजकीय महाविद्यालय, जयपुर को सम्मिलित करते हुए जवाहर लाल नेहरू मार्ग स्थित शैक्षणिक संस्थाओं को

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

Centre of Excellence के रूप में विकसित किये जाने के क्रम में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इस योजना हेतु 355.83 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इसका लगभग 20% कार्य पूर्ण हो चुका है।

माननीय सभापति महोदय, सामाजिक समरसता एवं सद्भाव विषय पर शोध हेतु मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर में 15 करोड़ रुपये की लागत से Centre of Excellence and Research की स्थापना की जा रही है, जिसके लिए जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निविदा जारी कर दी गई है।

सभापति महोदय, सरकार ने उच्च शिक्षा की पहुंच को दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय खोलने एवं भवन निर्माण हेतु बजट उपलब्ध कराने के साथ ही महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में टीचर्स की कमी को पूरा करने के लिए योग्यताधारी शिक्षकों का चयन कर छात्रों के अध्ययन हेतु विद्या सम्बल योजना लागू की गयी है।

सभापति महोदय, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता हेतु संकाय सदस्यों की उपलब्धता आवश्यक है। इस बाबत बहुत से सदस्यों ने अपनी चिन्ता व्यक्त की है। इस संबंध में सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि सहायक आचार्यों के 918 रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 31 विषयों की लिखित परीक्षा आयोजित की गयी, जिसमें से 648 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है, शेष नियुक्ति अप्रैल, 2023 तक दे दी जायेगी। वर्ष 2019 से अब तक 892 सहायक आचार्यों एवं 470 अशैक्षणिक, कुल 1362 पदों पर नियुक्ति दी गयी है।

सभापति महोदय, उक्त भर्तियों के अतिरिक्त दिनांक 16.01.2023 को राजस्थान लोक सेवा आयोग को 1952 सहायक आचार्यों के रिक्त पदों को भरने हेतु अभ्यर्थना प्रेषित की जा चुकी है। प्रयोगशाला सहायक के 480 पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही अन्तिम चरण में है। 241 अशैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु अर्थना प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रेषित कर दी गयी है। राजसेस सोसाइटी के अधीन संचालित महाविद्यालयों में भर्ती के नियम बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नियम बनाने के पश्चात् इन पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जावेगी।

सभापति महोदय, विगत 9 वर्षों से प्रदेश में 'सेट' परीक्षा नहीं हो रही थी। राज्य सरकार द्वारा निर्णय लेकर इस वर्ष 26 मार्च, 2023 को गोविन्द

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा द्वारा सेट परीक्षा आयोजित की जा रही है ताकि राज्य के योग्य अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर एवं प्रदेश को सहायक आचार्य उपलब्ध हो सकें।

सभापति महोदय, विभाग में लंबे समय से रिक्त चल रहे लाइब्रेरियन एवं पीटीआई, शारीरिक शिक्षकों की अंतिम भर्ती वर्ष 1991-92 में की गयी थी। वर्तमान सरकार ने लाइब्रेरियन एवं पीटीआई 247+247, कुल 494 पदों को भरने के लिए वित्त विभाग से वित्तीय स्वीकृति ले ली है। भर्ती के नवीन नियम बनाये जाने की कार्यवाही अंतिम चरण में है। हमारा प्रयास रहेगा कि शीघ्र ही अर्थना आरपीएससी को भिजवा दी जाये।

सभापति महोदय, प्रदेश में राज्य के निवासी विद्यार्थियों को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर में स्टेट डोमिसाइल आरक्षण प्रदान करने की मांग लंबे समय से लम्बित थी, जिसके लिए हमारी सरकार ने विशेष प्रयास करते हुए न केवल राज्य के डोमिसाइल विद्यार्थियों को, बल्कि ओबीसी वर्ग के लिए भी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर में आरक्षण करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है।

सभापति महोदय, ऐसी किशोरियां व महिलायें जो पारिवारिक एवं अन्य कारणों से नियमित रूप से कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं जा पाती हैं, उन्हें डिस्टेन्स एजुकेशन के माध्यम से उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू की गयी है।

सभापति महोदय, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फोर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, 2021 लागू की गयी जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष प्रदेश के 200 होनहार विद्यार्थियों को शीर्ष 150 विदेशी शिक्षण संस्थानों में अध्ययन के लिए पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। 30 प्रतिशत स्थान महिला विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं एवं 8 लाख से कम पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है। अब तक कुल 247 विद्यार्थियों का चयन हुआ है, जिनमें 120 छात्राएं शामिल हैं, इनमें से 38 छात्राओं को विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिला है। योजना की सफलता को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट वर्ष 2023-24 में विद्यार्थियों की संख्या प्रतिवर्ष 200 से बढ़ाकर 500 किये जाने की घोषणा की है।

सभापति महोदय, राज्य के नेट, स्लेट उत्तीर्ण शोधार्थी जिन्हें किसी

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

प्रकार की फैलोशिप प्राप्त नहीं होती है उन्हें शोध कार्य हेतु रुपये 20 हजार प्रति माह फैलोशिप दी जायेगी।

हमारी सरकार ने होनहार छात्राओं को प्रोत्साहित करने हेतु कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, देवनारायण स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजनान्तर्गत वितरित की जाने वाली स्कूटियों की संख्या सत्र 2022-23 से 13 हजार से बढ़ाकर 20 हजार की थी, जिसे बजट वर्ष 2023-24 में बढ़ाकर 30 हजार करने की घोषणा की गयी है। साथ ही बालिकाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी दिये जाने का भी विकल्प दिया जायेगा।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा बजट वर्ष 2023-24 में छात्राओं को अध्ययन के लिए आवास से महाविद्यालय आने जाने की सुविधा हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम लागू करने की घोषणा की गयी है।

सभापति महोदय, बजट वर्ष 2023-24 में छात्राओं को आवश्यक निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से राजकीय महाविद्यालयों में छात्रावासों का निर्माण चरणबद्ध रूप से करवाये जाने की घोषणा की गयी है।

सभापति महोदय, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत हमारी सरकार के द्वारा आज तक 2,93,300 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी है। विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री बी.एड. सम्बल में अब तक 1027 छात्राध्यापिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी।

सभापति महोदय, आज बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, जिसके निदान के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में युवाओं के लिए भर्तियों के साथ-साथ, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, रोजगार मेले इत्यादि आयोजित किये गये। दिनांक 24 फरवरी, 2023 को राजकीय महाविद्यालय, जयपुर द्वारा रोजगार निदेशालय, जयपुर के सहयोग से रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 22 कंपनियों ने भाग लिया तथा लगभग 1700 से अधिक विद्यार्थियों ने अपना पंजीकरण करवाया तथा 188 विद्यार्थियों का चयन किया गया। इस दिशा में आगे प्रयास जारी हैं।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2023-24 में प्रदेश के महाविद्यालयों में कैंपस प्लेसमेंट की व्यवस्था प्रारम्भ की घोषणा की गयी है। साथ ही वोकेशनल सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किये जायेंगे। इस हेतु 50 करोड़ का व्यय होगा।

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

सभापति महोदय, युवाओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु राजकीय महाविद्यालयों में ओपन जिम की स्थापना की जायेगी।

सभापति महोदय, युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एवं अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सावित्री बाई फुले वाचनालय स्थापित किये जा रहे हैं। इसे और आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट घोषणा वर्ष 2023-24 में समस्त ब्लाक मुख्यालयों पर सावित्री बाई फुले वाचनालय मय डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की है। इससे निश्चित ही दूरस्थ क्षेत्र के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, राज्य के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में NAAC प्रत्यायन को सुनिश्चित करने तथा प्रक्रिया को गति देने हेतु स्टेट लेवल क्वालिटी एश्योरेंस सैल सतत प्रयासरत है।

सभापति महोदय, राजस्थान में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु विश्वविद्यालयों के लिए हमारी सरकार ने राजस्थान हायर टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट स्कीम लागू की है।

सभापति महोदय, प्रदेश में निजी शिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान निजी शिक्षण संस्थान विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2023 के ड्राफ्ट पर स्टेक होल्डर्स से प्राप्त सुझावों एवं दिनांक 27.01.2023 को आयोजित मीटिंग में हुई चर्चा के दौरान प्राप्त सुझावों को गुणावगुण के आधार पर सम्मिलित करते हुए विधेयक को विधान सभा के वर्तमान सत्र में पुरःस्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षकों की गुणवत्ता में अभिवृद्धि हेतु देश-विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में रिसर्च एवं ट्रेनिग हेतु टीचर्स इंटरफेस फोर एक्सीलेंस प्रारम्भ किया जाएगा, जिसमें 500 शिक्षक लाभांवित होंगे। साथ ही शिक्षकों के शैक्षणिक सुधार एवं ओरिएंटेशन हेतु फैकल्टी डवलपमेंट एकेडमी स्थापित की जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, कोचिंग सेंटरों पर प्रभावी नियंत्रण मॉनिटरिंग एवं इनमें अध्ययनरत विद्यार्थियों को मानसिक सम्बल प्रदान करने हेतु, भ्रामक विज्ञापनों को रोकने एवं ईजी एक्जिट पालिसी के मुद्दों के समाधान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

एण्ड रेगुलेशन विधेयक, 2023 लाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में स्टेक होल्डर्स के साथ दिनांक 27.01.23 को आयोजित मीटिंग में प्राप्त सुझावों पर विचार कर गुणवत्ता के आधार पर उन्हें सम्मिलित करते हुए विधान सभा के वर्तमान सत्र में विधेयक पुर:स्थापित किये जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

माननीय सभापति महोदय, उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। हमारी सरकार द्वारा दूर-दराज के क्षेत्रों में नये महाविद्यालय खोलने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है, जैसा मैंने पूर्व में भी निवेदन किया है कि राज्य स्तर पर सकल नामांकन अनुपात 2018-19 में 22.7 से बढ़कर 2020-21 में 26.1 प्रतिशत हो गया, इसमें आगामी वर्षों में और वृद्धि देखने को मिलेगी। 2035 तक नेशनल एजुकेशन पालिसी के 50 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने अलग-अलग अपने विचार रखे हैं। अजमेर उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारी सरकार के बाद इस सरकार ने आरपीएससी को कोई अभ्यर्थना नहीं भेजी। मैं माननीय सदस्य एवं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि 920 सहायक आचार्यों की अभ्यर्थना पूर्ण करके हमारी सरकार द्वारा ही दिनांक 16.09.2020 को आरपीएससी को भेजी गई थी, जिसमें 648 को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। इसके उपरांत 16.01.2023 को भी आरपीएससी को 1952 सहायक आचार्यों के पदों की भर्ती हेतु अभ्यर्थना भेजी गई है। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि शेखावाटी विश्वविद्यालय, मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर एवं बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर तथा जीजीटीयू, बांसवाड़ा में एक भी पद पर भर्ती नहीं है। इस पर मैं यह कहना चाहता हूं कि शेखावाटी विश्वविद्यालय ने अशैक्षणिक पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है, शेष विश्वविद्यालयों को मॉडल रोस्टर के अनुसार भर्ती हेतु निर्देशित कर दिया गया है। माननीय सदस्य ने निजी विश्वविद्यालय एवं कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण की बात कही। इस पर मैं कहना चाहता हूं कि निजी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण हेतु राजस्थान निजी उच्च शिक्षण संस्थान विनियामक प्राधिकरण विधेयक एवं कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण हेतु राजस्थान कोचिंग संस्थान नियंत्रण एवं विनियामक विधेयक विधान सभा के वर्तमान सत्र में लाया जाना प्रस्तावित है।

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

माननीय सभापति महोदय, सुमेरपुर-पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने महाविद्यालय भवन का कार्य पूर्ण कराने के लिए राशि जारी करने की मांग की। मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर का निर्माण 24.12.2022 को पूर्ण किया जा चुका है। कन्या महाविद्यालय तखतगढ़ का कार्य प्रगति पर है, पूर्ण की संभावना तिथि 26.09.2023 तक है।

दूदू से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र में रिक्त पदों की समस्या बताई। राजकीय महाविद्यालय दूदू में 15 स्वीकृत पद पर 10 सह सहायक आचार्य कार्यरत हैं। राजकीय महाविद्यालय फागी में 15 स्वीकृत पद पर 12 सह सहायक आचार्य कार्यरत हैं। माननीय सदस्य ने निजी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण हेतु कानून बनाने एवं इन पर नैक एक्रेडिटेशन अनिवार्य करने की मांग उठाई। इस सम्बन्ध में मैं अवगत कराना चाहूंगा कि निजी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण का विधेयक इसी सत्र में लाया जाना प्रस्तावित है तथा निजी विश्वविद्यालयों को नैक से एक्रेडिटेशन हेतु अधिनियम में पहले से प्रावधान किया जा चुका है।

माननीय सभापति महोदय, चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य ने महाविद्यालय के रिक्त पद भरने के लिए कहा। मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि महाविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए आरपीएससी को 1952 पदों की अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है।

श्री जगदीश चन्द्र, माननीय विधायक द्वारा कुलपति की नियुक्ति पर बात उठाई गई। वर्ष 2017 में विश्वविद्यालय के अधिनियमों में परिवर्तन कर कुलपति की योग्यता यूजीसी के अनुकूल कर 10 वर्ष के प्रोफेसर के अनुभव वाले व्यक्ति को वाइस चांसलर बनाने का प्रावधान किया। वर्ष 2019 में उसे और संशोधित करते हुए योग्यता में सत्य निष्ठा के नैतिक, आचार और सांस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर वाला प्रख्यात शिक्षाविद् वाक्यांश जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त 2019 के इस संशोधन के माध्यम से कुलपति को हटाने का प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, सूरजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को मैं कहना चाहूंगा कि भवन निर्माण के लिए उनका जुलाई में पूर्ण होना संभावित है। राजकीय महाविद्यालय, सूरजगढ़ का साढ़े चार करोड़ रुपये का

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

बजट स्वीकृत हो गया है जिसकी भूमि डम्पिंग यार्ड होने से अतिरिक्त बजट 1 करोड़ 19 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण निर्माण कार्य शुरू होने में विलम्ब हुआ, इसका निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, सभी सदस्यों ने गहरी चिंता व्यक्त की थी कि कालेज शिक्षा में प्राचार्यों की कमी है, शिक्षाविदों की कमी है। मैं बताना चाहूंगा कि 292 राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पद हैं 6 हजार 933, जिनमें कार्यरत हैं 4 हजार 682, विद्या सम्बल से हमने और लिए हैं 1 हजार 442, कुल कार्यरत हो गए हमारे पास 6 हजार 124, मात्र 809 की कमी है। इसी तरह से 166 सोसायटी के जो राजकीय महाविद्यालय हैं, उनमें स्वीकृत पद हैं 1 हजार 854, कार्यरत हैं 112, विद्या सम्बल से 370, कार्य व्यवस्थार्थ 142, कुल कार्यरत 624, इसमें 1 हजार 230 शिक्षाविदों की कमी है। कुल मिलाकर 2 हजार 39 पदों की कमी है। 1 हजार 952 के लिए आरपीएससी को अभी और अभ्यर्थना भेज दी है। इसके साथ-साथ विद्या सम्बल में हमने पूरी छूट दे रखी है कि जहां भी कमी है उसको पूर्ण किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, हम उच्च शिक्षा के लिए कटिबद्ध हैं और कहीं पर भी आप चिंता व्यक्त करते हैं, चिंता की जरूरत नहीं है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, उन सबको जुलाई तक नये सत्र में खोल देंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बुलाकी दास कल्ला।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री):

"या देवी सर्वभूतेषु विद्या-रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥"

माननीय सभापति महोदय, मां शारदा को नमन करते हुए मैं अपनी बात प्रारम्भ करता हूं। आज मांग संख्या 20 और 21 के सम्बन्ध में जो प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित है, इसके बारे में 527 कटौती प्रस्ताव आये, 39 माननीय सदस्यों ने पक्ष और विपक्ष से अपने विचार व्यक्त किये। मैं उन सबका आभारी हूं जिन्होंने अपने अच्छे सुझाव दिये, हमारी कमियों को उजागर किया, भविष्य में क्या करना है इसके बारे में उपयोगी सुझाव दिये। मैं उन सबका और सदन का आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, किसी भी विद्यार्थी को यदि यह पूछा

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

जाए कि वह क्या बनना चाहता है तो सबसे पहले विद्यार्थी कहेगा कि मैं अध्यापक बनूंगा क्योंकि वो अध्यापक से प्रभावित होता है। फिर कई बच्चे डाक्टरों से प्रभावित होते हैं, वे कहते हैं, मैं डाक्टर बनूंगा। कई बच्चे प्रशासनिक सेवाओं से प्रभावित होते हैं कि मैं कलेक्टर बनूंगा, एसपी बनूंगा। कुछ लोग खेल से सम्बन्धित होते हैं, वे कहते हैं, मैं विराट कोहली बनूंगा, अजहरुद्दीन बनूंगा। हर व्यक्ति जीवन में कुछ न कुछ बनना चाहता है और बनने का माध्यम केवल शिक्षा ही है। तालीम के बिना व्यक्ति बुद्धू तो बन सकता है, लेकिन अच्छा नागरिक नहीं बन सकता।

मेरा ऐसा मानना है कि समाज में कोई भी परिवर्तन, नव जागरण या क्रान्ति होती है तो उसका सूत्रपात या माध्यम केवल शिक्षा ही है। उसके बिना नव जागरण नहीं हो सकता। शिक्षा के बिना क्रान्ति नहीं हो सकती। शिक्षा के बिना सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता, इसलिए सामाजिक अंधेरे को दूर करने के लिए, व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश में लाने के लिए शिक्षा ही सबसे बड़ा माध्यम है। इसीलिए हम कहते हैं- ''सा विद्या या विमुक्तये'', ''विद्या ददाति विनियम'', ''विद्या विनयेन शोभते'', विद्या विनयशीलता प्रदान करती है, विनयशील व्यक्ति को शिक्षा शोभा देती है। अतः विद्या जो है, इसका उपयोग कैसे करें, इसके बारे में कहा गया है-

"विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय।

खलस्य साधोर् विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय॥"

यदि किसी के पास विद्या है तो वह उसे दूसरे को सिखाने के काम में ले। यदि किसी के पास शक्ति है तो वह पीड़ित मानव की रक्षा करने के काम में आये। यदि किसी के पास धन है तो वह परोपकार के, पुण्य के कार्यों में खर्च हो। ऐसे लोग सज्जन व्यक्ति कहलाते हैं। जिनके पास विद्या है और कुतर्क करते हैं, जिनके पास धन है और अहंकार, दम्भ और अभिमान करते हैं, जिनके पास शक्ति है और दूसरों को परेशान करते हैं, ऐसे व्यक्ति दुर्जन व्यक्ति कहलाते हैं। विद्या जो है, उसका सज्जनता के आधार पर दूसरों को कुछ सिखाने में उपयोग करना चाहिए। मैं जब बचपन में पढ़ता था तो हमारे गुरु जी सिखाते थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मंत्री महोदय, यह किसकी तरफ अंगुली की आपने? दुर्जन व्यक्ति कौन है, अंगुली किस तरफ की आपने?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): मैंने किसी की तरफ अंगुली नहीं की।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): देखिये, मैं आपसे यह उम्मीद नहीं करता। आप करें तो उधर करें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): नहीं, मैंने किसी के लिए नहीं कहा।

श्री सभापति: इसमें पूछने जैसी बात ही नहीं है कि किसकी तरफ अंगुली की है। पूछने की क्या बात है?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): खुद ने ही प्रमाणित कर दिया कि किसके लिए कहा गया है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): देखिये, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का आदर करता हूं। मैं तो एक जनरल कहावत के बारे में कह रहा था। मैं आपसे यह कह रहा था कि विद्या, शक्ति और धन का सांगोपांग सदुपयोग करना चाहिए। जो सदुपयोग करते हैं, वे वास्तव में अच्छे संस्कारी होते हैं और देश के लिए काम करते हैं।

मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि यदि किसी के पास विद्या आ जाये और विद्या का दुरुपयोग करे, जैसे विज्ञान है, विज्ञान के अच्छे उपयोग भी हैं, विज्ञान के दुरुपयोग भी हैं। आज परमाणु बम पढ़े-लिखे लोगों ने बनाये हैं, लेकिन बुद्धि खराब हो जाये तो विनाश का कारण भी बन जाते हैं, इसलिए शिक्षा का उपयोग भी बहुत ढंग से करना चाहिए। आज के जमाने में मैं खास तौर से कहना चाहता हूं, जैसे मजहब और धर्म के बारे में कई बातें होती हैं।

"मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,
हिन्दी हैं हम, वतन है हिन्दोस्तां हमारा।।"

इसलिए शिक्षित व्यक्ति को इन सब बातों से ऊपर उठकर मानवता के बारे में सोचना चाहिए कि मानव को हम कैसे अच्छा नागरिक बनाएं। एक तरफ तो हम कहते हैं, "वसुधैव कुटुम्बकम्", यानी पूरा संसार जो है एक कुटुम्ब की तरह, एक परिवार की तरह है। दूसरी तरफ यदि हम भाषा, जाति, मजहब और धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करें तो यह शिक्षा नहीं सिखाती। शिक्षा तो यह सिखाती है कि मानव जो है वह एक कुटुम्ब की तरह है, एक परिवार की तरह है। हमारे सैंट्रल हॉल में ऊपर लिखा हुआ है-

अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम्।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

यह सैंट्रल हॉल में लिखा हुआ है। यह वेद की ऋचा बताती है कि यह तेरा-मेरा भारत की संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति उदार चरित्र वाली है, जिसमें सारा संसार एक कुनबे की तरह, एक परिवार की तरह है।

राजस्थान में हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो शिक्षा का बजट दिया है, उसकी सभी लोगों ने सराहना की है। एक रोल मॉडल के रूप में दूसरे स्टेट्स भी इसकी कापी कर रहे हैं। इसका कारण क्या है, इस बजट के माध्यम से जो शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन, नवाचार हुए हैं वे अपने आप में वास्तव में अनुकरणीय और दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणादायी हैं।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे पूर्व मंत्री गोविन्द सिंह जी डोटासरा को, उन्होंने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स शुरू किये। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, विद्याधर नगर की स्कूल में तीस सीटें थीं, 600 एप्लीकेशंस आयीं। 600 में लाटरी से एडमिशंस हुए तीस लोगों के। न तो किसी मंत्री, न किसी अधिकारी, किसी की भी कोई सीट रिजर्व्ड नहीं है। केवल लाटरी में उन गरीब लोगों के गाड़े वाले, खोमचे वाले, ठेले वाले, किसान, गरीब, आम आदमी के एडमिशंस हुए हैं। आज शुरू शुरू में नामांकन की बात आयी। कई माननीय सदस्यों ने कहा, नामांकन तो हमारे यहां कोविड के बाद में करीब-करीब 12 लाख बढ़े। 12 लाख बढ़ने के बाद इस साल जो है, चूंकि कोविड में प्राइवेट स्कूलों ने तो अपने झोली-डण्डे सम्भाल लिए थे, हमारी स्कूलें खूब चलीं। उसके कारण से प्राइवेट स्कूलों में कुछ लोगों ने एडमिशंस लिए, लेकिन जिस दिन महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स अधिक मात्रा में और खुल जाएंगे, उस दिन आप देखियेगा, लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ मुंह नहीं झांकेंगे। उसका कारण क्या है, हमारी स्कूलों में फ्री पढ़ाई, फ्री किताबें, नि:शुल्क ड्रेस, सारी चीजें मुफ्त हैं। प्राइवेट स्कूलों में आज 1 से 2 लाख रुपये तक की फीस ली जाती है। आम आदमी पढ़ा नहीं सकता, आम आदमी कम्पीट नहीं कर सकता।

अब हम लोगों ने 1133 महात्मा गांधी स्कूलों में प्री प्राइमरी एजुकेशन शुरू कर दी। सभापति महोदय, इससे भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आयेगा। जो नयी शिक्षा नीति आयी है, जिसका जिक्र अजमेर उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे थे, उसमें 5+3+3+4 का प्रावधान किया गया है। इसका मतलब यह है कि पहले एलकेजी, यूकेजी, प्रेप, पहली, दूसरी, ये पांच साल लगेंगे। फिर

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

तीन साल तीसरी, चौथी, पांचवीं में लगेंगे। उसके बाद में छठी, सातवीं, आठवीं में तीन साल। फिर चार साल में नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं। इसके लिए एक वर्ष से भारत सरकार से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है।

हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पर कमेटियां बना दीं। हमारे मुख्य सचिव स्टेट लेवल कमेटी के अध्यक्ष हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला कलेक्टर अध्यक्ष हैं। बराबर नयी शिक्षा नीति के पहलुओं पर काम किया जा रहा है। नीति बन गयी, पर बजट नहीं है। बजट के बिना उसका क्रियान्वयन कैसे होगा? इसी प्रकार पीएबी के अन्तर्गत जो हमें प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड द्वारा पहले 33 जिलों में पैसे मिलते थे, बीच में 22 जिलों में पैसे देने बन्द कर दिये। अभी ठीक दो महीने पहले 2463 करोड़ रुपये की डिमांड के पेटे 239 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। उसमें 40 परसेंट हमारा है और 60 परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि स्कीम बनाएं, लेकिन उसके साथ में बजट का भी प्रावधान होना चाहिए ताकि नयी शिक्षा नीति को हम इम्प्लीमेंट कर सकें।

मैं इस अवसर पर आपसे खास तौर पर यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जो नवाचार हुए, उनका परिणाम यह हुआ कि आज लगभग ढाई लाख बच्चे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जो मांग आ रही है, उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। अभी महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के बारे में अजमेर दक्षिण से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि उनके यहां एक भी स्कूल नहीं खुला है। उनके यहां पांच स्कूल खोलने के आदेश हो चुके हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भगवानगंज, अजमेर; राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलाबबाड़ी, अजमेर; राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गांधी भवन तोपदड़ा, अजमेर। मैं आपको आदेश की कापी भेज दूंगा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अर्जुनलाल सेठीनगर, अजमेर; राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुभाष नगर, अजमेर।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्या, प्लीज। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्या, यह नयी परम्परा नहीं है। विराजिये आप प्लीज। आपने कुछ प्रश्न किये, उन्होंने जवाब दे दिये। इसमें खड़ा होने की क्या जरूरत है। विराजिये आप। इंटरवीन नहीं करें बीच में।

(समय: 21.00 बजे)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि हमने हर क्षेत्र में काम किया। देखिये, आजकल के बच्चे मोबाइल एप, मोबाइल गेम खेलते हैं और खेलने के कारण, मैं उस गेम का नाम अभी भूल रहा हूं कि दीवार पर चढ़ जाओ, कूद जाओ, यह कर जाओ और इससे कई लोगों के एक्सीडेंट्स भी हो गये। इन सब चीजों से बचने के लिए हमने 19 नवम्बर, 2022 को चेस का गेम शुरू किया। आपको जानकर खुशी होगी कि यह विश्व रिकार्ड बना और लगभग 56 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने इस गेम को खेला। बहुत सी स्कूलों में ऐसा लगा कि चेस के कारण से खेल का माहौल बन गया और लोगों ने यह कहा कि वीडियो गेम से अच्छा तो यह दिमाग का गेम है, इससे रेडियेशन की बीमारी नहीं होगी, उन लोगों को ट्यूमर नहीं होगा और इस गेम से दिमाग में भी सुधार आयेगा तथा क्रियेटिव पावर उनकी बढ़ेगी। उनकी सोचने की शक्ति, प्लानिंग करने की शक्ति बढ़ेगी।

सभापति महोदय, इसी प्रकार 12 अगस्त को हमने 6 देश भक्ति के गीत गाये। उसमें वन्दे मातरम्, राष्ट्र-गान, झण्डा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, हम होंगे कामयाब एक दिन, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये छह जो गीत गाये उसका भी विश्व रिकार्ड बना। उसके बाद 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर हमने सर्वधर्म प्रार्थना सभा की जिसका भी विश्व रिकार्ड बना।

अभी 4 से 10 जनवरी के बीच में रोहट (पाली) में जम्बूरी हुई। उस जम्बूरी में भारत की राष्ट्रपति महोदया द्रोपदी मुर्मू जी पधारी थीं, माननीय मुख्य मंत्री जी थे, मैं स्वयं था और काफी लोग उसमें थे। उसमें जो हमने स्टेडियम बनाया, उस स्टेडियम के बारे में भी विश्व रिकार्ड बना और 25 करोड़ रुपये माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसके लिए स्वीकृत किये। इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट्स के अलग-अलग खर्चे हुए और 67 वर्ष बाद हमारे यहां इस राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन हुआ जिसमें काफी एशियाई देशों, अफ्रीकन कंट्रीज के लोग आये जिससे राजस्थान का नाम हुआ। स्काउटिंग के

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

क्षेत्र में, जिसमें यह सिखाते हैं कि हमारा कर्म है सेवा, हमारा धर्म है सेवा, हमारा ईमान है सेवा, यह स्काउटिंग में सिखाते हैं। इस स्काउटिंग-गाइडिंग की एक्टिविटी से राजस्थान का नाम पूरे भारत में ही नहीं, विदेशों में भी फैला।

इसके अलावा फिट इण्डिया में दो वर्षों से राजस्थान फर्स्ट आ रहा है। इंस्पायर अवार्ड है, उसके नोमिनेशन में लगभग तीन सालों से हम लोग फर्स्ट आ रहे हैं। अभी अजमेर उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, बीमारू राज्य में हम कभी होंगे पर अभी तो जो एजुकेशन लर्निंग प्रोसेस का सर्वे हुआ, उसमें राजस्थान पहले तीन राज्यों में से एक रहा है और हर क्षेत्र में राजस्थान आगे है। विश्व रिकार्ड बना रहा है। आपके वक्त में तो नहीं बने। आप बता दो अगर कोई एक भी विश्व रिकार्ड बना हो तो।

श्री सभापति: कृपया शांति से सुनें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): स्कूलों का जहां तक सवाल है तो अभी अजमेर दक्षिण से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थीं कि ड्राप-आउट की प्रोब्लम बहुत बढ़ रही है। ड्रापआउट की प्रोब्लम बढ़ी नहीं है। ड्राप-आउट की प्रोब्लम को हल करने के लिए हमने राजस्थान के उन गांवों में जिनकी आबादी 200-250 थी उनमें रेगिस्तानी और पर्वतीय इलाकों में 200 की आबादी पर और सामान्य क्षेत्र में 250 की आबादी पर हमने राजीव गांधी पाठशालाएं खोल दीं। मुझे अफसोस है कि हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने अपने समय में उन स्कूलों को बन्द कर दिया। फिर इन्होंने अभी कहा कि उसमें 1250 स्कूल ही खुले हैं, तो 1518 स्कूलों को हमने डी-मर्ज कर दिया है और अब एक भी एप्लीकेशन मेरे पास पैंडिंग नहीं है। जो डी-मर्ज करने के लिए मेरे पास आई थीं, जिन-जिन स्कूलों को खोलने की एप्लीकेशन मेरे पास आई, उन सभी स्थानों पर हमने उन स्कूलों को नये रूप में खोल दिया है।

इसी प्रकार वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 317 नवीन प्राथमिक शालाएं, 1456 प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर तक की शालाएं, 1195 उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर, 4443 माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर, 1197 उच्च प्राथमिक से सीधे उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूलें क्रमोन्नत की गई हैं।

बालिका शिक्षा- सभापति महोदय, बालिका शिक्षा बहुत जरूरी है। एक गाड़ी के दो पहिये हैं और एक पहिया पंक्चर हो जाएगा तो गाड़ी चल नहीं

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

पायेगी इसलिए सामाजिक गाड़ी के दो पहिये पुरुष और स्त्री हैं। यदि केवल पुरुष अकेला पढ़ लेगा तो समाज अधूरा रह जायेगा और महिला यदि पढ़ती है तो शादी से पहले पीहर में रहकर पीहर को फायदा देगी और शादी के बाद ससुराल जाएगी तो ससुराल में भी उसकी शिक्षा काम आयेगी। इसलिए नारी शक्ति को शिक्षित, स्वावलम्बी और सशक्त बनाना बहुत जरूरी है। हमारे यहां तो कहा गया है- 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:', जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। मैं जब शिविरा में लिखता हूं, आप पुराने शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं, आप उसमें पढ़िये, मैंने लिखा है- 'मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्।' परायी स्त्री को मां की तरह समझो और पराये धन को चोरे हुए धन के बराबर समझो। इस समय जो छोटी-मोटी घटनाएं हैं जिनका जिक्र अजमेर दक्षिण से आने वाली माननीय सदस्या ने किया, मैंने बहुत पहले ये बातें लिखीं और उसका असर पड़ा कि आज शिक्षण संस्थाओं में लोग शालीनता से रहते हैं और जिसने शालीनता या मर्यादा को भंग किया है, अनुशासन को भंग किया है, उसके खिलाफ शिक्षा विभाग सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा और उनको कानून के अनुसार सज़ा देगा।

115 बालिका प्राथमिक विद्यालयों को बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, 400 बालिका माध्यमिक विद्यालयों को बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, 480 बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे ही बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर तक क्रमोन्नत किया गया है।

इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार- मानसिक एवं शारीरिक क्षमता के संवर्द्धन हेतु रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के अन्तर्गत 2 लाख 50 हजार छात्राओं को प्रशिक्षित किया गया है जो जूडो-कराटे सीखकर 5-5, 10-10 अपने से बलिष्ठ लोगों से मुकाबला कर सकती हैं और ऐसा प्रदर्शन आपने 15 अगस्त और 26 जनवरी को छात्राओं का देखा होगा। हम चाहते हैं कि महिलाएं केवल शिक्षित ही नहीं हों, सशक्त बनें, स्वावलम्बी बनें, अपने पैरों पर खड़ी हों और हर तरीके से हर चीज का मुकाबला कर सकें।

इसी प्रकार 1439 अतिरिक्त संकाय जिसमें कृषि विषय भी सम्मिलित हैं। 57 नये ब्लाकों पर सीबीईईओ के आफिस खोले गये।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री बाल-गोपाल योजना के अन्तर्गत हमने दूध वितरण का काम एक सप्ताह में दो दिन के लिए शुरू किया था। माननीय

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

मुख्य मंत्री जी ने जो नये बजट में घोषणा की है उसमें नये सत्र से हम पूरे सप्ताह विद्यार्थियों को दूध पिलायेंगे। डेयरी का दूध आरसीडीएफ की लैब ने उसके सभी मानकों को टैस्ट करके दिया है और इसमें कोई संशय करने की जरूरत नहीं है और हमारी आरसीडीएफ के ऊपर भरोसा करके हमको चलना चाहिए। इसमें कहीं किसी भी प्रकार की शिकायत आयेगी तो उसको हम अच्छे तरीके से देखेंगे।

हमारे यहां कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई काफी प्रभावित हुई। इस बात को लेकर हमारे मुख्य मंत्री जी सदैव चिंतित रहते थे। कोरोना काल में जो लोग स्कूल जाने से वंचित रह गये थे या डिजिटल पढ़ाई नहीं कर पाये थे उनके लिए तीसरी से आठवीं तक के बच्चों के लिए हिन्दी, इंग्लिश और गणित का एक ब्रिज कोर्स बनाया और उसको पढ़ाने के बाद उनका एक आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के माध्यम से इवेल्युएशन कराया। आपको जानकर खुशी होगी, पूरे सदन को भी इस बात के बारे में एप्रिशियेट करना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का अमेरिका में भी तीसरी से आठवीं तक कभी इवेल्युएशन नहीं हुआ है और यह भी विश्व रिकार्ड बना। इससे हमारे विद्यार्थियों की इस कमी को हम दूर कर सके तथा उनको हिन्दी, इंग्लिश और गणित में अपने पूर्व स्तर पर लाने में कामयाब हो सके।

इसके अलावा हमारे यहां जितने भी सर्वे हुए हैं उनमें नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जिसमें कक्षावार, विषयवार औसत अंकों के आधार पर हमारा प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम तीन राज्यों में रहा। दिल्ली का बहुत प्रोपेगेंडा विज्ञापन होता है, दिल्ली का नम्बर सातवें स्थान पर रहा है। भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में राजस्थान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसमें आगे बढ़कर काम किया है। स्वच्छ भारत विद्यालय, इसमें भी विवेकानन्द मॉडल स्कूल, पनवाड़-टोंक; राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गंगापुर, भीलवाड़ा का चयन किया गया है।

इसी के साथ-साथ हमारे यहां यूनिफार्म के बारे में कई माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाये थे। लाडपुरा से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा था कि हजार रुपये सिलाई के मिलने चाहिए। भारत सरकार की 600 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत थी, उसमें से मात्र 174.23 करोड़ रुपये दिये हैं। राज्य सरकार ने कपड़े के लिए 116.16 करोड़, जनरल बॉय्ज को। भारत सरकार

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

एससी, एसटी, बीपीएल परिवारों और गर्ल्स चाइल्ड को, बाकी जितने भी बच्चे हैं, उनको राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से ड्रेस दी है। इसके अलावा 94.61 करोड़ रुपये हैं। सिलाई के लिए मात्र 60 रुपये बच रहे थे तो 140 रुपये राज्य सरकार ने अलग से अपने बजट से दिये हैं। राज्य सरकार ने 325.87 करोड़ और केन्द्र सरकार का इसमें सहयोग केवल 174.23 करोड़ का रहा है।

33 हजार 711 समन्वित आंगनबाड़ी के केन्द्र, जिसमें प्री-प्राइमरी बच्चों के लिए आउटडोर प्ले मैटेरियल, 37 हजार 400 आंगनबाड़ी केन्द्रों और अंग्रेजी माध्यम के प्री-प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर उपलब्ध कराया गया।

ज्ञान संकल्प पोर्टल पर दर्ज उपलब्धियां:- इसमें आपके वक्त में 78 करोड़ रुपये आये थे, हमारे इस कार्यकाल में 300 करोड़ रुपये उपलब्ध हुए हैं। इसका मतलब जनता का विश्वास है कि राजस्थान सरकार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। इनको अधिक से अधिक सहयोग दिया जाये।

कम्प्यूटर अनुदेशकों के 10 हजार 453 पद सृजित किये गये हैं और भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण कर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।

विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में विगत सरकार के वक्त में 1624 करोड़ के कार्य हुए हैं। हमारे वक्त में 2128 करोड़ रुपये के ढांचागत विकास के कार्य किये गये हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि मरम्मत के लिए कुछ नहीं है, स्कूलें जर्जर हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 120 करोड़ रुपये की राशि राजस्थान सरकार ने इसके लिए अभी हाल ही में प्रोवाइड की है, इससे अधिकांश स्कूलें, जो जर्जर हैं, खण्डित हैं या मरम्मत के योग्य हैं, उनके रख-रखाव के लिए यह पैसा खर्च किया जायेगा।

आईसीटी क्लासेज, राजस्थान में 17 हजार 475 सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल्स हैं। सभापति महोदय, हमने इनमें से करीब-करीब 13 हजार 403 के लिए तो प्रावधान किया हुआ है और 4 हजार 72 स्कूलें बची हैं। मेरा ऐसा अनुमान है कि हमारा विभाग टीम स्पिरिट से काम कर रहा है। उसके आधार पर हम अगले एक वर्ष के अन्दर-अन्दर तमाम राजस्थान की सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों में आईसीटी क्लासेज शुरू कर देंगे। इसका फायदा क्या होगा। सरकार तो आप देखना, हम जो बजट लेकर आये हैं न, आप सपने

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

लेना, हवाई किले बनाते रहना, यूट्यूबर बने रहना, सरकार जो काम करेगी, उससे सरकार को आगे आने का मौका मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि आईसीटी क्लासेज के साथ-साथ हमने बीकानेर में, उदयपुर में, जयपुर में स्टूडियो का निर्माण किया है। उनमें यहां से बैठे-बैठे शिव, बाड़मेर में फिजिक्स का टीचर नहीं है तो यहां से आईसीटी क्लासेज के माध्यम से उसको पढ़ाया जा सकेगा। फिजिक्स, केमेस्ट्री, मैथ्स कोई भी विषय, जिसका अध्यापक जिस स्कूल में नहीं है, आईसीटी क्लासेज के माध्यम से, हम स्टूडियो के माध्यम से, हम डायरेक्ट्रेक्ट के माध्यम से, उनको जिस विषय की आवश्यकता है उस विषय के अध्यापक से वहां पर क्लास रूम में जैसे पढ़ाई होती है, वैसी पढ़ाई करवा सकेंगे।

इसके साथ-साथ मैं जो बात कह रहा हूं, तथ्यात्मक कह रहा हूं। इनको एक-एक घंटे सुना है, मुझे कम से कम इनका जवाब भी देना पड़ेगा।

देखिये, नवीन प्राथमिक विद्यालय की स्थापना 266, हमने चार सालों में की। 13 दिसम्बर, 2013 से 31 दिसम्बर तक की मैं तुलना कर रहा हूं। आपने एक भी प्राथमिक स्कूल नहीं खोला। हमने प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय 1453 खोले, आपने 178 खोले। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक 1152, आपके यहां निल। नव-क्रमोन्नत विद्यालयों में सुदृढ़ीकरण के कार्य 506 और आपके वक्त में 174 कार्य। मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरे खिलाफ प्रिविलेज ले आना। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बीच में इंटरवीन नहीं करें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): नव-क्रमोन्नत विद्यालयों में सुदृढ़ीकरण 506 और आपके वक्त में 174, अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण 22 हजार 361, आपके वक्त में 21 हजार 524, मॉडल स्कूलों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का निर्माण 126, आपके वक्त में जीरो। मॉडल स्कूलों में बालिका छात्रावास का निर्माण 17, आपके वक्त में जीरो। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 39, आपके वक्त में जीरो। बालिकाओं को नि:शुल्क साइकिल वितरण इसमें 10 लाख 34 हजार 883, आपके वक्त में 8 लाख 31 हजार 393 और आपकी बेटी योजना में उपलब्ध कराई गई प्रोत्साहन राशि 1301.19 और आपके वक्त में 1183.30. इसी प्रकार इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना में उपलब्ध कराई गई प्रोत्साहन राशि 6 हजार 749.16, यह लाखों में है और आपके वक्त में निल।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

बालिका प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित बालिकाएं 2 लाख 77 हजार 71 और आपके चार वर्षों में 1 लाख 36 हजार 252. हमने नियुक्तियां दी हैं, आप कह रहे हैं न कि कोई नियुक्ति नहीं दी। 17 दिसम्बर, 2018 से 28 फरवरी, 2023 तक, जो नियुक्तियां और पदोन्नतियां दी गई हैं, उनमें प्रधानाध्यापक 1241, व्याख्याता 5 हजार 139, वरिष्ठ अध्यापक 10 हजार 554, शीघ्रलिपिक 27, शारीरिक शिक्षक ग्रेड-III 4 हजार 912, शारीरिक शिक्षक ग्रेड-II 46, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड-III भर्ती 731. एक माननीय सदस्य बता रहे थे, पुस्तकालयों में कोई भर्ती नहीं हुई है, पुस्तकालयों में भर्ती हुई है। वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक 246, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-III भर्ती 1231, कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती 7 हजार 656, वरिष्ठ अध्यापक अनुकम्पात्मक नियुक्ति 1, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक आउट टर्म 1, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-III अनुकम्पात्मक नियुक्ति 1121, कनिष्ठ सहायक अनुकम्पात्मक नियुक्ति 2518, सहायक कर्मचारी अनुकम्पात्मक नियुक्ति 773. आप लोगों ने कहा सहायक कर्मचारी बिलकुल नहीं किये। सहायक कर्मचारियों को नियुक्तियां दी हैं। सभापति महोदय, अध्यापक लेवल I एण्ड II 44 हजार 925, इस प्रकार 81 हजार 122 व्यक्तियों को हमने नियुक्तियां दे दीं और डीपीसी के माध्यम से 50 हजार 169 पदोन्नतियां अलग-अलग वर्गों में हमने दी हैं।

इसके बाद जो भर्तियां होने वाली हैं, उसकी सूचना भी, सभापति महोदय, आपके माध्यम से देना चाहता हूं। बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के 9 हजार 862 पदों हेतु चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 18.01.2023 को परिणाम जारी, आवेदन पत्रों की जांच विभागास्तर पर प्रक्रियाधीन है। व्याख्याता विभिन्न विषयों के 6 हजार पदों के लिए आयोग द्वारा अक्टूबर माह में परीक्षा आयोजित। आयोग स्तर पर परिणाम जारी किया जाना है। द्वितीय श्रेणी अध्यापक के 9,760 पदों के लिए आयोग द्वारा दिसम्बर माह में परीक्षा आयोजित। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के 461 पदों हेतु 30 अप्रैल, 2023 को परीक्षा आयोजित की जानी प्रस्तावित है। शारीरिक शिक्षा अध्यापक के 5,546 पदों हेतु चयन बोर्ड द्वारा अन्तरिम परिणाम जारी। पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड III के 460 पदों हेतु चयन बोर्ड द्वारा अन्तरिम परिणाम जारी। प्रयोगशाला सहायक ग्रेड III 461 पदों हेतु चयन बोर्ड द्वारा अन्तरिम परिणाम जारी। चयन बोर्ड द्वारा अभिस्तावना भिजवायी जानी शेष है। अध्यापक लेवल I के

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

21 हजार एवं अध्यापक लेवल II के 27 हजार पदों पर चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 25.2.2023 से 28.2.2023 तक परीक्षा आयोजित की गयी। कोई पेपर आउट नहीं हुआ। रीट सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। सहायक अध्यापक लेवल I व II अंग्रेजी माध्यम...। आपको पेपर आउट होने पर ज्यादा खुशी होती है क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति: बीच में नहीं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): हमने जब वरिष्ठ अध्यापकों के एग्जाम कराये थे, उस दिन गुजरात में पेपर आउट हो गया और आप कुछ नहीं कर सके। इसमें तो आपको और हमको मिल कर कार्रवाई करनी होगी और हमने कानून को मजबूत किया है, दस साल की सज़ा और सम्पत्ति को कुर्क करना।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): जारोली को दिलवाओ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): वह तो ऐसा है एसओजी जो भी कार्रवाई करेगी जिसके खिलाफ भी करेगी, कार्रवाई करेंगे। 27 हजार पदों पर चयन बोर्ड द्वारा यह परीक्षाएं आयोजित की गईं। सभापति महोदय, 48 हजार पद एक साथ भरे जायेंगे और जैसे ही परिणाम आयेगा हम उनकी नियुक्तियां करेंगे। सहायक अध्यापक लेवल I व लेवल II माध्यम संविदा के 9712 पदों हेतु विज्ञप्ति जारी।

अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के बारे में बहुत माननीय सदस्य चिन्ता कर रहे थे। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि जैसे ही ये पद भरे जायेंगे, केवल मात्र 2 हजार लगभग पद रिक्त हैं, उन पदों को हम भर लेंगे और जब तक ये नये पद नहीं भरे जाते हैं तब तक हम लोग सलेक्शन करके हमारा ही जो कॉडर है उसमें अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाने वाले लोगों को प्रतिनियुक्ति पर भेज कर इस काम को करा रहे हैं। इस प्रकार 90,262 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है।

अब जो कक्षा कमरों की कमी और मांग कर रहे थे कि चारदीवारी नहीं है, कहीं लैब नहीं है तो इसके लिए अभी हाल ही में 239 करोड़ रुपये की स्वीकृति आयी है, उसमें 143.40 करोड़ केन्द्र से और राज्य सरकार का 95.60 करोड़ पैसा लगेगा और इससे प्राथमिकता के आधार पर जो-जो बहुत जगह जहां अतिरिक्त आवश्यकता है कक्षा कमरों की उनको हम प्राथमिकता देकर कराने का प्रयास करेंगे।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

अब मैं इस बजट में जो प्रमुख घोषणायें हुई हैं उनको बताना चाहूंगा। गत बजट के अनुसार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एवं अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सावित्री बाई फुले वाचनालय स्थापित करने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। इसे और आगे बढ़ाते हुए अब समस्त ब्लाक मुख्यालयों पर सावित्री बाई फुले वाचनालय मय डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है। स्कूली विद्यार्थियों को रोडवेज बसों में उनके शिक्षण संस्थान से निवास स्थान तक दी जा रही छूट की परिधि को 50 किलोमीटर से बढ़ा कर 75 किलोमीटर किया जा रहा है।

वर्तमान में राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटीई के अन्तर्गत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों हेतु ही निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। पिछले बजट में राज्य सरकार के खर्चे पर छात्राओं के लिए कक्षा 9 से 12 तक निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा जारी रखने की व्यवस्था की गयी थी। अब छात्राओं के साथ ही छात्रों को भी आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने के उपरान्त कक्षा 1 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किये जाने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में की और इस हेतु कक्षा 9 से 12 में शिक्षण के लिए देय फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा और इस पर 75 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी।

प्रदेश के मेधावी छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहित करने की दृष्टि से नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की तर्ज पर दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों हेतु राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन स्कालरशिप प्रारम्भ की जायेगी। इसके अन्तर्गत दस हजार मेधावी विद्यार्थियों को स्कालरशिप दी जायेगी।

प्रदेश में स्कूली विद्यार्थियों की अध्ययन सुविधा का विस्तार करने की दिशा में प्रदेश में सौ नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने के साथ ही तीन सौ विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जायेगा तथा तीन सौ विद्यालयों में नवीन विषय खोले जायेंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर विज्ञान का ऐच्छिक विषय के रूप में लिए जाने का विकल्प दिया जायेगा।

प्रत्येक ब्लाक मुख्यालय पर एक-एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में चारों संकाय कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं कृषि की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। राजकीय विद्यालयों में आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण एवं सुविधाओं

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

के विस्तार हेतु प्रदेश के 358 शैक्षणिक ब्लॉकों पर विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों हेतु लर्निंग एड सामग्रीयुक्त सन्दर्भ कक्षों का निर्माण करवाया जायेगा। इस हेतु चालीस करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं यथा क्लास रूम, लैब्स, शौचालयों के निर्माण तथा जर्जर भवनों आदि के लिए भी लगभग जैसा मैंने आपको बताया था, 120 करोड़ रुपये की लागत से कार्य करवाये जायेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसको बढ़ा कर दो सौ करोड़ रुपये की राशि कर दी है।

आगामी वर्ष में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एक-एक हजार महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल और खोले जायेंगे। इन विद्यालयों में दो सौ से अधिक विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे, वहां भी प्राथमिकता से इंग्लिश मीडियम विंग प्रारम्भ की जायेगी।

चरणबद्ध रूप से प्रदेश के समस्त सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एनएसएस, एनसीसी, स्काउटिंग एवं गाइड्स की गतिविधियां प्रारम्भ की जायेंगी। नयी पहल करते हुए प्रदेश में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं। ये विद्यालय गुणवत्ता की दृष्टि से किसी भी निजी विद्यालय से बेहतर हों, इस दृष्टि से एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर लोंग टर्म स्ट्रेटेजी एवं एक्शन प्लान निर्धारित किया जायेगा।

प्रदेश में शिक्षण एवं अन्य सुविधाओं के विस्तार हेतु राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय एवं स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों के संस्था प्रधानों और चयनित शिक्षकों को स्पोकन इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन एवं लीडरशिप डवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जायेगी।

प्रदेश के 358 शैक्षणिक ब्लाक मुख्यालयों पर स्कूलों, कालेजों में बीस करोड़ रुपये की लागत से इंग्लिश लैंग्वेज लैब्स की स्थापना की जायेगी। इससे पचास हजार से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्री-स्कूल एजुकेशन उपलब्ध कराने के निर्णय के साथ-साथ चरणबद्ध रूप से प्ले एलिमेंट्स भी लगाये जायेंगे। इस पर आगामी वर्ष पचास करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायेगी।

आईसीटी परियोजना के तहत चार हजार उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 256 करोड़ रुपये की लागत से कम्प्यूटर लैब स्थापित किये जायेंगे। महाराव शेखाजी आर्म्ड फोर्सेज ट्रेनिंग अकेडमी, सीकर तथा सर्विसेज प्रिपेटरी

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

इंस्टीट्यूट, औरंगाबाद की तर्ज पर सम्भाग स्तर पर एक-एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में डिफेंस सर्विसेज प्रिप्रेटरी इंस्टीट्यूट की स्थापना की जायेगी और इस पर 35 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

सभापति महोदय, समस्त आवासीय तथा चयनित विद्यालयों में कक्षा 11वीं, 12वीं के विद्यार्थियों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ-साथ वर्कशाप में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा केन्द्र शुरू किये जायेंगे एवं आगामी वर्ष इस हेतु पचास करोड़ रुपये की राशि व्यय की जायेगी।

प्रदेश के कस्तूरबा गांधी विद्यालय, गांधी बालिका, एकलव्य, देवनारायण तथा अन्य सभी आवासीय विद्यालयों के साथ-साथ एससी/एसटी, ओबीसी/एमबीसी सहित सभी छात्रावासों में आधुनिकीकरण एवं आधारभूत सुविधाओं के विभिन्न कार्य सौ करोड़ रुपये की लागत से किये जायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं जो माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये, सबसे पहले तो...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मान ही गये हम। हम तो बिलकुल मान गये। हमने उत्तर प्राप्त कर लिया, आप तो मांग पारित करवाओ।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): एक सैकंड। आपने रिक्त पदों के बारे में कहा, उसके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया कि 48 हजार तो हम अध्यापकों के पद भर्ती कर रहे हैं और करीब 90 हजार टीचर्स की भर्ती अलग-अलग कर रहे हैं, तो सारी रिक्तियां भर जायेंगी। देखिये हाथ में सरसों उगाने की बात नहीं करते हैं हम। हम गुड डिलीवर करने की बात करते हैं और गुड डिलीवर करने के लिए आपको पूरा एक्शन प्लान बता दिया कि यह-यह चीजें हम करने जा रहे हैं, इसलिये रिक्त पदों के बारे में जिन-जिन माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की थी, वह दूर हो जानी चाहिये।

आपने कहा कि झंडी वितरण में 5 करोड़ का चंदा हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं वर्ष 2022 में छात्र-छात्राओं, अध्यापकों और कार्मिकों से 90 लाख 88 हजार रुपये प्राप्त हुए। यह कोई अभी से नहीं, 50 साल से यह काम हो रहा है। इस पैसे का उपयोग राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण परिषद् से शिक्षक कल्याण की गतिविधियों में होता है। यह आपके वक्त में भी हुआ था। आप शिक्षा मंत्री रहे हैं, कम से कम आपको यह बात नहीं उठानी चाहिये। जो

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

काम 50 वर्ष से चल रहा है, उसके बारे में सदन को बताना कि 5 करोड़ रुपये की राशि इकट्ठी कर ली, जैसे कोई हमने चंदा कर लिया हो।

आपने कार्य दिवसों के बारे में बताया, आप हमारा पंचांग पढ़ लें, इस वर्ष 184 कार्य दिवस हैं, मिनिमम 180 होने चाहिये। आप कोई चिंता नहीं करें, हम विद्यार्थी को किताबी कीड़ा नहीं बनाना चाहते, हम चाहते हैं,

"काक चेष्टा, बको ध्यानं,
श्वान निद्रा तथैव च।
अल्पहारी, गृहत्यागी,
विद्यार्थी पंच लक्षणं॥"

हम चाहते हैं विद्यार्थी कौवे की तरह चेष्टाशील बने। बगुले की तरह ध्यान केन्द्रित होकर पढ़े और उसकी जाग निद्रा हो, संतुलित आहार ले, घर गृहस्थी की बातों से अलग रहे और एक्स्ट्रा केरिकुलर, को-केरिकुलर एक्टिविटीज में वह भाग ले ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो।

एक बार अब्राहम लिंकन ने अपने बच्चों के टीचर से यह कहा था कि मेरे बच्चे को केवल सफल होना नहीं सिखायें, उसको असफल होने पर सफल होना सिखायें, गिरकर संभलना सिखायें। हम लोग नो बैग्स डे के अंतर्गत उसका सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं।

आपने स्कूलों में नामांकन में गिरावट की बात कही। 2019-20 में 81.6 लाख, 2020-21 में 88.3 लाख, 2021-22 में 96.50 लाख का नामांकन हुआ। गिरावट कहां आई है? इस साल जो हुआ है उसके लिए आपको बताया कोविड पीरियड के बाद प्राइवेट स्कूलें बंद हो गई थीं, इसके कारण से कुछ लोग प्राइवेट स्कूलों में चले गये।

इसके साथ चौरासी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पूर्व में स्कूल कालीबाई के नाम पर था। यह स्कूल डीमर्ज हो गई थी, अब वापस इसको खोल दिया है। मैं घोषणा करता हूं कि इसका नाम कालीबाई के नाम से कर दिया जायेगा।

जवाब तो मैं सबके दे सकता हूं, मैंने एक-एक का लिखा हुआ है, आप बोलो क्या करना है? (व्यवधान) खेतड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने शिक्षा के महत्व के बारे में बात की और यह कहा, जिस झुंझुनूं से पहले एक दो व्यक्ति ही पढ़ाई में आगे जाते थे, आज कम से कम 350 से ज्यादा लोग डाक्टर बन गये। शिक्षा के कारण ही सब लोग बनते हैं।

श्री सभापति: साढ़े बारह बजे आप लोगों ने शुरू किया था, माननीय मंत्री महोदय ने तो साढ़े बारह से लेकर साढ़े आठ बजे तक आपको झेला है, आधे घंटे में ही आप तो थक गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आसन निर्देश दे दे कि इनको कितने बजे तक झेलना है। आसन व्यवस्था दे दे, उतने घंटे झेलेंगे।

श्री सभापति: आपकी क्षमता पर है कि कितना झेल सकते हो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कितने घंटे?

श्री सभापति: आपको नाप रहे हैं कि कितना झेल सकते हैं आप। (व्यवधान) विराजिए, विराजिए।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने पेयजल की व्यवस्था के बारे, सब्जेक्ट टीचर के बारे में, खेल के मैदानों में अतिक्रमण के बारे में बताया। खेल के मैदानों में अतिक्रमण रोकने के लिए हमने निर्देश जारी किये हुए हैं। स्कूल डवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट कमेटी को पूरा अधिकार है कि वह अतिक्रमणों को खाली कराये और उसमें कलेक्टर और रेवेन्यू एजेंसी की जो भी सहायता होगी, वह करेंगे और कलेक्टर महोदय को भी यह निर्देश जारी किये हुए हैं कि वह इस संबंध में उनको सहयोग करें।

सादुलशहर से आने वाले माननीय सदस्य ने इंग्लिश मीडियम स्कूल के महत्व के बारे में और अध्यापकों की भर्ती की बारे में कहा था। इसमें भर्ती की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। वार्षिक उत्सव और पंजाबी टीचर्स की भर्ती के बारे में उन्होंने बताया, तो हमने हर भाषा के, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, जिन-जिन भाषा के टीचर की आवश्यकता थी और जो मांग थी, उसके अनुसार उनको भरने की कार्यवाही शुरू कर दी है।

आहोर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि परीक्षा का केन्द्र आपके यहां नहीं हुआ। जहां नकल होती है और अनफेयर मीन्स काम में लिए जाते हैं, उनके परीक्षा केन्द्र बोर्ड बंद कर देता है। बोर्ड आटोनोमस बॉडी है, हम उनको कभी इंटरफियरेंस नहीं करते... (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए, किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय सदस्य, मैंने किसी स्थान का नाम नहीं लिया है, मैंने तो यह कहा है कि जिन परीक्षा केन्द्रों में अनफेयर मीन्स होते हैं, उनके केन्द्रों को बोर्ड बंद कर देता है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए, प्लीज विराजिए। किसी का भी अंकित नहीं होगा।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): कुछ माननीय सदस्यों ने प्रबोधकों को वरिष्ठ अध्यापक बनाने के लिए यहां पर प्रस्ताव रखे। उनको हमने वरिष्ठ प्रबोधक बना दिया है और उनकी आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार आया है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपस में वार्ता नहीं, कृपया शांति रखें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): आहोर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ भामाशाहों का सम्मान करने की बात की। आप उन भामाशाहों की पूरी डिटेल मुझे दे दें, उन भामाशाहों ने मदद की है तो हम भामाशाह दिवस मनाते हैं, उसमें उनका सम्मान कर देंगे।

पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य ने विज्ञान संकाय खोलने के बारे में बात की है, आप प्रस्ताव भिजवाएं, अगर हमारे नोर्म्स में आयेंगे तो हम उस पर विचार करेंगे।

सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने खेल के मैदानों की कमी, खेल सामग्री, भवनों की कमी, विषय खोले जाएं, जर्जर भवनों की मरम्मत हो, इसके बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूं। इस बार 200 करोड़ रुपये माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसके लिए प्रस्तावित किये हैं। वैसे तो करीब-करीब 40 हजार स्कूलों में खेल के मैदान हैं और मैं आप सब जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूं कि खेल बहुत जरूरी हैं। मदन मोहन मालवीय जी कहते थे दूध पीओ, कसरत करो और नित्य करो गृह काम, हिम्मत से मेहनत करो सफल करेंगे श्रीराम। यह तो राम राम करते हैं, हमारे मदन मोहन मालवीय जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वह हमेशा खेलने पर, कसरत पर जोर देते थे। आपने तो यह कह दिया कि योगाभ्यास बंद कर दिया। हम हर दिन प्रार्थना सभा में योगाभ्यास करवाते हैं। कौन कहता है हमने बंद कर दिया? आप स्कूलों में जाकर देखिए।

बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्यों ने रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्रों में स्कूलें खोलने की बात कही है। यह बात सही है कि हमारे पहाड़ी क्षेत्र और रेगिस्तानी क्षेत्रों में स्कूलों की कमी है। पिछले बजट में डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट में ही केवल मात्र प्राथमिक स्कूल खोले गये थे। बाड़मेर में हमने प्राथमिकता से स्कूल खोले हैं, आगे भी ध्यान रखेंगे।

चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य ने इंग्लिश मीडियम स्कूलों के भवन, अध्यापक और कक्षा कक्ष में अधिक संसाधन देने की बात कही। आप

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

जानते हैं कि इस बार बजट 120 से 200 करोड़ का हो गया है, इस पर काम किया जायेगा।

खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य ने लाइब्रेरियन की भर्ती का सवाल उठाया था। इस बारे में मैंने बता दिया कि हम 450 से अधिक लाइब्रेरियन की परीक्षा ले चुके हैं, शीघ्र ही उनकी नियुक्ति की जायेगी। विवेकानंद मॉडल स्कूल, नये विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय पर भी उन्होंने अपने विचार दिये। नये विवेकानंद स्कूल खोलने अब बंद कर दिये गये हैं। 134 विवेकानंद विद्यालय हमने हमारे राज में खोले हुए हैं।

भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कई उपयोगी सुझाव दिये और थर्ड ग्रेड के स्थानांतरण की नीति बनाने की बात की। नीति प्रक्रियाधीन है, बहुत शीघ्र आपके सामने आयेगी।

अजमेर उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा कि आपने सैकण्ड ग्रेड के कर दिये, फर्स्ट ग्रेड के ट्रांसफर कर दिये, थर्ड ग्रेड के नहीं किये। आपने कब किये? (व्यवधान) चुनाव से पहले एक बार किये थे, चुनाव तो अभी बहुत दूर है। धीरे धीरे ठाकरा, धीरे सब कुछ होय।

पिंडवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कमरों की कमी का जिक्र किया। जैसा मैंने आपको बताया, प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड ने 22 जिलों को बीच में निकाल दिया था, अब वापस उन्होंने उसको जोड़ा है। जैसे-जैसे बजट उपलब्ध होगा, हम इसके बारे में कार्यवाही करेंगे।

नोहर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ उपयोगी सुझाव दिये हैं। लाडपुरा से आने वाली माननीया सदस्या ने भवनों को सुरक्षित रखने हेतु सर्वे करने की आवश्यकता बतायी है और एक स्कूल जो कि 1950 से चल रहा है, उसकी डिटेल आप देंगे तो मैं गुणावगुण के आधार पर उसकी बात करूंगा। आपने सिलाई का जो जिक्र किया था। एक हजार रुपये सिलाई, भारत सरकार दे देगी तो हम अपना हिस्सा दे देंगे। बाड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने स्कूल क्रमोन्नति के मामले उठाये और कुछ जगह स्टाफ की कमी का जिक्र किया, तो स्टाफ की कमी को हम शीघ्र दूर कर देंगे।

आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने बाउंड्रीवाल, डी एम एफ टी से कमरों का निर्माण। कुछ माननीय सदस्यों ने तो यहां तक कहा कि हम विधायक कोटे का पैसा स्कूलों में लगाने के लिए तैयार हैं। उसके लिए

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

कोई मनाही नहीं है। जहां तक डवटेल करने का सवाल है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहले से ही मनरेगा स्कीम में जो लेबर कम्पोनेंट लगती है और मैटेरियल कम्पोनेंट आप विधायक कोटे से देंगे तो कक्षा कमरों का काफी हो सकता है।

रामगढ़ से आने वाली माननीया सदस्या ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों और खास तौर से बालिका विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की बात की, उसके बारे में हम बजट के अनुसार कार्यवाही करेंगे। जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कोटड़ी में विज्ञान संकाय, खेल मैदानों को बचाने, अतिक्रमणों को हटाने के बारे में विस्तार से बता दिया। शिव से आने वाले माननीय सदस्य ने रेगिस्तानी इलाकों में अधिक से अधिक स्कूल खोलने की बात कही, तो हमने सबसे ज्यादा स्कूल शिव में ही खोले हैं, अभी जो 100 स्कूल खोले हैं। ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने भवनों के सुधार हेतु, हैंडपम्प का अभियान अभी हमने बीच में चलाया था।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, काफी हो गया।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): बस दो-तीन ही रहे हैं। चलो इसको समाप्त करता हूं। जो कटौती प्रस्ताव मेरे पास आये हैं, मैं बहुत शीघ्र उन सबके जवाब आपके पास पहुंचा दूंगा।

मैं खास तौर से यह कहना चाहूंगा कि शिक्षा जो है 'असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय' तो यह सत्य का मार्ग दिखाती है। विद्या हमें सही रास्ते पर ले जाती है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है और मृत्यु से अमृत की ओर ले जाती है। विवेकानन्द जी ने कहा था कि, "awake, arise and stop not until the goal is reached." उठो, जागो, और तब तक मत रूको, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। हमारा लक्ष्य क्या है, हम पूरे राजस्थान को शत प्रतिशत साक्षर करना चाहते हैं, शिक्षित करना चाहते हैं, स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी शिक्षा के बढ़ते कदम के माध्यम से हमारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से अच्छा बनाना चाहते हैं। आइये, इसमें आप और हम सब मिलकर चलें और शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हुए देश भर में राजस्थान को अव्वल नम्बर पर लाना है। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मांग संख्या 20 और 21 और 22 को पारित कराने की कृपा करें।

मांग संख्या 20-प्रारंभिक शिक्षा का पारण

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 20-प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,89,85,40,53,000/- (एक सौ नवासी अरब पचासी करोड़ चालीस लाख तिरेपन हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 21-माध्यमिक शिक्षा का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 21-माध्यमिक शिक्षा विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,43,92,25,08,000/- (दो सौ तैंतालीस अरब बानवे करोड़ पच्चीस लाख आठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 22-उच्च शिक्षा का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 22-उच्च शिक्षा विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 23,23,66,51,000/- (तेईस अरब तेईस करोड़ छियासठ लाख इक्यावन हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 02 मार्च 2023 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21:44 बजे गुरुवार, दिनांक 02 मार्च 2023 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

बाड़ी के सामान्य चिकित्सालय में रिक्त पद

224. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

सामान्य चिकित्सालय बाड़ी, बसई नवाब एवं सैपऊ में वर्तमान में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा उक्त में से कितने-कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

सामान्य चिकित्सालय बाड़ी, बसई नवाब एवं सैपऊ जिला धौलपुर में राजपत्रित संवर्ग के विशेषज्ञ/चिकित्सकों के 66 पद स्वीकृत, 25 पद कार्यरत एवं 41 पद रिक्त हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

सामान्य चिकित्सालय बाड़ी, बसई नवाब एवं सैपऊ जिला धौलपुर में अराजपत्रित संवर्ग के 236 पद स्वीकृत, 113 पद कार्यरत एवं 123 पद रिक्त हैं। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

जिला धौलपुर के सामान्य चिकित्सालय बसई नवाब एवं सैपऊ में एनएचएम के अन्तर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाड़ी में कार्यरत संविदा कार्मिकों की सूचना शून्य है।

रिक्त पदों को भरने से संबंधित सूचना परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

शेरगढ़ में छात्रवृत्ति के लम्बित आवेदन

231. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में वर्ष 2022-23 में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए? छात्रवृत्ति योजनावार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रवृत्ति आवेदनों में से कितनों में स्वीकृति जारी की गई व कितने प्रकरण वर्तमान में लम्बित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती मीना कंवर)

(3) क्या सरकार उक्त लम्बित छात्रवृत्ति प्रकरणों को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति-पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक एवं मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में प्राप्त आवेदन पत्रों का योजनावार विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त छात्रवृत्ति योजनाओं में विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के वर्ष 2022-23 में प्राप्त आवेदन पत्रों में से स्वीकृत एवं लम्बित आवेदन पत्रों का योजनावार विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(3) जी हां। उक्त लम्बित आवेदन पत्रों में से नियमानुसार पात्र आवेदन पत्रों को स्वीकृत किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में आनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने की अंतिम तिथि 28.02.2023 निर्धारित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नशा मुक्ति जागरूकता अभियान पर व्यय

177. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कुल कितने सरकारी व गैर सरकारी नशा मुक्ति केन्द्र संचालित हैं? श्रेणीवार एवं जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संचालित केन्द्रों में से कितने केन्द्र सरकार द्वारा तय नियमों के अनुसार संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने विगत बजट में गुरुशरण छाबड़ा जन जागृति अभियान के तहत बजट देने की घोषणा की थी? यदि हां, तो कितना? उक्त घोषित बजट में से अब तक कितना बजट नशा मुक्ति जागरूकता अभियान पर व्यय किया गया?

उत्तर

(1) विभाग द्वारा नशा मुक्ति केन्द्रों का संचालन नहीं किया जा रहा है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुदानित स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से राज्य में कुल 26 गैर सरकारी नशामुक्ति केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है, जिनकी जिलेवार संख्या निम्नानुसार हैः-

क्र.सं.	नाम जिला	संचालित नशा मुक्ति केन्द्रों की संख्या
1	जयपुर	2
2	दौसा	2
3	जोधपुर	1
4	जैसलमेर	2
5	सिरोही	1
6	बाड़मेर	1
7	कोटा	3
8	बारां	2
9	बूंदी	1
10	भरतपुर	2
11	करौली	1

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

क्र.सं.	**नाम जिला**	**संचालित नशा मुक्ति केन्द्रों की संख्या**
12	सवाई माधोपुर	2
13	श्रीगंगानगर	4
14	हनुमानगढ़	1
15	डूंगरपुर	1
	कुल	**26**

(2) राज्य में अनुदानित नशा मुक्ति केन्द्र भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी गाइड-लाइन के अनुसार संचालित हैं। इन केन्द्रों का समय-समय पर भारत सरकार द्वारा गठित Project Monitoring Unit टीम व CCTV के माध्यम से आनलाइन एवं राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है।

(3) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2021-22 के बिन्दु संख्या 289 अन्तर्गत नैतिक, धार्मिक एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से मद्यसंयम हेतु "स्वर्गीय श्री गुरूशरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान" अन्तर्गत 05 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। बजट घोषणा के विरुद्ध वित्त विभाग द्वारा कुल 3.14 करोड़ रुपये का बजट आबंटन किया गया।

अभियानान्तर्गत नशे की गतिविधियों में संलिप्त समुदायों/परिवारों/लक्षित समूह में जन-जागरूकता हेतु फिल्म प्रदर्शनी/लघुकथा/नुक्कड़ नाटक/स्थानीय प्रचलित कार्यक्रमों के माध्यम से अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, झालावाड़, उदयपुर, नागौर, जोधपुर, कोटा, झुन्झुनूं, जालौर, चूरू व हनुमानगढ़ जिले में जिला मुख्यालय/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत में जन-जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाकर 55.40 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के बिन्दु संख्या 210 में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा "स्वर्गीय श्री गुरूशरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान" अन्तर्गत 10 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। उक्त बजट घोषणा के क्रम में विभाग द्वारा 10 करोड़ रुपये का एक्शन प्लान वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित करवाया जाकर अभियान का क्रियान्वयन किया जाना प्रक्रियाधीन है।

सहाड़ा में भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण

178. श्रीमती गायत्री देवी त्रिवेदी (सहाड़ा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में अब तक कितने नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र कहां-कहां पर स्वीकृत हुए? उक्त केन्द्रों के लिए कहां-कहां पर भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है व उक्त में से कितने के कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने कार्य प्रगति पर हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवन निर्माण की स्वीकृति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में 94 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में विभिन्न योजनाओं में कुल 12 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 450.12 लाख की स्वीकृति जारी हुई जिसके तहत 02 उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, 08 उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है, 01 उप स्वास्थ्य केन्द्र टूंगच की निविदा प्रक्रियाधीन है एवं 01 उप स्वास्थ्य केन्द्र पालरा हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) जी हां। भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति चालू/आगामी वित्तीय वर्षों में भूमि, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जनसंख्या अनुपात में चिकित्सकों का पदस्थापन

179. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में चिकित्सकों के कुल स्वीकृत पदों में से कितने पद कार्यरत हैं एवं कितने रिक्त हैं? जनसंख्या के अनुपात में कितने चिकित्सक कार्यरत होने चाहिए? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में विगत चार वर्षों में कितने चिकित्सक सेवानिवृत्त हुए तथा कितने चिकित्सक भर्ती के माध्यम से नये लगाये गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री शंकर सिंह रावत)

(3) क्या सरकार प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में चिकित्सक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सक/विशेषज्ञों के स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों के विवरण की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थानों में स्वीकृत पदों के अनुरूप चिकित्सकों का पदस्थापन किया जाता है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उसके अधीन संस्थाओं में चिकित्सक शिक्षकों के रिक्त पदों की सूची निम्नानुसार है:-

राजकीय मेडिकल कालेज

पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
आचार्य/वरिष्ठ आचार्य	482	558	+76
सह आचार्य	660	439	221
सहायक आचार्य	1259	493	766
वरिष्ठ प्रदर्शक	552	283	239

राजमेस

पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
आचार्य	279	156	123
सह आचार्य	573	121	452
सहायक आचार्य	876	334	542
कुल	**1728**	**611**	**1117**

आरयूएचएस

पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
आचार्य	37	22	15
सह आचार्य	55	27	28
सहायक आचार्य	134	63	71
वरिष्ठ प्रदर्शक	63	20	43
मेडिकल आफिसर	08	04	04
कुल	**297**	**136**	**161**

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सक शिक्षकों के पद एमसीआई/ एनएमसी के मानदण्डानुसार स्वीकृत किये जाते हैं।

(2) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में विगत चार वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले चिकित्सकों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उसके अधीन संस्थाओं में विगत 04 वर्षों में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में 52, राजमेस में 04 तथा आरयूएचएस में 01 चिकित्सक शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं।

वर्तमान सरकार द्वारा चिकित्सा अधिकारी के पद पर की गई भर्ती का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार चिकित्सा संस्थान खोले जाने का प्रावधान है।

चिकित्सा संस्थानों में शैय्या वृद्धि के उपरान्त वित्त विभाग के स्टाफिंग पैटर्न के तहत चिकित्सकों के पद सृजित किये जाने का प्रावधान है। विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

संचालित चिकित्सा संस्थानों में स्वीकृत पदों के अनुरूप चिकित्सकों का पदस्थापन किया जाता है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

लूणकरणसर में पशु उप केन्द्रों हेतु भवन निर्माण

180. श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में कितने पशु उपकेन्द्र स्वीकृत हैं? उक्त स्वीकृत पशु उपकेन्द्रों में से कितने केंद्रों को कब-कब भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की गई? उक्त स्वीकृत उपकेन्द्रों में से कितनों का भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है व कितनों का शेष है? सरकार शेष के भवन निर्माण कार्य को कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में कुल 26 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र स्वीकृत हैं, जिनमें से 3 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति निम्नानुसार जारी की गई है:-

(पशुपालन मंत्री)

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्वीकृति जारी किये जाने की दिनांक
1	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, बडेरण	18.08.2017
2	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, खारी	20.08.2018
3	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, सहजरासर	03.03.2021

उक्त तीनों पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। पशु चिकित्सा संस्थाओं के भवन निर्माण कार्य विभाग के नाम भू-स्वामित्व के दस्तावेज उपलब्ध होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार प्राथमिकता से करवाये जाते हैं।

जगतपुरा (जयपुर) के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का क्रमोन्नयन

181. श्रीमती गंगा देवी (बगरू): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बगरू के शहरी राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने हेतु क्षेत्रीय विधायक की ओर से विगत चार वर्षों में सरकार को पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो प्राप्त पत्रों पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वर्ष 2023 में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जगतपुरा (जयपुर) को राजकीय सामुदायिक केन्द्र में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बगरू के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खोनागोरियान, जयपुर को क्रमोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने का पत्र क्रमांकः 168 दिनांक 20.01.2021 जिसका जवाब पत्र क्रमांकः 244 दिनांक 03.03.2021 के द्वारा भिजवाया गया था। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2021-22 की क्रियान्विति अन्तर्गत स्वीकृति दिनांक 29.06.2021 के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोनागोरियान को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नति की पदों सहित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। स्वीकृति आदेश परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

पत्र क्रमांकः 2057 दिनांक 22.03.2020 जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जगतपुरा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने बाबत उल्लेख है का जवाब पत्र क्रमांकः 139 दिनांक 23.02.2023 को भिजवाया गया है।

पत्र क्रमांकः 1894 दिनांक 07.02.2020 जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जगतपुरा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने बाबत उल्लेख है, उक्त पत्रों में मानदण्डानुसार वर्तमान में क्रमोन्नत किया जाना विचाराधीन नहीं है।

पत्र क्रमांकः 1892 दिनांक 07.02.2022 जिसमें बगरू सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत कर जिला स्तरीय चिकित्सालय किये जाने बाबत उल्लेख है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बगरू की वर्ष 2021 में शय्याओं की उपयोगिता दर (बी.ओ.आर.) 58.71 प्रतिशत रही है, जो नॉर्म्स अनुसार 95 प्रतिशत एवं उससे अधिक नहीं रही है। अत: सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बगरू की शैय्याओं में वृद्धि कर जिला स्तरीय चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(2) जगतपुरा पंचायत समिति सांगानेर जिला जयपुर में वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है।

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार 01 लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर निर्धारित मानदण्डानुसार पंचायत समिति सांगानेर में 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। इस प्रकार पंचायत समिति सांगानेर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मानदण्ड के अनुसार स्वीकृत होने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बीकानेर में समन्वित नाशीजीव प्रबन्धन प्रयोगशाला खोलने की कार्ययोजना

182. श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि किसानों के हितार्थ समन्वित नाशीजीव प्रबन्धन (आई.पी.एम.) प्रयोगशाला बीकानेर जिला मुख्यालय पर खोले जाने की लंबे समय से मांग की जा रही है? यदि हां, तो विभिन्न माध्यमों से सरकार को प्राप्त मांग-पत्रों पर अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिला मुख्यालय बीकानेर पर समन्वित नाशीजीव प्रबन्धन (आई.पी.एम.) प्रयोगशाला खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। किसानों के हितार्थ समन्वित नाशीजीव प्रबन्धन (आई.पी.एम.) प्रयोगशाला बीकानेर जिला मुख्यालय पर खोले जाने के संबंध में विभिन्न माध्यमों से सरकार को प्राप्त मांग पत्रों की अनुपालना में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राज्य में पौध संरक्षण हेतु जैव कारकों के उत्पादन, संवर्धन, जैव नियंत्रण कार्यों हेतु अनुसंधान संस्थाओं से समन्वय, जैव उत्पादों के गुण नियंत्रण, प्रशिक्षण, समन्वित कीट व्याधि प्रबन्धन (आईपीएम) को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राज्य में कुल 9 प्रयोगशालाएं यथा-1 राज्य स्तरीय राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा जयपुर एवं 8 क्षेत्रीय आई.पी.एम. प्रयोगशालाएं यथा-तबीजी (अजमेर), मलिकपुर (भरतपुर), छत्रपुरा (बूंदी), चितौडगढ़, हनुमानगढ़, बांसवाडा, रामपुरा (जोधपुर), आबूसर (झुन्झुनूं) में कार्यरत हैं। साथ ही माननीय मुख्य मंत्री बजट घोषणा वर्ष 2022 की अनुपालना में टोंक में प्रयोगशाला स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वतर्मान में बीकानेर मुख्यालय पर आई.पी.एम. प्रयोगशाला खोला जाना विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नागौर में एलसी-61 व एलसी-64 पर आर.ओ.बी. का निर्माण

183. श्री मोहन राम चौधरी (नागौर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नागौर में एलसी-61 (बीकानेर रेलवे फाटक) व एलसी-64 (मानासर रेलवे फाटक) दो लेन आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य ई.पी.सी. मोड पर चल रहा है? यदि हां, तो सरकार उक्त कार्य को कब तक पूर्ण करवा देगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोहन राम चौधरी)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य पूर्ण नहीं होने से आम जन बहुत परेशान है? यदि हां, तो उक्त कार्य के विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। एलसी-61 (बीकानेर फाटक) पर दो लेन आरओबी निर्माण कार्य प्रगतिरत था जिसकी भौतिक प्रगति 64 प्रतिशत एवं वित्तीय प्रगति 61.06 प्रतिशत है। संवेदक द्वारा कार्य में शिथिलता बरतने के कारण वर्तमान में उक्त कार्य का अनुबंध दिनांक 09.02.2023 को निरस्त किया जा चुका है। संवेदक के अंतिम कार्य का भुगतान किया जाकर शेष कार्य हेतु तकमीना एवं निविदा प्रक्रिया पूर्ण की जाकर कार्य शीघ्र सम्पन्न करवा लिया जाएगा।

एलसी-64 (मानासर फाटक) का कार्य प्रगतिरत है जिसकी भौतिक प्रगति 91.23 प्रतिशत एवं वित्तीय प्रगति 83 प्रतिशत है। कुल 13 स्पान में से 12 स्पान का कार्य पूर्ण हो गया है तथा 01 स्पान का कार्य भूमि अवाप्ति के मुआवजे के भुगतान पश्चात् शीघ्र कार्य पूर्ण करवा लिया जाएगा।

(2) आरओबी सी-64 के निर्माण कार्य के दौरान सुगम यातायात संचालन हेतु वैकल्पिक मार्ग का उपयोग किया जा रहा है, जिससे आमजन को कोई परेशानी नहीं हो रही है एवं आरओबी सी-61 के निर्माण कार्य में विलम्ब के लिए संबंधित संवेदक जिम्मेदार है, जिसके खिलाफ अनुबंध निरस्तीकरण की कार्यवाही दिनांक 09.02.2023 को की जा चुकी है।

बाली के नगरपालिका क्षेत्रों को जे.जे.एम. योजना से जोड़ने की कार्ययोजना

184. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र बाली में जल जीवन मिशन के तहत नगरपालिका क्षेत्र बाली, खुडाला-फालना, सादड़ी को भी सम्मिलित किया गया है? यदि नहीं, तो उक्त को कब तक सम्मिलित कर लिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ही हर घर नल से जल उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

विधान सभा क्षेत्र बाली के शहरी क्षेत्रों बाली, खुडाला-फालना एवं सादड़ी में अमृत 2.0 पेयजल योजना के तहत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राजस्थान अरबन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लिमिटेड (आरयूडीएसआईसीओ), जयपुर की स्वीकृति दिनांक 06.02.2023 द्वारा क्रमशः राशि रुपये 7.75 करोड़, 6.66 करोड़ एवं 11.72 करोड की जारी की जा चुकी है। उक्त योजनाओं के तकनीकी प्रस्ताव बनाने का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

स्टेट हाईवे को पुन: टोल मुक्त करने की कार्ययोजना

185. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के स्टेट हाईवे को टोल मुक्त किया गया था? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश के स्टेट हाईवे पर पुन: टोल चालू कर दिया गया है? यदि हां, तो कब से व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश के स्टेट हाईवे को पुनः टोल मुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से प्रदेश के राज्य राजमार्गों पर निजी वाहनों को टोल मुक्त किया गया था।

(2) जी हां। दिनांक 01 नवम्बर, 2019 से प्रदेश के राज्य राजमार्गों पर निजी वाहनों पर पुन: टोल चालू किया गया है। आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

टोल चालू करना राज्य सरकार का नीतिगत मामला है।

(3) वर्तमान में राज्य राजमार्गों को टोल मुक्त करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

नसीराबाद में जल जीवन मिशन योजना का संचालन

186. श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रामस्वरूप लाम्बा)

(1) विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में घर-घर जल कनेक्शन हेतु जल जीवन मिशन योजना कितने गांवों में स्वीकृत हुई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत योजना कितने गांवों में पूर्ण हो चुकी है व कितनों में लम्बित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार उक्त स्वीकृत व लम्बित योजनाओं को कब तक पूर्ण करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में कुल 154 ग्राम स्थित हैं। इन 154 ग्रामों में से 01 ग्राम रामसर पूर्व से ही हर घर क्रियाशील जल सम्बन्धों से लाभान्वित है। शेष 153 ग्रामों में से 56 ग्राम वृहद पेयजल परियोजना अजमेर पीसांगन, 41 ग्राम वृहद पेयजल परियोजना श्रीनगर-नसीराबाद एवं 56 ग्राम अन्य योजनाओं के अन्तर्गत जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत हैं। स्वीकृत योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) स्वीकृत 56 अन्य योजनाओं मे से 53 ग्रामों की योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं तथा 02 ग्रामों की योजनाएं प्रगतिरत हैं, जिन्हें मई, 2023 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है। एक योजना का कार्यादेश आदेशित संवेदक के द्वारा कार्य नहीं किये जाने के कारण निरस्तीकरण हेतु प्रक्रियाधीन है।

अजमेर-पीसांगन पेयजल परियोजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु मैसर्स जुबेरी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर को राशि रुपये 256.57 करोड़ का कार्यादेश दिनांक 16.03.2022 को जारी किया गया है। इस परियोजना का कार्य दिनांक 25.03.2024 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है। वर्तमान में परियोजना का कार्य प्रगति पर है।

श्रीनगर-नसीराबाद पेयजल परियोजना की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की 30वीं बैठक दिनांक 29.11.2021 के द्वारा राशि रुपये 163.49 करोड़ की जारी की जा चुकी है। योजना के पेयजल स्रोत बीसलपुर बांध में, अजमेर जिले के पेयजल हेतु 5 टीएमसी जल आरक्षित है परन्तु जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्धारित 55 एलपीसीडी से जलमांग बढ़ जाने के कारण बांध में अतिरिक्त 2.6 टीएमसी जलमांग की आवश्यकता प्रतिपादित की गयी है। जल संसाधन विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

बीसलपुंर बांध से अजमेर जिले के लिए अतिरिक्त 2.6 टीएमसी पेयजल नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा इन्टरलिंक परियोजना पूर्ण होने के पश्चात् ही सम्भव हो सकेगा, जिसके लगभग 6 से 7 वर्ष का समय लगना सम्भावित बताया गया है। अतः वर्तमान में बीसलपुर बांध में अभिकल्पित मांग अनुसार जल आरक्षण के अभाव में उक्त स्वीकृत योजना का क्रियान्वयन किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। विवरण परिशिष्ट-अ में निहित है।

(3) उपरोक्तानुसार।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पेयजल योजनाओं के संचालन हेतु रिक्त पदों पर भर्ती

187. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पेयजल योजनाओं के संचालन हेतु बेलदार, हेल्पर, फीटर एवं पम्प चालक के पदों पर भर्तियां नहीं किये जाने के कारण नियमित रूप से पेयजल उपलब्ध कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पदों पर भर्तियां करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में तकनीकी संवर्ग के पम्प ड्राइवर-द्वितीय, फिटर-द्वितीय, इलेक्ट्रिशियन-द्वितीय,लाइनमैन-द्वितीय, मीटर रीडर एवं हेल्पर के कुल 1309 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को दिनांक 12.07.2021 को भिजवाई गई है। भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

चौहटन के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसानों के उत्थान की कार्ययोजना

188. श्री पदमाराम (चौहटन): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र चौहटन के सीमावर्ती क्षेत्र के किसानों के जीवन उत्थान हेतु कोई नवीन योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

कृषि विभाग तथा उद्यान विभाग की सभी नियमित योजनायें, योजना के मापदण्डों के अनुसार विधान सभा क्षेत्र चौहटन के सीमावर्ती क्षेत्र सहित समस्त क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही हैं। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र चौहटन के सीमावर्ती क्षेत्र के किसानों के जीवन उत्थान हेतु अलग से कोई नई योजना बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

चूरू में भवनविहीन पशु चिकित्सा संस्थान

189. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला चूरू में विभिन्न श्रेणी के कितने पशु चिकित्सा संस्थान स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने कार्यरत हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले में बड़ी संख्या में पशु चिकित्सा संस्थान बिना भवन के संचालित हैं? यदि हां, तो तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र चूरू में कुल कितने पद पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु सहायक व लैब टेक्निशियन के रिक्त हैं? उक्त पदों पर पदस्थापन के लिए क्या-क्या कार्रवाई की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चूरू जिले में कुल स्वीकृत एवं कार्यरत पशु चिकित्सा संस्थाओं का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	पशु चिकित्सा संस्थाओं की श्रेणी	स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थाएं	कार्यरत पशु चिकित्सा संस्थाएं
1	बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय	1	1
2	प्रथम श्रेणी चिकित्सालय	23	23
3	पशु चिकित्सालय	61	57
4	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र	195	181
5	पशुधन आरोग्य चल इकाई	3	1
योग		**283**	**263**

(पशुपालन मंत्री)

चूरू जिले की कार्यरत पशु चिकित्सा संस्थाओं के अतिरिक्त शेष पशु चिकित्सा संस्थाओं का अतिरिक्त कार्यभार समीपवर्ती पशु चिकित्सा संस्थाओं के कार्मिकों को देकर इस क्षेत्र के पशुपालकों को पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में जिला चूरू की कोई भी पशु चिकित्सा संस्था बिना भवन के संचालित नहीं है। चूरू जिले में स्वीकृत समस्त पशु चिकित्सा संस्थायें राजकीय भवन/पंचायत द्वारा प्रदत्त भवन/वैकल्पिक व्यवस्था में उपलब्ध करवाये गये भवनों में संचालित हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र चूरू की पशु चिकित्सा संस्थाओं में वर्तमान में 02 वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, 06 पशु चिकित्सा अधिकारी, 07 पशु चिकित्सा सहायक, 01 लैब टैक्नीशियन व 03 पशुधन सहायक के पद (कुल 19 पद) रिक्त हैं।

900 पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने हेतु विभाग द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को प्रेषित अभ्यर्थना के क्रम में आयोग द्वारा जारी परीक्षा परिणाम पर दायर याचिका के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा है।

1436 पशुधन सहायकों के रिक्त पदों को भरने हेतु विभाग द्वारा कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को प्रेषित अभ्यर्थना के क्रम में बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के क्रम में 1177 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके हैं तथा शेष 259 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किया जाना प्रक्रियाधीन है।

पशुधन सहायकों के उक्त 1177 पदों में से 15 पशुधन सहायकों को विधान सभा क्षेत्र चूरू में नियुक्ति प्रदान की गई है। साथ ही विधान सभा क्षेत्र चूरू में वर्ष 2022 में 4 पशुधन सहायकों को आवश्यक अस्थायी आधार पर भी नियुक्ति दी गई है।

विधान सभा क्षेत्र चूरू में लैब टैक्नीशियन का 01 पद स्वीकृत है जिसका वेतनमान पशु चिकित्सा सहायक के समकक्ष (ग्रेड-पे 3600) है। पशु चिकित्सा सहायक का पद पदोन्नति का है, जिसे पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

रिक्त पदों को कार्मिकों की उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

ग्राम लोहार्गल (झुन्झुनूं) में चेतनदास जी की बावड़ी का जीर्णोद्धार

190. श्री बाबूलाल नागर (दूदू): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या जिला झुन्झुनूं में नवलगढ़ उपखण्ड क्षेत्र के लोहार्गल ग्राम में चेतनदास जी की ऐतिहासिक बावड़ी स्थित है? यदि हां, तो उक्त के जीर्णोद्धार संरक्षण हेतु कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

जी हां।

जी नहीं।

चूरू में पंचायत समिति मुख्यालय पर अम्बेडकर भवन

191. श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वर्ष 2019 की बजट घोषणा में सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर अम्बेडकर भवन बनवाये जाने थे? यदि हां, तो माह दिसम्बर, 2022 तक जिला चूरू में कितने भवनों का निर्माण करवाया जा चुका है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में उक्त भवन निर्माण हेतु कितने भवनों के लिए भू-आबंटन किया जा चुका है? संख्यात्माक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। चूरू जिले की समस्त 07 पंचायत समितियों का मुख्यालय नगरपालिका क्षेत्र में होने के कारण चूरू जिले में अम्बेडकर भवन निर्माण का कार्य प्रस्तावित नहीं है।

(2) चूरू जिले में उक्त भवन निर्माण का कार्य प्रस्तावित नहीं है। अत: भू-आबंटन नहीं किया गया है।

पंचायत समिति के प्रधानों हेतु राजकीय आवास

192. श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है पंचायत समितियों के प्रधान हेतु सरकारी आवास आबंटित हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनिवास गावड़िया)

(2) क्या सरकार जहां प्रधान हेतु सरकारी आवास आबंटित नहीं हैं वहां पर आवास आबंटन अथवा निर्माण करवाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में केवल जिला बीकानेर की पंचायत समिति कोलायत, खाजूवाला व नोखा तथा जिला डूंगरपुर की पंचायत समिति सागवाड़ा में प्रधान हेतु सरकारी आवास आबंटित हैं।

(2) वर्तमान मे इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

आसीन्द नगरपालिका के प्रेम सागर तालाब का सौन्दर्यीकरण

193. श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि नगरपालिका आसीन्द में स्थित सवाईभोज मन्दिर के किनारे प्रेम सागर तालाब स्थित है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तालाब का डी.एम.एफ.टी. फण्ड से मॉडल तालाब के रूप में सौन्दर्यीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट फण्ड से क्या-क्या कार्य करवाये जा सकते है, के प्रावधान राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 में किये गये हैं एवं इन्हीं प्रावधानों के अनुरूप कार्य करवाये जा सकते हैं। नियमों के संबंधित प्रावधान की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। अनुमत कार्यो में से क्या कार्य डी.एम.एफ.टी. फण्ड से उस जिले में कराया जाना है, का निर्णय जिले की डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट की गवर्निंग काउंसिल करती है और सन्दर्भित प्रेम सागर तालाब के सौन्दर्यीकरण कार्य के बारे में जिला गवर्निंग काउंसिल सक्षम स्तर है। प्राप्त सूचना अनुसार वर्तमान तक नगरपालिका आसीन्द में सवाईभोज मन्दिर के किनारे स्थित प्रेम सागर तालाब के सौन्दर्यीकरण हेतु प्रस्ताव डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट, भीलवाड़ा को प्राप्त नहीं हुआ है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

लूणी में अवैध खनन

194. श्री महेन्द्र बिश्नोई (लूणी): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र लूणी में अवैध खनन को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

जी हां। अवैध खनन को रोकना एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए सरकार सदैव प्रयत्नशील रहती है। सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का मुख्य विवरण निम्न प्रकार है:-

(1) खान विभाग के अधिकारियों/तकनीकी कर्मचारियों द्वारा क्षेत्र में निरन्तर/आकस्मिक चैकिंग की जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। समय-समय पर अवैध खनन के विरुद्ध अभियान चलाये जाते हैं।

(2) लूणी नदी में खनिज बजरी के अवैध खनन की रोकथाम हेतु जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा दिनांक 12.07.2018 से विशेष जांच दल गठित किया गया है, जिसके द्वारा भी समय-समय पर कार्यवाही की गई/जा रही है। आदेश दिनांक 12.07.2018 की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) लूणी नदी में खनिज बजरी के अवैध खनन के संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस, राजस्व विभाग एवं आर.ए.सी. के साथ संयुक्त कार्यवाही बाबत दिनांक 09.02.2023 से दलों का गठन किया गया है। उक्त दलों द्वारा भी कार्यवाही की जा रही है। आदेश दिनांक 09.02.2023 की प्रति परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(4) खान विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र लूणी में दिनांक 01.04.2019 से 31.01.2023 तक अवैध खनन के कुल 106 प्रकरण बनाये जाकर रुपये 1,73,04,415/- शास्ति के रूप में वसूल किये गये हैं तथा 25 प्रकरणों में संबंधित पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है, विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

सलूम्बर में नवीन उप कारागार का निर्माण

195. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या जेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अमृतलाल मीणा)

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में करावली रोड पर ईसरवास में आबंटित बारह बीघा भूमि पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में उप कारागार का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में करावली रोड पर ईसरवास में भूमि का आबंटन नहीं हुआ है।

इस वित्तीय वर्ष में उप कारागृह, सलूम्बर के नवीन जेल भवन का निर्माण प्रस्तावित नहीं है।

भविष्य में भूमि आबंटित होने पर एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर उप कारागृह, सलूम्बर के नवीन जेल भवन के निर्माण पर विचार किया जा सकेगा।

दिव्यांगों को विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के माध्यम से साइकिल व स्कूटी का वितरण

196. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

प्रदेश में दिव्यांगों को विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना व विभाग के माध्यम से ट्राई साइकिल व स्कूटी या अन्य वाहन उपलब्ध कराये जाने की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रदेश में दिव्यांगों को विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना व विभाग के माध्यम से ट्राई साइकिल व स्कूटी या अन्य वाहन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी किये गये परिपत्र की प्रति परिशिष्ट-अ संग्लन है।

इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2021-22 में बजट घोषणा 120 के अन्तर्गत कालेज जाने वाले दिव्यांग छात्र/छात्राओं तथा रोजगार हेतु अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए युवाओं को 2000 स्कूटी दी जायेंगी, की घोषणा की गई। उक्त बजट घोषणा के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों में से चयनित पात्र आवेदकों को 1984 स्कूटी वितरित की गईं।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट घोषणा संख्या 57 में कालेज जाने वाले दिव्यांग छात्र-छात्राओं तथा रोजगार हेतु अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए दिव्यांग युवाओं को इस वर्ष दी जा रही 02 हजार स्कूटी की संख्या को आगामी वर्ष में बढ़ाते हुए 'मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना' के अंतर्गत 05 हजार स्कूटी दिये जाने की घोषणा की गई। बजट घोषणा क्रियान्वयन का कार्य प्रक्रियाधीन है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

पिण्डवाड़ा में आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्थायी भवन

197. श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा में अस्थायी स्थानों पर संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्थायी भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

भूमि भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से नि:शुल्क भूमि आबंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित नोर्म्स के अनुसार करवाया जाता है।

बूंदी के आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पद

198. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बूंदी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कुल कितने पद रिक्त हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बूंदी के अन्तर्गत 02 बाल विकास परियोजनाएं क्रमश: बूंदी एवं तालेड़ा संचालित हैं, जिनके अन्तर्गत कार्यकर्ताओं के 11 पद रिक्त चल रहे हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

क्र.सं.	**परियोजना**	**आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के स्वीकृत पद**	**आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पद**
1	बूंदी	225	4
2	तालेडा	161	7
योग		**386**	**11**

(2) जी हां। माह नवम्बर 2022 में उक्त रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है, भर्ती प्रक्रिया जारी है।

विभाग द्वारा वर्ष में दो बार जून एवं नवम्बर माह में आगामी छह माह में रिक्त होने वाली रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए नियमित विज्ञप्ति जारी की जाती है।

प्रीति ग्रुप द्वारा संचालित धागा फैक्टरी में कार्यरत कर्मचारियों का बकाया वेतन

199. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र खानपुर में प्रीति ग्रुप द्वारा धागा फैक्टरी संचालित की जा रही है? क्या उक्त फैक्टरी बंद है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त फैक्टरी में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को नियमित व समय पर वेतन मिल रहा है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त कर्मचारियों को समय पर वेतन दिलाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में प्रीति ग्रुप के द्वारा धागा फैक्टरी के संबंध में वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको एवं महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र एवं वाणिज्य, (झालावाड़) द्वारा संयुक्त निरीक्षण करने पर इकाई बन्द पायी गयी है।

(2) फैक्टरी में कार्यरत समस्त कार्मिकों को माह सितम्बर-2022 तक के वेतन का भुगतान नियमित रूप से किया है। दिनांक 27.12.2022 को फैक्टरी में कार्यरत 162 श्रमिकों ने कार्यालय में उपस्थित होकर श्रम कल्याण अधिकारी, झालावाड़ को एक लिखित ज्ञापन प्रस्तुत कर माह अक्टूबर एवं नवम्बर 2022 का वेतन दिलवाने का निवेदन किया था। इस संबंध में

(उद्योग मंत्री)

समझौता कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं दिनांक 21.02.2023 को आयोजित द्वितीय वार्ता तक माह अक्टूबर 2022 को वेतन भुगतान भी करवाया जा चुका है। (कारखाना प्रबंधन से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न है)

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजनान्तर्गत देय ब्याज सब्सिडी

200. श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से माह दिसम्बर, 2022 तक कितने उद्यमियों को कितने रुपये की ब्याज सब्सिडी दी गई है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से माह दिसम्बर 2022 तक 8 उद्यमियों को 9,33,668/- रु. की ब्याज सब्सिडी दी गई है।

विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जनजाति छात्रावासों में अध्ययनरत बालक-बालिकाएं

201. श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के जनजाति छात्रावासों में कितने बालक-बालिकाएं अध्ययनरत हैं? छात्रावासवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त छात्रावासों में सीटें बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा 11 आश्रम छात्रावास एवं 01 ईएमआरएस विद्यालय कुल-12 छात्रावास संचालित हैं, जिनमें कुल 895 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं।

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

क्र. सं.	विद्यालय/छात्रावास का नाम	विधान सभा क्षेत्र	पंचायत समिति	वर्ग	क्षमता
1.	बेकरिया	गोगुन्दा	कोटडा	बालिका	100
2.	मेरपुर	गोगुन्दा	कोटडा	बालिका	65
3.	चित्रावास	गोगुन्दा	सायरा	बालिका	50
4.	छाली	गोगुन्दा	गोगुन्दा	बालिका	50
5.	पीपलीखेडा	गोगुन्दा	गोगुन्दा	बालिका	50
6.	गोगुन्दा	गोगुन्दा	गोगुन्दा	बालिका	25
7.	मालवा का चोरा	गोगुन्दा	कोटडा	बालक	95
8.	सायरा	गोगुन्दा	सायरा	बालक	50
9.	रावछ	गोगुन्दा	सायरा	बालक	50
10.	समीजा	गोगुन्दा	गोगुन्दा	बालक	50
11.	गोगुन्दा	गोगुन्दा	गोगुन्दा	बालक	50
12.	ईएमआरएस, दादिया	गोगुन्दा	गोगुन्दा	बालिका	260
बालक-295 **बालिका-600** **कुल-895**					**895**

(2) उक्त आश्रम छात्रावासों में छात्र क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विभाग में विचाराधीन नहीं है। विधिवत औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर संसाधन व बजट की उपलब्धता एवं अन्य क्षेत्रों के सापेक्ष क्षेत्र विशेष की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए छात्र क्षमता बढ़ाने का निर्णय सक्षम स्तर से लिया जायेगा।

नागौर में शहीदों के नाम पर सड़कों का नामकरण

202. श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): क्या सैनिक कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर में ऐसी कितनी सड़कें हैं जिनका नामकरण शहीदों के नाम पर किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त जिले में निर्मित सड़कों का नामकरण शहीदों के नाम पर रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला नागौर में शहीदों के नाम पर सड़क का नामकरण नहीं किया गया है।

(2) जी हां। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 2(1)सै.क./99 दिनांक 04.02.2004 (परिशिष्ट-क) के अंतर्गत शहीद के नाम पर सार्वजनिक स्थानों में से एक स्थान का नामकरण शहीद के नाम पर करने का प्रावधान है। उक्त आदेश के तहत यदि एक ही गांव में एक से अधिक सैनिक शहीद होने तथा गांव में एक ही स्कूल होने की स्थिति से गांव में स्थित अन्य राजकीय संस्था या मार्ग के नामकरण का प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नामकरण किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-01

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर)

छात्रों से निजी चिकित्सा विश्वविद्यालयों द्वारा अत्यधिक फीस वसूली

महोदय, निवेदन है कि राजस्थान के हजारों छात्र एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त करने के लिए विदेशों में जाते हैं। राजस्थान का एक बच्चा 15 से 20 लाख रुपये में पांच वर्ष में एमबीबीएस की डिग्री एवं एमडी की डिग्री हासिल कर लेता है। विदेश में डिग्री हासिल करने के बाद यहां पर आकर चिकित्सक बन जाता है जबकि राजस्थान में प्राइवेट यूनिविर्सिटी में एमबीबीएस की डिग्री के नाम पर लूटा जा रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है। जो डिग्री विदेशों में 15 से 20 लाख में हासिल हो रही है, वही डिग्री राजस्थान की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डेढ़ करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी आसानी से हासिल नहीं हो रही है। यूनिवर्सिटी द्वारा हॉस्टल खर्चा एवं डिग्री की फीस और लेट फीस के नाम से बच्चों को प्रताड़ित करते हुए लूटा जा रहा है, जिसके कारण बच्चे मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। क्या सरकार विदेश में 15 से 20 लाख रुपये में मिलने वाली डिग्री को राजस्थान में डेढ़ करोड़ के बजाय 15 से 20 लाख रुपये में बच्चों को दिलाने का विचार रखती है?

राजस्थान सरकार द्वारा इस ओर बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर सरकार द्वारा इस ओर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की डिग्री का अध्ययन करने वाले बच्चे आत्महत्या करेंगे।

अतः आपसे निवेदन है कि राजस्थान में प्राइवेट एमबीबीएस की हठधर्मिता पर रोक लगाकर उचित कार्यवाही की जावे।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर)

मुण्डावर में शीतलहर से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा

महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में पाले की मार से किसानों की फसल पूर्णतः बर्बाद हो गई थी। सरकार द्वारा सर्वे

करवाकर मुआवजा देने की बात सदन में कही गई थी। पाले की मार से जब किसानों की फसल खराब हुई तब मेरे द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर टीम बनाकर सर्वे कराने के लिए कहा गया, जिस पर अधिकारियों ने फसल खराबे के सर्वे के लिए टीम बनाई लेकिन किसानों का फसल खराबा सर्वे में 20 प्रतिशत ही दिखाया गया, जिसके कारण मेरे क्षेत्र के किसानों को फसल खराबे का मुआवजा नहीं मिल पाया। अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बहरोज, जिंदौली, सुहेठा, खरेटा, खानपुर, बडली, नंगली ओझा व मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र के अधिकांश गांवों में फसल खराबा 80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक हुआ है।

महोदय, देश का अन्नदाता कहा जाने वाला किसान आज इस खराबे से तनाव में तो था ही, ऊपर से उनका फसल का खराबा कम दिखाकर उनके घाव पर नमक छिडकने का काम किया गया है। प्रदेश सरकार अपने आपको किसान हितैषी बताती है। अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि किसान हित में मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में फसल खराबे का सर्वे बिना भेदभाव के करवाकर किसानों को उचित मुआवजा देकर राहत प्रदान करें।

श्री पुखराज (भोपालगढ़)

राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति को वर्तमान में देय आरक्षण में वृद्धि

महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य एवं प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के विभिन्न अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सामाजिक, राजनैतिक, कर्मचारी एवं अन्य संगठनों द्वारा राजस्थान में राजकीय सेवाओं में शिक्षण संस्थानों एवं अन्य विभिन्न राज्य सरकार की योजनाओं में राष्ट्रीय जनगणना 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुरूप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचिज जनजाति का आरक्षण प्रतिशत 16 एवं 12 से बढ़ाकार 17.8 प्रतिशत व 13.05 प्रतिशत करने की मांग समय-समय पर की जाती रही है।

झारखण्ड, छतीसगढ़, कर्नाटक एवं अन्य राज्यों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षण राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय जनगणना वर्ष 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुरूप बढ़ाया जा चुका हैं, परन्तु बड़े खेद का विषय है कि राजस्थान सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षण प्रतिशत अभी तक राष्ट्रीय जनगणना वर्ष 2011 के आंकड़ों अनुरूप नहीं बढ़ाया

गया हैं। अतः आपसे अनुरोध हैं कि राजकीय अध्यादेश द्वारा राजस्थान में राजकीय सेवाओं, शिक्षण संस्थानों एवं अन्य विभिन्न राजकीय योजनाओं में राजस्थान के अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षण वर्तमान प्रतिशत 16 एवं 12 है, (जो कि वर्ष 1961 की जनगणना के आंकडों पर आधारित है।) मेरा मुख्य मंत्री एवं सामाजिक न्याय मंत्री से आग्रह है कि प्रदेश में भी राष्ट्रीय जनगणना वर्ष 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुरूप बढ़ाकर 17.8 प्रतिशत व 13.05 प्रतिशत आरक्षण करने हेतु अध्यादेश जारी कर अनुग्रहित कर न्याय प्रदान करावें।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर)

सादुलपुर में एनएच-52 के क्रोसिंग पर अण्डरपास का निर्माण

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर, जिला चूरू से गुजरने वाले NH-52 पर होने वाली दुर्घटनाओं पर ध्यान आकर्षण करना चाहती हूं। लाखलाण, ढढाल, नरवासी ख्याली, गुलपुरा गांव के लिए जाने वाले लोगों को NH पर भारी वाहनों की आवाजाही के कारण काफी कठिनाई से गुजरना पड़ता है। काफी बार वाहन दुर्घटना होने से जान-माल की हानि हुई है। ये समस्या सर्दियों में कोहरे के कारण और भी गम्भीर हो जाती है। चूंकि अभी NH पर फोर लेन का कार्य प्रगति पर है, ऐसे में माननीय PWD मंत्री का ध्यान दिलाना चाहूंगी कि इन गांवों के रास्ते पर अण्डरपास बनवाने का कष्ट करें जिससे NH-52 को क्रोसिंग में होनी वाली दुर्घटनाओं से निजात मिल सके।

मैं सदन के माध्यम से निवेदन करती हूं, जब तक अण्डरपास न बने वहां एक ट्रैफिक सिग्नल की अति आवश्यकता है ताकि आवाजाही सुगम तरीके से हो सके।

सादर।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली)

आदिवासी एवं घुमन्तु जातियों के जीवन स्तर में उत्थान के लिए अतिरिक्त सुविधाएं

महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ऐसी जातियां जो आजादी के अमृतकाल में भी अत्यन्त पिछड़ी हुई हैं इनके उत्थान हेतु विशेष योजनाएं बनाकर उन्हें सक्षम समाजों के समकक्ष लायें, जिस प्रकार नवजीवन योजनांतर्गत कुछ जातियों को शिक्षा, कौशल, स्वरोजगार आदि की अतिरिक्त

सुविधाएं देकर इन्हें तेजी से आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास हुए वैसे ही निम्नलिखित जातियों हेतु भी योजनाएं बनायें:-

1. शहरी भील जाति के पुरुष हमाली एवं महिलाएं कचरा बीनने का कार्य करती हैं।
2. साठिया जाति की अनेकों युवतियां देह व्यापार कर परिवार चलाती हैं।
3. बावरी जाति के अधिकांश परिवार अंग्रेजी बबूल से कोयला बना परिवार चलाते हैं।
4. जोगी, कालबेलिया, सपेरा, नट जाति अपने परम्परागत कार्य या भीख मांग कर जीवन यापन करते हैं।
5. घुमन्तु जातियां जैसे गाडोलिया, लोहार आदि भी अन्यों से काफी पिछड़े हैं।

उक्त जातियां शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक तौर पर अन्य जातियों से अत्यन्त पिछड़ी हैं। गरीबी एवं अभाव में जीवन यापन कर रही हैं। इनके लिये अतिरिक्त सुविधाएं एवं प्रावधान कर इनका शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन स्तर उठाना सरकार का दायित्व है। अब तक सरकारों दवारा इन जातियों की अनदेखी किये जाने के कारण ये अन्य जातियों से बहुत ज्यादा पिछड़ गईं। राजनैतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में भी इनका प्रतिनिधित्व नहीं होने से इनकी मांगें सरकार तक नहीं पहुंचती है। ऐसे में सरकार को आगे आकर इन्हें किस प्रकार सक्षम जातियों के समकक्ष लाने हेतु योजना बना कार्य करने का दायित्व निभाना आवश्यक है। ये जातियां गरीब के साथ अशिक्षित भी हैं। इनको सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी नहीं होती, ऐसे में ये सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं उठा पाते हैं। इन जातियों को खाद्य सुरक्षा योजना एवं मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में सम्मिलित कर इन्हें सहायता प्रदान करें।

श्री पदमाराम (चौहटन)

चौहटन में प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचितों को लाभ

महोदय, निवेदन है कि मेरी विधान सभा चौहटन व बाड़मेर जिले के 01 लाख 25 हजार ऐसे लोग हैं जिनका या तो लैंडलाइन फोन के कारण व जियो ट्रेकिंग के कारण कई लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना से नाम काटकर वंचित कर दिया गया है। जो वंचित लोग हैं वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और ऐसे कई लोग जो बिना जानकारी के कारण वास्तव में योग्य हैं परन्तु पीएम आवास से वंचित रह गये हैं।

अतः आपके मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे योग्यजन लोगों की पीएम आवास से लाभान्वित करवाने हेतु जांच कराकर उनको लाभान्वित करावें।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़)

ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत समितियों द्वारा पट्टे प्रदायगी हेतु लागू नियम

महोदयजी, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान सरकार ने पंचायती राज विभाग द्वारा 300 गज का पट्टा जारी करने का नियम लागू कर रखा है जबकि कई वर्षों से परिवार निवास करते आ रहे हैं। गांवों में जीवन यापन करने का आधार कृषि एवं पशुपालन है, ज्यादा पशुधन रखने के लिए ज्यादा जमीन की जरूरत रहती है। परिवार संयुक्त रूप से निवास करते आ रहे हैं। पहले सरकार द्वारा कम से कम 1200 गज के पट्टे जारी किये जा रहे थे।

पिछले समय में भाजपा की सरकार ने गांवों में 300 गज के पट्टे जारी करने का आदेश निकालकर गांवों में बसने वाले ग्रामीणों पर कुठाराघात किया है। अब गांव में बसने वाले कमजोर व गरीब तबके के लोगों को कम रेट पर 1200 गज के पट्टे बनाने का नियम बनाया जावे जिससे आम गरीब को हक मिल सके और गोचर भूमि पर 20 वर्षों से परिवार घर बनाकर बसे हुए हैं उन्हें सरकारी लाभ आज तक पट्टों के अभाव में नहीं मिल पा रहा है। आये दिन इनके घर प्रशासनिक स्तर पर बेदखल करने की तलवार लटकती रहती हैं।

अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि नियम बनाकर गोचर में बसने वाले परिवारों को कम से कम 1200 गज का पट्टा कम दर में दिया जावे जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ आज तक जो वंचित रहे हैं, उनको मिल सके।

सादर।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा)

सोरसन (बारां), दर्रा एवं गांधीसागर को मिलाकर वृहद् जीव अभयारण्य की घोषणा

मान्यवर, सोरसन (बारां) अभयारण्य में 1990 के पूर्व 300 से अधिक संख्या में आबाद गोडावण अब नगण्य हैं। पूर्व में इस राज्य पक्षी की खुलेआम विचरण एवं अठखेलियां आमजन द्वारा देखी गई है।

वैज्ञानिक दृष्टि से गोडावण की बढ़ोतरी के प्रयासों की कमी, वन क्षेत्र के विकास तथा प्रभावी संरक्षण के अभाव से गोडावण के काफी संख्या में पलायन के पश्चात् इस दुर्लभ पक्षी के पुनः आबाद किये जाने के लिए 740 हैक्टेयर भूमि चिह्नित की जाने के उपरान्त 64 हैक्टेयर भूमि अवैध खनन एवं पशु चराई के लिए छोड़कर 676 हैक्टेयर भूमि को ही उपयुक्त मानने, गोडावण कृत्रिम प्रजनन केन्द्र (Captive Breeding Centre) हेतु भारतीय वन्य जीव संस्थान के प्रशासनिक, आवासीय भवन बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 3.43 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि वन विभाग को दिनांक 21.06.2019 को आबंटनोपरांत भी विभाग द्वारा भारतीय वन्य जीव संस्थान से कार्य प्रारम्भ करवाने में जान बूझकर देरी करने में विभागीय उदासीनता निराशाजनक है।

निकटवर्ती रासायनिक उर्वरक प्लांट गडेपान गोडावण के स्वतंत्र प्रजनन और विचरण में अवरोध पैदा कर रहा है, क्यों कि इसकी विशाल चिमनी और तीव्र प्रकाश की चमक से यह शर्मिला वन्य जीव असहज है।

अनुरोध है कि उद्योग के तेज प्रकाश को अवरुद्ध करने, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अभयारण्य विकसित करने हेतु 1000 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि की अवाप्ति, 2050 हैक्टेयर अतिरिक्त वन भूमि के प्रभावी संरक्षण एवं देखभाल, अभयारण्य के 10 किलोमीटर की परिधि में खनन कार्य पर प्रतिबन्ध, भारतीय वन्य जीव संस्थान की एक शाखा के सोरसन में संचालन, भारत सरकार के माध्यम से प्रजनन केन्द्र शीघ्र प्रारम्भ करने, सोरसन (बारां), दर्रा, गांधीसागर को मिलाकर वृहद्जीव अभयारण्य घोषित कर वन भूमि के प्रभावी संरक्षण एवं देखभाल किये जाने से इस दुर्लभ राज्य पक्षी को पुनर्वासित करने में सफलता प्राप्त होगी, जिससे गोडावण पक्षी पुनर्प्रवासोपरांत यहां अन्य वन्य जीवों के साथ संरक्षित तथा सुरक्षित रहकर विचरण कर सकेंगे।

श्री जगसी राम (रेवदर)

मंडार-रेवदर-सिरोही मेगा हाईवे की टोल संग्रहण की समयावधि में वृद्धि

महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये सरकार से आग्रह है कि मंडार-रेवदर-सिरोही मेगा हाईवे रोड का निर्माण कार्य शिव पूजा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी की ओर से करवाकर टोल संग्रहण का काम 01 मई, 2010 से शुरू किया गया, जो 31 मार्च, 2022 को बन्द होना था, परन्तु

कोविड-19 की वजह से राज्य सरकार द्वारा 6 महीने समयावधि बढ़ाकर टोल संग्रहण पूर्ण करने की अवधि बढ़ाकर 5 अक्टूबर, 2022 निर्धारित कर दी गई थी, लेकिन टोल प्लाजा कम्पनी द्वारा 5 अक्टूबर, 2022 के बाद भी टोल वसूली को आज दिनांक तक बन्द नहीं किया गया है। सम्बन्धित टोल प्लाजा कम्पनी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों एवं मंत्रालय में सांठगांठ कायम कर टोल संग्रहण की अवधि को पुनः आगे तक बढ़वा लिया गया है। टोल प्लाजा पर प्रतिमाह महीने की 05 तारीख अन्तिम टोल वसूली तिथि का स्टीकर लगाकर भोली भाली जनता, वाहन चालकों से छल-कपट, जोर जबरदस्ती से टोल वसूली की जा रही है। सरकार को बताना चाहूंगा कि मंडार रेवदर-सिरोही मेगा हाईवे सड़क जगह-जगह से जर्जर हो चुकी है, लेकिन शिव पूजा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी ने टोल रोड को दुरुस्त करने, पुनः डामरीकरण करने की जिम्मेदारी नहीं निभाई है। अतः सम्बन्धित टोल कम्पनी से उक्त समूची टोल रोड का पुनः डामरीकरण कराया जावे, 5 अक्टूबर, 2022 के बाद अवैध टोल वसूली से एकत्र की गई धनराशि को कम्पनी से लिया जाकर सरकारी खाते में जमा कराया जावे, टोल वसूली अवधि बार-बार बढ़ाये जाने के आदेशों की उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषी अधिकारियों एवं अवैध टोल वसूलकर्ता कम्पनी के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जावे।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर)

नर्सिंग अधिकारियों की पदोन्नति सूची में हुई गड़बड़ी की जांच कर पात्र कार्मिकों के नामों का सूची में सम्मिलन

महोदयजी, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 5953 नर्सिंगकर्मियों के पदोन्नति सूची में पदोन्नत किये गये कई कार्मिक ऐसे हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है और कई सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इन लोगों को सूची में शामिल कर लेने से कई योग्य कार्मिक पात्र होते हुए भी पदोन्नत नहीं हो पाए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि पूर्व में पदोन्नत हो चुके कार्मिकों को भी इस सूची में शामिल कर दोबारा प्रमोट कर दिया गया है। इसके अलावा टीएसपी क्षेत्र में बैकलाग होने के बाद भी लिस्ट जारी नहीं की गई है। आरपीएससी के बाद की रैंक के कर्मचारियों को पदोन्नति में शामिल कर दिया। पदोन्नति सूची में यह भी खामियां हैं कि आरपीएससी रैंक और नियुक्ति तिथि पदोन्नति सूची में अंकित नहीं है। डीपीसी वर्ष 2013-14 से 2019-20 तक रिव्यू डीपीसी जारी की गई हैं। इसमें

पूर्व में पदोन्नत सीनियर नर्सिंग आफिसर को भी शामिल किया है। टीएसपी एरिया का बैकलाग होने के बाद भी सूची जारी नहीं की। नोन टीएसपी क्षेत्र में प्रमोशन लेकर टीएसपी क्षेत्र में पदस्थापित होकर यहां के पद को भर देते हैं।

अतः माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि 5953 नर्सिंग अधिकारी की पदोन्नति सूची में गड़बड़ियों की जांच कर पात्र कार्मिकों के नाम सूची में शामिल करने एवं टीएसपी क्षेत्र में बैकलाग की लिस्ट जारी की जावे तथा पदोन्नति करने वाली कमेटी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जावे।

सादर।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा)

रावतसर एवं पीलीबंगा नगरपालिकाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितताएं

महोदय, उपरोक्त निवेदन है कि पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में पीलीबंगा व रावतसर दोनों नगरपालिकाओं में व्यापक अनियमितता है व भ्रष्टाचार फैला हुआ है व निर्माण कार्य की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही हैं। दोनों नगरपालिकाओं में मनमर्जी हो रही है। निर्माण कार्यों के टेण्डर ऑनलाइन न लगाकर ऑफलाइन लगाये जा रहे है। ठेकेदारों व पालिका प्रशासन की मिलीभगत व मनमर्जी के कारण उन कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को कार्य दिये जाते हैं। यदि ऑफलाइन टेण्डर कोई दूसरा ठेकेदार डालता है तो वो टेण्डर खोले नहीं जाते हैं व टेण्डर निरस्त कर दिये जाते हैं। नगरपालिका में इतना अधिक कमीशन है कि ठेकेदार काम की गुणवत्ता में समझौता कर घटिया निर्माण करता है। सड़क या अन्य निर्माण कार्य चन्द दिनों में बिखर जाता है, जो आज से 2 वर्ष पूर्व नगरपालिका पीलीबंगा व रावतसर में निर्माण कार्य की जांच की जावे। यदि दोनों नगरपालिकाओं में सीसी रोड, डामर रोड, नाली व नाला निर्माण व मिट्टी भरती व अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच व डीजल क्रय की जांच की जावे एवं भविष्य में नगरपालिकाओं में टेण्डर ऑफलाइन न लगाकर ऑनलाइन लगाये जायें ताकि ठेकेदार कार्यों का पूल समझौता न कर सके, निर्माण कार्यों में हो रही अनियमितता व भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके। घटिया निर्माणों की जांच करवाई जावे व नगरपालिका में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिये पार्षदों द्वारा संबंधित कार्यों की प्रमाणित प्रतिलिपि मांगने पर नहीं दी जाती है, जिससे स्पष्ट जाहिर होता है, भ्रष्टाचार व्यापक है। नकल की प्रमाणित प्रतिलिपि मिलनी चाहिए।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर)

जहाजपुर में कार्य व्यवस्थार्थ अथवा प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित शिक्षकों को उनके मूल पदस्थापन का कार्यभार

महोदय, जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी कोटड़ी एवं जहाजपुर के द्वारा शिक्षकों को मनमानी तरीके से कार्य व्यवस्थार्थ/पद विरुद्ध/डेपुटेशन पर अन्य विभागों में अपने मूल पदस्थापन स्थान के विरुद्ध लगाया हुआ है। राजकीय व्द्यालयों में अधिकांश पद शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के रिक्त पड़े हुए हैं साथ ही विद्यार्थियों की पढ़ाई चौपट हो रही है। हाल ही में सीबीईओ कोटड़ी द्वारा ब्लाक क्षेत्र के 25 शिक्षकों को बीज निगम के अध्यक्ष की निजी यात्रा में निकले तो सरकार की धौंस बताकर अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक को जिला मुख्यालय से कोटड़ी तक की पदयात्रा करने तथा कार्ड वितरण से लेकर स्वागत व अन्य व्यवस्थाओं में उच्च अधिकारियों की सहमति के बगैर ही कोटड़ी क्षेत्र के अधिकारियों व शिक्षकों को बुलाना पूर्णतया गैर जिम्मेदाराना है। ज्ञातव्य है कि सीबीईओ कोटड़ी द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर, 2022 को एक आदेश जारी कर 25 शिक्षकों को पदयात्रा में व्यवस्थाओं के नाम पर 14 से 17 अक्टूबर तक लगा दिया गया था। उक्त आदेश में, ड्यूटी कहां करनी है। इसी तरह विगत चार वर्षों में जहाजपुर व कोटड़ी सीबीईओ के अधीनस्थ शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अलावा कहां-कहां पदस्थापित किया गया, जैसे उपखण्ड अधिकारी कार्यालय व अवैध बजरी खनन के विरुद्ध चैक पोस्टों पर लगाया गया, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ है। छात्राओं को साइकिल वितरण कार्यक्रम में राजनैतिक कार्यक्रम कराया गया। उक्त गैर जिम्मेदाराना आदेश एवं विद्यालयों में वार्षिक उत्सव के नाम पर राजनैतिक कार्यक्रम किये जा रहे हैं तथा संबंधित समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए इस क्रम में मेरा आग्रह है कि उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाते हुए प्रकरण में दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाए। साथ ही शिक्षा विभाग से कार्य व्यवस्थार्थ/डेपुटेशन/मूल पदस्थापन स्थान के विरुद्ध लगाए हुए कार्मिक/अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाकर अपने मूल पदस्थापन स्थान पर भेजे जाने का श्रम करें।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर)

गोचर भूमि का संरक्षण एवं मंदिरों की सरकारी नियंत्रण से मुक्ति

महोदय, निवेदन है कि भारतीय सभ्यता में गोपालन कार्य पौराणिक काल से भारतीयों की रग-रग में बसा हुआ है। गोपालन मनुष्य के विकास के

लिए महत्वपूर्ण विषय है। समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग गाय को माता का दर्जा देकर उसकी पूजा करते आ रहे हैं। आज गोमाता की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। लोगों ने इन्हें बेसहारा छोड़ दिया। सरकार को गोमाता की चिंता करते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सरकारी खर्च से एक-एक गोशाला, नंदी शाला खोलने, सभी संस्थाओं द्वारा संचालित गौशालाओं में 9 महीने से बढ़ाकर 12 महीने का अनुदान दिलाने, गाय व नंदी पालन करने वाले परिवारों को अनुदान दिलाने की कार्यवाही करनी चाहिए।

साथ ही गायों की चराई, स्वच्छ विचरण हेतु आदि काल से आरक्षित गोचर भूमि को सुरक्षित, अतिक्रमण मुक्त करने की आवश्यकता है। लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना के पूर्व भी रियासत काल में राजाओं, महाराजाओं, जमींदारों, गांव के ठाकुरों एवं समाज के प्रत्येक वर्ग द्वारा गोपालन के लिए अपने द्वारा सार्वजनिक गोचर भूमि को प्रत्येक गांव में संरक्षित करने का कार्य किया। आज गोचर भूमि का अस्तित्व संकट में है, गोचर भूमि समाप्त होने पर गोवंश के जीवन पर व्यापक दुष्प्रभाव पड़ेगा। अतः सरकार से मांग है कि राजकीय नीतियों में बदलाव कर 1993 से पहले की स्थिति कायम करावे तथा गोचर भूमि का पूर्णतया अन्य कार्यों में उपयोग बंद करावें।

ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल से सरकार द्वारा हिन्दू मंदिरों का अधिग्रहण शुरू किया था, ब्रिटिश सरकार ने हिन्दू मंदिरों को कब्जे में लेना, चलाना, नियंत्रित करना जारी रखा। सरकार किसी अन्य धर्म के धार्मिक स्थलों को नियंत्रित नहीं करती है। मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख सभी अपने-अपने धार्मिक स्थलों के चलाने, संचालित करने के लिए स्वतंत्र हैं, सरकारी नियंत्रण से मुक्त हैं। केवल हिन्दुओं के साथ भेदभाव किया जाता है। इस संवैधानिक देश में सभी जाति धर्म के लोगों को समान मान्यता प्राप्त है और उनकी आस्थाओं को भी समान महत्व देने के प्रावधान हैं लेकिन आज भी देश में यह दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के अमृत काल में भी कई राज्यों सहित राजस्थान में मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है। मैं इस पवित्र सदन के माध्यम से सरकर से राजस्थान के सभी मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग करता हूं।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर)

रायसिंहनगर में गंगानहर परियोजना की खाटा माइनर की स्वीकृति व पानी की उपलब्धता

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में वर्ष 1974 में गंगनहर परियोजना के तीन माइनरों का सर्वे हुआ था। लखाहाकम, खाटा और भौमपुरा

माइनर, वर्ष 1997 में श्री भैरोंसिंह शेखावत सरकार के सिंचाई मंत्री श्री देवी सिंह भाटी जी के समय में भौमपुरा माइनर और लखाहाकम माइनर में मंजूर होकर पानी चालू कर दिया गया था, लेकिन खाटा माइनर के नक्शे में आई गलती की वजह से यह माइनर नहीं बन पाया, जिसकी वजह से आज सैकड़ों परिवार पलायन करने को मजबूर हैं। खुद की जमीन होते हुए भी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करना पड़ता है। जून, 2006 में तत्कालीन मंत्री हेमाराम जी के कार्यकाल में जल संसाधन विभाग ने इसके सर्वे के आदेश जारी किये, लेकिन वो सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गये, जिसका खामियाजा सात गांवों के लोग भुगत रहे हैं। खाटा माइनर का पानी 9.75 क्यूसेक्स है, जो आज भी रिजर्व है। वर्ष 2006 में सांवरलाल जाट जी द्वारा पीएस हैड का निरीक्षण किया और खाटा माइनर को चालू करने के प्रयास भी किये मगर प्रयास सिरे नहीं चढ़ सके। आज बोर्डर पर बसे हुए गांव खाटा, लूणेवाला 31 पीएस चाहरावाली ढाणी, 82 आरबी, 36 पीएस, समेजा, लखाहाकम के किसानों को 250 मुरब्बे जमीन बारानी एवं बंजर पड़ी है। लखाटिब्बा के 375 मुरब्बे सिंचित होना प्रस्तावित है। इस रकबे को सिंचित करने के लिए 27 क्यूसेक्स पानी की आवश्यकता है। खाटा माइनर नहीं बनने की वजह से चारों और बारानी ही बारानी दिखाई दे रही है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि खाटा माइनर मंजूर करके इसमें पानी चलाया जाये ताकि क्षेत्र को इसका लाभ मिल सके।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द)

आसीन्द के कतिपय गांवों में दाह-संस्कार हेतु श्मशान भूमि का आबंटन

महोदय, निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र आसीन्द हुरडा में ऐसे कई गांव हैं जिसमें किसी की मृत्यु होती है और उसका दाह-संस्कार करने जाते हैं तो कई तरह के विवाद हो जाते हैं क्योंकि कई गांवों में श्मशान भूमि श्मशान के नाम पर नहीं होने या चरागाह में होने या पुराने समय से व्यक्तिगत नाम पर दर्ज होने से आये दिन विवाद होते रहते हैं तथा हिन्दू समाज में ऐसी कई जातियां हैं जिनमें मृत्यु होने पर अलग-अलग तरह से दाह-संस्कार किये जाते हैं। जिनमें योगी तथा कुछ और जातियां हैं जिनमें मृत्यु होने पर समाधि दिए जाने की परम्परा है व कई जातियों में अग्निदाह करने की परम्परा है। इस वजह से मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि विधान सभा आसीन्द हुरडा के उन

सभी गांवों का सर्वे कराकर जिनमें श्मशान भूमि श्मशान के नाम पर दर्ज नहीं है, या है तो किसी का कब्जा है और दूसरी जगह दाह-संस्कार होता है तथा कुछ जगह नदी या और अन्य जगहों पर दाह-संस्कार होता है, उनकी लिस्ट बनाकर जगह नहीं है तो जगह आबंटन कराने की कृपा करावें ताकि आये दिन होने वाले झगड़ों से आम जनता को मुक्ति मिले। मेरा आपसे निवेदन है कि बहुत सी जगहों पर आये दिन कई तरह के विवाद होते हैं और इंसानियत शर्मसार होती है क्योंकि आये दिन बहुत से गांवों में इस तरह की घटनाएं होती हैं और वहां प्रशासन व पुलिस का सहयोग लेना पड़ता है तब जाकर दाह संस्कार होते हैं। ऐसी कई जातियां हैं जिनको परेशानी होती है और वहां गावों में जो लोग आपसी प्रेम भाव तथा भाईचारे से रहते हैं, वो आपस में ही एक-दूसरे के सामने हो जाते हैं और फिर प्रशासन या पुलिस आती है, समझाइश होती है, वहां लोगों को आश्वासन दिया जाता है कि अब यह भूमि श्मशान के नाम दर्ज करा देंगे, तब जाकर दाह संस्कार तो हो जाते हैं मगर समस्या वैसी की वैसी ही रह जाती है।

अतः इस समस्या का स्थायी समाधान कराने की कृपा करावें। आपकी अति मेहरबानी होगी।

परिशिष्ट-02

मांग संख्या 20 - प्रारम्भिक शिक्षा पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 20 - प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई):

1. विधान सभा क्षेत्र नदबई के राजकीय प्राथमिक विद्यालय चकचोबा (कल्याणपुर) को क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिए।
2. विधान सभा क्षेत्र नदबई के राजकीय प्राथमिक विद्यालय नगला परसा (भैंसा) को पुन: प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।
3. विधान सभा क्षेत्र नदबई के राजकीय प्राथमिक विद्यालय चन्दनपुरा (बरिधां) में स्टाफ नियुक्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

4. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के वार्ड नं. 18 में प्राथमिक स्कूल खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

5. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में नवीन प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत करने, प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने तथा विद्यालयों में भवन व फर्नीचर की उचित व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता के संबंध में आवश्यक चर्चा के लिए।

श्री पदमाराम (चौहटन):

6. विधान सभा क्षेत्र चौहटन के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों को क्रमोन्नत करने, रिक्त पदों को भरने तथा स्कूलों में भवन, शौचालय, पेयजल हेतु व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री संदीप कुमार (तिजारा):

7. विधान सभा क्षेत्र तिजारा में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने, विद्यालयों में भवन निर्माण करने, खेल मैदान (प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर) विकसित करने तथा शिक्षकों के रिक्त पद भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री वाजिब अली (नगर):

8. विधान सभा क्षेत्र नगर में 40 साल से संचालित प्राथमिक स्कूलों को क्रमोन्नत करने तथा उर्दू व पंजाबी भाषा भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लाखन सिंह (करौली):

9. विधान सभा क्षेत्र करौली में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने, स्कूलों को क्रमोन्नत करने तथा अध्यापकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

10. विधान सभा क्षेत्र दूदू में मापदण्ड के विपरीत मर्ज 128 विद्यालयों को डी मर्ज करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

11. विधान सभा क्षेत्र दूदू में तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के स्थानान्तरण करने, प्राथमिक विद्यालयों व तृतीय ग्रेड श्रेणी विद्यालयों को क्रमोन्नत करने तथा रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन):

12. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के पूर्व में बन्द प्राथमिक विद्यालय तरकेल ग्राम पंचायत सारण, हीराजी की कुड़ी झिझारड़ी, आसन मेलडा ग्राम पंचायत गुडा शूर सिंह, ऐलानी ग्राम पंचायत (इन्दरवाड़ा)-ब्लाक रानी तथा देवली उच्च बालिका (ब्लाक-मारवाड़ जंक्शन) विद्यालयों को पुन: प्रारम्भ करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

13. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के फुलाद बालिका (ब्लाक मारवाड़-जंक्शन) तथा बड़लीया कल्ला ग्राम पंचायत पनोता (ब्लाक देसूरी) में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

14. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में डायलाना खुर्द प्राथमिक विद्यालय (NIC-कोड नं. 504144), गुड़ा गोपीनाथ-(NIC-कोड नं. 504138) तथा सारीयों की ढाणी अऊवा-(NIC-कोड नं. 420337) प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

15. विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर के प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में बच्चों की संख्या के अनुसार कमरों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

16. विधान सभा क्षेत्र चितौड़गढ़ में संचालित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जीर्ण-शीर्ण विद्यालय भवनों के दुरुस्तीकरण के संबंध में चर्चा के लिए।

17. विधान सभा क्षेत्र चितौड़गढ़ में प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पड़े पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

18. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के RWM लुहारावाला चक रावतसर, 7 DWM रावतसर, 29 STG पीलीबंगा, 21 MOD पीलीबंगा के प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने तथा शिक्षकों के रिक्त पद भरने तथा विद्यालयों में कमरों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

19. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के बन्द पड़े राजकीय प्राथमिक विद्यालय मठ महु आ खेड़ा को पुन: संचालित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

20. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के बन्द पड़े कोरीपुरा (रेवई) विद्यालय को पुन: संचालित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

21. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के बन्द पड़े राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेड़ा (बाड़ी) को पुन: संचालित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

22. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के बन्द पड़े राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुदिन्ना पुरा को पुन: संचालित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

23. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के बन्द पड़े राजकीय प्राथिमक विद्यालय ऊची का पुरा (कुरेधा) को पुन: संचालित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल):

24. प्रदेश में जिला शिक्षा अधिकारियों के पदों की भर्ती करने, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों तथा PTI की भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

25. प्रदेश में प्रबोधक पदोन्नति पश्चात् शालादर्पण पर पदरचना नहीं बताने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

26. प्रदेश में विद्यालय एकीकरण योजना के तहत बंद किये गये विद्यालयों को पुन: प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता और वर्तमान में कम नामांकन के प्राथमिक विद्यालयों को बन्द किये जाने की प्रक्रिया को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. प्रदेश में प्रबोधक पदोन्नति पश्चात् उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के खाली पदों पर पदस्थापन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

28. प्रदेश में अध्यापकों की 6-डी होने पर खाली पदों पर नई भर्ती किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

29. प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के गिरते हुए स्तर को सुधारने के लिए पायलट प्रोजेक्ट की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़):

30. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में प्राथमिक विद्यालयों के भवन जर्जर होने, शौचालय एवं कमरों की कमी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

31. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के स्कूलों में रिक्त पड़े पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

32. विधान सभा क्षेत्र नोखा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय भौम बिलनियासर, शिवराज की ढाणी जयसिंहदेसर मगरा, हिंगड़ों की ढाणी सिलवा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय लूम्बासर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिंवरों की ढाणी दावा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय भाटियों की ढाणी बासी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मुरीदसर तथा

राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेघवालों की ढाणी तालवा को क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिए।

33. विधान सभा क्षेत्र नोखा में सिरोलो की ढाणी दासनू, रागाना डेरा भादला, सुंडलाई नाडी चरकड़ा, नायकों की ढाणियां तथा रायसर-दासनू रोड रायसर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने पर चर्चा के लिए।

34. विधान सभा क्षेत्र नोखा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय धांकलनगर नाथूसर को डी मर्ज कर चालू करने पर चर्चा के लिए।

35. विधान सभा क्षेत्र नोखा के समस्त प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद भरने पर चर्चा के लिए।

36. विधान सभा क्षेत्र नोखा के समस्त प्राथमिक विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन करने, चारदीवारी निर्माण, शौचालय निर्माण व मरम्मत कार्य पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

37. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में नये प्राइमरी स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर):

38. प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा में उर्दू माध्यम चालू करने, उर्दू शिक्षकों की भर्ती करने तथा संस्कृत विद्यालय खोलने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा):

39. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में पंचायत समिति कोटडा की ग्राम पंचायत खाम व गुरा में स्कूल खोलने के संबंध मे चर्चा के लिए।

40. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की पंचायत समिति कोटडा के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों झालरा, बोरली एवं राई में स्कूल भवन निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के जिन विद्यालयों के भवन खस्ता हालत में हैं, उनका सर्वे कर नये भवन बनाने व सुधार करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

42. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के अध्यापकों को अन्य सरकारी कार्य से

मुक्त कर शिक्षण कार्य में ही लगाये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

43. प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा में अधिक गुणवत्ता लायी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़):

44. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के सुजानगढ़ व बीदासर ब्लाक में क्रमोन्नत स्कूलों में कक्षा-कक्षों के निर्माण तथा रिक्त पदों की शीघ्र भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी):

45. लाडपुरा पंचायत समिति का अरवावा प्राथमिक विद्यालय में 50 विद्यार्थी उपलब्ध होने के बावजूद भी स्कूल बंद करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

46. विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी की पंचायत समिति खैराबाद के ग्राम खरनी बावड़ी में प्राथमिक विद्यालय पुन: प्रारम्भ नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

47. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के स्कूलों में लेवल 1 व 2 के अंग्रेजी माध्यम के अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

48. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवपुरा तथा खण्डेरिया (पंचायत समिति जहाजपुर) विद्यालयों को पुन: चालू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

49. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में चारदीवारी विहीन विद्यालयों में DMFT या अन्य योजना के तहत चारदीवारी निर्माण कराने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

50. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के सभी प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी स्कूलों में सुलभ शौचालयों का निर्माण कार्य एवं बिजली पानी की सम्पूर्ण व्यवस्था कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

51. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के सभी रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबु लाल (झाडोल):

52. विधान सभा क्षेत्र झाडोल के विद्यालयों में अध्यापकों की कमी दूर करने, विद्यालयों में कक्षा-कक्षों के निर्माण कराने तथा विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर):

53. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में स्टाफ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

54. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के प्रारम्भिक शिक्षा के बालक/बालिकाओं, जिनके स्कूल की दूरी 500 मीटर से ज्यादा है, के लिए वाहन व्यवस्था हेतु विभागीय पहल किये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

55. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के प्रारम्भिक शिक्षा विद्यालयों में फर्नीचर की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

56. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के प्रारम्भिक विद्यालयों में खेल के मैदानों के विकास की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

57. प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में बच्चों को पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

58. विधान सभा क्षेत्र कपासन के राजकीय प्राथमिक विद्यालय तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के खेल मैदान पर हो रहे अवैध कब्जों को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

59. विधान सभा क्षेत्र कपासन के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रूदडी (पंचायत समिति कपासन) के खेल मैदान पर हो रहे अवैध कब्जे को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

60. विधान सभा क्षेत्र कपासन के राजकीय प्राथमिक तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों तथा चारदीवारी के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61. विधान सभा क्षेत्र कपासन के राजकीय प्राथमिक विद्यालय तथा

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

62. विधान सभा क्षेत्र कपासन के राजकीय प्राथमिक एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर शीघ्र पदस्थापन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर):

63. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में उमरिया ग्राम पंचायत लिमी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

64. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में झालरा पाटन के चुना भाटी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का नया भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

65. प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में नये विद्यालय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

66. प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में नियुक्ति स्थान से अन्य स्थानों पर प्रतिनियुक्ति को शीघ्र निरस्त करने पर चर्चा के लिए।

67. प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में भवनों का निर्माण छात्र अनुपात में कराने पर चर्चा के लिए।

68. प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के तहत संचालित विद्यालयों में स्थित भवनों की मरम्मत पर चर्चा के लिए।

69. प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में स्वीकृत सभी शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):

70. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय साजीदेहड़ा में जर्जर भवन का जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादडी):

71. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के भीखाखेड़ा (भाटोली बागरियान) में नया प्राथमिक विद्यालय खोले जाने संबंधी आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

72. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के नांगेड़ी (तीतरड़ा) (ग्राम पंचायत नेगडीया) में नया प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

73. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पड़े पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगसी राम (रेवदर):

74. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों से पिछले 4 वर्षों के दौरान किये गये शैक्षणिक स्टाफ के तबादलों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

75. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में भवन, शौचालय एवं खेल मैदानों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

76. विधान सभा क्षेत्र रेवदर की राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में सफाई कर्मी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व नोन टीचिंग स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

77. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, भ्रमण, खेलकूद, मनोरंजन तथा कम्प्यूटर शिक्षा के लिए नाम मात्र के बजट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा):

78. विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को पाउडर के स्थान पर पौष्टिक दूध उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

79. विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा के सभी विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

80. विधान सभा क्षेत्र मावली के प्राथमिक विद्यालयों में चारदीवारी व कक्षा-कक्षों के निर्माण की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

81. विधान सभा क्षेत्र मावली के पुराने जर्जर व जीर्ण-शीर्ण प्राथमिक

विद्यालय भवनों व उनकी छतों की मरम्मत किये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

82. विधान सभा क्षेत्र मावली के वंचित राजस्व ग्रामों में राजकीय प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू):

83. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू के विद्यालयों में अध्यापकों की कमी की पूर्ति करने तथा कक्षा-कक्षों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

84. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में गैर-अनुसूचित क्षेत्र के तृतीय श्रेणी अध्यापक जो अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत है, उन्हें उनके गृह जिला या गैर-अनुसूचित क्षेत्र में स्थानान्तरण करके रिक्त पदों पर अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों को नियुक्त किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

85. प्रदेश में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में रिक्त रहे 1167 अनारक्षित ST के पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देकर राहत प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

86. विधान सभा क्षेत्र भादरा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय मलखेड़ा को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

87. विधान सभा क्षेत्र भादरा के 14 NTR जो कि ब्लाक नोहर है, में नया प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

88. विधान सभा क्षेत्र भादरा के 12 DPN (ब्लाक नोहर) में नया प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

89. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के सभी स्कूलों में बाउंड्रीवाल बनवाने, पानी की व्यवस्था करवाने तथा ग्राम पंचायत के राजस्व फूलसिंह गांव आड में उच्च प्राथमिक विद्यालय खुलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

90. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के सभी स्कूलों में जर्जर भवनों की मरम्मत करवाने एवं अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़):

91. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

92. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के प्राथमिक विद्यालय पुन्याखेड़ी ब्लाक दलोट को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने, पानमोड़ी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बालिका प्राथमिक विद्यालय खोलने तथा सेलारपुरा ग्राम पंचायत कूणी में बालिका प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के चौकली पिपली प्राथमिक विद्यालय ब्लाक दलोट तथा सातमहुडी ग्राम पंचायत मुख्यालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

94. प्रदेश में पूर्व में मर्ज किये गये विद्यालयों को फिर से शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

95. प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती कर रिक्त पद शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

96. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण करवाने व जर्जर भवनों की मरम्मत करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

97. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

98. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के सभी विद्यालयों में खेल मैदानों का निर्माण करने तथा खेल सामग्री उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती मंजु देवी (जायल):

99. विधान सभा क्षेत्र जायल के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में रिक्त पदों को भरने तथा कक्षा-कक्षों के निर्माण पर चर्चा के लिए।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

100. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में एकल शिक्षक वाले प्राथमिक शिक्षा के विद्यालयों की स्थिति, पूर्व प्राथमिक कक्षाएं शुरू करने, प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों द्वारा गैर शैक्षणिक कार्य करने से उत्पन्न स्थिति, खींवसर के सभी प्राथमिक विद्यालयों में LED के माध्यम से शिक्षण व ABL किट की उपलब्धता तथा बन्द पड़े विद्यालय भवनों में नये विद्यालय खुलवाकर उन्हें संचालित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमित चाचाण (नोहर):

101. विधान सभा क्षेत्र नोहर के विद्यालयों में कक्षा-कक्षों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

102. विधान सभा क्षेत्र नोहर के प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

103. विधान सभा क्षेत्र नोहर के विद्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

104. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी के शिक्षकों की भर्ती, प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त कक्षा-कक्षों का निर्माण, पेयजल की व्यवस्था तथा खेल मैदानों के विकास के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह (आहोर):

105. विधान सभा क्षेत्र आहोर के देलदरी गांव में पूर्व मे संचालित ढाणियों के लिए प्राथमिक विद्यालय देवरिया में पुन: विद्यालय शुरू करने संबंधी आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

106. विधान सभा क्षेत्र आहोर के हरजी गांव में पूर्व से संचालित बालिका प्राथमिक विद्यालय को डी मर्ज करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

107. विधान सभा क्षेत्र आहोर के आलावा 'सी', देवगढ़ छापरिया प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

108. विधान सभा क्षेत्र आहोर के बिठुडा ग्राम पंचायत के मंडला उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा-कक्षों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

109. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय खैरवा को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने व दो कक्षा-कक्षों का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

110. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संजयनगर, सुमेरपुर को राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय हाउसिंग बोर्ड, सुमेरपुर से तथा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तख्तगढ़ को राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय तख्तगढ़ से अलग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

111. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खिमाड़ा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भोपालसिंह की ढ़ाणी खीमाड़ा व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पालड़ीजोड़ में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पालड़ीजोड़ तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालय बलवना में राजकीय प्राथमिक विद्यालय बलवना को तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साण्डेराव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय साण्डेराव से अलग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

112. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, अध्यापक, शारीरिक शिक्षकों के लगभग 115 रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

113. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में राजकीय प्राथमिक व राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चारदीवारी, शौचालय, खेल मैदान की चारदीवारी तथा कक्षा-कक्षों के निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट):

114. विधान सभा क्षेत्र लोहावट के राजकीय विद्यालयों में जर्जर भवनों की मरम्मत व पानी के कनेक्शन की समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

115. जिला बाड़मेर में क्षेत्रफल एवं विद्यालयों की दृष्टि से प्रभावी पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण हेतु बालोतरा में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं अधीनस्थ कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

116. प्रदेश में विषम भौगोलिक परिस्थितियों (पहाड़ी/मरुस्थलीय आदि) क्षेत्रों में नियमों में शिथिलता प्रदान कर नवीन प्रा.वि. खोलने व उ.प्रा.वि. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

117. प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों (विशेषकर सीमावर्ती एवं मरुस्थलीय क्षेत्र के) में विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118. प्रदेश में वंचित नवीन ब्लाक मुख्यालय पर सीबीईओ कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

119. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में 4 नवीन प्राथमिक विद्यालय एवं 14 उच्च प्राथमिक विद्यालय के क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीराराम (बिलाड़ा):

120. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा की ग्राम पंचायतों में नये प्रारंभिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

121. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की पंचायत समिति सलूम्बर, सराड़ा, जयसमन्द, सेमारी व झल्लारा में प्रा. शिक्षक के रिक्त पड़े पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

122. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के प्रा. स्कूलों के भवनों की मरम्मत, चारदीवारी, शौचालय व कक्षा-कक्षों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

123. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों के खेलने के लिए खेल मैदान का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

124. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय व

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

125. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय व राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था एवं बिजली की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

126. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में ग्राम पंचायत रास्ता पाल में बजट घोषणा 2023-24 में खोली गई नवीन प्राथमिक विद्यालय का नामकरण वीर भील बाला काली कलासूआ के नाम से करने संबंधी चर्चा के लिए।

127. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवनों में शौचालय के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

128. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के अनुसूचित क्षेत्र के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में सरकार के निर्देशों के बावजूद भी स्थानीय भीली भाषा में अध्ययन नहीं करवाने से राजकीय विद्यालयों से विद्यार्थियों के पलायन करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद):

129. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद स्थित प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति करने एवं रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

130. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के रा.प्रा.वि. रेलवे स्टेशन मांगलियावास का भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

131. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के पुराने स्कूल भवनों की मरम्मत एवं नवीनीकरण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

132. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के रा.प्रा.वि., रावतों की ढाणी, सवाईपुरा व डाबला की ढाणी, सूरजकुंड व पंचायत समिति पीसांगन के भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

133. प्रदेश के IIIrd ग्रेड अध्यापकों की स्थानान्तरण नीति बनाये जाने तथा उसके अनुरूप स्थानान्तरण किये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

134. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पड़े अध्यापकों के पद शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

135. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के प्राइमरी स्कूलों में बिजली-पानी की समस्या दूर किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

136. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में भवन व भूमि रहित प्राइमरी विद्यालयों हेतु भूमि आबंटन व कक्षा-कक्षों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

137. विधान सभा क्षेत्र चौमूं की प्राइमरी स्कूलों के रिक्त भवनों को अतिक्रमण से मुक्त कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

138. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमीन खां (शिव):

139. विधान सभा क्षेत्र शिव में सीमावर्ती रेगिस्तानी क्षेत्र में नये प्राइमरी स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

140. बाड़मेर जिले के सीमावर्ती रेगिस्तानी क्षेत्र के प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों के खाली पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़):

141. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के गांव गोरीसर में अमर शहीद राजेन्द्र नैण के नाम पर बालिका विद्यालय स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

142. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के गांव छाबड़ी खारी, तालणियों की ढाणी व ढाणी रणवा स्थित प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

143. प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानान्तरण नीति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

144. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद):

145. शिक्षा विभाग में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की उपस्थिति बायो मैट्रिक व्यवस्था से करवाने बाबत चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना):

146. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के राजकीय प्राथमिक विद्‌यालय पंचपीपली, काजलिया एवं कटफली को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

147. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के भवन विहीन प्राथमिक विद्‌यालय बिशनखेड़ा एवं श्यापुरा में नया भवन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

148. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के रामलाल की ढाणी कल्याणसर नया, जाटों का मोहल्ला हनुमान मन्दिर के पास लिखमीसर उत्तरादा, पाटवानिया जोहड़ के पास बिग्गा बास रामसरा, बावरी मोहल्ला गौशाला के पास कालूबास श्रीडूंगरगढ़ में नवीन राजकीय प्राथमिक विद्‌यालय खुलवाये जाने, सुखराम का कुंआ बरजांगसर की राजकीय प्राथमिक विद्‌यालय को क्रमोन्नत करने तथा राजकीय प्राथमिक विद्‌यालय नायकों का मोहल्ला वाहानू में पूर्व में बंद की गई स्कूल को पुन: प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर):

149. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में प्रारम्भिक स्कूलों के कक्षा-कक्षों के निर्माण, कमरों की जर्जर अवस्था के सुधार तथा स्कूल के खेल मैदान व चारदीवारी निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-बटरू):

150. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू की ग्राम पंचायत कटावर के ग्राम अरणिया खेड़ा के बन्द पड़े प्राथमिक विद्‌यालय को पुन: चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली):

151. विधान सभा क्षेत्र बाली के प्राथमिक विद्‌यालयों में नये कक्षा-कक्षों व चारदीवारी के निर्माण करने तथा पीने के पानी की समस्या दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

152. विधान सभा क्षेत्र बाली के कुरका शिवाजी नगर फालना में नई प्राथमिक विद्यालय खुलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द):

153. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द-हुरड़ा के ग्राम पंचायत बोरेला के अर्जुनपुरा तथा ग्राम पंचायत रामपुरा के जालका बाड़ीया गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अविनाश (जैतारण):

154. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मरम्मत कार्य, जीर्ण-शीर्ण कक्षा-कक्षों की मरम्मत व आवश्यकता अनुसार नवीन कक्षा-कक्षों की स्वीकृति की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

155. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में सभी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद भरने तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

156. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में संचालित सभी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं व स्टाफ की सुविधा के लिए टीन-शैड, छत के पानी के उपयोग हेतु टांकों के निर्माण किये जाने तथा खेल मैदानों की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

157. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में संचालित प्राथमिक विद्यालयों को ग्रामवासियों की मांग पर व विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या के अनुसार क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

158. प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की स्थानान्तरण नीति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री कालूराम (डग):

159. विधान सभा क्षेत्र डग के सभी प्रारंभिक विद्यालयों के भवनों का मरम्मत कार्य करवाने, अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण तथा चारदीवारी बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

160. विधान सभा क्षेत्र डग के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय विशनिना, उमरिया, गुराड़ीया इसर, ढाबला गहलोत व सरकनीया को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

161. विधान सभा क्षेत्र डग के प्रारंभिक स्कूलों में अध्यापकों की कमी के कारण अध्ययन में हो रहे व्यवधान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

162. विधान सभा क्षेत्र डग के प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीनियर सैकन्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर):

163. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने, रिक्त पड़े पद भरने तथा फर्नीचर की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

164. विधान सभा क्षेत्र जालौर में संचालित समस्त राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने एवं ड्राप-आउट रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

165. विधान सभा क्षेत्र जालौर में संचालित समस्त राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त कक्षा-कक्षों के निर्माण तथा क्षतिग्रस्त एवं जीर्ण-शीर्ण भवनों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

166. विधान सभा क्षेत्र जालौर में संचालित समस्त राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के समस्त रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

167. विधान सभा क्षेत्र जालौर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को जनता की मांग के अनुरूप क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा):

168. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी दूर किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

169. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के प्राथमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

170. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के प्राथमिक विद्यालयों में शौचालयों की व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिए।

171. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के प्राथमिक विद्यालयों में पोषाहार का वितरण किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली):

172. पाली जिले के अधिकांश प्राइमरी विद्यालयों में क्षतिग्रस्त कक्षा-कक्षों की मरम्मत हेतु राशि आबंटित किये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

173. पाली शहर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मंडिया एवं इन्द्रा कालोनी को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

174. पाली शहर की पूर्व में बन्द की गई राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढाकों की ढाणी (नया गांव), बजरंगवाड़ी एवं रूणेचा कालोनी को पुन: प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

175. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) के ग्राम कड़ीला (जोरावरपुरा) एवं शेरगढ़ (नीमोला) में नवीन प्राथमिक विद्यालय संचालित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

176. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के राजकीय विद्यालय भवनों की जीर्ण-शीर्ण दशा सुधारने के लिए नाकाफी प्रयासों के चलते विभागीय विफलता पर चर्चा के लिए।

177. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में खेल मैदान विकसित कराने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिए।

178. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) के जीर्ण-शीर्ण स्थिति के कारण भवन विहीन होकर खुले में विगत 3 वर्षों से अध्ययन करवा रहे राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिजावता, श्रीपुरा आदि लगभग 10 विद्यालयों को भवन उपलब्ध कराने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिए।

179. गत 4 वर्षों में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में सेवारत तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण करने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिए।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

180. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

181. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के प्राथमिक विद्यालयों में भवन निर्माण एवं मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

182. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को समुचित सुविधाएं दिये जाने व रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

183. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर पदस्थापन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

184. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में अनार्थिक घोषित कर मर्ज किये गये विद्यालयों को पुन: शुरू कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

185. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के भवन विहीन एवं कक्षा-कक्षों की कमी वाले प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु नवीन कक्षा-कक्ष एवं भवन निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

186. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

187. राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुणेश की ढाणी (सांकड़) को वैकल्पिक स्थान पर यथावत संचालित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

188. विधान सभा क्षेत्र चूरू स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

189. विधान सभा क्षेत्र चूरू के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में विभिन्न संवर्ग के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

190. विधान सभा क्षेत्र चूरू में पंचायत स्तर पर नये राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

191. विधान सभा क्षेत्र चूरू में राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो विद्युतीकरण से वंचित हैं, में कनेक्शन किये जाने सहित चारदीवारी, मरम्मत व शौचालय निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

192. प्रदेश में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को डी-मर्ज कर प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

193. विधान सभा क्षेत्र सिरोही में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रांकरिया का भवन जर्जर होने से जानलेवा, घातक स्थिति में होने के बाद भी नया न बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

194. सिरोही जिले में मर्ज किये गये प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मानदंड में होने के बावजूद डी-मर्ज न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

195. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के झाडोलीवीर (शिवगंज) में नया राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

196. विगत सरकार में सिरोही जिले में बन्द किये गये प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कारण बड़ी संख्या में बच्चों के स्कूल छोड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

197. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भूतियावास, सिलदर (सिरोही) को डी-मर्ज कर पुन: प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

198. प्रदेश में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 के द्वारा शिक्षक छात्र अनुपात में अध्यापकों की उपलब्धता, खेल मैदान, पर्याप्त कक्षा-कक्ष, बालक-बालिकाओं के लिए पृथक्-पृथक् शौचालय, पुस्तकालय, पेयजल सुविधाएं तथा शारीरिक रूप से अक्षम बालक-बालिकाओं के लिए निर्बाध पहुंच आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रावधान वर्ष 2010 से लागू होने के 13 वर्षों बाद भी प्रदेश के प्रारंभिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

199. प्रदेश में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के कानून को लागू किये जाने के बावजूद प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा घुमन्तु एवं विमुक्त, सांसी, कंजर, रहवारी जाति के बालकों को प्रारंभिक शिक्षा से नहीं जोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

200. प्रदेश के प्रारंभिक शिक्षा विभाग में मिड-डे-मील योजना के तहत छात्र-छात्राओं को भोजन कराये जाने के बावजूद ड्रापआउट की समस्या के लगातार बने रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

201. प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अधिकांश प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालय किराये के भवनों में संचालित होने, जीर्ण-शीर्ण, जर्जर एवं असुरक्षित होने के कारण प्रारंभिक कक्षाओं के प्रवेशित बालक-बालिकाओं का आकर्षण विद्यालय की ओर न होने से तथा उनमें शिक्षा के प्रति उदासीन भावना विकसित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

202. सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाये जाने से शिक्षण की व्यवस्था गुणवत्तापूर्ण नहीं होने के कारण 5वीं से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को मातृभाषा का ज्ञान भी भली-भांति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

203. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में प्राथमिक विद्यालयों की मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

204. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के प्राथमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों की मरम्मत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

205. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

206. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के प्रारंभिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

207. राज्य में राजस्थान नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा नियम 2011 की प्रतिपूर्ति हेतु गैर राजकीय विद्यालयों में निर्धारित सीमा तक बालक-बालिकाओं के प्रवेश सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

208. विधान सभा क्षेत्र फलौदी के प्राथमिक विद्यालयों में सभी रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

209. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में नये राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

210. प्रदेश में राजकीय तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानान्तरण के लिए नई नीति बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

211. विधान सभा क्षेत्र आमेर के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शुद्ध पेयजल, विद्युत एवं शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

212. विधान सभा क्षेत्र आमेर के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जर्जर/क्षतिग्रस्त भवनों की शीघ्र मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

213. विधान सभा क्षेत्र आमेर के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को शीघ्र क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

214. पंचायत समिति आमेर एवं जालसू के प्राथमिक विद्यालयों/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

215. विधान सभा क्षेत्र आमेर के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के संस्था अनुपात में पर्याप्त कक्षा-कक्षों एवं शौचालयों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

216. अजमेर के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए रिक्त पदों पर शारीरिक शिक्षक लगाने और व्यवस्थित खेल मैदान तैयार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

217. प्रदेश के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के उत्तम स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें सप्ताह में 6 दिन पाउडर मिल्क की बजाय ताजा नेचुरल दूध वितरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

218. प्रदेश के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रतिदिन

प्रार्थनासभा के दौरान पुन: योगाभ्यास प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

219. प्रदेश में कम नामांकन के चलते बंद की गई प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के खाली पड़े भवनों का सद्उपयोग किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

220. प्रदेश के अंग्रेजी माध्यम महात्मा गांधी विद्यालयों में हिन्दी माध्यम स्कूलों के अध्यापक को साक्षात्कार के माध्यम से लेने के बजाय पृथक् भर्ती द्वारा अंग्रेजी माध्यम के ही शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

221. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय 8TGB (B) को क्रमोन्नत करवाये जाने की आवश्यश्कता पर चर्चा के लिए।

222. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय 4MLD (B) को क्रमोन्नत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

223. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय 11/12 LM को क्रमोन्नत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

224. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय 14 K(B) को पुन: इसी सत्र से प्रारम्भ करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

225. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय 9KWSM को क्रमोन्नत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):

226. झुन्झुनू जिले में अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त नियुक्ति तिथि के स्थान पर ए.सी.पी. का लाभ प्रशिक्षण प्राप्त करने की दिनांक से दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

227. प्रदेश में परिवीक्षाकाल पूर्ण करने वाले सभी तृतीय श्रेणी अध्यापकों का स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अनिल कुमार शर्मा (सरदारशहर):

228. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर स्थित विभिन्न राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समस्त रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

229. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के गांव नायक मौहल्ला घड़सीसर तथा मेघवाल मौहल्ला भोजूसर उपाधियान में नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

230. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के रामसर पड़िहारान, बास आगुणा, खेजड़ां दिखनादा, बणियासर तथा ढाणी महियान राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

231. प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षा नीति 2020 लागू करने में शिथिलता प्रदान किये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

232. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के प्राथमिक विद्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने के लिए।

233. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के प्राथमिक विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षा बाल वाटिका प्रारम्भ नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

234. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के प्राथमिक विद्यालय के भवनों की मरम्मत एवं नवीन कक्षा-कक्षों के निर्माण कार्य नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने के लिए।

235. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा हेतु।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी):

236. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में पूर्व में संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वर्तमान में बंद होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

237. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में प्राथमिक विद्यालयों में

निर्धारित मापदण्डों के आधार पर स्वीकृत पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

238. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के नियंत्रण के स्कूलों में समाज में व्याप्त अतिघृणित छुआछूत की दुष्प्रवृत्ति के निदान के प्रयासों को पाठ्यपुस्तकों में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

239. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा के प्राथमिक स्कूलों में खेल मैदान/स्टेडियम/ओपन जिम की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

240. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा जिला भीलवाड़ा के प्राथमिक स्कूलों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति का समय पर भुगतान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

241. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-जिला भीलवाड़ा के प्राथमिक स्कूलों के जर्जर भवनों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर):

242. प्रदेश में बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रारम्भिक शिक्षा स्तर से ही योगाभ्यास एवं खेल गतिविधियों को अनिवार्यता से दैनिक कालांश व्यवस्था का अंग शुमार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

243. प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में पाठ्यक्रम वैदिक गणित को पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

244. प्रदेश में बालकों में जीवनादर्श निर्धारण हेतु समाज के विभिन्न अलग-अलग क्षेत्रों के सफलतम व्यक्तियों की वार्ताएं राजकीय प्राइमरी विद्यालयों में आयोजित कराने की योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

245. प्रदेश में प्री-प्राइमरी स्कूल केन्द्रों के रूप में आंगनबाड़ी केन्द्रों को क्षेत्रीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक राजकीय विद्यालयों का अंग बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज):

246. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज शाहबाद में सोनीपुरा टापरा में प्राथमिक स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):

247. प्रदेश के राजकीय प्रारम्भिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं (शौचालय, चारदीवारी) नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

248. प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में विद्युत एवं पेयजल के कनेक्शन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

249. प्रदेश के डार्क जोन में स्थित जिलों के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के तृतीय श्रेणी अध्यापकों के कई वर्षों से स्थानान्तरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज):

250. जयपुर जिले के महाराजा सवाई मानसिंह विद्यालय में RTE के तहत कक्षा एक के बच्चों का प्रवेश निरस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

251. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

252. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के प्राइमरी विद्यालय भवनों की जर्जर स्थिति से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

253. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न प्राइमरी विद्यालयों में कक्षा कक्षों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

254. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

255. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के विभिन्न प्राइमरी विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में कक्षा कक्ष नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

256. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बजरंग कालोनी (ब्लाक किशनगढ़) एवं डोहरिया-झीरोता को डी-मर्ज करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

257. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय भारला (ग्राम पंचायत देवपुरी), पचीपला (ग्राम पंचायत कालानाड़ा), भीलों की

ढाणी (ग्राम पंचायत गोठियाना), मालियों की ढाणी (ग्राम पंचायत कुचील), रामगढ़ (ग्राम पंचायत मनोहरपुरा) को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

258. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के प्राइमरी विद्यालयों के भवन जर्जर होने से जनहानि की सम्भावना पर चर्चा के लिए।

259. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के प्राइमरी विद्यालयों में कक्षा कक्षों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

परिशिष्ट-03

मांग संख्या 21-माध्यमिक शिक्षा पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 21-माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/ करेंगी कि:-

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई):

1. विधान सभा क्षेत्र नदबई के कल्याणपुर में पंचायत स्तर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।
2. विधान सभा क्षेत्र नदबई में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खुडासा में विज्ञान संकाय के स्थान पर कला संकाय खुलवाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।
3. विधान सभा क्षेत्र नदबई में CBEO के नवीन कार्यालय भवन के निर्माण हेतु राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
4. विधान सभा क्षेत्र नदबई में CBEO उच्चैन हेतु वाहन व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
5. विधान सभा क्षेत्र नदबई के उच्चैन में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर)

6. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में माध्यमिक विद्यालयों में खाली पदों को भरने एवं इनमें खेल मैदान बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

7. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में उच्च प्राथमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने, क्रमोन्नत विद्यालयों में भवन निर्माण एवं विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पदमाराम (चौहटन):

8. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में

व्याख्याताओं, वरिष्ठ अध्यापकों एवं तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की नियुक्ति करने, इनमें भवन निर्माण हेतु आवश्यक राशि देने की स्वीकृति के साथ ही महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय के लिए भी भवन निर्माण की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री वाजिब अली (नगर):

9. विधान सभा क्षेत्र नगर के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नये संकाय खोलने, उर्दू विषय के मांग अनुसार नये पद सृजन करने एवं रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री लाखन सिंह (करौली):

10. विधान सभा क्षेत्र करौली के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नये संकाय यथा विज्ञान, कृषि आदि खोलने एवं रिक्त पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

11. विधान सभा क्षेत्र दूदू में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या के अनुसार नये कक्षा-कक्षों का निर्माण करने एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

12. विधान सभा क्षेत्र दूदू में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत पदों के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति करने एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय की एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कृषि संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन):

13 विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन (पाली) में एवं अऊवा के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम प्रारम्भ करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

14. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन (पाली) के गुड़ा भोपा, टोकरला ग्राम पंचायत केरली (ब्लाक रानी) एवं सोमेश्वर ग्राम पंचायत भादरलाऊ को अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

15. विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों की संख्या के अनुसार नये कक्षा-कक्षों के निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अविनाश (जैतारण):

16. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के ग्राम बर अथवा जैतारण में कन्या छात्रावास की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

17. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के सभी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में टीन शैड, पानी टांका एवं खेल मैदान की चारदीवारी बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

18. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों एवं खेल मैदानों की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

19. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के लाम्बिया, रास, राबड़ियावास सहित अन्य उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय की स्वीकृति देने तथा ठाकरवास, पीलपाया, दयालपुरा, केसरपुरी सहित अन्य मिडिल स्कूल को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

20. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में सभी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने, चतुर्थ श्रेणी पदों की भर्ती करने, सभी विद्यालयों में पेयजल के लिए मीठे पानी व RO की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

21. विधान सभा क्षेत्र चितौड़गढ़ में संचालित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के जीर्ण-शीर्ण भवनों का दुरुस्तीकरण कर नवीन कक्षा-कक्ष निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

22. प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे विद्यार्थी मनोबल के अभाव में कुंठित होकर आत्महत्या व आत्मघाती प्रयास न करें, इस हेतु सभी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विशेष कार्ययोजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

23. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा (हनुमानगढ़) के नूरपरा, लबाणा, 17PBN (अहमदपुरा), लढाणाचक सरामसर, 10MOD, मलकोका, 3MOD, 16DWD (रावतसर), प्रेमनगर (रावतसर), कुम्हारावाली ढाणी (रावतसर) आदि उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक में क्रमोन्नत करने एवं विद्यालयों में आवश्यकतानुसार शिक्षकों की नियुक्ति करने व विद्यालयों में कक्षा-कक्षों का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

24. प्रदेश के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सौर ऊर्जा की व्यवस्था एवं शौचालयों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

25. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को दो पारी में संचालित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

26. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के राजकीय बाड़ी उच्च माध्यमिक विद्यालय में कृषि विज्ञान एवं इतिहास विषय संकाय की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. बाड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी साहित्य एवं गृह विज्ञान संकाय स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल):

28. विधान सभा क्षेत्र घाटोल (बांसवाड़ा) के समस्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त प्रधानाचार्यों एवं व्याख्याताओं के पदों पर नियुक्ति करने, इनमें आवश्यकतानुसार नवीन भवनों का निर्माण किये जाने तथा खेल मैदानों के लिए जमीन आबंटन किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

29. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

30. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के उच्च माध्यमिक विद्यालय सिणरे एवं भलरो का वाड़ा में नये कक्षा-कक्षों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

31. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32. प्रदेश के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्य सम्पादन हेतु पदस्थापित विद्यालय सहायकों के लिए कार्य विभाजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

33. प्रदेश के उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं यथा बिजली, पानी एवं सड़क, भवन, नवीन उपकरणों आदि की उपलब्धता की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़):

34. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों की मरम्मत करने के साथ ही अतिरिक्त कक्षा-कक्षों व शौचालयों के निर्माण की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

35. विधान सभा क्षेत्र नोखा के समस्त माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

36. विधान सभा क्षेत्र नोखा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमश: कुम्भासर, खारा, मेघवालों की ढाणी बंधड़ा, बांगुड़ों की ढाणी सांईसर, झिंझोलाई नाडी मैनसर आदि को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

37. विधान सभा क्षेत्र नोखा के माध्यमिक विद्यालयों में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, चारदीवारी, मरम्मत कार्य करवाने व समस्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों में डिजिटल इन्टरेक्टिव बोर्ड तथा स्मार्ट टीवी लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. विधान सभा क्षेत्र नोखा के ब्लाक मुख्यालय पांचू स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान व वाणिज्य संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

39. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के गांव भोजपुर सहित अन्य गांवों में माध्यमिक स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर):

40 प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में उर्दू को ऐच्छिक विषय के रूप में शामिल करने व इस विषय के शिक्षकों की भर्ती करने के साथ ही उर्दू माध्यम के नये विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा):

41. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के कोटड़ा पंचायत समिति में ग्राम पंचायत बाकावास में माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

42. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की नई बनी ग्राम पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43. प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को शिक्षण व्यवस्था की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

45. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत पदों के अनुरूप शिक्षक पदस्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

46. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में बिजली, पानी, शौचालयों व कक्षा-कक्षों में CCTV कैमरों की व्यवस्था के साथ-साथ विषय अध्यापकों व प्रधानाध्यापकों को समय पर उपस्थित होने के लिए पाबंद किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

47. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कार्मिक, तृतीय श्रेणी अध्यापक, विषय अध्यापकों के साथ ही शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने व खेल मैदान हेतु जमीन आबंटित करने व इनको अतिक्रमण से मुक्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

48. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय

ग्राम गडबोदीया, तलोदा, आगरिया एवं नाथुण को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

49. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में माध्यमिक शिक्षा विभाग के समस्त विद्यालयों में लाइब्रेरी की स्थापना कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

50. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के माध्यमिक विद्यालयों में विषय अध्यापकों व व्याख्याताओं के समस्त रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबु लाल (झाड़ोल):

51. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों व कक्षा-कक्षों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर):

52. प्रदेश के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के बैठने के लिए आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध कराने एवं आफिस में आवश्यक सुविधाओं की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

53. प्रदेश के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को आगे के कैरियर के संबंध में मार्गदर्शन हेतु कैरियर सेमिनार आयोजित कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

54. प्रदेश के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी विद्यार्थियों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

55. प्रदेश के सम्पूर्ण माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

56. प्रदेश के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का सर्वे करवाया जाकर पुराने जर्जर भवनों की मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर):

57. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय

सूरपुरा को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

58. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बागावास अहीरान, बाड़ी जोड़ी, पालड़ी राजनोता, नाथावाला, जयसिंहपुरा, भामोद में विज्ञान संकाय प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

59. विधान सभा क्षेत्र कपासन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों, प्रयोगशाला भवन (मय उपकरण) तथा चारदीवारी निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

60. प्रदेश के विद्यालयों में विद्यार्थियों तथा शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61. विधान सभा क्षेत्र कपासन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रिंसिपल, व्याख्याता, II ग्रेड अध्यापक, III ग्रेड अध्यापक, प्रयोगशाला सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

62. प्रदेश के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कैमरे लगाने तथा प्रोजेक्टर के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

63. प्रदेश के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए पृथक् से कोच नियुक्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी):

64. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में विभिन्न राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं कला संकाय स्वीकृत करने एवं कक्षा-कक्षों के निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर):

65. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नागोनियान को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

66. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित विद्यालयों में नियम विरुद्ध शिक्षकों के प्रतिनियुक्तियों के आदेशों को निरस्त कर शिक्षकों को पुन: अपने नियुक्ति स्थान पर भेजे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

67. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में छात्रों की संख्या के आधार पर भवनों का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

68. प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा नये माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

69. प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित पुराने भवनों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70. प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):

71. प्रदेश के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल की पदोन्नति करने के संबंध में चर्चा के लिए।

72. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केशवपुरा कोटा में जर्जर भवन की मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी):

73. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय चिकारडा को माध्यमिक में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

74. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

75. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय मंगलवाड़ को माध्यमिक में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

76. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निकुम में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगसी राम (रेवदर):

77. विधान सभा क्षेत्र रेवदर की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्थानान्तरण से बड़ी संख्या में हुए रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

78. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के राजकीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूलों में भवन, कक्षा-कक्ष, फर्नीचर, लाइब्रेरी, खेलकूद सामग्री की कमी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा):

79. विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा के सभी सैकंडरी एवं सीनियर सैकंडरी विद्यालयों में छात्रों की संख्या के अनुपात में कक्षा-कक्षों की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

80. विधान सभा क्षेत्र मावली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़गांव (मावली) में वाणिज्य व विज्ञान संकाय खोले जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

81. विधान सभा क्षेत्र मावली के राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय चुण्डावत खेड़ी व पालवास को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

82. विधान सभा क्षेत्र मावली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोपड़ा में नवीन कक्षा-कक्षों का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

83. विधान सभा क्षेत्र मावली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसलिया, आमली, तुलसीदासजी की सराय, डबोक (अंग्रेजी माध्यम) में कक्षा-कक्षों का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

84. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

85. विधान सभा क्षेत्र भादरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छानी बड़ी के खेल मैदान की चारदीवारी के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

86. विधान सभा क्षेत्र भादरा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय उतरादाबास के खेल मैदान की चारदीवारी के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

87. विधान सभा क्षेत्र भादरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंजी में कृषि संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

88. विधान सभा क्षेत्र भादरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मलसीसर में लैब का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

89. विधान सभा क्षेत्र भादरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डोबी को माध्यमिक में क्रमोन्नत करने एवं इसे सह शिक्षा घोषित किया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

90. प्रदेश के सभी माध्यमिक स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय व कक्षा-कक्ष बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के सभी स्कूलों में जर्जर भवनों की मरम्मत करवाने, बाउंड्री वाल बनवाने एवं पानी की व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

92. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय करोली एवं जाम्बूवेला को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

93. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सभी संवर्ग के कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

94. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण व जर्जर भवनों की मरम्मत करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

95. प्रदेश के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के सभी विद्यालयों में प्रैक्टिकल विषयों की अध्यापन सामग्री उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

96. प्रदेश के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

97. प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यालयों में खेल मैदानों का आबंटन कर खेल सामग्री उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती मंजु देवी (जायल):

98. विधान सभा क्षेत्र जायल के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने एवं अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण व अन्य आवश्यक सुविधाओं की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर):

99. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने, स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल खोलने, सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आई.सी.टी. लैब शीघ्र शुरू करवाने, स्काउट गाइड कार्यालय स्वीकृत करवाने के साथ ही बोर्ड परीक्षा हेतु नये केन्द्र खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमित चाचाण (नोहर):

100. विधान सभा क्षेत्र नोहर के विद्यालयों में कक्षा-कक्ष, चारदीवारी एवं खेल मैदान के निर्माण की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

101. विधान सभा क्षेत्र नोहर के विद्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

102. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान, कला, वाणिज्य एवं कृषि संकाय खोलने, अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय भवनों के निर्माण की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह (आहोर):

103. विधान सभा क्षेत्र आहोर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय

रोड़ला, गुड़ा बालोतान, भवरानी, चादराई, हरजी शंखवाली में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

104. विधान सभा क्षेत्र आहोर के नवीन क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालय जोड़ा, छिपरवाड़ा, सांड़न, पादरली एवं बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नोरवा, कुआरडा में कक्षा-कक्षों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

105. विधान सभा क्षेत्र आहोर के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में व्याख्याता, प्रधानाचार्य, वरिष्ठ अध्यापक के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

106. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आवश्यकतानुसार विज्ञान, गणित, कलावर्ग, वाणिज्य, कृषि संकाय एवं जीव विज्ञान विषय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

107. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में केरला, पिचावा, राजपुरा, नवागुडा, सांगवा, धनापुरा, पेणावा, ऐन्दलावास, सापुनी, कानपुरा, बाला, वेनपुरा, पडासला कलां, बालिका खिवान्दी, बालिका बांकली, सुमेरपुर (वि.नं. 1) सुमेरपुर (संजयनगर) में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

108. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में सभी राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, उपप्रधानाचार्य, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक लेवल I, II व शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

109. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आवश्यकतानुसार कक्षा-कक्षों, विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष, आर्ट & क्राफ्ट कक्ष, वाचनालय कक्ष, शौचालय, पानी का टांका इत्यादि स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

110. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में चारदीवारी से वंचित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों व खेल मैदानों की चारदीवारी निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

111. प्रदेश में विभिन्न माध्यम एवं श्रेणी के विद्यालयों में शारीरिक एवं

नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने एवं उनके प्रशिक्षक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

112. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न विषयाध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

113. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

114. प्रदेश में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न श्रेणी के विषयाध्यापकों के रिक्त पदों से विद्यार्थियों को पढ़ाई में हो रहे नुकसान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

115. प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम स्कूल पर्याप्त संख्या में खोलने एवं इन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से प्रशिक्षित एवं दक्ष अध्यापकों के पदस्थापन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीराराम (बिलाड़ा):

116. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन):

117. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में विद्यालय भवनों की जर्जर स्थिति होने के कारण इनकी मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

118. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रिंसिपल, व्याख्याता, II ग्रेड अध्यापक, III ग्रेड अध्यापक, प्रयोगशाला सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

119. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के समस्त राजकीय माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों, शौचालयों व बाउन्ड्रीवाल, खेल मैदान का निर्माण तथा पानी की टपकती छतों की मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

120. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के समस्त राजकीय माध्यमिक विद्यालय,

उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कैमरे लगाने तथा प्रोजेक्टर के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

121. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के समस्त राजकीय माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कोच लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

122. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों तथा शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

123. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीलवा पचैला का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी सैगा भाई रोत एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झोथरी पाल का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी शिवरामजी रोत के नाम से करने के संबंध में चर्चा के लिए।

124. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पूनावाड़ा, उदडिया चिखली, चाडोली सीमलवाड़ा, खरवेण्डा, सुराता, सरथूना, नानाभाई खाट एवं रास्तापाल में अतिरिक्त विषय संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

125. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में समसा से आवश्यकता अनुसार भवन एवं शौचालयों के निर्माण की स्वीकृति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

126. प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पदों के कारण बिगड़ती शिक्षण व्यवस्था को सुधारने के लिए अनुसूचित क्षेत्र से गैर-अनुसूचित क्षेत्र में स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद):

127. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कानाखेडी पंचायत समिति श्रीनगर के खेल मैदान को स्टेडियम के रूप

में विकसित कराये जाने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

128. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तिहारी में 5 नवीन कक्षा-कक्षों के निर्माण कराये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

129. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देराठूं में 5 नये कक्षा-कक्षों के निर्माण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

130. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शिवपुरा पंचायत समिति पीसांगन को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़):

131. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन, आवश्यकतानुसार अध्यापक नहीं होने एवं अन्य सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

132. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गागोरिफे की ढ़ाणी, जाटावाली रावों की ढाणी, सीगोद कलां, नागल गोविन्द कानपुरा, डेहरा, यकरडा, भूतेडा, छोटा गुडा आदि में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

133. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्यानुसार अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

134. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खेल मैदान हेतु भूमि के आबंटन की आवश्यक्ता पर चर्चा के लिए।

135. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दोपगुण में कला एवं आलीसर, बोसा व धोबलाई में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

136. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रूपा राम (मकराना):

137. विधान सभा क्षेत्र मकराना के समस्त माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं जैसे दरी, फर्नीचर, टाटपट्टियां सहित अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

138. विधान सभा क्षेत्र मकराना के समस्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

139. विधान सभा क्षेत्र ओसियां के खारी, बासनी, डावरा, जाखड़ों की ढाणी, एकल खोरी सहित सभी स्थानों के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री महेन्द्र बिश्नोई (लूणी):

140. विधान सभा क्षेत्र लूणी के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अमीन खां (शिव):

141. विधान सभा क्षेत्र शिव (बाड़मेर) की पंचायत समिति रामसर स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय सजनकापार, गागरीया, बुरिया, चाडवा तखताबाद, सियाई, कन्टलकी पार में अधिकांश अध्यापकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

142. विधान सभा क्षेत्र शिव (बाड़मेर) की पंचायत समिति गडरारोड़ की उच्च माध्यमिक विद्यालय रांणासर, देतांनी, खांनीमांनी बान्डासर, खडीन, लालासर, सौलंकिया आदि में अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

143. विधान सभा क्षेत्र शिव के पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में स्थित विद्यालयों में अधिकांश अध्यापकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

144. सीमावर्ती जिला बाड़मेर में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 80 से अधिक अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़):

145. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के विद्यालयों में रमसा-समसा योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों को समय पर पूर्ण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

146. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के गांव जेगणिया बीकान स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों की खराब स्थिति पर चर्चा के लिए।

147. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-कक्षों के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

148. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त चल रहे विभिन्न पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

149. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में खोले गये अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाने वाले शिक्षकों के अभाव के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा हेतु।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद):

150. माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्टाफ की उपस्थिति हेतु आने व जाने के समय की मॉनिटरिंग बायो मेट्रिक व्यवस्था से करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना):

151. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के राजकीय माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में साइन्स, बायोलोजी एवं कृषि संकाय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

152. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के राजकीय माध्यमिक विद्यालय बुधवाड़ा को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

153. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रीछड़ी, गुराड़ी, रानीपुरा, पाटलिया लोढ़ान, मोग्या बेह भीलान को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

154. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ (बीकानेर) के अभयसिंहपुरा, मणकरासर, नारसीसर, झझेऊ, लालासर (सतासर) सिंधू की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने एवं ग्राम बाधनूं व बापेऊ में 10वीं तथा 12वीं बोर्ड परीक्षा केन्द्र स्वीकृत करने के साथ ही दुलचासर, इन्दिरा कालोनी टेऊ, साधासर में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरगढ़):

155. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में रिक्त पदों को भरने एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू):

156. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गजनपुरीया को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

157. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल अटरू में प्रिंसिपल के द्वारा की गई अनियमितता व स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार की जांच करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली):

158. विधान सभा क्षेत्र बाली (पाली) के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय बेड़ा नारलाई व घाणेराव को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

159. विधान सभा क्षेत्र बाली (पाली) के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याता, प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

160. विधान सभा क्षेत्र बाली (पाली) के जादरी, जुना बेड़ा, भारला, मालदर की ढाणी, लालपुरा बोरडी एवं राजपुरा में नये माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

161. विधान सभा क्षेत्र बाली (पाली) के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चारदीवारी व नये कक्षा-कक्षों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

162. विधान सभा क्षेत्र बाली (पाली) के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेड़ा व भाटुन्द, सादड़ी, नारलाई में विज्ञान संकाय प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द):

163. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द-हुरड़ा के कोरणास, उदलपुरा, गेनपुरा, गायलों का खेड़ा, भाटीखेड़ा के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालूराम (डग):

164. विधान सभा क्षेत्र डग (झालावाड़) के माध्यमिक विद्यालयों में खेल मैदान का निर्माण, मिनी खेल स्टेडियम एवं विद्यालयों की चारदीवारी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

165. विधान सभा क्षेत्र डग के माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

166. विधान सभा क्षेत्र डग (झालावाड़) के समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-कक्षों के निर्माण हेतु समसा द्वारा आवश्यक स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर):

167. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 10. सरकारी में कक्षा कक्षों, चारदीवारी एवं खेल मैदानों के निर्माण के साथ ही अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

168. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री विजयनगर में खेल मैदान एवं जीर्ण-शीर्ण हुए कमरों को डिस्मेन्टल कर नये कक्षा-कक्षों का निर्माण करवाये जाने के साथ ही सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

169. विधान सभा क्षेत्र जालौर में संचालित राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों, व्याख्याताओं एवं प्राचार्यों के समस्त रिक्त पदों को वर्तमान शैक्षणिक सत्र में ही भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

170. विधान सभा क्षेत्र जालौर में संचालित समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में कक्षा-कक्षों, प्रयोगशाला भवनों, पुस्तकालय कक्षों एवं अन्य आवश्यक कक्षों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

171. विधान सभा क्षेत्र जालौर में संचालित समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के क्षतिग्रस्त एवं जर्जर कक्षा-कक्षों एवं भवनों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा):

172. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा (कोटा) में स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नये संकाय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

173. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति, फर्नीचर की आपूर्ति एवं खेल मैदान का निर्माण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली):

174. विधान सभा क्षेत्र पाली के राजकीय माध्यमिक विद्यालय सांवलाता खुर्द तहसील रोहट में दो कक्षा-कक्षों का निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

175. कोटा जिले के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) सुल्तानपुर एवं इटावा को आबंटित भूमि पर आवश्यक भवन निर्माण हेतु राशि उपलब्ध करवाने में विभागीय विफलता पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

176. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के सुल्तानपुर में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय को आबंटित भूमि पर भवन निर्माण पूर्ण करवाने में विभागीय विफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

177. प्रदेश में गत चार वर्षों में माध्यमिक शिक्षा विभाग में सेवारत तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानान्तरण करने में विभागीय विफलता पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

178. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खातोली, गणेशगंज, बड़ोद आदि में जीव विज्ञान विषय संचालित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

179. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के लिए उपयुक्त मानदण्डों के खेल मैदान विकसित करवाने में विभागीय उदासीनता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

180. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

181. विधान सभा क्षेत्र देवली उनियारा में विद्यालयों के भवन एवं कक्षा-कक्षों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

182. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के राजकीय विद्यालयों के जर्जर भवनों के निर्माण व रमसा के तहत कमरे बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

183. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के बंद विद्यालयों को पुन: शुरू करने की आवश्यकता के संबंध में।

184. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के राजकीय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने व बिजली कनेक्शन के संबंध में चर्चा के लिए।

185. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के राजकीय विद्यालयों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जाने की आवश्यकता के संबंध में।

186. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के राजकीय विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया):

187. विधान सभा क्षेत्र संगरिया के सभी स्कूलों में भवन व टायलेट बनाने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति तथा क्षेत्र के महात्मा गांधी स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

188. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खेल मैदान विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

189. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वणधर, सांकड़ एवं बडगांव में कृषि विज्ञान संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

190. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर पदस्थापन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

191. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में कक्षा-कक्षों की कमी वाले माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन कक्षा-कक्ष निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

192. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में संचालित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

193. विधान सभा क्षेत्र चूरू स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न सवंर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने की अवश्यकता पर चर्चा के लिए।

194. विधान सभा क्षेत्र चूरू के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में डिजिटल इन्टरेक्टिव बोर्ड व स्मार्ट TV लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

195. विधान सभा क्षेत्र चूरू के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त शौचालयों एवं कक्षा-कक्षों के निर्माण सहित चारदीवारी की मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

196. विधान सभा क्षेत्र चूरू स्थित समस्त राजकीय विद्यालयों में खेल मैदान को विकसित करने व खेलों को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

197. विधान सभा क्षेत्र चूरू के विद्यालयों को आबंटित खेल मैदानों की भूमि पर अतिक्रमण होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

198. सिरोही जिले में जिला स्तरीय अंडर 17 एवं 19 छात्र-छात्रा खेलकूद प्रतियोगिताओं में कई विद्यालयों द्वारा अपनी टीम नहीं भेजने के संबंध में चर्चा के लिए।

199. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सपली (शिवगंज) को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

200. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मंडवाडा (सिरोही) को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

201. सिरोही जिले में पदस्थापित शिक्षकों से शिक्षण कार्य न करवाकर एवं राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना कर अन्यत्र प्रतिनियुक्ति करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

202. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में स्थित रजाकोठी उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलाबबाड़ी में स्ववित पोषण योजना के तहत चलाये जा रहे विषय को सरकार द्वारा पूर्णकालीन नियमित विषयों के रूप में राज्य वित्त पोषण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

203. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माखुपुरा एवं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलाबबाड़ी में कृषि संकाय और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कल्याणीपुरा एवं भगवानगंज व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहाड़गंज में विज्ञान संकाय और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगंज एवं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर में कला संकाय में चित्रकला एवं संगीतकला विषयों को जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

204. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में संचालित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषय अध्यापकों के रिक्त पदों पर अध्यापकों की शीघ्र नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

205. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 11वीं व 12वीं की पुस्तकों में आजादी के इतिहास एवं आजादी के बाद के 50 वर्षों का वर्णन ठीक प्रकार से नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

206. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण के विद्यालयों को मांग अनुसार महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

207. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में

बालिकाओं हेतु पृथक् से शौचालय निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

208. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के विद्यालयों में नवीन कक्षा-कक्षों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

209. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला का निर्माण व इनमें आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

210. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों को दुरुस्त कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

211. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खेल मैदानों (मय उपकरण) के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली):

212. पाली जिले के उपखण्ड रोहट की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खुटाणी, गाजनगढ़ एवं डूंगरपुर को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

213. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

214. विधान सभा क्षेत्र फलौदी के बाप ब्लाक में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय के भवन निर्माण में उपयोग में ली गई घटिया सामग्री में कथित भ्रष्टाचार की तत्काल उच्च स्तरीय जांच कराने व दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी):

215. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में स्थित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ग्रेड-I, ग्रेड-II के अध्यापकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

216. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम के अध्यापकों को नियुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

217. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में सभी नवक्रमोन्नत विद्यालयों हेतु नई बिल्डिंग नहीं बनाये जाने से विद्यार्थियों को आधारभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

218. विधान सभा क्षेत्र आमेर में नवीन महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

219. विधान सभा क्षेत्र आमेर में संचालित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खेल मैदान विकसित किये जाने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

220. विधान सभा क्षेत्र आमेर के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषय अध्यापकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

221. विधान सभा क्षेत्र आमेर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

222. विधान सभा क्षेत्र आमेर के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों के संख्या अनुपात में कक्षा-कक्षों के निर्माण, प्रयोगशाला एवं अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

223. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हाथीखेड़ा, अजमेर सहित प्रदेशभर में नव-क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनिवार्य विषय (हिन्दी-अंग्रेजी) के व्याख्याता पद स्वीकृत करने एवं उक्त को तत्काल भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

224. अजमेर सहित प्रदेश में संचालित स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में पहली से 5वीं तक की भी कक्षाएं संचालित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

225. अजमेर सहित प्रदेश के समस्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पड़े शैक्षणिक व अशैक्षणिक पदों को तत्काल भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

226. शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर माध्यमिक सैटअप में विद्यार्थियों की संख्यानुसार शैक्षणिक पदों का निर्धारण (स्टाफिंग पैटर्न) करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

227. प्रदेश में संचालित स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को भी गणवेश का कपड़ा नि:शुल्क दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

228. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खेल मैदान बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

229. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को आवश्यक भौतिक सुविधायें उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

230. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 3ND में कला वर्ग खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

231. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 8PSD (B) रावलामण्डी में विज्ञान संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

232. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामसिंहपुर में विज्ञान संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अनिल कुमार शर्मा (सरदारशहर):

233. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के विभिन्न राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी संवर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

234. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों उड़सर लोडेरा, पूलासर, मेलूसर बीकान में कृषि संकाय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

235. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों भादासर दिखनादा, राणासर, जैतासर, रामसीसर भेड़वालिया, खेजड़ां दिखनादा, पाबूसर, मेलूसर में विज्ञान विषय स्वीकृत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

236. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों श्रीमती फातिमा खोखर वार्ड 39, टांटिया, रामनगर बास नं. 6, ग्राम

छोटड़िया, हामूसर, राजासर चोर्डिया तथा चम्पावाली को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती दीप्ति किरण मोहश्वरी (राजसमन्द):

237. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का पदस्थापन किये जाने एवं रिक्त पदों पर भर्ती करने के संबंध में चर्चा के लिए।

238. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

239. प्रदेश में विद्यालयों से संबंधित शालादर्पण पर प्रविष्ट करने के उपरान्त भी विद्यालय प्रमुखों से उन्हीं सूचनाओं को सामाजिक मीडिया एवं भौतिक रूप से पुन: मांगने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

240. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

241. प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में गार्गी मंच का गठन नहीं होने से एवं उनमें पर्याप्त बजट आबंटन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा):

242. विधान सभा क्षेत्र महवा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़ हिम्मतसिंह, गहनौली, तालचिड़ी, समलेटी एवं खौंचपुरी में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

243. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा जिला भीलवाड़ा के माध्यमिक स्कूलों में खेलकूद, पेयजल, शौचालय आदि आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

244. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा जिला भीलवाड़ा के माध्यमिक स्कूलों में समसा के तहत विकास कार्य कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

245. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा जिला भीलवाड़ा के माध्यमिक स्कूलों में समाज में व्याप्त अतिघृणित छुआछूत की दुष्प्रवृत्ति के निदान के प्रयासों को पाठ के रूप में पाठ्यपुस्तकों में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

246. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा जिला भीलवाड़ा के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति के विद्यार्थियों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति समय पर उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

247. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा जिला भीलवाड़ा के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शुद्ध पेयजल, शौचालय एवं आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर):

248. प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत व्याकरण पाठ्यक्रम में श्रीमती पुष्पा दीक्षित के पौष्पी प्रक्रिया आधारित पाणिनीय अष्टाध्यायी क्रमानुसारी प्रक्रिया का समावेश करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

249. प्रदेश के बालकों में बढ़ रही आत्महनन की प्रवृत्तियों को रोकने के लिए प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धान्तों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

250. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कालीबेरी और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालीबेरी के खेल मैदान को खेल स्टेडियम के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

251. जोधपुर में रियासतकालीन हेरिटेज भवनों में संचालित राजकीय विद्यालयों में भवनों के जीर्णोद्धार और संरक्षण हेतु विशेष बजट प्रावधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज):

252. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज शाहबाद में घटी में बालिका माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

253. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज शाहबाद में परानियां में मॉडल गर्ल्स स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):

254. जयपुर शहर के राजकीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की संख्या के अनुरूप कक्षा-कक्ष, प्रयोगशालायें एवं अन्य आधारभूत सुविधाएं

उपलब्ध नहीं होने से हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

255. प्रदेश के विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम किये जाने से वहां अंग्रेजी माध्यम के अध्यापक नहीं होने के कारण छात्रों को अध्ययन में हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

256. प्रदेश के निजी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं से अधिक शुल्क एवं मनमानी फीस वसूल किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

257. प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त अध्यापकों के पद शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

258. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नये संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

259. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवनों की जर्जर स्थिति से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

260. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-कक्षों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

261. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

262. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

263. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के नव-क्रमोन्नत तथा पुराने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-कक्षों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

264. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नये संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

265. बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र के नवक्रमोन्नत राजकीय उच्च माध्यमिक

विद्यालयों में पर्याप्त स्टाफ के पदस्थापन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

266. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के नव-क्रमोन्नत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-कक्षों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

267. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के विद्यालयों के भवन जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

268. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खण्डाच (ग्राम पंचायत डीडवाडा) तथा झाड़ोल (ग्राम पंचायत मण्डावरिया) को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

परिशिष्ट-04

मांग संख्या 22-उच्च शिक्षा पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 22-उच्च शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगे कि:-

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई):

1. विधान सभा क्षेत्र नदबई की ग्राम पंचायत खानुआ में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
2. विधान सभा क्षेत्र नदबई के राजकीय महाविद्यालय नदबई व उच्चैन को स्नातक से स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

3. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर की ग्राम पंचायत चूनावढ़ में महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर):

4. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

5. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के विशाला में महाविद्यालय खोलने एवं कन्या महाविद्यालय में कला संकाय प्रारम्भ करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पदमाराम (चौहटन):

6. विधान सभा क्षेत्र चौहटन के महाविद्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने एवं बालिका महाविद्यालय खोलने, भवन निर्माण करने, शौचालय बनाने तथा पीने के पानी की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संदीप कुमार (तिजारा):

7. विधान सभा क्षेत्र तिजारा के भिवाड़ी महाविद्यालय में शिक्षकों के स्थायीकरण एवं नियुक्ति करने तथा टपूकड़ा में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री वाजिब अली (नगर):

8. विधान सभा क्षेत्र नगर के महाविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लाखन सिंह (करौली):

9. विधान सभा क्षेत्र करौली के शेरपुर व कोटड़ी में नये महाविद्यालय खोलने तथा करौली महाविद्यालय में रसायन, हिन्दी एवं उर्दू संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

10. विधान सभा क्षेत्र दूदू के दूदू व फागी महाविद्यालयों को क्रमोन्नत करने तथा राजकीय कन्या महाविद्यालय दूदू में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन):

11. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान व भूगोल विषय प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

12. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में स्थित महाविद्यालय को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अविनाश (जैतारण):

13. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जैतारण में नवीन विज्ञान संकाय खोलने एवं नवीन प्रयोगशालाएं निर्माण करने अतिरिक्त पांच कक्षा-कक्षों का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

14. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जैतारण के क्षतिग्रस्त भवन के पूर्व में किये गये मरम्मत का कार्य घटिया क्वालिटी से करने वाले संवेदक व अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा उक्त महाविद्यालय में भूगोल एवं वाणिज्य सहित अन्य नवीन संकाय की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

15. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में कन्या महाविद्यालय में B.Ed. कालेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

16. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के राजकीय पी.जी. महाविद्यालय जैतारण

में प्रधानाचार्य, प्रोफेसर सहित शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिकों के स्टाफ के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

17. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में राजकीय पी.जी. महाविद्यालय जैतारण में "खेलो इण्डिया योजना" के अन्तर्गत निर्मित इन्डोर स्टेडियम को स्थानीय महाविद्यालय को सुपुर्द किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

18. जिला चित्तौड़गढ़ में संचालित सभी राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य व सहायक प्राचार्य के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

19. प्रदेश में संचालित सभी राजकीय विश्वविद्यालयों के कार्मिकों का एकीकरण कर विशेष स्थानान्तरण नीति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

20. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के गोलूवाला, पीलीबंगा एवं डबली (पीलीबंगा) में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई):

21. विधान सभा क्षेत्र नदबई के तहसील मुख्यालय उच्चैन व नदबई में नवीन आधुनिक ई-लाइब्रेरी की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

22. विधान सभा क्षेत्र नदबई के उच्चैन में राजकीय महाविद्यालय में समाजशास्त्र व संस्कृत विषय आरम्भ करने तथा राजकीय महाविद्यालय, नदबई में भूगोल, राजनीति विज्ञान विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

23. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के सेपऊ राजकीय महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल):

24. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के महाविद्यालय में आचार्यों व लेक्चरर्स के रिक्त पदों पर भर्ती करने, भवन निर्माण करने तथा महाविद्यालयों के लिए जमीन आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

25. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में सिवाना कन्या महाविद्यालय के लिए आबंटित भूमि के दस्तावेजों एवं निर्माणाधीन भवन की गुणवत्ता की जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

26. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के महाविद्यालय में रिक्त पदों से प्रभावित होने वाले शिक्षण कार्य से उत्पन्न स्थिति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में सिवाना वीर नारायण परमार राजकीय महाविद्यालय का अतिरिक्त भवन निर्माण एवं चारदीवारी निर्माण को पूरा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

28. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के समदड़ी महाविद्यालय हेतु आबंटित भूमि मूल कस्बे से अधिक दूरी पर होने से छात्राओं के लिए असुविधा होने के कारण नजदीक खाली पड़ी भूमि को आबंटन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

29. विद्यालयों की भांति महाविद्यालयों में भी S.D.M.C. एवं S.M.C./ V.E.C. जैसी व्यवस्था करके अभिभावक एवं जनप्रतिनिधियों के साथ परिचर्चा करवाने की विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़):

30. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ की उप तहसील राजियासर एवं जैतसर में नवीन महाविद्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

31. विधान सभा क्षेत्र नोखा के पंचायत समिति मुख्यालय पांचू व ग्राम पंचायत मुख्यालय जसरासर में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32. विधान सभा क्षेत्र नोखा के मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय के स्नातक में भूगोल एवं गृह विज्ञान विषय खोलने तथा स्नातकोत्तर में एसएफएस में चल रहे रसायन शास्त्र, समाजशास्त्र को राजकीय विषय घोषित करने तथा राजनीति शास्त्र विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

33. विधान सभा क्षेत्र नोखा के राजकीय मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय व राजकीय कन्या महाविद्यालय में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34. विधान सभा क्षेत्र नोखा के राजकीय मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय में स्नातकोत्तर में एम.कॉम. संकाय शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

35. राजस्थान में उच्च शिक्षा विभाग से पुस्तकालय अध्यक्ष व पीटीआई के नब्बे प्रतिशत रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

36. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में गर्ल्स कालेज की भूमि आबंटन करने एवं भवन की स्वीकृति जारी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

37. महाविद्यालय में सहायक आचार्यों को कैरियर एडवान्स स्कीम (CAS) का लाभ लेने के लिए ओरियन्टेशन प्रोग्राम की अनुमति नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रूपाराम (जैसलमेर):

38. जयपुर स्थित जामडोली राजकीय महाविद्यालय का भवन बनाने एवं उसमें विभिन्न विषय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा):

39. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में गोगुन्दा राजकीय कालेज के परिसर की बाउन्ड्री वॉल हेतु राशि स्वीकृत की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

40. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के गोगुन्दा राजकीय कालेज में खेल मैदान हेतु राशि स्वीकृत की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के गोगुन्दा कालेज में विभिन्न विषयों के संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

42. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के गोगुन्दा कालेज में शैक्षिणिक स्टाफ की सीटें बढ़ाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के देवला खण्ड में कालेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़):

44. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के ग्राम सालासर में महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी):

45. विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में रामगंज मण्डी सैकण्डरी बालिका विद्यालयों को महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में विभागीय पहल किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

46. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के महाविद्यालय में विषय बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

47. जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड कोटड़ी में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

48. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में उपखण्ड स्तर पर कन्या महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबु लाल (झाडोल):

49. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के कोटड़ी व झाड़ोल महाविद्यालय को क्रमोन्नत करने व विज्ञान, अंग्रेजी एवं अर्थशास्त्र संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर):

50. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के राजकीय महाविद्यालय पावटा में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

51. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के बाबा नारायण दास महाराज राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा में स्नातकोत्तर स्तर पर अंग्रेजी और अर्थशास्त्र विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

52. बाबा भगवान दास महाराज राजकीय महाविद्यालय, चिमनपुरा के

पी.जी. में रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र, भौतिक शास्त्र और स्नातक स्तर पर भू-गर्भशास्त्र विषय प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

53. राजकीय महाविद्यालय, विराटनगर में विज्ञान संकाय के लिए पृथक् भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

54. विधान सभा क्षेत्र कपासन के श्री सांवलियाजी राजकीय महाविद्यालय मण्डफिया में अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास को बालक छात्रावास में परिवर्तित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

55. विधान सभा क्षेत्र कपासन के श्री सांवलियाजी राजकीय महाविद्यालय मण्डफिया में प्रिंसिपल, व्याख्याता एवं प्रयोगशाला सहायक के रिक्त पदों पर पदस्थापन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

56. विधान सभा क्षेत्र कपासन के सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महाविद्यालय में प्रयोगशाला भवन बनाने तथा फर्नीचर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

57. विधान सभा क्षेत्र कपासन के सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महाविद्यालय की भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों को हटाने तथा चारदीवारी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

58. विधान सभा क्षेत्र कपासन के सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महाविद्यालय में प्रिंसिपल, व्याख्याता एवं प्रयोगशाला सहायक के रिक्त पदों पर पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

59. विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर स्थित राजकीय विधि महाविद्यालय में छात्रों की संख्या के अनुसार कक्षा-कक्ष के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर):

60. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के शहीद मुकुट विधि राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पदों के भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के बकानी कस्बे में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

62. प्रदेश में विश्वविद्यालयों में आवश्यकता अनुसार छात्र अनुपात में कार्मिकों के पद स्वीकृत कर नियुक्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

63. उच्च शिक्षा विभाग के अधीन प्रदेश के विश्वविद्यालयों में जिसमें राज्य सरकार की पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू नहीं है, उनमें उक्त योजना शीघ्र लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

64. प्रदेश के विश्वविद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों, प्रोफेसरों एवं अन्य कर्मियों के द्वारा अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से छेड़छाड़ व दुष्कर्मों की घटनाओं की रोकथाम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

65. प्रदेश में नये विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

66. प्रदेश में विश्वविद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):

67. विधि कालेज कोटा में भवन विस्तार व अन्य मदों के लिए बजट आबंटित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

68. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में कला एवं विज्ञान महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी):

69. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के डूंगला में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के राजकीय महाविद्यालय बड़ी सादड़ी के भवन की चारदीवारी बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

71. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के राजकीय महाविद्यालय बड़ी सादड़ी में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगसी राम (रेवदर):

72. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के राजकीय महाविद्यालय आबूरोड, रेवदर में

शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

73. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के राजकीय महाविद्यालय आबूरोड व राजकीय महाविद्यालय रेवदर से वेतन आहरित करवाकर शैक्षिक स्टाफ के अन्यत्र प्रतिनियुक्ति प्रकरणों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा):

74. भीलवाड़ा शहर स्थित राजकीय छात्र एवं छात्रा महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के खाली पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

75. भीलवाड़ा शहर में स्थित S.M.M. कन्या महाविद्यालय में होमसाइंस एवं ड्राइंग पेंटिंग की स्नातकोत्तर कक्षाएं शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

76. विधान सभा क्षेत्र मावली के राजकीय महाविद्यालय में स्नातक में वाणिज्य व विज्ञान संकाय प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

77. राजकीय महाविद्यालय, मावली में कला स्नातकोत्तर (P.G.) में भूगोल, इतिहास, हिन्दी साहित्य एवं राजनीति विज्ञान विषय प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

78. विधान सभा क्षेत्र मावली के राजकीय महाविद्यालय, मावली में कला स्नातक वर्ग में समाज शास्त्र, चित्रकला व लोक प्रशासन विषय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

79. विधान सभा क्षेत्र मावली के राजकीय महाविद्यालय, मावली में स्नातक (कला) वर्ग की सीटें बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

80. विधान सभा क्षेत्र मावली के राजकीय महाविद्यालय, मावली में स्वच्छ पेयजल के लिए आर.ओ. सिस्टम लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

81. डूंगरपुर जिले के समस्त राजकीय महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

82. विधान सभा क्षेत्र भादरा के राजकीय महाविद्यालय भादरा को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

83. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के सभी महाविद्यालयों में रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

84. प्रतापगढ़ जिले में स्थित एक मात्र कन्या महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने व इसका नाम राणी देवली मीणा के नाम से नामकरण करने के संबंध में।

85. प्रतापगढ़ जिले के जिला मुख्यालय पर विधि महाविद्यालय खोलने तथा ग्राम पंचायत चुपना, दलोर, तहसील प्रतापगढ़ उपखण्ड मुख्यालय और मौखमपुरा में नवीन कन्या महाविद्यालय खोलने के संबंध में।

86. प्रतापगढ़ जिले की सुहागपुरा तहसील मुख्यालय पर नवीन महाविद्यालय खोलने तथा इसका नामकरण स्व. गोतम लाल मीणा के नाम पर करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

87. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में कन्या महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

88. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में विषय संकाय बढ़ाने के संबंध में।

89. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय तथा राजकीय महाविद्यालय टोडारायसिंह में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर):

90. जोधपुर स्थित महाविद्यालयों में रिक्त पड़े पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती मंजु देवी (जायल):

91. विधान सभा क्षेत्र जायल के राजकीय महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर

में क्रमोन्नत करने एवं रिक्त पड़े पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर):

92. खींवसर उपखण्ड मुख्यालय पर संचालित राजकीय महाविद्यालय का नामकरण लोकदेवता वीर तेजाजी के नाम पर करने, खींवसर विधान सभा क्षेत्र में स्थित विभिन्न सरकारी कालेजों में रिक्त पड़े पदों को शीघ्रता से भरने, ग्राम खजवाना में राजकीय महाविद्यालय खोलने एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय, खींवसर व राजकीय कन्या महाविद्यालय, पांचला सिद्धा में स्थायी पदों पर कार्मिकों की नियुक्ति करने तथा राजकीय महाविद्यालय, खींवसर में विज्ञान संकाय शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमित चाचाण (नोहर):

93. विधान सभा क्षेत्र नोहर के राजकीय महाविद्यालय तथा कन्या महाविद्यालय में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

94. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के बालिका महाविद्यालय, बांसखोह में विज्ञान संकाय खोलने, महाविद्यालय बस्सी में अर्थशास्त्र तथा इतिहास विषय पी.जी. स्तर तक क्रमोन्नत करने तथा कानोता एवं तूंगा कस्बे में राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह (आहोर):

95. विधान सभा क्षेत्र आहोर के हरजी, भाद्राजून, बागरा एवं चांदराई भवरानी में कन्या महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

96. विधान सभा क्षेत्र आहोर के राजकीय महाविद्यालय को क्रमोन्नत करने व संकाय बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

97. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के राजकीय महाविद्यालय में वाचनालय भवन के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

98. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के तख्तगढ़ कस्बे में कन्या महाविद्यालय

के नवीन भवन के कार्य को शीघ्र पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के तख्तगढ़ कस्बे में कन्या महाविद्यालय के शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

100. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में राजकीय महाविद्यालय के नये भवन के प्रथम फेज का कार्य शीघ्र पूर्ण करवाने व द्वितीय फेज की वित्तीय स्वीकृति जारी करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

101. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के राजकीय महाविद्यालय में सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

102. विधान सभा क्षेत्र भादरा के राजकीय महाविद्यालय को स्नातकोत्तर (P.G.) में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

103. विधान सभा क्षेत्र भादरा के राजकीय महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय शुरू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

104. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के एसबीआर व डीआरजे कन्या महाविद्यालय एवं कल्याणपुर महाविद्यालय में भवन निर्माण हेतु बजट आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

105. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में बालोतरा एवं कल्याणपुर के महाविद्यालयों में खेल मैदान तथा खेल सामग्री उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

106. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के बालोतरा एवं कल्याणपुर में बालक/ बालिका महाविद्यालय में विभिन्न श्रेणी के विषयाध्यापकों एवं कार्मिकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

107. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के एम.बी.आर. व डी.आर.जे. कन्या महाविद्यालय एवं कल्याणपुर में राष्ट्रीय कैडेट कॉर (एन.सी.सी.) खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

108. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के एम.बी.आर. व डी.आर.जे. कन्या महाविद्यालय एवं कल्याणपुर महाविद्यालय में शैक्षणिक एवं अन्य

गतिविधियों का संचालन हेतु संसाधन उपलब्ध करवाने हेतु बजट आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

109. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के राजकीय हाड़ारानी महाविद्यालय में प्रयोगशाला खोलने एवं भौतिक शास्त्र, रसायनिक शास्त्र, जीव शास्त्र एवं जीव विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

110. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के उप खण्ड सेमारी में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

111. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के राजकीय महाविद्यालय सांकड़ा में विभिन्न विषय के संकाय व प्रयोगाशाला खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

112. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के राजकीय महाविद्यालय, सकाड़ा में बाउण्ड्रीवाल, खेल मैदान और बच्चों को खेलने के लिए ट्रैक बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

113. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के राजकीय हाड़ारानी महाविद्यालय, सलूम्बर में खेल मैदान की बाउण्ड्रीवाल एवं खेलने के लिए ट्रैक बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

114. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के राजकीय महाविद्यालय चिखली, सिमलवाड़ा एवं चौरासी में व्याख्याताओं की कमी की वजह से बिगड़ती शिक्षण व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

115. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के लिंगानुपात को दृष्टिगत रखते हुए कन्या महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद):

116. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के राजकीय महाविद्यालय में B.Ed. संकाय चालू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

117. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के महाविद्यालय, पीसांगन हेतु नवीन भवन का निर्माण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

118. मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर में भवन व अन्य निर्माण हेतु वितीय स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रूपा राम (मकराना):

119. विधान सभा क्षेत्र मकराना के गच्छीपुरा में महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

120. विधान सभा क्षेत्र मकराना के राजकीय महाविद्यालय के नवीन भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़):

121. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के केशरी देवी लोहिया कन्या स्नातकोत्तर (P.G.) महाविद्यालय, रतनगढ़ में स्टाफ की कमी को पूरा करने, लैबोरेट्री खोलने एवं अन्य विषय के संकाय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

122. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के राजकीय जालान स्नातकोत्तर (पी.जी.) महाविद्यालय, रतनगढ़ में वाणिज्य व विज्ञान में पी.जी. खोलने तथा कला पी.जी. में अतिरिक्त विषय खोलने तथा भूगोल विषय को SFS स्कीम से हटाकर बजट की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

123. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ मुख्यालय पर विधि महाविद्यालय व B.Ed. college तथा B.S.T.C. college स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

124. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के राजकीय महाविद्यालयों में चल रहे रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

125. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के राजलदेसर राजकीय महाविद्यालय में वाणिज्य विषय खोलने व अतिरिक्त विषय के संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद):

126. शिक्षा विभाग में उपस्थिति हेतु आने व जाने के समय की मोनिटरिंग बायो-मैट्रिक व्यवस्था से करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना):

127. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

128. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के रिड़ी में राजकीय कन्या महाविद्यालय स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर):

129. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के S.B.P. राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पदों को भरने, नया भवन बनाने एवं प्रत्येक विषय में संकाय खोलने तथा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू):

130. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के महाविद्यालय अटरू में नवीन संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

131. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारां में आधारभूत संरचना के लिए विशेष बजट आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली):

132. विधान सभा क्षेत्र बाली के सभी महाविद्यालय के विभिन्न संकायों में सीटों की बढ़ोतरी की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

133. विधान सभा क्षेत्र बाली के जनजाति क्षेत्र के सभी भीमाणा में नया महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

134. विधान सभा क्षेत्र बाली के राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान संकाय की प्रयोगशाला खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

135. विधान सभा क्षेत्र बाली के राजकीय महाविद्यालय, बाली में भवन निर्माण एवं चारदीवारी बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द):

136. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द-हुरड़ा के गुलाबपुरा में बालक महाविद्यालय तथा उपखण्ड बदनोर में नया महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालूराम (डग):

137. विधान सभा क्षेत्र डग के बिड़ला महाविद्यालय भवानी मंड़ी में चारदीवारी, बाउंड्रीवाल बनाने एवं चौमहला व भवानी मंडी महाविद्यालय में खेल मैदान बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

138. विधान सभा क्षेत्र डग के चौमहला महाविद्यालय में रिक्त पदों को शीघ्र भरने व नये संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

139. विधान सभा क्षेत्र डग के भवानी मंडी व डग में बजट घोषणा के अनुरूप कन्या महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर):

140. श्रीविजयनगर में सरकारी महाविद्यालय खोले जाने एवं शहीद भगत सिंह महाविद्यालय रायसिंहनगर के सरकारीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमित चाचाण (नोहर):

141. विधान सभा क्षेत्र नोहर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नोहर में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत विषयों को राजकीय स्तर पर संचालित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

142. विधान सभा क्षेत्र जालौर में संचालित सभी राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

143. विधान सभा क्षेत्र जालौर शहर में संचालित राजकीय महाविद्यालयों में पर्याप्त कक्षा-कक्षों, प्रयोगशाला भवनों एवं अन्य आवश्यक कक्षों के निर्माण एवं वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक आधुनिक सुविधायुक्त सेमिनार हॉल के निर्माण की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

144. विधान सभा क्षेत्र जालौर के राजकीय महिला महाविद्यालय में कला स्नातकोत्तर में गृह विज्ञान विषय प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

145. विधान सभा क्षेत्र जालौर के वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नवीन विषय M.Sc., .M.A. (हिन्दी साहित्य, भूगोल एवं राजनीति विज्ञान) प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा):

146. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में छात्राओं के लिए महिला कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

147. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली):

148. विधान सभा क्षेत्र पाली के राजकीय बांगड़ महाविद्यालय के खेल मैदान को विकसित कर उसमें विभिन्न खेलों हेतु सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

149. विधान सभा क्षेत्र पाली के राजकीय कन्या महाविद्यालय, पाली के विभिन्न क्षेत्र के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

150. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के सुल्तानपुर (कोटा) में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

151. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के इटावा (कोटा) में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

152. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के राजकीय महाविद्यालय, इटावा में रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

153. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के राजकीय महाविद्यालय, इटावा (कोटा) में विज्ञान एवं कृषि संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

154. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के राजकीय महाविद्यालय, इटावा में खेल गतिविधियों हेतु खेल मैदान, खेल सामग्री तथा खेल प्रशिक्षक उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

155. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में नवीन महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

156. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के महाविद्यालयों में नवीन संकाय एवं विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

157. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के राजकीय महाविद्यालय हेतु भवन निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

158. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

159. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के राजकीय महाविद्यालय में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

160. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय से वंचित जसवंतपुरा उपखण्ड मुख्यालय पर नवीन राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय, रानीवाड़ा में प्राचार्य, आचार्य एवं सह-आचार्य के रिक्त पदों पर शीघ्र पदस्थापन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

162. विधान सभा क्षेत्र चूरू में खोले गये नये महाविद्यालयों सहित पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में नये विषय/संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

163. विधान सभा क्षेत्र चूरू में स्थित महाविद्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

164. विधान सभा क्षेत्र चूरू में स्थित महाविद्यालयों में भवन निर्माण सहित कक्षा-कक्षों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

165. विधान सभा क्षेत्र चूरू में स्थित महाविद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष, PTI सहित चतुर्थ श्रणी कर्मचारी (सहायक कर्मचारी) की भर्ती किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

166. विधान सभा क्षेत्र चूरू में स्थित विधि महाविद्यालय के रिक्त पदों को भरे जाने व लोहिया कालेज के छात्रावास की जीर्ण-शीर्ण अवस्था को ठीक करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

167. सिरोही जिले के महाविद्यालयों के अन्तर्महाविद्यालयी प्रतियोगिताओं एवं विश्वविद्यालय स्तरीय खेल-कूद प्रतियोगिताओं हेतु टीम भिजवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

168. राजकीय महाविद्यालय, कालन्द्री में व्याख्याताओं के पद-स्थापन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

169. राजकीय कन्या पी.जी. महाविद्यालय, सिरोही में गणित व इतिहास में स्नातकोत्तर कक्षाएं शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

170. विधि महाविद्यालय, सिरोही में विधि स्नातकोत्तर (LLM) की कक्षाएं शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

171. राजकीय स्नातकोत्तर सहशिक्षा महाविद्यालय, सिराही में MBA पाठ्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

172. प्रदेश के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में छात्र संघों के चुनाव शैक्षणिक वर्ष के आरम्भ में ही कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

173. अजमेर में महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय में रिक्त पड़े शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

174. प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता हेतु नियामक आयोग का गठन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

175. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न प्रतियोगी परिक्षाओं हेतु कोचिंग कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

176. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में स्थित राजकीय महाविद्यालय, बुहाना के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

177. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में स्थित राजकीय महाविद्यालय, सूरजगढ़ हेतु भूमि अधिग्रहण कर शीघ्र निर्माण कराये जाने की आवश्यक्ता पर चर्चा के लिए।

178. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के राजकीय महाविद्यालय में रिक्त सभी पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

179. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में स्थित बुहाना व सूरतगढ़ राजकीय महाविद्यालयों में सभी संकायों को चालू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी):

180. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के बबाई बालिका महाविद्यालय में स्थायी

स्टाफ लगाने और विद्यार्थियों हेतु विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

181. विधान सभा क्षेत्र आमेर में राजकीय कन्या महाविद्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

182. प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों द्वारा छात्र/छात्राओं से अधिक शुल्क एवं मनमानी फीस वसूल किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

183. प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में विषय-विशेषज्ञों एवं प्राध्यापकों के अधिकांश पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

184. राज्य के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में शोधार्थियों को आधुनिक संसाधन उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

185. राज्य सरकार द्वारा नव घोषित राजकीय महाविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व आवश्यक संसाधन यथा-शैक्षणिक स्टाफ, भवन आदि उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

186. अजमेर स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में रिक्त पड़े शैक्षणिक पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

187. अजमेर की कायड़ रोड स्थित लॉ कालेज में पार्किंग, खेल मैदान, कम्प्यूटर लैब इत्यादि मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

188. एमडीएस यूनिवर्सिटी में महर्षि दयानंद शोधपीठ, संस्कृत विभाग व वैदिक वांग्मय विभाग में निदेशक या फिर वैदिक विद्वानों की नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

189. राज्य सरकार द्वारा पिछले दो सालों में नये खोले गये महाविद्यालयों में शिक्षकों के पद भरने के साथ-साथ मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

190. कालेज शिक्षा में संयुक्त निदेशक पद पर आर.ए.एस. अधिकारी के स्थान पर प्रिंसिपल को नियुक्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

191. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के सेठ बिहारीलाल छाबड़ा राजकीय

महाविद्यालय को स्नातक से स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

192. श्रीगंगानगर जिले से घड़साना में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

193. श्रीगंगानगर जिले की रावला मण्डी में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

194. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के सेठ बिहारीलाल छाबड़ा राजकीय महाविद्यालय में दस अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

195. घड़साना में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

196. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में कन्या महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

197. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के कस्बा धौला में कन्या महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

198. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के कस्बा रायसर में कन्या महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अनिल कुमार शर्मा (सरदारशहर):

199. सरदारशहर स्थित सेठ बुधमल दूगड़ राजकीय महाविद्यालय में SFS में संचालित चार विषयों रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं जैनोलॉजी को स्नातकोत्तर (P.G.) स्तर पर करवाने तथा आवश्यकतानुसार पद सृजित करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

200. सरदारशहर स्थित सेठ बुधमल दूगड़ (SBD) राजकीय महाविद्यालय में उर्दू विषय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

201. सरदारशहर स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय को राजमेस योजना से राजकीय योजना में परिवर्तित कर पूर्णतया राजकीय महाविद्यालय किये जाने के आदेश जारी करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

202. सरदारशहर स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में छात्राओं की मांग

पर तीन नये विषय संस्कृत, इतिहास व राजनीति विज्ञान स्वीकृत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

203. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर स्थित विभिन्न राजकीय महाविद्यालय में छात्रों की मांग पर नये विषय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

204. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के सेठ रंजलाल कोठारी महाविद्यालय, राजसमन्द में विधि संकाय प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

205. नई शिक्षा नीति 2020 की क्रियान्विति में शिथिलता पर चर्चा के लिए।

206. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के किरण माहेश्वरी महाविद्यालय कुवरियां, राजसमन्द एवं द्वारकाधीश कन्या महाविद्यालय, राजसमन्द में पुस्तकालय सुविधा में कमी से उत्पन्न स्थिति और ई-पुस्तकालय प्रारम्भ करने पर चर्चा के लिए।

207. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के किरण माहेश्वरी महाविद्यालय कुवरियां, राजसमन्द एवं द्वारकाधीश कन्या महाविद्यालय, राजसमन्द में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

208. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के नये सामान्य एवं कृषि महाविद्यालयों में भवन निर्माण करने एवं रिक्त शिक्षकों के पदों की पूर्ति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा):

209. विधान सभा क्षेत्र महवा की तहसील बैजूपाड़ा में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

210. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में राजकीय महाविद्यालय, बनेड़ा (भीलवाड़ा) में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

211. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के श्री प्रतापसिंह बारहठ राजकीय महाविद्यालय में प्राचार्य, शिक्षकों व कर्मचारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

212. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के श्री प्रतापसिंह बारहठ राजकीय महाविद्यालय में पी.जी. स्तर पर विज्ञान संकाय व प्राणीशास्त्र के नये संकाय खोलने एवं अध्ययन प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

213. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के श्री प्रतापसिंह बारहठ राजकीय महाविद्यालय के जर्जर हो रहे भवन के स्थान पर नया भवन निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

214. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा जो किराये के परिसर में चल रहे हैं, के स्थान पर नव निर्मित भवन में स्थान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर):

215. प्रदेश के संचालित समस्त महाविद्यालयों में खेल गतिविधियों के विकास हेतु मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने एवं खेल प्रशिक्षक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

216. प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों में संस्कृत व्याकरण विषय में महर्षि पाणिनी कृत अष्टाध्यायी क्रम पर आधारित श्रीमती पुष्पा दीक्षित की पौष्पी प्रक्रिया का अध्ययन-अध्यापन आरम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

217. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के राजकीय महाविद्यालय में पी.जी. में अतिरिक्त विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

218. राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

219. जोधपुर में वेद-वेदाड्ग महाविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज):

220. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के नाहरगढ़ व शाहबाद में कन्या महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):

221. जयपुर शहर में वर्षों से संचालित राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण में हो रहे अत्यधिक विलम्ब के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

222. राजस्थान विश्वविद्यालय में नई लाइब्रेरी को शुरू नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

223. प्रदेश के विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

224. प्रदेश में नये खोले गये कतिपय राजकीय महाविद्यालयों को किराये के भवनों में संचालित किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

225. प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों को सुचारु रूप से चलाये जाने एवं उनकी मनमानी रोकने के लिए नियामक आयोग का गठन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

226. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न महाविद्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

227. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

228. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के महाविद्यालयों में स्टाफ की समुचित व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

229. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

230. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के राजकीय महाविद्यालय अरांई एवं आर.के. पटनी महाविद्यालय किशनगढ़ तथा महिला महाविद्यालय किशनगढ़ में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

परिशिष्ट-05

लिखित वक्तव्य

अनुदान की मांग संख्या 20-प्रारम्भिक शिक्षा, मांग संख्या 21-माध्यमिक शिक्षा व मांग संख्या 22-उच्च शिक्षा पर माननीय सदस्यगण के सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य

श्री बाबूलाल नागर (दूदू)

महोदय, आज दिनांक 01.03.2023 को सदन में मांग संख्या 20, 21, 22 पर चर्चा हो रही है, मुझे आपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया गया है। मुझे दिये गये समय की कमी के कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र दूदू से संबंधित मांगों से संबंधित कार्यों के संबंध में सारी बाते नहीं बोल सका हूं। इसलिए मांग संख्या-20 के अर्न्तगत विधान सभा क्षेत्र दूदू के ब्लाक दूदू, फागी व मौजमाबाद के कार्यक्षेत्र में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने तथा गत सरकार के दौरान एकीकृत कर बन्द किये गये विद्यालयों को पुनः प्रारम्भ करने तथा मांग संख्या-21 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने तथा राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम में रूपान्तरित करने की मांगों की सूची की प्रति सदन की मेज पर रख रहा हूं। कृपया मुझे अनुमति देने का श्रम कर मेरे भाषण के रिकार्ड में शामिल करने का श्रम करें।

मांग सख्या-20 में विधान सभा क्षेत्र दूदू के ब्लाक फागी के कार्यक्षेत्र में गत सरकार के दौरान एकीकृत कर बन्द किये गये निम्न विद्यालयों को जनहित में वरीयतानुसार पुनः प्रारम्भ करवाने का श्रम करें:-

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	विद्यालय का नाम	स्तर	समन्वित किये जाने का सत्र
1	2	3	4	5	6
1	फागी	मांदी	राप्रावि, बागरियो की ढाणी	PS	2016
2	फागी	फागी	राउप्रावि, फागी नं. 2	UPS	2014
3	फागी	फागी	राप्रावि, फागी नं. 1	PS	2014
4	पचाला	पचाला	राप्रावि, पचाला	PS	2014
5	नारेडा	छापरी	राप्रावि, ढाणी बैरवान छापरी	PS	2014
6	किशोरपुरा	मोहनपुरा राजावतान	राप्रावि, लाखावास	PS	2016

1	2	3	4	5	6
7	रोटवाडा	कुच्यावास	राप्रावि, भगत की ढाणी	PS	2016
8	मैन्दवास	नारीखेडा	राप्रावि, नारीखेडा	PS	2016
9	रोटवाडा	हरवंशपुरा	राप्रावि, कीरतपुरा	PS	2016
10	मण्डावरी	मण्डावरी	राप्रावि, गणेशपुरा फोजियान	PS	2016
11	मण्डावरी	मण्डावरी	राप्रावि, ढाणी मालियान	PS	2014
12	फागी	फागी	राउप्रावि, बालिका फागी	UPS	2016
13	चकवाडा	चकवाडा	राउप्रावि, चकवाडा	UPS	2014
14	चौरू	चौरू	राप्रावि, चौरू	PS	2014
15	कांसेल	कांसेल	राप्रावि, कांसेल	PS	2014
16	किशोरपुरा	किशोरपुरा	राप्रावि, किशोरपुरा	PS	2014
17	नीमेडा	नीमेडा	राउप्रावि, नीमेडा	UPS	2014
18	रोटवाडा	रोटवाडा	राप्रावि, रोटवाडा	PS	2014
19	मंडोर	मंडोर	राप्रावि, मंडोर	PS	2016
20	मेन्दवास	मेन्दवास	राप्रावि, बालिका मेन्दवास	PS	2016
21	कांसेल	टिकेल नरूकान	राप्रावि, टिकेल नरूकान	PS	2014
22	किशोरपुरा	समेलिया	राप्रावि, समेलिया	PS	2014
23	लसाडिया	लसाडिया	राप्रावि, लसाडिया	PS	2014
24	मण्डावरी	मण्डावरी	राप्रावि, मण्डावरी	PS	2014
25	मेन्दवास	मेन्दवास	राप्रावि, मेन्दवास	PS	2014
26	नारेडा	मण्डावरा	राप्रावि, मण्डावरा	PS	2014
27	नारेडा	नारेडा	राप्रावि, ढाणी बैरवान	PS	2014
28	परवण	परवण	राप्रावि, परवण	UPS	2014
29	परवण	परवण	राप्रावि, बैरव की ढाणी	PS	2014
30	फागी	फागी	राप्रावि, पाबूजी की ढाणी	PS	2014
31	सवाई जयसिंहपुरा	सवाई जयसिंहपुरा	राप्रावि, सवाईजयसिंहपुरा	PS	2016
32	मांदी	मांदी	राप्रावि, मांदी	PS	2016
33	किशोरपुरा	मोहनपुरा	राप्रावि, रामचन्द्रपुरा	PS	2016
34	चकवाडा	चकवाडा	राप्रावि, भरतपुरा	PS	2016
35	नारेडा	मण्डावरा	राप्रावि, बालिका मण्डावरा	PS	2016
36	चकवाडा	चकवाडा	राप्रावि बूढ़या का रास्ता	PS	2016
37	सवाई	गोविन्दपुरा बासडा	राप्रावि, शिक्षाकर्मी सारदडा	PS	2016

मांग संख्या-20 में विधान सभा क्षेत्र दूदू के ब्लाक दूदू के कार्यक्षेत्र में गत सरकार के दौरान एकीकृत कर बन्द किये गये निम्न विद्यालयों को जनहित में वरीयतानुसार पुनः प्रारम्भ करवाने का श्रम करें:-

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	विद्यालय का नाम	स्तर	समन्वित किये जाने का सत्र
1	2	3	4	5	6
1	मौजमाबाद	खेडीसुवा	राप्रावि, बागरियो की ढाणी	PS	2014-15
2	रहलाना	रहलाना	राप्रावि, बागरियो की ढाणी	PS	2014-15
3	झाग	झाग	राप्रावि, बणजारो की ढाणी	PS	2016-17
4	गागरडू	सिनोदिया	राप्रावि, बागरियो की ढाणी	PS	2016-17
5	अखेपुरा	अनन्तपुरा	राप्रावि, बागरियो की ढाणी	PS	2016-17
6	पडासौली	पडासौली	राउप्रावि, शेरगढ की ढाणी	UPS	2014-15
7	साखून	साखून	राप्रावि, सीपुरा	PS	2014-15
8	साली	साली	राउप्रावि, रेलवे स्टेशन साली	UPS	2014-15
9	झरना	केसरीसिंहपुरा	राप्रावि, केसरीसिंहपुरा	PS	2016-17
10	बिचून	नयाबास	राप्रावि, कुमावतो की ढाणी	PS	2016-17
11	नानण	नानण	राबाउप्रावि, नानण	UPSG	2016-17
12	महला	महला	राप्रावि, डागरो की ढाणी	PS	2016-17
13	सावरदा	सावरदा	राप्रावि, हाफलो की ढाणी	PS	2016-17
14	उगरियावास	उगरियावास	राउप्रावि, उगरियावास	UPS	2014-15
15	उरसेवा	उरसेवा	राप्रावि, उरसेवा	PS	2014-15
16	गाडोता	गाडोती	राप्रावि, गाडोती	PS	2014-15
17	गुढाबैरसल	गुढाबैरसल	राप्रावि, गुढाबैरसल	PS	2014-15
18	दूदू	दूदू	राप्रावि, शिवाजी नगर	PS	2014-15
19	धमाणा	धमाणा	राप्रावि, मोरो की ढाणी	PS	2014-15
20	बोराज	बोराज	राप्रावि, बोराज	PS	2014-15
21	महला	महला	राप्रावि, महला	PS	2014-15
22	मागलवाडा	मागलवाडा	राप्रावि, मागलवाडा	PS	2014-15
23	सावरदा	सावरदा	राप्रावि, सावरदा	PS	2014-15
24	अखेपुरा	अखेपुरा	राप्रावि, अखेपुरा	PS	2014-15

1	2	3	4	5	6
25	अखेपुरा	अखेपुरा	राप्रावि, दण्ड बरडा मीणो की ढाणी	PS	2014-15
26	अखेपुरा	महेशपुरा	रासंप्रावि, महेशपुरा	PSS	2014-15
27	खुडियाला	खुडियाला	राप्रावि, खुडियाला	PS	2014-15
28	गंगातीकंला	गंगातीकंला	राप्रावि, गंगातीकंला	PS	2014-15
29	गहलोता	गहलोता	राप्रावि, गहलोता	PS	2014-15
30	गागरडू	गागरडू	राउप्रावि, गागरडू	UPS	2014-15
31	गागरडू	गागरडू	राबाप्रावि, गागरडू	PSG	2014-15
32	गाडोता	गाडोता	राप्रावि, गाडोता	PS	2014-15
33	गिदानी	गिदानी	राप्रावि, गिदानी	PS	2014-15
34	गैजी	गैजी	राप्रावि, गैजी	PS	2014-15
35	झाग	झाग	राप्रावि, झाग	PS	2014-15
36	दूदू	दूदू	राप्रावि, दूदू	PS	2014-15
37	दातरी	दातरी	राप्रावि, दातरी	PS	2014-15
38	धमाणा	धमाणा	राप्रावि, धमाणा	PS	2014-15
39	धांधोली	धांधोली	राप्रावि, धांधोली	PS	2014-15
40	नानण	नानण	राप्रावि, नानण	PS	2014-15
41	पडासौली	पडासौली	राउप्रावि, पडासौली	UPS	2014-15
42	बिचून	बिचून	राप्रावि, बिचून	PS	2014-15
43	बिहारीपुरा	बिहारीपुरा	राप्रावि, बिहारीपुरा	PS	2014-15
44	बिंगोलाव	हदूपुरा	राप्रावि, हदूपुरा	PS	2014-15
45	मंमाणा	मंमाणा	राप्रावि, मंमाणा	PS	2014-15
46	मखा	मखा	राप्रावि, मरवा	PS	2014-15
47	मांगलवाडा	मांगलवाडा	राप्रावि, मांगलवाडा	PS	2014-15
48	मोखमपुरा	मोखमपुरा	राप्रावि, मोखमपुरा	PS	2014-15
49	मोजमाबाद	मोजमाबाद	राउप्रावि, मोजमाबाद	UPS	2014-15
50	रसीली	रसीली	राप्रावि, रसीली	PS	2014-15
51	रहलाना	रहलाना	राप्रावि, ज्याणी मोहल्ला	PS	2014-15
52	रहलाना	रहलाना	राप्रावि, रहलाना	PS	2014-15
53	साखून	साखून	राप्रावि, सीताराम जी का मन्दिर	PS	2014-15
54	सावली	सावली	राबाउप्रावि, सावली	UPSG	2014-15
55	सावली	सावली	राप्रावि, सावली	PS	2014-15

1	2	3	4	5	6
56	सिरोहीकंला	लदेरा	राप्रावि, लदेरा	PS	2014-15
57	सुनाडिया	छापरवाडा	राप्रावि, छापरवाड़ा	PS	2014-15
58	सुनाडिया	सुनाडिया	राप्रावि, सुनाड़िया	PS	2014-15
59	सेवा	सेवा	राप्रावि, सेवा	PS	2014-15
60	हरसौली	हरसौली	राउप्रावि, हरसौली	UPS	2014-15
61	दूदू	दूदू	राबाप्रावि, दूदू	PSG	2016-17
62	बिचून	बिचून	राबाउप्रावि, बिचून	UPSG	2016-17
63	मोजमाबाद	मोजमाबाद	राबाउप्रावि, मौजमाबाद	UPSG	2016-17
64	गागरडू	गेगा	राप्रावि, गुजरों की ढाणी	PS	2016-17
65	खुडियाला	खुडियाला	राबाउप्रावि, खुड़ियाला	UPSG	2016-17
66	गुढाबैरसल	गुढाबैरसल	राबाउप्रावि, गुढाबैरसल	UPSG	2016-17
67	सेवा	सेवा	राबाउप्रावि, सेवा	UPSG	2016-17

मांग संख्या-20 में मेरे विधान सभा क्षेत्र दूदू के ब्लाक दूदू व ब्लाक फागी के कार्यक्षेत्र में राजकीय प्राथमिक विद्यालय को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में वरीयतानुसार क्रमोन्नत करवाने का श्रम करें:-

क्र. सं.	पंचायत का नाम	विद्यालय का नाम	ब्लाक का नाम
1	2	3	4
1	कांसेल	राप्रावि, राताखेडा (463623)	फागी
2	भोजपुरा	राप्रावि, ढाणी मुसलमान (436315)	फागी
3	बिंगोलाव	राप्रावि, पंवालिया (405650)	दूदू
4	किशोरपुरा	राप्रावि, चान्दमा खुर्द (501995)	फागी
5	साली	राप्रावि, गुन्डा की ढाणी (404925)	दूदू
6	परवण	राप्रावि, कंवरपुरा (436682)	फागी
7	लसाडिया	राप्रावि, नैनस्या (502007)	फागी
8	नानण	राप्रावि, जैकमपुरा (409836)	दूदू
9	सुल्तानियां	राप्रावि, ढाणी मुसलमान सुल्तानियां (450908)	फागी
10	सुल्तानियां	राप्रावि, ढाणी बन्जारा आवण्डिया (445362)	फागी
11	सुल्तानियां	राप्रावि, गवारियो की ढाणी सावा का बास (448987)	फागी
12	लसाडिया	राप्रावि, सिरस्या (440192)	फागी

1	2	3	4
13	किशोरपुरा	राप्रावि, भीलो की ढाणी समेलिया (452995)	फागी
14	लसाडिया	राप्रावि, ढाणी मालीयान गड्डा (438465)	फागी
15	मण्डोर	राप्रावि, ढाणी मुसलमान पिनांच (463426)	फागी
16	नारेडा	राप्रावि, नारीखेडा (437904)	फागी
17	निमेडा	राप्रावि, बागरियो की ढाणी भोपान की ढाणी निमेडा (506489)	फागी
18	पचाला	राप्रावि, बागरियों की ढाणी पचाला (450827)	फागी
19	रोटवाडा	राप्रावि, ढाणी बैरवा किरतपुरा (450578)	फागी
20	सवाईजयसिंहपुरा	राप्रावि, गोविन्दपुरा बासडा (450668)	फागी
21	सावरदा	राप्रावि, अम्बेडकर कालोनी (405664)	दूदू
22	साली	राप्रावि, खंडूज (405515)	दूदू
23	रहलाना	राप्रावि, केरिया बुजुर्ग (218801)	दूदू
24	ममाणा	राप्रावि, बोकडावास (402125)	दूदू
25	ममाणा	राप्रावि, निमली की ढाणी (405657)	दूदू
26	गंगातीकलां	राप्रावि, नाईयो की ढाणी (404937)	दूदू
27	धांधोली	राप्रावि, बागरियों की ढाणी (405678)	दूदू

मांग संख्या-21 में मेरे विधान सभा क्षेत्र दूदू के ब्लाक दूदू व ब्लाक फागी के कार्यक्षेत्र में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वरीयतानुसार क्रमोन्नत करवाने का श्रम करें:-

क्र.सं.	पंचायत का नाम	विद्यालय का नाम	ब्लाक का नाम
1	2	3	4
1	पडासौली	राउप्रावि, नयागांव (410001)	दूदू
2	गिदानी	राउप्रावि, पालूकलां (405682)	दूदू
3	रोटवाडा	राउप्रावि, सांवल (493144)	फागी
4	बिहारीपुरा	राउप्रावि, सवाईमाधोसिंहपुरा (410541)	दूदू
5	किशोरपुरा	राउप्रावि, मोहनपुरा राजावतान (400615)	फागी
6	गागरडू	राउप्रावि, लापोडिया (405671)	दूदू
7	झरना	राउप्रावि, कोटजेवर (405690)	दूदू
8	झरना	राउप्रावि, देवला (401063)	दूदू
9	मोखमपुरा	राउप्रावि, केरिया (402295)	दूदू

1	2	3	4
10	सावरदा	राउप्रावि, कचनार (405666)	दूदू
11	सुनाडिया	राउप्रावि, छप्या (409797)	दूदू
12	मांदी	राउप्रावि, हथेली (455880)	फागी
13	लसाडिया	राउप्रावि, गड्डा (467994)	फागी
14	गंगातीकलां	राउप्रावि, खटवाड (405578)	दूदू
15	हरसौली	राउप्रावि, श्रीरामनगर (404319)	दूदू
16	मरवा	राउप्रावि, मोरडा (405659)	दूदू
17	बोराज	राउप्रावि, सुरपुरा (405693)	दूदू
18	धांधोली	राउप्रावि, ईटाखोई (410517)	दूदू
19	गाडोता	राउप्रावि, नासनोदा (410551)	दूदू
20	गुढाबैरसल	राउप्रावि, रामपुरा बाडिया (405614)	दूदू
21	गिदानी	राउप्रावि, पालूकलां (405682)	दूदू
22	उगरियावास	राउप्रावि, गोपालपुरा (404020)	दूदू
23	मांदी	राउप्रावि, रतनपुरा (484424)	फागी
24	दूदू	राउप्रावि, माल की ढाणी (404300)	दूदू
25	निमेडा	राउप्रावि, श्रीरामगंज (484070)	फागी
26	बिंगोलाव	राउप्रावि, दांतडा (404373)	दूदू
27	गैजी	राउप्रावि, जस्सुपुरा (404321)	दूदू
28	साखून	राउप्रावि, साखून (218785)	दूदू

मांग संख्या-21 में मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2021-22 की क्रियान्विति में विधान सभा क्षेत्र दूदू के ब्लाक दूदू, फागी व मौजमाबाद के कार्यक्षेत्र में राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में वरीयतानुसार रूपान्तरित करवाने का श्रम करें:-

क्र.सं.	**विद्यालय का नाम**	**राजस्व ग्राम का नाम**	**राजस्व ग्राम की आबादी**	**ब्लाक का नाम**
1	2	3	4	5
1	राउमावि, सावरदा	सावरदा	4921	मौजमाबाद
2	राउप्रावि, झाग	झाग	4592	मौजमाबाद
3	राउमावि रहलाना	रहलाना	4200	दूदू
4	राउमावि गुढाबैरसल	गुढाबैरसल	3836	मौजमाबाद

1	2	3	4	5
5	राउमावि लसाडिया	लसाडिया	3651	फागी
6	राउमावि उगरियावास	उगरियावास	3614	मौजमाबाद
7	राउमावि उरसेवा	उरसेवा	3500	दूदू
8	राउमावि लदाना	लदाना	3308	फागी
9	राउमावि पडासौली	पडासौली	3300	दूदू
10	सेठ पाचुलाल बागडी राउमावि साली	साली	3257	दूदू
11	राउमावि मांदी	मांदी	3200	फागी
12	राउमावि धमाणा	धमाणा	3175	मौजमाबाद
13	राउमावि बिहारीपुरा	बिहारीपुरा	3150	मौजमाबाद
14	राउमावि केसरीसिंहपुरा	केसरीसिंहपुरा	3145	मौजमाबाद
15	राउमावि गाडोता	गाडोता	3100	मौजमाबाद
16	राउमावि सांवली	सांवली	3095	मौजमाबाद
17	राउमावि अखेपुरा	अखेपुरा	3055	मौजमाबाद
18	राउमावि खुडियाला	खुडियाला	3050	मौजमाबाद
19	राबाउप्रावि मण्डावरी	मण्डावरी	3018	फागी
20	राउमावि धांधोली	घांधोली	3014	दूदू
21	राबाउमावि नारेडा	नारेडा	2941	फागी
22	राउमावि भोजपुरा	भोजपुरा	2860	फागी
23	राप्रावि बैरवा की ढाणी सुल्तानिया	सुल्तानिया	2801	फागी
24	राउमावि गैजी	गैजी	2714	दूदू
25	राउमावि गागरडू	गागरडू	2559	दूदू
26	राउमावि पचाला	पचाला	2380	फागी
27	राउमावि मरवा	मरवा	2331	दूदू
28	राउमावि समेलिया	समेलिया	2208	फागी
29	राउमावि सवाईजयसिंहपुरा	सवाईजयसिंहपुरा	2160	फागी
30	राउमावि रोटवाडा	रोटवाडा	2130	फागी
31	राउमावि परवण	परवण	2015	फागी
32	राउमावि दांतरी	दांतरी	2000	दूदू
33	राउमावि सिरोहीकलां	सिरोहीकलां	2000	दूदू
34	राउमावि कांसेल	कांसेल	1950	फागी
35	राउमावि कुडली	कुडली	1512	फागी
36	राउमावि नानण	नानण	1225	दूदू

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द)

आसीन्द ब्लाक

क्र. सं.	पदनाम	विषय	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Principal & Equivalent	--	43	24	19
2	Headmaster & Equivalent	--	0	0	0
3	Lecturer (1 Gr.)	Hindi	39	26	13
4	Lecturer (1 Gr.)	English	14	8	6
5	Lecturer (1 Gr.)	Informatics Practice	1	0	1
6	Lecturer (1 Gr.)	Physics	7	3	4
7	Lecturer (I Gr.)	Chemistry	8	4	4
8	Lecturer (1 Gr.)	Biology	7	7	0
9	Lecturer (1 Gr)	Mathematics	3	2	1
10	Lecturer (1 Gr)	Agriculture Science	4	2	2
11	Lecturer (1 Gr.)	Commerce	6	1	5
12	Lecturer (1 Gr.)	Economics	4	3	1
13	Lecturer (1 Gr)	Political Science	23	12	11
14	Lecturer (1 Gr)	Sanskrit Literature	3	1	2
15	Lecturer (I Gr.)	History	10	8	2
16	Lecturer (1 Gr.)	Geography	26	18	8
17	Lecturer (1 Gr.)	Urdu Literature	1	1	0
18	Lecturer (1 Gr.)	Sindhi Literature	0	0	0
19	Lecturer (1 Gr.)	Music (Gorge or Instrument)	0	0	0
20	Lecturer (1 Gr.)	Drawing	0	0	0
21	Lecturer (1 Gr.)	Home Science	0	0	0
22	Lecturer (1 Gr.)	Sociology	2	1	1
23	Lecturer (1 Gr)	Physical Education	1	1	0
24	Lecturer (I Gr.)	Public Administration	0	0	0
25	Senior Teacher (II Gr.)	Hindi	36	24	12
26	Senior Teacher (II Gr.)	English	38	14	24
27	Senior Teacher (II Gr)	Science	39	12	27

1	2	3	4	5	6
28	Senior Teacher (II Gr.)	Mathematics	42	8	34
29	Senior Teacher (II Gr.)	Social Science	45	26	19
30	Senior Teacher (II Gr.)	Sanskrit	49	26	23
31	Senior Teacher (II Gr.)	Urdu	1	1	0
32	Senior Teacher (II Gr.)	General/Head Teacher	8	4	4
33	Senior Teacher (II Gr.)	Special Education	3	0	3
34	Teacher (III Gr.) Level 2	Hindi	74	55	19
35	Teacher (III Gr.) Level 2	English	77	55	22
36	Teacher (III Gr.) Level 2	Mathematics/Science	72	50	22
37	Teacher (III Gr.) Level 2	Social Studies	59	48	11
38	Teacher (III Gr.) Level 2	Sanskrit	6	5	1
39	Teacher (III Gr.) Level 2	Urdu	1	1	0
40	Teacher (III Gr.) Level 1	--	468	373	95
41	Prabodhak Level-1	--	84	84	0
42	PET (I Gr.)	--	0	0	0
43	PET (II Gr.)	--	4	1	3
44	PET (III Gr.)	--	75	58	17
45	Computer Lab Incharge	--	0	0	0
46	Lab Assistant (II Gr.)	--	0	0	0
47	Lab Assistant (III Gr)	--	16	12	4
48	Librarian (I Gr.)	--	0	0	0
49	Librarian (II Gr)	--	6	0	6
50	Librarian (III Gr.)	--	7	6	1
51	Senior Assistant	--	12	8	4
52	Junior Assistant.	--	27	25	2
53	Jamadar	--	0	0	0
54	Lab Boy	--	4	0	4
55	Class IV	--	67	9	58
56	Vice Principal (School)	--	34	1	33
57	Trainer	--	0	0	0
58	Shiksha-karmi	--	3	3	0
59	Para Teacher	--	4	4	0

1	2	3	4	5	6
60	Female Para Teacher	--	4	4	0
61	varisht Shiksha-karmi	--	1	1	0
62	(grd-III) Vishesh Shishak (Level-1)	--	0	0	0
63	Prabodhak Sharirik Shikshak	--	2	2	0
64	Prabodhak Level-2	Hindi	2	2	0
65	Prabodhak Level-2	English	0	0	0
66	Prabodhak Level-2	Mathematics/Science	0	0	0
67	Prabodhak Level-2	Social Studies	4	4	0
68	Prabodhak Level-2	Sanskrit	1	1	0
69	Prabodhak Level-2-	Urdu	0	0	0
70	(grd-III) Vishesh Shishak (Level-2)	Hindi	0	0	0
71	(grd-III) Vishesh Shishak (Level-2)	English	1	1	0
72	(grd-III) Vishesh Shishak (Level-2)	Mathematics/Science	0	0	0
73	(grd-III) Vishesh Shishak (Level-2)	Social Studies	3	3	0
74	(grd-III) Vishesh Shishak (Level-2)	Sanskrit	0	0	0
75	(grd-III) Vishesh Shishak (Level-2)	Urdu	0	0	0
76	Agricultural Education In charge	--	0	0	0
77	Junior Accountant	--	0	0	0
78	Field Man and Field Rikhorder	--	0	0	0
79	Assistant Administrative Officer	--	12	10	2
80	Additional Administrative Officer	--	4	3	1
81	Varisht Prabodhak (L2)	Hindi	1	1	0
82	Varisht Prabodhak (L.2)	English	0	0	0
83	Varisht Prabodhak (L2)	Mathematics/Science	0	0	0
84	Varisht Prabodhak (L2)	Social Studies	2	2	0
85	Varisht Prabodhak (L2)	Sanskrit	0	0	0
86	Varisht Prabodhak (L2)	Urdu	0	0	0
87	Varisht Prabodhak (L1)	--	7	7	0
88	Basic Computer Instructor	--	35	0	35
89	Senior Computer Instructor	--	0	0	0

शिक्षकों व कर्मचारियों की कमी

कार्यालय मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा हुरडा भीलवाड़ा

विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के पंचायत समिति हुरडा व नगरपालिका गुलाबपुरा में संचालित राजकीय विद्यालयों में कर्मचारियों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का पदनाम संख्यात्मक विवरण:-

क्र. सं.	पदनाम	ब्लाक शिक्षा		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	प्रधानाचार्य	37	27	10
2	उप प्रधानाचार्य	28	5	23
3	व्याख्याता	121	71	40
4	वरिष्ठ अध्यापक	247	154	93
5	तृ.श्रे.अ. लेवल-2	274	214	60
6	तृ.श्रे.अ. लेवल-1	444	382	62
7	शाशि ग्रेड II/III	66	58	8
8	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	9	7	2
9	वरिष्ठ सहायक	15	12	3
10	क. सहायक	26	22	4
11	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड II/III	13	9	4
12	च.श्रे. कर्मचारी	61	19	42
योग		**1341**	**990**	**351**

क्र. सं.	पदनाम	कार्यालय मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा हुरडा		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी	1	1	0
2	अति मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी प्रथम	1	0	1
3	अति. मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी द्वितीय	1	1	0
4	आरपी	2	2	0
5	आरपी (विशेष शिक्षा)	2	0	2

परिशिष्ट-05-01 मार्च 2023-परिशिष्ट-05

1	2	3	4	5
6	कनिष्ठ अभियंता	1	0	1
7	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड II	1	1	0
8	कनिष्ठ लेखाकार	1	0	1
9	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0
10	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
11	वरिष्ठ सहायक	2	0	2
12	क. सहायक	2	2	0
13	च.श्रे. कर्मचारी	4	3	1
योग		**20**	**11**	**9**

कार्यालय मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति हुरडा जिला भीलवाड़ा

चारदीवारी विहीन विद्यालयों की सूचना 01.03.2023			
क्र.सं.	**पंचायत क्षेत्र**	**विद्यालय का नाम**	**वि.वि.**
1	खारी का लाम्बा	राउमावि खारी का लाग्बा	एक तरफ से अधूरी
2		रा.प्रा.वि. बाबरिया का खेडा	चारदीवारी विहीन
3		रा.शि. प्राथमिक विद्यालय, गणेशपुरा	चारदीवारी विहीन
4	गागेडा	राप्रावि रेबारियों की ढाणी	चारदीवारी विहीन
5		राप्रावि रुदपुरा	चारदीवारी विहीन
6		राप्रावि कांकरिया खेडा	चारदीवारी विहीन
7	रुपाहेली कलां	राप्रावि नंगाजी का खेडा	चारदीवारी विहीन
8	खेजड़ी	राप्रावि भीलों का खेडा डांग पर	चारदीवारी विहीन
9		राप्रावि प्रतापपुरा की झोपडियां	चारदीवारी विहीन
10	टोंकरवाड़ा	राउप्रावि, धनपुरा	चारदीवारी विहीन
11		राप्रावि, नयाखेड़ा	एक तरफ से अधूरी
12	भादवों की कोटड़ी	राउमावि भादवों की कोटड़ी	एक तरफ से अधूरी
13	उंखलिया	राप्रावि पुराना कुशालपुरा	चारदीवारी विहीन
14		राप्रावि नया कुशालपुरा	एक तरफ से अधूरी
15	फलामादा	राशिकप्रावि रेबारियों की ढाणी	चारदीवारी विहीन
16		राप्रावि भीलों का खेड़ा	चारदीवारी विहीन

1	2	3	4
17	तस्वारियां	राबाउप्रावि तस्वारियां	चारदीवारी ऊंची करवानी है
18		राप्रावि भैंरुखेडा	चारदीवारी विहीन
19	जालमपुरा	रा.उ.मा.वि. जालमपुरा	एक तरफ से अधूरी
20		रा.प्रा.वि. भीलों का खेडा	चारदीवारी विहीन
21		रा.प्रा.वि. कलकी खेडा	चारदीवारी विहीन
22		रा.प्रा.वि. दरोगा मोहल्ला	चारदीवारी विहीन
23	आगूंचा	राप्रावि इन्द्रा का खेडा	चारदीवारी विहीन
24	कंवलियास	राप्रावि नायको का खेडा	चारदीवारी विहीन
25		राप्रावि महादेवजी का खेडा	चारदीवारी विहीन
26		राप्रावि बैरवा मोहल्ला सनोदिया	चारदीवारी विहीन
27	शहरी क्षेत्र गुलाबपुरा	राप्रावि सजनाबाद	चारदीवारी ऊंची करवानी है।

कक्षा-कक्षों की कमी

1	गुलाबपुरा	राउप्रावि नया जोरावरपुरा	2	कक्षा-कक्ष की कमी	पुराने कक्षा कक्ष छोटे होने से
2	गुलाबपुरा	राउप्रावि मजदूर कालोनी	2	कक्षा-कक्ष की कमी	पुराने कक्षा कक्ष छोटे होने से
3	गुलाबपुरा	राउमावि जुना गुलाबपुरा	2	कक्षा-कक्ष की कमी	नामांकन अधिक एवं होने से
4	फलामादा	राउमावि फलामादा	5	कक्षा-कक्ष की कमी	पुराने कक्षा कक्ष छोटे होने से
5	सोडार	राउमावि सोडार	3	कक्षा-कक्ष की कमी	नामांकन अधिक एवं पुराने कक्षा कक्ष छोटे होने से
6	सोडार	राउप्रावि बख्तावरपुरा	2	कक्षा-कक्ष की कमी	पुराने कक्षा कक्ष छोटे होने से
7	अंटाली	राउमावि बारणी	3	कक्षा-कक्ष की कमी	नामांकन अधिक एवं क्रमोन्नत होने से
8	अंटाली	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंटाली	4	कक्षा-कक्ष की कमी	नामांकन अधिक एवं क्रमोन्नत होने से
9	दांतड़ा	राबाउमावि दांतड़ा	क्रमोन्नत होने से सम्पूर्ण भवन नये स्थान पर बनवाना		
10	कानियां	राबाउमावि कानियां	4	कक्षा-कक्ष की कमी	क्रमोन्नत होने से

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं)

महोदय, उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बेगूं (168) के ब्लाक बेगूं, गंगरार, भैसरोडगढ़ के लगभग समस्त विद्यालयों में पिछलें 5 वर्षो से प्रधानाचार्यों, व्याख्याताओं, वरिष्ठ अध्यापकों व तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद रिक्त चल रहे हैं, जिससे कि विद्यालय के छात्र-छात्राओं को अध्ययन करने में बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अतः आपसे निवेदन है कि विभाजन संख्या (103) के प्रस्तावों को तुरन्त प्रभाव से टेबल कर विद्यालयों में रिक्त पदों को जल्द से जल्द सृजित करने का कष्ट करें।

ब्लाक-बेगूं

प्राथमिक विद्यालय	**उच्च प्राथमिक विद्यालय**	**उच्च माध्यमिक विद्यालय**			
		उच्च माध्यमिक विद्यालय	**महात्मा गांधी**	**विवेकानन्द मॉडल बेगूं**	**कुल**
123	53	33	6	1	216

Principal			**Lecturer**			**2 Grade**			**3 Grade**		
स्वीकृत	**कार्यरत**	**रिक्त**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
41	6	35	161	75	86	259	123	136	483	422	61

कुल-318 पद रिक्त हैं।

बेगूं ब्लाक में 216 स्कूलों में 318 पद रिक्त हैं।

ब्लाक-गंगरार

प्राथमिक विद्यालय	**उच्च प्राथमिक विद्यालय**	**उच्च माध्यमिक विद्यालय**			
		उच्च माध्यमिक विद्यालय	**महात्मा गांधी**	**विवेकानन्द मॉडल बेगूं**	**कुल**
59	56	30	4	1	175

Principal			**Lecturer**			**2 Grade**			**3 Grade**		
स्वीकृत	**कार्यरत**	**रिक्त**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
35	19	16	105	68	37	223	119	104	641	536	105

कुल-262 पद रिक्त हैं।

गंगरार ब्लाक में 175 स्कूलों में 262 पद रिक्त हैं।

ब्लाक-भैसरोडगढ़

प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	उच्च माध्यमिक विद्यालय			
		उच्च माध्यमिक विद्यालय	महात्मा गांधी	विवेकानन्द मॉडल बेगूं	कुल
94	40	35	5	1	175

Principal			Lecturer			2 Grade			3 Grade		
स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
40	16	24	129	59	70	220	127	93	698	545	153

कुल-340 पद रिक्त हैं।

भैसरोडगढ़ ब्लाक में 175 स्कूलों में 340 पद रिक्त हैं।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़)

मांग संख्या- 20 व 21 (प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा)

विद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण

कुल विद्यालय	कुल स्वीकृत पद	कुल रिक्त पद	रिक्त पदों का प्रतिशत
198	1758	1134	65%

	प्रिंसिपल	वाइस-प्रिंसिपल	व्याख्याता	वरिष्ठ अध्यापक	तृतीय श्रेणी	अन्य
कुल स्वीकृत पद	66	55	213	373	960	91
कुल रिक्त पद	45	49	145	205	663	70
रिक्त पदों का प्रतिशत	70%	89%	68%	54%	69%	77%

1. सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव अभयसिंहपुरा, सिंधू, लालासर, माणकरासर, नारसीसर, झंझेऊ, सोनियासर गोगलियान, जयसिंहदेसर कलियां के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करना आवश्यक है। इसके अलावा बरजांगसर गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुखराम की ढाणी को क्रमोन्नत किया जावे।

2. सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव बाधनूं और बापेऊ में

10वीं व 12वीं में बोर्ड परीक्षा केन्द्र खुलवाया जावे क्योंकि इन गांवों के हजारों बच्चों को प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षा के समय नजदीकी गांवों में परीक्षा देने के लिए जाना पड़ता है।

3. सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव कल्याणसर नया में रामलाल की ढाणी, लिखमीसर उत्तरादा के हनुमान मंदिर, लोडेरां में गुसांईजी मंदिर, बिग्गाबास रामसरा में पाटवानिया जोहड़ और बावरी मोहल्ला श्रीडूंगरगढ़ शहर में नवीन राजकीय विद्यालय खुलवायें जावें क्योंकि इन सभी स्थानों पर बड़ी संख्या में बच्चे निवास करते हैं और यहां से नजदीकी विद्यालयों की दूरी अधिक होने के कारण परेशानी होती है। बीदासरी ग्राम मसूरी विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ बंद स्कूल चालू किया जाये।

4. सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत दुलचासर, टेऊ, लिखमीसर उत्तरादा, आडसर, धनेरू, कुचौर आथूणी, कीतासर भाटियान, लालासर, लालमदेसर छोटा में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जावें। राजस्थानी भाषा को राजस्थान में शिक्षा नीति इतिहास पाठ्यपुस्तक में लिया जाये।

मांग संख्या-22 (उच्च शिक्षा)

1. सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रीड़ी व दुलचासर बड़ी ग्राम पंचायतें हैं और यहां पर सरकारी व निजी विद्यालयों में प्रतिवर्ष हजारों बालिकाएं उच्च शिक्षा में प्रवेश करती हैं। अगर इन बालिकाओं को ग्राम पंचायत क्षेत्र में ही उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालय की सौगात मिल जाये तो यह बालिका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित होगा देराजसर प्राथमिक विद्यालय।

रीड़ी व दुलचासर कन्या महाविद्यालय

2. सभापति महोदय, सरकार ने इस बजट में मोमासर गांव में राजकीय महाविद्यालय की सौगात दी है, इसके लिए सरकार का धन्यवाद। मेरी सरकार से मांग है कि इसी बजट वर्ष में मोमासर महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु बजट आबंटन किया जावे।

3. सभापति महोदय, राजकीय महाविद्यालय श्रीडूंगरगढ़ व कन्या महाविद्यालय श्रीडूंगरगढ़ में बड़ी संख्या में स्टाफ के पद रिक्त हैं। इसलिए सरकार से मांग है कि इन रिक्त पदों को तुरंत प्रभाव से भरा जावे।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी)

राजकीय प्राथमिक विद्यालय से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हेतु:-

क्रं. सं.	नाम विद्यालय	विद्यालय क्रमांक	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला
1	राप्रावि सारण नं. 7	115	ढूंढी	चिखली	डूंगरपुर
2	राप्रावि बावड़ी खेड़ी	76	माल	झौथरी	डूंगरपुर
3	राप्रावि वागवा	101	सालेडा	चिखली	डूंगरपुर
4	राप्रावि धनोरा	93	लिखतिया पंचकुण्डी	चिखली	डूंगरपुर
5	राप्रावि भण्डारा	95	भादर	सीमलवाड़ा	डूंगरपुर
6	राप्रावि ढोलका	90	खरवर खुनिया	झौथरी	डूंगरपुर
7	राप्रावि रेंगदडा	81	सेण्डोला	चिखली	डूंगरपुर
8	राप्रावि आमलीफला	135	चिखली	चिखली	डूंगरपुर
9	राप्रावि रोयड़ा	102	सेण्डोला	चिखली	डूंगरपुर
10	राप्रावि आमलिफला बेडुवा	150	चिखली	चिखली	डूंगरपुर
11	राप्रावि शिशोट नवीन	126	शिशोट	चिखली	डूंगरपुर
12	राप्रावि ढेबरा	165	ढुंढी	चिखली	डूंगरपुर
13	राप्रावि सुनारिया फला	204	उटिया	झौथरी	डूंगरपुर
14	राप्रावि कलिहारी न. 8	101	नई बस्ती बडगामा	चिखली	डूंगरपुर
15	राप्रावि पाडली विरसिंह	95	पाडली गुजरेश्वर	झौथरी	डूंगरपुर
16	राप्रावि रोजेला	80	नागरिया पंचेला	झौथरी	डूंगरपुर

नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु बजट घोषणा सत्र 2023-24 में स्वीकृत कराने का श्रम करावें।

नवीन विद्यालय खोलने हेतु:-

क्र. सं.	नाम विद्यालय	ग्राम पंचायत	पचायत समिति	वि.वि
1	राप्रावि निचला गोईया	हड़मतिया	झौथरी	1.5 किमी की परिधि में विद्यालय नहीं है।
2	राप्रावि काउडाफला	बावड़ी ब	चिखली	1.5 किमी की परिधि में विद्यालय नहीं है।

क्र. सं.	नाम विद्यालय	ग्राम पंचायत	पचायत समिति	वि.वि
3	राप्रावि नवीन दुधेली का भाटड़ा	उटिया	झौथरी	1.5 किमी की परिधि में विद्यालय नहीं है।
4	राप्रावि घाटीफला	शिशोट	चिखली	1.5 किमी की परिधि में विद्यालय नहीं है।

उक्त विद्यालय में कक्षा-कक्ष का निर्माण

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	निर्माण कार्य (प्रस्तावित)	वि.वि.
1	राउप्रावि सुनारिया फला	हॉल निर्माण कार्य	झौथरी
2	राउप्रावि वागबोल	3 कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य	झौथरी
3	राउप्रावि वासुवा	3 कक्षा-कक्ष व सभागार निर्माण कार्य	झौथरी
4	राउप्रावि नानोड़ा, गडा वाटेश्वर	3 कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य	सीमलवाड़ा
5	राउप्रावि खरपेडा	3 कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य	सीमलवाड़ा
6	राउप्रावि पादरा, थाम का तालाब	3 कक्षा-कक्ष व टीन शेड निर्माण कार्य	सीमलवाड़ा
7	राउप्रावि भण्डारा बोडामली	3 कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य	चिखली
8	राउप्रावि कालापाणा बावड़ी ब	4 कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य	चिखली
9	राउप्रावि सलाखड़ी नं. 2	3 कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य	चिखली
10	राउप्रावि पोपटली	3 कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य	चिखली
11	राउप्रावि राठड़ी	3 कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य	चिखली
12	राउप्रावि ससलई	3 कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य	चिखली
13	राउमावि डोल कुंजेला	4 कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य	झौथरी
14	राउमावि गैंजी	4 कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य	झौथरी
15	राउमावि खरवेण्डा	4 कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य	झौथरी
16	राउमावि पोहरी पटेलन	सभा भवन निर्माण कार्य	झौथरी
17	राउमावि अन्नपुरा	4 कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य	झौथरी
18	राबाउमावि विकास नगर	4 कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य	झौथरी
19	राउमावि माना का देव	4 कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य	सीमलवाड़ा
20	राउमावि नया गांव खरपेडा	4 कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य	सीमलवाड़ा
21	राउमावि धम्बोला	4 कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य	सीमलवाड़ा

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	निर्माण कार्य (प्रस्तावित)	वि.वि.
22	राउमावि सादड़िया	4 कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य	सीमलवाड़ा
23	राउमावि भचडिया	4 कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य	सीमलवाड़ा
24	राउमावि बोरमाता	4 कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य	चिखली
25	राउमावि धनगांव	हॉल निर्माण कार्य	चिखली
26	राउमावि जोरावरपुरा	4 कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य	चिखली
27	राउमावि मालाखोलडा	4 कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य	चिखली
28	राउमावि सालेड़ा	4 कक्षा-कक्ष व सभागार निर्माण कार्य	चिखली
29	राउमावि गलालपुरा	4 कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य	चिखली
30	महात्मा गांधी विद्यालय चिखली	4 कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य	चिखली
31	रा.वरि.उपा. संस्कृत वि. चिखली	4 कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य	चिखली
32	राबाउमावि अम्बाडा	4 कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य	चिखली